भाकपा (माओवादी) की स्थापना की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित संकलन

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी से जारी प्रेस विज्ञप्तियां

(2004-2014)

केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

आमुख

भाकपा(माओवादी) के दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर पार्टी के कुछ अनमोल दस्तावेजों को हम संकलित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पार्टी स्थापना (21 सितम्बर 2004) से लेकर आज तक विभिन्न समयों में दिये गये प्रेस विज्ञाप्तियों का संकलन पेश कर रहे हैं। इसमें इन दस सालों में केन्द्रीय कमेटी द्वारा दिये गये ज्यादातर प्रेस विज्ञप्ति हैं। इन संदेशों में कुछ हम विभिन्न स्रोतों से जमा नहीं कर सकें। फिलहाल कुछ संदेश अनुपलब्ध है। उपलब्ध विज्ञाप्तियों में से भी सभी का अनुवाद हिन्दी में नहीं हुआ है।

इन दस सालों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रमुख राजनीतिक विषयों के बारे में भाकपा(माओवादी) ने ठोस रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किये हैं। इनके ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रमुखता को देखते हुए ये संकलन को पार्टी कतारों के बीच में, प्रगतिशील जनवादी संस्थाओं के बीच में, बुद्धिजीवी और माओवादी आन्दोलन के साथ-साथ चलने वाले लोगों के सामने रख रहे हैं। विभिन्न विषयों पर संगठन के रवैया को इन सभी के सामने रखना उपयोगी है। विभिन्न समयों में दिये गये पार्टी के आह्वानों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने लागू किया और इस तरह क्रान्तिकारी व्यवहार में भी इन विज्ञप्तियों का महत्व है।

इन प्रेस विज्ञाप्तियों में कुछ सेंट्रल रीजनल ब्यूरो के हैं और कुछ ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के हैं (केन्द्रीय कमेटी के हिस्से के रूप में इन ब्यूरोओं का गठन किया गया था)। इन दोनों ब्यूरोओं के सभी विज्ञप्तियों का हिन्दी अनुवाद हम नहीं कर पाए हैं। भविष्य में भारत की क्रान्तिकारी आन्दोलन सभी बयानों को हिन्दी में उपलब्ध कर सकेगी। इस काम को सफल बनाने के लिए योगदान देने के लिए क्रान्तिकारी शिविर को हम आह्वान करते हैं।

पिछले एक दशक में भारत की नवजनवादी क्रान्ति को सफल बनाने के लिए चलाए जा रहे दीर्घकालीन लोकयुद्ध में, गौरवशाली जनान्दोलनों में, गुरिल्ला लड़ाई में तेजी व व्यापकता लाने में, पार्टी नेतृत्व व कतारों तथा पीएलजीए कमांडरों व योद्धाओं और क्रान्तिकारी जनता के सर्वोच्च त्याग में अच्छी अनुभव मिली हैं। यह महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी प्रचार का भी दशक रहा है। इन सभी प्रेस विज्ञप्तियों को विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्तर पर विभिन्न समय में किए गये राजनीतिक प्रचार के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक उसी तरह इन बयानों को विश्व समाजवादी क्रान्ति के अंतर्गत साम्राज्यवादी और उनका पिछलग्गू और

प्रतिक्रियावादी शक्तियों के खिलाफ सर्वहारा पार्टियों का राजनीतिक प्रचार है। हम महसूस करते हैं कि विभिन्न रूपों में किये जा रहे दुश्मन के असत्य और झूठे प्रचार के तुलना में हमारा प्रचार काफी कम मात्रा में है।

अनगिनत व अथक प्रयासों के बावजूद 2008 से गहराती आर्थिक संकट से साम्राज्यवाद उभर नहीं पाया हें। दुनिया के विभिन्न इलाकों में साम्राज्यवाद के आक्रामक युद्ध के खिलाफ जनता की तीव्र प्रतिरोध के वजह से दुनिया के प्रमुख अंतरविरोध तीखे होते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य भारत में भी प्रतिबिम्बित हो रही है। दूसरी ओर दुनिया के स्तर पर कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ साम्राज्यवाद का क्रूर प्रचार धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन इसके साथ ही हमने एक राजनीतिक मोड़ का भी नजारा देखा जब साम्राज्यवाद के केन्द्र पूंजीपति देशों में मार्क्स की किताब पढ़ने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई हैं। ये लोग मार्क्स की किताब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पूंजीवादी आर्थिक संकट का असली कारण जाना जा सके। एक और धारा के लोग दुनिया की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं। ये सभी बयान सत्ता के दमन और शोषण से जुड़े विभिन्न सवालों का जवाब देती है। उतना ही नहीं, इनकी समाधान का रास्ता भी दिखाता है।

यह दशक भाकपा(माओवादी) को, इसके द्वारा मध्य और पूर्वी भारत तथा देश के कुछ अन्य इलाकों में बनाये जा रहे नयी राजनीतिक सत्ता तथा वैकल्पिक विकास मॉडल को ध्वस्त कर कारपोरेट एजेंडा को बिना कोई रोकटोक लागू करने के लिए भारत की शासक वर्गों द्वारा उनके साम्राज्यवादी आकाओं के दिशा-निर्देशन में चलाये जा रहे देशव्यापी, चौतरफा आक्रमण ग्रीन हंट अभियान का भी है जिसे सही रूप में 'जनता पर युद्ध' कहा गया है। इसका मतलब है हमारे देश के प्राकृतिक सम्पदाओं की खुली लूट, अपनी मेहनतकश जनता का शोषण और संघर्षरत जनता का बर्बर दमन।

इस दशक में भारत सरकार द्वारा छेड़े गये दमनकारी प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी कार्यवाईयों का डटकर मुकाबला करते हुए और मुहतोड़ जवाब देते हुए हमारे पार्टी ने छापामार युद्ध को आगे बढ़ाया। इसी दशक में भारत की लोकयुद्ध के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता भी पूरे दुनियाभर में विस्तार और मजबूत हुआ। फिलिप्पीन्स के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समर्थन में हमारे देश में एकजुटता सप्ताह मनाया गया।

एलआईसी नीति के अंतर्गत अमेरीकी साम्राज्यवाद के दिशा–निर्देशन में क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए दुश्मन जहरीला, गंदा, और क्रूर मनोवैज्ञानिक लड़ाई चला रहा है। इसलिए क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए अनिवार्य हो गयी है कि इसका मुहतोड़ जवाब दें। हम आशा करते हैं कि ये संकलन दुश्मन के प्रचार युद्ध का पल्टा जवाब देने के तरीके को समझने में मददगार होंगे। हमारा अनुरोध है कि पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और क्रान्तिकारी शिविर के सभी लोग इस संकलन को दुश्मन के खिलाफ प्रचार युद्ध में एक हथियार के रूप में प्रयोग करें।

क्रान्तिकारी अभिनंदन के साथ

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (माओवादी)

सितम्बर 1, 2014

विषयसूची

1. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गठन के बारे में सीसी का प्रेस विज्ञप्ति (14-10-2004).... 13

2. भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ की गई सामरिक समझौते के बारे में - सी.सी. (20-10-2004).... 19

3. नेपाली जन मुक्ति युद्ध पर भारत सरकार की हस्तक्षेप के विरोध में - सी.सी. (4-12-2004).... 21

4. राणीबोदिल रेड में भाग लेने वाले पीएलजीए कामरेडों को लाल लाल अभिनंदन – सी.एम.सी. (16-3-2005).... 24

5. मधुबन के शौर्यपूर्ण संघर्ष को बुलन्द करें – सी.एम.सी. (2-7-2005).... 25

6. राजनीतिक बन्दियों को बिना शर्त रिहा करो–सी.सी. (8-10-2005).... 30

7. क्रांतिकारी जनान्दोलनों पर चलाए जा रहे दमन अभियान के विरोध में 26 जनवरी भारत बंद सफल बनाओ–सी.सी. (4-12-2005).... 34

8. केन्द्रीय कमेटी द्वारा आहूत 26 जनवरी बंद को सफल बनाने के लिए सीएमसी प्रेस विज्ञप्ति1 (19-1-2006).... 40

9. केन्द्रीय कमेटी द्वारा आहूत 26 जनवरी बंद को सफल की गई क्रांतिकारी जनता को सीसी–सीएमसी बधाई और हार्थिक अभिनंदन (27-1-2006).... 42

10. केन्द्र सरकार की साम्राज्यवाद निर्देशित नीतियों के खिलाफ 14 दिसम्बर हड़ताल के समर्थन में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (2-2-2006).... 44

11. उत्पीडित जातियों का आरक्षण के समर्थन में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (22-5-2006).... 49

12. झूमरा पुलिस कैम्प पर पीएलजीए द्वारा की गई 'आपरेशन चक्रवात' के समर्थन में सीएमसी प्रेस विज्ञप्ति (29-6-2006).... 53
13. केन्द्र सरकार की साम्राज्यवाद निर्देशित नीतियों के खिलाफ 14 दिसम्बर हड़ताल के समर्थन में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (1-12-2006).... 58
14. केन्द्र-राज्य सरकारों द्वारा जारी कलिंगनगर-सिंगूर आदिवासियों की बेदखली की नीतियों के खिलाफ सीसी प्रेस विज्ञप्ति (25-12-2006).... 61
15. 26 जनवरी 2007 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाओ - सी.सी. (10-1-2007).... 63
16. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस संपन्न - सी.सी. (19-2-2007).... 66
17. 'स्वतंत्र नागरिक पहल' को माओवादियों का जवाब - सी.सी. (29-4-2007).... 70
18. संसदीय चुनाव का बहिष्कार करें - एक जनवादी, संघीय भारतीय गणतंत्र निर्माण के लिए नव जनवादी क्रान्ति को सफल करें - ई.आर.बी. व एन.आर.बी. प्रेस विज्ञप्ति (20-2-2009) 85
19. कामरेड आशुतोष (सीसीएम) और अन्य कामरेडों की गिरफ्तारी के बारे में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (15-3-2009).... 98
20. कामरेड्स सुधाकर रेड्डड्डी-वेंकटय्या की हत्या के खिलाफ पीएलजीए का प्रतिरोधात्मक कार्रवाई पर पूर्वी रीजनल ब्यूरो प्रेस विज्ञप्ति (13-6-2009).... 100
21. लालगढ़ जनता के ऊ पर दमन के बारे में पूर्वी रीजनल ब्यूरो प्रेस विज्ञप्ति (19-6-2009).... 102
22. शहीद स्मारक पर पुलिसिया कहर और तोड़-फोड़ के बारे में पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो प्रेस विज्ञप्ति (2-8-2009).... 105
23. कामरेड कोबाड गांधी गिरफ्तारी के बारे में उत्तर रीजिनल ब्यूरो प्रेस विज्ञप्ति (23-9-2009).... 107

24. ऑपरेशन ग्रीनहंट का विरोध में मध्य रीजियन में 72-घंटे बंद का सीसी, सीआरबी आह्वान (15-1-2010).... 111
25. चिंगावरम हमले के बाद चिदम्बरम के दुष्प्रचार के बारे में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (19-5-2010).... 115
26. कश्मीरी जनता के ऊपर दिन गोलीबारी पर सीसी प्रेस विज्ञप्ति (30-7-2010).... 119
27. कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे भारत शासक वर्गों की दरिंदगी के खिलाफ भारत बंद के लिए सीसी प्रेस विज्ञप्ति (23-9-2010).... 123
28. ओबामा के भारत दौरे के खिलाफ सीसी प्रेस विज्ञप्ति (31-10-2010).. 127
29. एकीकृत कार्ययोजना पर सीसी प्रेस विज्ञप्ति (27-11-2010).... 132
30. हिंदू सांप्रदायिकतावाद के खिलाफ 6 दिसम्बर को काला दिवस मनाओ - सीसी प्रेस विज्ञप्ति (4-12-2010).... 136
31. छत्तीसगढ़ अदालतों के फैसले पर सीसी प्रेस विज्ञप्ति (24-12-2010).. 139
32. महंगाई, घोटालों और सरकारी आतंक के खिलाफ भारत बंद (15-1-2011).... 145
33. लीबिया पर दुराक्रमणकारी युद्ध का विरोध करो, अरब जनता का समर्थन करो (31-3-2011) 150
34. पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो (5-4-2011).... 157
35. भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए जन संघर्षों को तेज करो (13-4-2011).... 162
36. जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलनरत जनता का समर्थन करो (28-4-2011) 166
37. ओसामा बिन लादेन की बर्बर हत्या का विरोध करो (4-5-2011).... 172
38. बिहार में माओवादी नेताओं की गिरफतारी के खिलाफ भारत बंद (11-5-2011).... 177
39. कामरेड भूपेशजी की गिरफतारी के खिलाफ भारत बंद (13-6-2011).... 185

40. छत्तीसगढ़ और ओड़िशा में प्रस्तावित नए सरकारी आक्रमण का मुकाबला करो (15-6-2011).... 189
41. माड़ क्षेत्र में बसाए जा रहे सेना के प्रशिक्षण केन्द्र के खिलाफ विरोध सप्ताह (18-6-2011).... 195
42. पोस्को विरोधी आंदोलनकारियों को लाल–लाल सलाम (22-6-2011).... 197
43. राष्ट्रपति द्वारा रखा गया शांति वार्ता का प्रस्ताव जनता को गुमराह करने का हथकण्डा (24-6-2011) 203
44. कामरेड्स जीतन मराण्डी और अन्यों को दी गयी फांसी की सजाओं को रद्द करो (2-7-2011).... 206
45. मुम्बई में हुए बम हमलों की भर्त्सना करो (17-7-2011).... 210
46. माओवादी नेतृत्व के खिलाफ जहरीले दुष्प्रचार को रद्दी के टोकरे में फेंक दो (19-8-2011).... 215
47. तेलंगानावासियों की 'सकल जन हड़ताल' के समर्थन में भारत बंद (30-9-2011).... 220
48. कामरेड किशनजी की बर्बर हत्या के खिलाफ भारत बंद (25-11-2011).... 224
49. सब्यसाची पण्डा का पार्टी से बहिष्कार (16-7-2012).... 230
50. दैनिक जागरण पत्रिका की दस सवालों को जवाब-ई.आर.बी. (2012).. 241
51. कुछ दुष्प्रचारों को जवाब - ई.आर.बी. (2012).... 268
52. कामरेड बीएसए सत्यनारायण के निर्धन पर - सी.आर.बी. (19-7-2012).... 289
53. अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ - सी.सी. (20-9-2012).... 293
54. रिटेल सेक्टार में एफ.डी.आई. का आगमन के विरोध में-सी.सी. (21-9-2012).... 298
55. सत्यमूर्ती के बारे में - सी.सी. (30-9-2012).... 307
56. अफजल गुरू को फांसी लगाने के बारे में - सी.सी. (13-2-2013).... 318

57. फिलिप्पीन्स क्रान्ति के समर्थन में - सी.सी. (22-3-2013).... 321

58. चतरा जिला (बिहार) हत्याकांड के विरोध में भारत बंद
- सी.सी. (31-3-2013).... 325

59. पुव्वार हत्याकांड के विरोध में सेन्ट्रल रीजियन बंद
- सी.आर.बी. (19-4-2013).... 329

60. भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में - सी.सी. (20-4-2013).... 335

61. 25 मई की हमला को एक बहाना बनाकर बड़ा आक्रामक
युद्ध छेड़ने के बारे में - सी.सी. (11-6-2013).... 343

62. उत्तराखंड में आई आपदा के बारे में - सी.सी. (26-6-2013)... 354

63. मलकानगिरी हत्याकांड के विरोध में - सी.सी. (17-9-2013).... 360

64. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बहिष्कार की गई जनता को
- सी.सी. (2-12-2013).... 364

65. दंडकारण्य संसदीय चुनाव पर सीसी प्रेस विज्ञप्ति (14-3-2014) 367

66. भा.क.पा.(माओवादी) और भा.क.पा.(मा-ले)नक्सलबाड़ी के
विलय का प्रेस विज्ञप्ति (1-5-2014).... 370

67. कामरेड सुनीति कुमार घोष को विनम्र श्रद्धांजलि - सी.सी.
(20-5-2014) 374

68. केन्द्रीय कमेटी सदस्य कामरेड सुशील राय एक लाल सूरज की तरह
हमारे राह को रोशन करते रहेंगें - सी.सी.(19-6-2014).... 380

69. रेल किराया वृद्धि पर सीसी प्रेस विज्ञप्ति (21-6-2014).... 388

70. पोलवरम परियोजना के बारे में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (29-6-2014).... 391

71. गाजा में इजरायेल हमले के बारे में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (30-7-2014) 402

72. कामरेड कोबाड गांधी को जेल में हैरान-परेशान करने के
बारे में सीसी प्रेस विज्ञप्ति (28-8-2014).... 404

73. कामरेड एम.टी. खान को श्रद्धांजलि (29-8-2014).... 408

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई)

दिनांकः 14–10–2004

सी.पी.आई.(एम–एल)[पीपुल्सवार] और एम.सी.सी.आई. का विलय सम्पन्न

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गठित

21 सितम्बर, 2004 को भारत के किसी एक छापामार क्षेत्र में जन गुरिल्ला योद्धाओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और जन संगठनों के कार्यकर्ताओं की एक सार्वजनिक सभा में क्रांतिकारी माहौल के बीच भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गठन की घोषणा की गई। अब यह घोषणा समूचे देश और दुनिया के जनता के लिए जारी की जा रही है। दोनों पार्टियों, भारत का माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी–लेनिनवादी) (पीपुल्सवार) एक एकताबद्ध पार्टी सी.पी.आई.(माओवादी) में विलयीत हो गईं। देश के मजदूर वर्ग, किसानों व समूची उत्पीड़ित जनता की यह इच्छा–आकांक्षा थी कि एक ऐसी सच्ची सर्वहारा पार्टी बने जो उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए नव जनवादी समाज की स्थापना और फिर समाजवाद व साम्यवाद की ओर आगे बढ़ने में नेतृत्व प्रदान कर सकें। इस नई पार्टी के गठन ने इसे पूरा किया है।

यह एकताबद्ध पार्टी उन विस्तृत बहसों के जरिए गठित हुई है जो पहले तो दोनों पार्टियों के उच्चत स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के बीच चलीं और बाद में जिन्हें दोनों की केन्द्रीय कमिटियों की संयुक्त बैठक द्वारा अंतिम रूप दिया गया। समानता के आधार पर चली इन गहन व रचनात्मक बहसों के

जरिए पांच दस्तावेजों का मसौदा तैयार हुआ और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। ये दस्तावेज हैं– मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के महान लाल बैनर को ऊंचा उठाए रखें, पार्टी कार्यक्रम, भारतीय क्रांति की रणनीति और कार्यनीति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिस्थिति पर राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी संविधान। इन दस्तावेजों के अलावा यह भी निर्णय हुआ की हमारी दोंनों पार्टियों के प्रिय नेताओं दिवंगत कामरेड चारू मजूमदार और कामरेड कानाई चटर्जी को इस एकताबद्ध पार्टी के संस्थापक नेताओं के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें उजागर किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ये दोनों पार्टियां जो साठ के दशक में उथल–पुथल वाले काल से खासकर, महान नक्सलबाड़ी उभार से उपजी हैं, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के लम्बे इतिहास में जो कुछ भी क्रांतिकारी था, उसकी विरासत का जीवन्त रूप से वह नई करती है। परिस्थिति की विशिष्टता यह रही कि क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन की दो अलग–अलग ध ााराओं के रूप में चली आ रही यह दोनों पार्टियां पिछले 35 वर्षों से ज्यादा अरसे से भरतीय क्रांति को आगे बढ़ाने के एक ही लक्ष्य से आगे बढ़ती रहीं। साथ–साथ उठाये गये उनके इन करदमों से साफ जाहिर है कि लाइन से जुड़े तमाम विचारध ाारात्मक व राजनीतिक सवालों पर उनमें लगभग समान समझ मौजूद थी। जो लाइन स्थापित हुई उससे दोनों पार्टियों की इस एकता को उसूली आधार उपलब्ध हुआ। इस एकता के आधार पर केन्द्रीय कमिटियों की संयुक्त बैठक ने दोनों पार्टियों की एक ही एकता पार्टी में एकताबद्ध करने के सवाल को अंतिम रूप से हल कर दिया और अब से इस पार्टी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कहा जाएगा। कामरेड गणपति सर्वसम्मति से इस नई पार्टी के महासचिव चुने गए।

एकता बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन निश्चित रूप से भारत के कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद पर आधारित एक एकताबद्ध माओवादी पार्टी हमारी कतारों समेत देश की क्रांतिकारी मिजाज वाली और उत्पीड़ित जनता तथा दक्षिण एशिया और समूची दुनिया की माओवादी ताकतों की लम्बे दिनों की ऊंची आकांक्षा व जरूरत थी। आज यह लम्बे दिनों से संजोय इच्छा–आकांक्षा और स्वपन वास्तविकता में रूपांतरित हुआ है।

यह नयी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भारतीय सर्वहारा वर्ग के एक सुदृढ़ राजनीतिक हिरावल के रूप में काम करेगी। सभी क्षेत्रों में इसकी सोच और क्रिया–कलापों का मार्गदर्शक सैद्धांतिक आधार होगा– मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद। यह दक्षिण और वाम भटकावों के खिलाफ खासकर संशोधनवाद के खिलाफ, उसे समग्रता में कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए एक प्रधान खतरा मानते हुए संघर्ष जारी रखेगी। यह अभी भी सच्चे माओवादी ग्रुपों व व्यक्तियों को एकताबद्ध करने का प्रयास करेगी, जो एकताबद्ध पार्टी से बाहर रह गए हैं। इस माओवादी पार्टी का फौरी लक्ष्य व कार्यक्रम होगा– अप्रत्यक्ष शासन–शोषण और नियंत्रण के तहत अर्धऔपनिवेशिक व अर्धसामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंककर विश्व सर्वहारा क्रांति के एक अंग के बतौर पहले से ही चल रही और आगे बढ़ रही भारत की नव जनवादी क्रांति को जारी रखते हुए उसे सम्पन्न करना। यह क्रांति साम्राज्यवाद–सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ संचालित होगी। यह क्रांति सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी युद्ध के जरिए यानी शस्त्र के बल पर सत्ता दखल को केन्द्रीय व प्रधान कार्यभार मानने वाले दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते से देहातों से शहरों को घेर लेने और अंतिम रूप से उनपर कब्जा कर लेने के रास्ते से आगे बढ़ेगी और पूरी होगी। अतः देहात और साथ–साथ दीर्घकालीन लोकयुद्ध हमारे पार्टी के गुरूत्वकेन्द्र होगी। जबकि शहरी कार्य इसका परिपूरक होगा। चूंकि इस क्रांति में संघर्ष का सबसे उंचा व मुख्य रूप सशस्त्र संघर्ष रहेगा और संगठन का मुख्य रूप रहेगा फौज अतः सशस्त्र संघर्ष एक निर्णायक भूमिका

निभाएगा। इस दृष्टि से संयुक्त मोर्चा भी सशस्त्र संघर्ष की प्रक्रिया से और सशस्त्र संघर्ष के जरिए सत्ता दखल के लिए बनेगा। जन संगठन और जन संघर्ष आवश्यक और अपरिहार्य है पर उनका उद्देश्य युद्ध की सेवा करना है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि पी.जी.ए. और पी.एल.जी.ए. एक एकताबद्ध पी.एल.जी.ए.(पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी– जनमुक्ति छापामार सेना) में विलयीत हो गई है। पूर्व की पी.जी.ए. सी.पी.आई.(एम–एल)(पी.डब्लू.) और पी.एल.जी.ए. (पूर्व की एम.सी.सी.आई.) के मृत्युंजयी साहस से भरपूर लड़ाइयों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस विलय ने उनके युद्ध निपुनता व योग्यता को व्यापक मात्रा में बढ़ाया है। अब इसके बाद पार्टी का सर्वाधिक अत्यावश्यक कार्य अर्थात् प्रध ाान कार्य एकताबद्ध पी.एल.जी.ए. को एक पूर्ण विकसित पी.एल.ए. (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) में और मौजूदा छापामार क्षेत्रों को आधार क्षेत्रों में बदल डालना तथा इस तरह लहरों की तरह आगे बढ़ते हुए नव जनवादी क्रांति को पूरा करना है। 2 दिसम्बर को हमारे तीन केन्द्रीय कमिटी सदस्यों– का. श्याम, महेश और मुरली की शहादत की पहली वर्षगांठ पर जन छापामार सेना का गठन हुआ था। यही 2 दिसम्बर अबकी पी.एल.जी.ए. का स्थापना दिवस है। इसके अलावा एकताबद्ध पार्टी जनता के विभिन्न राजनीतिक और अत्यंत मुद्दों पर क्रांतिकारी जन आंदोलनों की एक नई लहर खड़ी करने पर बल देती रहेगी। साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ संचालित इन संघर्षों में यह जनता की भारी बहुसंख्यक को सामिल करेगी। हमारे देश पर साम्राज्यवाद के खतरनाक हमलों के चलते जनता की पहले से मौजूद दरिद्रता खासकर देहाती क्षेत्रों में भारी पैमाने पर तबाही रूप ले चुकी है, हजारों की तादाद में आत्महत्याएं की जा रही हैं। यह पार्टी देश में साम्राज्यवाददियों के बढ़ते हमलों और राजकीय दमन के खिलाफ जनता की भारी बहुसंख्यक को गोलबंद करेगी तथा साथ ही

साम्राज्यवाद–सामंतवाद के खिलाफ संचालित सभी आंदोलनों के लिए समर्थन जुटाएगी। यह नई पार्टी अलग हो जाने के अधिकार सहित राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के संघर्ष को समर्थन देना जारी रखेगी और इन आंदोलनों पर क्रूर राजकीय आतंक का विरोध करेगी। यह क्रांति की एक जबरदस्त शक्ति के रूप में महिलाओं को गोलबंद करने व संगठित करने पर विशेष बल देगी और सामाजिक उत्पीड़न के सभी रूपों के खिलाफ खासकर छुआ–छुत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करेगी। यह ज्यादा खतरनाक हिन्दू फासीवादी ताकतों का भण्डाफोड़ करना उन्हें अलगाव में डालना और उन्हें परास्त करना जारी रखेगी तथा अन्यान्य सभी कट्टरतावादी ताकतों को भी बेनकाब करती रहेगी। इन तमाम कार्यों के साथ–साथ यह दिल्ली के नई कांग्रेसी शासकों व सी.पी.आई, सी.पी.एम. और उनके साम्राज्यवादी सरगनों के खिलाफ जन संघर्षों के हमले की दिशा को बनाए रखेगी।

यह भारतीय शासक वर्गों के विस्तारवादी मंसूबों के साथ–साथ उनके साम्राज्यवादी सरगनों खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों का भण्डाफोड़ करना और उनका प्रतिरोध करना जारी रखेगी। यह और भी ज्यादा सक्रिय रूप से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में संघर्षरत नेपाली जनता का समर्थन करना जारी रखेगी तथा नेपाल में भारतीय विस्तारवादियों और उभरी अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सैनिक हस्तक्षेप का जोरदार विरोध करेगी। साथ ही यह माओवादी पार्टियों के नेतृत्व में जारी पेरू, फिलिपीन्स, तुर्की तथा और भी जगहों के लोकयुद्ध को समर्थन करना जारी रखेगी। यह साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ संचालित सभी जन संघर्षों को भी समर्थन देती रहेगी। यह पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग के आंदोलन और अन्यान्य जन संघर्षों को भी समर्थन करेगी। यह अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हमलों और उनके कब्जे के विरूद्ध इराकी और अफगानी जनता के प्रबल प्रतिरोध संघर्षों के साथ खड़ी रहेगी।

एकताबद्ध पार्टी सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को ऊंचा उठाए रखेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सच्ची मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी शक्तियों को एकताबद्ध करने का अपना प्रयास और भी सक्रियता के साथ जारी रखेगी। इसके अलावा यह समूची दुनिया की उत्पीड़ित जनता व राष्ट्रों के साथ एकता कायम करेगी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साम्राज्यवाद और उनके खिदमतगारों के खिलाफ विश्व सर्वहारा क्रांति को आगे बढ़ाना जारी रखेगी तथा इस तरह दुनिया के पैमाने पर समाजवाद एवं तब साम्यवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी।

हमारे हजारों शहीदों ने इस महान लक्ष्य के लिए अपनी अनमोल जिन्दगी न्योछावर कर दी है। हमारी केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई) शपथ लेती है कि उनके द्वारा आलोकित मार्ग पर आगे बढ़ती जाएगी और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगी।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

गणपति

सचिव

केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई)

दिनांक: 20–10–2004

नेपाल के साथ की गई सामरिक समझौता भारत सरकार अविलम्ब रद्द करे, नेपाली जनता का कत्लेआम बंद करे।

आपको मालूम है कि विगत सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह में नेपाल के प्रधानमंत्री पांच दिनों के दौरे पर भारत आये थे। उस वक्त दिखाने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कुछ समझौते की बात कही गई। किन्तु असली बात थी सामरिक समझौता, जो आम प्रचार में कम लाई गई। इस समझौते के अन्दर सामरिक हेलिकॉप्टर, सैनिक संरंजाम–हथियार, गोला–बारूद, राइफल, मोर्टार के अलावे भारतीय सेना के एक बड़ी टुकड़ी भेजी जाएगी। जो पहले भेजी गई प्रशिक्षण के नाम पर सैन्य टुकड़ी दमन के साथ हो जाएगी। यह कत्लेआम की नीति अमरिकी साम्राज्यवादी नीति का एक हिस्सा है जिसमें एशिया के अधिकतम हिस्से को अपने कब्जे में कर लेने के विगत लम्बे समय से आकांक्षित लिप्सा जिसके लिए विश्व कुख्यात नरसंहार हिरोशिमा, नागासाकी और वियतनाम को श्मसान बना डाला है।

आज भारत का शासक वर्ग साम्राज्यवादियों के ठीक पालतू कुता का चरित्र दिखाने में अपने को गौरवांन्वित महसूस करता है। इसी भारतीय संस्कृति को गौरवमय संस्कृति बनाया जा रहा है। पास–पड़ोस में भी श्रीलंका, बंग्लादेश, सोमालिया आदि देशों में साम्राज्यवादी–सामंतवादी शोषण जुल्म–अत्याचार की शासन व्यवस्था के खिलाफ उठे तूफानी जन–ज्वार को खूनों की धार और लाशों की ढेरों में बदल डालने में प्रत्यक्ष मदद करता रहा है। इस जनसंहारी कत्लेआम की नीति में भारतीय फौजों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी साम्राज्यवादी गुलामी का सीधा–सीधी बिना लाग–लपेट का प्रमाण रहा है।

अंग्रजों के जमाने में भी ब्रिटीश साम्राज्यवादी हुकूमत विश्व के तमाम अपने उपनिवेशों में भारतीय फौजों का उपयोग भी इसी रूप में किया जाता रहा था। आज भी सबसे अफसोस जनक घृणास्पद, लज्जाजनक तथा आक्रोश का सवाल भारतीय मेहनतकश आवाम के सामने खड़ा है कि दिल्ली सरकार के नेपाली मिहनतकश आवाम के जनसंहारी कत्लेआम की नीति का मुकदर्शक बनकर देखते रहें।

भारत सरकार की यह नीति भारतीय उप–महाद्वीप को अमेरिकी योजनाओं के साथ जोड़कर अफगान और इराक में कारपेट बमों द्वारा बिछाये गये लाशों की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है।

भारतीय सेना नेपाली जनता के कत्लेआम को बंद करे तथा अविलम्ब फौज को वापस ले। साथ–ही–साथ पार्टी के तमाम कतारों पी.एल.जी.ए. के तमाम फॉरमेशनों, जनमिलिशियों प्रभावाधीन इलाकों की तमाम जनता की ओर से नेकपा (माओवादी) के नेतृत्व में साम्राज्यवाद–सामंतवाद विरोधी सशस्त्र गुरिल्ला संघर्ष को हार्दिक लाल अभिनन्दन करते हैं। तथा उनकी इस मुक्ति संघर्ष में कंधे–से–कंधा मिलाकर चलने का वादा करते हुए निश्चित विजय की गारंटी के प्रति पूर्ण आशा भरोसा और विश्वास व्यक्त करते हैं। चूकिं विश्व का सर्वहारा और शोषित–पीड़ित जनता की भावनायें आपके साथ जुड़ी हैं, इसलिए अंतिम विजय आपकी ही होगी।

एक बार पुनः हम भारत सरकार की इस साम्राज्यवाद–सामंतवाद परस्त नीति का विरोध करते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की केन्द्रीय कमिटी मांग करती है कि नेपाल के साथ की गई सामरिक समझौते को तुरंत रद्द करे।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

गणपति

महासचिव

केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई)

दिनांक: 4–12–04

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में जारी जनमुक्ति युद्ध में भारत सरकार के किसी भी किस्म के हस्तक्षेप का प्रतिरोध करें, परास्त करें

केन्द्र में सत्तासीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र को हर तरह के सहयोग करने की घोषणा की है। कुछ ही दिन पूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री घोषणा की है कि भूटान जैसा नेपाल की सेना वाहिनी रॉयल नेपाल आर्मी को भी हर तरह से सैनिक साजो–सामान आपूर्ति करेंगे, प्रशिक्षण देंगे और सीमा को सील कर देंगे। इस बयान का मकसद दिन का उजाला जैसा साफ है। भारत के शासक वर्ग नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्वाधीन जनमुक्ति फौज और नेपाली जनता के खिलाफ में एक अघोषित और छलपूर्ण युद्ध में शामिल होने जा रहा है।

वस्तुतः भाजपानीत राजग सरकार के जमाना से ही भारत सरकार नेपाल के राजतंत्र के समर्थन में सीधा–सीधी उतरनी चाही थी। परन्तु इराक दखल करने के बाद अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपाल में क्रांतिकारी संघर्ष को दमन करने के मामले में वह स्वयं देख–रेख करना चाहता था। उसने नेपाल की रॉयल नेपाल आर्मी के शिविरों में अनेकों सैनिक सलाहकारों को भेजा था, जिनलोग जनमुक्ति फौज के खिलाफ में संचालित युद्ध अभियानों की देख–रेख का काम कर रहे थे। भूतपूर्व राजग सरकार शांति रक्षा के बहाने कई एक बार श्रीलंका में एल.टी.टी.ई. नेतृत्वाधीन राष्ट्रीयता मुक्ति युद्ध में सीधा–सीधी हस्तक्षेप करने का असफल प्रयास की थी। याद होगा कि वर्ष 1987 में श्रीलंका की सरकार के साथ समझौता करके राजीव गांधी के जमाना में भारत सरकार शांति रक्षा के

नाम पर श्रीलंका में सेना भेजी थी। उसके पहले इन्दिरा के जमाना में वर्ष 1971 में मुक्ति वाहिनी के नाम पर भारत सरकार सेना भेजकर पाकिस्तान को दो टूकड़ा किया था और बंग्लादेश में एक कठपुतली सरकार बनाने के लिए पहल ली थी। बाद में उसने सिक्किम को दखल कर लिया। कईएक महीने पहले उसने असम में उल्फा नेतृत्वाधीन मुक्ति आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए भूटान में सैन्य अभियान चलाया था। विगत एक महीने से मणिपुर के पी.एल.ए. को ध्वस्त करने के उद्देश्य से वह बर्मा की सीमा पर तथा उसके अंदर गुप्त रूप से अभियार चला रही है। प्रत्येक घटना में ही देखा जाता है कि भारत सरकार साम्राज्यवादियों और अपने वर्ग स्वार्थ की रक्षा करने के लिए भारतीय उपमहादेश में दादागिरी चलाती है।

नेपाल की महान जनता कई एक वर्षो से राजतंत्र के खिलाफ में नव जनवादी समाज निर्माण करने के लक्ष्य में माओवादियों के नेतृत्व में संघर्ष चला रही है। साम्राज्यवाद और तमाम प्रतिक्रियावादी लोग हिंसात्मक रूप से नेपाल के इस क्रांतिकारी संघर्ष का विरोध कर रहे हैं। यूपीए सरकार के एक अन्यतम मददगार सी.पी.एम. भारत के पैमाने पर इस निर्णय का दिखावे के तौर पर निन्दा कर सकता है परन्तु वह कभी भी यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं करेगा और जहां वह सत्ता में है पश्चिम बंगाल में आतंकवाद दमन के नाम पर नेपाल की जनता के संघर्ष को हानि पहुंचाने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ते। सी.पी.एन. (माओवादी) के सर्वोच्च नेताओं में से एक कामरेड मोहन वैद्य सहित अनेकों नेता और कार्यकर्ताओं को बंगाल की मिल्ली से गिरफ्तार किया है।

हमारी केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई) नेपाल के महान क्रांतिकारी संघर्ष के समर्थन में भारत की क्रांतिकारी जनता को भारत सरकार के अन्याय आचरण के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए सच्ची एकता कायम करने का आह्वान करती है। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार अगर अंततः नेपाल

के दमन के लिए अपनी भाड़े की फौज को भेजती है तो उन्हें भी 1887 में श्रीलंका में भेजी गई भारतीय शांति रक्षा वाहिनी जैसा ही शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ेगा। केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई) भारत के उपमहादेश के तमाम क्रांतिकारी, जनवादी लोगों के पास विस्तारवादी शासक वर्ग और उसकी प्रतिक्रियावादी सेना वाहिनी के खिलाफ में एकताबद्ध संघर्ष निर्माण करने का आह्वान करती है।

केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई) भारत के तमाम क्रांतिकारी एवं जनवादी शक्तियों के पास न्यायप्रिय शांतिकामी जनता के पास नेपाल के आंतरिक मामले में विस्तारवादी भारत सरकार के हस्तक्षेप का तीव्र विरोध करने के लिए प्रतिरोध ा आंदोलन निर्माण करने का आह्वान करती है।

केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई) मेहनतकश वर्ग से आए हुए भारतीय सैन्य वाहिनी के जवानों के पास आह्वान करती है कि नेपाली जनता के खिलाफ में भारत सरकार द्वारा संचालित अन्यायपूर्ण सैन्य अभियान में हिस्सा लेकर अपने वर्ग भाइयों के खून से हाथ न रंगें।

दक्षिण एशिया सहित तमाम विश्व की जनता के पास हमारा आह्वान है कि हजारों–हजार नेपाली जनता के खून से हाथ रंगे राजा ज्ञानेन्द्र के मध्ययुगीन बर्बर शासन के स्वार्थ की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा नेपाल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किए जाने का सक्रिय विरोध करें और उसके खिलाफ एकताबुद्ध आंदोलन का निर्माण करें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

गणपति

महासचिव

केन्द्रीय कमिटी (अस्थाई)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

प्रेस विज्ञप्ति

पत्रांक :

तिथि : 16-3-2007

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन की ओर से राणीबोदिल रेड में भाग लेनेवाले पीएलजीए कामरेडों को गर्म-जोशी भरा लाल लाल अभिनंदन !

15 मार्च पूर्वाहं अहले सुबह लगभग 2 बजे इलाके की उत्पीड़ित अत्याचारित, फर्जी मुठभेड़, सलवा जुडूम का सामूहिक हत्या, गांव दहन करना, आदिवासियों को आतंकित करके विस्थापन और पुलिस कैंपों की जेल जीवन की झेल रही पीड़ाभरी स्थितियों से क्रान्तिकारी जनता की क्रोध, आक्रोश और घृणा ने पीएलजीए के सक्रिय सहयोग और साझेदारी से ऐसा विस्फोटक रूप ले लिया, जो बीजापुर जिले की राणीबोदिल कैंप को खाक में बदल दिया और वर्दीधारी गुंडे 54 मारे गये, और दर्जनों घायल हुए तथा सभी हथियार जप्त किये गये। साम्राज्यवादी कुत्तों का गिरोह शासक वर्ग में मातम, और जनता में खुशी की लहरें फैल गयी। जनता के सच्चे शहीद जनयोद्धा पुत्रों के सपने अभी भी जीवित हैं और पीएलजीए अत्याचारी जुल्मी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने को तत्पर ही नहीं वल्कि विस्तार भी पाया है। बीजापुर के राणीबोदिल कैंप पर प्रत्याक्रमण और वर्दीधारी शूरमाओ जो निहत्थे जनता के ऊपर मारपीट, लूटपाट, बच्चे, बूढ़े, बीमार, लंगड़ा, लुल्हा, महिलाओं से अभद्र व्यवहार से लेकर सामूहिक बलात्कार आदि इनके बहादुरी के दैनिक जीवन में सर्वत्र देखा जा सकता है, खास कर नव जनवादी क्रान्तिकारी संघर्ष के इलाके में। पर शायद शासक वर्ग जुल्म, अत्याचार के पहलू को ही समझता है, उसके लिए यही उचित भी है । पर जुल्म और अत्याचार का दूसरा पहलू प्रतिरोध है, जो अत्याचार के गर्भ से जन्म लेता है। अत्याचारों से पलता, बढ़ता और शक्तिशाली होता है, इसका क्रम विकास और अत्याचार को समाप्त करने तक प्रतिरोध सबकुछ झेलते हुए ही विकसित होता है। बिहार के लखीसराय जिला का खैरा पिकेट पर 4 सिपाहियों को मारा जाना, 4 घायल, जी.टी. रोड पर 4 रायफल और 2 बंदूकें, सुनील महतो का सफाया-4 इनसास जप्त आदि जारी अभियान एकता कांग्रेस 9वीं कांग्रेस की भावनाओं और कार्यभारों के सफल पहल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन उन दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी सदस्यों उक्त इलाके की मिलिटरी कमिशन, कमान, पीएलजीए के कमाण्डरों, जन मिलिशिया समेत पीएलजीए के तीनों बलों और इलाके की क्रान्तिकारी जनता जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लिए हैं, सभी को क्रान्तिकारी लाल-लाल अभिनंदन और बधाई देती है। इसके साथ ही साथ राज्यस्तर के तमाम कमिशनों और कमानों को सलाह देती है कि राणीबोदिल की तरह प्रतिरोधात्मक क्षमता का विस्तार करते हुए प्रत्याक्रमण को तेज करें। आक्रमण से बचने और रक्षा करने का उपाय प्रत्याक्रमण ही है। आत्मरक्षा के लिए आक्रमण ही एकमात्र रास्ता है । ढिलाई और आलस हमें कमजोर करता है और शत्रु शासक वर्ग के भाड़े के वर्दीधारी अत्याचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। इसलिए शत्रु की चौतरफा हमले को चौतरफा प्रतिरोध या प्रत्याक्रमण ही जवाब है । संघर्ष और लड़ाई के नीतियों का सार भी यही है।

क्रान्तिकारी अभिनंदन के साथ

केंन्द्रीय मिलिटरी कमिशन (सी.एम.सी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन

2-7-2005

मधुबन के शौर्यपूर्ण संघर्ष को बुलंद करें!

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 23 जून, 2005 को दोपहर 1.15 बजे जनमुक्ति छापामार सेना (पी.एल.जी.ए.) के लगभग 150 जवानों और 50 लड़ाकू जनता ने पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन बाजार पर आश्चर्यजनक ढंग से एक ही साथ 6 स्थानों– थाना, अंचल–कार्यालय, दो बैंकों, खूंखार जमींदार सीताराम सिंह के आवास और पेट्रोल पम्प पर बिजली की गति से हमला बोलकर आश्चर्यजनक रेड (Surprise Raid) अभियान की कार्रवाई को मिनटों में सफलतापूर्वक सम्पन्न कर थाना से 3- S.L.R., 1- 303 रायफल, अंचल–कार्यालय से 4- 303 रायफल, बैंक से 1– DBBL बंदूक तथा सीताराम सिंह के आवास से 2- DBBL और दोनों बैंकों से .... रूपया जप्त कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पिपराही से एक कार्बाइन और एक 303 रायफल भी जप्त किया गया है।

मधुबन के आश्चर्यजनक रेड अभियान की कार्रवाई को अपनी जान की कुर्बानी देकर सफल करने वाले जनमुक्ति छापामार सेना (P.L.G.A.) के प्लाटूनों, स्थानीय छापामार स्कवाडों (L.G.S.), जनमिलिशिया स्कवाडों (P.M.S.) और आत्मरक्षा दल (S.D.S.) के अदम्य साहसी वीर योद्धाओं और लड़ाकू जनता को केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन गरमजोशी भरा सहस्त्र लाल सलाम पेश करता है।

मधुबन के शौर्यपूर्ण संघर्ष का तात्पर्य क्या है?

ज्ञातव्य हो कि पिछले कई दशकों से भारत के माओवादी क्रांतिकारी पार्टी व संगठनों के नेतृत्व में सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी छापामार संघर्ष तीव्र से तीव्रतर होते जा रहा है। विगत 21 सितम्बर, 2004 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन होने के बाद तो भारत के क्रांतिकारी संघर्ष में एक नया उभार आ गया है। यह घटना क्रांतिकारी कतारों और जनता के अन्दर में जहां नया जोश, उत्साह और प्रेरणा पैदा की है, वहीं वर्ग–दुश्मनों– साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल पूंजीपति वर्गों के अन्दर में भय–आतंक और घबराहट पैदा

की है।

आज सी.पी.आई.(माओवादी) के नेतृत्व में तकरीबन हमारे देश के हर प्रांतों में क्रांतिकारी संग्राम व संगठन फैल चुका है और कई प्रांतों में तो क्रांतिकारी संघर्ष उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। अर्थात् गुरिल्ला जोन के स्तर से आधार इलाका के स्तर पर पहुंचने के दौर में है। जनता की जनमुक्ति छापामार सेना (P.L.G.A.) का गठन हो चुका है। गांव-गांव में, इलाके-इलाके में क्रांतिकारी जन-कमिटी की सरकार कायम की जा रही है, जमीन, जल और जंगल पर जनता का अधिकार कायम किया जा रहा है। शोषक-शासक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिक्रियावादी केन्द्र व राज्य सरकार ने भी खुद 13 राज्यों को उग्रवाद से प्रभावित (उनकी भाषा में) घोषित कर इसकी स्वीकृति प्रदान की है।

साम्राज्यवाद के दलाल भारतीय शोषक-शासक वर्गों ने साम्राज्यवाद के इशारे पर इस न्यायपूर्ण क्रांतिकारी संघर्ष को कुचलने के लिए क्रांतिकारी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित कर शीर्ष नेतृत्वकारियों, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्याएं करना, बर्बर शारीरिक और मानसिक यातनाएं देना, घेराव-दमन अभियान के तहत जनता को बेरहमी से मार-पीट करने, फर्जी मुठभेड़ में गोली मारने, माँ-बहनों एवं बहु-बेटियों का सामूहिक बलात्कार करने जैसा मध्ययुगिन बर्बर हमला चलाते आ रहा है। इसके बावजूद क्रांतिकारी संघर्ष दबने के बजाय और तीव्र से तीव्रतर होते जा रहा है। तब उसने Joint Operational Command (संयुक्त कार्रवाई कमान) का गठन कर घेराव-दमन अभियान में गुणात्मक रूप से बदलाव लाया। पुलिस व अर्द्ध-सैनिक बलों को अत्याधुनिक हथियारों, माइन-निरोधक, बुलेटप्रूफ वाहनों, यंत्रों और उपकरणों से लैस करने, छापामार युद्ध का मुकाबला करने हेतु 'जंगल वार फेयर' का प्रशिक्षण स्कूल खोलकर मिजोरम की पहाड़ियों में, हैदराबाद में अमेरिकी साम्राज्यवाद की प्रत्यक्ष मद्द पर अमेरिकी मरीन सैनिकों और अफसरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी इस प्रकार का प्रशिक्षण स्कूल खोला जा रहा है। JOC के अन्तर्गत सभी राज्यों में इसे खोलने का निर्णय लिया गया है। इन प्रशिक्षण स्कूलों में अर्द्ध-सैनिक बलों को प्रशिक्षण देकर ग्रे-हाउण्ड्स, कमांडो, S.T.F. आदि का गठन कर नेतृत्वकारियों के ऊपर लगातार हमले चलाये जा रहे हैं और जनता के ऊपर और बर्बर तरीके से हमले चलाये जा रहे हैं।

सी.पी.आई.(माओवादी) के गठन होने के बाद शोषक-शासक वर्ग इसको आंतरिक सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ा खतरा के रूप में चिन्हित किया है और क्रांतिकारी संघर्ष के ऊपर दमन चलाने के लिए सेना का इस्तेमाल करने हेतु तैयार है। सैनिक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना तो शुरू कर ही दिया है।

दूसरी तरफ, शोषक-शासक वर्ग जितना ही दमन चला रहा है उतना ही क्रांतिकारी संघर्ष तीव्र से तीव्रतर होते जा रहा है, यह कामरेड माओ के कथन की सच्चाई को ही प्रमाणित करता है कि जहां जुल्म और दमन होता है वहीं प्रतिरोध भी होता है। उससे भी आगे बढ़कर यहां जितना दमन हो रहा है उतना ही प्रतिरोध, प्रतिरोध और प्रतिरोध तेज होते जा रहा है। सी.पी.आई.(माओवादी) के नेतृत्वाधीन जनमुक्ति छापामार सेना (P.L.G.A.) भी हाथ में हाथ धरे चुप-चाप बैठी हुई नहीं है, बल्कि JOC के तहत चलाये जा रहे बर्बर घेराव-दमन के खिलाफ केन्द्रीय योजना अनुसार कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण के तहत जवाबी प्रतिरोधात्मक कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्रांतिकारी संघर्ष को गुरिल्ला जोन के स्तर से आधार इलाका के स्तर में विकसित करने हेतु उन्नत स्तर के संघर्ष की तैयारी में जुटी हुई है और परिस्थिति के मद्देनजर प्रतिरोधात्मक कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मधुबन के आश्चर्यजनक रेड अभियान उसका ही अभिन्न अंग है।

मधुबन का शौर्यपूर्ण संघर्ष, नक्सलबाड़ी के सशस्त्र विद्रोह के बाद उत्तर बिहार की धरती में जारी क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष का जो गौरवमय इतिहास रहा है उस गौरवमय संघर्ष की परम्परा को ही आगे बढ़ाया है। उत्तर बिहार की बहादूर जनता द्वारा वर्ग-संघर्ष को तेज करते हुए सामंतवाद पर करारी प्रहार किये जाने के कारण सामंती सत्ता लड़खड़ाने लगी है। तब सत्ता के मुख्य अंग राष्ट्र यंत्र यानी पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बल आकर उसकी रक्षा करने के लिए क्रांतिकारी जनता के ऊपर बर्बर दमन-अत्याचार बदस्तुर जारी रखा है।

ऐसी स्थिति में उत्तर बिहार की वीर जनता ने वर्ग संघर्ष को तेज करते हुए सामंती सत्ता को उखाड़ फेंककर क्रांतिकारी किसान कमिटी व क्रांतिकारी जन कमिटी की सरकार व हुकूमत कायम करने हेतु क्रांतिकारी संघर्ष को गुरिल्ला जोन में विकसित करते हुए विशाल मैदानी इलाके में अस्थाई मौसमी आधार इलाका कायम करने के उद्देश्य एवं JOC के तहत चलाये जा रहे घेराव-दमन के खिलाफ जवाबी प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करने, हमारे आर्थिक

भंडार को लूट लिये जाने के खिलाफ उनके आर्थिक भंडार बैंक को जप्त करने और विस्तारवादी भारत सरकार द्वारा नेपाल के जनयुद्ध को दमन करने हेतु नेपाल की प्रतिक्रियावादी सरकार को हथियार और सैनिक हेलीकॉप्टर भेजने के खिलाफ में मधुबन पर इस शौर्यपूर्ण संघर्ष की कार्रवाई की है।

मधुबन का आश्चर्यजनक रेड अभियान बिहार–झारखण्ड के अबतक के क्रांतिकारी संघर्षों में सबसे बड़ा तथा गुणात्मक रूप से उन्नत स्तर का संघर्ष है, जो की एक ही साथ 6 स्थानों पर हमले किये गये और लड़ाई को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। पुलिस के आला–अधिकारी ने भी इसे स्वीकारा है। यह लड़ाई उत्तर बिहार के विशाल मैदानी इलाके में क्रांतिकारी संघर्ष को गुरिल्ला जोन के स्तर में विकास करने तथा अस्थाई आधार इलाका के स्तर में जाने के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लड़ाई इस मायने में भी उन्नत स्तर की लड़ाई है क्योंकि जब मधुबन संघर्ष को सफल किये जाने के बाद दुश्मन द्वारा सी.आर.पी.एफ., एस.टी.एफ., एस.एस.बी. और आर.पी.एफ. के पांच सौ जवानों को लगाकर घेराबंदी अभियान चलाया गया जिसके दौरान कई मुठभेड़ हुई, तब पी.एल.जी.ए. (P.L.G.A.) के जवानों ने उसका डटकर मुकाबला करते हुए उन्हें धूल चटाते रहे, उनके कई सिपाहियों को मार गिराया और उनके हथियार को भी जप्त किया और अंततः 'वार प्लानिंग' के तहत घेरकर कुचल डालने के दुश्मन के बुरे मनसूबे को नकाम कर दिया।

दुश्मनों ने इस लड़ाई से जनता को भ्रमित करने और अपनी लाज बचाने के लिए झूठा अफवाह उड़ाने लगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसने दर्जनों, बीस–तीस की संख्या में माओवादियों को मार गिराया है, जोनल कमांडर कामरेड रवि को मार गिराया है आदि। सरासर यह झूठा और भ्रामक प्रचार है। वास्तविकता यही है कि मधुबन संघर्ष सफल करके लौटते वक्त पुलिस द्वारा रास्ते पर घेराबंदी किये जाने पर घेरे को तोड़कर सभी साथियों को सुरक्षित निकालने के दौरान डटकर पुलिस के साथ मुकाबला करने के दौरान पाँच साथियों को शहादत देनी पड़ी और थाना पर हमला करने के दौरान एक साथी शहीद हुए हैं।

जबकि पी.एल.जी.ए. के जवानों ने दुश्मन के 7 जवानों को मार गिराया। जिसमें मधुबन थाना पर दो सिपाहियों, बैंक के एक गार्ड, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में फेनहारा थानान्तर्गत श्यामपुर में दो जवानों को और पीपराही गांव की

मुठभेड़ के दौरान एक हवलदार और एक सिपाही को मार गिराकर उनसे एक कार्बाइन और एक 303 रायफल जप्त किया।

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन, PLGA के कॉमरेडों और उत्तर बिहार के क्रांतिकारी जनता को आह्वान करता है कि मधुबन के शौर्यपूर्ण संघर्ष से लेकर दुश्मन द्वारा 'युद्ध योजना' के तहत की गई घेराबंदी फेनहारा, श्यामपुर से लेकर बैरगनिया, पीपराही, सुल्तानगंज तक के घेरेबंदी के दौरान साहस और बहादूराना के साथ किये गये शौर्यपूर्ण संघर्ष को बुलंद रखें। विशाल देहाती इलाकों से सामंती सत्ता को उखाड़ फेंककर क्रांतिकारी जन-कमिटी की सरकार व हुकूमत कायम करने हेतु विशाल मैदानी इलाका को अस्थाई आधार इलाका में बदल डालने हेतु गांव-गांव में आत्मरक्षा दल, इलाके-इलाके में जनमिलिशिया स्कवाड का गठन करें तथा स्थानीय छापामार स्कवाड और प्लाटून की संख्या में वृद्धि करने हेतु व्यापक तौर पर नवयुवक, नवयुवतियों को PLGA में भर्ती करें, ''हर व्यक्ति को योद्धा बनाने, हर परिवार को पार्टी-सेल बनाने और हर गांव को किला बनाने'' के नारा को साकार करने हेतु आगे बढ़ें।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन

सी.पी.आई.(माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

8-10-2005

कामरेड सुशील राय, पतितपावन एवं चंडी सरकार समेत तमाम राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा करो!

प्यारे देशवासियो,

आप सबों को ज्ञात होगा कि हमारी पार्टी के पोलित ब्युरो सदस्य कामरेड सुशील राय (अशोक, शोम, बरूण दा) एवं पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी के सचिव व केन्द्रीय कमिटी सदस्य कामरेड पतितपावन (तापस), राज्य कमिटी सदस्य चंडी सरकार, किशोर, अरूप समेत लगभग 40 साथियों को (15 मई से 21 जून के भीतर) पश्चिम बंगाल की सामाजिक फासीवादी सी.पी.एम. की सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल की काली कोठरियों में कैद कर रखा है। 21 मई, 2005 को हुगली जिला के कोननगर रेलवे स्टेशन से कामरेड बरूण एवं तापस को गिरफ्तार किया गया तथा लगातार चार दिनों तक गुप्त रूप से रखकर उन्हें मानसिक उत्पीड़न एवं शारीरिक यातनाएँ दी गई और 24 मई को जन-दवाब के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन लोगों को गिरफ्तार कोननगर (कोलकता उपनगर) से किया गया है, पर फासीवादी शासन की पुलिस मनगढ़ंत कहानी गढ़कर उन्हें पश्चिमी मिदनापुर जिला के बेलपहाड़ी से गिरफ्तार करने की बात कह रही है तथा वहाँ के कई झूठे मुकदमे लादकर पश्चिमी मिदनापुर जेल में बंद कर रखा है।

हमारे पोलित ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी एवं राज्य कमिटी के सदस्यों की क्यों हुई है गिरफ्तारी? बिल्कुल साफ है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में देश के कई भागों में सशस्त्र संग्राम चल रहा है। यह संग्राम शोषित-उत्पीड़ित जनता के मुक्ति के लिए चल रहा है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता के जनवादी राज का निर्माण झारखण्ड-आन्ध्र-बिहार-दण्डकारण्य में हो रहा है। जमीन और जनसत्ता का प्रश्न आज और तीव्रता के साथ शोषक-शासक वर्गों के सामने उठ खड़ा हुआ है। फिर साम्राज्यवादी पूँजी

देश में धड़ल्ले से घुस रही है जिसके कारण लाखों–लाख कल–कारखाने बन्द हो गये हैं। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ी है। अतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं साम्राज्यवादी लूट तथा सामंतवादी शोषण के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी जनता सजग एवं संगठित हो सशस्त्र संग्राम में कूद पड़ी है। हमारी पी.एल.जी.ए. के छापामारों ने शोषक–शासक वर्ग एवं साम्राज्यवादी लूट तथा सामंती शोषण एवं दमन के खिलाफ कोरापुट, चंदौली, सारंडा, मधुबन जैसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में विजय हासिल कर वर्ग दुश्मनों के कलेजा को दहला दिया है। देशी–विदेशी शोषक–शासक वर्ग इससे घबरा उठा है और घबरा उठा है 21 सितम्बर, 2004 की गठित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से।

केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशिल गठबन्धन (संप्रग) की सरकार, जिसमें सी.पी.एम. भी हिस्सेदार है, आज 'आंतरिक सुरक्षा' के सवाल को प्रधानता से उठा रही है। दरअसल 'आंतरिक सुरक्षा' के नाम पर देश में चल रहे क्रांतिकारी संग्राम का दमन करना ही इनका मुख्य मकसद है। क्रांतिकारी जनता के दमन के लिए टाडा, पोटा, पोका, मकोका, एस्मा जैसे काले कानून लादे जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर अमेरिका ने हमारी पार्टी सी.पी.आई.(माओवादी) को प्रतिबन्धित घोषित किया है तथा हमें आतंकवादी संगठन की सूची में डाला है। आज देश के 13 राज्यों को लेकर एक संयुक्त ऑपरेशनल कमाण्ड (JOC) का गठन किया गया है। बिहार, आन्ध्र, झारखण्ड, दण्डकारण्य, उड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश के संघर्षशील इलाकों को अर्द्धसैनिक बलों एवं स्पेशल टास्क फोर्स से भरकर जनता पर भारी जुल्म–अत्याचार एवं दमन चलाया जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा प्रतिदिन दर्जनों क्रांतिकारियों को पूरे देश भर में हत्याएँ की जा रही हैं। पिछले एक साल में देश भर में हजारों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी की एक कड़ी है– का. बरूण दा, तापस, चंडी सरकार, किशोर, अरूप, प्रसूण, शोमा एवं बुटाई की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में 2800 से भी ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 1200 माओवादी हैं।

हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं छापामारों की फर्जी मुठभेड़ में हत्याएँ एवं गिरफ्तारियाँ हमारे संघर्ष को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। पूरे देश में हमारे ऊपर आघोषित युद्ध चलाया जा रहा है। कई राज्यों ने हमारी पार्टी को प्रतिबन्धित किया है और अधिकांश राज्यों ने बिना प्रतिबन्ध घोषित किये ही प्रतिबन्धित संगठन की तरह व्यवहार कर रही है।

किसी भी तरह के प्रतिवाद एवं प्रतिरोध पर रोक है। यहाँ तक की जनवादी संगठनों के कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। क्रांतिकारी जनता को शांतिपूर्ण एवं खुली जनसभा, रैली, गोष्ठी, सम्मेलन आदि तक नहीं करने दी जा रही है।

29 वर्षों से पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार है जिसका मुख्य नेता सी.पी. एम. है। उनके समाजवाद में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। अमलासोल एवं कांथी गांव में भूख से मरने वाली जनता सी.पी.एम. के समाजवाद का स्पष्ट उदाहरण है। समाजवादी फासीवादी बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डुबी है। भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी सी.पी.एम. का आदर्श है। जार्ज बुश की नीतियों को पालन करना तथा साम्राज्यवाद का जय-जयकार आज बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की समाजवादी कार्यक्रम का अंग है। दमन और सुधार सामाजिक फासीवादी शासन का सूत्र है। सी.पी.एम. भूमण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण (LPG) का केन्द्र व दूसरे राज्यों में विरोध करती है पर, पश्चिम बंगाल में इसको लागू करने को बेताब है। साम्राज्यवादी नीति (LPG) के लागू करने के लिए तथा साम्राज्यवाद को आश्वस्त करने के लिए ही पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी जन संग्राम को कुचलने का बीड़ा उठा रखा है सी.पी.एम. ने।

पश्चिम बंगाल के गिरफ्तारी के ठीक पहले अप्रैल माह में 'आंतरिक सुरक्षा' के नाम पर आर्मी कमांडरों की बैठक हुई थी, जिसमें माओवादियों को दमन करने की योजना बनाई गयी थी। फिर 17 जून को नक्सलपंथियों के दमन हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। 13 राज्यों के ज्वाइंट ऑपरेशनल कमाण्ड की बैठक तो अब हरेक एक-दो माह के भीतर चल रही है, जिसमें दमन के नित्य नये-नये हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं। उन हथकण्डों को लागू करने में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार भी किसी दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार से पीछे नहीं है। आज पश्चिम बंगाल माओवादियों के कैद का पिंजरा बना हुआ है कारण कि वाम मोर्चा सरकार जनता की रोजी-रोटी के सवाल को हल करने में विफल हो चुकी है। अत: राजनीतिक विरोध के चलते एवं जब पश्चिम बंगाल की जनता आज नये सिरे से पुन: माओवादियों के नेतृत्व में उठ खड़ी हो रही है तब वाम मोर्चा सरकार संघर्ष को दबाने के लिए दमन चला रही है। पर, दमन से दबाया नहीं जा सकता है क्रांतिकारी जनता के संग्राम को।

का. बरूण का राजनीतिक जीवन मजदूर आन्दोलन से शुरू हुआ। जय इन्जिनियरिंग वर्क्स (उषा कम्पनी) में 65-66 में जो हड़ताल हुई थी उसमें उनकी प्रमुख भूमिका थी। पश्चिम बंगाल के खाद्य आन्दोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। रूस-चीन की कम्युनिस्ट

पार्टी के बीच चली *''महान बहस''* के दौरान से ही वे चीनी लाइन के समर्थक थे। शुरू से ही 'चिन्ता' एवं 'दक्षिण देश' ग्रुप के साथ जुड़े रहे तथा 20 अक्टूबर, 1969 में गठित माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के साथ भी जुड़े रहे। शुरू से ही वे पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी के सदस्य थे। कामरेड के.सी. के निधन के बाद वे एम.सी.सी. के महासचिव बने। 1989 में एम.सी.सी. के प्रथम सम्मेलन में भी वे महासचिव निर्वाचित हुए। अपनी खराब स्वास्थ्य के चलते इन्होंने 1996 में महासचिव पद ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। एम.सी.सी.आई. और सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.डब्लु.) के विलय एवं नई पार्टी के गठन में भी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभायी। का. बरूण एम.सी.सी. के तमाम उतार-चढ़ाव के दौरान एक वरिष्ठ, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित नेता रहे हैं। कामरेड सुशील राय (शोम) दक्षिण एशिया के क्रांतिकारी खेमों के बीच भी जाने-माने नेता रहे हैं।

का. पतितपावन (तापस) बचपन से ही एम.सी.सी. के साथ जुड़े रहे हैं। ये मध्यम किसान परिवार के सदस्य रहे हैं। हुगली जिला में किसान आन्दोलन खड़ा करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इन्होंने दृढ़तापूर्वक पश्चिम बंगाल के पार्टी लाइन की रक्षा की है। कामरेड तापस ने नई पार्टी के गठन एवं पश्चिम बंगाल राज्य की कमिटियों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

कामरेड चंडी सरकार रेलवे में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, वहीं से वे मजूदर आंदोलन के साथ जुड़े। नक्सलबाड़ी के बाद नौकरी छोड़कर पेशेवर कार्यकर्ता बन सी.पी.आई. (एम-एल) में शामिल हुए। 70 के दशक में वे चार सालों तक जेल में रहे पर, अपने क्रांतिकारी उसूल पर अडिग रहे। जेल से छूटने के बाद पुन: क्रांतिकारी कामकाज में जुट गये। नदिया जिला में जननेता के रूप में पिछले तीस सालों से वे लोकप्रिय हैं।

अंत में हम मजदूर, किसान, छात्र-नौजवान, महिला, बुद्धिजीवी, कलाकार, जनपक्षीय एवं जनप्रेमी लोगों, लोकतांत्रिक संगठनों एवं व्यक्तियों से अपील करते हैं कि वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं क्रांतिकारी जनता समेत कामरेड बरूण, पतितपावन (तापस), चंडी सरकार, किशोर, अरूप एवं प्रसूण, शोमा, बुटाई के गिरफ्तारी का विरोध करें, उसकी निन्दा करें एवं भर्त्सना करें तथा इनके साथ-साथ तमाम राजनीतिक बंदियों के रिहाई के लिए एक देशव्यापी जन आन्दोलन को तेज करें।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ

केन्द्रीय कमिटी (अस्थायी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

4-12-2005

क्रांतिकारी जन आंदोलनों पर चलाये जा रहे दमन-अभियान का मुँहतोड़ जवाब दें! 26 जनवरी, 2006 को भारत बन्द करें!

प्यारे देशवासियो,

केन्द्र की वर्तमान यू.पी.ए. सरकार और उसके पहले एन.डी.ए. की सरकार भी एक सुर से आज आन्तरिक सुरक्षा के सवाल को केन्द्रीयसमस्या के रूप में उठा रही है। न केवल सरकार बल्कि पूरा विपक्ष एवं मिडिया भी एक ही राग अलाप रहा है। कल तक बाहरी खतरा का भूतदेखने वाली केन्द्र सरकार अचानक आन्तरिक सुरक्षा को देश की एक नम्बर की समस्या बता रही है और इसके साथ लड़ने के लिए सुधार एवं दमनका रास्ता भी अपना रही है। परन्तु, सवाल है कि आज देश के सामने भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, शोषण एवं विस्थापनआदि राष्ट्रीय संकट के रूप में क्यों नहीं आ रहा है? आन्तरिक सुरक्षा ही आज क्यों प्रमुख मुद्दा बना हुआ है? आखिर आन्तरिक खतरा किससे है?जनता के सामने बिल्कुल साफ है कि सरकार नक्सलवादियों (माओवादियों) को ही आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है। पर, वास्तव मेंक्या यह सच है? नहीं।

आज हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण (LPG) का अभियान जोरों पर है। साम्राज्यवादी देशों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (MNC) की पूंजी देश के सारे आर्थिक क्षेत्रों में बेरोकटोक निवेश हो रही है। देश के आधारभूत उद्योगों एवं खनिज संपदाओं को कौड़ी के मोलदलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग, साम्राज्यवादी देशों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बेचा जा रहा है। जल, जंगल, जमीन को इनके हाथों बेचनेके करार पर करार हो रहे हैं। साम्राज्यवादियों की लूट नीति के चलते देश के लाखों-लाख कल-कारखाने बन्द हो गये। साथ

ही उद्योगों केआधुनिकीकरण, मशीनीकरण एवं कम्प्युटरीकरण के चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये हैं। भारत सरकार की साम्राज्यवादपरस्त नीति एवं विश्वव्यापार संगठन के सदस्य बन जाने के कारण कृषि पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। भारत के आम किसान बर्बाद एवं तबाह हो चुके हैं। पिछले एक दशक में देश के हजारों किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। आदिवासियों का विस्थापन की समस्या और भी बिकराल रूप धारण करती जा रहीहै।

अत: दिन के उजाले की तरह जनता के सामने बिलकुल साफ है कि तमाम भूतपूर्व एवं वर्तमान केन्द्रीय सरकार दलाल नौकरशाह पूंजीपतिवर्ग, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं साम्राज्यवादियों की पूंजी की रक्षा एवं विकास चाहती है। इन्हीं के हित में उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरणकी नीति को अपनाकर लागू कर रही है। ये देश के प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) के दोहन एवं लूट तथा मेहनती मजदूर-किसान जनताके शोषण के लिए मुर्दानी शांति चाहते हैं। जबकि हम नक्सलवादी (माओवादी) तमाम तरह के शोषण एवं लूट के खिलाफ देश के बड़े भाग मेंसशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं। हम देश की स्वाध ीनता, राष्ट्र की मुक्ति एवं जनता के हित (साम्राज्यवाद, सामंतवाद से मुक्ति) हेतु लड़ रहे हैं। यह लड़ाईपिछले 38 वर्षों से जारी है, जो दिन-प्रतिदिन और तीखी, तीव्र एवं विस्तारित होती जा रही है।

अत: साफ है कि हमारे सशस्त्र संघर्ष जारी रहने के चलते साम्राज्यवादी लूट धड़ल्ले से नहीं चल सकती है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसाके खनिज सम्पदा के लूट के खिलाफ हमारा आंदोलन और तेज होता जा रहा है तथा इसमें लाखों-लाख आदिवासी जनता हिस्सा ले रही है व सशस्त्रहो रही है और पी.एल. जी.ए. में शामिल हो रही है। फलत: देश के शोषक-शासक वर्ग एवं साम्राज्यवादी शक्तियां भयाक्रांत हैं। अत: इसको दमनकरने के लिए नाना किस्म के उपाय कर रहे हैं। जिसमें दमन एवं सुधार प्रमुख हैं। परन्तु दमन ही इनकी प्रधान रणनीति है।

देश में चल रहे क्रांतिकारी जन आंदोलनों के दमन हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकारें अमेरिकी खुफिया विभाग सी.आई.ए. एवं एफ.बी.आई. तथाइजरायल के खुफिया विभाग मोसाद से मदद ले रही है। एफ.बी.आई. की तो दिल्ली में बजाप्ते कार्यालय भी खुल गया

है। साम्राज्यवाद के युद्धसंबंधी नीति कम तीव्रता वाले युद्ध (स्वू पदजमदेपजल बवदसिपबज. स्प्ब) की नीति केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारें अपना रही हैं। इसके लिए एक तरफतो पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों को नये-नये तरीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। मिजोरम के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध से लड़ने का प्रशिक्षण दियाजा रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.), इंडियन रिजर्व बटालियन, सेंगल (आग) बटालियन -झारखण्ड, ग्रेहाउण्डस -आन्ध्रप्रदेश, आदिजैसे बलों का गठन किया गया है। सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो-तिब्बत सीमा बल, नागालैंड सशस्त्र बल एवंएस.एस. बी. आदि अर्द्धसैनिक बलों को संघर्षशील इलाकों में तैनात किया गया है। टाडा, पोटा, पोका, मकोका, 17 सी.एल.ए. आदि काले कानूनोंके तहत संघर्षशील जनता को लम्बे काल तक जेलों में बन्द रखना तथा फांसी की सजा सुनाना आदि कार्रवाई जारी है। फिर 13 राज्यों को लेकरज्वायंट ऑपरेशनल कमांड का गठन कर दमन-अभियान जारी है। जिसमें फर्जी मुठभेड़ में हत्या, मां-बहनों के साथ बलात्कार करना, जनता केघर-मकान को लूटना-ढ़ाहना, मार-पीट, गाली-गलौज, धौंस-धमकी तथा गिरफ्तार कर जेल भेजने का सिलशिला जारी है। इसके अलावा जनताके बीच प्रतिक्रियावादी तत्वों को लेकर विभिन्न किस्म के संगठन एवं सेना खड़ा किया जा रहा है। ताकि जनता के बीच आपस में ही लड़वायाजाये। इन सेना एवं संगठनों को केन्द्र व राज्य सरकारें एवं उनका पुलिस-प्रशासन तथा खुफिया विभाग आर्थिक एवं सामरिक मदद करता है तथाजनता पर जुल्म-अत्याचार चलाने एवं सामूहिक जनसंहार करने के लिए आदेश एवं दिशा-निर्देश देता एवं जारी करता है। दरअसल इस तरह केसंगठन एवं सेनाओं में समाज के सुचिन्हित वर्ग-दुश्मन, प्रतिक्रियावादी अपराधी, लुंपेन एवं अध:पतित तत्वों को लेकर गठित की जाती है। साथही जनता को गुमराह करने के लिए जाति, धर्म, बाहरी-भीतरी, आदिवासी-गैरआदिवासी हिंसा-अहिंसा एवं लोकतंत्र व विकास विरोधी सेंटीमेंटको काम में लगाती है।

पूरे देश भर में सरकार संरक्षित ग्राम रक्षा दल का गठन किया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा समिति (पूर्व-पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड), ग्रामसुरक्षा समिति (झारखण्ड), शांति सेना (गुमला-लोहरदगा, झारखण्ड), झारखण्ड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा, जनसंहारों के लिए कुख्यात बिहार कीरणवीर सेना, गण सुरक्षा समिति (पश्चिम बंगाल) तथा आन्ध्र प्रदेश में ग्रीन टाईगर्स, प्लानाडू टाईगर्स, नल्ला-मल्ला टाईगर्स, नल्ला-मल्ला कोबरा,नरसा कोबरा एवं नईम गिरोह आदि का गठन एवं संचालन किया जा रहा है। सेंदरा (सामूहिक शिकार) एवं सलवा जुडुम (शांति यात्रा) के द्वाराक्रांतिकारी जनता पर जुल्म, अत्याचार एवं हत्या

अभियान चलाया जा रहा है।

सलवा जुडूम – छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में सलवा जुडूम चलाया जा रहा है, जिसका समर्थन एवं सहयोग भाजपा की रमण सिंह सरकार कर रही है। सलवा जुडूम के नाम पर क्रांतिकारी आदिवासी जनता की हत्याएं एवं आगजनी की कई घटनाएं की गई है। 19 जून को कोतरापाल गांव पर हमला कर 4 मकानों को जला दिया गया। पुनः एक जुलाई को कोतरापाल गांव पर ही हमला कर 7 और मकानों को जला डाला गया और दो बूढ़े किसानों- वंजामी मंगू (58 वर्ष), उईके सन्नू (52 वर्ष) को सी.आर.पी.एफ. ने गोली मारकर हत्या कर दी और एक बूढ़ी महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। सरगुजा जिला के गणेश राम भगत एवं वर्तमान गृह मत्री रामविचार नेतामभी इसी किस्म का प्रयास उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में चला रहे हैं। दरअसल इसके पिछे लक्ष्य यह है कि बस्तर के संसाधनों को लूटने की छूटदेशी-विदेशी लूटेरों को दी जाये। इसके लिए छत्तीसगढ़ के रमण सिंह सरकार ने दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उद्योग लगाने का न्योता दिया है और उनको भारी छूट देने की भी घोषणा की है। तकरीबन 60 हजार करोड़ रूपयों के करारों पर हस्ताक्षर किया गया है। जिनमें 7 हजार करोड़ रूपये के इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए ईस्सार के साथ तथा 10 हजार करोड़ रूपये के इस्पात संयंत्र स्थापित करने का टाटा के साथ हुए करार प्रमुख हैं।

सेंदरा – झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के एस.पी. अरूण उरांव ने 2003 में नक्सलवादियों को सेंदरा करने का खुला ऐलान किया था और एक साजिश के तहत गुड़ाबांधा थाना के लांगो गांव में 9 माओवादियों की हत्या करवाई थी। इसी तरह के प्रयास पश्चिमी सिंहभूम के एस.पी. प्रवीण कुमार एवं झारखण्ड के पूर्व मुखमंत्री एवं भाजपा नेता बाबूलाल मराण्डी एवं उनका भाई नुनुलाल मराण्डी गिरिडीह जिला में चला रहे हैं। वे ग्राम रक्षा दल के नाम पर भोली-भाली जनता को लोभ-लालच देकर बहका रहे हैं। पर भेलवाघाटी की घटना के बाद उनके षड़यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। आमतौर पर मुसलमान विरोधी भाजपा एवं बाबूलाल मराण्डी ग्राम रक्षा दल में मुसलमानों को आगे बढ़ाकर बलि का बकरा बना रहे हैं। भेलवाघाटी (थाना-तिसरी, जिला- गिरिडीह) की घटना के बाद लगभग तीन दर्जन गांवों के करीब एक हजार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। झारखण्ड के गिरिडीह एवं सारंडा में सेंदरा का सपना बाबूलाल मराण्डी एवं एस.पी. प्रवीण कुमार का चकनाचूर हो गया।

एल.आई.सी.(Low Intensity conflict-कम तीव्रता वाले युद्ध) खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक नया युद्ध-कौशल है। दरअसल इसका मकसद यह है कि जहां भी जनता के आंदोलन जो साम्राज्यवाद, सामंवाद के नाश के लिए हो या कमजोर करने के लिए हो उसको ध्वस्त करने के लिए उस आंदोलन के नेताओं को जनता से अलग-थलग करो। इसके लिए एक तरफ अपनी खुफिया नेटवर्क को मजबूत कर उन नेताओं कोया तो मार गिराओ नहीं तो फिर गिरफ्तार कर फर्जी मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल में सड़ाते रहो। साथ ही जाति, धर्म, बाहरी-भीतरी, विकास एवं लोकतंत्र तथा हिंसा-अहिंसा आदि का भ्रम फैलाकर उस आंदोलन के खिलाफ जनता के ही एक तबका को खड़ा करो। इसके लिए तथाकथित पक्ष विपक्ष के तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को खुले या गुप्त रूप से शामिल करो तथा दिखावा के लिए आंदोलन का रूप दो। इसी की एक कड़ी है- सेंदरा, सलवा जुडूम एवं जनजागरण अभियान। दरअसल ये सारे अभियान दमन अभियान के ही एक सूचक हैं। पूर्वी सिंहभूम के नागरिक सुरक्षा समिति के नेता हैं भाजपा के धनई किसकु एवं जे.एम.एम. का शंकर हेम्ब्रम, ग्राम रक्षा दल के सर्वे-सर्वा है भाजपा के पूर्व मुख्य मंत्री बाबूलाल मराण्डी एवं उसका भाई नुनुलाल मराण्डी एवं कांग्रेस का रविन्द्र राय। बिहार में जनसंहारों के लिए कुख्यात रणवीर सेना के संरक्षक है भाजपा के सी.पी. ठाकुर, जनार्दन शर्मा, कांग्रेस के रामजतन शर्मा, राजद के अखिलेश प्रसाद सिंह एवं सुरेन्द्र प्रसाद यादव, जदयू के अरूण कुमार तथा वर्तमान एवं भूतपूर्व जिला एवं हाइकोर्ट के न्यायाधीश तथा कई-एक आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस.। सलवा जुडूम के महेन्द्र कर्मा (कांग्रेस), रमण सिंह (मुख्यमंत्री), रामविचार नेताम (गृह मंत्री) एवं गणेश राम भगत (भाजपा)। आन्ध्र प्रदेश में जो विभिन्न टाईगर्स एवं कोबरा गिरोह हैं उसका संरक्षक है तेलुगु देशम, कांग्रेस एवं भाजपा के कई विधायक, सांसद तथा कईएक बड़े पुलिस अफसर। और यही लोग विभिन्न नामों के संगठन, सेना एवं गिरोह खड़ा कर क्रांतिकारी नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं जनता पर नाना किस्म के जुल्म-अत्याचार, उत्पीड़न एवं हत्याकांड कर व चलवा रहे हैं और यह अमेरिकी साम्राज्यवाद का एल.आई.सी. का ही एक अभिन्न हिस्सा है। आज देश के भीतर जहां भी साम्राज्यवाद, सामंतवाद एवं दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के खिलाफ

जन आंदोलन उठा खड़ा हो रहा है वहीं उसके दमन हेतु नाना किस्म के हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें अपने कथित लोकतंत्र एवं संविध ान को ताक पर रखकर जन आंदोलनों पर फासिस्ट एवं तानाशाही किस्म का हमला एवं अत्याचार चला रही हं। वे जनता की खुली, कानूनी एवं नि:शस्त्र सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, कॉन्वेंशन एवं विचार-गोष्ठी तक नहीं करने दे रही है। इतना ही नहीं कई जन संगठनों को वे प्रतिबन्धित घोषित कर चुकी हैं जिसमें छात्र-युवा, महिला, मजदूर, लेखक, कवि एवं कलाकार संगठनों तक को भी नहीं छोड़ा है। साथ ही बुद्धिजीवियों एवं कवियों को उन्होंने जेल केअन्दर कैद कर लिया है। आज आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में क्रांतिकारी जन संगठनों तथा आम लोकतांत्रिक संगठनों के कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दिया गया है। जनता के अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक किस लोकतंत्र एवं आजाद मूल्क का परिचायक है? साफ है - न तो भारत में कोई लोकतंत्र है और न ही आजादी। भारत में लोकतंत्र और आजादी सिर्फ हाथी के दांत हैं।

अत: हम देश के मजदूर, किसान, छात्र-नौजवान, कलाकार, कवि, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा जनप्रेमी, जनपक्षीय एवं लोकतांत्रिक व्यक्तियों व संगठनों से अपील करते हैं कि केन्द्र, राज्य सरकारों के विभिन्न रंग-रूप एंव प्रकार के दमन-अभियान का मुँहतोड़ जवाब दें, उसका विरोध करें, उसकी निंदा करें, भर्त्सना करें तथा इसके खिलाफ जनता को सजग-सचेत एवं गोलबन्द कर कृषि क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष एवं क्रांतिकारी जन संग्राम को तेज करें। अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सभा, जुलूस, प्रदर्शन, नुक्कड़ सभा, रैली, कॉन्वेंशन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन करें तथा 26 जनवरी, 2006 को भारत बन्द करें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

केन्द्रीय कमिटी (अस्थायी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन

19-1-2006

भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय कमिटी द्वारा आहूत 26 जनवरी बंद को सफल करें!

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन की क्रान्तिकारी जनता एवं पी.एल.जी.ए. सदस्यों (मिलिटरी फार्मेशनों) से अपील

भारत का दलाल शासक वर्ग की दलाल केन्द्र-राज्य सरकारें साम्राज्यवाद की सेवा और आदेश पालन में सार्वभौमत्व, नागरिक स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार तार-तार होकर गुलामी की वास्तविक व्यवस्था का भयानक रूप सामने खड़ा है। जिसका व्यावहारिक रूप सरकारी-गैरसरकारी जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, दमन और शोषित-पीड़ित वर्ग की अधिकारहीनता का आलम देशव्यापी है। प्रगतिशील विचार और कार्यक्रम शासक वर्ग के सामने उग्रवाद का दानव लगता है तथा हर प्रगतिशील कार्यक्रम वैध-अवैध तरीका से रोकना सरकार अपना दायित्व समझती है। देशभक्त, ईमानदार, जनसेवी, प्रगतिवादी या प्रगतिशील मिहनतकश अवाम अपराधी ठहरा दिये जाते हैं तथा जेलों के सीकचों में बंद होते हैं। अपराधी, गुंडा, अपहरणकर्ता, डाकू सरदार, भूमिचोर, कालाबाजारी, बलात्कारी संसद, विधान सभा और न्यायाधिशों के पद पर आसीन हैं। जनता का आक्रोश चोटी पर है और अन्याय के खिलाफ न्याय की रणभेरी की गूंज देशवासियों को रणक्षेत्रों में ललकार रहा है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बनने की घोषणा और पी.एल.जी.ए. का निर्माण की घोषणा से साम्राज्यवादी आदमखोरों और भारतीय दलालों के शोषण, जुल्म, अत्याचार, दमन-उत्पीड़न की ठोस खूंखार जनविरोधी व्यवस्था दमन की एक और बाढ़ लेकर उभरी। केन्द्रीय सरकार के नेतृत्वाधीन JOC के तहत एक तरफ गैरसरकारी या अर्द्धसरकारी सेनाएं व कार्यक्रम ग्रीन ब्रिगेड,

कोबरा गेंग, रणवीर सेना, नागरिक सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा दल आदि के नेतृत्व में सलवा जुड़ूम, सेंदरा, जन-जागरण के नाम पर हत्या का तांडव, आगजनी, साम्प्रदायिक तनाव, जातीय दंगा आदि का नंगा नाच चला रहा है, तो दूसरी ओर वर्दीधारी सेनाएं हमारे पार्टी के वयोवृद्ध नेताओं को अपहरण कर यातनाएं दे रही हैं। का. सुशील राय (65) और का. नारायण सान्याल (68) पोलित ब्यूरो सदस्य, का. पतित पावन (43) केन्द्रीय कमिटी सदस्य के अलावे राज्य स्तर के सैकड़ों सदस्यों, दसियों हजार कार्यकर्ता व समर्थक जनता को यातना के लिए जेलों में बंद कर रखा है। इसमें हम उन्हें जेलों को तोड़ कर ही निकाल सकते हैं, जैसे हमने जहानाबाद जेल को तोड़ा है।

क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के ऊपर चलाये जा रहे इस बर्बर जुल्म, अत्याचार के खिलाफ पार्टी ने 26 जनवरी को बंद का आह्वान किया है जिसे सफल बनाने के लिए केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन सम्पूर्ण शोषित-पीड़ित जनता को अपील करता है तथा पी.एल.जी.ए. सदस्यों का इस बंद को सफल बनाने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक केन्द्रीय बलों के विफल करने के हर प्रयास और हमले को नाकाम करते हुए जनता की सेवा में अपने को समर्पित जनसेवक का परिचय देना समय की मांग है।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी

(माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

27-1-2006

26 जनवरी आहूत 'भारत बंद' को सफल करने के लिए भारत की क्रांतिकारी जनता को बधाई और हार्दिक अभिनन्दन!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमिटी और केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन ने भारत की केन्द्रीय व राज्य सरकारों की सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी दमनात्मक, क्रूरतम, फांसीवादी बर्बर जनविरोधी– सलवा जुडूम, सेंदरा, रणवीर सेना, ग्राम रक्षा दल (बेलतू), नागरिक सुरक्षा समिति, झारखण्ड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा आदि के अलावे संयुक्त कार्रवाई कमान (जे.ओ.सी.) के द्वारा हजारों–हजार सैनिक, केन्द्रीय बलों की कंपनियों द्वारा मार–काट, लूट–पाट, आगजनी, फर्जी मुठभेड़ तथा पार्टी के बयोवृद्ध देशभक्त, क्रांतिकारी नेताओं– का. सुशील राय उर्फ वरूण दा, का. तापस, का. नारायण सान्याल उर्फ विजय दा के अलावे हजारों कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी आदि की कार्रवाइयों के खिलाफ आहूत 'भारत बंद' को सफल करने के लिए देश के तमाम क्रांतिकारी जनता को हार्दिक लाल अभिनन्दन करते हैं। हमारी सर्वहारा वर्ग की अगुआई वाली पार्टी के तमाम वर्ग दोस्तों की राजनीतिक समझदारी, राजनीतिक एकजुटता के प्रदर्शन के लिए तमाम दोस्त वर्गों– छोटे–छोटे व्यवसायी, छोटे उद्योगपति, बस–ट्रक मालिकों, शिक्षक, चिकित्सक सहित तमाम मेहनतकश अवाम को हार्दिक लाल अभिनन्दन करते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम 'भारत बंद' को विफल करने पर उतारू केन्द्र–राज्य सरकारों की शासन–प्रशासन ने तोड़–फोड़ करने को ललकारा था। फिर भी अनुशासनबद्ध हमारे कार्यकर्ता एवं कतारों ने संयम, साहस और धैर्य की असीम प्रतिबद्धता के साथ इसे सफल किया है। इसके लिए उन सभी कतारों को हार्दिक अभिनन्दन

देते हैं। तोड़-फोड़ का जिम्मेवारी प्रशासन की है, जिसने विफल करने के लिए सैनिक बलों का उपयोग किया है।

केन्द्रीय कमिटी और केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन अपने अधिनस्थ तमाम पार्टी कमिटियों, पार्टी सदस्यों, पी.एल.जी.ए. के तमाम फारमेशनों, जनमिलिशियाओं, ग्राम रक्षा दलों, स्वयं सेवक दलों, क्रांतिकारी किसान कमिटियों, जन कमिटियों, जनसंगठनों के मोर्चों पर तैनात सदस्यों, 'केन्द्रीय कमिटी द्वारा आहूत भारत बंद' को सफल करने के प्रति समर्पित जनसेवी सदस्यों को हार्दिक लाल अभिनन्दन करता है। तथा अनुशासनबद्ध कार्यक्रम के पालन में तमाम कतारों को हार्दिक बधाई देती है।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ

प्रवक्ता
आजाद
केन्द्रीय कमिटी (अस्थायी)
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ
समरजीत
केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

2-2-2006

दुनिया के एक नंबर का आतंकवादी और युद्धबाज जार्ज डब्ल्यू बुश की हमारे देश की प्रस्तावित यात्रा का जम कर विरोध करें !
विराट प्रदर्शनों के जरिये बुश और दलाल मनमोहन सिंह सरकार को यादगार सबक सिखाएं !!

अव्वल नंबर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और दुनिया की अवाम के सबसे बड़े दुश्मन जार्ज डब्ल्यू बुश ने इस साल मार्च महीने में भारत आने की योजना घोषित की है। दुनिया के इस सबसे बड़े बदमाश की हमारे देश की यात्रा का एकमात्र मकसद हमारे देश पर अमेरिकी महाशक्ति की पकड़ और कसना ही है। बुश के दौरे का तुरंत का उद्देश्य इरान, सीरिया, उत्तर कोरिया और दीगर देशों द्वारा भले ही सीमित हद तक, पर अमेरिका का विरोध करने की मुद्रा के कारण उन देशों को अकेला गिराने के लिए भारत के दलाल शासकों को बाध्य करना है। साथ ही, इराक और अफगानिस्तान में उसके द्वारा खेली जा रही खून की होली और सारी दुनिया में युद्ध की विभीषिका फैलाने की नीति वाली उसकी करतूतों के लिए समर्थन हासिल करना है। भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी(माओवादी) की केंद्रीय कमेटी हमारे देश की जनता से इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोहबाज/गैंगबाज के प्रस्तावित दौरे का विरोध करने तथा उनकी पहुंच में मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल दुनिया के इस सबसे खतरनाक अपराधी के विरोध में करने को आगे आने का आव्हान करती है। हमारी ओर से हम इस दुनिया की जनता के हत्यारे को हमारी महान मातृभूमि पर अपने घृणास्पद कदम न रखने देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे।

11 सितंबर 2001 को विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन –अमेरिकी फौजी मुख्यालय– पर हुए हमलों का बहाना करते हुए अमेरिकी पेट्रोलियम सौदागरों के गिरोह और फौजी–उद्योग गिरोह के उकसावे से इस दरिंदे ने इस सदी के सबसे खूंरेज़ युद्ध अफगानिस्तान और इराक पर हमला करके शुरू किये हैं जहां यह आज तक खून के दरिये बहाता चला आ रहा है। इसने इरान, सीरिया, उत्तर कोरिया के अलावा दुनिया भर में कई दूसरे मुल्कों को हमले की धमकी दे रखी है। फलस्तीनी नागरिकों पर

इज़राइली जियोनिस्ट शासकों के उन सबसे खूंख्वार दहशतगर्द हमलों को, जिनमें औरतों , मासूम बच्चों और लाचार बड़े बूढ़ों तक को तथाकथित प्रतिशोधकारी हमलावर कार्रवाइयों में बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है,यह अव्वल नंबर का दहशतगर्द कसाई खुल कर समर्थन दे रहा है। इस सिरफिरे हत्यारे ने वेनेजुएला, बोलीविया, और लातीन अमेरिका के कई दूसरे देशों में अशांति और गड़बड़ियों को हवा दी है। आतंकवाद रोकने के नाम पर इसने दूसरे देशों में 'निशानों' पर हवाई हमले कर मासूम लोगों का बेरहमी से कत्ल–ए–आम किया है, जैसा कि अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कबाइली इलाके बाजूर के डामडोला गांव पर मिसाइलों से पिछली 13 जनवरी को किये गये हमले में 13 मासूम बेगुनाह लोगों की हत्या की घटना में किया है। यह सत्तामद में चूर पगलाया हाथी खुलेआम भारत जैसे देशों को धमकियां दे कर उनका भयदोहन (ब्लैकमेल) कर रहा है। जैसा भारत में इसके (अमेरिकी) राजदूत डेविड मलफोर्ड ने गत 27 जनवरी 2006 को धमकाते हुए बयान दिया कि ''भारत को इरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ऐटमी ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) में मतदान करना पड़ेगा ....वरना...!'' चीन के साथ संयुक्त रूप से सीरिया में पेट्रोलियम परियोजना में पूंजी लगाने की भारत की योजना छोड़ देने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा है।

'इस्लामी दहशतगर्दी' से लड़ने के नाम पर और सी आइ ए (CIA) द्वारा गढ़ी गयी झूठी कहानियों को आक्रामक रूप से प्रचारित करते हुए जनता को गुमराह करते, ठगते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद ने बुश के नेतृत्व में सारी दुनिया में मुस्लिम जनता पर घृणास्पद हमलों का सिलसिला चला रक्खा है। इस भूमंडलीय आतंकवादी ने नेपाल के क.पा.ने. (माओवादी), फिलिपाइन में क.पा.फि., भारत में भा.क. पा.(माओवादी) सरीखी कई माओवादी पार्टियों पर या तो पाबंदी लगा रखी है, या उन पर आतंकवादी होने की मनगढ़ंत तोहमत लगा कर इन देशों के प्रतिक्रियावादी राज्यों को वहां की क्रांतिकारी तथा जनवादी आंदोलनों पर फासिस्ट दमनचक्र चलाने के लिए भारी पैमाने पर मदद मुहय्या की है। बुश तथा अन्य साम्राज्यवादी सरगनों के नेतृत्व में छेड़े गये तथाकथित 'आतंकवाद के खिलाफ जंग' के पीछे का असली मकसद यही है। इस भयदोही/ब्लैकमेलर, बांहमरोडू, लालची लुटेरे, सिरे से मक्कार , झूठे, लोभी, दुनिया की जनता के सबसे बड़े दुश्मन को हमारी धरती पर पैर रखने देना भारत के सौ करोड़ से ज्यादा नागरिकों के लिए शर्मनाक बात होगी।

कांग्रेस की अगुआई वाले **संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन** सरकार (संप्रग),भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनवादी गठबंधन (राजग), तेलुगुदेशम पार्टी, एआइएडीएमके, इत्यादि नस–नस से दलाल एजेंट ही इस देश की जनता के हितों को अपनी इच्छा से / जानबूझ कर बेच रहे हैं और इस बड़े बदमाश के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। पिछली जुलाई की अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद को तब अमेरिकी साम्राज्यवादियों का विश्वस्त एजेंट साबित किया जब उसने वाशिंग्टन में अपने आकाओं को आश्वस्त किया कि ईरान से भारत प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाने की भारत–ईरान परियोजना को भारत आगे नहीं बढ़ायेगा। तथाकथित भारत–अमेरिका परमाणु संधि की पेशकश के जरिये अमेरिका ने भारत पर अपना शिकंजा कस लिया, जिस के तहत इस शर्त पर अमेरिका दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नॉलॉजी के व्यापार पर से पाबंदी हटा लेगा कि भारत भी अपने नागरिक और सामरिक / फौजी परमाणु संस्थानों को अलग करे। इस समझौते की अभी तक अमेरिकी संसद / कांग्रेस ने अभिपुष्टि नहीं की है और इस बात का इस्तेमाल भारत को ईरान पर अमेरिकी रुख का समर्थन करने पर मजबूर करने के लिए किया जा रहा है। **यह सीधे–सीधे बांह मरोड़ने का मामला है।** 'नागरी परमाणु संधि' में मनमोहन सिंह द्वारा मान ली गयी शर्तों को अब तक बड़ी सावधानी के साथ गुप्त रक्खा गया है, जिस में, कहा जाता है कि आइ ए ई ए द्वारा निरीक्षण/इन्सपेक्शन की शर्त भी मान ली गयी है। यह भारत की स्वतंत्रचेता जनता का सरासर अपमान है। भारत की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने पिछले 24 सितंबर को ही आइ ए ई ए में अमेरिकी साम्राज्यवादी हुक्मरानों के आदेशों के अनुरूप बहुत ही अपमानजनक ढंग से ईरान के खिलाफ मतदान भी किया। वाशिंग्टन से कुछ टुकड़ों की आस में 2 फरवरी 2006 को होने जा रही आइ ए ई ए की बैठक में इसी बेइज्जतीभरे कदम को यह सरकार फिर से दोहराने को तैयार खड़ी है और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सामने धकेल दिया जायेगा, जो दुनिया में असुरक्षा पैदा करने में खुद सबसे बड़ी वजह के तौर पर पहचान बना चुका है। सत्तासीन इन देशद्रोहियों की इन करतूतों का स्वतंत्रताप्रेमी भारत की जनता द्वारा पुरजोर विरोध होना बेहद जरूरी है।

आइए,हम इराक, अफगानिस्तान और फलस्तीनी इलाकों के जांबाज योद्धाओं को अटल समर्थन देने की प्रतीज्ञा करें, जो अमेरिकी हमलावर हत्यारों से रातदिन लोहा ले

रहे हैं। ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, बोलीविया तथा अमेरिकी साम्राज्यवादी हमलावरों के खतरे से जूझते सभी देशों की जनता को हमारा समर्थन दें। बाजूर में अमेरिकी हवाई हमलों की मुखालिफत कर रही पाकिस्तानी अवाम को भी हम हमारा बेहिचक समर्थन जाहिर करें। चलिए, दुनिया के अव्वल नंबर अपराधी बुश की अगुआई में अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा छेड़े गये हमलावर युद्धों का विरोध करने में हम समूची दुनिया की जनता के साथ एकजुट हो जाएं। साम्राज्यवादियों द्वारा दूसरे देशों की सीमित सी संप्रभुता तक पर किये जा रहे दखलंदाजी, धौंस, दादागिरी, विनाशकारी कार्रवाइयों का मुकाबला करने में हम तमाम दुनिया की जनता से जा मिलें।

बुश का भारत दौरा हमारे देश पर धौंसपट्टी जमाने, बांह मरोड़ने की कार्रवाई के उद्देश्य से हो रहा है। साथ ही देशद्रोही संप्रग सरकार के साथ जघन्य समझौते करने के लिए भी यह बदमाशों का सरदार भारत आ रहा है। इस भयदोही/ब्लैकमेलर गिरोहबाज के पैरों पर बेशर्मी के साथ भारत की जनता के हितों की बलि चढ़ाने के लिए भरत की मौजूदा संप्रग सरकार हर पल तैयार खड़ी है। इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोहबाज, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के हमारे देश के प्रस्तावित दौरे का विरोध करने के लिए अपने देश के तमाम जनवादी और क्रांतिकारी शक्तियों को एकताबद्ध करें। दुनिया के सबसे बड़े खून के प्यासे साम्राज्यवादी देश के प्रमुख और हमारे देश पर राज कर रहे उसके छुपे दलालों / एजेंटों को विराट रैलियों, रास्ता रोको, पुतला दहन,तथा सभी संभव विरोध के रूपों एवं तरीकों को अपनाते हुए समुचित सबक सिखने के लिए आगे आयें, अगर दरिंदों का यह सरगना भारत की जनता के विशाल बहुमत की इच्छा के खिलाफ हमारे देश के दौरे पर आने की हिम्मत करे!

हमारी पार्टी के लिए यह सचमुच बड़े ही गर्व की बात है कि दुनिया की जनता का दुश्मन नंबर एक, अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने हमारी पार्टी का नाम 'काली सूची' में दर्ज किया है। यह बात खुद ही साबित कर देता है कि इन गिरोहबाजों के हितों के लिए हमारी पार्टी किस कदर गंभीर खतरा बन कर उभरी है। साथ ही यह हमारी पार्टी के कंधों पर दुनिया की जनता का खून पी रहे इस दैत्य के खिलाफ अपने देश की जनता के संघर्षों का नेतृत्व करने की चुनौती भरी जिम्मेदारी भी सौंपता है। हम भारत और संपूर्ण विश्व की उत्पीड़ित जनता के कंधों से कंधे मिला कर अमेरिकी साम्राज्यवादी दैत्य से संघर्ष में अपनी भूमिका निभायेंगे, यह दैत्य उसके हथियारखानों में मौजूद

खतरनाक से खतरनाक व्यापक जनसंहार के तमाम भारीभरकम हथियारों से लैस होने के बावजूद आखिर एक 'मिट्टी के पैरों वाला महादैत्य' भर है। सभी प्रतिक्रियावादी शक्तियों की ही तरह जनता की ताकत से मुकाबिल होने पर आखिर वह भी महज **एक कागजी बाघ** है।

आज़ाद, प्रवक्ता,
केंद्रीय कमेटी (अस्थायी),
भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

22-5-2006

भारत के उत्पीड़ित जातियों का अधिकार है आरक्षण ! ऊंची जातियों के हिंदू अंधाहंकारवादी शक्तियों के आरक्षण विरोधी भावनाएं भड़काने के षड़यंत्रों से सावधान!!

पिछड़ी जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा ने एक बार फिर से ऊंची जातियों के छात्रों में आरक्षण विरोधी आंदोलन का सूत्रपात किया है.एक सप्ताह से कुछ ज्यादा अरसे से हिंदू कठमुल्लावादी शक्तियां और ब्राह्मणवादी ऊंची जातियों की शक्तियां प्रशासन की मिलीभगत से इन विरोध प्रदर्शनों को हवा देते आ रही हैं.विभिन्न संसदीय पार्टियां भी अपने विरोधियों से बाजी मारने के प्रयास में इन विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल कर रही हैं.दिल्ली और मुंबई में पुलिस द्वारा आंदोलनकारी छात्रों पर आंदोलन के पहले ही दिन किये गये नृशंस लाठीचार्ज की घटनाओं ने छात्र समुदाय में रोष ही का संचार किया है और इस तरह छात्रों में से एक लक्षणीय हिस्से को आंदोलन में ला खड़ा किया है.

पुलिस लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हुए ही **भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी)** की केंद्रीय कमेटी छात्रों को तथा आम जनता को रा स्व से सं, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल के नेतृत्व में तथा कांग्रेस और दीगर पार्टियों के भीतर ब्राह्मणवादी ऊंची जातियों की शक्तियों और हिंदू कठमुल्लावादी शक्तियों द्वारा आरक्षण का मुद्दा भड़का कर छात्र बिरादरी को बांटने की धूर्त राक्षसी योजनाओं को पहचानने को आगाह करती है. यह हमारे देश के उन सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षिण दिये जाने का पुरजोर समर्थन करती है, जिन्हें सदियों से समाज में उनके न्यायपूर्ण हिस्से से वंचित रखा गया.

हमेशा की तरह आरक्षण विरोधी पंडित अपने ठेठ अभिजातवादी तर्कों की बासी खिचड़ी परोस रहे हैं; मसलन : अगर अनुसूचित जातियों(एस.सी)जन जातियों(एस.टी), तथा अन्य पिछड़ी जातियों(ओबीसी)वर्गों को आरक्षण देना जारी रहा तो व्यावसायिक स्तर

और गुणवत्ता में गिरावट आयेगी; मेधावी(मेरिट)छात्रों को अवसरों से वंचित होना पड़ेगाा इत्यादि;इत्यादि. वे इस नग्न सत्य से साफ कन्नी काट जाते हैं और इन तथ्यों को धुंधला कर देने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह मनु के समय से ही घिनौनी जाति व्यवस्था ने तथा जाति आधारित उत्पीड़न ने भारत की जनता को विभाजित कर रखा है. वे उलटे बहस करते हैं कि आक्षण की नीति ही की वजह से समाज विभाजित हो रहा है. आरक्षण विरोध ाी ये महानुभाव उत्पीड़ितों के प्रति मौखिक सहानुभूति दिखलाने में बड़े ''उदार'' बनते हैं, जब वे कहते हैं कि इन पिछड़ों को आर्थिक समर्थन दिया जा सकता है– पर साथ ही यह कहना नहीं भूलते कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में उन्हें किसी भी कीमत पर आरक्षण न दिया जाय! ऐसा असल में इसलिए है, क्योंकि इन संस्थानों पर तो हमेशा से ही ऊंची जातियों के ब्राह्मणवादियों का, पश्चिम की ओर उड़ जाने को बेताब अभिजात वर्गों का वर्चस्व रहता आया है और आगे भी बना रहेगा. टाटा, बिड़ला, अंबानियों, नारायण मूर्तियों जैसे हजारों करोड़ रुपयों के मालिक औद्योगिक और व्यपारिक धन्नासेठ भी – यानी, दलाल दफ्तरशाह पूंजीपति –ाी ҍ भी जनता के इन पिछड़े हिस्सों को आरक्षण देने के विरोध के इस रथ पर आ सवार हुए हैं और कह रहे हैं कि यह आरक्षण भारत जो ''प्रगति'' कर रहा है, उस पर शिकंजा बन जायेगा. मेरिट का यह लोकतांत्रिक सा लगने वाला तर्क वैसा ही है जैसे विश्व बैंक, आइएमएफ, डब्ल्यूटीओ और दीगर साम्राज्यवादी ताकतें सभी देशों के लिए एक ही ध ारातल वाला (समतल) खेल का मैदान रखने के तर्क दे रहे हैं.

केंद्र में कांग्रेस (इ) की अगुआई वाली सरकार ने लगभग दो महीने पहले केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि में विधानसभा चुनावों को नज़र में रखते हुए आरक्षण संबन्ध ाी नीति वक्तव्य घोषित किया, जिसको अब दो महीने से जयादा समय हो गया है, पर मंत्रिमंडल ने आज तक इस नीति पर तत्काल अमल का फैसला नहीं किया है. अब वह ओबीसी के आरक्षण से होने वाले 'नुकसान' के एवज में उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के द्वारा उच्च जाति के तबकों की मिजाजपुर्सी करने की कोशिश में है.कोई भी बुर्जुआ संसदीय पार्टी आरक्षण का विरोध करने आज की तारीख तक खुल कर सामने नहीं आयी है, पर कई चोरीछिपे आरक्षण विरोधी आंदोलन की मदद कर रहे हैं, खास कर, मेडिकल छात्रों के आंदोलन को हवा देते हुए अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं. एआइआइएमएस का निदेशक निवासी डॉक्टरों को आरक्षण के खिलाफ हड़ताल करने को खुल कर प्रोत्साहन दे रहा है.

भारत में जाति व्यवस्था एक वास्तविकता है और जाति उत्पीड़न एक क्रूर सच्चाई है. सामाजिक शोषण–उत्पीड़न के वर्तमान परिदृष्य में और नग्न विषमता के बीच शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की मांग सर्वथा उचित और समर्थनीय जनवादी मांग है. बहुत ही नगण्य संख्या में केन्द्रीय और राज्य सरकारी विभागों में आरक्षण के बूते रोजगार पाये मुट्ठीभर अनुसूचित जातियों–जनजातियों के उम्मीदवारों पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण का कितना लाभ उन्हें सचमुच मिला. अतः सभी तबकों की जनता के लिए यह फर्ज बन जाता है कि वे आरक्षण के न्यायपूर्ण और जनवादी मांग का समर्थन करें.

उच्च जाति के अभिजात लोगों ने अपने धन–बल और राजनीतिक प्रभाव के बल पर इन उच्चभ्रू कुलीनवादी संस्थानों में जगह कब्जायी है तथा 'मेरिट' का स्थान दोयम ही है. उच्च–जाति के ब्राह्मणवादी आस्थापना/व्यवस्था में गहरी जड़ें जमाये इन उच्च शिक्षा संस्थानों में जगह न दिये जाने और नौकरियां न दिये जाने के कितने ही मेधावी उम्मीदवारों के किस्सों से इनका इतिहास भरा पड़ा है. इन उच्च शिक्षा संसथानों में आरक्षण लंबे अरसे से विलंबित/बकाया है जिसके बिना ये हमेशा ही कुलीनवादी संस्थान ही बने रहेंगे, जो दलाल दफ्तरशाह बुर्जुआ और साम्राज्यवाद की सेवा में रत रहने वाले उच्चभ्रू अभिजात संस्थान ही बने रहेंगे.

बुर्जुआ संसदीय पार्टियां आरक्षण नीति के खिलाफ खुल कर नहीं आती हैं, पर सब के सब आरक्षण विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहित करती हैं.शासकवर्ग हमेशा आरक्षण विरोधी–अल्पसंख्यक विरोधी भवनाएं भड़का कर जनता को बांटे रखना चाहती है.

लेकिन, यह याद रखना होगा कि सिर्फ आरक्षण अकेले भारत के उत्पीड़ित जातियों की बुनियादी समस्याओं को कभी सुलझा नहीं सकता है. समस्या का समाधान तो जमीन के फिर से बंटवारे में, धनसंपदा तथा दूसरी संपत्तियों के गरीबों, उत्पीड़ितों के पक्ष में पुनर्वितरण में निहित है, जिनका बहुसंख्य हिस्सा उत्पीड़ित जातियों का है; और भी अहम बात यह हैकि वे मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सभी जातियों की उत्पीड़ित जनता के कंधे से कंधा मिला कर राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल कर सकें.

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी विद्यार्थी समुदाय से अपील करती है कि वह पिछड़ी जातियों को दिये जाने वाले आरक्षण का विरोधा करने के द्वारा शासक वर्गों के विभाजनकारी दांवपेंचों के शिकार न बने. हम उन से अपने

देश की सामाजिक – आर्थिक असमानता और पिछड़ी जातियों की दयनीय घोर स्थितियों और सच्चाइयों पर गौर करने और 'मेरिट' की भ्रांत तर्कों/धारणाओं के जाल का शिकार न होने की अपील करते हैं.

हम तमाम लोकतांत्रिक तथा प्रगतिशील ताकतों से भी शासक वर्गों की नीतियों को बेनकाब रिने की अपील करते हैं जो जनता को टुकड़ों में बांटने के लिए आरक्षण विरोधी भावनाओं को हवा दे रहीं हैं.

- उच्च शिक्षा के केन्द्र हमेशा हमेशा के लिए उच्चजाति के अभिजात वर्ग की बपौती नहीं रह सकते!
- आरक्षण सिर्फ एक सुधार भर है, जमीन, संपत्ति तथा दूसरे माल–असबाबों का वितरण तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित अधिकारपूर्ण भागीदारी डत्पीड़ितों की समस्याओं को हल करने की पूर्वशर्त है!
- मेरिट तो मिथक है, मेधा की संकल्पना भ्रामक है ! यह पैसा और राजनीतिक 'पहुंच' और लग्गा ही है जो उच्च शिक्षा संस्थानों के दरवाजे उच्च जाति के छात्रों के लिए खोल देती है. सारी संपत्ति का फिर से बंटवारा करो! और तब आरक्षण समाप्त करो !

आज़ाद,
प्रवक्ता,
केंद्रीय कमेटी (अस्थायी),
भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन

29-6-2006

“ऑपरेशन चक्रवात” के तहत झूमरा पुलिस कैम्प पर पीएलजीए द्वारा किया गया हमला देहाती क्षेत्रों से शोषक-शासक वर्ग की शोषणमूलक सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा मेहनतकश जनता की शोषणमुक्त सत्ता व सरकार
कायम करने हेतु की गई कार्रवाई है

झूमरा स्कूल से पुलिस कैम्प को उखाड़ फेंकने हेतु की गई “ऑपरेशन चक्रवात” की कार्रवाई में भाग लेनेवाले पीएलजीए के वीर योद्धाओं को केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन क्रान्तिकारी लाल अभिनन्दन पेश करता है।

दोस्तो, जग जाहिर है कि सी.पी.आई (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रान्तिकारी संघर्ष आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां देहाती क्षेत्रों से शोषक-शासक वर्ग की शोषणमूलक सत्ता को उखाड़ फेंक कर मेहनतकश अवाम की क्रान्तिकारी जन कमिटी की सत्ता व सरकार कायम करने की ओर अग्रसर है। इससे शोषक-शासक वर्ग आतंकित एवं भयभीत है। तभी तो वह इस क्रान्तिकारी संघर्ष को देश की आन्तरिक मामले में सबसे बड़ा खतरा के रूप में चिन्हित करते हुए सी.पी.आई. (माओवादी) को आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर दमनात्मक अभियान को तेज कर इसे कुचल डालने हेतु देहाती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पुलिस व अर्ध सैनिक बलों का कैम्प देहाती क्षेत्रों के स्कूलों में डाल रखा है।

वास्तविकता यह है कि देहाती क्षेत्रों में शोषक-शासक वर्ग की सत्ता और मेहनतकश जनता की सत्ता के बीच कड़ा संघर्ष जारी है तथा एक-दूसरे को उखाड़ फेंकने हेतु प्रयासरत है। लेकिन शोषक-शासक वर्ग इस सच्चाई को छुपाने का प्रयास करता है तथा इस सच्चाई से जनता को दिगभ्रमित करने के लिए क्रान्तिकारी संघर्ष

पर उग्रवाद–आतंकवाद का लेबल लगाकर इसके खिलाफ षड्यंत्रात्मक ढंग से दुष्प्रचार चला रहा है। झूमरा पहाड़ के प्राथमिक विद्यालय पर स्थित अर्ध सैनिक बलों के कैम्प को उखाड़ फेंकने हेतु पी.एल.जी.ए. द्वारा किया गया हमले की सच्चाई से जनता को दिगभ्रमित करने हेतु शोषक–शासक वर्ग के भाड़े के टट्टू द्वारा यह कहकर दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया और दिनांक 27–06–06 के कई अखबारों ने भी इसी को समाचार का शीर्षक बनाकर यह प्रचार किया है कि "उग्रवादियों (उनकी भाषा में) ने हमले के दौरान यह पेशकस की थी कि 90 करोड़ रूपया ले लो और झूमरा पहाड़ को खाली कर दो" यह सरासर सफेद झूठ है। सच्चाई यही है कि हमले के दौरान पी.एल.जी.ए. ने यह एलान कर रहा था कि "हम 90 करोड़ मेहनतकश जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं और तुम मुठीभर शोषक–शासक वर्ग के हित की रक्षा के लिए लड़ने वाले भाड़े के टट्टू व पालतू कुत्ते हो जो जनता के ऊपर जुल्म ढाने के लिए गरीब बच्चों के स्कूलों में कैम्प डाल रखे हो और उन्हें पढ़ाई–लिखाई से वंचित कर रखे हो, स्कूल को अविलम्ब खाली कर दो नहीं तो हम तुम्हें ध्वस्त कर देंगे।" इस सच्चाई को रखने की उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि इस सच्चाई को रखने से उनके जनविरोधी प्रतिक्रयावादी क्रिया–कलाप का भंडाफोड़ हो जायेगा। इसी के डर से तथा पी.एल.जी.ए. को कमजोर एवं उग्रवादी–आतंकवादी के रूप में दर्शाने के मकसद से कि पीएलजीए संघर्ष के जरिए पुलिस कैम्प को नहीं हटा पाने के कारण रुपया देकर हटाने की पेशकस कर रही है। अगर रुपया देकर पुलिस कैम्प को हटाने का ही होता तो इतनी भारी संख्या में पी.एल.जी.ए. के जवान हथियारों से लैस होकर पुलिस कैम्प पर हमला करने का औचित्य क्या था। पी.एल.जी.ए. न कभी रुपया देकर दुश्मन से समझौता की है और न कभी करेगी। यह पी.एल.जी.ए. का उसूल नहीं है। यह उसूल शोषक–शासक वर्ग और उनके भाड़े के टट्टू का है जो पी.एल.जी.ए. पर थोपना चाहता है।

दिन–प्रतिदिन वर्ग संघर्ष के आईने में शोषक–शासक वर्ग और उसके राष्ट्रयंत्र का चरित्र साफ नजर आने लगा है कि वह किसके हित में कार्यरत है। फासिस्ट भाजपानीत मुण्डा की सरकार व भाड़े का टट्टू किस जनता के हित में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मेहनतकश बच्चों के स्कूलों में पुलिस कैम्प डाल रखा है और कौन सा ऐसा जनहित का कार्य हो रहा है वास्तव में उनके व्यावहारिक क्रिया–कलाप ही उसकी कसौटी है।

दरअसल, उग्रवाद–आतंकवाद दमन के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कैम्प

डालकर भाड़े के टट्टू के जो कार्य हैं, वे हैं- ग्रामीण क्षेत्रों में रोज दिन छापामारी अभियान के तहत क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी जनता, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करने, फर्जी मुठभेड़ में गोली मार कर हत्या करने, कुर्की-जब्ती के नाम पर जनता के घरों की सम्पत्ति को लूटने, तहस-नहस करने व घर-मकान को ढाहने जैसा बर्बर पुलिसिया जुल्म व दमन-अत्याचार चलाना आदि। क्या यह जनता के हित में किया गया कार्य है? नहीं, कतई नहीं। जनता का रक्षक कहलाने वाली पुलिस एवं अध सैनिक बल के क्रिया-कलाप से यह दिन के उजाला जैसा साफ है कि वह जनता का रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक है। वह जनता के सेवक नहीं, बल्कि मुट्ठीभर शोषक-शासक वर्ग के सेवक, वफादार कुत्ता व भाड़े का टट्टू है तभी तो वह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों के स्कूलों को पुलिस कैम्प में बदल डाला है और बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से वंचित कर रखा है। सचमुच में अगर जनता के प्रति तनिक भी हमदर्दी होती और इज्जत-अधिकार बोध होता तो जनता के अधिकार पर हस्ताक्षेप नहीं करता अर्थात बच्चों के स्कूलों में डेरा डाल कर बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से वंचित करने के इस तरह के जन विरोधी क्रिया-कलापों से बाज आते। क्या यह कार्य वास्तव में जनता के हित के लिए है या जनता के हित के विरूद्ध है? देहाती इलाकों में पुलिस कैम्प डाल कर वह जनता के हित में कौन सा कार्य की है? जनता की मार-पीट, गाली-गलौज, माँ-बहनों, बहु-बेटियों की बेइज्जती-बलात्कार करना, फर्जी मुठभेड़ में गोली मार कर हत्याएं करना आदि क्या जनता के हित में किया गया कार्य है या बर्बर जुल्म व दमन-अत्याचार की कर्रवाई है?

आज ज्यों-ज्यों क्रान्तिकारी वर्ग संघर्ष तेज होते जा रहा है त्यों-त्यों शोषक-शासक वर्ग के शासन तन्त्र का असली चेहरा साफ होते जा रहा है कि वास्तव में पुलिस-प्रशासन किसके हित के रक्षक व सेवक है। आज जब मेहनतकश जनता शोषक-शासक वर्ग के शोषण व जुल्म के खिलाफ तथा सही इज्जत-आजादी व अधिकार हेतु हाथ में हथियार उठाकर क्रान्तिकारी आन्दोलन में कूद पड़ी है और जल, जमीन और जंगल पर अपना अधिकार कायम कर रही है तो उन्हें उग्रवादी-आतंकवादी करार देकर उनके ऊपर बर्बर पुलिसिया जुल्म व दमन-अत्याचार चलाया जा रहा है। यही वास्तविकता है।

अतएव वास्तव में जनता के हितैषी है कौन और उग्रवादी-आतंकवादी है कौन? भले ही शोषक-शासक वर्ग और उसके जूठन चाटने वाले मुठीभर प्रतिक्रियावादी और बुरे शरीफजादों के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी मेहनतकश अवाम

उग्रवादी-आतंकवादी नजर आये, लेकिन वास्तव में वे 90 प्रतिशत मेहनतकश जनता की नजरों में उनके हितैषी है। वास्तव में मेहनतकश अवाम के लिए उग्रवादी-आतंकवादी तो वो है जो उनके ऊपर सदियों से शोषण-जुल्म और दमन-अत्याचार जारी रखा है और आज भी जब वे उनके शोषण-जुल्म और दमन-अत्याचार के खिलाफ तथा अपने सही इज्जत -आजादी और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उलटे उनका ही उग्रवादी-आतंकवादी करार देकर दमन किया जा रहा है।

अतः यह स्पष्ट है कि सी.पी.आई. (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रान्तिकारी वर्ग संघर्ष को उग्रवादी-आतंकवादी करार देकर कुचल डालने के बुरे मनसुबे से देहाती क्षेत्रों के स्कूलों में जो पुलिस व अर्ध सैनिक बलों का कैम्प डाल रखा है वह जनविरोधी व प्रतिक्रियावादी क्रिया-कलाप छोड़कर और कुछ भी नहीं। शोषक-शासक वर्ग के इस दमन मुहिम के खिलाफ जवाबी कार्यनीतिक आक्रमणात्मक अभियान का एक हिस्सा है "ऑपरेशन चक्रवात" के तहत झूमरा स्कूल के पुलिस कैम्प पर की गई जबरदस्त सैनिक कार्रवाई। "ऑपरेशन चक्रवात" शोषक-शासक वर्गों की शोषण सत्ता को उखाड़ फेंककर क्रांतिकारी जन कमिटी की सत्ता व सरकार कायम करने हेतु तथा स्कूलों से पुलिस कैम्प को उखाड़ फेंककर बच्चों की पढ़ाई को बहाल करने की कर्रवाई की यह शुरूआत तथा पहला कदम है। भले ही कुछ सैनिक तकनीक की कमी के कारण ऑपरेशन चक्रवात की यह पहली कार्रवाई पूर्णतः सफल नहीं हो सकी है अपितु यह कार्रवाई पी.एल.जी.ए. के जवान आगे जारी रखेगा और इसे सफल करके ही दम लेगा। न केवल झूमरा के पुलिस कैम्प को बल्कि झारखण्ड सहित अन्य प्रांतों के देहाती क्षेत्रों से पुलिस कैम्प को उखाड़ फेंककर क्रान्तिकारी जन कमिटी की सत्ता व सरकार कायम करने का ऑपरेशन चक्रवात का अभियान जारी रहेगा।

अतः केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन पी.एल.जी.ए. के तमाम फारमेशनों सहित क्रान्तिकारी लड़ाकू जनता से आह्वान करता है कि क्रान्तिकारी संघर्ष को कुचल डालने हेतु शोषक-शासक वर्ग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पुलिस कैम्प डालकर क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं, समर्थक जनता तथा मेहनतकश अवामों के ऊपर बर्बर पुलिसिया जुल्म व दमन अभियान के खिलाफ पी.एल.जी.ए. की ओर से जो जवाबी कार्यनीतिक आक्रमणात्मक अभियान के बतौर "ऑपरेशन चक्रवात" की शुरुआत झूमरा के पहाड़ पर स्थित स्कूलों में किया गया पुलिस कैम्प पर जबरदस्त हमले

की कार्रवाई से की गई है उसे बुलन्द रखें तथा शोषक–शासक वर्ग की शोषण सत्ता को ग्रामीण क्षेत्रों से उखाड़ फेंककर क्रान्तिकारी जन कमिटी की सत्ता व सरकार कायम करने हेतु ऑपरेशन चक्रवात की धारावाहिकता को तब तक जारी रखें जब तक ग्रामीण क्षेत्रों से पुलिस कैम्प को उखाड़ फेंककर ग्रामीण क्षेत्र मुक्त न हो जाय तथा क्रान्तिकारी जन कमिटी की सत्ता व सरकार कायम न हो जाय।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ

समरजीत

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

1-12-2006

केन्द्र सरकार की साम्राज्यवाद–निर्देशित औद्योगिक तथा कृषि नीतियों
के खिलाफ मजदूर वर्ग की 14 दिसम्बर की हड़ताल का समर्थन करें !

आगामी 14 दिसम्बर को अनेक आखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों ने केन्द्र सरकार की साम्राज्यवाद–निर्देशित जन–विरोधी औद्योगिक नीति के साथ ही कृषि नीति के विरुद्ध आखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया है। यह एक विडम्बना ही है कि इन ट्रेड यूनियनों का राजनीतिक नेतृत्व खुद इन्हीं नीतियों के मुख्य रचयिताओं में शामिल हैं और वे मजदूरों के संघर्षों के साथ विश्वासघात कर औद्योगिक मैनेजमेण्ट (प्रबन्धकों) को लाभ पहुँचाने के लिए कुख्यात हैं।

संप्रग सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति पिछले डेढ़ दशक से हमारे देश के दलाल शासकों द्वारा खोले जा रहे उदारीकरण–निजीकरण–वैश्विकरण की साम्राज्यवादियों की नीतियों के पिटारे में से निकली है। सरकार चाहे काँग्रेस की हो या भाजपा की, उसको भाकपा–माकपा का समर्थन चाहे रहा हो या न रहा हो, इन्हीं नीतियों ने मजदूर वर्ग और तमाम किसानों की जिन्दगी में तबाही मचायी है। पिछले डेढ़ दशक से हजारों–लाखों मजदूरों की छटनी हो चुकी है। यह लॉक–आउट, उद्योगों का ठप हो जाना, ''गोल्डन हैण्डशेक'' से छुट्टी कराना, पूँजीपतियों के पक्ष में श्रम कानून तथा मैनेजमेण्ट के पक्ष में अदालतें, छोटे–छोटे उद्योगों की हजारों में बन्दी आदि का परिणाम है। बेरोजगारों तथा अर्द्ध–रोजगार वालों के लिए अच्छी नौकरी की व्यवस्था करना

तो दूर, दो जून की रोटी की व्यवस्था होने की आशा भी नहीं दिखायी दे रही है।

साथ ही मध्य भारत आज खनिज पदार्थों के दोहन और इस्पात आदि के बड़े–बड़े संयन्त्राों की स्थापना के लिए आमादा अन्तरराष्ट्रीय तथा दलाल पूँजीपतियों की चपेट में है। इससे आदिवासी लोगों की विशाल आबादी के साथ ही कुछ गैर–आदिवासियों पर भी अपने जल–जंगल–जमीन और सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश से उजाड़े जाने का खतरा आन पड़ा है। देश–विदेश के थैलीशाहों ने देश की जनता की धरोहर यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पाधावा बोल दिया है।

इसी बीच समूचे देहाती अंचल में हजारों की तादाद में किसान खुदकुशी का रास्ता चुनने को मजबूर किये जा रहे हैं। चाहे विकसित पंजाब हो या पिछड़ा बुन्देलखण्ड या फिर विदर्भ और तेलंगाना की हृदयस्थली, नगदी फसल लेने वाले काश्तकारों पर टूट पड़ा यह अद्वितीय पहाड़ सरकार की निर्यातोन्मुख कृषि नीति का असली रूप दिखा रहा है। जमीन जोतनेवाले अभी कृषि भूमि के बढ़ते कॉर्पोरेटीकरण के झटके से उबरे भी नहीं थे कि साम–दाम–दण्ड–भेद से जमीन हासिल कर ऐसे ''विशेष आर्थिक जोन'' बनाने के प्रयास तेज हुए हैं, जहाँ देश के कानून तक लागू नहीं होंगे। बाढ़, सूखा, अकाल और असिंचित खेती से बेहाल किसान अब महँगी होती लागत और अपनी उपज के ठहरे हुए दामों के चलते कृषि के जानलेवा संकट में जकड़ा है। सामन्तवाद को उखाड़ फेंकने के लिए भूमि सुधार लागू करना तो दूर, ''आधुनिक'' भारत के सत्ताधारी आजकल बड़े भूस्वामियों तथा उद्योगपतियों की सेवा में देश के सीलिंग कानून संशोधित करने में लगे हैं।

14 दिसम्बर की आखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल का आह्वान भाकपा–माकपा की दोगली भूमिका का अंग है। एक ओर उन्हें साम्राज्यवादियों तथा दलालों की सेवा करते हुए उनके राज्य के अधीन समर्पित प्रबन्धक की भूमिका अदा करनी होती है। तो दूसरी ओर मजदूरों के सुलगते असन्तोष को देखते हुए प्रतीकात्मक आह्वान भी करने पड़ते हैं। हम ट्रेड यूनियनों के आम

सदस्यों के दबाव के कारण उठ रही मांगों का समर्थन करने के साथ–साथ इन ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व कर रहे भाकपा–माकपा के नकली कम्युनिस्टों का विरोध करते हैं।

अन्त में इस देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल के अवसर पर हम मजदूरों तथा किसानों से अपील करना चाहते हैं कि वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में देश के कई हिस्सों में चल रही सशस्त्रा कृषि क्रान्ति के आन्दोलन के साथ अपना रिश्ता कायम करें। सशस्त्रा ताकत के बल पर सामन्तवाद और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंककर ही हम न्यायपूर्ण, आजाद और स्वावलम्बी भारत का निर्माण कर सकते हैं और खेतों–कारखानों में श्रम कर रहे करोड़ों–करोड़ लोगों के दुःखों का अन्त होगा।

आजाद

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमिटी (अस्थायी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

25-12-2006

कलिंगनगर (उड़ीसा) से सिंगूर (पश्चिम बंगाल) तक केन्द्र-राज्य सरकारों द्वारा जारी आदिवासियों की बेदखली की नीतियों का विरोध करो !

साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं बड़े दलाल पूंजीपतियों के हित में हो रही देश की प्राकृतिक संपदाओं की खुली लूट की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलन्द करो !

वर्ष 2006 के दूसरे ही दिन, यानी 2 जनवरी 2006 को उड़ीसा सरकार ने कलिंगनगर में 13 आदिवासियों को, जो टाटा कम्पनी के विस्तार के लिए अपनी जमीनें देने से इनकार कर रहे थे, गोलियों से भूनकर नए साल का जश्न मनाया था. इसी साल के आखिरी महीने के दूसरे दिन, यानी 2 दिसम्बर 2006 को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा को अपनी जमीनें देने से इनकार करने वाले किसानों पर तथाकथित वामपंथी सरकार ने गोलियां बरसाईं. पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश - लगभग हर राज्य से जल-जंगल-जमीन से आदिवासियों की बेदखली और पुलिस फायरिंग की खबरें आए दिन आ रही हैं. सरकारों की जिन नीतियों के चलते आदिवासियों को हत्याकाण्ड, विस्थापन, बलात्कार, अपमान आदि भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है, उन आदिवासी-विरोधी एवं किसान-मजदूर विरोधी नीतियों में साल-दर-साल और इजाफा हो रहा है.

छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड में टाटा, एस्सार, जिन्दल, मित्तल, टेक्सास पावर जेनरेशन (टीपीजी), पोस्को आदि बड़े पूंजीपतियों की कम्पनियां एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तेजी से पांव पसार रही हैं. हजारों आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल करने के प्रयास जोरों पर जारी हैं. इन राज्यों की सरकारों ने इन कम्पनियों के साथ लाखों करोड़ों के पूंजीनिवेश के एमओयू पर दस्तखत करके देश की अकूत सम्पदाओं की लूट के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं. इन कम्पनियों के लिए आदिवासियों एवं उत्पीड़ित जनता की

लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए न केवल जोर-जबर्दस्ती पर उतारू है, बल्कि उन्हें अपने जल, जंगल एवं जमीन से बेदखल करने के लिए हर तरह के हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं. जबसे टाटा, एस्सार, जिन्दल, मित्तल आदि कम्पनियों की घुसपैठ शुरू हुई तभी से 'नक्सलवादियों के सफाए' के इरादे से एक सुनियोजित साजिश रचकर बस्तर में 'सलवा जुडूम', झारखण्ड में 'सेन्देरा', उड़ीसा में 'जन जागरण अभियान' एवं महाराष्ट्र में 'गांवबन्दी' आदि नामों से फासीवादी सैनिक जुल्मी अभियान चलाए जा रहे हैं. इन अभियानों के तहत 'सब कुछ लूटो, सब कुछ ध्वस्त करो, सबको मार डालो' की नीति अपनाकर सैकड़ों आदिवासियों को मौत के घाट उतारे जा रहे हैं. दरअसल इन बड़ी कम्पनियों की लूट की राह में बहुत बड़ी बाधा के रूप में इन राज्यों के आदिवासी अंचलों में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलना ही इन अभियानों का मकसद है.

'आजाद' भारत के इतिहास में बड़ी परियोजनाओं, रक्षित वनों एवं नेशनल पार्कों के नाम से1950 से 1990 तक 85 लाख से ज्यादा आदिवासियों को जंगलों से भगाया जा चुका है. अब तक विस्थापित लोगों में 55.16 प्रतिशत आदिवासी ही हैं, जबकि देश की आबादी में इनका प्रतिशत सिर्फ 8.1 है. इस तरह विस्थापित लाखों लोग रिक्षा चालक, कुली, बेरोजगार बन गए हैं. बड़ी संख्या में विस्थापित आदिवासी महिलाएं वेश्यावृत्ति की गर्त में धकेल दी गई हैं.

देश के अनेक हिस्सों में आदिवासियों के सामने विस्थापन एक विकराल समस्या के रूप में खड़ा हुआ है. विस्थापन के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कलिंगनगर में गोलियां बरसाकर उनका खून बहाया गया तो बस्तर में सलवा जुडूम का कहर ढाया जा रहा है.

हम मेहनतकश जनता, जनवाद पसन्द लोगों एवं जन संगठनों से अपील करते हैं कि आदिवासियों के विस्थापन की सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं तथा सरकारों की साम्राज्यवाद परस्ती नीतियों की निंदा करें. जल-जंगल-जमीन पर अपना अधिकार कायम करने के लिए संघर्षरत आदिवासी जन समुदायों का तहेदिल से समर्थन करें.

गणपति
सचिव, केन्द्रीय कमिटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

10-1-2007

26 जनवरी 2007 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाओ !

आन्ध्र की एसआईबी द्वारा झूठी मुठभेड़ में मारे गए भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड बालकृष्ण (चन्द्रमौली) एवं डिवीजनल कमेटी सदस्या कॉमरेड करुणा की बहादुराना शहादत को ऊंचा उठाए रखो !

एक तरफ देश के लुटेरे शासक वर्ग भारतीय गणतंत्र की 57वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी आदि समस्याओं से दो-चार देश की मेहनतकश जनता संघर्षरत है. खासकर विशाल जंगली इलाकों में बसी आदिवासी जनता विस्थापन, पुलिसिया हत्याकाण्ड, दमन, आदि समस्याओं से बुरी तरह परेशान है. देश की सार्वभौमिकता एवं स्वाभिमान साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के पास गिरवी रखने वाले सत्ताधीश एसईजेड के नाम से देश की लाखों एकड़ जमीनें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करते हुए रंगरेलियां मना रहे हैं. देश के संविधान की रक्षा करने के दम्भ भरने वाले शासन-प्रशासन व पुलिस अमले के अधिकारी संघर्षशील जनता के दमन हेतु संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं. आदिवासी इलाकों में मौजूद अपार प्राकृतिक सम्पदाओं को बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने को बेताब दलाल नेता वहां के मूल निवासियों को खदेड़ने के लिए सलवा जुडूम, सेंदेरा, गांवबंदी जैसे तरह-तरह के हथकण्डे अपना कर उन्हें हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी आदि का शिकार बना रहे हैं. अंग्रेजी

उपनिवेशकों से 'आजादी' मिले 60 बीतने के बावजूद देश की अत्यधिक जनता की रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत समस्याओं का भी समाधान करने में बुरी तरह नाकाम सरकारें उलटे माओवादी आन्दोलन को विकास का बाधक बताकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिशें कर रही हैं. इसके लिए वे मीडिया का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही हैं.

दूसरी तरफ देश के हजारों किसान मजदूरों ने भाकपा (माओवादी) की अगुवाई विभिन्न इलाकों में शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह का परचम बुलन्द कर रखा है. आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आधार इलाकों के लक्ष्य के साथ हथियारबन्द संघर्ष चल रहा है. दण्डकारण्य और झारखण्ड में लुटेरों के झूठे लोकतंत्र को धता बताकर मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर जनता के सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो रही है. देश की तमाम शोषित जनता के लिए आशा की नई किरण के रूप में क्रान्तिकारी जन कमेटियां ग्राम, इलाका एवं जिला स्तर पर उभरने लगी हैं. केन्द्र व राज्यों की सरकारें जनता के इस नए विकल्प को कुचलने के लिए हजारों अर्ध-सैनिक बलों, कमाण्डो, ग्रेहाउण्ड्स एवं पुलिस बलों को उतार कर अमानवीय दमन ढा रही हैं. इसी की कड़ी के रूप में भाकपा (माओवादी) के सर्वोच्च नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में कैद करना, सजाएं देना, झूठी मुठभेड़ों में हत्या करना आदि कर रही हैं. अक्टूबर महीने में हमारी केन्द्रीय कमेटी के दो सदस्य कॉमरेड शीला दीदी और कॉमरेड चिन्तन जी को गिरफ्तार कर उन्हें बुरी यातनाओं का शिकार बनाया गया. और 27 दिसम्बर को हमारी केन्द्रीय कमेटी के एक अन्य सदस्य कॉमरेड वडकापुर चन्द्रमौली (बालकृष्ण) एवं उनकी पत्नी कॉमरेड करुणा, जो आन्ध्र-उड़ीसा सीमान्त विशेष जोन की पूर्वी डिवीजनल कमेटी की सदस्या थीं, की आन्ध्र की एसआईबी ने एक झूठी मुठभेड़ में की. उन्हें 26 तारीख को एक मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा के किसी शहर से गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें क्रूरतम यातनाओं का शिकार बनाकर आन्ध्रप्रदेश के विशाखपट्टनम जंगलों में ले जाकर गोली मारकर मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी गई. इनकी हत्या के लिए केन्द्र एवं आन्ध्रप्रदेश की फासीवादी सरकारें जिम्मेदार हैं. कॉमरेड चन्द्रमौली और करुणा ने सर्वहारा के लक्ष्य की पूर्ति

के लिए तमाम यातनाएं सहकर भी पार्टी का एक भी रहस्य न खोलकर शहादत को चूम लिया. माओवादी नेताओं की हत्या कर जनता के जायज आन्दोलनों को कुचल सकने का दिवास्वप्न देखने वाले लुटेरे शासक वर्गों को जनता जरूर सबक सिखा देगी, इतिहास इसका गवाह है.

हम देश की मेहनतकश जनता से अपील करते हैं कि बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्नियों के हित में जल-जंगल-जमीन से आदिवासियों की बेदखली; एसईजेड के नाम से देश की रही-सही सार्वभौमिकता को विलुप्त करना; सलवा जुडूम, सेन्देरा जैसे छद्म आन्दोलनों की आड़ में आदिवासियों को हत्या, लूट एवं बलात्कार का शिकार बनाना; झूठी मुठभेड़ों में माओवादी नेताओं की हत्या करना आदि दमनकारी नीतियों के खिलाफ 26 जनवरी 2007 के दिन देशव्यापी विरोध दिवस (या काला दिवस) मनाया जाए. हम देश के प्रबुद्ध एवं जनवाद पसन्द पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों, वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों से अपील करते हैं कि वे केन्द्र एवं राज्य सरकारों की साम्राज्यवाद परस्त एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करें.

गणपति

महासचिव,

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

19-2-2007

भाकपा (माओवादी) की बहु–प्रतीक्षित ऐतिहासिक एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस सम्पन्न

– भारतीय क्रान्ति में एक मील का पत्थर

भाकपा (माओवादी) की बहु–प्रतीक्षित ऐतिहासिक एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस सम्पन्न

– भारतीय क्रान्ति में एक मील का पत्थर

जनवरी–फरवरी 2007 में भाकपा (माओवादी) की एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई. यह भारत की उत्पीड़ित जन समुदायों और विश्व की जनता के लिए एक ऐतिहासिक महत्व वाली घटना है. इस कांग्रेस ने समूची पार्टी में उच्च स्तर की एकता हासिल की और भारतीय क्रान्ति की दो महान धाराओं – भाकपा (मा–ले) और एमसीसीआई की एकता, जो 21 सितम्बर 2004 को बनी थी, को इस कांग्रेस ने पूर्ण बनाया. पार्टी के अन्दर के विवादास्पद मुद्दों को इसने जीवन्त, जनवादी और कॉमरेडाना वितर्क और बहस के जरिए हल किया. यह कांग्रेस 1970 में सम्पन्न 8वीं कांग्रेस के बाद 36 सालों के अन्तराल में आयोजित की गई. यह भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के लम्बे इतिहास में एक और मील का पत्थर है तथा भारत के माओवादी आन्दोलन के इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस भारत में मौजूद कई गुरिल्ला जोनों में से एक में घने जंगलों के बीच सम्पन्न हुई. पीएलजीए की 3 कम्पनियों की सुरक्षा की छाया में 'कॉमरेड्स चारु मजुमदार–कन्हाई चटर्जी कम्यून' में आयोजित इस कांग्रेस के स्थल की पहरेदारी चौबीसों घण्टे कई संतरी पोस्टों के माध्यम से की गई. दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई दलों ने लगातार गश्त लगाई और आसपास के गांवों

की जनता ने पार्टी के लिए आंखों और कानों का काम किया. इसी की बदौलत, इसमें बाधा डालने के लिए प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा की गई तमाम कोशिशों को नाकाम बनाते हुए यह कांग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई. इस कांग्रेस के कुछ ही दिन पहले आन्ध्रप्रदेश के एसआईबी (स्पेशल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो) के गुण्डों ने भाकपा (माओवादी) का केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं केन्द्रीय सैन्य आयोग के सदस्य कॉमरेड चन्द्रमौली उर्फ नवीन तथा उनकी जीवन संगिनी एवं डिवीजनल कमेटी सदस्य कॉमरेड करुणा को गिरफ्तार कर क्रूरतम यातनाएं देने के बाद उनकी जघन्य हत्या की. ये दोनों कॉमरेड यातना-शिविर में दृढ़तापूर्वक डटे रहे तथा उन्होंने जनता और पार्टी के हित में, और तो और कांग्रेस के सफल आयोजन में अपना योगदान देते हुए अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर किया. कांग्रेस हाल का नाम ''कॉमरेड्स करम सिंह - चन्द्रमौली हाल'' रखा गया.

दुश्मन की व्यापक घेराव मुहिमों के बीचोबीच यह कांग्रेस आयोजित की गई. सरकार ने इस कांग्रेस को विफल करने के लिए एक विशेष सेल का भी गठन किया. सभी गुरिल्ला जोनों में खुफिया छानबीन बढ़ा दी गई थी तथा इन जोनों के अन्दर व आसपास सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई थी. मीडिया ने यहां तक कि कांग्रेस के आयोजन की सम्भावित तिथियों की भविष्यवाणी की. इसके बावजूद, गहन घेराबन्दी के बीचोबीच, 16 राज्यों से आए हुए एक सौ से ज्यादा प्रतिनिधियों ने, जो भारत के माओवादी नेतृत्व का कोर हैं, अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया.

पार्टी के तत्कालीन महासचिव कॉमरेड गणपति ने कांग्रेस का उद्घाटन किया. कॉमरेड किशन ने उपस्थित तमाम कॉमरेडों का स्वागत किया. शहीद वेदी पर पुष्पमालाएं अर्पित की गईं. 8वीं कांग्रेस से अब तक शहीद हुए तमाम महान कॉमरेडों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजली पेश की गई. उसके बाद एक एक जुलूस निकाला गया, जिसका समापन करमसिंह-चन्द्रमौली कांग्रेस हाल के पास हुआ. प्रतिनिधिगण ने कांग्रेस हाल में प्रवेश किया और कार्यक्रम शुरू हुए.

इस ऐतिहासिक कांग्रेस ने एकीकृत पार्टी के पांच बुनियादी दस्तावेजों -- मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के चमकते लाल झण्डे को ऊंचा उठाए रखो; पार्टी कार्यक्रम; पार्टी संविधान; भारतीय क्रान्ति की रणनीति-कार्यनीति और मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति पर राजनीतिक प्रस्ताव -- को मुक्त और खुले तौर पर चलाई गई व्यापक और गहन बहसों के बाद पारित किया. 1969 में गठित दोनों पुरानी पार्टियों के अतीत के व्यवहार की समीक्षा पर इस कांग्रेस में विशेष

ध्यान दिया गया. इसके अलावा पुरानी पीपुल्सवार पार्टी की 2001–2004 तक के तीन सालों की कांग्रेस के बाद की समीक्षा तथा नव गठित पार्टी की पिछले दो सालों के व्यवहार की समीक्षा पर भी चर्चा हुई. इसके साथ–साथ, अन्तर्राष्ट्रीय एवं देशीय स्तर पर वर्तमान समय के विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किए. पिछले दो सालों से समूची पार्टी में एरिया, जिला, रीजनल एवं राज्य स्तर पर आयोजित अधिवेशनों में इन दस्तावेजों पर गहराई से बहसें हुई थीं और निचले स्तर से सैकड़ों संशोधन इस कांग्रेस को भेजे गए थे. यह कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम कड़ी थी.

इस एकता कांग्रेस ने नव जनवादी क्रान्ति, जिसकी धुरी कृषि क्रान्ति है, की आम लाइन को तथा भारतीय क्रान्ति की दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन, जो नक्सलबाड़ी विद्रोह के साथ पहली बार एजेंडे में आई थी, को ऊपर उठाए रखा. इसने पार्टी की राजनीतिक–सैनिक लाइन को और भी समृद्ध बनाया. इसने पार्टी के सामने कई नए कार्यभार रखे जिसमें आधार इलाकों की स्थापना पर मुख्य जोर दिया गया जोकि समूची पार्टी का फौरी, बुनियादी और केन्द्रीय कार्यभार है. इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि देश भर में लोकयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए जन सेना को और ज्यादा मजबूत किया जाए; पार्टी के जनाधार को गहन बनाया जाए; तथा साम्राज्यवाद के निर्देश पर प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा लागू भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नव–उदारवादी नीतियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर एक जुझारू जन आन्दोलन छेड़ा जाए.

पार्टी दस्तावेजों में जोड़े गए/विकसित किए गए महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं : भारत के सामन्तवाद/अर्ध–सामन्तवाद के ठोस लक्षण को सूक्ष्म रूप से चिन्हित करना कि यह जाति–प्रणाली और ब्राह्मणवादी विचारधारा से गहराई से गूंथा हुआ है; कृषि सम्बन्धों में, खासकर पंजाब में हो रहे बदलावों का अर्ध–सामन्ती ढांचे के तहत आंकलन कर हमारी कार्यनीति पर इसके प्रभावों को चिन्हित करना; भारत के संदर्भ में दलाल नौकरशाह पूंजीपति के बारे में ज्यादा स्पष्ट समझदारी पर पहुंचना; विशेष रूप से भारत के संदर्भ में छापामार आधार, आधार इलाका, दोहरी सत्ता, आदि अवधारणाओं पर एक गहरी समझदारी पहुंचना; लोकयुद्ध को आगे बढ़ाना, पीएलजीए को पीएलए में रूपांतरित करना, गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में तब्दील करना, गुरिल्ला जोनों को आधार इलाकों में तब्दील करना; मजदूर वर्ग में काम का महत्व, संयुक्त मोर्चा और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे.

कई मौजूदा घटनाओं पर भी इस कांग्रेस ने अनेक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए, जैसे कि – विश्व जनता के संघर्ष, राष्ट्रीयता संघर्षों के प्रति समर्थन, भारतीय विस्तारवाद के खिलाफ, खैरलांजी के बाद के दलित उभार एवं जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ, हिन्दू फासीवाद के खिलाफ, सेज एवं विस्थापन के खिलाफ, आदि. तीन जादुई हथियारों पार्टी, जन सेना एवं संयुक्त मोर्चा को मजबूत करने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पारित किए गए. एकीकृत पार्टी के दो–वर्षीय वित्तीय लेखा–जोखा भी सदन में पेश किया गया. इसके बाद निवृत्तमान केन्द्रीय कमेटी ने सामूहिक रूप से आत्मालोचना पेश की जिसमें उसने अपनी मुख्य कमजोरियों को ठोस रूप से चिन्हित किया. बाद में उसने कांग्रेस के प्रतिनिधियों से अपनी आलोचनाएं पेश करने को कहा. इस प्रक्रिया के बाद नई केन्द्रीय कमेटी का चुनाव किया गया जिसने बाद में पार्टी के महासचिव के रूप में कॉमरेड गणपति को दोबारा चुन लिया.

यह कांग्रेस विश्व जनता का यह आह्वान करते हुए उत्साह के माहौल में सम्पन्न हुई – साम्राज्यवाद और उसके पालतू कुत्तों का सफाया करने के लिए लहरों की तरह उमड़ पड़ें! विश्व भर में क्रान्तिकारी युद्ध को आगे बढ़ाएं!! इस एकता कांग्रेस – 9वीं कांग्रेस ने आखिर में देशवासियों का यह आह्वान किया कि वे देश में जारी लोकयुद्ध और भ्रूण रूप में पनप रही जनसत्ता के समर्थन में; इंसाफ और समानता पर आधारित तथा सम्राज्यवाद व अर्ध–सामन्ती बन्धनों से मुक्त एक सच्चे जनवादी समाज की स्थापना करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आएं.

गणपति

महासचिव,

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

29-4-2007

'स्वतंत्र नागरिक पहल' को माओवादियों का जवाब

प्रति,

सदस्यगण,

स्वतंत्र नागरिक पहल

प्रिय मित्रों,

स्वतंत्र नागरिक पहल के उन छह जानी मानी हस्तियों का पत्र मुझे मिला जिन्होंने मई महीने में तथ्यों के अन्वेषण हेतु छत्तीसगढ़ के दन्तेवाड़ा जिले का दौरा किया था. यह पत्र मुझे कब लिखा गया यह मैं नहीं जान सका क्योंकि उस पर तारीख नहीं थी. पर मुझे यह पत्र हाल ही में मिला अपनी पार्टी की तरफ से मेरी आप सबको धन्यवाद. न सिर्फ इस पत्र के लिए, वरन हम अभारी हैं. आप सबकी स्वैच्छिक उत्तरदायी प्रवृत्ति के लिए और दन्तेवाड़ा में जारी उस सशस्त्र संघर्ष खत्म करने की मिली चाहत के लिए जो एकतरफा दमित आदिवासियों और दूसरी तरफ राज्य पोषित सलवा जुड़ूम, पुलिस और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के बीच चल रहा है. पत्रोत्तर में विभिन्न कारणों से हुए विलम्ब के लिए मैं क्षमा पार्थी हूँ.

जून 2005 से अचानक भड़के दर्दनाक संघर्ष की आग को शांत करने हेतु आपके द्वारा किए गए कष्ट साध्य प्रयास को हमारी पार्टी सराहना करती है. अब तक इसने 400 से अधिक जानें ली हैं. भारतीय समाज के सबसे दमित कुचले गए लोगों की मुक्ति की खासकर न्याय के युद्ध में लगे हम सब लोगों के लिए आप जैसे ...... जनतांत्रिक बुद्धिजीवियों का यहां आकर तथ्यों को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करना उत्साहवर्धक है. आप लोगों ने कुछ तथ्यपरक आलेख लिखे जो अच्छे लगे. डॉ. ई.ए.एस. शर्मा का 'द हिन्दू' में छपा आलेख जिसमें यहां की सच्चाई को वस्तुपरख तरीके से प्रस्तुत किया गया. उन्होंने सलवा जुड़ूम की उत्पत्ति और प्रकृति का सही विश्लेषण किया है जो इस

मिथ्या प्रचार का मुंहतोड़ जवाब है कि ''सलवा जुडूम माओवादियों के विरुद्ध जनता का स्वतःस्फूर्त आन्दोलन है. कदापि जन आन्दोलन नहीं है – जैसा कि प्रचारित किया है. यह एक राज्य पोषित अभियान है जिससे भोले-भाले आदिवासियों का युद्ध में गोलों की तरह उपयोग किया जा रहा महज कुछ निजी हितों की स्वार्थ साधना के लिए. ''उन्होंने गैर आदिवासी व्यापरी-ठेकेदार गठजोड़ से किए जाने वाले आदिवासियों के शोषण की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है.'' दशकों से अनैतिक भूमि पर कब्जा करने वाले, शातिर व्यापारी और शोषक ठेकेदारों ने इस क्षेत्र के आदिवासी जन जीवन पर अपना वर्चस्व बेरोकटोक कायम किया हुआ है जो सबके सब गैर आदिवासी हैं.

सतप्रेम मैं यह भी शीशे की तरह साफ कर देना चाहता हूँ कि आपकी ही तरह हमारी पार्टी भी यही मानती है. दन्तेवाड़ा या अन्य आदिवासियों की बेहतरी या सर्वान्मुखी विकास ही, किसी भी बहस या प्रयास के केन्द्र में होना चाहिए जिसका सीधा या परोक्ष प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता हो.'' किन्तु हम आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा राजनीतिक अहिंसक और खुली व्यवस्था में अधिक कारगर ढंग से सकती है. ....स्वत सशस्त्र संघर्ष के.'' और इसी सैद्धांतिक-राजनीतिक सोच के विरोधाभास ने हमारे और आपके पक्ष को ठीक एक दूसरे के विरुद्ध आमने-सामने खड़ा कर दिया है. जिस कारण दन्तेवाड़ा के आदिवासियों को हक दिलाने के लिए साधन के रूप में चल रहे वर्ग-युद्ध पर हम दोनों पक्षों की राय अलग-अलग है. समझ ओर दृष्टि के इसी फर्क के कारण तथा अपने वर्ग पूर्वाग्रह के कारण ही इस टकराव का सही समाधान खोजने के मार्ग में रोड़ा पड़ता है. इसे इस तरह करना बेहतर होगा कि दन्तेवाड़ा ही नहीं पूरे देश के विभिन्न भागों में क्रान्तिकारी और प्रतिक्रान्तिकारी ताकतों के बीच चल रहा युद्ध. क्या आप भारत के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जहां आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा अहिंसक एवं खूले तरीकों से हो पाई है? सिर्फ भारत ही क्या वैश्विक स्तर पर भी यही हाल है नहीं है? कलिंगनगर के आदिवासियों को टाटा स्टील के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध करके क्या हासिल हुआ?

आपने हमारी पार्टी से 9 सवाल पूछे हैं. संक्षेप में ये नियमानुसार हैं – सरकार से बातचीत हेतु युद्ध बंद करने के आपके आह्वान पर हमारी चुप्पी, हत्या के बाबत हमारा गैर जिम्मेदाराना रवैया, मणिकोंटा की तरह लगाई जन अदालतों को वैधानिकता, हमारी पार्टी का सभी जगह सुरंग बिछाना, अवयस्क किशोरों के हाथों में बन्दूक देना,

केन्दीय सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग किए गए स्कूली इमारतों को नष्ट करना, मताधिकार प्रयोग करने के विरुद्ध हमारी पार्टी का फरमान, सड़क तथा विकास कार्यों में रुकावटें डालना, जनता को खतरे में डालना और सशस्त्र संघर्ष को जारी रखकर भयानक दमन काण्ड हेतु आमंत्रित, राज्य की सत्ता हथियाने के फेर में दन्तेवाड़ा-बस्तर के लोगों के हितों की अनदेखी तथा नागरिकों और लड़ाकुओं के बीच फर्क न करना आदि.

आपके प्रश्नों के तेवर और स्तर हमेशा नरमपंथ. लोकतांत्रिक बुद्धिजिवियों को धोखे में रखते हैं अतः इनका उत्तर देने के पहले मैं एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अनेक तथ्यों के ढेर से आप सच कैसे जानेंगे? क्या आप विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि दन्तेवाड़ा की सचाई की आपकी समझ माओवादी आन्दोलन और हिंसक क्रान्ति के प्रति आपके सैद्धांतिक पूर्वग्रहों के कारण अस्पष्ट नहीं हुई? क्या किसी के लिए भी यह संभव है कि सशस्त्र क्रान्ति के प्रति नकारात्मक सोच रखते हुए भी वह तटस्थ विश्लेषण करके सही निष्कर्ष पर पहुंच सकेगा?

हम जानते हैं कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे. यह संभव भी नहीं है. क्योंकि दमित-शोषित जनता को उनकी दयनीय स्थिति से उबारने के साधन या उपाय को लेकर हमारी और आपकी राजनीतिक-सैद्धांतिक अवधारणाएं अलग-अलग हैं. क्रूरतापूवर्क शोषित, बर्बरतापूर्वक दमित जनता की रक्षा एक तरफ और दूसरी तरफ हजारों-लाखों जनता के शोषण से पोषित समाज के 5% लोगों के बीच चल रहे वर्ग युद्ध में ऐसा समन्दारातल है ही नहीं. वर्ग भेद भरे समाज में कोई सच कभी नहीं होता. दमित जनता का सच दमनकारी लोगों के सच से अलग होता है. यह तब से चला आ रहा एक ऐसा सच है जब स्पार्टकस और अनाम योद्धाओं ने गुलामी प्रथा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था. या तो आप उन गुलामों के साथ होते जिसमें स्पार्टकस और विद्रोही गुलामों के तर्क को न्यायसंगत और सच मानना होता या फिर उन मालिकों के साथ रहकर गुलामों के विद्रोह को उनके द्वारा किया गया अन्याय मानना होता उन वर्गों की जिन्होंने अपने आकाओं की सेवा करने से इंकार किया. इसी तरह यदि भगतसिंह भारतीयों की दृष्टि में महान क्रान्तिकारी नायक थे तो उपनिवेशवादी अंग्रेजों की दृष्टि में वह महान खलनायक और आतंकवादी थे.

वर्ग संघर्ष में - सामन्य खेल स्पर्धाओं से हटकर यह संभव नहीं कि कोई ऐसा तटस्थ पंच (रेफरी) हो जो किसी भी पक्ष द्वारा नियम के उल्लंघन होने पर सीटी बजाकर भ्रष्ट

खिलाड़ी को रोक सके. यह युद्ध दो असमान पक्षों के बीच है जिसमें एक तरफ सम्पन्न राजसत्ता है जो धनाढ्य वर्ग की मनमानी शोषण के ''अधिकार'' की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है. तो दूसरी तरफ धरती के अभागे-भूखे, बेघर, दबे, कंकाल हुए बेसहारों का हुजूम - जो सत्ता की दृष्टि में आज भी सदियों पहले के गुलामों से अलग नहीं. संविधान के तहत नियम-कानून उन्हीं शोषकोंने बनाए हैं. जिससे उन्होंने अपने लिए संविधानिक पकड़ से बचने के रास्ते भी बनाए हुए हैं. वर्गयुद्ध में जो लोग तटस्थ पंच के रूप में आते हैं और दोनों पक्षों के लिए एक जैसे कायदे रखते हैं वे अंततः शोषकों के सामने घुटने टेकने पर बाध्य होते हैं बावजूद इसके कि उन लोगों के उद्देश्य और प्रवृत्ति में कोई दोष नहीं होता. जो भी व्यक्ति वर्गभेदी समाज में तटस्थ होकर रहना चाहेगा वह अपनी इस आदर्श, आकर्षक, ... अवास्तविक सोच का शिकार होकर ही रहेगा.

आपने दोनों तरह की हिंसा की निंदा की है यानि राज्य की सत्ता और सलवा जुडूम के गुण्डों द्वारा बहुराष्ट्रीय, साम्राज्यवादी कम्पनियों, बड़े औद्योगिक घरानों जैसे टाटा, एस्सार बेईमान जिसमें वे आदिवासी नेता भी हैं जो अब सत्ता में रहकर .... के नुमाईंदे बन गए हैं. और ऐसे मजबूर आदिवासियों पर जुल्म ढा रहे हैं जो अब जाग्रत होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं. और पार्टी के बैनरतले अपनी मुक्ति का अभियान चला रहे हैं. तथा उन पर भी अत्याचार कर रहे हैं जो दमित आदिवासी एक न्यायसंगत क्रान्तिकारी संघर्ष में सीमित हिंसा कर रहे हैं. इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी आप दोनो ही पक्षों को दोषी करार रहे हैं. दमनकारियों की हिंसा को आप उनकी हिंसा के विरुद्ध प्रतिहिंसा के बराबर कैसे मान सकते हैं. जो चुपचाप अब तक दमन सहते रहे आदिवासियों ने अपने बचाव में की है. ऐसा करके अंततः आप किसकी सहायता करेंगे? इससे दमनकारियों को ही अपना दमन जारी रखने में मदद नहीं मिलेगी जिससे कि वे अपना वर्चस्व बरकरार रख सकेंगे? इन सभी बिन्दुओं पर लोकतंत्र समर्थक बुद्धिजिवियों का गहन चिन्तन जरूरी है. हमारी आप से यही प्रार्थना है कि आप शान्ति से दमित-शोषितों के पक्ष में खड़े हों और तब आप खुद-बखुद उन सभी प्रश्नों के सही उत्तर पा जायेंगे जिन प्रश्नों को लेकर आपका मन-मष्तिष्क अभी उथल-पुथल में है.

अब हम आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संक्षिप्त उत्तर देने की कोशिश करेंगे

1. आपने हमसे कहा था कि हम युद्धविराम घोषित करके शासन से वार्तालाप करें. आप नाराज थे कि हम आपकी बात मानने की बाजाए अधिक उग्र हो गए थे. आपने यह भी पूछा था कि क्या हम बातचीत के लिए तैयार हैं. जब जनता के दुश्मन संघर्षरत जन समुदाय के दमन का उद्देश्य लेकर बर्बता बढ़ाते जायें तब बातचीत कैसे हो सकती है? दरअसल हम तो 1998 से हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर बातचीत करने के प्रस्ताव पर सार्थक रुख अपनाते रहे बस शर्त यह भी कि सरकार आदिवासियों पर अपनी दमनात्मक कार्रवाई रोके तथा पुलिस और सशस्त्र बलों को क्षेत्र से वापस लेकर वार्ता के उपयुक्त वातावरण तैयार करे तथा हत्याओं और बलात्कारों के दोषी अधिकारियों को दंडित करें.

आज, उपरोक्त मांगों के साथ ही तत्काल सलवा जुडूम पर प्रतिबन्ध, जनता पर अत्याचार के दोषियों को दंड, जन सुरक्षा अधिनियम 2006 का निलंबन तथा कथित राहत शिविरों से वापस आने के इच्छुक आदिवासियों को अपने गांव जाने की छूट भी देनी होगी. सत्ता पक्ष से वार्ता के उपयुक्त वातावरण बनाने की पहल के बिना हमसे एकतरफा युद्धविराम करके वार्ता हेतु तैयारी की मांग करना क्या न्यायोचित है? आंध्रप्रदेश में शब्द की वार्ता ने भारतीय सत्ताधारी वर्ग के पाखंड और घृणित हिंसात्मक प्रवृत्ति को ही उजागर किया है. वहीं दूसरे दौर की बातचीत सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वाई,एस रेड्डी की सरकार ने युद्धविराम की सीमा बहाने से इंकार करते हुए क्रूर हमले शुरू कर दिए थे. इन कड़वे अनुभवों ने भारत में कहीं भी बातचीत से हमें दूर रहने पर मजबूर किया है. मजबूर जनता पर शोषकों के क्रूर दमन के जारी रहते हुए हमारा एकतरफा युद्ध विराम घोषित करके वार्ता करना क्या आत्मघाती नहीं होगा? यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि एक मेमना कसाई पर भरोसा कर ले. हमारी आपसे गुजारिश है कि आप आज की हालात में हमसे की गई एकतरफा युद्धविराम के प्रस्ताव के खतरों पर दुबारा विचार करें.

2. आपने हमारी ''जान ले लेने की लापरवाह प्रवृत्ति'' पर अपनी चिन्ता जताई है. गड़चिरोली से आ रही बारात और कांकेर के व्यापारियों के साथ हुआ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था और पहचानने में हुई गलती के कारण हुआ. कोई भी क्रान्तिकारी भोली जनता पर ऐसे आक्रमण करने की सोच ही नहीं सकता. ''समाज वैज्ञानिक और खोजी पत्रकार सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं करते. वह उन घटनाओं के पीछे उनके कारण, इतिहास तथा घटना को अंजाम देने वालों की सोच, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता तथा उस परिवेश को भी दृष्टिगत रखते हैं जिसमें ऐसी दुर्घटनाएं हुईं. दण्डकारण्य में 25

वर्ष से भी अधिक समय से चल रहे हमारे प्रदीर्घ संघर्ष में ये घटनाएं अपवाद हैं. हमारे सिंद्धान्त और राजनीतिक विचारधारा तो हमें जनता की रक्षा अपने आंखों की भहौं की तरह करने की सीख देती हैं. हम मानव के जीवन को किसी भी राजनीतिक पार्टी या मानवतावादी से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. जनता के प्रति हमारे लगाव और प्रतिबद्धता के कारण ही हम लोगों ने अपने घर-परिवार त्यागे तथा अपने प्राण न्यौछावर करके भी व्यापक जनता को शान्ति प्रदान करने हेतु प्रेरित किया. हमारी ''जान लेने की लापरवाह प्रवृत्ति'' बुर्जुआ समाचार माध्यम के दुष्प्रचार से उपजी एक मिथ्या धारणा है, एक झूठा आरोप है. इस दुष्प्रचार से न केवल समाज का सामान्य वर्ग वरन सत्ता वर्ग के कटु आलोचक भी कुछ न कुछ प्रभावित होते ही हैं. हम आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अधिक सचेत होकर तथा त्रुटिहीन योजना बनाकर हम भविष्य में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकेंगे.

हमारी छापामारी और मुठभेड़ों में पुलिस वालों के मारे जाने से हम भी उतने ही दुखी होते हैं जितना कि आप. हमने कई बार पुलिस वालों और उनके परिजनों से यह मार्मिक अपील की कि वह निहत्थे भोले लोगों को तथा हमारे समर्थकों पर हमलों से परहेज करें. हमने पर्चे छापकर नागा बटालियन के जवानों, केन्द्रीय सुरक्षा बल से कहा कि वे हम पर हमला करने के उनके अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करें. हमने कई ऐसे गीत बनाए हैं जिनमें गरीबी के दुखद चित्रण के साथ ही पुलिस में जाने की विवशता का चित्रण भी किया है जो बेरोजगारी जनित है. जब कभी हम पुलिस पर हमला करते हैं हम चाहते हैं कि न्यूनतम खून-खराबा हो. हमने आज तक किसी भी ऐसे पुलिस वाले की हत्या नहीं की जो आत्मसमर्पण किया हो. सामान्य पुलिस वालों पर हमारा कोई क्रोध नहीं होता पर जब लोगों पर अत्याचार हों, हत्याएं हों, महिलाओं पर बलात्कार हों, घरों को जलाया जा रहा हो तब ऐसा करने वाले सशस्त्र बलों व पुलिसियों और सलवा जुडूम के गुण्डों को हम चुपचाप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम जनता के अधिकारों की रक्षार्थ ही तो हैं और इसी कारण हम उन पर हमले करते हैं जो जनता से उनके जीवन का अधिकार छीनना चाहते हैं. आपने जनयुद्ध की रणनीति पर पुनर्विचार हेतु न कहा होता यदि आपने उन गलतियों पर ध्यान देने से पहले यह जानते कि हमने किन कारणों से शस्त्र उठाये.

3. मणिकोंटा की जन अदालत के बारे में हम सबसे पहले यह बताना चाहते हैं कि वे

व्यक्ति सामान्य ग्रामीण न होकर वेतनभोगी एसपीओ तथा सलवा जुडूम के गुण्डे थे. जिन्होंने सलवा जुडूम के नाम पर गांव के निवासियों पर खौफनाक अत्याचार किए थे. इसका प्रतिकार करना ऐसी हरकतों को अंजाम देने वाले गुण्डों को रोकने के लिए जरूरी था. सामान्य जनता प्रायः ऐसे अत्याचारियों की हत्या नहीं कर पाती. सैकड़ों जन समुदाय की उपस्थिति में ऐसी घटना का होना स्वयं खून ..... से अनवरत हो रही अत्याचारों से उपजी घृणा और अपने अधिकारों की रक्षा किए गए प्रतिशोध को ही रेखांकित करती है.

आपने हमसे जन अदालत में प्रक्रिया के ...... पालन की बाबत प्रमाण मांगा है. हमारा आग्रह है कि ऐसे सवाल पूछने से पहले आप उस कथित न्याय प्रणाली की जांच करते जो दन्तेवाड़ा या अपने देश की जनता पर थोपा गया है. क्या सही प्रक्रिया का .... व्यावसायिक वकीलों को लगाने से है (जो प्रायः अनैतिक लफ्फाज होते हैं) जो किसी अपराध को सिद्ध करें (जो अपने देश में असंभव सा लगता है, आप वास्तविक जीवन में अपराधियों को उच्च पदों पर तथा हजारों-हजार निपराधों को बरसों से सुनवाई की प्रतिक्षा में जेलों में जीने को विवश रहते देखकर भी यह कैसे सोच सकते हैं? यह सर्वविदित सत्य है कि 16 से 9 मामलों में हमारी अदालतों में न्याय नहीं मिलता फिर आप उस जनता में क्यों दोष देख रहे हैं जो अत्याचारियों को खुद सजा देते हैं. जैसा कि हमारी पार्टी की अगुवाई में मणिकोंटा में भी हुआ? आप जानते हैं कि हमने शिविरों से 57 लोगों को पकड़ा था जिनमें से 44 लोगों को पूछताछ के बाद निर्दोष पाकर छोड़ दिया और केवल 13 दोषियों को ही दण्डित किया. जबकि अदालतों में जिरह के बाद प्रायः दोषी व्यक्ति ही छूट जाते हैं और मजलूमों को दण्डित किया जाता है. बरसों तक जेल में रखा जाता है. इससे बढ़कर आप हमारे इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि हमने कई पुलिस अफसरों को भी पकड़ा था किन्तु उनके खिलाफ आपराधिक हत्याओं के प्रमाण न पाकर उन्हें आजाद कर दिया. वो केवल आपराधिक प्रवृत्ति के, जनविरोधी सबसे खतरनाक दुश्मनों के गुर्गे ही थे जिन्हें सबसे बडी सजा - प्राणदंड दिया गया.

सिद्धांततः हम मृत्यदंड के विरोधी हैं तथा सत्ता हथियाने के बाद हमारी व्यवस्था में मृत्युदण्ड खत्म करके रहेंगे. किन्तु वर्तमान में दमित जनता और हमारे क्रान्तिकारी ऐसा करने को विवश हैं क्योंकि यदि प्रतिक्रान्तिकारी तत्वों को खुली छूट मिल जाए

तो जनता पर उनका जुल्म बढ़ता जाएगा और हमारी जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचाकर वे हमारे अस्तित्व का संकट खड़ा कर देंगे. प्रमाण के लिए आप अपने अदालत से कहें कि वह पुलिस को निर्दिष्ट करें कि मृत्युदंड देकर मारे गए लोगों के शवों के पास जो जन अदालत के रिकार्ड किए गए कैसेट तथा पत्र रखे गए थे उन्हें प्रस्तुत करें. ये दस्तावेज पुलिस ले गई थी. जिससे इन अपराधियों के अपराध और जन अदालत की कार्रवाई का पूरा लेखा-जोखा था जिससे आपको हमारी कार्रवाई की प्रमाणिकता मिल जाएगी. यदि आप चाहें तो दन्तेवाड़ा आकर स्वयं लोगों से पूछकर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं इसके लिए हजारों लोग मिल जायेंगे.

4. यह आरोप एकदम निराधार है कि हमने सब तरफ बारूदी सुरंगे बिछा दी हैं. जो जनता अपना अस्तित्व बनाए रखने में उसे सैकड़ों की तादाद में घुसने वाले अर्धसैनिक बलों और सलवा जुडूम के गुण्डों को अचानक आने से रोकने के लिए यहां-वहां कुछ सुरंगे लगाना जरूरी है वरना गांवों में उनके आतंक का राज हो जाएगा. यह न तो बेताद है नहीं अकारत है. हम यह जानते हैं कि सुरंग लगाकर हम सलवा जुडूम को रोक नहीं सकते, हम विश्व की जनता के साथ बारूदी सुरंगों तथा व्यापक विनाशकारी अन्य तमाम अस्त्र-शस्त्रों के उपयोग की भर्त्सना करते हैं. जिनसे होने वाला ''समपाश्विक नुकसान'' कहीं ज्यादा होता है, जैसा कि जार्ज बुश जुनियर ने कहा - यद्यपि वे स्वयं विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी खुद हैं, हम इन शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं. यदि राज्य की सत्ता के सैनिकों द्वारा अनियंत्रित ग्रेनेड मोर्टरें और हवाई बमबारी पर रोक लगा सकें - जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग हताहत होते हैं - तो हमें इस शस्त्र के उपयोग की कोई जरूरत ही नहीं होगी कदापि नहीं.

हमारा विश्वास है कि ऐसा होना सम्भव है. जनता स्वयं व्यापक राजनीतिक आन्दोलन से और उनके हमलों का अपने शस्त्रों से जवाब देकर सलवा जुडूम को खत्म कर देगी. शस्त्रों का उपयोग हमारे (पीएलजीए) जन मुक्ति गुरिल्ला सेना और जन मिलिशिया द्वारा किया जाता है ताकि दुश्मनों के प्राणघाती शस्त्रों से मुकाबला किया जा सके. जो स्थानीय जनता के शांतिपूर्ण आन्दोलन को कुचलने के लिए उनका उपयोग करते हैं. दरअसल सलवा जुडूम और पुलिस, अर्धसैनिक बलों के व्यापक अत्याचारों ने जनता को अपनी आत्मरक्षा के लिए बड़ी संख्या में खुद को सशस्त्र बनाकर खुद सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी. अपनी आत्मरक्षा की उनका अधिकार है जिस हेतु वे किसी भी किस्म के शस्त्र का

उपयोग कर सकते हैं.

5. अवयस्क किशोरों के प्रशिक्षण की बात हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी नीति और जन मुक्ति गुरिल्ला सेना के संविधान में प्रशिक्षित हेतु न्यूनतम उम्र 16 साल पूरी होने पर ही भर्ती किए जाने का नियम है. इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है. इस युद्ध क्षेत्र में परिस्थिति ऐसी है कि 16 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते किशोरों को राजनीतिक और मानसिक परिपक्वता आ जाती है. क्योंकि वे बचपन से ही जाने-अनजाने विभिन्न राजनैतिक क्रान्तिकारी कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं. वे बुनियादी शिक्षा और राजनीतिक प्रशिक्षण अपने अल्पायु में ही लेने लगते हैं जबकि उनकी सांगठनिक अनुभव उन्हें 'बाल संगठन' में मिलता है.

किन्तु अब दुश्मनों ने इस पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल दी है. क्योंकि 'सबको मारो, सबको जलाओ, सबको नष्ट करो'' की नीति के तहत अब वे बुढ़ों और बच्चों को भी नहीं बख्शते. ऐसे बूढ़े और बच्चे भागकर जंगलों में शरण लेते हैं और अपनी जान बचाने की खातिर शस्त्र भी धारण करते हैं. जबकि दुश्मन हर तरह से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को ठेंगा दिखा रहा है. दमित-शोषित जनता को भी पूरा अधिकार है कि वह शस्त्र धारण करे और लड़े. उम्र को आधार बनाकर विवाद करना व्यर्थ है जहां जन शत्रु बच्चों को भी निर्ममतापूर्वक जान से मार रहा हो. यदि लड़के और लड़कियां शस्त्र त्याग दें तो उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा. सभ्य समाज के बुद्धिजीवियों को यहां की अमानवीय क्रूर परिस्थिति को समझकर जन पक्ष में आना चाहिए न कि आदर्शवादी प्रश्न उठाकर जनता को भीरु न बनाएं.

केन्द्रीय सुरक्षा बलों द्वारा कैम्प के रूप में उपयोग किए गए शाला भवनों को ध्वस्त करने के विषय में यहां की जनता या पार्टी की राय सकारात्मक है. यहां कोई गलती नहीं हुई. शाला भवन पर सशस्त्र बलों का कब्जा होते ही वह जनता का यातनागृह बन जाता है और उसका उपयोग पुनःशाला भवन के रूप में होनी की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं दिखती. कई गांवों में जहां अब तक कोई शाला भवन नहीं था वहां भी युद्ध स्तर पर सीमेंट कंक्रीट के शाला भवन बन रहे हैं. तथा कथित आजादी के 60 वर्षों बाद बन रही ये सीमेंट कंक्रीट की इमारतें पढ़ने-पढ़ाने के लिए न होकर, दरअसल जमीनी सुरक्षा तंत्र के विचार के लिए आवश्यक अधोसंरचना के रूप में है. ग्रामीण जनता भी जानती है कि ये इमारतें क्यों बन रही हैं. यही वजह है कि उन्होंने ऐसे भवनों को ध्वस्त करने का

फैसला किया है और हमारी पार्टी पुख्ता रूप से जनता के साथ है.

आदिवासियों की शिक्षा ऐसे शाला भवनों के ध्वस्त होने से प्रभावित नहीं होती जिसमें सशस्त्र बलों और सलवा जुडूम के गुण्डों द्वारा .... समूची गांव को ध्वस्त किए जाने हुई. जून 2005 से अब तक 900 से अधिक गांव उजाड़े जा चुके हैं. जुलाई के मध्य में हजारों छात्रों ने सड़कों पर नारे लगाकर अपनी शिक्षा की मांग की जो सलवा जुडूम की गुण्डागर्दी से अस्त-व्यस्त हो चुकी थी. साथ ही पुलिस और सलवा जुडूम वालों के खिलाफ इस अव्यवस्था को फैलाने का आरोप लगाते हुए नारे भी बुलंद किए. हम सबको गांवों कस्बों के शाला भवनों, महाविद्यालय भवनों से केन्द्रीय सुरक्षा बलों व पुलिस को हटाये जाने की मांग करनी चाहिए. सलवा जुडूम के गुण्डों द्वारा गांवों को उजाड़ने, शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ गुण्डागर्दी खत्म करने की ग्रामीण जनता को उनके गांवों में कथित पुनर्वास शिविरों से वापस जाने देना चाहिए तथा शिक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए तथा शिक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए. शाला की इमारतें तो कुछ ही गांवों में तोड़ी गई हैं जहां भी व्यक्ति अब नहीं रहता. फिर भी आप इससे शिक्षा में बाधा समझते हैं. बेहतर होगा कि आप सोच का दायरा बढ़ाकर देखें कि जहां जनता रहेगी वहीं बच्चे रहेंगे तभी शाला भी उपयोगी होगी. हम उत्सुकतापूर्वक यह जाना चाहेंगे कि आप उन सैकड़ों गांवों में - जहां कोई माओवादी दहशत नहीं है - स्कूल भी नहीं हैं? अब आप खुद यह फैसला करें कि दन्तेवाड़ा क्षेत्र की अशिक्षा हेतु कितने जिम्मेदार है?

6. एक और सफेद झूठ - जबसे माओवादी आन्दोलन की पहचान बनी तभी से समाज के वर्ग द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि हम विकास विरोधी हैं. हम लोगों को मताधिकार के प्रयोग से रोकते हैं तथा सरकार पोषित विकास कार्यों में भागीदारी करने से मना करते हैं. हमें दुखद आश्चर्य इस बात पर हुआ कि आप भी इस पर यकीन कर गए जो सरकार और बिके हुए मीडिया का भ्रमक प्रचार अभियान है. आपने लिखा है - ''विकास न होने की सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं थोपी जा सकती, जनता को मतदान का अधिकार है, सड़क निर्णाम योजना में काम करने, पंचायत से मदद प्राप्त करने आदि सभी को आपकी पार्टी विरोध करती है.''

क्या हम सचमुच विकास न होने के जिम्मेदार हैं? हमने कभी भी, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि कभी भी हमने सरकार की किसी ऐसी योजना का विरोध नहीं किया जो वास्ताव

में जनता के जीवन में सुधार कर सकती हो. आप हमारे इस ...... की स्वतंत्र जांच कर सकते हैं. उन शिकायत कर्ताओं की बात पर न जायें जो इस बात पर दुखी हैं कि सरकारी पैसों का प्रवाह रुकने से उनकी जेबों में पहुंच सकने वाली रकम रुक गई. ऐसे लोगों में महेन्द्रकर्मा, उनके गुर्गे तथा तमाम शोषक गैर आदिवासी लोग ही हैं.

हमारी पार्टी प्रवक्ता ने पहले ही बाताया है कि विकास का कैसा मॉडल हमारी पार्टी को पसंद है. इसका विशुद्ध विवरण इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित भी हुआ अतः मैं इस पर कोई विस्तार नहीं करुंगा. मुख्य मुद्दा यह है कि हम ऐसे विकास के विरोधी हैं जो जनता के जीवन में बवंडर खड़ा कर दे. आपको पता चल गया होगा कि कैसे एस्सार और टाटा ने बन्दूक के जोर पर फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेजों पर आदिवासियों की सहमति प्राप्त की. (द्रष्टव्यः डॉउन टु......... अक्टूबर 31, 2006) झारखण्ड से लेकर आन्ध्रप्रदेश तक व्याप्त आदिवासी पट्टी में अकूत प्राकृतिक संपदा है और तमाम बड़े लोगों की लालची नजर उस पर है. इसलिए वे कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते चाहे इसके लिए उन्हें मूल निवासियों का संहार ही क्यों न करना पड़े. सारे गांव को जमींदोज करना पड़े या बुनियादी अधिकारों की कभी अनदेखी करनी पड़े. सिर्फ तीन राज्यों झारखण्ड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही तीन लाख करोड़ रुपयों से अधिक का पूंजी निवेश किया गया ताकि लोहा और एल्युमिनियम के इन सामन्तों की तिजोरी में उसका कई गुना अधिक मुनाफा जमा हो साम्राज्यवादी देशों को भी इसका लाभ मिले. और कर्मा जैसे कथित आदिवासी नेता भी इसमें मोटा कमीशन पात्र की गरज से इस इलाके से माओवादियों की सफाई में जुटे हुए हैं. सलवा जुडूम के पीछे का वास्तविक तर्क यही है.

हमने सभी सड़कों या रेल मार्गों के निर्माण पर कोई आम पाबंदी नहीं लगाई है. हम सिर्फ उन्हीं सड़कों और रेलमार्गों का विरोध कर रहे हैं जो इस क्षेत्र की संपदा को लूटने अथवा सशस्त्र बलों की आवाजाही के लिए बनाए जा रहे हैं. वाल्टेयर से किरंदुल तक रेल लाईन तो इसी गरज से बनी थी कि यहां का कच्चामाल जापान जैसे साम्राज्यवादी देश तक पहुंच सके ठीक वैसे ही जैसा कि उपनिवेश काल में ब्रितानी किया करते थे. यह एक ऐसी गोपनीय बात है जिसे सभी जानते हैं. रावघाट से जगदलपुर तक रेल मार्ग का प्रस्ताव भी इसी दृष्टि से बना है. क्या आप जैसे ज्ञानी बुद्धिजीवी भी ऐसी विशाल विकास परियोजनाओं का समर्थन करेंगे जिससे व्यापक स्थानीय आबादी की

बर्बादी हो और उनका जीवन दयनीय हो जाए.

हम आदिवासियों की इस जायज मांग का समर्थन करते हैं कि इस क्षेत्र के कच्चामाल पर उनका अधिकार है, कि विकास के नाम पर चाहे वह लोहा कारखाना ही क्यों न हो – उनका विस्थापन नहीं होना चाहिए. और क्षेत्र के लूट की खातिर रेलमार्ग या सड़कें नहीं बनना चाहिए. इन विशाल परियोंजनाओं, रेल, सड़कों के विरुद्ध संघर्षरत आदिवासियों के साथ हम पहली पंक्ति में खड़े होते हैं. क्योंकि इनका निर्माण आदिवासी इलाके की सम्पत्ति को लूटने के उद्देश्य से हो रहा है. आदिवासी इलाके की सम्पत्ति को क्षेत्र से या देश से बाहर ले जाने से रोकने की खातिर चल रहे संघर्ष में हम आप जैसे जनतांत्रिक बुद्धिजीवियों का समर्थन चाहते हैं. हमारे पास विकास का अपना मॉडल है जिसका अवलोकन आप हमारे उन इलाकों में कर सकते हैं. जहां हमने वास्तविक जनतांत्रिक शासन स्थापित किया है. आप अच्छी तरह जानते हैं कि अधिकांश विकास मंद का पैसा वास्तविक जरूरत मंदों तक कभी नहीं पहुंचता. विकास की इतनी गाथा ही क्या पर्याप्त नहीं?

बड़ा मेजदार आरोप लगाया है आपने हम पर कि हम लोगों को मतदान करने से रोकते हैं. यह आरोप लगाने वाले वही लुटेरे हैं जो जनता के उन बुनियादी अधिकारों को अपने जूतों तले रौंदते हैं जिनकी गारंटी कथित संविधान देता है. जब माओवादी चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते हैं तब ये बौखला जाते हैं. यहां हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनता को न केवल मतदान का अधिकार है वरन चुनाव बहिष्कार का भी अधिकार है. किन्तु इस अधिकार को बन्दूक के जोर पर लूटने के लिए भारी तादाद में सशस्त्र बलों को लगाया जाता है जो डरा-धमकाकर जनता को अपने दमनकारियों, शोषकों के पक्ष में मतदान करने को बाध्य करते हैं. इसका सबसे घृणित रूप आन्ध्रप्रदेश में देखा जा सकता है. जहां न केवल वोट न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती है वरन जबरन घसीटकर मतदान केन्द्रों तक लाने का काम भी होता है. छत्तीसगढ़ में भी पिछले विधान सभा चुनाव, 2003 में हेलिकॉप्टरों से माओवादियों को रुकावट डालने से रोकने के नाम पर – जनता को भयाक्रान्त किया गया, भारी तादाद में अर्धसैनिक बल लगाए गए. जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियों को अपने पक्ष में प्रचार करने का अधिकार है ठीक उसी तरह माओवादियों को भाकपा (माओवादी) को भी इस चुनाव के बहिष्कार का अधिकार है जो उनके दमन के लिए ही होते हैं. लोगों

को मताधिकार प्रयोग करने से रोकने के लिए हमने कभी बल प्रयोग नहीं किया. इसका प्रमाण आप हमारे संघर्ष क्षेत्र में लोगों से मिलकर पा सकते हैं.

चुनाव का बहिष्कार हमारी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है. जिसके जरिये हम दमित-शोषित जनता को लामबन्द करते हैं, संगठित करते हैं संघर्ष हेतु प्रेरित करते हैं ताकि जनता यह समझ सके कि वर्तमान व्यवस्था सड़-गल चुकी है जिसे जनयुद्ध के जरिए उखाड़ फेंकना जरूरी है. ऐसा होने के बाद ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकार का चुनाव संभव है. इस उद्देश्य से, पार्टी की अगुवाई और जन मुक्ति गुरिल्ला वाहिनी (पीएलजीए) की सुरक्षा में दन्तेवाड़ा-बस्तर की दमित शोषित जनता न केवल चुनावी पाखंड का बहिष्कार करती है जो शोषकों द्वारा जनता पर थोपा गया है बल्कि अपने नवगठित राजनीतिक सत्ता केन्द्रों के लिए 'जनता की सरकार' का चुनाव भी गहन राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ करती है .

7. मैं आपके 7वीं और 8वीं सवालों को एकसाथ हल करुंगा क्योंकि ये दोनों परस्पर संबंधित हैं. ये दोनो ही प्रश्न जनयुद्ध की रणनीति और - हमारी पार्टी और जनता के बीच एक बनावटी दीवार खड़ी करने की कोशिश है. जैसा कि हमारी पार्टी के एक महान संस्थापक सदस्य कॉ. चारु मजुमदार ने चिन्हित किया ''जनहित ही पार्टी का हित है''. किसी भी वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कोई और हित हो ही नहीं सकता सिवाय जनता के हित के. वे हमारे सशस्त्र दल नहीं जो वास्तविक युद्ध लड़ रहे हैं बल्कि जनता खुद ही यह लड़ाई लड़ रही है.

हमारा दृढ़ विश्वास है कि जनता, सिर्फ जनता ही इतिहास गढ़ती है. उन्हें खुद ही स्वयं को तमाम किस्म के तमाम किस्म के दमन से मुक्ति पानी है. कल यदि कम्युनिस्ट पार्टी खुद सत्ता पाने के बाद अपना रंग बदलकर नौकरशाही व्यवस्था कायम कर दे - जैसाकि रूस और चीन में हुआ तो जनता उनसे भी कड़ा संघर्ष करेगी. हमारी पार्टी और सशस्त्र दल सिर्फ उत्प्रेरक हैं जो जनता को उनकी मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं. वास्तविक नायक तो जनता ही है. हमले सिर्फ उनके जागरण और मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी सिद्धान्तों से उन्हें सुसज्रित करते हैं. यही सिद्धांत सही विधि से समझ हासिल करने के बाद उनके शक्ति और उर्जा का संचार करती है. हमारी पार्टी और जनमुक्ति गुरिल्ला वाहिनी (पीएलजीए) दुश्मन के दमन की पराकाष्ठा झेलकर भी सक्रिय रहेंगे क्योंकि हमारी रक्षा करने हेतु जनता स्वयं हमारे चारों ओर फौलादी किला बनाकर खड़ी रहती है. पार्टी

और जनता के मध्य का द्वंदात्मक सम्बन्ध समझना जरूरी है. वरन जनता और पार्टी को अलग-अलग देखने की गलती होना स्वभाविक है.

आप जब हम से पूछते हैं कि क्या हम ''सशस्त्र संघर्ष करके बदतर दमन को न्यौता नहीं दे रहे हैं'' मैं कहता हूँ ''हां! किन्तु बिना सशस्त्र संघर्ष के तो जनता बेइज्जत होकर गुलामी में रहेगी तथा भुखमरी में दर-दर की ठोकर खाते खत्म हो जाएगी - या कीड़े-मकोड़ों की तरह खत्म कर दी जाएगी.'' इसी लिए हमारा नारा ''भूख की शिकार होकर मरने बेहतर है संघर्ष करते हुए मरो'' जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ है. आपको यह तिलमिलाने वाली जानकारी होगी ही कि पिछले एक दशक में भूख और बीमारी से मरने वालों की संख्या पिछली दो शताब्दियों में क्रान्तिकारी युद्धों में मारे गए लोगों की संख्या से कहीं अधिक (अनुमानतः पांच गुना) है?

सत्ताधारी वर्ग न तो राजनीतिक सत्ता छोड़ेगा न ही अपना शोषण, दमन और जनता पर अत्याचारों में कोई कमी करेगा जब तक कि उसे जबरिया उखाड़ फेंका न जाये. क्या बेइज्जत गुलाम होकर दब्बू, शांतिपूर्ण विरोध करते हुए जीना है (सरदार सरोवर के विस्थापित लोग दो दशकों बाद भी बिना कुछ हासिल किए शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं - यह एक उदाहरण काफी होगा) या फिर शस्त्र उठाकर उस आधार को ही खत्म करना है जो सभी के दमन, शोषण और अत्याचार की जननी है - ताकि स्वतंत्र, मानवीय जीवन जीना चाहिए. हमारा सशस्त्र संघर्ष मानवता ...... के इतिहास पर हमेशा के लिए पर्दा डालकर एक वास्तविक मानवीय इतिहास की नई सुबह लायेगा जहां जनता स्वयं अपने तकदीर का निर्माण करेगा. न कि कुछ गिने चुने सरमायादारों और कार्पोरेटों के मातहत होकर रहेगी.

हमारी पार्टी को कितना जन समर्थन है यह तो कोई भी जाकर जांच सकता है. सैकड़ों गांवों में पुलिस को एक भी मुखबीर नहीं मिला जिस कारण दमन करना उनके लिए दूभर हो गया. दर असल, यह जनता का अकूत समर्थन ही है जो हमें मिला है. वहीं सत्ताधारी वर्गों को बैठकर सोचने के लिए बाध्य किए हुए हैं कि सशस्त्र बलों के अलावा भी इनका दमन कैसे हो? इस तरह सलवा जुडूम एक .... के तहत पैदा हुआ ..... हेतु गैर आदिवासी शोषकों, जन अदालतों में दंडित किए गए आदिवासी, ... विरोधी कार्रवाईयों में लिप्त रहते हैं तथा हमारे संघर्ष क्षेत्र से बाहर के लोगों को जुटाया गया. मतदान के समय कई गांवों में एक भी वोट नहीं पड़ता जबकि प्रायः इस क्षेत्र के अन्य गांवों में भी इक्के-दुक्के ही वोट पड़ते हैं यह भी हमारी लोकप्रियता का ही

सूचक है.

9. हम आपकी अन्तिम बात से पूरी तरह सहमत हैं कि ''नागरिकों और लड़ाकुओं के बीच फर्क होना जरूरी है'' और यह कि ''जो जनता के लिए संघर्षरत हैं वे पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व सहित संघर्ष करें''. हमारी पार्टी ने हमेशा नागरिकों और लड़ाकुओं के बीच फर्क बनाए रखा है. किन्तु आप कहते हैं कि आप यह फर्क खत्म हो गया है. आपसे हमारी गुजारिश है कि आप बताएं कि कहां-कहां आपको यह फर्क नहीं दिखा. यदि आपकी सूचना सच पाई गई तो हम तत्काल इस गलती को दुरुस्त करेंगे. जिन लोगों को जबरिया सलवा जुडूम में शामिल किया गया था जोर जबरदस्ती से एसपीओ बनाया गया उन्हें हम अपना दुश्मन नहीं मानते. सरकारी राहत शिविरों में गांवों से खदेड़कर ठूंसे गए लोगों को भी हम दुश्मन नहीं समझते. जो जनता पर जिस आदिवासी जनताने इनके क्रूरता भरे जुल्मों को सहा है या देखा है वे तो एसपीओ को पुलिस और सशस्त्र बल से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं. कोई भी तटस्थ और स्वतंत्र जांच से यह सिद्ध हो जाएगा. हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बाबत हम अब और अधिक सावधानी बरतेंगे.

भवदीय

महासचिव

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
पूर्वी रिजनल ब्यूरो व उत्तर रिजनल ब्यूरो

20-2-2009

संसदीय चुनाव का बहिष्कार करें !
एक जनवादी, संघीय भारतीय गणतंत्र के निर्माण के लिए
नव जनवादी क्रान्ति को सफल करें !!

(नव जनवादी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में ली जाने वाली कुछ नीतियों की एक झलक)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया की स्थिति ऐसी न रही कि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों में प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन चला सके। तब दुनिया में नव औपनिवेशिक शोषण का दौर शुरू हुआ। 1947 में हमारे देश भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन खत्म हुआ। देश को औपचारिक (नकली) आजादी मिली पर एक बहुत बड़ी कीमत पर। धर्म के नाम पर, अंग्रेजों के षडयंत्र के परिणामस्वरूप व देशी दलाल शासकों के मिलीभगत से, अभूतपूर्व खून-खराबे के बाद देश का विभाजन हुआ। भारत का बड़ा पूंजीपति वर्ग व जमीन्दार वर्ग पूरे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के दलाल मददगार व विश्वस्त सेवक बने रहे व अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का शोषण करते रहे। इन्हीं दलाल पूंजीपतियों व जमीन्दारों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण हुआ व इन शासक वर्गों की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आई। इस तरह भारत एक अर्द्धऔपनिवेशिक व अर्द्धसामंती देश में तब्दील हो गया। बड़े पूंजीपति व सामन्तों की इस सरकार ने राज्य के विकास के लिए ऐसी नीति अपनायी जिससे साम्राज्यवादी (विदेशी) पूंजी व तकनीक पर देश की निर्भरता बढ़ती गयी। प्रशासन, राजनीति, संस्कृति, न्यायपालिका, सेना आदि में औपनिवेशिक ढांचा व कायदे-कानून बहुत हद तक अक्षुण्ण बने रहे, उनका कोई जनवादीकरण

नहीं हुआ। संसद, जिसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की सभा कहा गया, दरअसल उत्तर-47 भारत के सबसे बड़े झूठों में से एक है। संसद में लिये गये फैसले बड़े उद्योगपतियों व उनके तरफदार कुछ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिये गये फैसले होते हैं। संसद में किसी बिल के पास होने न होने का फैसला संसद के बाहर पैसा व ताकत के खेल से तय होता है। नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूंजीपतियों द्वारा बनाये गये 'बाम्बे प्लान' को अपनाते हुए पहले पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की। तब मंदी व विश्वयुद्ध से टूट चुके व सोवियत समाजवादी गणराज्य के प्रभाव व विकास से घबड़ाये साम्राज्यवादियों ने कींस का नुस्खा मान राजकीय (सार्वजनिक, सरकारी) पूंजी की भागीदारी अर्थव्यवस्था में शुरू की व एक 'कल्याणकारी' पूंजीवादी राज्यों का ढोंग सामने लाया। तब भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरे हाल में थी। ठहरी हुई बाजार व्यवस्था, औद्योगिक विकास के ढांचागत सुविधाओं व उसके लिए पूंजी के अभाव ने शासकों के सामने राजकीय पूंजी की बड़े पैमाने पर जरूरत को सामने लाया। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर निजी व सार्वजनिक क्षेत्र अस्तित्व में आये जो साम्राज्यवादी बाजार, उनकी पूंजी (कर्ज) व तकनीक के उपर आश्रित थे। सरकारी देख रेख में, पंचवर्षीय योजनाएं अपेक्षाकृत नये साम्राज्यवादपरस्त देशी दलाल पूंजीवाद को मजबूत करता गया। 'कल्याणकारी राज्य' का दावा करने के बावजूद शिक्षा, चिकित्सा जैसी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च घटते गये। तंगहाली व भूखमरी बढ़ती गयी। सन् 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे (वैसे लोग जिनकी आमदनी प्रतिदिन 20 रू. या उससे कम थी)

हमारी पार्टी मानती है कि समस्याओं की जड़ इस तथाकथित लोकतंत्र के बुनियाद में है। भारत की जनता ने केन्द्र में व प्रांतों में कई सरकारों को बदला। पर फायदा क्या हुआ? वर्त्तमान तंगहाली व भूखमरी किसी एक सरकार के कारण नहीं बल्कि पिछले 60 सालों से शासक वर्गों के विभिन्न सरकारों द्वारा

ली गयी नीतियों का परिणाम है। हमारी पार्टी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए संघर्षरत है। चुनाव इस व्यवस्था के बुनियादी आधार अर्द्ध–उपनिवेशवाद, अर्द्ध–सामंतवाद को बदले बिना सरकारों को बदलती है। यह सिर्फ मुखौटा बदलने के बराबर है। हम दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिये भारत के शासकों–दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों (बड़े पूंजीपति) व जमीन्दारों– व उनके आका साम्राज्यवाद की सत्ता खत्मकर शोषित–उत्पीड़ित जनता यानी मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ (छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, साधारण सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी, आदि) व राष्ट्रीय बुर्जुआ (छोटे व मंझोले उद्योगपति) के संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाना चाहते हैं। **प्रसंगवश हम बता दें कि हम किसी भी आतंकवादी कार्रवाई, जिनमें बेकसूर लोगों की हत्या की जाती है, के हम सख्त खिलाफ हैं। हम जन–दिशा व वर्ग–दिशा पर सख्ती से अमल करते हैं व शोषित–पीड़ित जनता को गोलबंद करके ही क्रान्तिकारी परिवर्त्तन लाना चाहते हैं** ऐसी सरकार नव जनवादी क्रान्ति सफल होने के बाद ही बन सकती है। यह नई जनवादी सत्ता राजनीति व अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल देगी व एक आत्मनिर्भर, जनवादी व स्वतंत्र भारत की निर्माण करेगी व उसे मजबूत करेगी। ऐसा भारत सचमुच धर्मनिरपेक्ष व विभिन्न राष्ट्रीयताओं का स्वैच्छिक संघ होगा। भारत को ऐसा बनाने के लिए क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा की सरकार के नेतृत्व में नव जनवादी सत्ता विभिन्न क्षेत्रों में जो कदम उठायेगी उसकी एक अति संक्षिप्त झलक हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

एक नये संविधान की आवश्यकता

सर्वप्रथम नये व्यवस्था के लिए नये संविधान का होना जरूरी है। दरअसल वर्त्तमान भारतीय संविधान ही वह आधार प्रदान करता है जो न सिर्फ पूंजी के असीम भंडारण व उससे उपजे समृद्ध व निर्धन की विशाल इकाई को बरकरार रखता है बल्कि यही भारतीय समाज के अन्य अन्तरविरोधों को भी

जिन्दा रखता है या जन्म देता है, जैसे: खेती में अर्द्ध-सामंती सम्बंध, उद्योग में दलाल बड़ी पूंजी का प्रभुत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्द्ध-औपनिवेशिक चरित्र, केन्द्र राज्य के बीच अन्तरविरोध, एक पाखंडपूर्ण संघीय गणराज्य, राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न, साम्प्रदायिक व जातीय उत्पीड़न, महिलाओं के साथ भेदभाव आदि। इन अन्तरविरोधों को हल करने हेतु, एक संवैधानिक आधार अनिवार्य है। इसलिए एक नया संविधान लिखे जाने की आवश्यकता है। नया राज्य नये संविधान पर आधारित होगा।

एक मुक्त कृषि क्षेत्र

यह कृषि में शोषणमूलक उत्पादन-सम्बन्धों को खत्म करेगा व साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कृषि की निर्भरता खत्म कर वास्तविक कृषि विकास करेगी। अभी देश की कुल खेती योग्य जमीन का 30 प्रतिशत जमीन्दारों के कब्जे में हैं तथा कुल किसानों में से 65 प्रतिशत भूमिहीन गरीब किसान हैं जिनकी जोत एक हेक्टेयर से भी कम है। नव जनवादी राज्य जमीन्दारों, मठाधीशों की सारी जमीन जब्त करेगा व 'जोतने वालों को जमीन' के आध ार पर भूमिहीन गरीब किसानों व खेतीहर मजदूरों के बीच अतिरिक्त जमीन का बंटवारा करेगा। यह भूमिहीन व गरीब किसानों के सारे सरकारी (बैंक) व साहूकारी कर्ज को रद्द कर देगा व व्यापार धंधों को अपने नियंत्रण में लायेगा। यह सहकारी खेती को प्रोत्साहन देगा। जनता का श्रम व पूंजी ही इस सहकारिता के मुख्य संघटक होंगे जबकि इसमें कुंजीवत पहलू श्रम है। उपभोक्ता व ऋणदाता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह पूंजीवादी फार्मरों के बड़े फार्म, कारपोरेट सेक्टरर्स के फार्म, फार्म हाउस व बागान आदि की सारी जमीन जब्त कर उनपर सामूहिक खेती कराये जाने को प्राथमिकता देगा।

सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के बजाय जमीन के बनावट के अनुसार छोट-दोटी परियोजनाओं को प्रश्रय देगी।

ताकि पर्यावरण क नुकसान व विस्थापन से बचा जा सके। किसी बड़ी परियोजना को अनिवार्यत: स्थानीय जनता की सहमति से व पर्यावरण का ख्याल रखकर ही बनाया जायेगा।

बाजार के उतार-चढ़ाव व कर्ज के बोझ से यह किसानों को आजाद करेगा। यह विश्व व्यापार संगठन से बाहर आयेगा व किसान विरोधी हर घरेलू नीतियों को खारिज कर देगा। खेती में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषणकारी घुसपैठ को बंद किया जायेगा। खेती में नपुंसक संकर बीजों व बंजर बनाने वाले कृषि आगतों को प्रतिबंधित किया जायेगा व मिट्टी व जलवायु को ध्यान मे रखकर देशी बीजों व खादों के प्रयोग एवं उसके अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा। यह कृषि में जरूरी चीजों में सहकारी समितियों व छोटे किसानों को सब्सीडी देगा यह सबसे पहले खाद्यान के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनायेगा व सब्सीडी देकर सस्ते दामों खाद्यान के बंटवारे को सुनिश्चित करेगा। यह सरकारी योजनाओं में खेती पर खर्च को बढ़ायेगा व इसे प्राथमिकता देगा।

एक आत्म निर्भर व स्वतंत्र उद्योग क्षेत्र

नव जनवादी राज्य उद्योग धंधों को साम्राज्यवादी नियंत्रण से पूरी तरही मुक्त कर देगा व इसे आत्मनिर्भर बनायेगा। यह साम्राज्यवादी व दलाल बड़े पूंजीपतिों की तमाम औद्योगिक व बैंकिंग पूंजी, सटोरियों की पूंजी, उनके जमीन, भवन, बागान आदि, बड़े नौकरशाहों की अकूत संपत्ति व बैंकों में उनकी जमा राशि को जब्त करेगा। यह बड़े पूंजीपतियों, विदेशी पूंजीपतियों के तमाम फैक्टरियों, बैंकों, इन्श्यूरेंश कंपनियों, अन्य वित्तीय निगमों, आर.डी. विभागों आदि का राष्ट्रीयकरण कर देगा। यह बड़े उद्योगों में किसी भी किस्म के निजी पूंजी के अस्तित्व को खत्म कर देगा। यह शासक वर्गों द्वारा किसी भी साम्राज्यवादी वित्तीय संस्था या देश से लिये गये कर्जों को (जो दरअसल उन्हें मोटा करने में खर्च हुए हैं) को रद्द कर देगा। यह आईएमएफ, विश्व

बैंक आदि साम्राज्यवादी संस्थानों से किये गये उन समझोतों को भी रद्द कर देगा जो हमारे उद्योग को निर्भरशील व प्रजीवी बनाते हैं। यह निजीकरण व उदारीकरण के साम्राज्यवादपरस्त नीतियों को खारिज कर देगा। यह आमतौर पर सरकारी पूंजी को मजबूत करते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी के संचयन पर एक सिलिंग लगायेगा। कृषि को आधार बनाकर ही उद्योगों की स्थापना व विकास होगा। यह श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी।

आज संगठित क्षेत्र में मात्र 7.26 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। यह उद्योगों में रोजगार को प्राथमिकता देगा, न कि मुनाफे को। यह मजदूरों के सन्दर्भ में कहीं भी ठीका प्रथा को समाप्त करेगा। यह महिला व पुरूष के लिये समान मजदूरी दर कायम करेगा। यह बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म कर देगा। नव जनवादी राज्य तमाम सेज (विशेष आर्थिक जोन) को रद्द कर देगा।

नवगठित सरकार छोटे व मंझोले उद्योगों को संरक्षण देगा। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के उद्योग धंधों को सीमित व नियंत्रित करेगा व उद्योगा एवं व्यापार वाणिज्य के चहुंमुखी विकास के लिए सहकारिता आंदोलन को भरपूर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

एक वास्तविक स्वैच्छिक संघ का निर्माण

नव जनवादी राज्य बंदूक के बल पर किसी भी राष्ट्रीयता को भारतीय संघ में रखने का हिमायती नहीं जैसा कि अभी किया जा रहा है। कश्मीर को 5 लाख भारतीय फौज ने बूटों से रौंद रखा है। मणिपुर, नगालैंड व असम समेत तमाम उत्तर–पूर्वी प्रांतों को वस्तुतः सैनिक राज्य में तब्दील कर दिया गया है। नवगठित राज्य तमाम राष्ट्र्यताओं के अलग होने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देकर तथा उन सबों को समान मर्यादा देकर समानता के आधार पर देश को एकताबद्ध करेगा। जो राष्ट्रीयता भारतीय संघ में रहना चाहेंगे उन्हें रक्षा मंत्रालय, विदेश नीति, मुद्रा का चलन आदि पर छोड़ तमाम आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक मामलों में स्वायत्ता रहेगी। इस तरह

जनवाद व आपसी सहमति पर आधारित होकर संघीय गणराज्यों के स्वैच्छिक संघ की स्थापना यह राज्य करेगा। यह राज्य सभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं को समान दर्जा देगा। यह बिना लिपि की भाषाओं के विकास में सहायता करेगा। राष्ट्र भाषा या सम्पर्क भाषा के नाम पर या किसी भी रूप में यह राज्य दूसरी राष्ट्रीयताओं पर किसी भी भाषा को नहीं थोपेगा, बल्कि सर्वसम्मति से एक आम रूप से स्वीकृत भाषा का विकास करने का प्रयास करेगा।

एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण

धर्मनिरपेक्ष होने की संवैधानिक घोषणा के बावजूद भारतीय सत्ता 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' के अंधराष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। नव जनवादी राज्य किसी भी किस्म की सांप्रदायिकता, खासकर बहुमत की साांप्रदायिकता, व राज्य के सांप्रदायिकरण के खिलाफ है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार व धर्म-आधारित सामाजिक असमानताओं को समाप्त करेगा। यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये विशेष नीतियों को लागू करेगा। यह धार्मिक मामलों में राज्य की दखलंदाजी समाप्त करेगा, साथ ही यह राजनीतिक उद्येश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगायेगा। यह धर्म को मानने और न मानने की व्यक्तिगत आजादी की गारंटी करेगा।

एक जनवादी संस्कृति का निर्माण

भारतीय समाज हजारों साल से जाति में विभाजित ब्राह्मणवादी सामाजिक रीति व अंध कुसंस्कारों पर आधारित एक समाज रहा है। ब्राह्मणवाद यहां के सामंतवाद की सांस्कृतिक रीढ़ है। नवगठित राज्य घृणास्पद जातिप्रथा, जहां जन्म के आधार पर सामाजिक तौर पर कोई ऊंच-नीच होता है, छुआछुत, भेदभाव को पूर्ण रूप से खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा और यह तबतक दलितों व सामाजिक रूप से सभी उत्पीड़ित जातियों की उन्नति के लिए

आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। यह जातीय भेद–भाव करने वालों के साथ कड़ाई से निबटेगा।

यह आदिवासियों के साथ किये जा रहे भेदभाव को खत्म करेगा। यह जल, जंगल व जमीन पर आदिवासियों–मूलवासियों के सामूहिक स्वामित्व को मान्यता देगा व उसको जन हित में इस्तेमाल हो, इसके लिए उन समुदायों को प्रोत्साहित करेगा। यह सभी आदिवासी समुदायों के सम्पूर्ण विकास के लिए उन्हें विभिन्न स्वायत्तताएँ सुनिश्चित करेगा और तदनुसार विशेष नीतियाँ लागू करेगा। यह क्षरणशील सामंती, औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी संस्कृति के स्थान पर जनवादी व प्रगतिशील संस्कृति को स्थापित करेगा।

एक सही लोकतांत्रिक राज्य व स्वस्थ्य केन्द्र–राज्य संबंध

यह नया राज्य सभी स्तरों पर जनता के जनवादी संविधान के अनुसार और उसके आधार पर क्रान्तिकारी जन समितियों और जन सरकारी परिषदों के द्वारा जनता की राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेगा। धूर्त प्रतिक्रियावादियों को छोड़कर प्रत्येक नागरिक को, जो 18 वर्ष का हो चुका है / चुकी है, सभी स्तरों पर चुनने व चुने जाने का और निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा। यह प्रतिनिधि सभाओं को गप्पबाजी का अड्डा व दिखावे का दांत नहीं, सही कामकाजी सत्ता केन्द्र के रूप में विकसित करेगा। यह भारत की राजनीति, शासन व संस्कृति मे विद्यमान सभी औपनिवेशिक ढांचों, कानूनों व प्रभावों को खत्म कर देगा।

सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति के अधिकार पर इकट्ठा होने, संगठित होने और हड़ताल व प्रदर्शन करने के अधिकारों जैसे जनवादी अधिकारों को यह राज्य सुनिश्चित करेगा। यह राजसत्ता पर जनता के नियंत्रण के अधिकार को सुनिश्चित करेगा तथा इस अधिकार को घटाने की हर कोशिश को रोकेगा।

यह केन्द्र व प्रांत क बीच अत्यंत गैर–बराबरी पूर्ण रिश्तों को खत्म करेगा। यह विभिन्न कमीशनों के सकारात्मक सुझावों के आधार पर केन्द्र व प्रांत के बीच लोकतांत्रिक महौल को कायम कर प्रांतों को यथासंभव अधिकार देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा व केन्द्र व प्रांत के बीच मौजूदा मालिक–सेवक के रिश्ते को खत्म करेगा। यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयासों के जरिये क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा।

महिलाओं को समान अधिकार

यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह पुरूष–प्रभुत्व तथा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। यह जमीन सहित सम्पति पर उनके समान अधिकार की भी गारंटी करेगा। यह सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, रंगभेद आदि महिला विरोधी कुप्रथाओं को प्रतिबन्धित करेगा व इन कार्यों में लिप्त पाये गये दोषियों को सजा देगा। यह उपभोक्तावाद व महिलाओं को माल के रूप में इस्तेमाल करने के हर साम्राज्यवादी–पूंजीवादी प्रथा जैसे: नंगे विज्ञापन, सौन्दर्य प्रतियोगिता आदि को प्रतिबंधित करेगा। यह राज्य वेश्यावृति में लिप्त महिलाओं का पुनर्वास करेगा और उन्हें सामाजिक मान्यता दिलवायेगा। यह महिलाओं को घरेलू कामकाज के जेल से मुक्त करायेगा व सामाजिक उत्पादन व अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।

एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य

यह रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा के अधिकारों को बुनियादी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा व बेरोजगारी को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह अभिजात्य केन्द्रित व देशी–विदेशी बड़ी पूंजी की सेवा करने के उद्देश्य से बनायी गयी शिक्षण पद्धति को खत्म कर एक जनवादी, सर्वसुलभ, देशज हितों व विशेषताओं को ध्यान में रखने वाली शिक्षण पद्धति को विकसित

करेगा। यह राज्य बेकारी भत्ता और सामाजिक बीमा लागू करेगा तथा लोगों के लिए बेहतर जीवन-यापन की स्थिति सुनिश्चित करेगा।

यह शारीरिक रूप से विकलांगों, मानसिक रूप से अक्षम व विकलांगों, बुजुर्गों व अनाथो तथा अपंगता से ग्रस्त अन्यान्य लोगों को उपयुक्त आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तथा एक स्वस्थ्य सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण मुहैय्या करायेगा।

यह सभी लोगों के लिए खासकर मजदूरों, किसानों व अन्यान्य मिहनतकश जनता के लिए उतम स्वास्थ्य व मुफ्त चिकित्सा की सुनिश्चितता प्रदान करनेवाली एक जनमुखी चिकित्सा प्रणाली को लागू करेगा। मुनाफा के लिए चलाये जा रहे निजी नर्सिंग होम को प्रतिबंधित किया जायेगा व चिकित्सकों का अस्पताल में जाना अनिवार्य बनाया जायेगा।

यह पेयजल, बिजली व यातायात, संचार व अन्य जनोपयोगी क्षेत्र में मुनाफे पर आधारित निजी व्यवस्था खत्म करेगा व तमाम क्षेत्रों को सरकारी दायरे में लायेगा। यह मानसिक व शारीरिक श्रम के बीच दूरी को क्रमशः घटाने का प्रयास करेगा। यह राज्य में प्रगतिशील कर-प्रणाली लागू करेगा।

जनपक्षीय न्याय प्रणाली

यह एक जनपक्षीय, प्रगतिशील और जनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सबों को सुधारने के लिए यथोचित न्याय सुनिश्चित करने वाली न्याय प्रणाली व न्याय व्यवस्था को लागू करेगा। इस दिशा में यह मंहगी न्याय प्रणाली को सस्ता व जनसमुदाय बनायेगा।

पर्यावरण व विस्थापन

मुनाफे की होड़ में दुनिया भर के पूंजीपतियों, खासकर अमरीका व बाकी साम्राज्यवादी देश के पूंजीपतियों, ने पर्यावरण का अवर्णनीय नुकसान किया है; इतना कि पृथ्वी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। यह राज्य दुनिया

के अन्य समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर साम्राज्यवादी देशों पर प्रदुषण घटाने व इसके लिए लागत देने हेतु दबाव बनायेगा। यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं, जंगल की कटाई, अन्य पर्यावरण विरोधी प्रोजेक्टों को हतोत्साहित करेगा व जरूरत पड़ने से उन्हें प्रतिबंधित करेगा।

भारत में विभिन्न परियोजनाओं में 47 से अबतक 600 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं। यह राज्य बिना जनमत संग्रह किये किसी भी स्थान पर विकास प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करेगा। किसी भी प्रोजेक्ट से हुए विस्थापन की स्थिति में सम्पूर्ण पुनर्वास व रोजगार की गारंटी के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

एक सशक्त राष्ट्र व जनवादी पड़ोसी

यह साम्राज्यवादियों के साथ मौजूदा प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी सरकार द्वारा किये गये सभी असमान, राष्ट्रविरोधी, देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाले संधियों को रद्द करेगी।

यह विदेशी पूंजी व तकनीक को समानता के आधार पर बातचीत कर जरूरत के हिसाब से स्वीकार करेगा व इसे देश में विदेशी शोषण का हथियार नहीं बनने देगा। यह देश की सुरक्षा के लिए जनता को हथियारबंद करेगा।

वर्तमान शासकों के विस्तारवादी मंसूबें के विपरीत यह राज्य अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण सम्बंध कायम करेगा। यह पड़ोसी देशों के साथ सीमा, पानी और दूसरे विवादों को शान्तिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का भरपूर प्रयास करेगा और उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करेगा। यह राज्य पड़ोसी देशों के साथ कभी भी विस्तारवादी व्यवहार नहीं करेगा।

विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के साथ सम्बन्धों में यह राज्य

निम्न पाँच सिद्धान्तों का पालन करेगा – क्षेत्रीय अखण्डता व सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक–दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, बराबरी एवं परस्पर हित तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व।

आज दंडकारण्य (द. छत्तीसगढ़), झारखंड, बिहार, ओड़ीसा, प. बंगाल, आंध्र प्रदेश व दूसरे प्रांतों में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में साम्राज्यवाद –विरोधी, सामंतवाद–विरोधी हथियारबन्द संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष का लक्ष्य नव जनवादी क्रान्ति पूरी कर नव जनवादी राज्य बनाना है ताकि अपने देश को मुक्त, आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाया जा सके। इस आन्दोलन से करोड़ों भूमिहीन व गरीब किसान, खेतीहर मजदूर, मध्यम किसान जुड़ चुके हैं व रोज अपने सपनों का भारत बनाने के लिए शहीद हो रहे हैं। शासक वर्गों की सरकार इसे किसी भी हालत में कुचल देना चाहती है। देश का मुखिया जो स्वयं अमरीका का विश्वस्त एजेंट है, और उसके सिपहसलार जो अमरीका के भरोसेमंद दलाल व सेवक हैं, इस आन्दोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। भारत की जनता इसी देश के सैन्य बलों से युद्ध लड़ने को मजबूर है। इसे शासक वर्ग 'उग्रवाद' बताकर न सिर्फ आंदोलन को बदनाम कर रहा है बल्कि जनता को झूठ बताकर उन्हें दिग्भ्रमित भी कर रहा है।

देश के संघर्षरत किसानों ने नव जनवादी राजसत्ता के भ्रूण के रूप में क्रान्तिकारी जन कमिटी (आरपीसी) को बनाना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर जिला स्तर तक की क्रान्तिकारी जन कमिटी संगठित कर ली गयी हैं। भविष्य में विकास क्रम में यही सरकार भारत के क्रान्तिकारी संघीय जनवादी सरकार के रूप में विकसित होगी। इस सरकार को जनता के विभिन्न हिस्से के लोग प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं। यह चार वर्गों – मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ, राष्ट्रीय बुर्जुआ की संयुक्त मोर्चा की सरकार है। हालांकि शासक वर्गों की सरकार इसे कुचल देने हेतु जी–जान से लगी है,

पिर भी जनता की सरकार ने अपने जनपक्षीय नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है।

तमाम देशभक्त, प्रगतिशील व जनवादी व्यक्तियों / समूहों का हम आह्वान करते हैं कि वो इस नये भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, इस युद्ध में शामिल हों व नव जनवादी राज्य बनाने के लिए वर्तमान शोषणकारी, साम्राज्यवादपरस्त राजसत्ता को नकार कर इनके प्रतिनिधि सभाओं (संसद, विधानसभा, पंचायत) के लिये होने वाले चुनावों का बहिष्कार करें।

पूर्वी रिजनल ब्यूरो व उत्तरी रिजनल ब्यूरो
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

15-3-2009

हमारी केन्द्रीय कमेटी के सदस्य और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के महान जन-मुक्ति संघर्ष के नेता का० आशुतोष और का० संदीप सहित पाँच क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी और सात दिनों तक उनके ऊपर ढाये गये क्रूरतम यातना व बर्बर पाश्विक अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हो !

शोषण उत्पीड़न व अत्याचार से मुक्ति के लिए इस अन्यायी व्यवस्था को उखाड़ फेकें ! जनता का राज कायम करने के लिए जन मुक्ति संघर्ष को तेज करें !

कामरेडो, दोस्तो और बहादूर मेहनतकश जनता।

आप जानते होंगे कि हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी और केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन के सदस्य व हमारे मुक्ति संघर्ष के नेता का0 आशुतोष उर्फ मोती लाल सोरेन को उड़ीसा की पुलिस ने 25 फरवरी 2009 को राउरकेला से अपहरण कर लिया। उनके साथ एक युवा अतुल उर्फ राजू यादव भी थे। फिर उन्हें सात दिनों तक गुप्त रुप से हिरासत में रखा गया। पूछताछ और गुप्त रहस्यों को उगलवाने के नाम पर पूरे सप्ताह भर इन पुलिस दरिंदो द्वारा अत्याचार व यातना के सारे बर्बर तरीके अपनाए गये। जिस्म के अंग-अंग को पीटकर नाकाम कर देना, शरीर के संवेदनशील अंगो में बिजली का झटका देना, उल्टा लटका कर तलवों पर डंडे से पीटना, मुर्गा बनाना, तब तक पीटना जब तक कि बेहोशी न आ जाए, फिर मारकर होश में लाना फिर पीटना, क्या-क्या जुल्म नहीं ढाया गया इनपर। वैसे आज जनता के न्यायपूर्ण संघर्षो व आन्दोलनों खासकर हमारी पार्टी के नेतृत्व में चल रहे मुक्ति संघर्षो को कुचलने के लिए जुल्म, अत्यचार व यातना के उपरोक्त तरीके अपनाना, मुठभेड़ के नाम पर हत्या कर देना आम बात हो गई है। देश की समूची शोषित उत्पीड़ित मेहनतकश जनता आज खूफिया विभाग और सरकार के खूनी बलों (एस.टी.एफ.) ग्रे हाउन्ड्स/स्पेशल एक्शनटीम/आंतकवार विरोधी दस्ता आदि के इन क्रूर काले कारनामों से परिचित हो गई है और किसी न किसी रुप के इसका अनुभव भी कर रही है। फिर भी उपरोक्त घटना से सम्बन्धित तथ्यों को एक बार जनता के समस्त पेश करना हमारी जिम्मेदारी है।

22 फरवरी, 2009 को दिन के करीब एक बजे हमारे चार कार्यकर्ता झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले के सोनुआ थाने इलाके से मोटर साइकिल से एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे। तभी सरकारी गुड़ों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर 25 फरवरी को इन्होंने का0 आशुतोष व का0 राजू का अपहरण किया। साथियों की गिरफ्तारी को गुप्त रखकर झुठी मुठभेड़ो के नाम पर गुप्त हत्या का तरीका ये सरकारी जल्लाद किस प्रकार लेते आए है, यह छुपा नहीं है। आम जनता इसे जानती-समझती है। अत: उपरोक्त साथियों (संदीप सोरेन, संजय बेसरा, अमृत हंस और हरमन मंगा) तथा आशुतोष आदि की गुप्त हत्या के षड्यंत्र व मंसूबो को सार्वजनिक करने के लिए हमने 28 फरवरी 2009 को चार राज्यों- झारखंड, उड़ीसा, बंगाल व बिहार में 24 घंटे के बंद की अपील की। जनता ने सरकारी जल्लादों और उनकी अपराधिक कार्यशैली के खिलाफ प्रचंड गुस्से का इजहार किया और हमारी समर्पित पार्टी कतार, बहादूर पी. एल. जी. ए. बलों एवं क्रान्तिकारी जनता की साहसिक पहल व सक्रियता से बंद अभूतपूर्व ढंग से सफल हुआ।

जनता के सच्चे सपूतों, इन संग्रामी जननेताओं की गुप्त हत्या की साजिश और इनपर अकथ्य उत्पीड़न के खिलाफ इस जन कार्यवाई ने शासक शोषको को आतंकित कर दिया। अंतत: 2 मार्च की शाम को उन्होंने का0 आशुतोष और राजू की अपहरणनुमा गिरफ्तारी को सार्वजनिक किया। उन्होंने गिरफ्तारी दिखाई 2 मार्च को ही। उधर 22 फरवरी को गिरफ्तार साथियों पर भी रेलवे डकैती तथा गोली-बारूद, पिस्तौल व नक्सली साहित्य रखने का आरोप लगाया। इस तरह एक तरफ तो उन्होंने गुप्त हिरासत व बर्बतम यातना को झुठलाया, दूसरे तरफ अवैध व जाली मुकदमे भी लादे। हमारी विकसित होती व फैलती जा रही सशस्त्र कृषि क्रान्ति को कुचलने के लिए स्पष्ट है कि ये जन हत्यारे ऐसे तौर तरीके ले रहे है जो उन्ही के संविधान और कानून के मुताबिक असंवैधानिक और गैर कानूनी है।

आज सचमुच ही इस जनहत्यारी शोषणमूलक वर्गीय व्यवस्था का संकट चरम पर पहुँचता जा रहा है। इस व्यवस्था के संचालक बड़े जमीदारों और बड़ पूंजीपतियों (दलाल-नौकरशाह-पूंजीपतियों) तथा उनके आका साम्राज्यवादीगण खासकर अमरीकी साम्राज्यवादी अभी चौतरफा संकटों से घिरतें जा रहे है। खासकर, इसवार की आर्थिक महा मंदी ने एक महासंकट का रुप लेकर पूरी साम्राज्यवादी विश्व-व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। साम्राज्यवादियों और उनके दलाल शासक वर्गो द्वारा अपने इस महासंकट को जनता के विभिन्न तबकों वर्गो पर लादते जाने की वजह से विभिन्न जगहों में जनता का असंतोष विद्रोह व बगावतें सशस्त्र रुप लेकर फूट पड़ रही है व फैलती जा रही है। हमारे देश में हम जनविद्रोहों व संघर्षो के तरह-तरह के रुप देख पा रहें है। फिर यहाँ राष्ट्रीयता के संघर्षो व महिलाओ, दलितों व अल्पसंख्यकों के न्यायोचित संघर्ष भी बढ़ रहे है। पर इन सबकी अगली कतार में है हमारी पार्टी के नेतृत्व के बहादूर जन मुक्ति छापामार सेना और कान्तिकारी जनसमुदाय द्वारा संचालित लोकयुद्ध व क्रान्तिकारी जनआन्दोलन का विराट उभार। इसी ने इन जनशत्रुओं को इतनी दहशत में डाल दिया हैं कि वे उन्मादित होकर ''सबको मार डालो, सब कुछ जला डालो, सब कुछ नष्ट कर दो'' की फासीवादी नीति अपना रहे है। इसी के लिए हमारे आन्दोलन को देश की अन्दरुनी सुरक्षा के लिए सबमे बड़ा खतरा बताते हुए इसे कुचलने के लिए वे अपनी भारी ताकत झोंक रहें है। साम्राज्यवादियों खासकर उनकी खूफिया संस्थाओं सी.आई.ए, एफ. बी. आई., मोसाद आदि के प्रत्यक्ष निर्देशन में उनकी दमनात्मक

नीति एल आई सी (कम तीव्रता के युद्ध की नीति) की नीति के तहत हमारे आन्दोलन को कुचलने के लिए वे कमर कस कर उतर पड़े है ''नेताओं का पता लगाओं पकड़ो मार डालो'' इसके लिए जघण्यतम तौर तरीका भी लेने में न हिचको यह उनकी दमन नीति का मूलमंत्र है। इसी के तहत उन्होंने 70 साल के वृद्ध साथियों हमारे केन्द्रीय कमेटी के नेताओं-वरुण दा और विजय दा को नाजायज तरीके से कैद में रखा है उनपर जाली मुकदमा लादते जा रहे है और बीमार साथियों पर भी दमन की क्रूरता की हदें पार कर रहे है। साथ ही उन्होंने हमारे और भी केन्द्रीय नेताओं-

और अब का0 आशुतोष को गिरफ्तार कर काल कोठरियों में यातना दे रहे है। दमन की पाशविकता की सारी हदे पार कर रहे है। इन दमनात्मक तौर तरीको ने यहाँ तक कि निर्पेक्ष न्यायपालिका के भी सहयोग से रिमाण्ड पर लेकर पाशविक अत्याचार की इनकी बर्बरता ने इनके कथित लोकतंत्र की मानवाधिकार की वास्तविक असलियत को बेपर्द कर दिया है, जनता समझ रही है कि कथित लोकतंत्र की आढ़ में यहाँ जो चल रही है, वह बड़े जमीन्दारों व बड़े पूंजीपतियों की तानाशाही है।, कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल सामंती निरंकुशता की सी स्थिति है। तकरीबन समूची मेहनतकश जनता को ही उपरोक्त स्थितियों को रोज-ब-रोज भुगतना पड़ रहा है।

दूसरी ओर शासक वर्गों की तिकड़ी-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपलिका में खुल्लम-खुल्ला तौर पर कमश: 70%, 35% और 35% संख्या अपराधियों, घोटालेबाजों, घूसखोरों, दलालों, हत्यारे, लूटेरों, डकैतों, बलात्कारियों और कबूतरबाजों की है, ऐसे जनविरोधियों व समाज विरोधियों की है, जिनकी हरकतें असंवैधानिक, गैर कानूनी और अवैध है, जिन्हें स्पष्टत: इनका संविधान अपराध की संज्ञा देता है। ये सारे के सारे मिलकर शोषण, अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न पर आधारित व्यवस्था के संचालन में शामिल हैं, और जनता तथा उनके पक्ष में संघर्षरत शक्तियों पर दमन व जुल्म ढाने में पूरी तरह एकजुट होकर काम करते है।

स्पष्ट है कि आज पूरा भारत इस साम्राज्यवादी-सामंती शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार के खिलाफ सीना तानकर उठ खड़ा हो गया है। चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, पंजाब हो, कश्मीर हो या देश के भीतर कृषि क्रान्ति का बढ़ता ज्वार मजदूर, किसानों व मेहनतकश जनता के मुक्ति के उफान भरते सपने अपने भीषण संघर्ष का फहराती व ललकारती प्रचण्ड वेगवाना धारा और उफनते नक्सलवाद की उत्ताल तरंगों ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया है। देश के कुछेक हिस्से में हमारे नेतृत्व में चल रही जनता की कान्तिकारी सरकार इस व्यवस्था के बदले एक नई व्यवस्था, जनता की जनवादी व्यवस्था के रुप में एक विकल्प के रुप में सामने आने लगी है। इन सबसे आंतकित शासक वर्गों और उनके दलाल आंतकवाद, माओवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद का हौव्वा खड़ाकर तथा सम्प्रदायिकता, धर्मान्धिता खासकर हिन्दू साम्प्रदायिक फासीवाद और अंधराष्ट्रवाद आदि विचारधारात्मक हथियारों के जरियें इस उभरती परिवर्तनकारी शक्तियों को कुचलने को आमादा है। एक से एक काले कानून और पूलिस मिलिट्री व अन्यान्य खूनी सैन्य बलों के बूटों व संगीनो के बर्बर पाशविक दमन, जुल्म व अत्याचार के बलपर ये जनकान्ति के उफान को दबाने में एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में आज दण्डकारण्य झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के रास्ते पर चलते हुए हथियार उठाकर लड़ना सशस्त्र कृषि कान्ति की दिशा में जन फौज को शक्तिशाली बनाते हुए लोक युद्ध को तेज करना व चौरफा फैला देना और इस तरह दमन अत्याचार की इन शक्तियो का मुंहतोड़ जवाब देना आज जनता के सामने एक महत्वपूर्ण व फौरी कार्यभार के रुप मे सामने आ गया है। ऐसे में आइए, हम का0 आशुतोष संदीप जैसे दर्जनों जनकान्ति के नेताओं व योद्धाओं पर तथा सभी परिवर्तन कारी ताकतों पर जारी पाशविक यातना व जुल्म के खिलाफ, शोषण दमन, उत्पीड़न की हर कोशिश के खिलाफ एकजूट हों संगठित हों अपनी आवाज बुलंद करें आज परिवर्तन कारी शक्तियाँ शहादत, यातना झेलने और कुर्बानी व आत्म त्याग की जो अभूतपूर्व मिसाल पेश कर रही है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें।

उपरोक्त स्थितियों के मद्देनजर हमारी केन्द्रीय कमेटी सभी मजदूरों, किसानों छात्र युवाओं मध्यवर्गीय जनसमुदाय, छोटे व मझोले व्यवसायियों, व्यापारियों और तमाम मेहनतकश जनता के साथ सभी न्यायपसंद, प्रगतिकारी बुद्धि जीवियों व समुदायों से अपील करते है- आइए, हम वर्ग संघर्ष के उन्नत रुप इस हथियार बंद जनमुक्ति संघर्ष को, इस वर्ग युद्ध को नई ऊचाइयों तक विकसित करें अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ न्यायपूर्ण युद्ध, मुक्ति युद्ध को आगे बढ़ाने में लाखों-लाख की संख्या मे सामने आएं। आज भारत का मुक्ति संग्राम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खडा है और आप सबो से मांग कर रहा है कि या तो एकजुट हो, लड़ो, और मुक्ति हासिल करो या फिर शोषण व गुलामी की चक्की में पिसकर रोज-रोज घुट-घुट कर व घिसट-घिसट कर मरते रहो! आवें संघर्ष में कूद पड़ें और कैद में यातना झेल रहे सभी राजनीतिक बंदियों की मुक्ति के लिए भी संघर्ष तेज करें सैंकड़ों हजारों गिफ्तारियों व उन पर जारी बर्बर अत्याचारों के मद्देनजर हमारा फौरी कार्य है-जेल को तोड़ डालो, बंदियों को मुक्त करो और एक वेगवान धारा की तरह बढ़ चलो, जनमुक्ति के मार्ग पर। यही वक्त की पुकार है।

15 मार्च 2009

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ

केन्द्रीय कमेटी भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
पूर्वी रिजनल ब्यूरो

13-6-2009

केन्द्रीय कमिटी सदस्य-का. सुधाकर रेड्डी और डी. सी. एम. का. वैंकटइया की हत्या के खिलाफ सफल प्रतिरोधात्मक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के लिए बिहार-झारखण्ड-उत्तरी छत्तीसगढ़ स्पेशल एरिया कमिटी और स्पेशल एरिया मिलिटरी कमिशन को गर्मजोशी भरा लाल अभिनन्दन।

देश की तमाम शोषित, पीड़ित, दलित वर्ग की जनता जानती और अच्छी तरह समझती भी है कि दलाल भारतीय सत्ता-उग्रवाद, आतंकवाद दमन के नाम पर हत्याओं और नर संहारों को बैधता प्रदान कर वर्गीय दमन को जारी रखने का प्रयास चला रही है। जागरूक, राजनीतिक रूप से सचेत और क्रान्ति के प्रति समर्पित क्रान्तिकारी जनता यह भी जानती है कि उनके क्रान्तिकारी नेतृत्व के सफाये के लिए नेतओं और कार्य-कर्त्ताओं की हत्या का तांडव खुलेआम चलाया जाता रहा है और प्रक्रिया में षड़यंत्र और झूठ की चासनी मिलाकर और तेज किया जा रहा है। 22 मई 09 को केन्द्रीय सरकार का गुप्तचर विभाग और पुलिस तथा आंध्रा का गुप्तचर विभाग और पुलिस तथा विभिन्न तरह के प्रशिक्षित हत्यारा गिरोहों ने का. सुधाकर रेड्डी और का. वैंकटइया को नासिक में पकड़ा, ठंढे दिमाग से और योजनाबद्ध तरीके से उत्पीड़न करते हुए मार डाला तथा उनका गृह इलाका आंध्रा प्रदेश में लाश फेंक कर मुठभेड़ की कहानी गढ़ी गई। प्रतिक्रियावादी व्यवस्था-शोषित, पीड़ित वर्ग का बुचड़खाना है, का कंकाल स्वरूप झूठ के आवरणों से छुप

नहीं पा रहा है। इसीलिए शोषित पीड़ित जनता अपनी रक्षा करने और सत्ता के खूंखार भेड़ियों को दफनाकर अमन और शान्ति के बीज को उगाने के लिए संकल्पित हो अपनी खूनों से सींच रहे हैं। दमन के हर पहलू और तरीकों के खिलाफ हमारा प्रतिरोध संघर्ष के बढ़ते चरण और आकार में प्रतिशोध ात्मक संघर्ष भी अत्यावश्यक भूमिका अपनाने को वाध्य कर देता है।

10 जून 09 को झारखण्ड के पश्चिमी सिंहभूम में दो सब-इंसपेक्टर और एक इंसपेक्टर सहित ग्यारह वरदी धारी हत्यारा गिरोहों की सफाया और 12 जून 09 को बोकारो जिले की नावाडीह और फूसरो में 13 अर्ध सैनिक बलों की सफाया तथा बीसों को घायल करने के लिए, बिहार-झारखण्ड-उत्तरी छत्तीसगढ़ स्पेशल एरिया कमिटी एवं स्पेशल एरिया मिलिटरी कमिशन को, पूर्वी रिजनल ब्यूरो हार्दिक अभिनन्दन करती है तथा मारे गये सत्ता के हत्यारा गिरोहों तथाकथित सुरक्षा बलों के खूनों (मार का बदला मार और खून का बदला खून) से का. सुधाकर रेड्डी और का. वैंकटइया की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी शपथ और संकल्प को दुहराते हैं। शत्रु शासक वर्ग की मनसा हत्याओं की तांडव से क्रान्तिकारी ज्वार को रोक देंगे, को ध्वस्त कर क्रान्ति के पथ को सुदृढ़ और विस्तार करके अंतिम मंजिल तक जायेंगे ही। प्रत्याक्रमण आत्मरक्षा का अति महत्वपूर्ण उपायो में से एक है। इसे व्यापक बनाते हुए तेज करें।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ
अनिमेष, प्रवक्ता
पूर्वी रिजनल ब्यूरो,
सीपीआई (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
पूर्वी रिजनल ब्यूरो

19-6-2009

विषय-केन्द्र-राज्य सरकार द्वारा लालगढ़ की जनता पर हमले और दमन के खिलाफ "आहूत 24 घंटे का बन्द" 22 जून 09 को सफल करने का आह्वान!

देश की मेहनतकश जनता साम्राज्यवादी दलाल केन्द्रीय व राज्य सरकारों के दमन और हमले को जानती है, समझती है और नकाम करने के तरीके से प्रतिरोध युद्ध को विकसित कर चुकी है। विगत लगभग तीन दशकों से पश्चिम बंगाल में वामपंथ के नाम पर मार्क्सवादी खोल में पलता हिटलरशाही और सर्वहारा की मुक्ति का प्रतीक लाल झण्डे को साम्राज्यवादी पूंजी और दलाल देशी पूंजीपतियों की सेवा में अर्पित करने वाली हरमद वाहिनी, ठीक नाजी वाहिनी का प्रतिरूप बनकर जनता पर हमले पर हमला चलाती रही है। सिंगुर, नंदीग्राम, खजुरी और लालगढ़ तो उन खूंखार हरमद वाहिनियों के और सत्ता की संगठित शक्ति राज्य की पुलिस के सम्मिलित हमले के खिलाफ प्रतिरोध में खड़ी संगठित व्यापक जनशक्ति का उभरा हुआ रूप है, जो सारे दमनात्मक शक्ति को बाहर करते हुए जल, जमीन, जंगल और जनवाद पर आधारित जनवादी सत्ता की स्थापना के साथ सुदृढ़ी करण के लिए झाड़-पोंछ कर रही है। 'जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, झोपड़ी से बना हमारा गाँव उजड़ने नहीं देंगे' से बढ़ता हुआ संघर्ष आज सत्ता, दमन, विकल्प सत्ता और मुक्ति का सवाल लेकर पूंजीवादी सामंती साम्राज्यवादी जनतंत्र की जगह सच्चा और सही जनता का जनवादी जनतंत्र तक निर्माण की आवश्यकता का सवाल को हल करने पर जनता उतारू है।

लालगढ़ की जनता, बहादुर जनता जनवाद और जनतंत्र विरोधी शक्तियों

को बाहर करते हुए अपनी रक्षा के लिए शत्रु शासक-वर्ग की दमनात्मक शक्ति को बाहर निकाल रही है। अपनी शासन व्यवस्था को तथा समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम है, तो अपराध क्या है। वहाँ पर पुलिस थाना, पिकेट, और कैम्प की क्या जरूरत है? यह तो शोषक-शासक वर्ग का शोषण-दमन का हथियार है। वे लूट करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार ही नहीं सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर रहे हैं। मणीपुर और कश्मीर तो मात्र उदाहरण के लिए अपराध के समुद्र में एक बुंद जैसा है।

18 जून 09 के अपराह्न से केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल और पश्चिम बंगाल के राज्य सैनिक बलों तथा हरमद वाहिनी का संयुक्त हमला लालगढ़ की जनता पर माओवाद के दमन की आड़ में जनता के न्यूनतम जनवादी अधिकार पर हमला शुरू हो गया है। आँसू गैस, लाठी चार्ज आदि के द्वारा मानव श्रृंखला की सुरक्षा घेरे को तोड़कर गाँवों में घुसने और अत्याचार, बलात्कार के लिए केन्द्र-राज्य सरकार उतारू है; वैसे ही लालगढ़ एवं आस-पास की जनता कमर कसकर समरांगन में आत्महूति या मुक्ति के लिए उतर पड़ी है।

पूर्वी रिजनल ब्यूरो देश के तमाम देशभक्त, जनवाद प्रिय जनवादी शक्ति किसान, मजदूर, अन्य मिहनतकश वर्ग, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, पत्रकार, छोटे दुकानदार, दुकान कर्मी आदि तमाम वर्गो से साग्रह निवेदन के साथ अपील करती है कि लालगढ़ की जनता के उपर हो रहे केन्द्र-राज्य सरकार के साथ सी. पी. एम. के हरमद वाहिनी जैसे गुण्डों के दमन, अत्याचार के संयुक्त हमलों के खिलाफ लालगढ़ की जनता और जनवाद के पक्ष में दृढ़ता से खड़े हों और जवाबी कार्रवाई के लिए भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी संघर्ष में योगदन करते हुए सैंकड़ों लालगढ़ बनाने की ओर आगे बढ़े। पूर्वी रिजनल ब्यूरो अपने अधीन कार्यरत कमिटियों और कमिशनों से साग्रह निवेदन करती है कि प्रतिरोध संघर्ष के इलाके में लालगढ़ के मुद्दों और दमन की प्रक्रिया पर व्यापक बहस-मुबाहिसा के दौरान संघर्ष और प्रतिरोध संघर्ष के कार्यक्रम में तेजी लाये और व्यापक बनाये ताकि शत्रु शासक वर्ग के

खिलाफ अनेक मोर्चे बन सकें।

हमले के खिलाफ फिलहाल प्रतिवाद-प्रतिरोध स्वरूप ब्यूरो अपने अधीन कार्यरत चार राज्यों, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखण्ड और बिहार में 22 जून 09 को 24 घंटे का बन्द सफल करने के लिए सभी संगठनों, पार्टी सदस्यों, फौजी कमिशनों से अपील करती है तथा प्रतिरोध के लिए बन्द को प्रतिरोध जैसा पालन करने का आदेश निर्गत करती है।

नोट : आवश्यक दूध, पानी, एम्बूलेंस, प्रेस आदि सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ
अनिमेष, प्रवक्ता
पूर्वी रिजनल ब्यूरो,
सीपीआई (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
पूर्वी रिजनल ब्यूरो

2-8-2009

शहीद स्मारक पर पुलिसिया कहर और तोड़-फोड़ की निंदा, भर्त्सना, क्षोभ और आक्रोश प्रकट करते हैं।

पूर्वी रिजनल ब्यूरो आम जनता को यह बताना चाहती है कि दिनांक 1 अगस्त09 को लगभग 12 बजे दिन में लुटुआ पंचायत ढोंगला मोड़ पर बना शहीद स्मारक को सैकड़ों की संख्या में आई पुलिस ने तोड़ डाली है। शहीद स्मारक का. रामेश्वर उर्फ का. बच्चन के शहादत के याद में बनाया गया है। क्रान्ति के प्रति समर्पण के लिए त्याग, बलिदान, मिहनतकश जनता की सेवा की भावना से ओत-प्रोत, प्रतिकुल परिस्थितियों में भी क्रान्ति के उतरदायित्व को निभाने में भरपूर रूचि, उत्साह, साहस के साथ प्रतिक्रियावादी के खिलाफ लड़ते हुए जनयुद्ध के रणांगन में जनयोद्धा शहादत देते हैं, वे जनता के हृदय स्थल में निवास करते हुए अमरत्व प्राप्त कर प्रतिक्रियावादी-प्रतिक्रान्ति के खिलाफ आम जनता को ऊर्जा और उत्साह भरते हुए कठिनाइयों पर जीत हासिल करने को ललकारते हैं तथा उनकी शहादतों से जनता की सेवा की भावना के सिख हमें मिलती है। इसलिए स्मारक का तोड़ा जाना एक सांस्कृतिक रूप से शोषित, पीड़ित, दलित करोड़ों जनता की भावनाओं पर हमला है। इसका जितना निंदा और भर्त्सना किया जाय कम ही है।

पूर्वी रिजनल ब्यूरो आम जनता के आहत भावनाओं और आक्रोश को संभालकर रखने की सलाह देती है और इस घटना को व्यापक जनता के बीच बहस और प्रचार की जरूरत के साथ आम जनता की भावनाओं को

समझने, उनके प्रतिक्रिया को समझने तथा एक सार्वभौम मत बनाकर कुछ कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए।

पूर्वी रिजनल ब्यूरो तमाम अधिनस्थ कमिटियों, कमिशनों और कमानों से भी साग्रह अपील करती है कि शहीद सप्ताह को मनाने की पार्टी के निर्णय के अनुरूप ही मनाया जाना चाहिए। मौजूदा शोषणमूलक व्यवस्था तो हमले के लिए ही है और उसका चरित्र ही जन विरोधी हमलावर और साम्राज्यवादी मालिकों की पूजा, अर्पण और हमेशा पूंछ हिलाते रहने का है। ऐसी स्थिति में हमें धीरज के साथ जनता को जागरूक व गोलबंद कर हर ऐसी कार्रवाई का कड़ा विरोध करना होगा तथा और उत्साह के साथ आम जनता की पहल से शहीद स्मारक बनाना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ
अनिमेष, प्रवक्ता
पूर्वी रिजनल ब्यूरो,
सीपीआई (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
उत्तर रिजनल ब्यूरो

23-9-2009

हमारी पार्टी और भारतीय क्रांति के सुयोग्य नेता कामरेड कोबाड गांधी की गिरफ्तारी और उनको दी जा रही बर्बर यातना के विरोध में उठ खड़े हों !
भारत की प्रतिक्रियावादी केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा भारत वर्ष की मेहनतकश जनता के खिलाफ छेड़े गये अन्यायपूर्ण व बर्बर युद्ध के खिलाफ गरज उठें !!

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एपीएसआईबी के निर्मम हत्यारों ने हमारी पार्टी और भारतीय क्रांति के एक महत्वपूर्ण नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य का. कोबाड गांधी को गत 20 सितम्बर की शाम को गिरफ्तार किया है और अभी रिमाण्ड पर लेकर उनको बर्बर व अकथ यातना देने के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं। 63 वर्ष के एक बुजुर्ग के खिलाफ, जिन्हें हाल की बीमारियों ने शारीरिक रूप से काफी कमजोर बना डाला है, ऐसे बुरे मंसूबे पालना और उन्हें चरितार्थ करने के लिए तरह-तरह की जुगत भिड़ाना उनकी दरिंदगी व बौखलाहट का जीवन्त सबूत है। हम अपनी पार्टी के उत्तरी रिजनल ब्यूरो (एन.आर.बी.) के नेतृत्वाधीन सभी पार्टी संगठनों, फौजी संगठनों, जन संगठनों और उत्तर भारत की समग्र क्रान्तिकारी जनता की ओर से इस गिरफ्तारी व उनको दी जा रही बर्बर यातना की घोर भर्त्सना करते हैं, और देश की समूची शोषित-उत्पीड़ित व मेहनतकश जनता और सभी न्यायपसंद, प्रगति शील व जनवादी ताकतों से इसके खिलाफ प्रतिवाद व प्रतिरोध खड़ा करने की अपील करते हैं।

सवाल है कि ये कोबाड गांधी हैं कौन और क्यों हुई है उनकी यह गिरफ्तारी? यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कामरेड कोबाड गांधी हमारी पार्टी व भारतीय क्रान्ति के ऐसे

कर्मठ नेता हैं जिन्होंने अपने षानदार कैरियर और उच्च मध्यवर्गीय जीवन को लात मारकर भारतीय क्रान्ति और भारत की मेहनतकश जनता की मुक्ति के संघर्ष में अपने आपको 70 के दशक के शुरुआत से ही झोंक दिया था। आज भी उनका त्याग, उनकी कर्मठता, उनका सादा जीवन और तीक्ष्ण राजनीतिक विवेक हम सभी के लिए एक आदर्श है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारत की प्रतिक्रियावादी सरकार की हत्यारी पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी दरअसल साम्राज्यवाद की दलाल भारत सरकार द्वारा जल, जंगल और जमीन पर अधिकार के लिए संघर्षरत भारत की मेहनतकश जनता के खिलाफ चलाए जा रहे एक अन्यायपूर्ण चौतरफा युद्ध के तहत ही की गयी एक बर्बर कार्रवाई है।

आज दिन के उजाले की तरह यह बिल्कुल साफ है कि वि वव्यापी भयानक मंदी की चपेट में डूबता-उतराता साम्राज्यवाद इस अभूतपूर्व संकट के समूचे बोझ को पिछड़े देशों की मेहनतकश जनता के सर पर लाद रहा है। खुद को इस मंदी से उबारने के लिए पिछड़े देशों की मेहनतकश जनता के लूट-खसोट को चरम मात्रा तक बढ़ाना उसके लिए तत्काल जरूरी हो उठा है। अरब देशों की अगाध तेल सम्पदा को अपनी मुट्ठी में करने के लिए समूची अरब जनता के खिलाफ 90 के दशक से उन्होंने एक अन्यायपूर्ण व बर्बर युद्ध छेड़ रखा है। अभी उनकी गिद्ध दृष्टि लगी है हमारे देश की अकूत प्राकृतिक सम्पदा पर। इसकी लूट-खसोट को अगर अबाध व सुगम बनाना हो तो उनके सामने मुख्य समस्या है - हमारी पार्टी, उसकी पीएलजीए और हमारी पार्टी के नेतष्त्व में जल, जंगल व जमीन पर अपने अधिकार के लिए उठ खड़ी हुई सचेत, संगठित व सशस्त्र करोड़ों-करोड़ जनता, उनके इस बेपनाह लूट-खसोट को और इसे जारी रखने वाली उनकी प्रतिक्रियावादी राजसत्ता को उखाड़ फेंककर जनता की जनवादी राजसत्ता की स्थापना के लिए संघर्षरत जनसमुदाय तथा इस मुक्तियुद्ध की अगली कतार में खड़ी दण्डकारण्य, बिहार-झारखण्ड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पष्चिम बंगाल की जनता, उनकी जनताना सरकार।

दरअसल हमारी पार्टी, उसकी पीएलजीए और करोड़ों-करोड़ जनता द्वारा चलाया जा रहा हमारा क्रान्तिकारी आन्दोलन भारतवर्ष के बड़े जमींदार वर्ग, बड़े पूंजीपति वर्ग

और उनके आकाओं के लिए सचमुच ही एक ऐसा आतंक बन गया है जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। तभी तो देखते हैं, अमरीका की एफबीआई और इस्राएल के कुख्यात मोसाद से लेकर भारत सरकार की समूची खूफिया मशीनरी तथा अत्याधुनिक हथियारों से लैस लाखों की संख्या में पुलिस, अर्द्धसैन्य बल व सेना को लेकर ये बिल्कुल निराशोन्मत होकर टूट पड़े हैं। खासकर दण्डकारण्य (दक्षिणी छत्तीसगढ़) के माड़ क्षेत्र और बिहार-झारखण्ड व उड़ीसा की आदिवासी जनता को उन्होंने मुख्य निशाना बनाया है। विकास व बंदूक के जरिये निपटने की पूर्ववर्ती लफ्फाजी के बजाय प्रतिक्रियावादी सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गिरोह ने साफ घोषणा की है कि माओवाद-नक्सलवाद को वे बंदूक के बल पर ही खत्म करेंगे। साथ ही उन्होंने हमारी पार्टी के नेताओं को चुन-चुनकर पकड़ने व हत्या कर देने के लिए अपनी समूची खूफिया मशीनरी को लगा दिया है और जिसकी कमान थामी है कुख्यात एफबीआई और मोसाद ने। जनता की बगावतों को कुचलने के लिए अमरीकी सरकार द्वारा बनाई गई एलआईसी की नीतियों को लागू करते हुए इन्होंने इस चौतरफा युद्ध के एक अंग के बतौर ही हमें जनता के बीच बिल्कुल घिनौने, जन-विरोधी व बेरहम हत्यारों के रूप में चिन्हित करने के लिए रेडियो, टीवी, अखबार, इन्टरनेट सहित समूचे मीडिया तंत्र की ताकत को झोंक दिया है। इस तरह ये हमें जनता से बिल्कुल अलग-थलग करने, हमारे खिलाफ, भारत की संघर्षरत करोड़ों-करोड़ जनता द्वारा जारी न्यायोचित संघर्ष के खिलाफ एक प्रतिक्रियावादी जनमत बनाना चाहते हैं। इनके बूरे मंसूबे ये हैं कि इसी प्रतिक्रियावादी जनमत पर खड़े होकर ये इस पूरे आन्दोलन को खून की दरिया में डूबोकर खत्म कर डालें! गौर करना जरूरी है कि हमें खूनी हत्यारा और जनविरोधी बताने वाले वे लोग हैं जिनके खूनी कारनामों की गवाह है क मीर से लेकर उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनता जहां कि उन्होंने 6-7 लाख सेना को उतारा है और रोज-ब-रोज कत्लेआम से लेकर विभत्स किस्म के जुल्म-अत्याचार व उत्पीड़न करवा रहे हैं। लाखों-लाख जनसमुदाय और उनके नेताओं की बेरहम हत्याओं के जिनके कारनामे जगजाहिर हैं, भारत का वह प्रतिक्रियावादी सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गिरोह भारत की जनता और उसके नेताओं को कातिल व हत्यारा बताकर अपने कुकर्मों पर पर्दा डाल

रहा है।

ऐसी एक परिस्थिति में हमारे संघर्ष के केन्द्रीय क्षेत्रों पर जबर्दस्त सैन्य दबाव बढ़ाया जा रहा है, चुन-चुनकर हमारे नेताओं को पकड़ा व मारा जा रहा है तथा हमें जनता के बीच देशद्रोही, जनविराधी व विकास विरोधी एक बेरहम हत्यारों के गिरोह के रूप में चित्रित करने के लिए अविराम झूठी व विभत्स कुत्सा और कुप्रचार का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जनता के सभी न्यायोचित संघर्षों, जमीन-जीविका-जनवाद के लिए हो रहे सभी आन्दोलनों और इनके पक्ष में खड़े होने वाले सभी सचेत नागरिकों व बुद्धिजीवियों को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें दमन व यातना का शिकार बनाया जा रहा है। आज की एक ऐसी परिस्थिति में हम उत्तर भारत में बसने वाली करोड़ों-करोड़ जनता, यहां के जागरूक व सचेत बुद्धिजीवियों व न्यायपसंद अवाम से इस प्रतिक्रियावादी दमन-अभियान के खिलाफ आवाज बुलंद करने व उठ खड़े होने और इन जनहत्यारे व लूटेरे वर्गों के खिलाफ युद्ध के नये मोर्चे खोलने की अपील करते हैं। खासकर उनके द्वारा न्यायोचित अधिकारों के लिए संघर्षरत जनता को कुत्सित रूप में चित्रित करने वालें प्रचार-अभियान के खिलाफ व्यापक भंडाफोड़ अभियान चलाने और व्यापक लोगों को इस संघर्ष के पक्ष में खड़ा करने हेतु क्रान्तिकारी प्रचार-अभियान विभिन्न रूपों में चलाने की अपील करते हैं। इसी क्रम में इसीबीच हमारे नेता और जनता के सभी न्यायोचित संघर्षों की अगली कतार में हमेशा डटे रहने वाले कामरेड कोबाड गांधी की गिरफ्तारी और उन पर ढायी जा रही क्रूर यातना के खिलाफ उठने वाली हर आवाज और की जाने वाली हर कोशिश का अभिनन्दन करते हैं तथा इस सबके खिलाफ एक जबर्दस्त प्रतिवाद-आन्दोलन खड़ा करने का आहवान करते हैं!

भास्कर
प्रवक्ता
उत्तर रिजनल ब्यूरो
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी - मध्य रीजनल ब्यूरो

15 जनवरी 2010

फासीवादी सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गिरोह द्वारा भारतीय जनता के ऊपर छेड़े गए जन संहारक ऑपरेशन ग्रीनहंट का विरोध करो!

जनवरी 25-27 तक भारत के मध्य क्षेत्र में 72-घण्टे का बंद सफल बनाओ!

पिछले जून माह से, पश्चिम बंगाल के लालगढ़ क्षेत्र में व्यापक प्रति-क्रांतिकारी सशस्त्र आक्रमण से शुरू कर फासीवादी सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गिरोह की अगुवाई में देश के प्रतिक्रियावादी शासकों ने मध्य व पूर्वी भारत के खनिज संपदा से समृद्ध व आदिवासी बहुल इलाकों की समूची जनता के खिलाफ क्रूरतम हमला बढ़ा दिया। दण्डकारण्य में, जोकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके व महाराष्ट्र के गढ़चिरौली व चंद्रपुर जिलों से युक्त है, पिछले सितम्बर से व्यापक स्तर पर जन संहारक युद्ध छेड़ दिया। तब से 82 आदिवासियों की निर्मम हत्या की गई और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया या अगवा कर लिया गया। दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। आदिवासियों की कई करोड़ों रूपए की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। 10 नवम्बर को किष्टारम के पास 7 आदिवासियों का अपहरण कर बाद में हत्या कर दी गई। 7 व 9 नवम्बर के बीच चिंतागुप्पा पुलिस थाना के तहत बुरकापाल, एलमगोण्डा व मिनपा गांवों से सीआरपीएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस व एसपीओ द्वारा अपहृत 24 आदिवासियों के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है कि वे जीवित हैं या नहीं। इस वर्ष 9 जनवरी को दंतेवाड़ा व नारायणपुर जिलों में 8 आदिवासियों की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या कर दी गई। दंतेवाड़ा रेंज के डीआईजी एसआरपी कल्लूरी, जो सरगुजा जिले में एसपी रहते हुए एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार कर कुख्यात हो चुका था, दंतेवाड़ा एसपी अमरीश मिश्रा, बस्तर रेंज का आईजी टीजे लांगकुमेर और डीजीपी विश्वरंजन, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जालिम है,

आदिवासियों की हत्या, बलात्कार, अपहरण व यातनाओं के इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं।

असहमति की हर आवाज को अत्यंत क्रूरता से दबा दिया जा रहा है। यहां तक कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, जो तथ्यों की छानबीन करने इलाके का दौरा करना चाहते हैं, सरकार-प्रायोजित सलवा जुडूम, मां दंतेश्वरी स्वाभिमान मंच और अन्य भाड़े के गिरोहों से हमले करवाए जा रहे हैं। मीडिया को दबा दिया जा रहा है और पुलिसिया अत्याचारों से सम्बन्धित सभी तथ्यों को पुलिस व रमनसिंह की भगवा आतंकवादी सरकार द्वारा दबा दिया जा रहा है जिसे केन्द्र की खादी आतंकवादी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का सक्रिय समर्थन हासिल है। हत्या का शिकार सभी आदिवासियों को माओवादी गुरिल्लों के रूप में दिखाकर अपनी इन कायराना कार्रवाइयों को माओवादियों के खिलाफ पुलिस बलों को मिल रही बड़ी सफलताओं के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इस तरह के झूठे दावों के जरिए पुलिस के आला अधिकारी और सरकार अपने बलों के गिरते मनोबल को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो माओवादियों के साथ वास्तविक लड़ाइयों में बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं।

गृहमंत्री चिदम्बरम हिटलर की तरह एक तरफ हजारों केन्द्रीय बलों को भिजवाकर पश्चिम मिडनापुर-पुरूलिया-बांकुरा से आंध्रप्रदेश के उत्तरी आंध्र व उत्तरी तेलंगाना तक फैले हुए आदिवासी पट्टी में बर्बर नरसंहार मचवाते हुए, जोकि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में अभूतपूर्व है, दूसरी तरफ निर्लज्जता के साथ झूठ बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट भ्रामक है और पूरी तरह मीडिया द्वारा गढ़ा गया है। भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी सशस्त्र संघर्ष के इलाकों में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की 58 बटालियनें अब तक भेजी जा चुकी हैं। 25 दिसम्बर को दण्डकारण्य स्पेशल जोन में छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र पुलिस बलों ने एक व्यापक संयुक्त अभियान शुरू कर दिया। इस व्यापक संयुक्त आक्रमण की घोषणा से एक दिन पहले चिदम्बरम ने देश की राजधानी में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक लेकर बताया कि केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ शामिल हैं, की 33 अतिरिक्त बटालियनें भेजी जा रही हैं ताकि और ज्यादा खून बहाया जा सके। इन केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के पुलिस बल, महाराष्ट्र के सी-60 कमाण्डो व नियमित पुलिस बल, आंध्रप्रदेश

के ग्रेहाउण्ड्स, ओडिशा के राज्य सशस्त्र पुलिस व स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप मध्य भारत में जारी संयुक्त अभियानों में भाग ले रहे हैं। भाकपा (माओवादी) के मध्य रीजनल ब्यूरो के तहत आने वाले तीन जोनों - दण्डकारण्य, उत्तरी तेलंगाना व आंध्र-ओडिशा सीमांत स्पेशल जोन में लगभग डेढ़ लाख सशस्त्र बल इस संयुक्त अभियान में भाग ले रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवादियों और दलाल पूंजीपति घरानों के दलाल, जो हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, समूचे वन क्षेत्रों से आदिवासियों को खाली कर मोटी दलाली के एवज में खनिज संपदा से समृद्ध इस भूखण्ड को अपने प्रभुओं के हवाले करने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 62 सालों के दरमियान इन लुटेरों ने यहां की जनता को पीने का पानी भी मुहैया करवाने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन अब ये हजारों करोड़ों रूपए खर्च कर वायुसेना के अड्डे (एअर बेस), हेलिपैड, चमचमाती पक्की सड़कें और अन्य ढांचागत निर्माण करने जा रहे हैं ताकि जनता का दमन करने में अपने भाड़े के बलों की आवाजाही में सुविधा हो सके। हाल ही में, छत्तीसगढ़ ने घोषणा की कि सरकार द्वारा संचालित शिविरों या रणनीतिक बसाहटों (strategic hamlets) को, जिन्हें सरकार-प्रायोजित आतंकी सलवा जुडूम अभियान के जरिए 800 आदिवासी गांवों को जला देने के बाद स्थापित किया गया था, नियमित ग्राम पंचायतों में बदल दिया जाएगा। इस तरह उसने जनता के खिलाफ अपने युद्ध का असली उद्देश्य जाहिर किया। वह चाहती है कि आदिवासियों को उनके पुश्तैनी गांवों से हमेशा के लिए भगा दिया जाए और समूचे जंगलों को कॉर्पोरेट मालिकों और साम्राज्यवादी गिद्धों को सौंप दिया जाए।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी और उसका मध्य रीजनल ब्यूरो छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, आंध्र-ओडिशा सीमांत क्षेत्र और विदर्भ के गढ़चिरौली, गोंदिया व चंद्रपुर जिलों की जनता का आह्वान करते हैं कि मध्य भारत में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों तथा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओडिशा के पुलिस बलों द्वारा जारी जन संहारक संयुक्त अक्रमण के विरोध में 25 से 27 जनवरी तक 72-घण्टे के बंद का पालन किया जाए। हम तमाम क्रांतिकारी, जनवादी व शंति-प्रिय ताकतों से अपील करते हैं कि केन्द्र व राज्य सरकारों के देशव्यापी फासीवादी आक्रमण का, खासकर माओवादी आंदोलन तथा दण्डकारण्य, उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी आंध्र व ओड़िशा के मूलनिवासी आदिवासी समुदायों पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओडिशा सरकारों द्वारा जारी संयुक्त ऑपरेशन

का प्रतिरोध करें। हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि जनता के प्रति भाईचारा प्रकट करें और इस अभूतपूर्व बर्बर सरकारी आतंकी हिंसा का शिकार हुए लोगों की मदद करें। हम तमाम शांतिप्रिय नागरिकों को न्यौता देते हैं कि वे इन इलाकों का दौरा करें और यहां हो रही अमानवीय हिंसा को बाहरी दुनिया में उजागर करें। हम पुलिस व केन्द्रीय बलों का आह्वान करते हैं कि वे उन प्रतिक्रियावादी व जन-विरोधी शासकों के हाथों में औजार न बनें जो अपने पूंजीपति मालिकों के हित में हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को तबाह कर रहे हैं। इसके बजाए वे अपनी बंदूकें उन प्रतिक्रियावादी देशद्रोहियों के सीने पर तान दें जो देश के हितों को बेच रहे हैं।

आइए, हम सब एक शक्तिशाली जन आंदोलन का निर्माण करें ताकि प्रतिक्रियावादी शासकों पर आदिवासी इलाकों में जारी रक्तपात रोकने का दबाव डाला जा सके। हम पार्टी के तमाम कतारों, पीएलजीए के बहादुर योद्धाओं और क्रांतिकारी जन समुदायों का आह्वान करते हैं कि वे साम्राज्यादियों के दलाल शासकों के द्वारा छेड़े गए बर्बर व दमनकारी युद्ध का पलटकर जवाब दें और अनुपम शूरता व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए वर्तमान में जारी प्रतिरोध ी जनयुद्ध को उच्च स्तर पर विकसित करें।

आजाद	**प्रताप**
प्रवक्ता	**प्रवक्ता**
केन्द्रीय कमेटी	**मध्य रीजनल ब्यूरो**
भाकपा (माओवादी)	**भाकपा (माओवादी)**

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

19 मई 2010

चिंगावरम हमला कोया कमाण्डो पर हमला था, आम नागरिकों पर नहीं!
आम लोगों की मौत के लिए चिदम्बरम-रमनसिंह गिरोह ही पूरी तरह जिम्मेदार है!!
चिदम्बरम और उसके युद्धोन्मादी गिरोह द्वारा जारी दुष्प्रचार अभियान की निंदा करो!!!

16 मई को दंतेवाड़ा जिले के चिंगावरम के पास हुए एक माओवादी ऐम्बुश के बाद सबसे बड़े युद्ध पिपासु चिदम्बरम का नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने जहर उगलने वाला बहुत बड़ा दुष्प्रचार अभियान छेड़ दिया। चिदम्बरम और उसके सहयोगी जी.के. पिल्लई ने यहां तक कहा था कि माओवादी केन्द्रीय अध -सैनिक बलों, स्थानीय पुलिस व एसपीओ तथा आम नागरिकों के बीच फर्क नहीं देख पा रहे हैं। इससे उनके विचारधारात्मक व राजनीतिक दिवालिएपन तथा माओवादियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान के पीछे उनके बुरे मंसूबों को समझा सकता है। इस तरह के सफेद झूठों से वे अपने बर्बर व अन्यायपूर्ण युद्ध को वैधता हासिल नहीं कर सकते।

माओवादी पीएलजीए के इस ऐम्बुश के बाद गृह मंत्रालय ने पहले यह प्रचार किया था कि माओवादियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन जब ये खबरें आने लगी थीं कि मारे गए लोगों में कोया कमाण्डो और एसपीओ की संख्या ही ज्यादा है, उन्होंने अपना स्वर बदलते हुए यह कहना शुरू किया कि एसपीओ भी नागरिक हैं और माओवादियों ने पुलिस वालों और नागरिकों के बीच फर्क नहीं देखा। फासीवादी दिमाग वाले गृहमंत्री ने अपना पुराना राग

अलाप दिया कि नक्सलवादियों से निपटने के लिए उसे सीमित आदेश (मैंडेट) प्राप्त है और कैबिनेट कमेटी के सामने उसके पुराने प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है। उसका कहना है कि लोग नक्सलवादियों के खिलाफ सख़्त कदम चाहते हैं जैसे कि हवाई ताकत का इस्तेमाल और यहां तक कि सेना का प्रयोग। जब यह फासीवादी अपने को प्राप्त तथाकथित सीमित आदेश से ही छत्तीसगढ़ के व्यापक इलाकों में इतनी ज्यादा तबाही मचाने में समर्थ है और सैकड़ों आदिवासियों का कत्लेआम करने व उन पर बर्बरतापूर्ण जुल्म छेड़ने में सक्षम है, तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसे माओवादियों और देश की गरीबतम जनता के खिलाफ जारी युद्ध में खुली छूट या पूरा आदेश देने से क्या कुछ कर सकता है। यह स्पष्ट है कि अगर चिदम्बरम को वो जैसा चाहे करने की इजाजत होगी तो वह आदिवासी बहुल इलाकों में एक विनाशकारी नस्लकशी को अंजाम देगा, इन्हें कब्रगाहों में तब्दील कर जनता के शवों पर यहां की जमीनें साम्राज्यवादियों और बड़े पूंजीपति घरानों के हवाले कर देगा। अश्चर्य है कि इस मंजे हुए झूठे ने जल्द ही अपने बयान को बदला और कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा था कि उसे सीमित आदेश दिया हुआ है, बल्कि उसका यह कहना रहा कि राज्यों को असीमित आदेश प्राप्त हैं। इस तरह के झूठे व अजीबोगरीब बयानों से उसने अपने आपको भारतीय राजनीति का एक बहुरूपिया साबित किया।

हाल ही में पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में माओवादियों द्वारा पुलिस मुखबिरों को सजा देने की घटनाओं का चिदम्बरम और उसके गिरोह ने आम नागरिकों के खिलाफ हमलों के रूप में गलत चित्रण किया। पहली बात तो यह है कि युद्ध-पिपासु दरिंदों को छोड़कर दूसरा कोई भी इन्सान यह विश्वास नहीं करेगा कि माओवादी ठीक उन्हीं आम लोगों को निशाना बना सकते हैं जिनके हित में उन्होंने हथियार उठाए हैं। यह भी सच है कि इस युद्ध में गरीब एसपीओ, सलवा जुडूम कार्यकर्ता और गरीब पुलिस जवान हताहत हो रहे हैं। और इन मौतों की पूरी जिम्मेदारी खुद सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गिरोह की है जो इन्हें निस्संदेह बलि के बकरों की तरह इस्तमाल कर रहा है ताकि देश के संसाधनों को अपने आकाओं के पैरों में रखने की घिनौनी मंशा को पूरा किया जा सके।

दंतेवाड़ा के चिंगावरम में हुई 15 आम नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के प्रति हम गहरा शोक प्रकट करते हैं। और हम आश्वासन देते हैं कि हम पीड़ितों के परिवारों की यथासंभव सहायता करेंगे और आगामी हमलों में पूरी सावधानी बरतेंगे ताकि आम नागरिकों की मौतों को कम से कम किया जा सके। हम साफ शब्दों में घोषणा करते हैं कि एक भी आम नागरिक मारा जाता है तो हमें अफसोस होता है और हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी ताकि इस चल रहे युद्ध में गैर–लड़ाकुओं को हताहत होने से बचाया जा सके। हालांकि हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, फिर भी हमारी तरफ से गंभीर चूक यह हुई थी कि बस के अंदर आम नागरिकों की उपस्थिति को हम समझ नहीं पाए थे। चूंकि कोया कमाण्डो बस की छत पर कब्जा किए हुए थे, इसलिए यह धोखा हुआ था। केन्द्र का सत्तारूढ़ सोनिया–मनमोहन–चिदम्बरम गिरोह और राज्यों में सत्ता पर काबिज विभिन्न प्रतिक्रियावादी पाटियों को जनता के प्राणों और उनके बुनियादी अधिकारों के प्रति जरा भी चिंता नहीं होती। ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू होने के बाद पिछले दस महीनों में देश भर में 250 से ज्यादा निर्दोष व निहत्थे लोगों और पकड़े जा चुके माओवादी क्रांतिकारियों की निर्मम हत्या के लिए यही प्रतिक्रियावादी जिम्मेदार हैं। माओवादी गुरिल्लों के हमलों से अपने आपको बचाने के लिए अर्ध–सैनिकों, पुलिस और एसपीओ द्वारा आम नागरिकों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल करने की घिनौनी कोशिशों का हम विरोध करते हैं। चिंगावरम की इस घटना में बदनाम और गैर–कानूनी कोया कमाण्डों ने, जो एक गांव में आतंक का तांडव मचाकर लौट रहे थे, बस के ड्राइवर और अन्य मुसाफिरों के विरोध की जरा भी परवाह किए बगैर बस में चढ़ बैठे थे और इस तरह उन्होंने आम नागरिकों की जानों को खतरे में डाला था। हम फिर एक बार जनता से अपील करते हैं कि वह उन वाहनों में सफर न करे जिनमें भाड़े के सशस्त्र बल बैठे हुए हों। निजी वाहनों के मालिकों से अपील है कि वे इन वर्दीधारी सशस्त्र गुण्डों के लिए अपने वाहन न दें।

हम सभी जनवादी सोच वाले संगठनों व शख्सों और समूची जनता का आह्वान करते हैं कि वे उन परिस्थितियों को समझें जिसमें आम नागरिकों की मौत हुई थी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि अर्ध–सैनिक बलों, कमाण्डो

बलों, स्थानीय पुलिस बलों, एसपीओ और विभिन्न संसदीय पार्टियों के नीति-निध रिकों को निशाना बनाते हुए हमले करते समय भविष्य में हम ज्यादा सावधानी बरतेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आम नागरिकों को नुकसान न हो। क्रांति के शुभ-चिंतकों और जन-पक्षधर संगठनों व बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि वे प्रतिक्रियावादी शासकों द्वारा छेड़े जाने वाले दुष्प्रचार अभियान से प्रभावित न हों क्योंकि वे माओवादियों के द्वारा गैर-इरादतन की गई हर गलती का भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि क्रांतिकारी आंदोलन को बदनाम किया जा सके व नीचा दिखाया जा सके। जबरिया भूमि-अधिग्रहण, आदिवासियों व गरीब किसानों का विस्थापन, जनता के खिलाफ जारी बर्बर राजकीय आतंकवादी व राज्य-प्रायोजित आतंकवादी हमले, बुनियादी मानवाधिकारों का हनन, भारतीय धरातल के बड़े-बड़े भूखण्ड साम्राज्यवादी आकाओं और दलाल पूंजीपति घरानों के हवाले करने की शासकों की साजिश, और इस तरह ग्रामीण इलाकों में उभर रही नई क्रांतिकारी जन सत्ता के अंगों को खत्म करने की साजिश... आदि वास्तविक मुद्दों को धुंधलाने की शासक वर्गों की घिनौनी करतूतों से हमें कतई भ्रमित नहीं होना चाहिए।

आजाद
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

30 जुलाई 2010

कश्मीरी जनता पर आए दिन गोलीबारी व हमले करते हुए नौजवानों की निर्मम हत्या कर रहे भारत के सरकारी सशस्त्र बलों के जुल्मों का पुरजोर विरोध करो!
कश्मीर कश्मीरियों का ही है! कश्मीरी जनता के न्यायपूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का बेखौफ समर्थन करो!!

पिछले एक माह से कश्मीर फिर एक बार भड़क रहा है। हर दिन भारत सरकार के पुलिस/अर्ध-सैनिक बल वहां की जनता पर अंधाधुंध गोलीबारियां करते हुए अब तक 19 लोगों (इनमें ज्यादातर 13 से 19 साल के बीच के हैं) को मौत के घाट उतार चुके हैं। सैकड़ों लोग घायल हो गए। ताजातरीन घटना में आज 30 जुलाई को कश्मीर घाटी में कई जगहों पर हुए जन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों ने गोलीबारी की जिसमें कम से कम 4 लोगों की जानें गईं और सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारत के शासक वर्ग भले ही यह दावा करते हों कि कश्मीर में अब मिलिटेन्सी खत्म हो गई है और वहां के 'अलगाववादी' संगठनों को कुचला जा चुका है, पर सच यह है कि कश्मीरी जनता हर दिन किसी न किसी समस्या को लेकर संघर्ष कर ही रही है। 2008 में अमरनाथ श्राइनबोर्ड के विवाद के संदर्भ में और 2009 में शेपियन कस्बे में दो महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर कश्मीरी जनता ने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आकर पुलिस/अर्ध-सैनिक बलों की गोलीबारी की परवाह किए बगैर तथा कर्फ्यू और प्रतिबंधों को धता बताते हुए लहरों की तरह कई दिनों तक संघर्ष को जारी रखा था। अबकी बार 11 जून को पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस का गोला फटने से एक स्कूली छात्र के मारे जाने की घटना को लेकर ताजातरीन विरोध-आंदोलन शुरू हुआ है। कश्मीरी जनता के शांतिपूर्ण

व लेकतांत्रिक विरोध–संघर्षों से भी खफा भारत सरकार और उसकी जी–हुजूरी करने वाली उमर अब्दुल्ला सरकार ने अभी तक कई बार गोलीबारी, कर्फ्यू, लाठीचार्ज व आंसू गैस का प्रयोग किया पर यह आंदोलन बिना रुके अभी भी जारी है।

गौरतलब है कि कश्मीर में विरोध–संघर्ष चाहे किसी भी रूप में या किसी भी मुद्दे पर शुरू होता हो, उसमें 'आजादी' का ही नारा प्रमुखता से उभरकर आता है। यह कश्मीरी जनता के दिलोदिमाग में अपनी राष्ट्रीयता की मुक्ति के प्रति और अपनी आजादी के प्रति मौजूद अदम्य चाहत का प्रतिबिंब है। भारतीय विस्तारवादी शासक मीडिया के जरिए भले ही खूब प्रचारित करे कि 'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है', इतिहास की जानकारी रखने वाला कोई भी शख़्स इस सच्चाई को नकार नहीं सकता कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा था और वह एक अलग देश के रूप में कई सालों से बना रहा था। दूध के दांत टूटे हुए नन्हे बच्चों से लेकर कश्मीरी समाज के हर शख़्स के अंदर अपनी 'आजादी' की जबर्दस्त चाहत जो दिखाई देती है, उसका सिर्फ लश्कर–ए–तोइबा के द्वारा बढ़ावा दिए जाने से या विदेशी ताकतों के द्वारा पैसा दिए जाने से ही उत्पन्न परिणाम के रूप में गलत चित्रण करना कश्मीरी जनता की आकांक्षाओं और आत्मसम्मान का घोर अपमान है। 7 लाख से ज्यादा विभिन्न सशस्त्र बलों की तैनाती से दुनिया में ही सबसे ज्यादा सैन्यीकृत इलाका माने जाने वाले कश्मीर में हालांकि सशस्त्र संघर्ष करने वाले संगठन फिलहाल कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन जनता, खासकर नौजवान अपने हाथ में मिले पत्थरों का ही हथियार के तौर पर प्रयोग करते हुए पुलिस व अर्ध–सैनिक बलों से जूझ रहे हैं। इसे उनमें छिपी आजादी की जबर्दस्त आकांक्षा की अभिव्यक्ति के रूप में न देखते हुए भारत के शासक ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं मानों आखिर उनके हाथों में पत्थर भी विदेशों से आयातित किए गए हों। जिस तरह गेंद को जितने जोर से जमीन पर मारने से उतने ही जोर से ऊपर उछलती है, उसी तरह बर्बरतम दमन चलाने के बावजूद भी कश्मीरी जनता के संघर्ष उतने ही उग्र होने लगे हैं। इन संघर्षों के फलस्वरूप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत शासक नेशनल कान्फ्रेंस गिरोह, विपक्षी पीडीपी और यहां तक हुरियत का नरमपंथी धड़ा भी पूरी तरह अलग–थलग पड़ चुके हैं। जनता की तीखी नफरत का शिकार बनकर वो

लाचारी में छटपटा रहे हैं। कश्मीरी जनता उनके मुंह पर ही 'भारतीय कुत्ता' कहकर दुत्कार रही है।

निरंतर जारी कर्फ्यू, गोलीबारी, 'मुठभेड़' हत्याओं, लापता करना, पग-पग पर अपमानजनक तलाशी आदि तमाम अमानवीय हालात की परवाह किए बगैर पुलिस की गोलीबारियों में मारे जाने वाले नौजवानों के जनाजों में हजारों की तादाद में उमड़ते हुए और समूची घाटी को जंग-ए-मैदान में तब्दील करते हुए हत्यारे पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों से जूझ रही कश्मीरियों का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) तहेदिल से इंकलाबी सलाम पेश करती है। सीआरपीएफ और पुलिस बल कश्मीर में जिस तरह निहत्थे नौजवानों की अंध ाधुंध गोली मारकर हत्या कर रहे हैं, उसी तरह यहां हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी संघर्ष के इलाकों में, खासकर दण्डकारण्य में कई निहत्थे आदिवासियों का नरसंहार कर रहे हैं। वहां पर आप लोग हाथ में आए पत्थरों से भाड़े के बलों के अत्याधुनिक हथियारों के सामने सीना तानकर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, यहां पर तीर-धनुषों से ही हमारी जनता लड़ रही है। चूंकि यहां की जनता की सुरक्षा में हमारी पार्टी के नेतृत्व में जन मुक्ति छापामार सेना खड़ी है, इसलिए आतंकी बलों पर हम कड़े प्रहार कर पा रहे हैं। यहां भी और वहां भी दुश्मन एक ही है। सामंती और बड़े पूंजीपति शासक वर्ग और उनके समर्थन में खड़े साम्राज्यवादी ही वहां और यहां पर अपने पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों को जनता के ऊपर उकसा रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के समूल उन्मूलन के लक्ष्य से 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से जनता के खिलाफ जारी युद्ध के तहत कई जुल्म व अत्याचार कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कि इन सांझे शत्रु बलों के खिलाफ आपके द्वारा किए जा रहे सभी संघर्षों का हमारी पार्टी, जन सेना और क्रांतिकारी जनता समर्थन करती रहेंगी।

कश्मीर पूरी तरह कश्मीरी जनता का ही है। उसके भविष्य का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ कश्मीरियों को ही होना चाहिए। न तो भारत सरकार को और न ही पाकिस्तान को कश्मीर पर कोई अधिकार है। कश्मीरी जनता का 'आजादी' आंदोलन पूरी तरह न्यायसम्मत है। कश्मीरी जनता की आजादी की तमन्ना को कुचलने के लिए ही भारतीय शासक वर्ग उसके खिलाफ नीचतापूर्ण दुष्प्रचार करते हुए अंतहीन दमन और फासीवादी हत्याकाण्डों को अंजाम दे रहे हैं। इसका

हिस्सा ही है लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाएं... कश्मीरी युवाओं को गोली मारकर कत्ल करने वाली घटनाएं। हम समूचे देशवासियों और जनवादियों से आग्रह करते हैं कि वे सरकार से मांग करें कि कश्मीर से तमाम अर्ध-सैनिक व सैनिक बलों को हटाया जाए और कश्मीरी नौजवानों को गोलियों से भून डालने वाले पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों और उनके अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम तमाम देशवासियों से अपील करते हैं कि वे कश्मीरी जनता के खिलाफ तथा उसके द्वारा जारी जायज संघर्षों के खिलाफ शोषक शासक वर्गों, खासकर भगवा आतंकवादी गिरोह द्वारा सुनियोजित ढंग से जारी भड़काऊ दुष्प्रचार से प्रभावित न हों और सच्चाई को समझते हुए न्याय के पक्ष में मजबूती से खड़े हों। कश्मीरी जनता के इस जबर्दस्त संघर्ष के सामने नैतिक रूप से पराजित होकर और ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर आदिवासियों के ऊपर अत्यधिक हिंसा व आतंक मचाने के बावजूद भी सामने आ रहे तीखे जन प्रतिरोध से बौखलाए हुए चिदम्बरम जी 'बातचीत' के नाम से और 'शंति' के नाम से जो बकवास कर रहे हैं उससे किसी को भ्रमित नहीं होना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी समूचे अवाम से इस सच्चाई को देखने की अपील करती है कि जनता की वास्तविक शांति, सुहृद्‌भाव, स्वतंत्रता आदि के लिए भारत के शासक वर्गों के साथ-साथ उनसे गुंथे हुए साम्राज्यवादी ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम तमाम जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन सांझे दुश्मनों के खिलाफ सभी वर्गों और सभी राष्ट्रीयताओं के लोग जब तमाम तरह के संघर्षों को तेज करेंगे और जब उनकी शोषणकारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तभी असली शांति और भाईचारा कायम होंगे तथा तभी जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वतंत्रता, सम्मान व समानता मिल जाएंगे।

अभय

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

23 सितम्बर 2010

अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे भारतीय शासक वर्गों की दरिंदगी की निंदा करो!

सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा लगातार जारी हत्याओं के खिलाफ तथा कश्मीरी जनता के न्यायपूर्ण आंदोलन के समर्थन में...

30 सितम्बर 2010 को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाओ!!

कश्मीर में सरकार द्वारा लोगों की हत्याओं का सिलसिला बेलगाम जारी है। सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा लगातार जारी मनमानी हत्याओं, अत्याचारों, बिना रुके जारी कर्फ्यू आदि की अवहेलना करते हुए पूरी कश्मीर की घाटी में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। 'आजादी' का नारा समूची घाटी में गूंज रहा है। 11 जून से शुरू कश्मीरी जनता के इस न्यायपूर्ण संघर्ष को कुचलने के लिए अर्ध सैनिक, सैनिक व पुलिस बलों द्वारा की जा रही गोलीबारियों में अभी तक सौ से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। (इनमें अत्यधिक बीस साल से कम उम्र के किशोर व नौजवान हैं।) सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। निहत्थे, शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर भारत के विस्तारवादी लुटेरे शासक वर्ग, जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, बेशर्मी के साथ सशस्त्र बलों को उकसाकर बेहद क्रूरता से दमन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार, खुद को वामपंथी कहने वाली सीपीएम व सीपीआई समेत सभी शासक पार्टियां कश्मीरियों पर हो रहे इस दमनचक्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रही हैं, वहीं हिंदू साम्प्रदायिकतावादी भाजपा सरकार को बार-बार उकसा रही है कि वह कश्मीरियों का बेहद सख्ती से दमन करे। केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीरी जनता पर जारी हिंसा में भाग लेने वाले भारतीय शासक वर्गों का वफादार सेवक ओमर अब्दुल्ला की सरकार जनता से पूरी तरह अलग-थलग पड़कर उनकी तीखी नफरत का शिकार बन रही है। लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ने के साथ-साथ हर प्रदर्शन पर गोलीबारी करना एक रिवाज सा बन गया है। इसी पृष्ठभूमि में कश्मीरी जनता, खासकर नौजवान हाथ में आए पथ्तरों से ही इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। इस अमानवीय दमनचक्र के विरोध में और अपनी आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा यह प्रतिरोध पूरी तरह न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक है।

कश्मीरी जनता ने खुद को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना। 1947 में अंग्रेजी शासकों से भारत और पाकिस्तान को मिली झूठी आजादी के पहले तक कश्मीर राजा हरिसिंह के शासन में एक स्वतंत्र देश के रूप में था। लेकिन कुटिलता में माहिर ब्रितानी साम्राज्यवादियों के पिट्ठू भारतीय व पाकिस्तानी लुटेरे शासक वर्गों ने अपने हितों के मद्देनजर कश्मीर को अपने देशों में जबरन मिला लिया जोकि कश्मीरियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं से पूरी तरह खिलाफ था। एक हिस्से पर भारतीय शासक वर्गों ने कब्जा किया तो बाकी हिस्से को पाकिस्तान ने हड़प लिया। इस तरह बेहद निंदनीय तरीके से इन्होंने कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया। उस समय कश्मीरियों के विरोध को ठण्डा करने के लिए नेहरू सरकार ने लिखित रूप से कश्मीरी जनता व संयुक्त राष्ट्र संघ से यह वादा किया था कि कश्मीर में रायशुमारी (जनमत संग्रह) कराई जाएगी और जनता अगर आजादी चाहती है तो दे दी जाएगी। नेहरू ने इस वादे को कई बार दोहराया भी था। लेकिन कुछ ही समय बाद से उन्होंने सैन्य जूतों तले कश्मीर को रौंदना शुरू किया। नेहरू से लेकर आज के सोनिया-मनमोहन तक दिल्ली में गद्दी संभालने वाली हर शासक पार्टी ने कश्मीरियों के साथ वादाखिलाफी ही की। जब भी आजादी के लिए आवाज उठी, भारतीय विस्तारवादी सरकारों ने कश्मीरियों पर दमन का ही प्रयोग किया। आंखों के सामने घट रहे इतिहास को और अपने ही किए हुए वादों को छुपाते हुए भारतीय शासक सुनियोजित तरीके से यह प्रचार करते आ रहे हैं कि 'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।' तबसे कश्मीरियों के दिलों में सुलगती आई आजादी की अदम्य इच्छा ने 1990 के दशक में मिलिटेंट हथियारबंद आंदोलन का रूप ले लिया। कई मिलिटेंट संगठनों ने हथियारबंद संघर्ष चलाया। उन संगठनों के राजनीतिक लक्ष्यों में कुछ फर्क होने के बावजूद उन्हें जनता का समर्थन हासिल हुआ था क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों की राष्ट्रीय मुक्ति की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया। लेकिन उस संघर्ष को कुचलने के लिए भारत के फासीवादी शासक वर्गों ने 7 लाख से ज्यादा सैनिक और अर्ध सैनिक बलों को तैनात कर समूची कश्मीर की घाटी का सैन्यीकरण किया और अभी तक 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों की जानें लीं। हजारों लोगों को सरकार ने लापता कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की किसी भी राष्ट्रीयता के संघर्ष पर किसी भी सरकार ने इतने ज्यादा समय तक, इतनी तीव्रता से, इतनी भारी संख्या में सशस्त्र बलों को उतारकर, इतने क्रूर तरीके से दमन नहीं किया। जब मिलिटेंट आंदोलन तीखे रूप से चल रहा था, तभी भारतीय शासक वर्गों ने कई साजिशों और षड्यंत्रों को रचकर 'फूट डालो और राज करो' वाली नीति से कश्मीरी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा पैदा किया। कश्मीरी जनता के जायज आंदोलन के खिलाफ कश्मीरी पंडितों को खड़ा करने की साजिशें लगातार जारी हैं। इसमें विशेषकर विस्तारवादी देशीय अंध

राष्ट्रवादी कांग्रेस और हिंदू धार्मिक साम्प्रदायिकतावादी फासीवादी संघ गिरोह की भूमिका बेहद नीचतापूर्ण है। 'मिलिटेन्सी' के रूप में प्रचलित कश्मीरियों के उस संघर्ष में कुछ पाकिस्तान-अनुकूल ताकतों और इस्लामिक ताकतों के शामिल होने के बहाने भारतीय शासकों का यह प्रचार कि कश्मीरियों का राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम पूरी तरह पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आंदोलन है तथा उनके आंदोलन का लक्ष्य भारत से अलग होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाना है, सरासर झूठ है। कश्मीरी जनता की आकांक्षा शुरू से ही अपनी राष्ट्रीयता की आजादी रही है। यही वजह है कि कश्मीर में मिलिटेन्सी को खत्म करने के दावे भले ही भारतीय शासक करते रहें, दरअसल यह संघर्ष रुका ही नहीं। अलग-अलग मौकों पर जिस किसी भी मुद्दे को लेकर यह आंदोलन उफान पर आया हो, 'आजादी' का नारा ही उसमें प्रमुखता से उठाया जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दृढ़तापूर्वक घोषणा करती है कि अपनी राष्ट्रीयता की आजादी के लिए तथा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए कश्मीरी जनता द्वारा जारी आंदोलन पूरी तरह न्यायपूर्ण है और कश्मीर पर न तो भारत को न ही पाकिस्तान को कोई हक है।

आजादी-पसंद कश्मीरी लोगो,

अपनी आजादी के लिए तथा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गों के खिलाफ जारी आपके संघर्ष का हमारी पार्टी समर्थन करती है और तहेदिल से भाईचारा प्रकट करती है। गोलीबारियों, लाठीचार्ज, कर्फ्यू, लगातार जारी तलाशी मुहिमों और अंतहीन अपमानों का मुकाबला करते हुए दृढ़ता के साथ जारी आपके संघर्ष का हमारी पार्टी भारत की समूची क्रांतिकारी, जनवादी व संघर्षरत जनता की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। अंधाधुंध गोलीबारियां करते हुए दर्जनों की संख्या में युवक-युवतियों का कत्लेआम करने के बावजूद भी शहीदों के शवों को कंध ों पर उठाकर जनाजों में हजारों की संख्या में भाग लेते हुए 'आजादी' का नारा बुलंद करने का आपका जज़्बा और कुरबानी का जोश इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। भारतीय विस्तारवादियों के भाड़े के सशस्त्र बलों की गोलीबारियों में अपनी जानें गंवाने वाले शहीदों के परिजनों, दोस्तों और समूचे कश्मीरी कौम के प्रति हमारी पार्टी गहरी संवेदना प्रकट करती है। आज जो भारतीय शासक वर्ग आपके संघर्ष पर विघटनकारी और देशद्रोहपूर्ण आंदोलन का ठप्पा लगाकर आपको अलग-थलग करने के नापाक मंसूबे से मनमानी हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, वे ही आज भारत की समूची शोषित जनता, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और व्यापक जन समुदायों के घोर दुश्मन हैं। इसलिए, आइए, अपने सांझे दुश्मनों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर लड़ें। इस लड़ाई को और तेज करें।

भारत के इंसाफ-पसंद लोगो,

कश्मीरी जनता के जायज संघर्ष के खिलाफ भारतीय लुटेरे शासक वर्ग, खासकर कांग्रेस व भगवा आतंकी गिरोह सुनियोजित तरीके से जो भड़काऊ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उससे प्रभावित न होवें। हमारी पार्टी आप सभी से अपील करती है कि आप सच्चाई को समझते हुए न्याय के पक्ष में मजबूती से खड़े होवें।

इस मौके पर हमारी पार्टी की ठोस मांगें इस प्रकार हैं -

1) कश्मीर में भारत के सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी हत्याओं को फौरन रोको।

2) सैन्य बलों को जनता को मनमाने ढंग से मार डालने का अधिकार देने वाले फासीवादी कानून - 'सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार कानून' (एफपीएसए) को फौरन रद्द करो।

3) कश्मीर से अर्ध सैनिक व सैनिक बलों को फौरन वापस लो।

4) कश्मीर में रायशुमारी (जनमत संग्रह) करवाकर कश्मीरी जनता को अपने भविष्य का फैसला खुद ही करने का अधिकार दो।

5) तमाम राजनीतिक बंदियों को फौरन रिहा करो।

आप सभी से हमारा आह्वान है कि कश्मीरी जनता पर सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी हत्याकाण्डों के खिलाफ तथा कश्मीरियों के जायज संघर्ष के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए आप 30 सितम्बर को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाएं। इस 'भारत बंद' के दौरान छह राज्यों - बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र के गड़चिरोली, गोंदिया व चंद्रपुर जिलों तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में रेलवे, सड़कें, बैंक, सरकारी व निजी कार्यालय, उद्योग-धंधे, शिक्षा व व्यापार संस्थानों को बंद रखने व उसमें उपस्थित न होने का हम जनता से आह्वान कर रहे हैं। हालांकि हम मेडिकल आदि अत्यावश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखेंगे।

आनंद
सचिव, मध्य रीजनल ब्यूरो
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

31 अक्टूबर 2010

विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद का सरगना
बराक ओबामा के भारत दौरे का जोर शोर से विरोध करो!
गांव-गांव और गली-गली में "ओबामा! वापस जाओ!!" का नारा बुलंद करो!!

आगामी 6 नवम्बर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आने वाला है। हमारे देश के दलाल शासक उसके स्वागत में लाल कालीन बिछाकर मुम्बई व दिल्ली महानगरों को सजाने-संवारने में लगे हुए हैं। यह देश के तमाम जनवाद-पसंद, अमन-पसंद और देशभक्त अवाम के लिए बड़ा अपमान है। दुनिया के पिछड़े देशों का बेरहमी से शोषण करने वाला, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का दमन करने वाला, बदनाम तानाशाहों को सत्ता पर बिठाने वाला, सहयोग नहीं देने वाले देशों को आए दिन डराने-धमकाने वाला, विश्व के तेल, खनिज व अन्य तमाम सम्पदाओं और संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने के लिए किसी भी हद तक जाकर दरिंदगी का नंगा प्रदर्शन करने वाला अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन है। इसका नेतृत्व करने वाला बराक ओबामा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे समूची जनता को दुत्कारना चाहिए। चूंकि उसके पूर्वाधिकारी जार्ज बुश से दुनिया भर की जनता बेहद नफरत करने लगी थी, इसलिए अमेरिकी साम्राज्यवादी आकाओं ने सुनियोजित तरीके से बराक ओबामा को सामने लाया ताकि उसके शरीर के रंग से लोगों को धोखा दिया जा सके। बुश की नीतियों के विरोध में ओबामा ने चाहे जो भी कहा हो, व्हाइट हाउज में कदम रखने के बाद से अभी तक उसने जो भी नीतियां अपनाईं और जो भी फैसले लिए, वो सब बुश प्रशासन की धारावाहिकता के रूप में ही हैं। दरअसल जार्ज बुश और बराक ओबामा के बीच शरीर के रंग में तथा प्रतिनिधित्व वाली पार्टियों

के नाम में ही फर्क है। दुनिया की जनता, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, देशों और अमेरिकी मजदूर वर्ग को लूटने-खसोटने में तथा उनका दमन करने में उनके बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं है। यह अकाट्य सच्चाई है कि अमेरिकी साम्राज्यवादी व्यवस्था को अपने उंगलियों पर नचाने वाले एकाधिकारी कॉर्पोरेट संस्थाओं के बदनाम गोरे प्रभुओं ने ही इस काले रंग के राष्ट्रपति का चयन किया था।

आज अफगानिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान में अमेरिकी साम्राज्यवादी हर दिन बम बरसाकर तथा ड्रोन हमले कर मासूम नागरिकों के कत्लेआम कर रहे हैं। इराक में बर्बर कत्लेआमों का सिलसिला अभी भी जारी है। ओबामा ने अपने शासनकाल में अफगानिस्तान को 30 हजार अतिरिक्त अमेरिकी फौजियों को भिजवाकर अपने युद्धोन्मादी चरित्र का परिचय दिया। इस भूगोल को कम से कम दस बार तबाह कर सकने वाले विनाशकारी हथियारों के जखीरे पर खड़ा अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने युद्ध उद्योग को, जोकि उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, संकट में फंसने से बचाने के लिए युद्ध भड़का रहा है और खुद युद्ध कर रहा है। दूसरी तरफ वह परमाणु क्षमताओं को विकसित करने के नाम पर इरान व उत्तर कोरिया को निरंतर धमकियां दे रहा है। फिलहाल वह अल क़ायदा को शह देने के आरोप में येमेन पर निशाना साध रहा है। 9/11 के हमलों के बाद 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के नाम से जार्ज बुश द्वारा शुरू किए गए फासीवादी हत्याकाण्ड व हिंसाकाण्ड को ओबामा बिना किसी व्यवधान के जारी रखते हुए अल क़ायदा, तालिबान और इस्लामिक आतंकवादियों का दमन करने के नाम से अंधाधुंध हमले कर रहा है। गाज़ा को धरती पर नरक में तब्दील करने वाले इज़्राएली यहूदी अंधराष्ट्रवादियों द्वारा जारी पाशविक हमलों और उसके बदनाम खुफिया संगठन मोसाद द्वारा जारी षड़यंत्रपूर्ण हत्याओं को रुकवाने की कोशिश न करके तथा उसका खण्डन न करके ओबामा सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत का जिम्मेदार बन गया।

अमेरिकी खुफिया संस्था एफबीआई घिनौनी करतूतों को अंजाम देते हुए स्टिंग ऑपरेशन्स के जरिए मासूम अमेरिकी मुसलमानों को, खासकर पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नौजवानों को हमलों के लिए उकसाकर, आखिर में कोवर्ट ऑपरेशन्स में उन्हें सबूतों के साथ गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबियां हासिल करने का झूठा प्रचार कर रहा है। यह तरीका ओबामा के शासन में स्पष्ट रूप से सामने आया है जोकि बुश की विरासत ही है। इस तरह उसकी सरकार एक तरफ

अमेरिकी जनता में असुरक्षा की भावना को लगातार बरकरार रखते हुए दूसरी तरफ जनता से जुटाए गए धन को भारी पैमाने पर अपने 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' में लगा रही है। इस तरह वह अमेरिका के अंदर मुस्लिम समुदाय को, कुल मिलाकर अमेरिकी श्रमिक जनता को पीड़ा और हताशा के गहरे गड्ढे में धकेल रही है।

आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऐसे तीव्र आर्थिक संकट में फंसी हुई है जहां से उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। सब-प्राइम संकट के रूप में फूट पड़ने वाले इस संकट ने इतना तीव्र रूप धारण कर लिया है कि 1930 के दशक के बाद कभी नहीं देखा गया। 10 प्रतिशत से ऊपर चली गई बेरोजगारी की दर उसके इतिहास में ही अभूतपूर्व है। लेकिन ओबामा तो सैकडों अरब डॉलरों का जन-धन पहले से बेहद मोटाए हुए एकाधिकारी कार्पोरेट संस्थाओं की जेबों में पहुंचाकर अमेरिकी जनता को, खासकर श्रमिकों व मध्यम वर्ग को बेहिसाब तकलीफें पहुंचा रहा है। उसने जन कल्याणकारी योजनाओं में कई कटौतियां कीं। इसके बावजूद भी इस संकट के भंवर से बाहर आने में नाकाम अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वह पिछड़े व गरीब देशों से संसाधनों की लूट-खसोट में और ज्यादा तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। अब ओबामा के साथ-साथ कॉर्पोरेट घरानों के मोटाए हुए बड़े सेठ हमारे देश में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुम्बई और दिल्ली महानगरों की खूबसूरती को देखकर खुश हुआ जा सके। बल्कि यहां पर और ज्यादा पूंजी का बहाव कर, इस देश का खून और ज्यादा क्रूरता से चूसने वाले कई और समझौते करने के लिए वो आ रहे हैं ताकि अपने संकट का बोझ भारत पर और ज्यादा लादने की योजनाओं को अंजाम दिया जा सके। हमारे देश के संसाधनों को मनमाने लूटने-खसोटने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट के रूप में खड़े माओवादी आंदोलन समेत सभी जन आंदोलनों का और ज्यादा क्रूरता से दमन करने में सलाह-सुझाव देने के लिए वो यहां आ रहे हैं।

भारत के सामंती व बड़े पूंजीपति शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूपीए सरकार और उसका नेतृत्व करने वाले मनमोहनसिंह ने अपने शासन के पहले ही दौर में जनता की खिलाफत की जरा भी परवाह न करते हुए अमेरिका के साथ परमाणु करार कर अमेरिकी साम्राज्यवाद के नमकहलाल सेवक के रूप में घुटने टेक दिया था। अभी हाल में संसद द्वारा पारित 'परमाणु दायित्व विध ेयक' इसी नीति की कड़ी है। हजारों लोगों की बेमौत तथा लाखों लोगों की

जिंदगी में अंधेरा छाने के लिए जिम्मेदार भोपाल गैस रिसाव के हादसे का जख़्म और उसकी पीड़ा भारतवासियों के दिलोदिमाग में अभी भी ताजा है। इसके बावजूद ऐसे कई और 'भोपाल' पैदा करने के लिए तथा ऐसी घोर दुर्घटनाएं होने पर भी उसके लिए जिम्मेदार विदेशी पूंजीपतियों को जहां तक संभव हो कम से कम 'जुर्माना' भरकर आसानी से बच सकने का मौका देते हुए (जैसे कि वारेन एण्डरसन और डाउ केमिकल्स को दिया गया था) यूपीए सरकार ने निर्लज्जता और निरंकुशता से इस विधेयक की रूपरेखा तैयार की थी। इस विधेयक को पारित करवाने में जहां भाजपा ने 'चोर-चोर मौसेरे भाई' की तरह सरकार की मदद की, वहीं अपने आपको कम्युनिस्ट बताने वाली चुनावी वामपंथी पार्टियों ने इस देशद्रोहपूर्ण विधेयक का मजबूती से विरोध न करके तथा इसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा न करके अपने दलाल चरित्र की फिर एक बार नुमाइश पेश की। ओबामा के भारत दौरे से पहले ही इस विधेयक को पारित करवाने के लिए मनमोहनसिंह ने कमर कसकर पूरा जोर लगाया था।

हाल के सालों में अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी मानचित्र पर नए खिलाड़ी के रूप में उभरने वाले चीन को घेरने वाली अमेरिकी भू-राजनैतिक रणनीति में भारत सरकार अमेरिका के मोहरे की तरह काम कर रही है। अमेरिका इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने इशारों पर नचवाते हुए दूसरी तरफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन दोनों के बीच दुश्मनी बरकरार रहे। वह दोनों देशों को हथियार बेचते हुए, दोनों ही देशों के बाजारों को लूट रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र पर दबदबा कायम करते हुए वह अपनी वैश्विक आधिपत्यवादी रणनीति को लागू कर रहा है। इसके बावजूद भी कि अमेरिका हर दिन अफगानिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में बमबारी कर रहा है, भारत के शासक वर्ग इस पर जरा भी आपत्ति नहीं जताते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके बदले में अमेरिका दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा लागू दखलंदाजी और लूट-खसोट की नीतियों का समर्थन कर रहा है। सांठगांठ की इस राजनीति का हिस्सा ही है ओबामा का यह दौरा और यहां के दलाल शासकों व विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा स्वागत।

संसदीय वामपंथी ओबामा के इस दौरे का साफ तौर पर विरोध करने की बजाए संसद में इस जंगखोर के भाषण को ध्यान से सुनने को बेताब हो रहे हैं। यह कहते हुए कि बुश और ओबामा में फर्क है, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि इन दोनों के बीच फर्क इतना ही है

जितना कि नागनाथ और सांपनाथ के बीच है। सहज ही, भाजपा अपने कट्टर दलाल चरित्र के अनुसार कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर ओबामा का स्वागत कर रही है।

प्यारे लोगो! जनवाद के प्रेमियो!! ओबामा का स्वागत करने का मतलब है संप्रभुता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, शांति, न्याय, लोकतंत्र वगैरह मूल्यों के साथ गद्दारी। ओबामा के लिए लाल कालीन बिछाने का मतलब है उसकी युद्धोन्मादी, दुराक्रमणकारी, लूटखोर और आधिपत्यवादी नीतियों के सामने घुटने टेकना। इसलिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी तमाम जनता, क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों तथा देशभक्तिपूर्ण ताकतों का आह्वान कर रही है कि वो ओबामा के आने के मौके पर विभिन्न स्वरूपों में अपना विरोध प्रकट करें तथा 'ओबामा! वापस जाओ' का नारा बुलंद करें। हम आह्वान कर रहे हैं कि वो इस मौके पर पर्चों, पोस्टरों व बैनरों से, सभा-सम्मेलनों का आयोजन कर ओबामा के दौरे का विरोध करें; अमेरिकी सम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेककर देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाने वाली यूपीए सरकार और उसके सुर में सुर मिलाने वाली अन्य दलाल संसदीय पार्टियों की दगाबाजी का कड़ा विरोध करें।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी,

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

27 नवम्बर 2010

क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लक्ष्य से नक्सल इलाकों के 'विकास' के नाम से लाई गई एकीकृत कार्य योजना जनता की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं करेगी! हजारों करोड़ों रुपए के घोटालों से देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने-खसोटने वाले देशद्रोहियों को कड़ा सबक सिखाओ!!

नक्सल प्रभावित जिलों में 'विकास' के नाम पर केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा बनाई गई 13,742 करोड़ रुपए की 'एकीकृत कार्य योजना' का कल 26 नवम्बर को केन्द्रीय आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अनुमोदन किया था। दो साल तक चलने वाले इस योजना के पहले चरण में 9 नक्सल प्रभावित राज्यों के 60 जिलों के लिए मौजूदा वर्ष 2010-11 के लिए 25 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में प्रत्येक जिले को 30 करोड़ के हिसाब से पैसा आवंटित करते हुए कुल 3,300 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम ने की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट कमेटी ने दो सालों बाद इस योजना की समीक्षा करने का फैसला लिया। शासकों का कहना है कि इन गरीब व आदिवासी जिलों में जहां 50 फीसद से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर 'विकास' करना उनका लक्ष्य है ताकि नक्सलवाद की 'समस्या' का हल किया जा सके। जिन 'बुनियादी सुविधाओं' की बात ये लोग कह रहे हैं उसमें सड़कें सबसे ऊपर हैं और उसके बाद पंचायत भवन, बिजली, स्कूल भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हैं। एक तरफ 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से पिछले एक साल में इन इलाकों में शासकों द्वारा दो लाख से ज्यादा विभिन्न अर्धसैनिक बलों को तैनात कर सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार करते हुए, दूसरी तरफ इन्हीं इलाकों में करोड़ों रुपए का बहाव क्या

जनता के हितों में कर रहे हैं? या फिर जनता पर जारी दमनकारी कार्रवाइयों में और ज्यादा तेजी लाने के लिए? इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है। यह घोषणा करते हुए चिदम्बरम ने जोर देकर कहा था कि आगामी मार्च माह तक आवंटित धन राशि को पूरा खर्च करके 'विकास' दिखाया जाएगा। इस योजना को लागू करने में पुलिस विभाग को भी शामिल करते हुए पुलिस अधीक्षकों को कमेटियों में भागीदार बनाने का फैसला अब तक लागू फासीवादी दमन की नीतियों पर 'विकास' का मुखौटा पहनाने की कोशिश भर है। सड़कों और भवनों का निर्माण क्या 'गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब जनता' के लिए किया जाएगा? या फिर उन सरकारी सशस्त्र बलों की सुविधा के लिए जो जनता के जीने के अधिकार को कुचलते हुए अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब इन इलाकों में कोई भी आदिवासी दे सकता है। एक सच्चाई यह है कि अब तक मौजूद विद्यालयों को सरकारी सशस्त्र बल अपने अड्डों में बदलकर यहां पर शिक्षा के प्रसार के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा खुद ही बन गए हैं। इस बात को छिपाकर करोड़ों रुपयों से शिक्षा की सुविधाएं बनाने का दावा करना ध ोखा ही है। उल्टी, दस्त जैसी छोटी-छोटी बीमारियों से हर साल सैकड़ों, हजारों की संख्या में बेमौत मर रहे आदिवासियों पर कभी नहीं ध्यान देने वाले शासकों के इस कथन को कि वो इस पैकेज से जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, कोई भी विश्वास नहीं करेगा।

वास्तव में, खासतौर पर पिछले दो महीनों से ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन घोटालों की बात नहीं हुई हो। हजारों करोड़ों का जन धन किस तरह भ्रष्ट राजनेताओं, मंत्रियों, बड़े-बड़े अफसरों, कार्पोरेट मालिकों और नामी मीडिया सम्राटों की जेबों में जा रहा है, देश की जनता साफ तौर पर देख-समझ रही है। माओवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है कहकर बार-बार चिल्लाने वाले शासक और उनका ढोल बजाने वाले ढोंगी बुद्धिजीवी खुद कितने बड़े डाकैत हैं, इसे समझने के लिए इतिहास की गहराई में न जाकर कामनवेल्थ गेम्स घोटाला (करीब एक लाख करोड़ रुपए का), 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला (एक लाख छहत्तर करोड़ वाला), आदर्श हाउजिंग सोसाइटी घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला वगैरह कुछ ताजा उदाहरणों पर नजर डालना

काफी होगा। कांग्रेस, भाजपा, डीएमके, जनतादल वगैरह सभी शोषक वर्गों की पार्टियां बिना किसी अपवाद के इस अंधाधुंध लूटखसोट में भागीदार बन गईं। इन सभी घोटालों ने इस सड़ी-गली व्यवस्था को जनता की आंखों के सामने नंगा कर दिया है। व्यवस्थीकृत भ्रष्टाचार से ओतप्रोत इस शोषक व्यवस्था को ढहाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इस माओवादी अवधारणा को देश की जनता की स्वीकृति दिन-ब-दिन बढ़ रही है। दरअसल यही शोषक शासक वर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

भ्रष्टाचार की यह ताजातरीन तस्वीर जब लोगों की नजरों में इतनी साफ हो, इस आर्थिक पैकेज के तहत दिए जाने वाले करोड़ों रुपए किनकी जेबों में जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वास्तव में यह घोषणा करते समय शासकों को डर लगना चाहिए था कि आज की परिस्थिति में ऐसे आर्थिक पैकेजों से जनता का विकास होने की बात करने से लोग हंस पड़ेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया, जिन्होंने इस एकीकृत कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की थी, और चिदम्बरम जिन्होंने इसे स्वीकृति दी, साम्राज्यवादी कार्पोरेट संस्थाओं की पूरी वफादारी से सेवा कर चुके हैं। इस शासक गिरोह की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह अपनी उम्र का आधा से ज्यादा हिस्सा साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं की सेवा में गुजार चुके हैं। ऐसे में यह समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं से किनके हित पूरे होने वाले हैं। सरकारें एक तरफ देश के आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूटखसोट का रास्ता साफ करते हुए कॉर्पोरेट कम्पनियों के साथ दसियों करोड़ों रुपए के एमओयू पर दस्तखत कर रही हैं जिससे आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। दूसरी ओर, उन समझौतों का जनता के सामने खुलासा करने और उन्हें रद्द करने की मांग, जो देश की जनता और जनवादियों की तरफ से उठाई जा रही है, को अनसुना करते हुए 'विकास' की रट लगाना हास्यास्पद है।

हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी इस जन विरोधी 'एकीकृत कार्य योजना' का कड़ा विरोध करती है। हमारी केन्द्रीय कमेटी मानती है कि यह केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से लागू

फासीवादी दमन अभियान का ही हिस्सा है और उसमें सहायता करने वाली है। यह कहना कि इससे पिछड़े इलाकों का विकास होगा, बहुत बड़ा ढोंग है। अगर इन व्यापक वन इलाकों में आदिवासियों और शोषित जनता के विकास के प्रति जरा भी ईमानदारी है तो सरकारों को उन्हें जल-जंगल-जमीन पर अधिकार देना चाहिए; बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपतियों की कम्पनियों के साथ किए गए एमओयू को रद्द कर देना चाहिए; भारी बांधों, खदानों, अभयारण्यों, भारी-भरकम स्टील प्लांटों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के चलते लाखों लोगों को विस्थापित करने वाली सारी योजनाओं को वापस लेना चाहिए; आदिवासियों के नरसंहारों से चलाए जा रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट को फौरन बंद कर देना चाहिए।

हमारी केन्द्रीय कमेटी इस मौके पर मांग करती है कि कामनवेल्थ गेम्स, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श हाउजिंग सोसाइटी घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला आदि में लिप्त राजनेताओं, मंत्रियों व कॉर्पोरेट घरानों के मालिकों को; और मलेगांव, अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद आदि बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकी नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

अभय

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

4 दिसम्बर 2010

6 दिसम्बर को हिंदू साम्प्रदायिकतावाद के खिलाफ काला दिवस मनाओ!

बाबरी मस्जिद का उसी जगह पर पुनरनिर्माण करो! हिंदू फासीवादी ताकतों को अलग-थलग कर हरा दो!! मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, समझौता एक्सप्रेस आदि बम विस्फोट की घटनाओं के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकवादियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दो!

आज से 18 साल पहले, 1992 में, दिसम्बर 6 तारीख को संघ गिरोह के हिंदू साम्प्रदायिक फासीवादी गुण्डों ने केन्द्र में सत्तारूढ़ तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रत्यक्ष/परोक्ष मदद से आयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। करीब 500 सालों से मुसलमानों की प्रार्थनास्थल के रूप में अस्तित्व में रही बाबरी मस्जिद को यह कहकर कि वह पहले राम की जन्म भूमि थी, विवाद खड़ा कर हिंदू साम्प्रदायिक फासीवादियों ने देश में कई दफे साम्प्रदायिक दंगे भड़काकर हजारों मुसलमानों की जानें लीं। हमारे देश में साम्प्रदायिक फासीवादियों का सबसे भयानक हमला था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इसमें प्रत्यक्ष रूप से शिरकत करने वाले एल.के. आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण तोगड़िया, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा आदि को हमारे देश की अदालतों ने आज तक कोई सजा नहीं दी। विवादित जमीन के मालिकाने को लेकर 61 सालों से लंबित मामले की सुनवाई करते हुए 30 सितम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने अपनी ब्राह्मणवादी हिंदूवादी विचारधारा के

अनुरूप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की। बिना किसी ऐतिहासिक आधार के और बिना किसी पुरातात्विक सबूत के ही उस स्थल को राम के जन्म-स्थल के रूप में व्याख्यायित किया। बाबरी मस्जिद को हड़पकर उसे तोड़ने और अब मस्जिद की जमीन पर कानूनी रूप से मंदिर बनाने का फैसला सुनाते हुए जमीन को मस्जिद तोड़ने वाली ताकतों को ही सौंप कर भारतीय राज्य ने अपने हिंदू फासीवादी चरित्र को फिर एक बार उजागर किया है। इस फैसले से यह बात फिर एक बार साबित हो गई कि देश की अदालतें लुटेरे वर्ग-अनुकूल और ब्राह्मणवादी हिंदूवादियों की हितैषी हैं तथा मजदूर-किसानों, दलितों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ नहीं करने वाली हैं। यह बात फिर एक बार स्पष्ट हो जाती है कि यह अदालतों के फैसलों से हल होने वाला नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को जड़ से बदलकर नई जनवादी राज्यव्यवस्था की स्थापना करने से ही इसका समाधान हो सकता है।

हाल ही में मालेगांव, अजमेर शरीफ, हैदराबाद मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस आदि बम विस्फोटों के मामलों में संघ गिरोह के भगवा आतंकी गुटों का हाथ होने के कई सबूत सामने आए हैं। 'अभिनव भारत' आदि छद्म नामों से वीएचपी, आरएसएस, बजरंगदल आदि संगठनों के नेताओं ने कई साजिशों और षड़यंत्रों के तहत बम विस्फोट करवाकर कई बेकसूर लोगों की जानें लीं। जहां भी बम विस्फोट होता है, यहां तक कि मस्जिदों में भी बम विस्फोट होता है, तब भी मुसलमानों को ही दोषी ठहराना हमारे देश में पुलिस और खुफिया संगठनों के लिए आम बात हो गई है। सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को बिना वजह गिरफ्तार कर क्रूर यातनाएं देना, फर्जी मुठभेड़ों में मार डालना, झूठे मामलों में फंसाना, आईएसआई के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करना सरकारों की साम्प्रदायिक फासीवादी नीतियों का हिस्सा है। मुसलमान होना ही आतंकवादी होने के बराबर दिखाते हुए मीडिया के जरिए प्रचार कर उनका हर प्रकार से दमन किया जा रहा है। मुम्बई हमलों में शामिल अजमल कसाब को फांसी की सजा देने की मांग करने वालों का संघ गिरोह के हिंदू साम्प्रदायिक हत्यारों के बारे में चुप्पी साध लेना या फिर जोर से आवाज नहीं उठाना एक खतरनाक संकेत है। सरकारें भगवा आतंकियों को गिरफ्तार न

करके, कुछेक बार गिरफ्तार करने पर भी सतही छानबीन के बाद फिर से रिहा करते हुए निर्दोष करार दे रही हैं। दूसरी ओर इन हिंदू साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, मीडिया संगठनों, अखबारों और कलाकारों पर संघ गिरोह कई जगहों पर हमले कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की राज्यव्यवस्था में साम्प्रदायिक फासीवादी रुझान रोज-ब-रोज तीव्र रूप धारण करने लगे हैं।

हिंदू साम्प्रदायिक फासीवाद के खिलाफ सभी धर्मों से जुड़े तमाम ध र्मनिरपेक्ष ताकतों, जनवादियों और प्रगतिशील सोच वालों को संगठित होकर लड़ना चाहिए। हिंदू फासीवादी ताकतों के द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों आदि ध ार्मिक अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों का कड़ा विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ, सभी किस्म के धार्मिक कट्टरवाद का विरोध करना चाहिए।

हमारी पार्टी शुरू से यह मांग करती आ रही है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी वह मुसलमानों की है; उस पर मुसलमानों का ही मालिकाना होना चाहिए; बाबरी मस्जिद का फिर से उसी जगह पर निर्माण करना चाहिए; और उसे ढहाने वाले संघ गिरोह के फासीवादी नेताओं को कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील व क्रांतिकारी ताकतों, संगठनों और पार्टियों से आग्रह करती है कि वे इस मांग का समर्थन करें। हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनता का आह्वान करती है कि 6 दिसम्बर को हिंदू धर्मोन्माद के खिलाफ 'काला दिवस' मनाएं तथा इस मौके पर सभा, सम्मेलनों और जुलूसों का आयोजन करें और काली पट्टियां पहनें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

24 दिसम्बर 2010

जनता की सेवा षड़यंत्र नहीं है! जन पक्षधरता देशद्रोह नहीं हो सकता!!
लाखों करोड़ों रुपए की जनता की गाढ़ी कमाई को डकारने वाले घोटालेबाज ही देशद्रोही हैं!
देश को साम्राज्यवादियों के हाथों बेचने वाले सौदेबाज ही षड़यंत्रकारी हैं!!

मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन, माओवादी नेता कॉमरेड नारायण सन्याल और व्यापारी पियूष गुहा को देशद्रोह के मामले में आजीवन कारावास; तथा पत्रिका संपादक असित सेनगुप्ता को आठ साल के कारावास की सजा सुनाते हुए छत्तीसगढ़ की फासीवादी अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ 2 से 8 जनवरी 2011 में विरोध सप्ताह मनाएं!

24 दिसम्बर को रायपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन, हमारी पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड नारायण सन्याल और व्यापारी पियूष गुहा को फर्जी मामलों में फंसाकर आई.पी.सी., छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून और गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यू.ए.पी.ए.) के तहत आजीवन कारावास की सजा देते हुए फैसला सुनाया। आई.पी.सी. की धारा 124 (देशद्रोह) और 120-ख (षड़यंत्र) के तहत आजीवन कारावास और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून व यू.ए.पी.ए. की कई धाराओं के तहत विभिन्न सजाएं निर्धारित करते हुए बी.पी. वर्मा द्वारा सुनाया गया यह फैसला देश के शासक वर्गों की जन विरोधी व फासीवादी नीतियों का घिनौना उदाहरण है।

हमारी पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड नारायण सन्याल के साथ-साथ पी.यू.सी.एल. के उपाध्यक्ष बिनायक सेन, जो पिछले 30 सालों से जनता की सेवा में निस्वार्थ रूप से समर्पित डॉक्टर तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में

सुविख्यात हैं, और कोलकाता के एक व्यापारी पियूष गुहा को आजीवन कारावास की सजा देना देश के शासकों की बेशर्मी भरी करतूत है, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते नहीं थकते हैं। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि डॉक्टर बिनायक सेन को यह सजा सिर्फ इसलिए दी गई हैं क्योंकि वो सरकार की दमनकारी नीतियों और फासीवादी सलवा जुडूम का शुरू से विरोध करते रहे; काला कानून छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून (सी.एस.पी.एस.ए.) के खिलाफ आवाज उठाते रहे; और जायज जन आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे। मई 2007 में जब उन्हें गिरफ्तार कर दो सालों तक जेल में रखा गया था, तब देश भर में तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनवादी तबकों, चिकत्सा जगत् तथा नोबेल लारिएटों की तरफ से बड़े पैमाने पर प्रकट हुए विरोध को भी दरकिनार करते हुए दी गई ये सजाएं देश के फासीवादी शासक गिरोह द्वारा जनवादी, प्रगतिशील और देशभक्तिपूर्ण तबकों को दी जा रही निर्लज्ज और उन्मत्त धमकी है। जन समस्याओं को कानूनी और जनवादी तरीके से उठाना, ईमानदारी से जनता की सेवा करना और सरकारों की जन-विरोधी नीतियों की आलोचना करना - अगर यही देशद्रोह है तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस देश में लागू 'लोकतंत्र' किस ढंग का है और उससे जनता को कितना खतरा है। दुनिया भर में कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी प्रत्रिका - 'ए वर्ल्ड टु विन' का हिंदी संस्करण संभालने वाले असित सेनगुप्ता, जो अवैध गिरफ्तारी के बाद पिछले तीन सालों से जेल में हैं, को भी इसी दिन एक और फैसले में जिला अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायमूर्ति ओ.पी. गुप्ता ने आठ साल की सजा सुनाई, जोकि प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। हाल ही में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, डी.जी.पी. विश्वरंजन, बस्तर आई.जी. लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एस.पी. कल्लूरी के गिरोह ने 'मां दंतेश्वरी आदिवासी स्वाभिमानी मंच' के नाम से पर्चे छापकर जनवादी बुद्धिजीवी हिमांशु कुमार व अरुंधति रॉय के साथ-साथ पत्रकार एन.आर.के. पिल्लै, अनिल शर्मा और यश्वंत राव की हत्या करने की खुलेआम धमकी दी जो उनकी फासीवादी नीतियों का हिस्सा है।

हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व 73 साल के उम्रदराज कॉमरेड नारायण सन्याल को छत्तीसगढ़ की दमनकारी रमन सरकार ने पिछले पांच सालों से जेल की कालकोठरी में बंद कर कई झूठे मुकदमों में फंसाकर रखा है। वो 1968 से शुरू कर पिछले चार दशकों से ज्यादा समय से देश की दबी-कुचली जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेता हैं। उन्हें जेल के भीतर गंभीर बीमारियों के साथ-साथ कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़

रही हैं। आतंकी सोनिया-मनमोहन सिंह-चिदम्बरम-रमन सिंह गिरोह जहां एक तरफ क्रांतिकारी नेताओं को षड़यंत्रकारी तरीके से उठा ले जाकर फर्जी मुठभेड़ों में हत्या कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फर्जी मामलों में फंसाकर काले कानूनों के तहत कठोर सजाएं दिलवा रहा है।

छत्तीसगढ़ के विधायकों को माओवादी प्रचार की सीडी भेजने के मामले में विगत 29 जुलाई को सुनाए गए एक फैसले में हमारी पार्टी कार्यकर्ता कॉमरेड मालती उर्फ शांतिप्रिया व मजदूर सुरेंद्र कोसरिया को छत्तीसगढ़ सरकार ने झूठी गवाहियों के आधार पर दस साल की सजा दिलवाई। झारखण्ड के रांची जेल में बंद हमारी पार्टी के एक और पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड अमिताभ बागची और बंगाल राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड कार्तिक को भी एक फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए सरकार ने उम्र कैद की सजा सुनवाई। आंध्रप्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर को अलिपिरी मामले (आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू पर किए गए हमले के मामले) में झूठी गवाही दिलवाकर कॉमरेड पाण्डूरंगा रेड्डी उर्फ सागर समेत चार लोगों को सात साल की सजा दिलवाई। और भी कई जगहों पर अनगिनत क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और आम जनता को इन शोषक वर्गीय अदालतों ने फांसी से लेकर विभिन्न किस्म की सजाएं सुनाईं। वरिष्ठ व उम्रदराज नेता तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कॉमरेड्स सुशील रॉय व कोबड गांधी के साथ-साथ शोभा, पतितपावन हलदार, प्रमोद मिश्र, विजय, आशुतोष, बलराज, चिंतन, बिमान, बिधान, चंडी सरकार, बालगणेश आदि हजारों कॉमरेडों व लोगों को, सांस्कृतिक संगठन 'झारखण्ड अभेन' के नेता जीतन मराण्डी आदि जन नेताओं को लम्बे समय से जेलों में बंदकर, उनकी जमानत की अर्जियों को नामंजूर करते हुए, उन पर एक के बाद एक फर्जी मामला दर्ज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की जेल में कॉमरेड स्वपनदास को जेल प्रशासन ने चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कर कत्ल कर दिया जोकि यू.ए.पी.ए. के तहत पहली हत्या थी।

हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं तथा श्रमशक्ति को वेदांता जैसी साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल जैसे दलाल पूंजीपतियों के हाथों लुटवाने की ठान लेकर यू.पी.ए. सरकार ने इस मनमानी लूट की राह में बाधा के रूप में खड़े माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया। इसके तहत ही वह अपने प्रचार साध नों के जरिए जहरीली दुष्प्रचार-मुहिम चला रही है। अगस्त 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ बर्बर हमला चलाया जा रहा है जिसके तहत हजारों पुलिस व अर्धसैनिक बलों

को उतारकर, खासकर आदिवासियों का कत्लेआम किया जा रहा है। यह हमला साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में तथा संपूर्ण समर्थन से चल रहा है। हमारे देश को साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के शिकंजे से आजाद कर मजदूर-किसान एकता के आधार पर जनवादी वर्गों की जन सत्ता स्थापित करने के महान लक्ष्य से संघर्षरत हमारी पार्टी को आतंकवादी और देशद्रोही के रूप में चित्रित करने के लिए लुटरे शासक नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। नित नए घोटालों में खुद भागीदार बनकर, जनता के खून-पसीने को चूसकर, लाखों करोड़ों रुपए का जनधन स्विस बैंकों में छिपाने वाले मंत्रियों, राजनेताओं, बड़े पूंजीपतियों और उनके दलालों पर, जो बेखौफ घूमते हैं, देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाता? भोपाल त्रासदी के जिम्मेदारों और दोषियों को बचाने वालों पर षड्यंत्र का मामला क्यों नहीं चलाया जाता? दबी-कुचली जनता की मुक्ति की खातिर संघर्ष करना देशद्रोह कैसे बनता है? जन आंदोलनों के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए अपनी आवाज व कलम उठाने वाले षड्यंत्रकारी कैसे हो सकते हैं?

ये फैसले शासकों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिससे कि वे अपनी जन-विरोधी, देशद्रोहपूर्ण व अनैतिक नव-उदार आर्थिक नीतियों को बेरोकटोक जारी रख सकें। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में देश में फासीवाद और ज्यादा घातक रूप धारण करने वाला है। जो लोग नादानगी से यह विश्वास रखते हैं या इस धोखे में रहते हैं कि इस देश में जो चल रहा है वह लोकतंत्र है, उनकी इन फैसलों से आंखें खुलनी चाहिए। ऊपरी तौर पर देश का शासक गिरोह माओवादी आंदोलन को अपने हमले का निशाना भले ही घोषित कर रहा हो, दरअसल इस फासीवादी हमले के निशाने पर तमाम प्रगतिशील व जनवादी शक्तियां हैं जो देश के हितों तथा जन की भलाई के प्रति समर्पित हैं। अतः हमारी पार्टी तमाम जनता से यह अपील करती है कि इस हमले के खिलाफ एकजुटता से खड़े होकर, दृढ़तापूर्वक लड़कर हरा दिया जाए।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा लागू काला कानून होमलैण्ड सेक्यूरिटी की तर्ज पर ही देश की कॉर्पोरेट-दलाल सरकारें गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यू.ए.पी.ए.), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून (सी.एस.पी.एस.ए.), मकोका, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (ए.एफ.एस.पी.ए.) आदि काले कानूनों के तहत जन आंदोलनों और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। मक्का मसजिद, मालेगांव, अज़्मेर शरीफ आदि बम विस्फोटों में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें लेने वाले भगवा आतंकवादियों को तथा एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ

घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला आदि अनगिनत मामलों में लिप्त घोटालेबाजों और राजनीतिक दगाबाजों को आज तक किसी भी अदालत ने कोई सजा नहीं सुनाई। यही आदलतें क्रांतिकारियों, जन आंदोलन के नेताओं, जनवादियों, कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों से जुड़े कार्यकर्ताओं को उपरोक्त काले कानूनों के तहत सजाएं सुना रही हैं।

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और केन्द्र की यूपीए सरकार ने सांठगांठ के साथ अपनी प्रतिक्रियावादी न्यायव्यवस्था के जरिए षड्यंत्रकारी तरीके से जो सजाएं सुनाई हैं, इसकी कड़ाई से निंदा करने तथा सड़कों पर उतरकर आंदोलन चलाने का आह्वान हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनवाद-पसंद व देशभक्तिपूर्ण ताकतों, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनकारियों, मानवाधिकार संगठनों व कार्यकर्ताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों, अध्यापकों, लेखकों, कलाकारों, चिकित्सकों, वकीलों, मीडियाकर्मियों, मजदूरों और किसानों से करती है। हम अपील करते हैं कि यू. ए.पी.ए., सी.एस.पी.एस.ए., मकोका और ए.एफ.एस.पी.ए. को फौरन रद्द करने की मांग करते हुए एकजुटता से आंदोलन छेड़ दें। हमारी केन्द्रीय कमेटी विभिन्न देशों के प्रगतिशील, जनवादी व क्रांतिकारी संगठनों, समुदायों और शख़्सों से अपील करती है कि वे भारतीय शासक वर्गों की इस वाहियात कार्रवाई का कड़ाई से खण्डन करें और भारत सरकार के प्रति अपना विरोध विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के जरिए व्यक्त करें। जिस तरह विगत में डॉक्टर बिनायक सेन की अवैध हिरासत की निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत के जन आंदोलनों के समर्थन में खड़ा हुआ था, अब वक्त आ गया है कि उसी प्रकार वह फिर एक बार और ज्यादा दृढ़ता से इस भूमिका को निभाए। हमारी पार्टी का आह्वान है कि इन सजाओं के खिलाफ 2 से 8 जनवरी 2011 में देशव्यापी विरोध-सप्ताह मनाया जाए जिसके अंतर्गत पत्रकार-वार्ता, बयानों, विरोध प्रदर्शनों, धरना, रास्ता रोको, सभा-सम्मेलनों, हस्ताक्षर अभियान, काली पट्टियां बांधकर और पुतला-दहन आदि कार्यक्रमों को रचनात्मकता से अपनाया जाए; न्याय के लिए संघर्ष छेड़ दें; तथा शासकों के जन-विरोधी व फासीवादी नीतियों का जोर शोर से विरोध करें।

इस मौके पर हमारी केन्द्रीय कमेटी अपनी पार्टी के तमाम कतारों, पीएलजीए बलों तथा क्रांतिकारी जन संगठनों का आह्वान करती है कि वे जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद करके विभिन्न रूपों में विरोध-कार्यक्रम आयोजित करें।

हमारी केन्द्रीय कमेटी यह भी स्पष्ट करती है कि इस विरोध-सप्ताह के

दौरान ‘बंद’ का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि तमाम जनवादी तरीकों में जनता के विरोध–कार्यक्रम होंगे। हम जनता और मीडिया से आग्रहपूर्वक अपील करते हैं कि इसे ‘बंद’ के रूप में चित्रित करते हुए सरकार व पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले प्रचार पर विश्वास न करें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

15-1-2011

महंगाई, घोटालों और सरकारी आतंक के खिलाफ... 4 से 6 फरवरी तक देशव्यापी विरोध दिवस तथा 7 फरवरी को 'भारत बंद' सफल बनाओ!

महंगाई आसमान को छू रही है। प्याज, मिर्च, सब्जियां, आटा, दाल आदि खाने-पीने की सभी चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी जारी है। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति की दर 18.5 प्रतिशत से ऊपर हो गई। प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गई जिससे गरीब व मध्यम तबकों के लोग बुरी तरह परेशान हैं। फिर आज, 15 जनवरी की आधी रात से पेट्रोल का दाम ढाई रुपए बढ़ाकर देशवासियों पर जो गाज गिराई गई, इससे तो महंगाई और ज्यादा खतरनाक रूप धारण करने वाली है। बात-बात पर 'आम आदमी' की दुहाई देने वाली यूपीए सरकार आज उसी आम आदमी का जीना हराम कर रही है।

हर तरफ हो रही आलोचनाओं और जनता में बढ़ते रोष से बचने के लिए यूपीए सरकार बेसिरपैर की और अजीबोगरीब बयानबाजी कर रही है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया है कि देश में महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गरीब लोग आजकल ज्यादा खाने लगे हैं। साम्राज्यवादियों के इस पसंदीदा अर्थशास्त्री-प्रधानमंत्री, जिसने अपनी आधी से ज्यादा उम्र आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी आदि की चरण-सेवा में बिताई थी, के मुंह से बुश के लफ्ज़ निकले हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? जिस प्रधानमंत्री के शासनकाल में एक अम्बानी 3,500 करोड़ रुपए का गगनचुंभी महल खड़ा करता है और एक मंत्री पंचसितारा होटल में रहकर काम करता है, उसके शासन में गरीबों का 'ज्यादा खाना' अपराध हो गया! दरअसल वायदा कारोबार (future trading), जमाखोरी, कालाबाजारी, लुंज-पुंज सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि महंगाई की बुनियादी वजहों को हल करने में अपनी विफलता को छुपाते हुए वह गरीबों को ज्यादा खाने का दोषी ठहरा रहा

है। खुद सरकार द्वारा गठित कई कमेटियों का निष्कर्ष यह है कि देश में गरीबी बढ़ी है; कि प्रतिव्यक्ति खाद्य उपलब्धता पहले से कम हुई है; और कि देश के 83 करोड़ लोग 20 रुपए से भी कम आमदनी पर जीने को मजबूर हैं। सच यह भी है कि हमारे देश की श्रमशक्ति का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करता है, लेकिन बढ़ती महंगाई के मुताबिक उनकी मजदूरी बढ़ाने की कोई व्यवस्था यहां नहीं है। ऐसे में, जबकि देश की अत्यधिक आबादी के लिए एक जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है, वहीं इन घोटालेबाज नेताओं का यह कहना कि 'गरीब ज्यादा खाने लगे हैं', न सिर्फ देश की गरीबी का भद्दा मजाक है, बल्कि अपनी नाकामियों और काली करतूतों पर परदा डालने की कोशिश भी।

एक तरफ कमरतोड़ महंगाई से जनता त्रस्त है तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ों रुपए के जो नित नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, वो जनता के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। हाल में देश के सबसे बड़े 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर, जिसमें सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा था, गंदा राजनीतिक खेल जारी है। जहां इस घोटाले ने कॉर्पोरेट जगत् के बड़े खिलाड़ियों, मंत्रियों और मीडिया के दिग्गजों की सांठगांठ को नंगा कर दिया, वहीं लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों ने सभी संसदीय राजनीतिक दलों को बेनकाब कर दिया। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की संयुक्त संसदीय कमेटी द्वारा जांच कराने की मांग कर संसद के एक पूरे सत्र को ठप्प करके भाजपा ने खुद को घोटालों से पाक साफ दिखाने की विफल कोशिश की। लेकिन कर्नाटका में येदियूरप्पा के घोटाले, खदान माफिया रेड्डी बंधुओं के साथ सुष्मा स्वराज समेत कई भाजपाई नेताओं के सम्बन्ध आदि किसी से छिपे नहीं हैं। मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद आदि बम विस्फोटों के तार भगवा आतंकियों से जुड़े होने के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे जनता का ध्यान बंटाने के लिए ही भाजपा अब 2जी स्पेक्ट्रम और महंगाई पर हाय तौबा मचा रही है। और उधर कांग्रेस सारा दोष सिर्फ ए. राजा के सिर मढ़कर उसे मंत्री पद से हटाकर यह दिखलाने की कोशिश कर रही है कि मनमोहन और सोनिया घोटालों से पाक साफ हैं। जबकि सच यह है कि इन दोनों की भागीदारी के बिना इतना भारी घोटाला हो ही नहीं सकता था। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के भी बड़े-बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई किन-किन लोगों की जेबों में जा रही है। कई राज्यों में आज

जिस प्रकार बड़ी व विदेशी पूंजीपति कम्पनियों के साथ धड़ल्ले से एमओयू किए जा रहे हैं, उसमें सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपयों की घपलेबाजी आम हो गई है। खासकर नवीन पट्नायक, रमनसिंह, वाईएस राजशेखर रेड्डी (अब मृत), येदियूरप्पा, नितीश कुमार, बुद्धदेब, नरेंद्र मोदी, विलासराव देशमुख, अशोक चवान आदि वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कॉर्पोरेट मालिकों से भारी-भरकम दलाली कमा ली है।

लुटेरे नेता-मंत्री-अफसरों के तमाम भ्रष्टाचार-घोटालों तथा सरकारों की तमाम जन-विरोधी नीतियों व महंगाई के खिलाफ जनता हर जगह अलग-अलग रूप में तथा विभिन्न स्तर पर संघर्ष कर रही है। पर सबसे संगठित और जुझारू संघर्ष हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में हो रहा है। इसीलिए देश के शासक गिरोह सोनिया-मनमोहन- चिदम्बरम ने माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से एक देशव्यापी चौतरफा हमला छेड़ दिया। ज्यों-ज्यों वर्तमान शासक गिरोह बड़े-बड़े घोटाले कर महंगाई को बढ़ाने वाली जन-विरोधी नीतियों में तेजी ला रहा है, वह संघर्षरत जनता और उसकी अगुवाई करने वाली भाकपा (माओवादी) पर हमला भी तेज करने लगा है जो पिछले दो महीनों से खास तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम इस आशय के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में छह राज्यों के पुलिस अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के आला अफसरों के साथ की गई बैठक में चिदम्बरम ने खुफिया एजेंसियों और बलों के बीच तालमेल ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। इस तरह हजारों करोड़ों के जन-धन को जन दमन पर खर्च करने का निर्णय लिया।

पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी सीपीएम आने वाले चुनावों को नजर में रखते हुए अपने गुण्डा गिरोह हर्मद बाहिनी और पुलिस-अर्धसैनिक बलों के साथ जंगलमहल व लालगढ़ इलाकों में 140 से ज्यादा कैम्प खोलकर आतंक का तांडव मचा रही है। वो जनता पर रोज हमले कर रहे हैं। जन नेताओं को कत्ल कर रहे हैं। महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं लगातार जारी हैं। 3 दिसम्बर 2010 को पुलिस ने हमारी पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड सुदीप चोंगदार, राज्य कमेटी सदस्य कल्पना मैती, बरुन सुर, अनिल घोष समेत कुछ अन्य कॉमरेडों को तथा इसके पूर्व एक और राज्य कमेटी

सदस्य कॉमरेड द्विजन हेमब्रम उर्फ अनंतो को गिरफ्तार किया। उन्हें क्रूर यातनाएं देकर झूठे मामले दर्ज कर जेल भेज दिया। खासकर महिला कॉमरेड कल्पना के साथ अमानवीय व अपमानजनक बरताव किया जा रहा है।

बिहार और झारखण्ड में माओवादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों, यातनाओं, गांवों पर वहशी हमलों और हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। आंध्रप्रदेश में सरकार एक तरफ माओवादी आंदोलन को कुचल डालने के दावे करते हुए ही फर्जी मुठभेड़ों और जनता पर हमलों का सिलसिला जारी रखी हुई है। 17 दिसम्बर 2010 को विशाखापटनम जिले में किए गए एक हमले में ग्रेहाउण्ड्स ने तीन महिलाओं समेत चार कॉमरेडों की हत्या की। सेज व थर्मल बिजली परियोजनाओं के खिलाफ तथा पृथक तेलंगाना के लिए आंदोलनरत आम लोगों पर सरकारी जुल्म जोरों पर जारी है।

ओड़िशा में पिछले दो महीनों में सरकारी सशस्त्र बलों ने अंधाधुंध हमले कर करीब 25 माओवादी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता की हत्या कर दी। वहां से अभी तक जितनी भी 'मुठभेड़' की खबरें आईं, अधिकांश झूठी हैं। 2 जनवरी को कलिंगनगर क्षेत्र में पांच, 9 जनवरी को नियमगिरी इलाके में नौ और 12 जनवरी को क्योंझर जिले में दो माओवादियों के कथित मुठभेड़ों में मारे जाने की घटनाएं सरकारी आतंक के कुछ ताजा उदाहरण हैं। इस साल की शुरूआत में बरगढ़ जिले के दो ग्रामीणों की सरेआम हत्या कर उसे 'मुठभेड़' के रूप में चित्रित किया गया।

दण्डकारण्य के बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है। 8 अक्टूबर 2010 को महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले के सांवरगांव के स्कूल पर आईटीबीपी के दरिंदों ने मोर्टार के गोले दागे थे जिसमें दो स्कूली बच्चों समेत छह ग्रामीणों की मौत हुई जबकि 8 अन्य बुरी तरह घायल हुए। अगले ही दिन 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किए गए एक और हमले में पीएलजीए के छह साथी शहीद हुए थे और पुलिस ने वहां दो निर्दोष ग्रामीणों की ठण्डे दिमाग से हत्या की। 23 नवम्बर को दंतेवाड़ा जिले के जेगुरगोण्डा के पास सीआरपीएफ ने 9 ग्रामीणों की हत्या की। सरकारी हिंसा का विरोध करने पर जनवादी बुद्धिजीवियों को भी धमकियां देना, गिरफ्तार कर जेल भेजना और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. बिनायक सेन, भाकपा (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. नारायण सन्याल, व्यापारी पियूष गुहा,

पत्रिका सम्पादक असित सेनगुप्ता को सजाएं देना छत्तीसगढ़ सरकार के बढ़ते फासीवादी रुझानों के उदाहरण भर हैं। हालांकि आज यह हमला ऊपर से देखने पर माओवादियों पर केन्द्रित नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में यह हमला सरकारों की नीतियों का विरोध करने वाले हर शख़्स और हर संगठन पर है।

प्यारे देशवासियो! यह वक्त यह सब देखकर हताश या निराश होने का नहीं है, बल्कि एकजुटता के साथ सरकारों की दमनकारी, जन-विरोधी और साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ने का है तथा घोटालेबाजों, जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ अपने संघर्षों को केन्द्रित करना का है।

हमारी केन्द्रीय कमेटी देश की समूची जनता से आह्वान करती है कि बढ़ती महंगाई, घोटालों और सरकारी आतंक के खिलाफ आगामी 4 से 6 फरवरी तक तीन दिनी देशव्यापी विरोध कार्यक्रमों और 7 फरवरी को 24-घण्टे का 'भारत बंद' को सफल बनाया जाए। हम इस मौके पर यह भी स्पष्ट करते हैं कि विरोध कार्यक्रमों के दौरान बंद नहीं रहेगा तथा 'भारत बंद' का पालन छह राज्यों - पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार, ओड़िशा, छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश में तथा महराष्ट्र के तीन जिलों - गड़चिरोली, गोंदिया व चंद्रपुर और मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में किया जाएगा। हालांकि हम मेडिकल सुविधाओं, छात्रों की परीक्षा, साक्षात्कार आदि को बंद से मुक्त रखेंगे।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

31-3-2011

लीबिया पर अमेरिका-फ्रांस-ब्रिटेन के दुराक्रमणकारी युद्ध का विरोध करो!
लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ रही टुनीशिया, मिस्र, येमेन, बहरीन, अलजीरिया, मोरक्को, जोर्डान आदि देशों की जनता का समर्थन करो!
अरब देशों के अंदरूनी मामलों में साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी, ब्रितानी और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों की दखलंदाजी का विरोध करो!

पिछले कुछ हफ्तों से अरब दुनिया में जो जन उभार देखने को मिल रहा है, इसने जहां एक तरफ साम्राज्यवाद को, खासकर अमेरिका को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ विश्व जनता को बेहद प्रभावित किया है। टुनीशिया से शुरू होकर कई अन्य अरब देशों में फैली इस जन त्सुनामी से डरकर टुनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली, जो पिछले 23 सालों से जनता का दमन-शोषण कर रहा था तथा पिछले 30 सालों से मिस्र में राज करते आ रहे होस्नी मुबारक गद्दी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और येमेन, बहरीन, अलजीरिया, मोरक्को, जोर्डान आदि देशों में भी जन आंदोलन इसी तर्ज पर चल रहे हैं। अरब जनता चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि साम्राज्यवादियों से सांठगांठ कर दशकों से जनता पर तानाशाही चलाने वाले तमाम शासक गद्दी छोड़ दें। लाखों अरब जनता, खासकर युवा वर्ग तमाम प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए सड़कों पर आ रहा है। कई हफ्तों तक सड़कें और चौराहें जन समंदर में तब्दील हो गईं। जनता के प्रदर्शनों पर सरकारों द्वारा किए गए हमलों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। हजारों लोग घायल हो गए। अब जबकि लीबिया पर अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों ने दुराक्रमणकारी युद्ध छेड़ दिया, तो अरब दुनिया में घटनाक्रम ने

एक अहम मोड़ ले लिया।

लीबिया में गद्दाफ़ी की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए विद्रोह को दबाने के लिए लीबिया सरकार को अपने सैन्य बलों का प्रयोग करने से रोकने के नाम पर सुरक्षा परिषद ने 'उड़ान-वर्जित क्षेत्र' (नो-फ्लाई ज़ोन) का प्रस्ताव किया। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जबकि रूस, चीन, जर्मनी, ब्राजील और भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। वीटो अधिकार प्राप्त रूस और चीन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश नहीं की। प्रस्ताव का विरोध न करने वाले इन देशों ने स्पष्ट तौर पर लीबिया पर नाटो की सैन्य कार्रवाई का परोक्ष समर्थन किया। इस हमले का खण्डन न करते हुए सिर्फ चिंता जाहिर कर मनमोहनसिंह सरकार देश और दुनिया की जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। इस्राएल के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए दर्जनों प्रस्तावों को रद्दी के टोकरे में डालकर जब यहूदीवादी शासकों ने अनगिनत मौकों पर फिलिस्तीनियों की अंधाधुंध हत्याएं कीं, तब उस पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने जरा भी आपत्ति नहीं की थी। (बल्कि अमेरिका ने तो इस्राएल के लिए अपने वीटो अधिकार का अंधाधुंध इस्तेमाल किया।) लेकिन लीबिया के मामले में तो इन देशों ने प्रस्ताव पर श्याही सूखी ही नहीं थी कि आनन-फानन में उस पर अमल करते हुए बमों की बारिश शुरू कर दी। कथित रूप से अंतरराष्ट्रीय अभियान बताए जाने वाले इस दुराक्रमणकारी हमले के पहले ही दिन फ्रांस के 18 बमवर्षक विमानों ने कई लक्ष्यों पर 40 बम गिराए। अमेरिकी और ब्रितानी नौसेनाओं ने लीबिया की सुरक्षा व्यवस्था को लक्ष्य बनाकर कई क्रूइज़ मिस्साइलों का प्रयोग किया। अमेरिकी वायुसेना के 18 बी-2 विमानों ने 100 से ज्यादा मिस्साइलों का प्रयोग किया। कई लक्ष्यों पर बम गिराए। गद्दाफ़ी की सेनाओं द्वारा संभावित कत्लेआम को रोकने के बहाने शुरू किए गए इस युद्ध में पिछले तीन हफ्तों में सैकड़ों नागरिक मारे गए। इस बात पर कि किनके बमों से मारे जाएंगे, लीबियाइयों की जानों (मौतों) की कीमत बदल जाएगी, ऐसा दुनिया को यकीन दिलवाने की हरकत से ज्यादा घटियापन और कुछ नहीं हो सकता! मीडिया को खुद ही कहना पड़ा कि मारे गए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल साम्राज्यवादियों के मुखपत्र की तरह काम करने वाला मीडिया सच्चाइयों को तोड़-मरोड़कर गलत सूचनाओं का प्रसार कर रहा है। इस दुराक्रमणकारी युद्ध में मीडिया ने फिर एक बार अपने वर्गीय स्वभाव का परिचय दिया है।

खुद को निष्पक्ष संगठन बताने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों की कठपुतली के रूप में इस मौके पर फिर एक बार साफ तौर पर साबित हो गई। उसके महासचिव बानकी मून ने खुद को अमेरिका के पैरों के पास पूंछ हिलाने वाले कुत्ते के रूप में साबित किया। जब दिसम्बर 2008 में गाज़ा पर इज्राएल ने अमानवीय हमले किए थे जिसमें 1,417 फिलिस्तीनी – जिनमें अत्यधिक बच्चे और महिलाएं थीं – मारे गए थे और कई हजार लोग घायल हो गए थे; जब इज्राएली सेना ने गैर–कानूनी ढंग से सफेद फॉस्फरस जैसे बेहद खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया था जिससे गाज़ा के कई निवासी कैंसर का शिकार हुए थे; जब उसने एफ–16 विमानों का प्रयोग कर 'टार्गेटेड किल्लिंग्स' का सिलसिला चलाया; बिजली, पानी जैसी न्यूनतम जरूरतों से भी वंचित कर जब उसने 15 लाख गाज़ा के लोगों को 'खुले जेल' जैसे हालात में जीने को मजबूर किया तब राष्ट्र संघ ने 'उड़ान वर्जित क्षेत्र' का प्रस्ताव करने का साहस नहीं किया। जब नव–नात्सी राजपक्षे सरकार ने एलटीटीई का सफाया करने के लिए विनाशकारी युद्ध शुरू कर नागरिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों पर कई टन बम गिराए थे; जब उसने युद्ध के सिर्फ आखिरी दो दिनों के अंदर 20 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दी थी; मारी गई या पकड़ी गई महिला टाइगरों पर सिंहली अंधराष्ट्रवादी सेनाओं ने अकथनीय अत्याचार किए थे तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ भी नहीं किया था। अपनी आजादी के लिए संघर्षरत कश्मीर की जनता पर दमनचक्र चलाते हुए भारत सरकार पिछले 25 बरसों से 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करती आ रही है तो संयुक्त राष्ट्र संघ कुंभकर्ण की नींद सो रहा था जो अब यह कह रहा है कि उसने लीबिया में गद्दाफ़ी के खिलाफ लड़ रही जनता को बचाने के लिए कमर कस ली है। शर्म है! कुल मिलाकर देखा जाए, तो दर्जनों मौकों पर अमेरिका, इज्राएल और पश्चिमी देशों के हितों को कथित रूप से जब नुकसान पहंचता है, तब राष्ट्र संघ ने जो दिलचस्पी या तत्परता दिखाई, उत्पीड़ित देशों व राष्ट्रीयताओं के मामले में कभी नहीं दिखाई।

दरअसल लीबिया युद्ध खुद अपने आप में संयुक्त राष्ट्र संघ के 'उड़ान–वर्जित क्षेत्र' प्रस्ताव के खिलाफ है। लीबिया को अपनी वायु सेना का इस्तेमाल कर विद्रोहियों पर हमले करने से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव को लागू करने का दावा करते हुए लीबिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो अंधाधुंध बमबारी शुरू की वह दुराक्रमण के अलावा कुछ नहीं है। गद्दाफ़ी

को गद्दी से उतारकर अपने लिए अनुकूल किसी शासक गिरोह को सत्ता पर बिठाकर लीबिया में मौजूद तेल संपदा को लूटना ही उनका असली मकसद है। बहरीन में जन विद्रोह को दबाने के लिए पिछले दरवाजे से साउदी अरब की सेनाओं को उतरवाने वाले ओबामा का यह कहना कि लीबियाई विद्रोहियों को बचाने के लिए ही उन्हें यह बमबारी करनी पड़ रही है, छिछोरापन की पराकाष्ठा है। अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आए दिन अंधाधुंध ड्रोन हमले करते हुए सैकड़ों लोगों की जानें ले रहे 'नोबेल शांति पुरस्कार' से नवाजे गए इस रक्त-पिपासू को दरअसल जनता के प्राणों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। साउदी अरब, येमेन, जोर्डान आदि देशों में दलाल शासकों के खिलाफ जिनका वे अब तक समर्थन करते रहे, संघर्षरत जनता को सशस्त्र बलों द्वारा गोली मार देने पर भी चुप्पी साधने वाले पश्चिमी देशों का यह कहना कि गद्दाफ़ी को सत्ता से हटा देना चाहिए, उनके दोगलेपन का साफ सबूत है। सोलह आणे की साम्राज्यवादी दोहरी नीति है!

पश्चिमी साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी से सांठगांठ करने वाले दलाल शासक - टुनीशिया का राष्ट्रपति बेन अली, मिस्र का राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, येमेन का राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह, बहरीन का अमीर इसा अल खलीफा, जोर्डान का राजा अब्दुल्ला वगैरह - कई दशकों से अपने-अपने देशों में तानाशाही चला रहे हैं। नाम के वास्ते चुनाव होने पर भी उसमें कितना फर्जीवाड़ा होता होगा इसे समझने के लिए बस टुनीशिया का एक उदाहरण काफी है - राष्ट्रपति बेन अली को हर दफे 97 से 99 प्रतिशत वोट मिलते थे?! जनता को किसी भी प्रकार के नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं हैं। पुलिस व खुफिया अमले जनता की हर गतिविधि को नियंत्रित करते हुए दमन करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का विरोध न उठने पाए। इन सभी देशों में बेरोजगारी का तांडव जारी है। मिसाल के तौर पर येमेन में 40 प्रतिशत बेरोजगारी है। दूसरी ओर यहां के शासकों को तेल स्रोतों पर मालिकाना है जिसके फलस्वरूप उन्होंने अनगिनत संपदाएं इकट्ठी कर रखी हैं। अरबों डॉलर का धन विदेशी बैंक में छुपाकर रखा है। टुनीशिया से भागते-भागते बेन अली अपने साथ डेढ़ टन सोना भी ले उड़ा जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक-एक तानाशाह ने जनता को लूटकर कितना धन इकट्ठा किया होगा। दूसरी ओर 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाले संकट का असर भी अरब देशों पर पड़ रहा था जिससे जनता अकथनीय मुश्किलों से परेशान है। आबादी का आधा से ज्यादा

हिस्सा रोजाना दो डॉलर से कम आमदनी पर दुभर जिंदगी जी रहा है। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के तहत इन देशों के तानाशाह अल कायदा को कुचलने के नाम पर जन धन का अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। येमेन ने 75 करोड़ डॉलर पर आतंकवाद-विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर जन धन का इस तरह दुरुपयोग करना भी जनता को नागवार गुजरा। अभी तक धर्म के नाम से तथा शिया और सुन्नियों बीच तथा विभिन्न कबीलों के बीच मौजूद अंतरविरोधों का फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादियों ने इन तानाशाहों का हर तरह से समर्थन किया। और जनता पर उनके शोषण, उत्पीड़न समेत सभी दमनात्मक कदमों का समर्थन किया। लेकिन जन उभार की तीव्रता को भांपकर इन बूढ़े घोड़ों का पिंड छुड़ाकर नए घोड़ों को तलाश लेना बेहतर समझा। चुपके से बेन अली और मुबारक को सत्ता से हटवाकर वहां के सैन्य जनरलों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करवा दिया। वहीं दूसरे देशों में पश्चिमी देश अभी भी शासकों के ही पक्ष में खड़े हैं। 22 अरब देशों का गठबंधन अरब लीग इस पूरे संदर्भ में पश्चिमी देशों के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। अरब राष्ट्रवाद या अरब जनता की साम्राज्यवाद-विरोधी आकांक्षाओं का वह जरा भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है।

जनता की जनवादी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले तथा तमाम जनता को एकजुट कर साम्राज्यवाद का मुखर विरोध करने वाले शासक ही अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं और अपने देश की सम्प्रभुता को टिकाए रख सकते हैं। जनता पर तानाशाही चलाने वाले शासक, चाहे वह गद्दाफ़ी हो या फिर कोई और, साम्राज्यवाद से समझौताहीन संघर्ष नहीं कर सकते। जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े नहीं रख सकते। अपार तेल संसाधनों से समृद्ध पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका पर अपना दबदबा कायम करने के लिए साम्राज्यवादी शुरू से कई साजिशों, षड़यंत्रों और दुराक्रमणकारी युद्धों को अंजाम देते आ रहे हैं। ऐसे तानाशाहों का जो उनके सामने घुटने टेकते हुए उनके हितों को तवज्जो देते हैं, वे समर्थन करते हैं। ऐसे तानाशाहों के प्रति जिनके बारे में वे समझते हैं कि उनके हितों को कहीं न कहीं नुकसान कर सकते हैं, वे 'यूज़ एण्ड थ्रो' (इस्तेमाल करो और फेंक दो) वाली नीति लागू करते हैं।

अरब देशों की जनता से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आह्वान :

अरब देशों की जनता को चाहिए कि वह तानाशाहों और साम्राज्यवादियों के खिलाफ अपने आंदोलनों को दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखें। साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा इन आंदोलनों का अपहरण करने की कोशिशों का मजबूती से मुकाबला करना चाहिए। सत्ता से हट चुके तानाशाहों का स्थान ग्रहण करने वाले सैन्य परिषदों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमारी पार्टी अरब जगत् की समूची जनता को सावधान करती है कि वे उन सैन्य जनरलों से, जिन्होंने अभी तक तानाशाहों का साथ दिया था, यह उम्मीद न रखें कि वे लोकतंत्र की गारंटी कर सकते हैं। मजदूरों और किसानों समेत सभी जनवादी तबकों, मध्यम वर्ग, देशभक्त व साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतों को एकजुट होना होगा। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष करने के अलावा अरब जनता के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। अरब दुनिया के घटनाक्रम ने इस सच्चाई को फिर एक बार साबित कर दिया कि उत्पीड़ित जन समुदायों की वास्तविक मुक्ति के लिए मार्क्सवादी विचारधारा का मार्गदर्शन और सर्वहारा के अग्रणी दस्ते के रूप में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बेहद जरूरी हैं। विभिन्न देशों को औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद एक जमाने के उपनिवेशवाद का स्थान लेने वाला नव-उपनिवेशिवाद कितने दूभर हालात पैदा कर सकता है, इसे अरब दुनिया की जनता ने पिछले 40-50 सालों में अपनी आंखों से देखा है। अगर नव-उपनिवेशवाद का खात्मा कर असली आजादी हासिल करनी है तो अरब जनता को अपने पैरों पर खड़े होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ दृढ़तापूर्वक लड़ना होगा। लीबिया पर अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ने वाले अमेरिकी, ब्रितानी और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के खिलाफ एकजुटता से लड़ना चाहिए। भाकपा (माओवादी) यह आशा करती है कि अलग-अलग देशों में साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त दलाल तानाशाहों के खिलाफ लड़े जाने वाले संघर्षों का ऐसा विकास हो जो साम्राज्यवाद का मुखरता से विरोध करते हों, उसकी दखलंदाजी और उसके द्वारा थोपे जाने वाले अन्यायपूर्ण युद्धों का दृढ़ता से प्रतिरोध करते हों। तभी अरब दुनिया तानाशाहों और साम्राज्यवादियों के शिकंजे से मुक्ति प्राप्त कर सकेगी।

भारत की जनता और विश्व जनता से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आह्वान :

आजादी और लोकतंत्र के लिए अरब देशों की जनता द्वारा किए जा रहे आंदोलन पूर्णतः न्यायपूर्ण हैं। इसके बावजूद भी कि आंदोलनकारी ताकतों में ध

ार्मिक कट्टरपंथी और अन्य प्रतिक्रियावादी कुछ हद तक मौजूद हों, ये आंदोलन लोकतांत्रिक और प्रगतिशील हैं। इन आंदोलनों का तहेदिल से समर्थन करना चाहिए। अरब क्षेत्र के मामलों में साम्राज्यवादियों की दखलंदाजी तथा लीबिया पर पश्चिमी साम्राज्यवादियों द्वारा थोपे गए अन्यायपूर्ण युद्ध का एक स्वर में विरोध करना चाहिए।

- **लीबिया पर अमेरिका के नेतृत्व में जारी नाटो के अन्यायपूर्ण युद्ध को फौरन रोक दो!**
- **लीबिया के अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार साम्राज्यवादियों को कतई नहीं है!**
- **अरब दुनिया के मामलों में साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की हस्तक्षेप भरी नीतियों का पर्दाफाश करो!**
- **अरब देशों में जारी जायज जन आंदोलनों का समर्थन करो!**

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

5-4-2011

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो! शोषण-उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हिंसा, अत्याचार और अपमान से भरी मौजूदा अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंककर जनता की जनवादी राजसत्ता की स्थापना हेतु जनयुद्ध को तेज करो!

पांच राज्यों - असम, तमिलनाडू, केरल, पांडिच्चेरी और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चुनावों का ढकोसला शुरू हो गया। जहां सारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, संसाधनों की लूट, विस्थापन, पर्यावरण का विनाश आदि समस्याओं से दो चार है, वहीं सभी संसदीय पार्टियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है ताकि जनता को फिर एक बार धोखा देकर इन राज्यों में सत्ता हथियाई जा सके। देश में साम्राज्यवाद-निर्देशित आर्थिक नीतियों को लागू करने में आगे रहने वाली प्रमुख शोषक वर्गीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा समेत; सीपीएम जो पिछले 30 सालों से पश्चिम बंगाल में फासीवादी शासन लागू करती आ रही है; डीएमके और अन्ना डीएमके जो भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए खासा बदनाम हैं; असम की जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ गद्दारी करने वाला असम गण परिषद वगैरह पार्टियां मुख्य रूप से इन राज्यों में सत्ता पर कब्जा करने के लिए मैदान में हैं। सभी नेता ध न बल, बाहु बल, जाति, धर्म आदि हथियारों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं ताकि वोट बटोर लिए जा सके। फूहड़ता की हदें पार कर मतदाताओं को साड़ियों से लेकर कम्प्यूटर तक कुछ भी दे देने का आश्वासन देने में एक दूसरे को मात दे रहे हैं। करोड़ों रुपए का धन बहाकर 'वोटों को खरीदने' की कोशिशों में लगे हुए हैं।

पिछले 30 सालों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी शासन चलाती आ रही सीपीएम ने सामंती, साम्राज्यवादी व दलाल नौकरशाह पूंजीवादी

लूटखसोट का समर्थन कर खुद को जनता की नजरों में नंगा कर लिया। टाटा, जिंदल जैसे दलाल पूंजीपतियों के हित में तथा एसईजेड के नाम से किसानों की जमीनें छीनने की कोशिशों के खिलाफ नंदीग्राम और सिंगूर में आंदोलन छेड़ने वाली जनता पर तथा लालगढ़ इलाके में पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ उमड़े जन सैलाब के ऊपर सीपीएम ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अपनी गुण्डा सेना 'हर्मद बाहिनी' के जरिए बर्बर दमन, अमानवीय हत्याकाण्ड और महिलाओं के साथ अत्याचारों का जो सिलसिला चलाया, वह इतिहास में काले धब्बा बनकर रह जाएगा। सीपीआई, फार्वर्ड ब्लॉक जैसी वाम मोर्चे की घटक पार्टियां सीपीएम की जन विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाली दिवालिया पार्टियों के रूप में जनता में नंगी होती जा रही हैं। सीपीएम के प्रति सभी वर्गों की जनता में सुलग रहे असंतोष और गुस्से का फायदा उठाकर ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरकर आई है। इससे सीपीएम इस बार सत्ता के सुख से हाथ धोने का खतरा झेल रही है। आज ममता बनर्जी की कथनी चाहे जो भी हो, कल चुनाव जीतने के बाद जो शासन वह चलाएगी, वह सीपीएम से बुनियादी रूप से भिन्न नहीं रहेगा। यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस से गठबंधन के बल पर ममता जो शासन लाएगी वह सामंतवाद व कार्पोरेट अनुकूल और जन विरोधी नीतियों की ध ारवाहिकता के रूप में ही होगा जिसे सीपीएम समेत तमाम अन्य शासक वर्गीय पार्टियां लागू करती आ रही थीं। कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम की तरह तृणमूल भी वही पार्टी है जो सामंती व दलाल पूंजीपति वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और जो साम्राज्यवाद के सामने नतमस्तक है। इसलिए बंगाल की जनता के सामने एक रास्ता बचता है कि वे इन ढोंगी चुनावों का बहिष्कार कर, लालगढ़ जनता के उज्ज्वल संघर्ष की प्रेरणा से माओवादी जनयुद्ध को केन्द्र में रखते हुए जुझारू जन संघर्षों का निर्माण करें। असली विकल्प यही है कि ऐतिहासिक लालगढ़ आंदोलन के परिणामस्वरूप भ्रूण रूप में अस्तित्व में आई वैकल्पिक जन राजसत्ता का और ज्यादा सुदृढ़ व जुझारू ढंग से विस्तार किया जाए।

तमिलनाडू मुख्यमंत्री करुणानिधि, पूर्व टेलिकॉम मंत्री ए. राजा और उनके डकैतों का गिरोह जिसने राज्य में सत्ता और केन्द्र में यूपीए गठबंधन में भागीदारी का फायदा उठाते हुए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए थे, अब फिर से प्रदेश में सत्ता हथियाने के लिए करोड़ों रुपए बहा रहा है। करुणानिधि सरकार ने तकरीबन 70 एसईजेड को मंजूरी देकर हजारों हेक्टेयर जमीनें बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों के हवाले कर दीं। किसानों और मजदूरों की जिंदगी दूभर बना दी। अकेले तिरपुर शहर में पिछले दो सालों में 25 हजार मजदूरों की नौकरियां छीन ली गईं जिसके परिणामस्वरूप दो हजार कपड़ा–मजदूरों ने खुदकुशी कर ली। वर्तमान में डीएमके के प्रति जनता में बढ़े हुए असंतोष का फायदा उठाते हुए जयललिता की अगुवाई वाली अन्ना द्रमुक किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। लेकिन गौरतलब है कि जयललिता भी कम बड़ी चोर नहीं है जिसका विगत में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हजारों करोड़ रुपए की सम्पत्तियां हासिल करने का इतिहास रहा है। तमिल राष्ट्रीयता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का दम्भ भरने वाली डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने श्रीलंका में सिंहली अंधराष्ट्रवादी राजपक्षे सरकार द्वारा एलटीटीई का सफाया करने के लक्ष्य से किए गए अन्यायपूर्ण युद्ध और तमिलों के कत्लेआम का परोक्ष रूप से समर्थन किया था। अत: तमिलनाडू की जनता के सामने यही विकल्प है कि वह उक्त दो पार्टियों के साथ–साथ उनकी सभी सहयोगी पार्टियों को नकार कर जन आंदोलनों और क्रांतिकारी संघर्षों को तेज कर दे।

केरल में सीपीएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की सरकार कई घपलेबाजियों व घोटालों में लिप्त होकर कॉर्पोरेट वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए जनता में खासी बदनाम हो चुकी है। जनता के असंतोष का फायदा उठाते हुए वहां पर कांग्रेस–नीत गठबंधन यूडीएफ किसी न किसी तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए कई पापड़ बेल रहा है। असम में असम गण परिषद, जिसका विगत में असमिया जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आंदोलन चलाने का इतिहास रहा है, आज राष्ट्रीय हितों के साथ गद्दारी कर सत्ता की होड़ में लगा हुआ है। उल्फा, बोडो आदि न्यायपूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का दमन करने में उसने कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर रखी है।

खासकर पिछले कुछ समय से देश में आए दिन घपलों और घोटालों के खुलासे होने लगे हैं, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था का असली रूप दिन–ब–दिन साफ तौर पर सामने आ रहा है। हाल में उजागर होने वाले 2जी स्पेक्ट्रम आदि घोटालों से यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो गई कि किस तरह सभी पार्टियों के मंत्री, नेता, कॉर्पोरेट घरानों के मालिक और मीडिया सम्राट सांठगांठ कर लाखों करोड़ रुपए डकार रहे हैं। जहां एक तरफ अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाली विभिन्न तबकों की जनता, जन आंदोलनों और

क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से लुटेरे शासक अपने सशस्त्र बलों के जरिए दमन अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फासीवादी कानूनों को तैयार कर जनता और आंदोलनकारियों को बिना किसी सुनवाई के सालों तक जेलों में बंद कर रहे हैं तथा उन्हें कठोर सजाएं दिलवा रहे हैं। कथित रूप से संविधान द्वारा प्राप्त जीने के अधिकार समेत जनता के तमाम बुनियादी अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

इन चुनावों को 'सुचारू रूप से' (यानी हिंसा, अत्याचार, जनता पर गोलीबारी, गिरफ्तारियां और फर्जी मतदान के रूप में समझ लेना चाहिए) संपन्न कराने के लिए केन्द्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 800 से ज्यादा कम्पनियां तैनात कर दीं। गौरतलब है कि इनमें से 600 से ज्यादा कम्पनियां पश्चिम बंगाल में भेजी जा रही हैं जहां माओवादी आंदोलन अपेक्षाकृत मजबूत है। चुनावों से काफी पहले से ही सीपीएम ने अपने गुण्डों की सेना हर्मद वाहिनी के हजारों हथियारबंद गिरोहों को खासकर जंगलमहल इलाके के दर्जनों गांवों में लगा दिया। इन हथियारबंद गुण्डा गिरोहों और संयुक्त बलों के पाशविक अत्याचार और अकथनीय हिंसा पहले से जारी है। इसका मतलब यह है कि वोट डालने से इनकार करने वाली जनता को बंदूक की नोक पर मतदान केन्द्रों पर हांक ले जाने तथा अभूतपूर्व स्तर पर भारी फर्जी मतदान करने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में सीपीएम बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंक मचाने के लिए मुस्तैदी से तैयार है ताकि वह किसी न किसी तरीके से सत्ता पर बने रह सके।

सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन रहे या फिर जो भी पार्टी या गठबंधन चुनाव जीतकर सत्ता में आना चाहता हो, वे सभी सामंतों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के हितों को ही पूरा करेंगे न कि मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं, दलितों आदि उत्पीड़ित वर्गों/तबकों की भलाई के लिए काम करेंगे जो आबादी का 95 प्रतिशत हैं। यह सच्चाई पिछले 64 सालों के तथाकथित स्वतंत्र भारत के इतिहास में साबित हो चुकी है। दरअसल यह चुनाव ही सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। यह लुटेरे वर्गों के शासन को पुख़्ता करने वाला एक कवायद है। इन चुनावों से ज्यादा से ज्यादा शासक गिरोह के रंग में या उसकी पार्टी में बदलाव आ सकता है, मौजूदा व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव कतई नहीं आएगा। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी जनता की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं होगा। चुनावों में पूंजी के तौर पर

पैसा ही लगाया जाता है। संसद और विधानसभा का संचालन भी पैसे वाले ही करते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी कई गुना पैसा कमाते हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन जुर्मों में लिप्त आपराधिक चरित्र वालों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी उनके स्वभाव को प्रतिबिम्बित कर रही है। इसीलिए हमारी पार्टी यह स्पष्ट करती है कि संसद और विधानसभाएं 'सुअरबाड़ों' के अलावा कुछ नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्था को जड़ से बदले बिना जनता की जिंदगियां नहीं बदलेंगी। नई जनवादी क्रांति को सफल बनाकर मजदूर-किसान एकता के आधार पर तमाम शोषित जनता की जनवादी राजसत्ता का निर्माण करना ही एक मात्र विकल्प है। हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनता का आवाहन करती है कि वह इसके लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध में शामिल हो।

प्यारे लोगो!

फिलहाल पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें। 'लोकतंत्र' बताए जाने वाले देश में वोट डालने के अधिकार के साथ-साथ वोट नहीं डालने का अधिकार भी होना चाहिए। इस अधिकार के हनन के खिलाफ संघर्ष करें। सशस्त्र पहरे में जनता को बलपूर्वक मतदान केन्द्रों में हांक ले जाने के खिलाफ आवाज उठाएं। भ्रष्टाचार-घोटालों से सड़-गल चुकी इस ढोंगी संसदीय जनवादी व्यवस्था को ठुकरा दें। दण्डकारण्य, बिहार-झारखण्ड, ओड़िशा, बंगाल आदि जगहों पर हमारी पार्टी के नेतृत्व में प्राथमिक स्तर पर आकार ले रही जनता की जनवादी राज्य व्यवस्था का स्वागत करते हुए देश के चारों ओर जनता की राजसत्ता की स्थापना के लिए कमर कस लें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

13-4-2011

व्यवस्थीकृत हो चुके भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए जन संघर्षों को तेज करो!

हाल के दिनों में उजागर हुए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला, आदर्श हाउजिंग सोसायटी, कर्नाटका जमीन खरीद, एस-बैंड स्पेक्ट्रम आदि घोटालों ने भ्रष्टाचार को फिर एक बार एक बड़ी समस्या के रूप में सामने लाया। मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं, मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्ग आदि सभी वर्गों और सभी तबकों की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी प्रकट कर रही है। जनता में भ्रष्टाचार, भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों तथा उन पार्टियों के नेताओं के प्रति संचित गुस्से का नतीजा ही था हाल में अन्ना हजारे द्वारा की गई भूख हड़ताल को देश भर में जनता से मिली प्रतिक्रिया। जहां उनकी अनशन का लक्ष्य जन लोकपाल विधेयक ही था, वहीं देश के चारों कोनों से व्यक्त हुई जनता की आकंक्षा तो भ्रष्टाचार का जड़ से सफाया करने की है। लोकपाल विधेयक तैयार करने हेतु कमेटी का गठन कर उसमें आधे सदस्यों का चयन नागरिक समाज में से करने का सरकार ने जो फैसला लिया, इससे इस समस्या का हल हो गया या हो जाएगा, ऐसा मानना नादानगी ही होगी।

दरअसल आज भ्रष्टाचार के इतने गहरे तक जड़ें जमा लेने और बेहिसाब बढ़ जाने का यह कारण नहीं है कि यहां इसे रोकने का कोई कारगर कानून-कायदा ही मौजूद नहीं है। कानून चाहे जितने भी हों, चूंकि उन पर अमल करने और करवाने वाली व्यवस्था पर ही लुटेरे वर्गों का कब्जा है, इसीलिए यह बदहाली व्याप्त है। एक जमाने के जीप घोटाला और लॉकहीड विमान खरीदी घोटाले से लेकर राजीव गांधी के समय का बोफोर्स घोटाला आदि अनगिनत घोटालों का लम्बा इतिहास रहा है हमारे देश में। चंद करोड़ रुपयों से शुरू कर

आज लाखों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ गए हैं। कांग्रेस, भाजपा जैसी मुख्य संसदीय पार्टियों से लेकर आरजेडी, बीएसपी, एसपी, डीएमके, अन्ना डीएमके, तेलुगुदेशम वगैरह सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों के नेता व मंत्री तथा उनके पिट्ठू प्रशासनिक अधिकारी सभी का दामन भ्रष्टाचार से दागदार है। देश में पहले से मौजूद कानूनों पर ठीक से अमल कर और विभिन्न भ्रष्टाचार-विरोधी विभागों का ठीक से संचालन कर ऐसे भ्रष्टाचार-घोटालों को रोका जा सकता है तथा उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजाएं दिलवाई जा सकती हैं। लेकिन पिछले 64 सालों के 'आजाद' भारत के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें भ्रष्ट राजनेताओं, मंत्रियों, कार्पोरेट घरानों के मालिकों और नौकरशाहों को कभी कोई सजा मिली हो। जनता और विपक्ष के दबाव के कारण विरल मौकों पर किसी को गिरफ्तार कर किया भी गया तो सालों साल तक खिंचने वाली अदालती कार्रवाई के बाद मामलों को रफा-दफा कर दिया जाता है। बिना किसी सजा के या नाम मात्र की सजा से बरी भी कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौजूदा न्यायव्यवस्था भी देश की शोषक राज्य मशीनरी का अभिन्न अंग है। यह उम्मीद रखना कि कानूनों या न्यायालयों के जरिए भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा, मरीचिका में पानी की उम्मीद रखने के बराबर होगा।

सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार चंद बुरे लोगों या लोभियों के आचरण से उपजा हुआ मामला नहीं है। भ्रष्टाचार व घोटाले उस पूंजीवादी व्यवस्था का विकृत परिणाम है जिसका मूलमंत्र ही मुनाफे के पीछे भागना है। हालांकि पूंजीवाद ऊपर से लोकतंत्र का चोला ओढ़ा हुआ रहता है तथा आजादी, समानता आदि मूल्यों की रट लगाया करता है, लेकिन वास्तव में वह दूभर श्रम-शोषण, रिश्वतखोरी, दलालखोरी आदि अव्यवस्थाओं से भरा रहता है। इसलिए भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को जड़ से खत्म करने का मुद्दा व्यवस्था-परिवर्तन से जुड़ा हुआ सवाल है। यह मानकर चलना एक कोरा भ्रम ही होगा कि देश में मौजूद अर्धऔपनिवेशिक व अर्धसामंती व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही चंद बेहतर कानूनों के सहारे से इस समस्या का पूरी तरह समाधान किया जा सकता है।

दरअसल घोटालों के रूप में जो उजागर होते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा रोशनी में आए बिना ही रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्रप्रदेश के मृत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, ओड़िशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखण्ड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुण्डा, कर्नाटका मुख्यमंत्री येदियूरप्पा समेत और कई नेताओं ने जिस प्रकार माइनिंग माफिया से हाथ मिलाकर दलाली खाई और कई बड़ी कम्पनियों के साथ गुप्त एमओयू कर दलाली के रूप में हजारों करोड़ रुपए अवैध रूप से जो कमाए, उसके बारे में यहां तक कि अखबारों ने भी चर्चा की है। सरकारों द्वारा लागू उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों ने ही इस तरह के कई भ्रष्टाचार-घोटालों के लिए तथा देश की सम्पदाओं की मनमानी लूटखसोट के दरवाजे खोल रखे हैं। इस पृष्ठभूमि में इन साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों का विरोध किए बिना तथा उनके खिलाफ संघर्ष छेड़े बिना ही भ्रष्टाचार का अंत कर पाने की आस लगाए बैठना या कर पाने का दावा करना जनता को गुमाराह करना ही है।

लोकपाल विधेयक के लिए सरकार द्वारा सांझी कमेटी की घोषणा की जाने के बाद अन्ना हजारे ने तो अपनी अनशन तोड़ दी, लेकिन जनता को इससे इंसाफ नहीं मिला जो देश भर में उनकी हड़ताल के साथ खड़ी हुई थी। दरअसल सरकार ने यह मांग अन्ना की भूख हड़ताल से डरकर पूरी नहीं की, बल्कि उनके समर्थन में उभर कर आए जनता के आक्रोश को ठण्डा करने के लिए की। उससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि शासक वर्ग भली भांति जानते हैं कि इस तरह के काननों से मौजूदा व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसीलिए उन्होंने बेखौफ होकर लोकपाल विधेयक के लिए कमेटी की घोषणा की।

भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में आगे आई जनता का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी स्वागत करती है। भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष का हमारी पार्टी तहेदिल से समर्थन करती है। हमारी पार्टी का यह विश्वास है कि जनता के सांझे, संगठित और जुझारू संघर्षों के जरिए ही भ्रष्टाचार का अंत

करना संभव हो सकेगा। हमारी पार्टी देश की जनता से आग्रह करती है कि वह सरकार द्वारा घोषित सतही कानूनों और कानून तैयार करने के लिए कमेटियों के गठन की घोषणाओं से संतुष्ट होकर अपने संघर्ष को समाप्त न करे, बल्कि संघर्ष की राह पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारियों, जनता की भलाई चाहने वाले गांधीवादियों समेत तमाम देशभक्त तबकों का हमारी पार्टी आह्वान करती है कि वे देश में कैंसर की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाकर सड़कों पर उतर आएं। हमारी पार्टी की अपील है कि यह नारा बुलंद किया जाए कि उन डकैतों और महाचोरों को सत्ता में एक पल के लिए भी बने रहने का हक नहीं है जो अंतहीन भ्रष्टाचार व घोटालों में लिप्त होकर देश की जनता का खून-पसीना चूसते हुए लाखों करोड़ों रुपए का काला धन स्विस बैंकों में छुपा रहे हैं।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

28-4-2011

जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर पुलिस की गोलीबारी और गिरफ्तारियों की निंदा करो!

जैतापुर संयंत्र समेत देश में प्रस्तावित सभी परमाणु बिजली संयंत्रों को रद्द करने के लिए संघर्ष करो!

18 अप्रैल 2011 को जैतापुर के 9,900 मेगावाट वाले प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलन कर रही जनता पर पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें परमाणु-विरोधी कार्यकर्ता तबरेज़ सोयेकर (32) की मौत हुई जो नाटे गांव का निवासी था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला आदमी था। आठ अन्य प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गए। विरोध-प्रदर्शनकारियों ने एक अस्पताल पर हमला कर दिया ताकि वहां पर सरकारी शव-परीक्षण को रोका जा सके क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं था कि सरकार निष्पक्ष शव-परीक्षण करवाएगी। जापान में फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र में हुए परमाणु हादसा के बाद तेजी पकड़ने वाले इस चार साल पुराने आंदोलन ने अच्छा-खासा अनुभव प्राप्त किया था जिससे सरकार की संवेदनहीनता को समझा जा सके।

बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों की अनदेखी करते हुए तथा पीड़ितों को मुआवजा देने या आश्वस्त करने की कोई कोशिश नहीं करते हुए पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और महाराष्ट्र सरकार (जो साम्राज्यवादियों के पालतू कत्ते हैं) ने अपना मंतव्य दोहराया कि वे 'दुनिया के इस बहुत बड़े परमाणु बिजली सुमदाय' के निर्माण को जारी रखेंगे जिसमें छह रिएक्टर होंगे। दरअसल, सरकार ने फुकुशिमा त्रासदी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए 'किसी भी कीमत पर' परमाणु बिजली पार्क को बनाने की जो नीति अपनाई, उसके खिलाफ हुआ था उपरोक्त विरोध प्रदर्शन।

पुलिस ने करीब 100 लोगों और जाने-माने कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया, जो भारत के हर कोने (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्यप्रदेश) से इकट्ठे हुए थे ताकि 23 से 25 अप्रैल तक तारापुर से, जहां भारत का पहला परमाणु बिजली प्लांट की स्थापना हुई, जैतापुर तक प्रस्तावित राष्ट्रीय परमाणु-विरोधी यात्रा में भाग लिया जा सके। दरअसल, फुकुशिमा के बाद परमाणु बिजली परियोजनाओं के खिलाफ देश में चारों तरफ, खासकर हरियाणा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में कुछ नए और कुछ पहले से चले आ रहे विरोध-प्रदर्शनों का एक सिलसिला ही चल पड़ा। लेकिन इससे हमारे बहरे शासकों के कान में जूं तक नहीं रेंगी।

इस परमाणु संयंत्र के तहत पांच गांव - मडबन, निवेली, करेल, मितगावणे और सखारी नाटे आते हैं जो महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के जैतापुर क्षेत्र में स्थित हैं और यह भूकम्प के प्रभाव में आ सकने वाला क्षेत्र है। यहां पर 968 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया। इस संयंत्र से 40 हजार जनता प्रभावित होगी जिसमें 16 हजार आबादी मछवारों की है।

फुकुशिमा हादसे के बाद जहां कई देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर दोबारा विचार कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़िग है। इस सचाई को छिपाकर कि भारत के रिएक्टरों को दुनिया के सबसे अक्षम और खतरनाक माने जाते हैं, कुछ जन-विरोधी वैज्ञानिक जनता को गुमराह करने के लिए सफेद झूठ बोल रहे हैं कि भारत के सुरक्षा मानक जापान से भी बेहतर हैं! जयराम रमेश जो अभी तक खुद को पर्यावरणवादी मंत्री कहते नहीं थकते थे, अब यह कहते हुए कि परमाणु ऊर्जा का कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने अपना असली कॉर्पोरेट-अनुकूल चेहरा दिखा दिया है। वह अब मनमोहनसिंह की भाषा बोल रहे हैं जिन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद भारत-अमेरिका परमाणु करार पर दस्तखत कर परमाणु कम्पनियों से मिली अरबों रुपए की दलाली से वोट खरीदे थे। जब समूची दुनिया विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को तलाश रही है, ये मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है, मानों हम सब भारतीय बेवकूफ हों जो इस बकवास पर विश्वास करें। अगर घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की बिजली की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी हैं तो यहां सब कुछ संभव है। लेकिन ऐसे देश में जहां मुकेश अम्बानी का एक महीने का बिजली बिल 71 लाख रूपए का है और जहां बिजली की भारी खपत की जरा भी

परवाह किए बिना दिन और रात के क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि संकट में फंसे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं जिसका एक कारण बिजली की किल्लत भी है। लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में मद्धिम रोशनी देने वाली एक बत्ती तक नहीं है। ऐसे में यह कयास लगाया जा सकता है कि मंत्री महोदय किन लोगों की ऊर्जा की जरूरतों की बात कर रहे हैं। केन्द्र और राज्यों की दलाल सरकारों ने भारत के व्यापक ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मौजूद अपार खनिज भण्डारों का उत्खनन करने के लिए सैकड़ों एमओयू पर दस्तखत कर रखे हैं। खदानों और विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत है। कार्पोरेट कम्पनियों की इन जरूरतों ने ही जयराम रमेश, मनमोहनसिंह जैसे लोगों को पागल बना दिया है जो जनता के जबर्दस्त विरोध के बावजूद भी बिजली संयंत्रों को बनाने पर आमादा हैं। जनता की आजीविका, देश के पर्यावरण की सुरक्षा आदि मुद्दे जो विरोध–प्रदर्शनकारी उठा रहे हैं वो इनके लिए बेतुके हैं। एक मात्र समाधान जो वो जानते हैं वह है उन्हें 'कानून और व्यवस्था' की समस्या के रूप में देखना।

और तो और, हम यह कभी नहीं जान पाएंगे (बशर्तेकि कोई और विकी 'लीक' सामने न आ जाए) कि हमारे दलाल शासकों ने फ्रांस की कम्पनी 'आरेवा' से कितनी दलाली ले रखी होगी जिससे हम रिएक्टर आयात कर रहे हैं जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे परमाणु–अनुकूल देशों ने इस कम्पनी को डिजाइन क्लियरेन्स देने से इनकार कर दिया। दुनिया में अभी तक एक भी इवोल्यूशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टर (ईएफआर) का न तो निर्माण हुआ और न ही उसकी सुरक्षा की जांच हो पाई जिससे ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय और असुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। फिर भी अपने साम्राज्यवादी आकाओं के तलवे चाटने वाले हमारे शासक उन्हें खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं जबकि वो मानवीय और पर्यावरणीय क्षति का जरा भी अंदाजा नहीं लगा रहे हैं।

फुकुशिमा हादसे ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और उसका संहारक परमाणु विकिरण का प्रभाव दसियों हजार सालों तक रहेगा। स्वतंत्र यूरोपियाई चिकित्सा विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि रिएक्टर के 200 किलोमीटर के दायरे में 4 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से ग्रस्त होंगे और इस संयंत्र का विकिरणीय प्रदूषण पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 25 साल पहले चेर्नोबिल में हुए परमाणु हादसे के बाद चार लाख लोगों को खाली कराया गया था। अन्य दसियों लाख लोग अभी भी लगातार प्रदूषित वातावरण में डर के साये में जीने को मजबूर हैं

कि कभी भी उन्हें कैंसर जकड़ ले सकता है और उनकी कई आने वाली पीढ़ियां गंभीर बीमारियों के साथ जन्म ले सकती हैं। अभी तक करीब दस लाख लोग उसके विलम्बकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से मारे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। अगर जैतापुर में कोई बड़ा हादसा होगा तो समूचे रत्नगिरी जिले को पूरी तरह खाली करवाना पड़ेगा और पुणे व मुम्बई समेत समूचा पश्चिम महाराष्ट्र दसियों हजार सालों तक विकिरणीय प्रदूषण से ग्रस्त रहेगा।

जैतापुर की कोंकणी जनता जो इन सभी दुष्प्रभावों से, खासकर फुकुशिमा के बाद अच्छी तरह वाकिफ है, इस परमाणु संयंत्र के खिलाफ दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर रही है। सरकार ने इस संघर्ष को दबाने के लिए एक बर्बर दमन अभियान छेड़ दिया। लाठीचार्ज, धारा 144 और धारा 37(3) को लागू करना जिसके तहत लोगों की सभी किस्म की गोलबंदी पर प्रतिबंध रहेगा, मारपीट, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर करना (जिसमें एक हत्या का प्रयास भी है!) और अब पुलिसिया गोलीबारी। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के खिलाफ रत्नगिरी जिला छोड़ने का आदेश जारी किया गया। नारायण राणे ऐसी धमकियां भी दे रहे हैं कि जो लोग जिले में कदम रखेंगे वो जिंदा लौटकर नहीं जाएंगे! पुलिस ने मीडिया को यह भी बताया कि वह इस आंदोलन पर कड़ी नजर रख रही है ताकि 'नक्सलवादियों के साथ संभावित सम्बन्धों' का पता लगाया जा सके, जोकि उसकी चिर-परिचित धमकी है। इस संघर्ष का समर्थन करने वाले इस क्षेत्र के जाने-माने नागरिकों के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इन सभी कार्रवाइयों से जैतापुर आंदोलन का हौसला कम नहीं हुआ जो पूरे भारत में विभिन्न ज्वलंत मसलों को लेकर लड़े जा रहे समझौताहीन संघर्षों में एक और मिसाल बनकर शामिल हो रहा है।

पिछले चार सालों के दौरान जब यह आंदोलन चल रहा था, चुप्पी साधकर रहने वाली शिवसेना ने अब इसमें प्रवेश किया क्योंकि वह इसमें कोंकण इलाके में नारायण राणे के दल बदलने के बाद खोई हुई जमीन को फिर से पाने की संभावना देख रही है। राजनीतिक रूप से सचेतनशील जैतापुर जनता को चाहिए कि वह इन अवसरवादियों को, जिन्होंने एनरॉन को अरब सागर में फेंक देने का दावा किया था और सत्ता में आने के बाद बात बदल दी थी, अपने स्वार्थ हितों के लिए इस संघर्ष को गुमराह करने का कोई मौका न दे। परमाणु करार के मुद्दे पर अपने आपको चैम्पियन के रूप में पेश करने वाली सीपीएम, परमाणु ऊर्जा

को एक मात्र विकल्प के रूप में चुनने वाले सरकारी के फैसले के खिलाफ मजबूत हो रहे इस मोर्चे पर कहीं नहीं दिख रही है। आंध्रप्रदेश में तेलुगुदेशम जैसी विपक्षी पार्टियां हालांकि बिजली संयंत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की गोलीबारी में मारे जाने वाले लोगों पर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, लेकिन जब एक बार वे सत्ता में आएंगी तो यही काम करेंगे क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड यही बता रहा है। जहां एक तरफ परमाणु बिजली संयंत्रों का विरोध करने वाली सभी तरह की ताकतों को एकजुट कर एक विशाल आधार पर संघर्ष को व्यापक बनाने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ हितों या वोट बैंक की राजनीति के लिए संघर्ष को असल मुद्दे से भटका देने की सभी किस्म की साजिशों के प्रति जनता को सतर्क रहने की जरूरत है।

भाकपा (माओवादी) यह मांग करती है कि जैतापुर परमाणु पार्क समेत भारत में प्रस्तावित सभी परमाणु बिजली संयंत्रों को रद्द किया जाए। परमाणु प्लांट से उत्पन्न होने वाले खतरों से अपनी जिंदगियों और पर्यावरण को बचाने के लक्ष्य से लड़ रही कोंकणी जनता के न्यायपूर्ण आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए जा रहे दमनकारी कदमों का हमारी पार्टी खण्डन करती है। 18 अप्रैल को हुई गोलीबारी की न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग करते हैं। परमाणु–विरोधी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए गए सभी फर्जी मुकदमों, अवैध जिला–बदर आदेश और प्रतिबंधों को वापस लिया जाए। दरअसल रत्नगिरी के लोगों को यह घोषणा करनी चाहिए कि नारायण राणे जैसे लोगों को, जो संसाध नों से समृद्ध कोंकणी तटवर्ती इलाके को साम्राज्यवादियों को बेचने और उनकी आजीविका को तबाह करने पर आमादा हैं, इस इलाके में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है, न कि परमाणु–विरोधी कार्यकर्ताओं को जो उनके लिए निस्वार्थपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं।

आइए, हम यह घोषणा करें कि हमें किस तरह का विकास या ऊर्जा के स्रोत चाहिए यह तय करने का अधिकार देश की जनता को ही होना चाहिए, न कि भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं को जो साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नमकहलाल नौकरों की तरह काम करते हैं। आइए, हम कोंकणी जनता के परमाणु संयंत्र विरोधी संघर्ष का दृढ़तापूर्वक समर्थन करें और शासक वर्गों द्वारा बढ़ाए जा रहे बिजली के असुरक्षित और खतरनाक विकल्प के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान का निर्माण करें। हमें तबरेज़ जैसों की कुरबानियों को व्यर्थ

नहीं होने देना चाहिए, जैसा कि रत्नगिरी की जनता ने घोषणा की।

आज हमारा देश इस बात का गवाह है कि चारों तरफ जल-जंगल-जमीन, सच्चा लोकतंत्र, विकास, आत्मनिर्भरता आदि को केन्द्र में रखते हुए जनता के जुझारू संघर्षों का एक बाढ़ सा आया हुआ है। जनता इन संघर्षों को (कुछ को तो कई सालों से) शांतिपूर्ण और जुझारू तरीके से तथा भीषण दमन के बावजूद भी पीछे न हटते हुए संचालित कर रही है। ये सभी संघर्ष परस्पर प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। वक्त का तकाज़ा है कि इन सभी संघर्षों को एक दूसरे के भाईचारे में और आपसी समर्थन में मजबूती से खड़े होकर एक साझा मंच में लाना चाहिए ताकि साम्राज्यवादियों, भारत के बड़े कॉर्पोरेट दैत्यों तथा सामंती सरदारों के खिलाफ लड़ा जा सके जो इन जन-विरोधी नीतियों को लागू कर रहे हैं और संघर्षरत जनता का दमन कर रहे हैं। भारत के तमाम संघर्षरत जन समुदायों का एक विशाल, समवेत और जुझारू आंदोलन ही इस देश और जनता को दरिद्रता के अंधेरे गर्त से बचा सकता है जिसमें जनता के दुश्मन हमें धकेलने की साजिश रच रहे हैं।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

4-5-2011

ओसामा नहीं; बल्कि युद्धोन्मादी, कसाई और खून का प्यासा ओबामा ही दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है जिससे विश्व शांति को खतरा है!

अल क़ायदा से नहीं; बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद से ही सबसे बड़ा खतरा है, न सिर्फ दुनिया के समूचे उत्पीड़ित राष्ट्रों और अवाम को, बल्कि अमेरिकी नागरिकों को भी!

दुनिया का दरोगा सीआईए द्वारा एक कोवर्ट ऑपरेशन में मारे गए ओसामा बिन लादेन की बर्बर हत्या का विरोध करो!

2 मई को अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने हेलिकॉप्टरों से हमला कर अल क़ायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की हत्या की। पाकिस्तान के एब्बोटाबाद शहर के एक बंगले पर अमेरिका ने रात के अंधेरे में बम गिराए जिसमें ओसामा ने शरण ली हुई थी। पाकिस्तानी सरकार को इस बाबत सूचना तक न देकर अमेरिका ने पाकिस्तान की संप्रभुता का मजाक उड़ाया। उन्होंने पाकिस्तानी राडॉरों को जाम कर दिया और चार हेलिकॉप्टरों को उसके आसमान पर उड़ाया। उस मकान पर धमाके कर अपने 'अचूक ऑपरेशन' को अंजाम दिया। इस हमले में एक महिला और दो अन्य पुरुष भी मारे गए और बताया जा रहा है कि ओसामा की पत्नी भी घायल हो गईं। चालीस मिनट तक चले इस ऑपरेशन में उनकी बच्ची इत्तेफाक से बच गई। निर्दयी ओबामा प्रशासन ने ओसामा के शव के साथ भी संवेदनहीनता बरतते हुए उसे उनके परिवार वालों को सौम्पने की बजाए अरब सागर में फेंक दिया! यह दुनिया भर में मुसलमानों के घावों पर नमक छिड़कने के बराबर है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इससे वे कितना अपमान और गुस्सा महसूस करेंगे।

ज्यों ही ओबामा ने अल क़ायदा के प्रमुख की मौत की उल्लासपूर्ण घोषणा की, अमेरिकी सरकार की फासीवादी सहयोगियों, यानी साम्राज्यवादी देशों के

राष्ट्राध्यक्षों और तीसरी दुनिया के दलाल शासकों ने खुशी से फूले न समाते हुए इसे आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध में एक महान उपलब्धि बताई। भारत के दलाल शासक वर्गों ने मौके का फायदा उठाते हुए आरोप लगाए कि पाकिस्तान अपनी धरती पर इतने 'खतरनाक आदमी' को शरण दे रहा था। सार्क के एक सदस्य देश पर उसकी संप्रभुता का जरा भी कद्र किए बगैर किए गए इस एकतरफा हमले की निंदा में एक शब्द तक नहीं कहा। इस बात पर एक प्रश्न तक नहीं उठाया कि इस उप-महाद्वीप की धरती पर अमेरिकी युद्ध मशीनरी को क्या काम था। भारत के दलाल शासक वर्गों के इस पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने तीसरी दुनिया में कई बार साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका और नाटो द्वारा उन देशों की संप्रभुता पर हमला करते हुए किए गए दुराक्रमणकारी युद्धों और दखलंदाजियों का खुला और छिपा समर्थन किया था और वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के आगे हमेशा घुटने टेकते रहे।

2001 में अफगानिस्तान पर नाटो के युद्ध के बाद से आतंक के खिलाफ अपने तथाकथित युद्ध में पाकिस्तानी सरकार का 'समर्थन हासिल करने' के लिए अमेरिका अपनी बाह-मरोड़ और धौंस जमाने की नीति में आए दिन बढ़ोत्तरी कर रही है। इस युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका का विस्तारित पिछवाड़ा बना हुआ है। यह ऑपरेशन इस युद्धोन्मादी धौंसिया के अनगिनत अंधाधुंध हमलों का एक ताजा उदाहरण है और यह खासकर पिछले दस सालों में उसके द्वारा पाकिस्तान में अनगिनत बार की गई बेरोकटोक दखलंदाजियों की धारावाहिकता भर है। पाकिस्तान के दलाल शासक उसके आगे इस कदर नतमस्तक हो गए कि इस प्रकार की आक्रामक कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तानी सरकार ने सभी अंतराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए किए गए इस हमले का खुलकर खण्डन तक नहीं किया। समूचे पाकिस्तान में उठ खड़े हुए व्यापक आंदोलनों से बने दबाव के चलते ही उसने दबी जुबान से यह बात कही कि यह हमला अवैध था और इसे उसकी जानकारी के बगैर अंजाम दिया गया था। लेकिन जब मालिक ने यह कहा कि 'तो क्या है? हम माफी नहीं मांगने वाले हैं' तो इस नौकर का मुंह बंद हो गया। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सामने दुम हिलाते हुए इसने जिस प्रकार पूरी तरह घुटने टेक रखे हैं, इसे देखते हुए यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया का नम्बर एक आतंकवादी ओबामा आए दिन पाकिस्तान के पश्तूनी कबीलाई इलाकों में अनगिनत ड्रोन हमले कर रहा है जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों (जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं) की मौत हो रही है।

दर्जनों संभावित खून के प्यासे रेमण्ड डेविस पाकिस्तान की सड़कों पर बेधड़क घूम रहे हैं जिन्हें आम पाकिस्तानी नागरिकों का खून बहाने में जरा भी संकोच नहीं है। फिर भी ये बेशर्म और बेहया पाकिस्तानी शासक वर्ग इस हत्यारे 'नोबेल शांति पुरस्कार विजेता' के लिए लाल कालीन बिछाने में मशगूल हैं जो पाकिस्तानियों के खून से सना है।

कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल क़ायदा द्वारा किए गए 9/11 के हमलों के बाद से तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व में अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने दुनिया भर में वहशियाना मुस्लिम विरोधी दुष्प्रचार शुरू किया। अफगानिस्तान और इराक में दुराक्रमणकारी युद्ध किए। इन अन्यायपूर्ण युद्धों में लाखों आम जनता हताहत हुई। कहने की जरूरत ही नहीं है कि महिलाओं और बच्चों के साथ कितनी बर्बरता बरती गई। आतंकवाद पर युद्ध के नाम पर दुनिया भर में मुसलमानों को निशाने पर लिया गया और उन पर बेहद अत्याचार किए गए। अल क़ायदा को इस 'आतंकवाद' के चेहरे के रूप में दिखाया गया और ओसामा को अमेरिका और दुनिया का नम्बर एक दुश्मन बताकर बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया गया। अल क़ायदा को हरेक आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया ताकि मुसलमानों के खिलाफ जारी सभी किस्म के अत्याचारों को जायज ठहराया जा सके। ओसामा और अल क़ायदा के दूसरे नेताओं की धरपकड़ की मुहिम चलाई गई और तथाकथित 'आंतकवाद पर युद्ध' में अरबों डॉलर बहा दिए गए। अफगानिस्तान और इराक में कठपुतली सरकारों की स्थापना की गई और पाकिस्तान की स्थिति करीब-करीब उपनिवेश जैसी बन गई। मुस्लिम जन समुदायों को 'आतंकवाद पर युद्ध' का दैत्य रौंद रहा है जिसमें लाखों लोगों को कुचला जा रहा है।

इतिहास में यह बात कई बार साबित हो चुकी है कि एक नेता को मारकर आप किसी संगठन को खत्म नहीं कर सकते। जब तक कि उसकी बुनियादी वजहों को, जैसे कि इस मामले में अंधाधुंध साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीड़न, दखलंदाजी और अपमान हैं, दूर नहीं करेंगे तब तक इसे आप हल नहीं कर सकते। साम्राज्यवादियों के खिलाफ, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों और इज्राएली यहूदीवादियों के खिलाफ मुस्लिम जनता के दिलों में सुलग रहे गहरे आक्रोश और असंतोष की अभिव्यक्ति कई रूपों में सामने आ रही है जिसमें अल क़ायदा एक है। अरब दुनिया में उठ रहे जन उभार इस आक्रोश की - जो उनके देशों के तानाशाहों और साम्राज्यवाद के खिलाफ है - एक और

अभिव्यक्ति है। साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में अल क़यदा जैसे संगठनों द्वारा लागू कुछ तरीकों से आम लोगों को क्षति हो रही है और जिन तरीकों से निर्दोष लोगों की मौत होती है उसका खण्डन करना जरूरी है। लेकिन हमें इन्हें संदर्भ से अलग कर नहीं देखना चाहिए और इन्हें 'अमेरिका से निहायत नफरत करने वाले' कुछ सिरफिरों की कार्रवाइयों के रूप में नहीं देखना चाहिए जैसा कि अमेरिकी सरकार चाह रही है कि उसके नागरिक इसे विश्वास करें। **अगर साम्राज्यवादी दखलंदाजियां और दुराक्रमणकारी युद्ध नहीं होते तो अल क़ायदा नहीं होता। अगर बुश और ओबामा जैसे हत्यारे नहीं होते तो आसामा भी नहीं होता।**

भाकपा (माओवादी) समूची जनता का आह्वान करती है कि वह अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा की गई ओसामा बिन लादेन की बर्बर हत्या का खण्डन करे। हमारी मांग है कि 'आतंकवाद पर युद्ध' के नाम से मुसलमानों पर जारी सभी किस्म के हमलों को फौरन बंद किया जाए।

भाकपा (माओवादी) दृढ़तापूर्वक दोहराती है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद ही ऐसी एक मात्र विचारधारा है जो दुनिया में हर किस्म के शोषण और उत्पीड़न का अंत कर सकती है। सिर्फ सर्वहारा और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में उत्पीड़ित राष्ट्र और जन समुदाय, जोकि तानाशाहों, 'लोकतंत्र' के नाम पर चलाई जा रही बुर्जुआई तानाशाहियों और साम्राज्यवाद द्वारा दबे-कुचले जा रहे हैं, सम्पूर्ण मुक्ति हासिल कर सकते हैं। अल क़ायदा या उस जैसे दूसरे संगठनों की कितनी भी कार्रवाइयों से साम्राज्यवादियों के दुराक्रमण और दखलंदाजी से आजादी या संप्रभुता जीती नहीं जा सकती। फिलिस्तीनियों के संघर्षों समेत अरब दुनिया में उठ रहे जन-उभार जब तक अपने देशों में साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ जनयुद्धों के रूप में संगठित नहीं होंगे तब तक उनके संगठनों द्वारा जारी अथक संघर्ष और उनकी अनमोल कुरबानियां सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचेंगी।

भाकपा (माओवादी) दुनिया के समूचे उत्पीड़ित राष्ट्रों और जन समुदायों का आह्वान करती है कि वे साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हमलों का विरोध करें जो अन्यायपूर्ण तरीके से आतंकवाद के खिलाफ तथाकथित युद्ध शुरू कर दुनिया भर में मुस्लिम जन समुदायों पर हमले कर रहे

हैं। हम अमेरिकी नागरिकों से यह समझने की अपील करते हैं कि तथाकथित आतंकवादी नहीं, बल्कि उनके अपने शासकों द्वारा तीसरी दुनिया के देशों में लागू बर्बर साम्राज्यवादी नीतियां ही अमेरिकी नागरिकों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं; आप्रवासी नहीं, बल्कि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ही बारम्बार पैदा होने वाले वित्तीय संकटों के लिए जिम्मेदार है जिससे उनके हित खतरे में पड़ रहे हैं या उनके बीच बेरोजगारी बढ़ रही है। हम अमेरिकी जन समुदायों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे सांझे दुश्मन के खिलाफ उसके घरेलू मैदान में अपनी आवाज बुलंद करें। आप अपने देश के शासकों द्वारा दबी-कुचली जा रही जनता के जायज संघर्षों का समर्थन कर खुद की मुक्ति का रास्ता भी सुगम बना सकेंगे। हमें उम्मीद है कि इजारेदार पूंजी के खिलाफ अमेरिका समेत सभी साम्राज्यवादी देशों के मजदूर वर्ग व जन समुदाय के संघर्ष तथा उत्पीड़ित राष्ट्रों और तीसरी दुनिया के जन समुदायों के संघर्ष एकताबद्ध होंगे और एक भारी तूफान का शक्ल ले लेंगे जिसमें हमारा सांझा दुश्मन निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा।

भाकपा (माओवादी) खासतौर पर दक्षिण एशिया के जन समुदायों का आह्वान करती है कि वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो बलों की बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और उनकी फौरन वापसी की मांग करें। पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हमलों के खिलाफ तथा साम्राज्यवादी धौंस व दखलंदाजी के खिलाफ संघर्षरत पाकिस्तान के अवाम का समर्थन करें।

आइए, हम सब इस बात को समझ लें कि अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन है जिससे विश्व शांति, तीसरी दुनिया के देशों की संप्रभुता और उनके विकास को खतरा है। आइए, हम साम्राज्यवादियों और अपने देशों में मौजूद उनके दलालों को उखाड़ फेंक दें ताकि हम शोषण और उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त जिंदगी जी सकें तथा इज्जत से सिर उठाकर जी सकें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

11-5-2011

बिहार में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा करो!

भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय नेताओं की गिरफ्तारी, देश के शासक गिरोह द्वारा जनता के ऊपर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध तथा उसके अंतर्गत ही उत्तरप्रदेश के किसानों पर जारी दमन के खिलाफ

21-22 मई को 'भारत बंद' सफल बनाओ!

29 अप्रैल को बिहार के कटिहार जिले के ग्राम बारसोई में केन्द्रीय तथा आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की खुफिया संस्थाओं ने सुनियोजित हमला कर हमारी पार्टी के तीन केन्द्रीय कमेटी सदस्यों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कॉमरेडों में केन्द्रीय कमेटी के सदस्य पुलेंदु शेखर मुखर्जी उर्फ साहेब दा, वारणासी सुब्रह्मण्यम् उर्फ विमल उर्फ श्रीकांत, विजय कुमार आर्य उर्फ जसपाल जी के अलावा बिहार-झारखण्ड स्पेशल एरिया के अंतर्गत उत्तर बिहार-उत्तरप्रदेश रीजनल ब्यूरो सचिव अभिमन्यु उर्फ उमेश यादव, नोखेलाल चौधरी, श्यामजी ऋषि, और आश्रयदाता अनिरुद्ध रविदास शामिल हैं। क्रांतिकारियों की ढूंढ़-ढूंढकर हत्या करने के लिए कुख्यात आंध प्रदेश एसआईबी पिछले कुछ महीनों से कॉमरेड सुब्रह्मण्यम् का पीछा कर रही थी। पिछले साल जुलाई के आखिर में वे उसके हमले से बाल-बाल बच गए थे। जब ये कॉमरेड एक बैठक के सिलसिले में इकट्ठे हुए थे, उसी मौके पर केन्द्र-राज्य खुफिया संस्थाओं द्वारा दी गई पक्की सूचना के आधार पर बिहार के एसटीएफ अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया।

पार्टी में साहेब दा, गगन दा, आकाश दा आदि नामों से बुलाए जाने वाले

67 वर्षीय वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड पुलेंदु शेखर मुखर्जी पिछले 45 सालों से क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कलकत्ता शहर में पैदा होने वाले साहेब दा नक्सलबाड़ी आंदोलन की प्रेरणा से उच्च शिक्षा को छोड़कर क्रांतिकारी संघर्ष में कूद पड़े थे और जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने लम्बे क्रांतिकारी सफर में उन्होंने बंगाल समेत देश के विभिन्न इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए तथा सच्चे क्रांतिकारियों व कम्युनिस्ट संगठनों की एकता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। दमा, पेट का अल्सर आदि बीमारियों से बुरी तरह पीड़ित होकर भी वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहे।

विमल नाम से आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी खेमे में तथा श्रीकांत के नाम से देश भर में पार्टी कतारों में मशहूर कॉमरेड वारणासी सुब्रह्मण्यम् ने विशाखापटनम के आंध्र विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पूरी करके क्रांतिकारी गतिविधियों में कदम रखा था। 1970 के दशक में उन्होंने रैडिकल छात्र संगठन और बाद में रैडिकल युवा संगठन व सिंगरेणी मजदूर संघ का नेतृत्व किया था। पार्टी के आह्वान पर उत्तर भारत में जाकर उन्होंने वहां के कई राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए अथक प्रयास किए। अपनी गंभीर अस्वस्थता की परवाह किए बगैर वे विभिन्न स्तरों और विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय कार्य करते रहे।

विजय कुमार आर्य के नाम से बिहार की जनता में लोकप्रिय कॉमरेड जसपाल जी एक महत्वपूर्ण कॉमरेड हैं जिन्होंने किसानों और सांस्कृतिक मोर्चे का नेतृत्व करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में उल्लेखनीय कार्य किया। पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से वे विभिन्न मोर्चों और विभिन्न इलाकों में क्रांतिकारी क्रियाकलापों का नेतृत्व करते रहे और जन आंदोलनों का निर्माण करते रहे।

बेअंत क्रूरता के लिए बदनाम सीआईए, मोस्साद जैसे विदेशी खुफिया संगठनों द्वारा प्रशिक्षित भारतीय खुफिया अधिकारी क्रांतिकारी आंदोलन का लम्बे समय से नेतृत्व करने वाले कॉमरेडों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ रहे हैं। दरअसल अमेरिका की सीआईए और एफबीआई ही हमारे देश की खुफिया संस्थाओं को चला रही हैं। पिछले दो सालों में पकड़े जाने वाले अग्रणी कॉमरेडों में पटेल सुधाकर, शाखामूरी अप्पाराव और आजाद की खुफिया संस्थाओं ने हत्या

कर दी। कुछ और केन्द्रीय व राज्य स्तर के नेतृत्वकारी कॉमरेडों को गिरफ्तार कर जेलों में कैद किया। इन्हें अलग-अलग राज्यों के झूठे मामलों में फंसाकर लम्बे समय तक बिना किसी जमानत के जेलों में पड़े रहने पर मजबूर किया जा रहा है। झूठी गवाहियां दिलवाकर कठोर सजाएं और आजीवन सजाएं दी जा रही हैं। विभिन्न राज्यों के जेलों में बंद महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा अमानवीयता के साथ शारीरक और मानसिक यातनाओं का शिकार बनाया जा रहा है। जेलों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित सुशील रॉय, शीला दीदी, नारायण सान्याल, कोबाड गांधी, अमिताभ बाग्ची आदि कॉमरेडों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

तीखे संकट से ग्रस्त विश्व अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए साम्राज्यवादी पिछड़े देशों में संसाधनों की लूटखसोट में तेजी ला रहे हैं। जिन-जिन देशों से वे अपने हितों को जरा भी खतरा महसूस करते हैं उनके खिलाफ वे धौंस व धमकियों पर उतारू हो रहे हैं। जो उनकी बात नहीं मानते उन पर एकतरफा बमबारी करते हुए अन्यायपूर्ण युद्ध कर रहे हैं। भारत के सामंती व दलाल पूंजीपति शासक वर्ग यह झूठा दावा करते हुए कि देश में इस संकट का कोई प्रभाव नहीं है, दिन-ब-दिन संकट में गहरे फंसते जा रहे हैं। साम्राज्यवादी लूटखसोट के लिए सारे दरवाजे खोलते हुए नव उदार नीतियों पर निर्लज्जता से अमल कर रहे हैं। केन्द्र व राज्यों की सरकारें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू कर देश की प्राकृतिक सम्पदाओं को औने-पौने दामों में बेच रही हैं। एसईजेड, परमाणु रिएक्टरों की स्थापना, थर्मल बिजली परियोजनाएं, भारी बांध, एक्सप्रेस हाईवे, अभयारण्य आदि योजनाओं के नाम पर जनता से जमीनें बलपूर्वक छीन रही हैं। जल-जंगल-जमीन का, कुल मिलाकर पर्यावरण का विनाश करते हुए जनता को, खासकर आदिवासियों को बेघरबार कर रही हैं। इन नीतियों की आड़ में ही मंत्री, मुख्यमंत्री और नौकरशाह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व घोटाले करते हुए लाखों करोड़ रुपए डकार रहे हैं। इस तरह जमा किए गए काले धन को स्विस बैंकों में छुपा रहे हैं। इस तरह वे मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग की जिंदगी दूभर बना रहे हैं। जहां एक ओर टाटा, बिड़ला, अंबानी, जिंदल, मित्तल, महेंद्रा, रुइया, निको जयस्वाल, सन नेटवर्क आदि अपनी सम्पत्तियों को हजारों, लाखों करोड़ों में बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की 77 फीसदी जनता रोजाना 20 रुपए से भी कम आमदनी से भूखों मर रही है। भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, विस्थापन, बीमारियां,

कुपोषण आदि समस्याओं के भंवर में फंसकर देश की जनता छटपटा रही है। इसका विरोध करने वाली और आंदोलन करने वाली जनता का लौह पैरों से रौंदने के लिए शासक लाखों पुलिस व अर्धसैनिक बलों का प्रयोग कर रहे हैं। नागरिक व जनवादी अधिकारों का हनन करते हुए काले कानून बना रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का जन धन पानी की तरह बहा रहे हैं ताकि जनता का दमन करने वाली मशीनरी के पंजों की धार बढ़ाई जा सके।

लुटेरे शासक वर्गों के प्रति जनता में फूट पड़ रहे असंतोष और आक्रोश से माओवादी आंदोलन को मजबूती मिल रही है, इस सचाई को चिन्हित कर शासक वर्गों ने सुनियोजित तरीके से यह प्रचार शुरू किया कि 'माओवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है'। माओवादी आंदोलन को हिंसावाद के रूप में तथा माओवादी पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में चित्रित करते हुए बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार मुहिम शुरू कर दी। अपनी साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों को लागू करने तथा उसके अंतर्गत संसाधनों की लूटखसोट के रास्ते में माओवादी पार्टी को बहुत बड़ी बाधा मानते हुए उन्होंने माओवादी पार्टी का जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से खासकर पिछले दो सालों से एक बेहद पाशविक व फासीवादी हमला शुरू किया जिसका नाम 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' रखा गया है। माओवादी आंदोलन के इलाकों में विभिन्न स्तरों पर विकसित हो रही वैकल्पिक जन राज्यव्यवस्था का भी गला घोंटने के लक्ष्य से जारी इस हमले में जनवरी 2011 से तेजी लाई गई और इसे अब 'ऑपरेशन ग्रीन हंट-2' कहा जा रहा है। इसके तहत पुलिस, अर्धसैनिक व विशेष बलों तथा उनके द्वारा बनाए गए प्रति-क्रांतिकारी गुण्डा गिराहों ने आंदोलन के क्षेत्रों में फर्जी मुठभेड़, कत्लेआम, गांव-दहन, लूट, महिलाओं पर बलात्कार, गिरफ्तारी और बर्बर यातना का सिलसिला तेज कर दिया। शासक वर्ग छत्तीसगढ़ में सेना की तैनाती की तैयारियां पूरी करके माड़ क्षेत्र में 800 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। माड़ क्षेत्र और छत्तीसगढ़-ओड़िशा की सीमा पर दो सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने जा रहे हैं। वायु सेना के बेस स्थापित करने की तैयारियों के अलावा 'आत्मरक्षा' के नाम पर उसे हमले करने का अधिकार भी दे दिया गया है।

दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़) के चिंतलनार इलाके में 11 से 16 मार्च तक 350 कोबरा बलों, कोया कमाण्डों बलों और सैकड़ों एसटीएफ बलों ने मोरपल्ली, तिम्मापुरम और ताड़िमेटला गांवों पर भारी तबाही मचाकर 300 घरों

में आग लगा दी। हजारों कुंटल अनाज जला दिया। घर–घर को लूटा। तीन ग्रामीणों की हत्या की। दो ग्रामीणों को लापता कर दिया। पांच महिलाओं के साथ बलात्कार किया। करीब 50 ग्रामीणों के साथ बुरी तरह मारपीट की। इसकी जांच–पड़ताल के लिए जा रहे जनवादियों, रिपोर्टिंग के लिए जा रहे मीडियाकर्मियों तथा पीड़ितों को राहत–सामग्री ले जा रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फासीवादी मुख्यमंत्री रमनसिंह, शासक वर्गों के वफादार कुत्ते डीजीपी विश्वरंजन, बस्तर आईजी लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एसएसपी कल्लूरी ने सोची–समझी साजिश के तहत सलवा जुडूमी गुण्डों से हमले करवाकर उन्हें उस इलाके में जाने से रोक दिया। इन घटनाओं को लेकर प्रदेश और देश में बड़े पैमाने पर हुए प्रचार की पृष्ठभूमि में रमनसिंह को ताड़िमेटला गांव के दौरा करने पर मजबूर होना पड़ा। उस मौके पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की सभा चल ही रही थी, तो दूसरी तरफ कोया कमाण्डो दरिंदों ने गांव के दूसरे कोने में फिर 15 घरों में लूटपाट मचाई और कुछ लोगों के साथ मारपीट कर एक महिला के साथ बलात्कार किया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में फासीवादी आतंक कितना भयावह रूप धारण कर चुका है। इस तरह के हमले बस्तर क्षेत्र के साथ–साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आए दिन किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन इलाकों में गोपनीय हत्यारे दस्तों को उकसाकर जन संगठन कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाई जा रही हैं। खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार और हमले करवाए जा रहे हैं। 19 अप्रैल को नारायणपुर जिले के चिनारी गांव में 14 वर्षीय किशोर रजनू की हत्या कर मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी गई। दण्डकारण्य में आए दिन चल रहे भीषण दमनचक्र के ये चंद ताजा उदाहरण भर हैं।

14 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह माओवादी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या की। कुछ अन्य कॉमरेडों को गिरफ्तार किया। झारखण्ड सरकार माओवादी नेताओं की हत्या करने के बुरे मंसूबे से हजारों पुलिस व अर्धसैनिक बलों को उतारकर हमले कर रही है। अंधाधुंध गिरफ्तारियां चला रही है। विस्थापन और जबरिया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर फासीवादी हमले कर रही है। ओड़िशा में दलाल नवीन पटनायक सरकार ने राज्य के चारों कोनों में फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला चलाकर पिछले चार महीनों में ही 25 से ज्यादा माओवादी कार्यकर्ताओं, खदान–विरोधी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की हत्या की। मृतकों में 12 वर्षीय

बालिका जांगा और कुछ अन्य किशोरियां भी शामिल हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटनायक सरकार की दमनकारी नीतियों ने कितना घिनौना रूप ले लिया है।

पिछले 34 सालों से जारी अपने फासीवादी शासन को किसी भी तरह टिकाए रखने के लक्ष्य से पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार ने चुनावों के पहले जनता और माओवादियों पर हमले तेज किए। पुलिस व अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ अपनी गुण्डा वाहिनी - हर्मद बाहिनी के जरिए वह अमानवीय हत्याकाण्डों और जघन्य अपराधों को अंजाम दे रही है। नेताई हत्याकाण्ड, शशध र महतो की हत्या जैसी घटनाएं चंद ताजा उदाहरण हैं। गिरफ्तार माओवादी नेताओं पर, खासकर महिलाओं पर वह अमानवीय हिंसा कर रही है। हाल ही में मेदिनीपुर जेल में हड़ताल कर रहे राजनीतिक कैदियों पर उसने पुलिस बलों को उकसाकर हमला करवाया। राज्य में माओवादी आंदोलन का सफाया करने का ढिंढ़ोरा पीटने वाली आंध्रप्रदेश सरकार ने अपने पुलिस बलों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। माओवादी नेताओं को पीछा कर मार डालने की नीतियों में उसने तेजी लाई। पृथक तेलंगाणा राज्य के लिए आंदोलनरत जनता का वह दमन कर रही है। महाराष्ट्र सरकार आदिवासी आंदोलन के क्षेत्रों में सी-60 कमाण्डों बलों के सहारे दमनचक्र को लगातार तेज कर रही है। शहरी इलाकों में माओवादी नेताओं और जनवादियों को गिरफ्तार कर उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा रही है।

यह फासीवादी हमला सिर्फ माओवादी आंदोलन पर ही नहीं चल रहा है। लुटेरे शासक वर्ग हर जनवादी आंदोलन पर फासीवादी दमन का ही प्रयोग कर रहे हैं। पिछले माह 18 तारीख को महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु बिजली परियोजना के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर पुलिस ने गोली चलाकर तबरेज़ नामक एक प्रदर्शनकारी की जान ली। और अब उत्तरप्रदेश में ग्रेटर नोइडा से आग्रा तक प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए अपनी जमीनें देने से इनकार करने वाले किसानों पर पुलिस बल पाशविक दमनचक्र चला रहे हैं। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। कम से कम दो किसान मारे गए। पुलिसिया जुल्म का भट्टा-परसौल और उसके आसपास के गांवों की जनता ने बहादुराना तरीके से प्रतिरोध किया। इसमें दो पुलिस वाले मारे गए, जबकि कुछ अन्य अधिकारी व पुलिस वाले घायल हो गए। अगले दिन आग्रा, अलीगढ़ आदि इलाकों में भी जनता ने अपना आंदोलन

तेज कर दिया। पुलिस जुल्म का प्रतिरोध किया। इस बहाने फासीवादी मायावती सरकार उत्तरप्रदेश के किसानों पर तीव्र दमन चला रही है। गांवों की नाकेबंदी कर जनता के ऊपर कई अत्याचार कर रही है।

प्यारे लोगो! जनवाद के प्रेमियो! देशभक्तो! उपरोक्त फासीवादी दमनात्मक कार्रवाइयां और माओवादी नेताओं की गिरफ्तारियां ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से जारी उस युद्ध का हिस्सा हैं जिसे देश का शासक गिरोह – यानी सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम गिरोह साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ से देश की जनता के खिलाफ चला रहा है। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था जिस तीव्र संकट में फंसी हुई है, उसका प्रभाव हमारे देश के सभी क्षेत्रों में पड़ रहा है और इसी पृष्ठभूमि में इस राजनीतिक दमन, हत्याकाण्डों और मानवाधिकारों पर हमलों को समझना चाहिए। माओवादी आंदोलन का जड़ से सफाया कर लुटेरी सरकारों की साम्राज्यवाद–परस्त और जन–विरोधी नीतियों को बेरोकटोक जारी रखने की साजिश का ही हिस्सा है यह सब। यह एक ऐतिहासिक सचाई है कि दमन प्रतिरोध को जन्म देता है। सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम शोषक शासक गिरोह हत्याओं, गिरफ्तारियों और दमनात्मक मुहिमों से जन आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने का जो सपना देख रहा है वह दिवास्वप्न ही साबित होगा। कॉर्पोरेट घरानों को अंधाधुंध मुनाफा पहुंचाकर किसानों व आदिवासियों को बेघरबार करने वाला 'विकास' का ढोंगी नमूना देशवासियों पर थोपते हुए, देश को बेचने वाले ये सामंती, दलाल पूंजीपति शासक वर्ग और उनको चलाने वाले साम्राज्यवादी ही बहुत बड़े दुश्मन हैं जिनसे हमारे देश के विकास, स्वावलम्बन, सम्प्रभुता, स्वतंत्रता और जन कल्याण को भारी खतरा है। हमारी केन्द्रीय कमेटी का यह आह्वान है कि इन दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य से हमारी पार्टी की अगुवाई में जारी जनयुद्ध तथा नई जनवादी क्रांति में आप सब बड़े पैमाने पर गोलबंद हों। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, जनवादियों और शांति वार्ता की हिमायत करने वालों से हमारी केन्द्रीय कमेटी अपील करती है कि वे हमारे आंदोलन के इलाकों का दौरा कर यहां पर हो रहे अमानवीय दमन और हत्याकाण्डों की खुद जांच–पड़ताल करें। हमारी केन्द्रीय कमेटी यह आग्रह करती है कि 'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' कहलाने वाले इस देश के बीचोबीच बेहद गरीब जनता पर, आदिवासियों पर हो रही सरकार की फासीवादी हिंसा से जुड़ी सचाइयां देश की तमाम जनता के सामने उजागर करें।

हमारी केन्द्रीय कमेटी जनता और जनवादियों का यह आह्वान करती है कि

वे इन गिरफ्तारियों, कत्लेआमों, पुलिसिया जुल्म, तबाही, लूटपाट, अत्याचारों, दुष्प्रचार, राज्य के फासीकरण, जबरिया जमीन अधिग्रहण और यूएपीए जैसे काले कानूनों का खण्डन करें और इसके खिलाफ एकजुटता से संघर्ष करें। सरकार से हमारी मांग है कि माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। सरकारी फासीवादी आतंक का एकजुटता और जुझारू तरीके से प्रतिरोध करना ही एक मात्र रास्ता है, अतः हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम क्रांतिकारी जनता का यह आह्वान करती है कि वह इसके लिए हिम्मत के साथ आगे आए। हम स्पष्ट करते हैं कि पार्टी और पीएलजीए के नेतृत्व में जारी जन प्रतिरोधी आंदोलन को और ज्यादा तेज कर तथा इसमें हजारों, लाखों की संख्या में गोलबंदी से ही इस हमले को पराजित किया जा सकता है।

हमारी केन्द्रीय कमेटी देश की तमाम जनता से अपील करती है कि माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी, जनता के ऊपर देश के शासक गिरोह द्वारा जारी युद्ध और उत्तरप्रदेश के किसानों पर जारी दमन के खिलाफ 21-22 मई को 48-घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाया जाए। यह बंद प्रमुख रूप से 6 राज्यों - झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के तीन जिलों - गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया में, मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में तथा उत्तरप्रदेश के बिहार के सीमावर्ती जिलों में लागू किया जाएगा। अन्य राज्यों में विभिन्न रूपों में विरोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हालांकि हम चिकित्सा सेवाओं, छात्रों की परीक्षाओं व साक्षात्कार जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखेंगे।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

13-6-2011

Hkkjrh; Økfr ds ofj"B usrk vkSj mRihfM+r turk ds I;kjs usrk

dkWejsM txnh'k ekLVj mQZ Hkwis'k th dks fcuk 'krZ fjgk djks!

dkWejsM txnh'k ekLVj dh fxjQ~rkjh vkSj Økfrdkjh vkanksyu ij 'kk"kd oxksZa }kjk tkjh Qklhoknh neu ds f[kykQ 23 twu dks ^Hkkjr cUn* lQy cukvks!

बिहार की शोषित जनता के बीच कॉमरेड 'जगदीश मास्टर' के नाम से लोकप्रिय, भाकपा (माओवादी) के पोलिटब्यूरो सदस्य और पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक कॉमरेड भूपेश जी को 11 जून को पुलिस ने बिहार के गया जिले के गुरार से गिरफ्तार किया। 72 साल के वयोवृद्ध और करीब दस सालों से गंभीर अस्वस्थता से जूझते हुए भी जनता के बीच, जन संघर्षों को अपनी सांस बनाकर काम कर रहे कॉमरेड भूपेश जी को सादे कपड़ों में आए बिहार व केन्द्रीय फासीवादी खुफिया गुण्डों ने उस समय उठा लिया जब वे इलाज के सिलसिले में जा रहे थे। अपने ही संविधान व कानून का, जिसका पालन करने का वे दावा करते नहीं थकते, घोर उल्लंघन करते हुए उन्होंने कॉमरेड भूपेश जी को 24 घण्टे बीत जाने पर भी अदालत में पेश न करके उन्हें तरह–तरह की यातनाओं और प्रताड़नाओं का शिकार बनाया।

पार्टी कतारों में 'कॉमरेड भूपेश' के नाम से सुविख्यात कॉमरेड जगदीश मास्टर पिछले चार दशकों से क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए अथक प्रयास करने वाले एक महत्वपूर्ण नेता हैं। जब वे शिक्षक की नौकरी कर रहे थे तब उनका परिचय भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के महान नेताओं में से एक शहीद कॉमरेड कन्नाई चटर्जी के साथ हुआ था। उनकी प्रेरणा से वे

क्रांतिकारी राजनीति में आ गए और 1970 के दशक के शुरूआती दौर से उन्होंने पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। सामंती शोषण और उत्पीड़ित जातियों के लोगों पर अगड़ी जातियों की सामंती सेनाओं के बर्बर हमलों के लिए बदनाम बिहार में उन्होंने शोषित जनता के जुझारू नेता बनकर कई जन संघर्षों का नेतृत्व किया। अब इस गिरफ्तारी से नव सामंत नीतिशकुमार और सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम गिरोह यह मंशा जाहिर कर रहे हैं कि वे बिहार के किसान समुदायों को फिर से अंधकार में ले जाना चाहते हैं। जमींदारों से हजारों एकड़ जमीन जब्त कर भूमिहीन व गरीब किसानों में बांटने तथा उन पर होने वाले सामाजिक उत्पीड़न का मुकाबला कर आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जीने की स्थिति निर्मित करने में कॉमरेड भूपेश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपनी वृद्धावस्था और बुरी तरह बिगड़ते स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, दुश्मन के हाथों पड़ने तक जनता के बीच ही रहकर जनता, काडरों और नई पीढ़ियों में प्रेरणा और उत्साह का संचार करने वाले कॉमरेड भूपेश जी की गिरफ्तारी एक बड़ा सद्मा है।

देश के शासक वर्ग माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए उसका नेतृत्व कर रहे केन्द्रीय व राज्य स्तर के नेताओं को गिरफ्तार करना, मुठभेड़ के नाम से गोली मार देना जैसी करतूतों पर उतारू हैं। खासकर पिछले दो सालों से जारी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से जारी देशव्यापी हमले के अंतर्गत एक तरफ महत्वपूर्ण नेताओं को निशाने पर लेकर उन पर वार करते हुए ही दूसरी तरफ आंदोलन के इलाकों में फासीवादी दमनचक्र चला रहे हैं। मुठभेड़ों के नाम से निहत्थे लोगों की अंधधाधुंध हत्याएं करना, गांवों को जलाना, महिलाओं पर अत्याचार, सम्पत्तियों को तबाह करना, लूटपाट, मारपीट, झूठे मामलों में फंसाकर सालों साल बिना सुनवाई या जमानत के जेलों में सड़ाना आदि मध्ययुगीन क्रूरतापूर्ण दमनात्मक तरीकों और नात्सी किस्म के फासीवादी स्वरूपों में यह हमला – ऑपरेशन ग्रीन हंट – चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के वे हिस्से जहां क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के लौह जूतों तले रौंदे जा रहे हैं।

जनवरी 2011 से जारी ऑपरेशन ग्रीनहंट के कथित दूसरे चरण में सरकारें एक ओर गांवों और जनता पर भीभत्सपूर्ण हमले करते हुए ही दूसरी ओर वे

इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले लेखकों, कलाकारों, जनवादियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का गला घोंटने के लिए चरम फासीवादी हमलों पर उतारू हैं। छत्तीसगढ़ में जन डॉक्टर व मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा देना; चिंतलनार क्षेत्र में सरकारी बलों द्वारा मचाए गए बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए जा रहे स्वामी अग्निवेश आदि लोगों पर हमले; पीयूसीएल पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां; लेखकों और पत्रकारों पर झूठे केस दायर करना व हमले करना; ओड़िशा में कॉर्पोरेट कम्पनियों द्वारा जारी जबरिया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर दमनचक्र; मुठभेड़ के नाम पर खदान–विरोधी कार्यकर्ताओं को गोली मार देना; बिहार में जनता पर गोलीबारी व हत्याएं; झारखण्ड में बेजा कब्जा हटाने के नाम पर जनता को विस्थापित करने वाले सरकारी फैसलों का विरोध करने वाली जनता पर गोलीबारी व जुल्म; पंजाब में पत्रिका सम्पादक व जन संगठन कार्यकर्ता हरविंदरसिंह जलाल की गिरफ्तारी और यातनाएं; उत्तरप्रदेश में शासक वर्गों के 'विकास' के ढोंगी नमूने का विरोध करने पर किसानों का दमन; महाराष्ट्र में दलित आंदोलन का कार्यकर्ता व पत्रिका सम्पादक सुधीर ध ावळे को राजद्रोह के मामले में गिरफतार करना; आंध्रप्रदेश में पृथक तेलंगाना आंदोलन पर विभिन्न तरीकों में जारी दमनचक्र आदि इसके कुछ उदाहरण भर हैं।

देश की सम्पदाओं को साम्राज्यवादियों व दलाल पूंजीपतियों की कॉर्पोरेट कम्पनियों के हवाले करने पर तुले हुए भारत के शासक वर्गों ने इस राह में सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़े माओवादी आंदोलन का जड़ से उन्मूलन करने के इरादे से जारी इस अन्यायपूर्ण युद्ध में अब सेना को उतार दिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सैन्य बलों को 'प्रशिक्षण' के नाम पर मैदान में उतरा जा चुका है। कथित रूप से देश की सीमाओं पर शत्रु सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए निर्मित भारतीय सेना को अब देश के बीचोबीच देश की जनता के खिलाफ जारी युद्ध में झोंक दिया जा रहा है। सैन्य बलों के प्रशिक्षण के नाम पर बस्तर के माड़ इलाके में 750 वर्ग किलोमीटर जमीन देने वाले रमनसिंह सरकार के फैसले से माड़ क्षेत्र का पांचवां हिस्सा हड़प लिया जाएगा। दूसरी ओर कॉर्पोरेट कम्पनियां हजारों एकड़ जमीनों को निगलने वाली परियोजनाओं के साथ आगे आ रही हैं। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन

के इलाकों में जनता को बलपूर्वक विस्थापित करने वाली साजिशें बड़े पैमाने पर जारी हैं।

एक ओर देश में अंधाधुंध भ्रष्टाचार–घोटालों में लिप्त कांग्रेस, भाजपा समेत सभी शासक वर्गीय पार्टियों के अनैतिक नेता, कॉर्पोरेट डकैत और बड़े अधिकारी हजारों, लाखों करोड़ रुपए डकारकर देश की जनता के गुस्से व नफरत का शिकार बन रहे हैं। महंगाई, भुखमरी, अकाल, महम्मारी, विस्थापन, संसाधनों का दोहन आदि समस्याओं से देश की करोड़ों जनता दो–चार है। जनता की एक भी बुनियादी समस्या का हल न करने वाली सरकारें जायज जन आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से फासीवादी दमन व हत्याकाण्डों पर उतारू हैं। वहीं दूसरी तरफ, जनता के लिए निःस्वार्थ, समर्पित व अविराम परिश्रम करने वाले क्रांतिकारी नेताओं को जेलों में ठूंस रही हैं और उनकी हत्याएं कर रही हैं। कॉमरेड भूपेश जी की गिरफ्तारी इसी सिलसिले का हिस्सा है।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी देशवासियों का आह्वान करती है कि कॉमरेड भूपेश जी की गिरफ्तारी के खिलाफ तथा क्रांतिकारी आंदोलन पर जारी शासक वर्गों के फासीवादी दमनचक्र के खिलाफ 23 जून को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाया जाए। यह बंद मुख्य रूप से छह राज्यों – झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के तीन जिलों – गढ़चिरौली, चंद्रपुर व गोंदिया जिलों, उत्तरप्रदेश के बिहार की सीमा से लगे हुए जिलों तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आयोजित होगा। अन्य राज्यों में विभिन्न रूपों में विरोध कार्यक्रम होंगे। चिकित्सा सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं, छात्रों की परीक्षाओं और साक्षात्कार आदि को हम बंद से मुक्त रखेंगे।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

15-6-2011

vkij'ku xhu gV d nlj pj.k d rgr
NRrhlx< vkj vkfM'kk e
iLrkfor u, ljdkjh vkØe.k dk edkcyk djk!
n'k dk yVu&[klkVu d y{; l tkjh gj
Qklhoknh vkØe.k dk
n'k dh LokfHkekuh turk viu cgknjkuk ifrjk/k
l gjkdj jgxh!

14 जून 2011 को केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर इन दो राज्यों में 'वामपंथी उग्रवाद' का खात्मा करने के लिए एक नया आक्रमण शुरू करने की घोषणा की। हमेशा दोहराए जाने वाले अपने दोहरे मंत्र – 'विकास और पुलिस कार्रवाई' की आड़ में गृहमंत्री ने यह आश्वासन देते हुए कि इन दो राज्यों को बर्बर आक्रमण चलाने में पूरा समर्थन दिया जाएगा, उन्हें पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ने को कहा। ओड़िशा के खून के प्यासे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जिसके हाथ उन सैकड़ों लोगों के खून से सने हैं जो 'विकास के भगवान' के लिए इंसानी बलि के तौर पर चढ़ाए गए थे, अब हेलिकॉप्टरों की मांग की है ताकि बेचारे आदिवासियों पर बमबारी की जा सके। रमनसिंह जो संभवतः इतिहास में एक ऐसे भगवा फासीवादी के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसने दुनिया के प्रचीनतम मानव समुदायों में से एक बस्तर के आदिवासियों के लिए मौत की घंटियां बजा दीं, ने अपने राज्य में बढ़ रहे बहादुराना सशस्त्र प्रतिरोध से बने दबाव को धुंधलाते हुए माओवादियों के सफाए को लेकर ऊंचे–ऊंचे दावे किए। कुछ दिन पहले जून महीने के पहले सप्ताह में (प्रध

ानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में हुई 'माओवाद–प्रभावित' राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक के बाद एक सप्ताह के अंदर ही) आंध्रप्रदेश और ओड़िशा की सरकारों ने माओवादियों का सफाया करने की मंशा से एक बड़ा अभियान चलाने की घोषणा की जिसके बारे में यह बताया गया कि वह तीन माह तक चलेगा। उन्होंने घोषणा की कि वे आधुनिक तकनीक और नए तरीकों व दावपेंचों का इस्तेमाल करेंगे जिसके तहत माओवादियों पर 'पानी, हवा और जमीन' से वार किया जाएगा। हेलिकॉप्टरों का भी इस्तेमाल करने की संभावना जताई। और अब यह जगजाहिर है कि छत्तीसगढ़ में 'प्रशिक्षण' के बहाने सेना को उतारा जा चुका है।

यह घोषणा उस समय की जा रही है जिसके कुछ ही दिन पहले सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने बस्तर (छत्तीसगढ़) क्षेत्र में मौजूद रावघाट खदानों के निजीकरण की घोषणा की। और यह उस समय की जा रही है जबकि ओड़िशा की जनता ने पोस्को द्वारा किए जा रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जबर्दस्त प्रतिरोध खड़ा किया हुआ है, जहां 'भारत का सबसे बड़ा विदेशी पूंजीनिवेश' किया जा रहा है (जो दरअसल 'इतिहास में भारत के प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की सबसे बड़ी कोशिश' है।) और यह घोषणा ऐसे वक्त की जा रही है जिसके चंद दिन पहले हमारी पीएलजीए (जन मुक्ति गुरिल्ला सेना) द्वारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के उन इलाकों में जो दण्डकारण्य में आते हैं, लगातार हमलों का सिलसिला छेड़ा गया था। शासक वर्गों ने इन राज्यों की सीमाओं पर अपने हमले को केन्द्रित किया है ताकि उनकी लूटखसोट के लिए कोई सीमा न रह सके तथा अपनी लूटखसोट का दायरा निर्बाध रूप से बढ़ाया जा सके। (उदाहरण के लिए पूर्व में जैसा ओड़िशा और झारखण्ड के बीच; पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के बीच; छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच; और छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश–महाराष्ट्र के बीच चलाया गया था।) अब साफ जाहिर है कि काज और कारण के बीच क्या सम्बन्ध है।

दरअसल सच्चाई यह है कि यह घोषणा इस पृष्ठभूमि में की गई है कि भारत की समूची जनता ने – उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, खासकर मध्य भारत में – दलाल शासक वर्गों के 'विकास के नमूने' को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश,

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूवोत्तर क्षेत्र समेत समूचे देश में करीब–करीब हर उस परियोजना के खिलाफ जो देश को बेच डालने और लूटने–खसोटने की लिए लाई गई हो, बढ़ रहा प्रतिरोध इसका ऐसा स्पष्ट उदाहरण है जिसे सिर्फ वो लोग देख नहीं पाते हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर 'विकास' का दृष्टिहीन चश्मा पहन रखा हो। और हवा में तैर रहे 'जल–जंगल–जमीन पर अधिकार हमारा है' और 'ढोंगी विकास की योजनाओं को बंद करो' के नारे सिर्फ वो लोग सुन नहीं पाते हैं जिनके कानों में 'पुलिस कार्रवाई' के ध्वनिरोधक प्लग लगे हों।

दरअसल अपने देश को गिद्ध जैसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े दलाल पूंजीपतियों से बचाने के लिए देश के निर्धनतम लोगों द्वारा जारी तमाम किस्म के प्रतिरोधी संघर्षों – हिंसात्मक और अहिंसात्मक; जुझारू और शांतिपूर्ण; सशस्त्र और निःशस्त्र संघर्षों – पर देश का हर देशभक्त इंसान गर्व करेगा। और न सिर्फ अपने बाल–बच्चों के लिए, बल्कि देश के हर नागरिक को इज्जत से जीने का अधिकार हासिल करने के लिए उनके द्वारा दी जा रही कुरबानियों को तहेदिल से नमन करेगा। लेकिन भारत के शासक वर्ग इसे उलटा देख रहे हैं। इन प्रतिरोधी संघर्षों को लेकर वे बौखलाए हुए हैं, सहमे हुए हैं, घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और गले तक गुस्साए हुए हैं क्योंकि इससे उन्हें उन 'वायदों' को पूरा करने में दिक्कत आ रही है जो उन्होंने अपने साम्राज्यवादी आकाओं और अपने वर्ग से कर रखे हैं कि वे देश की तमाम सम्पदाओं को चने–मुर्रे के भाव में बेच डालेंगे। उनके आका अब उनके सीने पर बैठकर उनसे 'विकास का रास्ता सुगम बनाने' के नाम पर पेट फटते तक खाई हुई दलाली के बदले 'नतीजे दिखाने' का दबाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि वे इन प्रतिरोधी संघर्षों को कुचलने की हताशा भरी कोशिशों के तहत नए–नए अभियान छेड़ते जा रहे हैं।

सबसे पहले हमें उनके इन सफेद झूठों से धोखा नहीं खाना चाहिए कि ये आक्रमण अभियान सिर्फ माओवादियों को कुचलने के लिए चलाए जा रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दरअसल ये आक्रमण इन इलाकों के तमाम किसानों, आदिवासियों और मजूदूरों को; महिलाओं, बच्चों, पुरुषों और बूढ़ों को; जनवादियों, देशभक्तों और क्रांतिकारियों को; एक शब्द में कहें तो देश के उन तमाम नागरिकों को जिनका इस देश के संसाधनों पर वाजिब हक है, कुचलने के लिए चलाए जा रहे हैं। इसलिए हमें एक व्यक्ति बनकर समवेत स्वर में

आवाज उठानी चाहिए ताकि अपने प्यारे देश को बेच डालने की उनकी तमाम साजिशों को हरा दिया जा सके।

हमें सरकारों से सवाल करने हैं कि – जनता द्वारा खारिज किए गए 'विकास के नमूने' को उन्हीं के नाम पर अमल करने का अधिकार उन्हें आखिर किसने दिया है? देश की जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च कर पुलिस कार्रवाइयों और सैन्य अभियानों में खुद के नागरिकों को मार डालने का अधिकार उन्हें आखिर किसने दिया है? लाखों सशस्त्र बलों को बलि के बकरे बनाकर ऐसे युद्ध में झोंकने का अधिकार उन्हें किसने दिया है जो उनके हित में या उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कतई नहीं लड़ा जा रहा हो, बल्कि साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और सामंतों के हितों में लड़ा जा रहा हो? सबसे अहम, अपनी आजीविका और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत जनता पर नरसंहार, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार, फर्जी मुठभेड़ें, हिरासती हत्याएं आदि कुकृत्य करने का अधिकार इन सरकारों को कहां से मिला है?

माओवादी संघर्ष वाले इलाकों में, खासकर छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में एक के बाद एक लगातार हुए हमलों के चलते सरकारी सशस्त्र बलों के गिरते मनोबल को ऊपर उठाने के लिए गृहमंत्री ने कहा कि उनके बल माओवादियों का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और इस साल 125 मुठभेड़ों में कुल 78 माओवादियों को मार गिराया। हम देश और दुनिया की जनता का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये आंकड़े सच्चाई को बयां नहीं करते, बल्कि सच यह है कि सैकड़ों निहत्थे लोगों को (चाहे वे क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक या कार्यकर्ता हों या न हों) सरकारी सशस्त्र बलों ने ठण्डे दिमाग से फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला। 'माओवादी' महज एक बहाना बना है जिसका ठप्पा लगाकर जनता के जायज संघर्षों को दबाया जा रहा है जिनमें न सिर्फ वो संघर्ष शामिल हैं जिनका नेतृत्व माओवादी कर रहे हैं और जिनमें सिर्फ वही संघर्ष शामिल नहीं हैं जिनका माओवादी नेतृत्व कर रहे हैं।

गैंग्स्टर मुख्यमंत्रियों और डाकू पुलिस महा निदेशकों (डीजीपी) की हर बैठक में आंध्रप्रदेश सरकार की पीठ यह कहकर थपथपाई जाती है कि उसने अपने राज्य में माओवादी आंदोलन को सुचारू रूप से कुचल दिया। सच्चाई यह है कि इस 'उपलब्धि' को हासिल करने के लिए उन्होंने लगातार चार

दशकों तक फासीवादी हमले कर क्रांतिकारियों, जनता और खासकर तेलंगाना के लोगों का काफी खून बहाया। अब यह उकसाया जा रहा है कि हर राज्य इसी फासीवादी नमूने पर अमल करे। आंध्रप्रदेश के ग्रेहाउण्ड्स के बल ओड़िशा और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में खुलेआम घुसपैठ करते हैं ताकि माओवादियों और सीमावर्ती इलाकों की आदिवासी बस्तियों पर हमले किए जा सके। देश के किसी भी हिस्से में हुई माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी और प्रत्येक फर्जी मुठभेड़ के पीछे एपीएसआईबी का हाथ है। इसलिए केन्द्र सरकार के पूर्ण समर्थन से एओबी में आंध्रप्रदेश और ओड़िशा सरकारों द्वारा तालमेल के साथ तीन माह तक चलने वाले इस भारी आक्रमण को हम अगर मजबूत प्रतिरोध के जरिए रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो इतिहास में एक बेहद खूनी अध्याय शुरू होने का खतरा है। सलवा जुडूम, शांति सेना तथा सशस्त्र बलों के कई किस्म के अत्याचारों के लिए बदनाम छत्तीसगढ़ और ओड़िशा में यह हमला बेहद बर्बर तरीके से चलेगा क्योंकि साम्राज्यवाद–परस्त सरकारी नीतियों के खिलाफ इन राज्यों में मजबूत सशस्त्र और निःशस्त्र जन प्रतिरोध ा जारी है। केन्द्र सरकार ने अब इन दो राज्यों पर आक्रमण को केन्द्रित करते हुए आंध्र के सीमावर्ती इलाकों को भी इसमें जोड़ दिया। इस व्यापक इलाके में प्रतिरोध को दबाकर वे फिर दूसरे इलाकों की ओर निकल पड़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि झारखण्ड या पश्चिम बंगाल में हमले रुकने वाले हैं। इसका यही मतलब है कि देशव्यापी युद्ध के अंतर्गत अब इस इलाके पर फोकस रहेगा।

अपनी जिंदगी के लिए और अस्तित्व के लिए संघर्षरत भारत के लोगों के प्रति देश की तमाम जनता और विश्व जनता की ओर से हमेशा समर्थन मिला है, मिल रहा है। देश के शासक वर्गों द्वारा किए जा रहे इन फासीवादी आक्रमणों के संदर्भ में उनका समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए, हम देश–दुनिया की तमाम सच्ची जनवादी ताकतों से अपील करते हैं कि वे भारत के शासक वर्गों की साजिशों का पर्दाफाश कर, उसके खिलाफ हर संभव तरीके से संघर्ष छेड़ें। हमारी अपील है कि वे संघर्ष के क्षेत्रों में सेना की तैनाती को रोकने और तमाम आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक व मनोवैज्ञानिक हमलों को रोकने की मांग के साथ आंदोलनों का निर्माण करें।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी छत्तीसगढ़–ओड़िशा, आंध्रप्रदेश–ओड़िशा और छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश की

सीमावर्ती इलाकों की तमाम लड़ाकू जनता का आह्वान करती है कि वे इस नए फासीवादी हमले का बहादुरी के साथ मुकाबला करें। समूची पार्टी और पीएलजीए बलों को चाहिए कि वे इस व्यापक इलाके में जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सभी मोर्चों में दुश्मन के इस हमले का प्रतिरोध करें तथा सशस्त्र प्रतिरोध को तेज करें।

★ छत्तीसगढ़–ओड़िशा, ओड़िशा–आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में प्रस्तावित नए फासीवादी आक्रमण को फौरन रोक दिया जाए!

★ ऑपरेशन ग्रीन हंट को तत्काल बंद किया जाए!

★ पोस्को, रावघाट रेल लाइन और खदानों के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण को रोका जाए!

★ पोस्को परियोजना के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर चलाए जा रहे सरकारी दमनचक्र का विरोध करो!

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

18-6-2011

4 ls 11 tqykbZ rd e/; jhtu esa fojks/k lIrkg euk;k tk,!
ukjk;.kiqj ftys ¼ekM+ {ks=½ ds chpkschp clk;s tk jgs
lsuk ds izf'k{k.k dsUæ dks rRdky can djks!

छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भारतीय सेना के लिए एक काउण्टर–गुरिल्ला प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जा रहा है। यह इलाका एक प्राचीन आदिवासियों का जीवन–स्थल है। इन्हीं आदिवासियों के बारे में विगत दो दशकों से सरकार का कहना है कि यह कबीला विलोप के कगार पर है। आज यहां के एक बड़े भू–भाग पर सैनिक अड्डा बसाना उस प्रक्रिया को और तेज करने के सिवाए कुछ नहीं है। 'माओवादी शीर्ष नेताओं ने इन पहाड़ों को अपना अड्डा बनाया है और यहां पर उनकी भूमिगत गतिविधियां खुलेआम चलती हैं' कहकर छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत पांच सालों से इस क्षेत्र को एक सैनिक छावनी में तब्दील किया हुआ है। विगत दो साल से यहां पर ग्रीन हंट ऑपरेशन के तहत सघन सैनिक अभियान चलाया जा रहा है। आज यहां पर एक सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना यहां के आदिवासियों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। वास्तव में इसके पीछे कारण यह है कि यहां के बहुमूल्य खनिज सम्पत्ति को लूटकर ले जाना उनका मकसद है। यहां की जनता इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इस तीखे जन विरोध को कुचलने के षड़यत्र से सेना को तैनात किया जा रहा है। हमारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और जनता से आह्वान करती है कि इसके विरोध में जन संघर्ष को तेज किया जाए।

माड़ क्षेत्र से सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रस्ताव को तुरंत रद्द करने की मांग से 4 से 11 जुलाई तक मध्य रीजन के छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश–ओड़िशा सीमा क्षेत्र में आयोजित 'विरोध सप्ताह' सफल बनाया जाए। भारत की व्यापक जनता और जनवाद के प्रेमियों व आदिवासियों के हितैषियों से हमारी अपील यह है कि वे इस विरोध सप्ताह को सफल बनाने हेतु आगे आएं।

भारतीय सेना के जवानों से हमारी अपील यह है कि वे लुटेरे शासक वर्गों के हित में आदिवासी जनता के खिलाफ युद्ध मत करें। 'माओवादी' के बहाने जनता पर फायरिंग मत करें।

प्रताप
प्रवक्ता
मध्य रीजनल ब्यूरो
भाकपा (माओवादी)

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

22-6-2011

u flQ viuh tehuk dk] cfYd viu cPpk dk Hkfo"; Hkh Nhu yu okyh ikLdk ifj;ktuk dk cgknjkuk ifrjk/k dj jg ikLdk&fojk/kh vknkyudkfj;k dk yky&yky lyke!

u nyky o rkuk'kkg 'kkld uohu iVuk;d dk vkj u gh lkfu;k &euekgu&t;jke je'k&fpnEcje dk] cfYd flQ turk dk ;g r; dju dk vf/kdkj g fd ge fdl fdLe dh ifj;ktuk, pkfg,! ikLdk fojk/kh vknkyu d leFku e n'k Hkj e 0;kid tu vknkyuk dk fuek.k dj!

भारत की जनता पिछले एक सप्ताह से ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में जारी 'पोस्को–विरोधी आंदोलन' का साक्षी रही है जोकि आधुनिक भारत के इतिहास में किसी साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की परियोजना के खिलाफ जारी एक बेहद दृढ़तापूर्ण व उम्दा संघर्ष है। 52 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना को, जिसके बारे में 'सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश' कहकर ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा है, हर हाल में रोकने के मजबूत इरादों के साथ संघर्षरत ओड़िशा की जनता को भाकपा (माओवादी) लाल अभिनंदन पेश करती है और अपना पूरा समर्थन प्रकट करती है।

15 मई 2007 को केन्द्र सरकार ने पोस्को परियोजना को आनन–फानन में अनुमति मंजूर की। इसके खिलाफ जनता की ओर सें बड़े पैमाने पर सामने

आए विरोध को नजरअंदाज करते हुए मनमोहन ने खुद दक्षिण कोरिया सरकार को यह आश्वासन दिया कि उसकी सरकार इस परियोजना के निर्माण में पूरा सहयोग करेगी। वन अधिकार कानून के नियम–कायदों तथा 2009 में जारी वन और पर्यावरण मंत्रालय के मार्गदर्शक नियमों का ओड़िशा सरकार के साथ–साथ खुद उस मंत्रालय ने भी खुलेआम उल्लंघन किया। दरअसल 5 अगस्त 2010 को इस परियोजना को रोकने हेतु इस मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया, उसका यही आधार था। राज्य सरकार बार–बार इस बात से इनकार करती आ रही थी कि इस इलाके में आदिवासी निवासरत हैं। लेकिन सक्सेना कमेटी और मीना गुप्ता कमेटि ने अपनी तथ्यान्वेशण रिपोर्टों में इस बात के अकाट्य सबूत पेश किए थे कि प्रस्तावित इलाके में परम्परागत वननिवासी मौजूद हैं जो अपने जीवन यापन के लिए परम्परागत रूप से जंगलों पर ही निर्भर हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्टों में यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार मौजूदा वन अधिकारों पर अमल नहीं कर रही है। धिंकिया और गोविंदपुर गांवों के 65 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अपनी पल्ली सभाओं (ग्रामसभाओं) में यह मत प्रकट करते हुए प्रस्ताव किया कि वे किसी भी प्रकार के जमीन–अधिग्रहण के खिलाफ हैं। लेकिन राज्य सरकार ने बेशर्मी के साथ इन तथ्यों पर परदा डालकर वन और पर्यावरण मंत्रालय को दी गई अपनी रिपोर्ट में झूठ बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव ही गलत थे। इस तरह के कई सबूत हैं जिसमें कि राज्य सरकार ने झूठों का सहारा लेकर सच्चाइयों और आंकड़ों को तोड़–मरोड़कर पेश किया हो। मीना गुप्ता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वन सलाहकार कमेटी ने वन अनुमति को वापस लेने की सिफारिश की। लेकिन इन सबका उल्लंघन करते हुए 2 मई को जयराम रमेश ने इस परियोजना को पर्यावरणीय अनुमति दे डाली। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए जून महीने में पुलिस बलों को उतार दिया है।

इस पूरे दौर में जनता ने इस 12 मिलियन टन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र के निर्माण के खिलाफ, सुंदरगढ़ जिले में इस कम्पनी के लिए प्रस्तावित लोहा खदान के खिलाफ और परादीप बंदरगाह से 12 कि.मी. दूर पर व प्रस्तावित स्टील कारखाने के नजदीक पोस्को द्वारा प्रस्तावित निजी बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ संघर्ष का परचम बुलंद कर जमीन–अधिग्रहण की हर कोशिश का विरोध किया है। सच्चाई यह है कि केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ने इस साजिश को अंजाम दिया। जयराम रमेश ने यह कहकर कि 'पर्यावरण सम्बन्ध

ाी अनुमति देने का यह मतलब नहीं है कि जमीन का बलपूर्वक अधिग्रहण किया जाए' शिगूफा जो छोड़ा है और इस जन आंदोलन के समर्थन के नाम पर कांग्रेसियों के गोविंदपुर की ओर निकल पड़ना महज धोखा है। जयराम रमेश ओड़िशा सरकार को यह हिदायत दे रहा है कि जमीनों का अधिग्रहण 'लोकतांत्रिक तरीके' से किया जाए! हो सकता है कि उसके मार्के के 'लेकतंत्र' में झूठ बोलना और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से दलालखोरी करना भी शामिल हों! लेकिन इस तरह की परियोजनाओं का विरोध करने वाली जनता को (जिसमें आदिवासियों की बहुसंख्या है) जिस 'लोकतंत्र' का स्वाद चखाया जाता है उसमें सिर्फ फर्जी मुठभेड़ें, यातनाएं और बिना किसी सुनवाई के सालों साल जेलों में बंद करना शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि योजना आयोग के वेबसाइट में जाकर लोगों को वहां लगी तस्वीरों को देखना चाहिए कि पिछड़े इलाकों (खासकर 'माओवादी' इलाकों) में सड़कों, आंगनवाड़ी और शाला भवनों के निर्माण के साथ 'विकास' कितनी तेजी से हो रहा है। उसने यह भी जोड़ा है कि 'तस्वीरें अपने आप सच्चाई को बयां करती हैं'। क्या जी.के. पिल्लई गिरोह ने उन तस्वीरों को देखा है जिसमें बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को एक के पीछे एक घेरा बनाकर कतारों में लेटे हुए देखा जा सकता है जो अपनी जमीनों को नवीन पटनायक के 'लाइसेंसी हत्यारों' के दमनपूर्वक सहयोग से बहुराष्ट्रीय दैत्य द्वारा हड़पने की कोशिशों को रोक रहे थे? क्या वे तस्वीरें किसी सच्चाई को बयां कर रही हैं?

आखिर हजारों आंदोलनकारी पोस्को के प्रवेश को रोकने के लिए क्यों अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं? जब भी दलाल शासकों ने नव उपनिवेशवादियों के हाथों देश की सम्पदाएं बेचने की कोशिश की, तो सरकारी नीतियों के खिलाफ लड़ने वालों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ये आंकड़े किसी सच्चाई को बयां कर रहे हैं?

सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़, नारायणपटना, भट्टा–परसौल, श्रीकाकुलम, बस्तर और लोहरदग्गा में ही नहीं, बल्कि देश के हर राज्य में, हर गांव में और कस्बे में क्यों इतने सारे जन आंदोलनों का अनवरत सिलसिला चल पड़ा है जिसमें जनता की व्यापक भागीदारी है? हाल के दिनों में भड़क रहे इन जन आंदोलनों की लम्बी फेहरिश्त क्या किसी सच्चाई को बयां कर रही है?

सिंगूर की तपसि मलिक से लेकर जैतापुर में तबरेज़ तक और कलिंगनगर के 13 आदिवासियों से लेकर सोम्पेटा, काकरापल्ली के किसानों तक ऐसे आंदोलनों में जान गंवाने वाले जन नेताओं और आंदोलनकारियों की कुरबानियां तथा उनकी अंतिमयात्राओं में हजारों लोगों के हजूम का निकल पड़ना क्या किसी सच्चाई को बयां कर रहे हैं? धराशायी हुए इन शहीदों का स्थान खामोशी से पर दृढ़तापूर्वक पूरा करते हुए, 'जल–जंगल–जमीन हमारा है' का नारा बुलंद करते हुए क्यों हजारों लोग संघर्ष के कतारों में भर्ती होने लगे हैं?

उन लोगों के लिए संदेश साफ है जो सुनना चाहते हैं। देश का अत्यधिक बहुमत मुनाफा–केन्द्रित व साम्राज्यवाद–परस्त विकास के नमूने को ठुकराकर विकास के उस नमूने को अपना रहा है जो जन–केन्द्रित और जन–अनुकूल हो। शासक वर्गों की ओर से भी संदेश साफ है। जनता को और देश को चाहे जितना भी नुकसान हो, साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में और उनके पूरे सहयोग से दलाल शासक अपनी लूटखसोट और शोषण को जारी ही रखेंगे। यह 'नुकसान' न सिर्फ 'भौतिक रूप से' जमीन, पानी, हवा, समुद्र, बंदरगाह, प्राकृतिक संसाधन, जंगल, पर्यावरण, दुर्लभ वृक्ष, वन्यप्राणी, प्राचीन सभ्यताएं, सम्पत्तियां, शरीर के अंग और प्राणों को गंवाने के रूप में रहेगा, बल्कि आत्मसम्मान, संप्रभुता, आजादी, स्वाधीनता, अभिमान आदि मूल्यों को खोने के रूप में भी रहेगा जो हमें खुद को इंसान के रूप में पहचानने के लिए बेहद जरूरी हैं।

जगतसिंहपुर की जनता एक सीधा–सादा सवाल पूछ रही है – हम इन सबको क्यों गंवाएं? दरअसल वो कौन होते हैं जो यह तय कर रहे हैं कि हम इन सबको गंवा दें? वो एक सच्चाई को बयां कर रहे हैं जिसकी जानकारी सभी को जरूर होनी चाहिए – हमें क्या चाहिए इसे तय करने का अधिकार हम जनता को ही होगा। वो शासक वर्गों को सीधी चुनौती दे रहे हैं – जनता के गुस्से का मुकाबला करने तैयार हो जाएं क्योंकि हम घुटने टेकना नहीं चाहेंगे। वो एक नियमबद्ध तथ्य की घोषणा कर रहे हैं – भारत की जनता गुलामों सी जिंदगी में धकेले जाने का विरोध कर रही है।

दरअसल तस्वीरें भी कई बार सच्चाई को बयां नहीं कर सकतीं! मसलन, 'माओवादी इलाकों' में निर्मित शाला भवनों की तस्वीरें यह सच बयां नहीं करेंगी कि उनका निर्माण पूरा होते ही उन पर कब्जा करने के लिए सरकारी

सशस्त्र बल ताक में बैठे हुए हैं। लेकिन सालों से, लाखों लोगों का अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आंदोलन करना एक सच को जरूर बयां करता है। एक ऐसा सच जिसे फिलहाल हमारे देश में दूसरे किसी भी सच से ज्यादा बोलने और सुनने की जरूरत है। एक ऐसा सच जोकि हमारे देश का भविष्य तय करने वाला है। इसी सच को 19वीं और 20वीं सदियों में ब्रितानी उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़े गए अनगिनत किसानों और आदिवासियों की बगावतों और संघर्षों (जिनमें ज्यादातर सशस्त्र थे) ने भी बयां किया था। एक ऐसा सच जो सभी किस्म के उपनिवेशी व नव उपनिवेशी शोषण व उत्पीड़न को खत्म कर देना चाहता है। अंग्रेजों ने इस सच को न देखने और न सुनने के लिए अपनी आंखें और कान बंद कर रखे थे और पाशविक बल के सहारे उसका दमन करना चाहा था। भारत के वर्तमान शासक वर्ग भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। अगर वे 'जनता पर अपने अन्यायपूर्ण युद्धों' को इसी तरह जारी रखेंगे तो यह रास्ता उन्हें भी कब्रगाह में ही ले जाएगा जैसाकि उनके साम्राज्यवादी आकाओं के साथ हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से माओवादी इलाकों में पुलिस व अर्धसैनिक बलों को (अब सेना को भी) उतारना, या एक भट्टा–परसौल में या फिर एक गोविंदपुर में पुलिस व अर्धसैनिक बलों को उतारना – इन सबका मकसद न्यायपूर्ण जन संघर्षों को कुचलना ही है। दिसम्बर 2010 से लेकर अभी तक नवीन पटनायक सरकार द्वारा 25 से ज्यादा खदान–विरोधी कार्यकर्ताओं की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या करना और ओड़िशा व छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित माओवाद–विरोधी दमनकारी कार्रवाइयों को लेकर नवीन पटनायक व रमनसिंह के साथ पी. चिदम्बरम की बैठक इस बात को दर्शाते हैं कि केन्द्र व राज्य सरकारें जन आंदोलनों का किस तरह दमन करना चाहती हैं।

जबरिया जमीन अधिग्रहण और देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूटखसोट के खिलाफ जारी कई अन्य संघर्षों के साथ–साथ पोस्को–विरोधी आंदोलन यह फैसला कर सकने की क्षमता रखता है कि देश में निर्बाध रूप से आ रहे तमाम दूसरे विदेशी पूंजीनिवेशों का भविष्य क्या रहेगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी ओड़िशा की जनता को अपने संघर्ष में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है और समूचे देशवासियों का यह आह्वान करता है कि वे इस बहादुर जनता के समर्थन में संघर्षों का निर्माण करें। जगतसिंहपुर की जनता को चाहिए कि वह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों

और नागरिक समाजों से उसको मिल रहे समर्थन को स्वीकारते हुए ही तमाम संभावित साजिशों व षड़यंत्रों के प्रति सावधान रहे क्योंकि उनमें से कुछ, खासकर संसदीय राजनीतिक पार्टियां इस संघर्ष को गुमराह कर सकती हैं। इस बात को नहीं भुलाना चाहिए कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां उन जगहों पर जहां वे सत्ता में होती हैं या सत्ता में भागीदारी लेती हैं, इसी प्रकार की साम्राज्यवाद–परस्त नीतियों पर अमल कर रही हैं। जब वे विपक्ष में होती हैं तब भी वे इन नीतियों को परोक्ष समर्थन कर रही हैं।

जगतसिंहपुर जाकर पोस्को–विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के अलावा जहां–तहां हर राज्य में उनके समर्थन में प्रचार व आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों को अपनाने की जरूरत है। भारत की जनता और विश्व जनता से भाकपा (माओवादी) की अपील है कि वे इस बहादुराना जन संघर्ष के प्रति व्यापक समर्थन प्रकट करें। आज फौरी जरूरत इस बात की है कि ऐसे तमाम संघर्षों के बीच एक व्यापक आधार पर एकजुटता कायम कर न सिर्फ पोस्को जैसी परियोजनाओं को रद्द करने की मांग से बल्कि पूरे देश से सभी किस्म के साम्राज्यवादी शोषण, नियंत्रण और उत्पीड़न का अंत करने के लक्ष्य से लड़ने वाले सांझा मंच खड़ा किया जाए।

- ★ पोस्को के लिए जारी जमीन अधिग्रहण को तत्काल रोक दिया जाए!
- ★ जगतसिंहपुर जिले से पुलिस व अर्धसैनिक बलों को तत्काल वापस बुलाया जाए! जनता पर दबाव बनाने वाले हर किस्म के हथकण्डों को रोका जाए!
- ★ देश की प्राकृतिक सम्पदाओं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ जनता का जायज हक है, की लूटखसोट की खुली छूट देकर देश को बेच डालने हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ किए गए तमाम एमओयू रद्द किया जाए!

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

24-6-2011

jk"Vªifr }kjk j[kk x;k 'kkfr okrkZ dk iLrko turk dks xqejkg djus dk ,d vkSj gFkd.Mk!

अपने रायपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल ने आज, यानी 24 जून 2011 को हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि 'माओवादी हिंसा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आएं और मुख्य धारा से जुड़ जाएं ताकि आदिवासियों के विकास में शामिल हुआ जा सके'। राष्ट्रपति का प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जबकि भारतीय सेना के करीब एक हजार जवान बस्तर क्षेत्र के तीन जिलों में अपना पड़ाव डाल चुके हैं ताकि देश की निर्धनतम जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध – ऑपरेशन ग्रीन हंट में शिरकत कर सकें। वे ऐसे वक्त 'वार्ता' की बात कह रही हैं जबकि खनिज सम्पदा से भरपूर देश के कई इलाकों से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बाबत् सरकारों और कार्पोरेट कम्पनियों के बीच वार्ता के कई दौर पूरे हो चुके हैं और लाखों करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए जा चुके हैं। वे 'वार्ता' की बात तब कह रही हैं जबकि बस्तर क्षेत्र में 750 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र, जिसके दायरे में दर्जनों गांव और हजारों माड़िया आदिवासी आते हैं, सेना के हवाले करने का फैसला बिना किसी वार्ता के ही लिया जा चुका है।

देश की ये सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति हमें ऐसे समय हिंसा छोड़ने की हिदायत दे रही हैं जबकि इसी छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित ताड़िमेट्ला, मोरपल्ली, पुलानपाड़ और तिम्मापुरम गांवों में सरकारी सशस्त्र बलों के हाथों बलात्कार और मारपीट की शिकार महिलाओं के शरीर पर हुए जख्म भरे ही नहीं। वे ऐसे समय हमें हिंसा त्यागने की बात कह रही हैं जबकि न सिर्फ इन गांवों में, बल्कि दण्डकारण्य, बिहार–झारखण्ड, ओड़िशा, महाराष्ट्र, आदि कई प्रदेशों में, खासकर माओवादी संघर्ष वाले इलाकों या आदिवासी इलाकों में सरकारी हिंसा रोजमर्रा की सच्चाई बन गई है। दरअसल सरकारी हिंसा एक ऐसा बहुरूपिया है जो अलग–अलग समय में

विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जैसे कि अगर आज का ही उदाहरण लिया जाए, तो रातोंरात मिट्टी तेल पर 2 रुपए, डीज़ल पर 3 रुपए और रसोई गैस पर 50 रुपए का दाम बढ़ाकर गरीब व मध्यम तबकों की जनता की कमर तोड़ देने के रूप में भी होती है जो पहले से महंगाई की मार से कराह रही थी। लेकिन राष्ट्रपति को इस 'हिंसा' से कोई एतराज नहीं!

भारत की यह प्रथम नागरिक हमें उस 'मुख्यधारा' में लौटने को कह रही हैं जिसमें कि उस तथाकथित मुख्यधारा के 'महानायकों' – घोटालेबाज मंत्रियों, नेताओं, कार्पोरेट दैत्यों और उनके दलालों के खिलाफ दिल्ली से लेकर गांव–कस्बों के गली–कूचों तक जनता थूं–थूं कर रही है। वो ऐसी 'मुख्यधारा' में हमें बुला रही हैं जिसमें मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं आदि के लिए अन्याय, अत्याचार और अपमान के अलावा कुछ नहीं बचा है।

और श्रीमति प्रतिभा पाटिल हमें उस पृष्ठभूमि में वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही हैं जबकि ऐसी ही एक पेशकश पर हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया सरकार के सामने रखने वाले हमारी पार्टी के प्रवक्ता और पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड आजाद की हत्या इसी सरकार ने एक फर्जी झड़प में की थी। इत्तेफाक से उनकी शहादत की सालगिरह अब से ठीक एक हफ्ता बाद है जबकि साल भर पहले करीब–करीब इन्हीं दिनों में चिदम्बरम और उनका हत्यारा खुफिया–पुलिस गिरोह उनकी हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे। कॉमरेड आजाद ने वार्ता पर हमारी पार्टी के दृष्टिकोण को साफ तौर पर देश–दुनिया के सामने रखा था और उसका जवाब उनकी हत्या करके दिया था आपकी क्रूर राज्यसत्ता ने। और उसके बाद भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पकड़कर जेलों में कैद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। 60–70 साल पार कर चुके वयोवृद्ध माओवादी नेताओं को जेलों में न सिर्फ अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं, बल्कि उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर 10–10 या 15–15 राज्यों के झूठे केस लगाए जा रहे हैं ताकि ताउम्र उन्हें जेल की कालकोठरियों में बंद रखा जा सके।

इसलिए, देश की जनता से हमारा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि –

आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि 'शांति वार्ता' की पेशकश

करने से पहले उनकी सरकार जनता पर जारी युद्ध – ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद करे; बस्तर में सेना का 'प्रशिक्षण' बंद करे; और तमाम माओवाद–प्रभावित इलाकों से सेना व अर्धसैनिक बलों को वापस ले। अगर सरकार इसके लिए तैयार होती है तो दूसरे ही दिन से जनता की ओर से आत्मरक्षा में की जा रही जवाबी हिंसा थम जाएगी।

आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि 'विकास' की बात करने से पहले उनकी सरकार कार्पोरेट घरानों और सरकारों के बीच हुए तमाम एमओयू रद्द करे। बलपूर्वक जमीन अधिग्रहण की सारी परियोजनाओं को फौरन रोके; उनकी सरकार यह मान ले कि जनता को ही यह तय करने का अधिकार होगा कि उसे किस किस्म का 'विकास' चाहिए।

आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि 'मुख्यधारा' में जुड़ने की बात करने से पहले सरकार सभी घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को गिरफतार कर सजा दे। विदेशी बैंकों में मौजूद सारा काला धन वापस लाए। घोटालों और अवैध कमाई में लिप्त तमाम मंत्रियों और नेताओं को पदों से हटाकर सरेआम सजा दे।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

2-7-2011

vkfnoklh o nfyr lkLd'frd dk;ldrk o urk dkejM l thru ejk.Mh] vfuy jke] euk t jktoj vkj N=ifr e.My dk nh xbl Qklh dh ltkvk dk Qkju jí djk!

23 जून को झारखण्ड के गिरिडीह सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति इंद्रदेव मिश्र ने 2007 में छिलकारी में हुई 19 लोगों की हत्या के मामले में जीतन मराण्डी, अनिल राम, मनोज राजवर और छत्रपति मण्डल को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही राजसत्ता ने फिर एक बार अपने फासीवादी चरित्र का नंगा प्रदर्शन किया। जीतन मराण्डी और अन्य लोग हमेशा खुलेआम काम करते रहे और वे जिन संगठनों से जुड़े थे वे प्रतिबंधित भी नहीं थे। ऐसे लोगों को एक ऐसे मामले में जिसके साथ उनका कोई लेना–देना नहीं था, मौत की सजा सुनाने का साफ मतलब यह है कि यह एक बदले की कार्रवाई के तहत दी गई सजा थी क्योंकि वे अपने नाच–गानों के साथ साम्राज्यवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी, खासकर विस्थापन–विरोधी जन संघर्षों की मजबूती से पक्षधरता कर रहे थे। देश में माओवादी आंदोलन का, खासकर मध्य और पूर्वी भारत में, दमन करने की मंशा से शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत केन्द्र व राज्य सरकारें अत्यंत गरीब आदिवासियों पर बेहद घिनौने व पाशविक अत्याचार कर रही हैं। मौत की ये सजाएं इस बात का एक और सबूत है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के अत्यंत पाशविक स्वरूप छत्तीसगढ़, झारखण्ड व ओड़िशा के खासकर उन आदिवासी इलाकों में लागू किए जा रहे हैं जहां माओवादी आंदोलन मजबूत है।

जीतन मराण्डी एक जाने–माने आदिवासी सांस्कृतिक कलाकार हैं। वे सांस्कृतिक संगठन 'झारखण्ड अभेन' के नेता हैं और अखिल भारतीय क्रांतिकारी सांस्कृतिक संघ के भी नेता हैं। क्रांतिकारी गीतों और संस्कृति का

प्रचार करते हुए उन्होंने देश भर में दौरे किए। अनिल राम, मनोज राजवर और छत्रपति मण्डल भी आदिवासी व दलित सांस्कृतिक कलाकार हैं। जीतन ने बचपन से ही सांस्कृतिक मामलों में अपनी कुशलता का परिचय दिया था। ध ीरे–धीरे वे देश के अत्युत्तम कलाकारों में से एक बन गए। एक सचेतनशील किशोर के रूप में वे अपने आदिवासी समाज की हालत पर ध्यान दिए बिना रह नहीं सके। आदिवासियों में व्याप्त गरीबी, शोषण और उत्पीड़न की जड़ों को समझने के मकसद से किया गया सामाजिक अध्ययन उन्हें क्रांतिकारी राजनीति की तरफ लेकर गया। खुद वे और उनका सांस्कृतिक संगठन जनता की चेतना बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार करते हैं।

अपने विचारों का खुले तौर पर प्रचार करना अपराध नहीं है। इसके लिए किसी को भी दण्डित नहीं किया जा सकता। भारत के शासक वर्ग किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। जनता की प्राकृतिक सम्पदाओं और अपार खनिज सम्पदाओं की लूटखसोट को सुगम बनाने वाली साम्राज्यवाद–परस्त और जन विरोधी नीतियों के विरोध में उठने वाली हर आवज को दबाने के लिए वे हर प्रकार का हथकण्डा अपना रहे हैं। सच्चे जन कलाकारों के रूप में वे झारखण्ड में जारी विस्थापन–विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जहां से देश के शासक वर्गों द्वारा लागू विस्थापन की नीतियों के खिलाफ बेहद मजबूती से प्रतिरोध उठ रहा है। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि राजसत्ता उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए सजा दे रही है, न कि किसी छिलकारी केस के सिलसिले में। बिहार व झारखण्ड में हुए सामंतवाद–विरोधी संघर्षों के दौरान जमींदारों ने अपनी निजी सेनाओं के जरिए किसानों, खासकर दलितों के कत्लेआम किए थे। किसानों को अपनी आत्मरक्षा में जवाबी हिंसा का रास्ता अख्तियार करने पर बाध्य होना पड़ा। छिलकारी जैसी घटनाएं इसी सिलसिले का हिस्सा हैं। ऐसी घटनाओं की गहराई में जाकर कारणों का पता लगाने की बजाए राजसत्ता इस आड़ में जन संगठनों पर फर्जी मुकदमे दायर कर उनका गला घोंटने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने 2007 में जीतन मराण्डी पर रांची में राजभवन के सामने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के सवाल को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का एक मामला दायर किया था। तबसे उन्हें जेल में डालकर झूठे मामलों में फंसाते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके पहले भी उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ

कई बार बुरी तरह मारपीट की गई। आखिर में इन तमाम साजिशों की पराकाष्ठा के रूप में उन्हें मौत की सजा सुनाकर उनकी आवाज हमेशा के लिए दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में राजसत्ता की बेशर्मी का आलम यह है कि उन पर पीरटांड और तीसरी पुलिस थानों के ऐसे मामले भी दायर किए गए हैं जो दरअसल उस समय हुए थे जब वे जेल में बंद थे!

हमारा देश दो सौ सालों के लम्बे अरसे तक अंग्रेजों के उपनिवेशी शासन में रहा। फलस्वरूप यह कई आदिवासी विद्रोहों का गवाह भी रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आधुनिक हथियारों के सहारे पाशविक ताकत का प्रयोग कर इन विद्रोहों को कुचलने की कोशिश की। विद्रोहों के नायकों को फांसी देना उनका एक प्रचलित दमनात्मक दावपेंच था। उपनिवेशवादी शासकों की दमनकारी मशीनरी के वारिसों के रूप में भारत के दलाल शासक वर्ग उन्हीं के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। कॉमरेड्स भूमैया और किष्टागौड़ 'आजाद' भारत के पहले क्रांतिकारी किसान कार्यकर्ता थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। उसके बाद भी कई क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं, खासकर बिहार (जिसमें आज का झारखण्ड भी शामिल था) के क्रांतिकारी किसान कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर मौत की सजाएं सुनाई गईं। जन वकील और मानवाधिकार संगठनों के नेता के.जी. कन्नबीरन, पत्तिपाटी जैसे शख़्सों ने अपने संगठनों के जरिए अदालतों के अंदर और बाहर भी न सिर्फ मौत की सजाओं के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि मौत की सजा को ही पूरी तरह रद्द करने की मांग से व्यापक आंदोलनों का निर्माण किया। इस पृष्ठभूमि में कि राजसत्ता आदिवासी बस्तियों में आए दिन कत्लेआम, फर्जी मुठभेड़ और अत्याचारों को जारी रखते हुए ही फांसी की सजा जैसी फासीवादी कार्रवाइयों पर भी उतारू है, इस संघर्ष को और भी व्यापक आधार पर तेज करने की जरूरत है। नारायणपटना संघर्ष से जुड़े हुए नेता सिंगन्ना को पुलिस ने सीधे तौर पर गोली मार दी। लालगढ़ संघर्ष के लोकनायक लालमोहन टुडू की पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी। अब झारखण्ड में जीतन मराण्डी को फांसी की सजा सुनाई गई। सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ जारी जन आंदोलनों से उभर रहे नेताओं को कत्ल करने की साजिश के तहत ही यह सब हो रहा है। उनकी कोशिश यह है कि जन संघर्षों को नेतृत्वविहीन कर आदिवासी इलाकों से प्राकृतिक सम्पदाओं को बेरोकटोक लूटने के रास्ते में मौजूद तमाम बाधाओं को खत्म किया जाए।

जैसा कि फांसी की सजा सुनाने के तुरंत बाद जीतन के साथ–साथ अदालत में मौजूद जनता ने गीत गाकर सुनाया, 'वह सुबह कभी तो आएगी' जब राजसत्ता द्वारा लागू इन तमाम फासीवादी कार्रवाइयों को जन उभारों से खत्म किया जाएगा। जेलखाने और फांसी के तख़्त जनता के सच्चे नेताओं के क्रांतिकारी जज़्बे को खत्म नहीं कर सकेंगे। वे आखिर तक लड़ते रहेंगे।

भाकपा (माओवादी) यह मांग करती है कि जीतन मराण्डी, अनिल राम, मनोज राजवर और छत्रपति मण्डल को दी गई मौत की सजाओं को तुरंत रद्द किया जाए। हम सभी जनवादी, मानवाधिकार संगठनों, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए संघर्षरत संगठनों, खासकर कला व साहित्य से जुड़े संगठनों तथा आदिवासी सांस्कृतिक संगठनों से अपील करते हैं कि वे इन मौत की सजाओं को समाप्त करने, इन जन कलाकारों की रिहाई के लिए व्यापक आंदोलनों का निर्माण करें। मौत की सजा को पूरी तरह रद्द करने की मांग के साथ चलने वाले आंदोलन के रूप में इसे व्यापक आधार पर आगे बढ़ाएं।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

17-7-2011

eEcbl e g, chHkR l i.k ce geyk dh HkR l uk djk!

eDdk efLtn] ekyxko] le>krk ,Dl il ler ce foLQkV dh lHkh ?kVukvk dh fu"i{k vkj Lor= tkp djokdj nkf"k;k dk dMh l dMh ltk nu dh ekx djk!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मुम्बई में 13 जुलाई 2011 को हुए बम हमलों की तीव्र निंदा करती है। इन सिलसिलेवार विस्फोटों को, जिसमें लगभग 20 आम लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, हमारी पार्टी अमानवीय मानती है। किन लोगों ने इन बम विस्फोटों को अंजाम दिया होगा यह स्पष्ट होने से पहले ही और जांच की प्रक्रिया तक शुरू होने से पहले ही लुटेरे शासक वर्गों और उनके पुलिस/खुफिया संगठनों ने हमारी पार्टी पर षड़यंत्रकारी व बेबुनियाद ढंग से आरोप लगाए हैं कि इसमें माओवादी पार्टी का भी हाथ हो सकता है। इसका हमारी पार्टी पुरजोर खण्डन करती है। देश की उत्पीड़ित जनता को साफ तौर पर मालूम है कि शोषित जनता की मुक्ति के लिए लड़ने वाली हमारी पार्टी आम लोगों को निशाना बनाने और उनकी जान को जोखिम में डालने वाले हमले कभी नहीं करती। लुटेरे शासक वर्ग और उनके सुर में सुर मिलाने वाला कॉर्पोरेट मीडिया अपने बुरे मंसूबों के साथ हम पर जानबूझकर इसलिए झूठे आरोप मढ़ रहे हैं ताकि हमारी पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में तथा हमारे जायज जन आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन के रूप में चित्रित किया जा सके जिससे कि उनकी दमनकारी नीतियों तथा जनता पर जारी युद्ध – ऑपरेशन ग्रीन हंट के दूसरे चरण के तहत शुरू हुई सेना की तैनाती को वैधता हासिल की जा सके।

हमारे देश में अब तक हुए बम विस्फोटों का जायज़ा लिया जाए, तो ज्यादातर

घटनाओं में यह बात साफ हो ही नहीं पाई कि उनके असली दोषी कौन थे और दोषियों के रूप में दिखाए जा रहे लोगों के पीछे छिपे असली गुनाहगार कौन थे। यह रिवाज सा बना है कि विस्फोट की कोई भी घटना घटती है तो हिंदू धर्म की पक्षपाती भारतीय राज्यसत्ता और उसके खुफिया/जांच संस्थाएं व कार्पोरेट मीडिया तुरंत ही और बिना किसी आधार के मुसलमानों और तथाकथित इस्लामिक आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह के तमाम हमलों के लिए मुस्लिम समाज को गुनाहगार निरूपित करने हेतु भारतीय राज्यसत्ता और कांग्रेस, भाजपा जैसी शासक वर्गीय पार्टियों के नेताओं द्वारा रची गई साजिश के तहत आईबी ने खुद ही इंडियन मुजाहिद्दीन नामक एक छद्म संगठन खड़ा किया जिसे हाल में हुए हर बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार बताकर प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे आरोपों की सत्यता को लेकर प्रश्न उठाने वालों और उन पर समग्र व निष्पक्ष जांच की मांग करने वालों पर एकायक देशद्रोही का ठप्पा लगाकर कार्पोरेट मीडिया के सम्राट और शासक वर्गों के तलवे चाटने वाले बुद्धिजीवी उन पर बेतुके, आवेशपूर्ण और आक्रामक ढंग से टूट पड़ रहे हैं। इससे बहुसंख्यक जनता को यह जानने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि सच्चाई क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले हमारे देश में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि सच्चाइयों का पता लगाने की मांग नहीं करना देशभक्ति की और करना देशद्रोह की कसौटी बन गई है!

विगत में हुए मक्का मस्जिद, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस आदि बम विस्फोट के मामलों में पुलिस ने सैकड़ों निर्दोष मुसलमानों, खासकर नौजवानों को गिरफ्तार कर, अमानवीय यातनाएं देकर जेलों में बंद कर दिया। कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला। बाद में यह सबूत मिलने के बावजूद भी कि संघ गिरोह (आरएसएस) से जुड़े हिंदू कट्टरवादी संगठनों ने इन जघन्य करतूतों को अंजाम दिया था, पीड़ित मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। अभिनव भारत, हिंदू डिफेंस फोर्स, राष्ट्रीय जागरण मंच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि हिंदू आतंकी संगठनों के एक भी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर संसद पर हमले के मामले में अफ्जल गुरू को, गोधरा रेल जलाने के मामले में 11 मुसलमानों को पिछले 1 मार्च को सुनाई गई फांसी की सजाएं राज्यसत्ता की मुस्लिम विरोधिता और हिंदू कट्टरवाद की पक्षधरता को समझने के लिए चंद उदाहरण भर हैं। जब दो हजार से ज्यादा मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जैसे हत्यारे सीना तानकर घूम रहे हों, वहीं बेतुके और आधे–अधूरे सबूतों से मुसलमानों

को सजाएं सुनाकर राज्यसत्ता ने मुसलमानों को बेहद नाराज और आक्रोशित किया।

एक सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज, खासकर नौजवानों का एक बड़ा तबका बाबरी मस्जिद की तबाही, गुजरात नरसंहार आदि के चलते भारत के शासक वर्गों से बेहद असंतुष्ट है। एक और अकाट्य सच्चाई यह है कि इस असंतोष ने कुछ इस्लामिक संगठनों को पैदा किया। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर, इस तरह के संगठनों को अपने प्रभाव में लेकर या फिर उन्हें षड़यंत्रकारी ढंग से गुमराह कर, कुछ नए संगठनों को पैदा कर दोनों भारत और पाकिस्तान की आरएडब्ल्यू (रॉ), आईबी, आईएसआई जैसी संस्थाएं अपने स्वार्थ राजनीतिक हितों के मद्देनजर दोनों ही देशों में इस तरह के बम विस्फोट और हमले करवा रही हैं। कई असंतुष्ट और आक्रोशित मुस्लिम नौजवान इस जाल में फंसकर, यह नहीं समझते हुए कि उनके असल दुश्मन कौन हैं, इस तरह की अविवेकपूर्ण हिंसात्मक कार्रवाइयों में शिरकत कर रहे हैं। और आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। यह इस तरह का जहरीला दुष्चक्र है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन लोग परदे के पीछे से उन्हें चला रहे हैं और इस किस्म के हमलों से किन वर्गों के हित पूरे हो रहे हैं।

दूसरी ओर, इस बात के ठोस सबूत मिलने के बाद कि मक्का मस्जिद, मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस विस्फोटों के लिए 'अभिनव भारत' नामक संघ गिरोह (आरएसएस) से जुड़ा संगठन जिम्मेदार है, देश की जनता ने भगवा आतंकवाद को एक खतरनाक रुझान के रूप में पहचानना शुरू किया। बाद में जब यह पता चला कि अजमेर शेरीफ में हुए बम विस्फोट के लिए भी भगवा आतंकी ही जिम्मेदार हैं, यह मांग उभरकर आई कि देश में विभिन्न जगहों पर हुए तमम बम विस्फोटों की घटनाओं पर हुई जांचों की समीक्षा की जाए। पुलिस अत्याचारों से पीड़ित मालेगांव और हैदराबाद के मुसलमान नौजवानों ने यह मांग की सरकार उनसे माफी मांग ले। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ऊपर से चाहे कुछ भी कहे, अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों के मद्देनजर भगवा आतंकवाद को शह देते हुए इन मांगों को अनसुना करती आ रही है। आम तौर पर हिंदू धार्मिक कट्टरवाद का समर्थन करने वाला कॉर्पोरेट मीडिया जहां एक तरफ बिना किसी सबूत के ही मुसलमानों और इस्लामिक संगठनों पर आक्रामक ढंग से टूट पड़ता है, वहीं दूसरी ओर बम विस्फोट की विभिन्न घटनाओं में भगवा आतंकी संगठनों का हाथ होने का साफ सबूत मिल जाने के बावजूद भी वह या तो उस पर कम से कम रिपोर्टिंग करता है या फिर दबा देता है।

इस पृष्ठभूमि में, 13 जुलाई के मुम्बई बम विस्फोटों के लिए दक्षिणपंथी भगवा

आतंकी संगठन या फिर आईबी, रॉ जैसी खुफिया संस्थाओं द्वारा प्रायोजित तथाकथित इस्लामिक मिलिटेंट संगठन जिम्मेदार होने की संभवना ज्यादा है। या फिर पुलिस अधिकारियों और शासक वर्गीय राजनेताओं से सांठगांठ करने वाले माफिया गिरोह भी इन हमलों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन हमलों को चाहे किसी ने भी अंजाम दिया हो, इस तरह की अविवेकपूर्ण हिंसात्मक कार्रवाइयों का फायदा शासक वर्गों को ही मिलेगा। पहला, वर्तमान में ज्वलंत समस्याओं के रूप में मौजूद महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, काला धन, स्विस बैंक खाते आदि से जनता का ध्यान बंटाना। दूसरा, आतंकवाद को बहुत बड़े खतरे के रूप में दिखाकर और ज्यादा क्रूरतापूर्ण कानूनों को तैयार करना तथा लाखों करोड़ का जन धन का दुरुपयोग करते हुए साम्राज्यवादी देशों से बड़े पैमाने पर हथियार और तकनीक की खरीद कर दमनकारी मशीनरी के दांतों को और ज्यादा धारदार बनाना। तीसरा, 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के नाम पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा छेड़े गए दुराक्रमणकारी युद्धों, हमलों और धौंस का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करते हुए दक्षिण एशिया में उसके कनिष्ठ भागीदार की भूमिका निभा रहे भारतीय राज्य का होमलैण्ड सेक्यूरिटी, नागरिक परमाणु समझौता आदि देशद्रोहपूर्ण समझौतों से देश को साम्राज्यवाद के आगे पूरी बेशर्मी से घुटने टेक देना। चौथा, सरकारों द्वारा लागू जन विरोधी और साम्राज्यवादपरस्त नव उदार नीतियों के खिलाफ सुलग रहे जन आंदोलनों और बढ़ते माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन का सैनिक रूप से दमन करने के पक्ष में आतंकवाद का डर दिखाकर जनमत को तैयार कर लेना। और सबूतों के बिना ही हर बार इस तरह के विस्फोटों के लिए मुसलमानों और इस्लामिक संगठनों को जिम्मेदार बताकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत बनाना तथा रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, विस्थापन जैसी बुनियादी समस्याओं से देश की जनता का ध्यान बंटाकर अपने शोषणकारी शासन को बेरोकटोक जारी रखना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए तथा सामंती व दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गों के लिए, जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, जरूरी है।

इसलिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) यह मानती है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही यह पता लगाना संभव है कि मुम्बई विस्फोटों के लिए जिम्मेदार कौन हैं। हमारी पार्टी देश की जनता और जनवादियों से यह अपील करती है कि वे शासक वर्गों, उनके खुफिया संगठनों और कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा जारी उन्मादपूर्ण प्रचार, गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों का शिकार न बनें। हमारी पार्टी मांग करती है कि इन विस्फोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ़ निकालकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही, हमारी पार्टी देशवासियों का यह आह्वान करती है कि वे सरकारों से यह मांग करें कि 1992 से लेकर अभी तक हुए बम

विस्फोट की तमाम घटनाओं पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए तथा जेलों में बंद मुसलमानों और ईसाइयों को बिना शर्त रिहा किया जाए। देश की तमाम जनता से हमारा आग्रह है कि वह बाबरी मस्जिद का विध्वंस, गुजरात नरसंहार, कंधमाल (ओड़िशा) हमलों समेत देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकी सरगनाओं को कड़ी सजा देने की मांग करे तथा हिंदू धार्मिक कट्टरवाद और सभी किस्म के धार्मिक अधराष्ट्रवाद का खण्डन करे।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

19-8-2011

ekvkoknh urRo d f[kykQ yVj 'kkld oxk vkj dkikjV ehfM;k }kjk pyk, tk jg tgjhy n"ipkj dk jíh d Vkdj e Qd nk!

आज भारत का क्रांतिकारी आंदोलन कठिन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जीत–हार–जीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस क्रांतिकारी आंदोलन को जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से लुटेरे शासक वर्ग साम्राज्यवादियों के सम्पूर्ण समर्थन से बर्बर दमनकारी युद्ध चला रहे हैं। ये फासीवादी खासकर उस एलआईसी (कम तीव्रता वाला संघर्ष) की रणनीति पर अमल करते हुए प्रति–क्रांतिकारी युद्ध को चला रहे हैं जिसे अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने तैयार किया। खासकर 2009 से यूपीए सरकार ने राज्य सरकारों के साथ तालमेल कर 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से देशव्यापी दमनकारी युद्ध छेड़ रखा है। सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम–प्रणब मुखर्जी गिरोह की अगुवाई में देश की जनता के खिलाफ जारी इस अन्यायपूर्ण युद्ध में 'दमन और विकास' (जनता का दमन और कॉर्पोरेट कम्पनियों का विकास समझना चाहिए) को रणनीति के रूप में बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत, मनोवैज्ञानिक युद्ध को एक रणनीतिक हथियार के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका अहम हिस्सा है क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व के खिलाफ दुष्प्रचार। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में मीडिया को एक मुख्य साधन के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्पोरेट वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले मीडिया के प्रतिनिधि और शोषक वर्गों की विचारधारा का समर्थन करने वाले छद्म बुद्धिजीवी माओवादी आंदोलन पर कीचड़ उछालने वाली इस मुहिम को जारी रखते हुए दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध में बढ़–चढ़कर भाग ले रहे हैं।

क्रांतिकारी आंदोलन का जितना लम्बा इतिहास है क्रांति–विरोधी दुष्प्रचार

का भी उतना ही इतिहास है। जर्मनी के फासीवादी प्रचार मंत्री गोबेल्स, जिसने यह बताया था कि एक झूठ को सौ बार दोहराने से वह सच होकर रहेगा, के असली भारतीय अवतार के रूप में सामने आए हुए सोनिया, मनमोहनसिंह, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, रमन सिंह, नवीन पटनायक, नितीश कुमार, किरण कुमार आदि शासक तथा अरणाब गोस्वामी, चंदन मित्रा जैसे उनके प्रवक्ता मीडिया के जरिए विभिन्न रूपों में दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। क्रांतिकारी सिद्धांत मार्क्सवाद के अप्रासंगिक होने से शुरू कर माओवादी नेताओं के बीच तीव्र मतभेद होने के प्रचार तक कोरी कल्पनाओं, झूठों और अर्धसत्यों से क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व व नेतृत्वकारी संस्थाओं के खिलाफ आए दिन खबरें प्रकाशित व प्रसारित कर रहे हैं। क्रांतिकारी सिद्धांत पर, क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली हमारी पार्टी पर तथा पार्टी नेतृत्व पर गलतफहमियां, संदेह और भ्रम पैदा कर जनता और क्रांतिकारी कतारों को दिग्भ्रमित करना तथा निराशा और अविश्वास फैलाना ही इस दुष्प्रचार मुहिम का एक मात्र लक्ष्य है। लुटेरे शासक और उनका ढिंढ़ोरा पीटने वाले छद्म बुद्धिजीवी यह सपना देख रहे हैं कि इस तरह जनता को भ्रमित कर वे अपना शोषणकारी शासन बेरोकटोक जारी रख सकेंगे और साम्राज्यवाद–परस्त आर्थिक नीतियों को बिना किसी विरोध के लागू कर सकेंगे। इस श्रेणी में आने वाले कुछ पत्रकार खुफिया अधिकारियों से सांठगांठ कर कार्पोरेट मीडिया संस्थाओं के जरिए माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन पर कीचड़ उछालते हुए घटिया किस्त की रद्दी को प्रचारित व प्रसारित कर रहे हैं। इसी का हिस्सा है 17 जुलाई 2011 को अंग्रेजी अखबार 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'बिट्टर डिफरेन्सेस क्राप अप बिट्वीन माओइस्ट्स पीडब्ल्यू एण्ड एमसीसी फैक्शन्स' के शीर्षक से छपी घटिया व मनगढ़ंत कहानी।

देश की खुफिया संस्थाओं द्वारा तैयार और राखी चक्रबर्ती द्वारा लिखी गई इस कपोलकल्पित कहानी के अंदर न सिर्फ माओवादी पार्टी के नेतृत्व को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया, बल्कि पार्टी में पीडब्ल्यू और एमसीसी गुटों को कृत्रिम तरीके से पैदा कर उनके बीच तीखे मतभेद होने की बात लिखी गई है। देश की उत्पीड़ित जनता और दुनिया भर के क्रांतिकारी कतारों की चिर–प्रतीक्षित आकांक्षाओं के फलस्वरूप, कई समृद्ध अनुभवों के आधार

पर तथा 'काला अध्याय' के रूप में चिन्हित किए गए एक पीड़ादायक दौर को पार करके दो क्रांतिकारी पार्टियों के बीच जो एकता निर्मित हुई है वह हमारे देश के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक महान व उज्ज्वल अध्याय है। सिर्फ सच्चे और निस्वार्थपूर्ण क्रांतिकारी ही इस तरह अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर जनता से माफी मांग सकते हैं और उनकी पुनरावृत्ति न हो, उस दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए इस सच्ची एकता से देश व दुनिया भर में उत्पीड़ित जन समुदाय व क्रांतिकारी कतार जितने उत्साहित हुए थे, उतने ही घबरा गए थे भारत के लुटेरे शासक वर्ग और उनके साम्राज्यवादी आका। गौरतलब है कि साम्राज्यवादियों का नमकहलाल गुलाम और देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस ऐतिहासिक एकता की पृष्ठभूमि में ही माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताना शुरू किया। यह भी एक अकाट्य सच्चाई है कि इस एकता के बाद से ही देश के शासक गिरोह ने क्रांतिकारी आंदोलन पर अपने फासीवादी हमले को अंधाधुंध बढ़ाया।

शोषक शासक वर्गों की यह बहुत पुरानी चाल है कि क्रांतिकारी पार्टियों के उच्च नेताओं के बीच मनगढ़ंत मतभेद पैदा किया जाए ताकि जनता को यह झूठा एहसास दिलाया जा सके कि क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं में व्याप्त इस तरह के केरीरिज़्म और आपसी अंतरविरोधों के चलते ये पार्टियां भी उसे ठीक से नेतृत्व नहीं दे सकेंगी। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जिनमें से एक है 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपी यह खबर जो दशकों से निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा कर रहे हमारे नेताओं के खिलाफ चलाए गए बेहद जहरीला दुष्प्रचार मुहिमों में से एक है। उन नेताओं में से कुछ फिलहाल जेलों में कैद हैं जिन्हें सभी सुविधाओं से वंचित कर, बूढ़ी उम्र में भी उन्हें इलाज की सुविधाएं न देते हुए राजसत्ता अपनी अमानवीयता का खुला प्रदर्शन कर रही है। शोषित जनता की मुक्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले हमारे नेताओं के प्रति राजसत्ता जो दमनकारी रवैया अपना रही है वह आए दिन अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ रहा है। एक प्रकार से कहा जाए, तो इससे यह साबित होता है कि क्रांतिकारी राजनीति के बढ़ते प्रभाव को लेकर राजसत्ता कितनी आतंकित है और इसे घटाने के लिए वह किस तरह

बेकार की चालें चल रही है। हमारे नेतृत्व पर लगाए जा रहे इन तमाम आरोपों को हमारी पार्टी सिरे से खारिज कर देती है और शोषित जनता व क्रांतिकारी शिविर से अपील करती है कि इसमें से एक शब्द पर भी यकीन न करें।

सभी सच्ची क्रांतिकारी पार्टियों में मत भिन्नताएं होती हैं। उनके सदस्यों में सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांगठनिक, सैनिक, सांस्कृतिक आदि मामलों को लेकर भिन्न–भिन्न मत रहते हैं। विभिन्न विचारों को लेकर बहसें होती हैं। उन पर हर सदस्य द्वारा अपना मत प्रकट करने के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। क्रांतिकारी पार्टियों के भीतर लागू इस जनवादी प्रक्रिया को शासक वर्गीय पार्टियों के अंदर न हम कभी देख पाएंगे, न ही वे इसे समझ पाएंगी। इस तरह की बहसों और आलोचना–आत्मालोचना के दौर से गुजरते हुए ही एक क्रांतिकारी पार्टी अपने क्रांतिकारी तत्व को बनाए रख सकती है, न कि किसी नेता का अंधानुसरण करते हुए जैसा कि बुर्जुवाई पार्टियों में होता है। वर्ग संघर्ष के शोलों में तपकर और आलोचना–आत्मालोचना के कई सत्रों में भाग लेकर ही क्रांतिकारी खुद को फौलाद बना लेते हैं। खुफिया संस्थाएं पार्टी के भीतर मौजूद ऐसे स्वस्थ माहौल को तोड़–मरोड़कर उसके ठीक विपरीत में चित्रित करने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के भीतर, वह भी पीडब्ल्यू और एमसीसी गुटों के बीच तीखे मतभेद होने का प्रचार कर रही हैं ताकि जनता और कतारों को भ्रम में डाला जा सके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी देश और दुनिया की जनता, जनवादियों और क्रांतिकारी कतारों से अपील करती है कि वे इस दुष्प्रचार का पुरजोर खण्डन करें; राजसत्ता द्वारा चली जा रही चालों के प्रति सतर्क रहें; तथा इस दुष्प्रचार को कूड़े के ढेर में फेंककर क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन में दृढ़तापूर्वक डटे रहें।

आखिर में, हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड गणपति ने पिछले साल अक्टूबर में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में पीडब्ल्यू और एमसीसी के कथित गुटों के बीच मौजूद कथित मतभेदों पर हो रहे दुष्प्रचार पर टिप्पणी करते हुए जो बात कही थी, उसे इस संदर्भ में भी पेश करना मुनासिब समझते हुए हमारी केन्द्रीय कमेटी इसे फिर एक बार दोहरा रही है।

”...पार्टी में सही विचारों और गलत विचारों के बीच संघर्ष हमेशा रहता है।

हम जनवादी केन्द्रीयता और मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की रोशनी में अपने मतभेदों को हल कर लेते हैं। इसी से हमारी पार्टी के विकास का रास्ता सुगम हो जाता है। विलय के साथ हमने महान एकता हासिल की। अब हमारी पार्टी में चाहे जो भी बहसें हो जाएं और वैचारिक संघर्ष हो जाएं, वे एक एकताबद्ध पार्टी के भीतर होने वाली राजनीतिक व सैद्धांतिक बहसों के रूप में ही होंगे, पुरानी सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) और पुरानी एमसीसीआई के बीच मतभेदों के रूप में कतई नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि विलय के पहले वाली झड़प की स्थिति तो कभी नहीं आ सकती।"

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

30-9-2011

i'Fkd rsyaxkuk jkT; dk QkSju xBu djuk pkfg,!

rsyaxkukokfl;ksa dh ^ldy tu gM+rky* ds leFkZu esa

11 vDVwcj 2011 dks ^Hkkjr can* lQy cukvks!

पृथक तेलंगाना राज्य को लेकर तेलंगाना के लोगों में जनवादी आकांक्षा अभूतपूर्व ढंग से उमड़ रही है। तेलंगाना की जनता में जबर्दस्त एकता देखी जा रही है। सरकारी कर्मचारी, सिंगरेनी कोयला खदानों के मजदूर, राज्य परिवहन निगम व बिजली विभाग के मजदूर व कर्मचारी, छात्र, वकील, अध्यापक – सभी की पहलकदमी पर शुरू हुई इस 'सकल जन हड़ताल' *(सकल जनुला सम्मे)* ने दस्तकारों, आटो ड्राइवरों, असंगठित मजदूरों, मुनिसिपल कर्मचारियों, व्यापारियों, पुजारियों, किसानों समेत हर तबके के लोगों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों की भागीदारी से एक व्यापक आम हड़ताल का रूप धारण कर लिया है जोकि दिन–ब–दिन तेज होती जा रही है। इस संघर्ष की व्यापकता को समझने के लिए एक उदाहरण काफी है कि इसमें बूढ़ों से लेकर महिलाओं और बच्चों तक सभी उम्र के लोग भागीदारी ले रहे हैं। सकल जन हड़ताल के प्रभाव को देखते हुए जनता से अलग–थलग पड़ जाने के डर से कांग्रेस, तेलुगुदेशम, भाजपा आदि तेलंगाना क्षेत्र की शासक वर्गीय पार्टियां एक से बढ़कर एक 'इस्तीफों' का नाटक खेल रही हैं जिन्हें मंजूर नहीं किए जाने वाला है। कांग्रेस यह दिखावा कर रही है कि वह अपनी हाई कमान पर दबाव डालकर तेलंगाना राज्य हासिल करने की कोशिश कर रही है। हड़ताल और तेज होने के बाद कांग्रेसी नेता दिल्ली जाकर गुलाम नबी आजाद के साथ सलाह–मशविरा शुरू कर दी जो खुद को तेलंगाना के मसले के हल के लिए कोशिश करने का दावा करते रहे हैं। मामूल की तरह उन्होंने अपनी रिपोर्ट

में तेलंगाना के गठन पर फैसला लेने के लिए 'और थोड़ा समय' लगने की बात कहकर फिर एक बार दगा किया। दूसरी ओर तरह–तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। सीमा–आंध्र इलाके के धनाढ्य वर्गों से सांठगांठ करने वाली कांग्रेस की हाइ कमान पहले से तय योजनाओं को अमल में लाने की फिराक में है। उसी का हिस्सा है हैदराबाद को तेलंगाना से अलग कर उसे केन्द्र शासित क्षेत्र या दो राज्यों की साझी राजधानी बनाने की साजिश। इसके अंतर्गत एक तर्क और प्रचारित किया जा रहा है जिसमें हैदराबाद को अलग कर बाकी तेलंगाना के साथ कर्नूल जिले को मिलाकर अलग राज्य बनाने की बात कही जा रही है। इन प्रस्तावों को तेलंगाना की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है जो एक अकाट्य ऐतिहासिक सच्चाई है। तेलंगानावासियों को चाहिए कि वे ऐसे तेलंगाना का, जिसमें हैदराबाद न हो, गठन करने की साजिशों का एकजुटता के साथ नाकाम कर दें।

19 दिनों से जारी इस जबर्दस्त सकल जन हड़ताल का दमन करने के लिए सरकार तीखे दमन का प्रयोग कर रही है। मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करते हुए एस्मा कानून का प्रयोग; फैक्टरियों, खदानों और दफ्तरों की पुलिस छावनियों में तब्दीली; प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज व रबड़ की गोलियों का प्रयोग; तेलंगानावादियों की अवैध गिरफ्तारियों और धमकियां देने का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर वह यह कोशिश भी कर रही है कि तेलंगाना की जनता और तटीय आंध्र क्षेत्र के सेटिलरों के बीच झगड़ा पैदा कर आंदोलन को कुचल दिया जाए। उसी साजिश के मुताबिक हड़ताल के अंदर विघटनकारियों को घुसाकर मजदूरों पर हमले करवा रही है। इसके तहत ही कर्मचारियों के नेता स्वामी गौड़ पर हमला किया गया। इसी साजिश के तहत लगडापाटी राजगोपाल राज्य परिवहन निगम (आरटीसी) के मजदूरों का हालचाल पूछने के नाम पर हैदराबाद आया था जो सीमा–आंध्र के इलाके से भाड़े के ड्राइवरों को लाकर आरटीसी की हड़ताल को तोड़ने में लगा हुआ है। राज्यपाल नरसिंहन, मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी और डीजीपी दिनेश रेड्डी केन्द्र सरकार के आदेश पर सकल जन हड़ताल का दमन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। हैदराबाद में कांग्रेसी मंत्री दानम नागेंदर, मुकेश गौड़ और मज़लिस के नेता ओवैसी बंधु पृथक तेलंगाना आंदोलन के खिलाफ खड़े होकर गद्दारी कर रहे हैं। सरकारें और शासक वर्ग 'श्रीकृष्ण कमेटी' की रिपोर्ट

के 8वें अध्याय में दिए गए सुझावों पर चलते हुए मीडिया को पूरी तरह नियंत्रित कर रहे हैं ताकि बेहद उच्च स्तर पर चल रही सकल जन हड़ताल का प्रचार आंध्रप्रदेश और देश के दूसरे प्रदेशों में न हो सके। इस तरह वे देश की जनता को अंधेरे में रखकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोगो, सकल जन हड़ताल को और ज्यादा दृढ़ता व तेजी के साथ जारी रखें। कठिन संघर्षों के लिए तैयार होकर ही तेलंगाना राज्य को हासिल किया जा सकता है। यह मानना बेमानी है कि जनता के न्यूनतम अधिकारों का भी हनन करने वाले ये शासक वर्ग इतनी आसानी से पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पिछले इतिहास से भी यह पता चलता है कि तेलंगाना की जनता को अपने न्यूनतम अधिकारों को हासिल करने के लिए भी कितना खून बहाना पड़ा था। दीर्घकालीन, एकताबद्ध और जुझारू आंदोलनों के लिए तैयार होने और संघर्ष ही एक मात्र रास्ता मानकर आगे बढने से ही केन्द्र सरकार को अलग तेलंगाना देने पर झुकाया जा सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि शासक वर्गीय पार्टियां और उनके नेता हमेशा मोलभाव करते हुए हर मौके पर आंदोलन पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। इन साजिशों का हर कदम पर पर्दाफाश कर हरा देना चाहिए। लम्बे समय से जारी आंदोलन के दौरान आंदोलन के नेतृत्व में आने वाले ढुलमुलपन का समय–समय पर मुकाबला करते हुए आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) जिसका दृढ़ विश्वास है कि लॉबीइंग के जरिए ही तेलंगाना राज्य को हासिल किया जा सकता है, मजबूरी में सकल जन हड़ताल में भाग ले रही है ताकि खुद को जनता से अलग–थलग पड़ने से बचाया जा सके। लेकिन दूसरी ओर, उसने सकल जन हड़ताल को गुमराह करने की नीयत से ही बांसवाड़ा उपचुनाव में तेलुगुदेशम से दलबदल करने वाले अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की। खुद को तेलंगाना राज्य के लिए समर्पित बताने वाली कांग्रेस ने इस चुनाव में उम्मीदवार खड़ाकर अपने अवसरवाद को जाहिर किया। शुरू से तेलंगाना का विरोध करते आ रही तेलुगुदेशम पार्टी द्वारा यह कहकर कि जब तक तेलंगाना नहीं मिलेगा तब तक चुनावों में वह भाग नहीं लेगी, बांसवाड़ा उपचुनावों का बहिष्कार करना उसके घोर अवसरवाद का सबूत भर है। इस मौके पर हमारी पार्टी सभी संयुक्त कर्याचरण समितियों (जेएसी) से अपील करती है कि वे इस

सकल जन हड़ताल के दौरान तेलंगाना जनता के अंदर सामने आई एकजुटता के आधार पर आगे बढ़ें तथा वे अपने अंदर विभिन्न मौकों पर सामने आ रहे ढुलमुलपन को दरकिनार कर जनता के जुझारू आंदोलन का सही ढंग से नेतृत्व करें।

'सकल जन हड़ताल' का संघर्षशील प्रभाव आज पूरे देश पर पड़ रहा है। इससे पृथक राज्य की मांग से जारी विभिन्न आंदोलनों को प्रेरणा मिल रही है। फिलहाल तेलंगाना की जनता के समर्थन में खड़े होना देशवासियों का एक अहम फर्ज बनता है। हमारी पार्टी रायलासीमा और तटीय आंध्र क्षेत्रों के लोगों से तहेदिल से अपील करती है कि वे सकल जन हड़ताल के दौरान उमड़ आई तेलंगाना की जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए पृथक तेलंगाना राज्य की मांग का समर्थन करें तथा वे तेलंगाना और सीमा–आंध्र क्षेत्रों की जनता के बीच फूट डालने की नीयत से जारी शोषक वर्गों की साजिशों का शिकार न बनते हुए इस जनवादी मांग का स्वागत करें।

इस मौके पर हमारी पार्टी तेलंगाना की जनता की पुरजोर मांग को मानकर पृथक तेलंगाना राज्य का तत्काल गठन करने की मांग करते हुए तथा सकल जन हड़ताल के समर्थन में 11 अक्टूबर 2011 को 'भारत बंद' का आह्वान करती है। हम मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, जनवादियों, प्रगतिशील जन संगठनों व व्यक्तियों, कवियों, कलाकारों समेत तमाम जन समुदायों से अपील करते हैं कि भारत बंद को सफल बनाया जाए। हम समूचे देशवासियों से अपील करते हैं कि दफ्तरों, शिक्षा संस्थानों और कारोबार को बंद रखकर तेलंगाना की जनता के पृथक राज्य आंदोलन के प्रति भाईचारा प्रकट करें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

25-11-2011

शोषित जनता के प्यारे सपूत, भारतीय क्रांति के नेता और भाकपा (माओवादी) के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड मल्लोजुला कोटेश्वर राव (किशनजी/रामजी) की बर्बर हत्या का पुरजोर विरोध करो!

29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक देशव्यापी विरोध सप्ताह तथा 4-5 दिसम्बर को 48-घंटे का 'भारत बंद' को सफल बनाओ!!

24 नवम्बर 2011 का दिन भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में काले दिन के रूप में अंकित हुआ है। भाकपा (माओवादी) को 'देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा' के रूप में प्रचारित करते हुए देशव्यापी दमनचक्र व शोषित जनता के खिलाफ अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ने वाले फासीवादी सोनिया–मनमोहन सिंह–प्रणब–चिदम्बरम– जयराम रमेश शासक गिरोह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सांठगांठ कर एक षड़यंत्र के तहत कॉमरेड कोटेश्वर राव को जिंदा पकड़कर कत्ल किया। पिछले साल 1 जुलाई को पार्टी के प्रवक्ता कॉमरेड आजाद की हत्या कर चुके इस गिरोह ने फिर एक बार पंजा मारकर अपनी खून की प्यास बुझा डाली। कॉमरेड आजाद की हत्या पर मगरमच्छ के आंसू बहाई ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद एक तरफ माओवादी पार्टी के साथ 'शांति वार्ता' का ढोंग करते हुए ही दूसरी ओर एक अन्य अग्रणी नेता कॉमरेड कोटेश्वर राव की हत्या कर अपने जन विरोधी व फासीवादी चेहरे पर से मुखौटा हटा लिया। केन्द्रीय

खुफिया संस्थाओं, पश्चिम बंगाल व आंध्रप्रदेश की हत्यारी खुफिया संस्थाओं ने बड़ी सोची–समझी साजिश के तहत उनका पीछा किया और एक संयुक्त ऑपरेशन में उनकी कायराना हत्या करके मुठभेड़ की मनगढंत कहानी फैला दी। केन्द्रीय गुह सचिव आर.के. सिंह ने जहां एक तरफ यह घोषणा की कि मुठभेड़ में मारे जाने वाले व्यक्ति के बारे में शत प्रतिशत कहना मुश्किल है क्योंकि उसकी शिनाख़्त करना बाकी है, वहीं दूसरी ओर यह कहकर कि इससे माओवादी आंदोलन को बड़ा झटका लगा, इस हत्या के पीछे की साजिश की ओर खुद ही इंगित किया। लुटेरे शासक वर्गों और उनका मार्गदर्शन करने वाले साम्राज्यवादियों को, जो यह दिवास्वप्न देख रहे हैं कि वे क्रांतिकारी आंदोलन के उच्च नेतृत्व की हत्या कर माओवादी पार्टी का जड़ से सफाया कर सकेंगे, शोषित जनता जनयुद्ध के जरिए जरूर दफना देगी।

पार्टी और जनता के बीच प्रह्लाद, रामजी, किशनजी, बिमल आदि नामों से लोकप्रिय कॉमरेड कोटेश्वर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। पिछले 37 सालों से एक अथक योद्धा के रूप में, उठाई हुई बंदूक को कभी नीचे न रखते हुए, शोषित जनता की मुक्ति के लिए लड़ते हुए अपने सिद्धांत व उसूलों की खातिर जान कुरबान करने वाले कॉमरेड कोटेश्वर का जन्म 1954 में आंध्रप्रदेश के उत्तर तेलंगाना क्षेत्र में आने वाले जिला करीमनगर के पेद्दापल्ली कस्बे में हुआ था। पिता वेंकटैया, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे और मां मधुरम्मा, जो प्रगतिशील विचारों वाली महिला हैं, के लालन–पोषण में पले–बढ़े कॉमरेड कोटेश्वर में बचपन से ही देश और देश की मेहनतकश जनता के प्रति प्रेम की भावना पैदा हुई। पेद्दापल्ली कस्बे में हाईस्कूल की पढ़ाई करने के दौरान 1969 में उभार के रूप में सामने आए पृथक तेलंगाना आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। करीमनगर के एसआरआर महाविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के दौरान महान नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम के संघर्षों से प्रेरित होकर वे क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे। 1974 से उन्होंने पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। आपातकाल के अंधेरे दौर में कुछ समय के लिए जेल जाने वाले कॉमरेड कोटेश्वर ने आपातकाल को हटाने के बाद पार्टी संगठनकर्ता के रूप में अपने गृह जिला करीमनगर की जनता के बीच कामकाज शुरू किया। पार्टी द्वारा दिए गए 'चलो गांवों की ओर' के आह्वान को पाकर गांवों में जाकर उन्होंने किसानों के साथ संपर्क कायम कर लिया। 1978 में 'जगित्याल

जैत्रयात्रा' के रूप में मशहूर हुए किसान आंदोलन के उभार में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में वे एक थे। उसी सिलसिले में वे भाकपा (मा–ले) की आदिलाबाद–करीमनगर संयुक्त जिला कमेटी के सदस्य के रूप में चुन लिए गए थे। 1979 में जब यह कमेटी दो कमेटियों के रूप में अलग हुई थी तो उन्हें करीमनगर जिला कमेटी के सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। 1980 में आयोजित आंध्रप्रदेश के 12वें राज्य अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था जहां उन्हें राज्य कमेटी में चुन लिया गया था और उसके सचिव बनाया गया था।

1985 तक एपी राज्य कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश भर में आंदोलन का विस्तार करने में तथा गुरिल्ला जोन के लक्ष्य से जारी उत्तर तेलंगाना के आंदोलन को विकसित करने में कॉमरेड कोटेश्वर ने अहम भूमिका निभाई। 1980 में दण्डकारण्य में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार करने और उसे विकसित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1986 में वे स्थानांतरित होकर दण्डकारण्य आंदोलन में शामिल हो गए जहां उन्होंने फॉरेस्ट कमेटी सदस्य की जिम्मेदारी उठाई। दण्डकारण्य में उन्होंने गुरिल्ला दस्तों और जनता का नेतृत्व व मार्गदर्शन किया। 1993 में उन्हें पार्टी की केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी (सी.ओ.सी.) के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया।

1994 से उन्होंने खास तौर से बंगाल समेत पूर्वी और उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार व विकास में योगदान दिया। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां नक्सलबाड़ी आंदोलन के पीछे हटने के बाद कई टुकड़ों में बिखर चुकी क्रांतिकारी शक्तियों को एकजुट कर क्रांतिकारी आंदोलन का पुनरनिर्माण करने में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल की शोषित जनता से तथा क्रांतिकारी खेमे के अंदर विभिन्न तबकों से घनिष्ठता के साथ घुलमिलकर, बंग्ला भाषा को दृढ़ संकल्प के साथ सीखकर उन्होंने वहां की जनता के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। कई क्रांतिकारी ग्रुपों से एकता कायम करने और पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने अथक परिश्रम किया। इस दौरान 1995 में आयोजित पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन में उन्हें केन्द्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में चुन लिया गया। 1998 में पीपुल्सवार और पार्टी यूनिटी के बीच एकता कायम करने में उन्होंने मजबूती से काम किया। 2001 में आयोजित पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) पार्टी की कांग्रेस में उन्हें फिर से केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया और पोलिटब्यूरो सदस्य चुन लिया गया।

उत्तर रीजनल ब्यूरो सचिव की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। उसी समय पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) और एमसीसीआई के बीच चली एकता वार्ता में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2004 में दो पार्टियों के विलय के बाद गठित एकीकृत केन्द्रीय कमेटी और पोलिटब्यूरो में सदस्य बनकर उन्होंने पूर्वी रीजनल ब्यूरो (ई.आर.बी.) के अंतर्गत काम किया। पश्चिम बंगाल राज्य के आंदोलन पर प्रधान रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए वे ई.आर. बी. के प्रवक्ता के रूप में बने रहे।

पार्टी में उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के संचालन और राजनीतिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 'क्रांति', 'एर्राजेंडा', 'जंग', 'प्रभात', 'वैनगॉर्ड' आदि पत्रिकाओं के संचालन में उनका योगदान रहा। पश्चिम बंगाल से प्रकाशित कई क्रांतिकारी पत्रिकाओं के पीछे उनका खासा योगदान रहा। इन पत्रिकाओं में उन्होंने कई सैद्धांतिक व राजनीतिक लेख लिखे थे। पार्टी के अंदर राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए बनी सब–कमेटी में सदस्य रहकर कॉमरेड कोटेश्वर ने पार्टी के कतारों को मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद विचारधारा पर शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। पार्टी के समूचे इतिहास में देखा जाए तो, क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार में, पार्टी के दस्तावेजों को समृद्ध बनाने में और आंदोलन को विकसित करने में उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही। जनवरी 2007 में आयोजित पार्टी की एकता कांग्रेस – 9वीं कांग्रेस में उन्हें फिर से केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया और आखिर तक उन्होंने पोलिटब्यूरो व पूर्वी रीजनल ब्यूरो में सदस्य के तौर पर काम किया।

पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी सीपीएम सरकार द्वारा लागू जन विरोधी व कॉर्पोरेट–परस्त नीतियों के खिलाफ 2007 से सिंगूर और नंदिग्राम में भड़क उठे जन आंदोलनों, खासकर पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लालगढ़ इलाके में एक जबर्दस्त उफान के रूप में उठे जन विद्रोह को उन्होंने राजनीतिक मार्गदर्शन दिया जोकि काफी महत्वपूर्ण था। बंगाल की राज्य कमेटी और पार्टी के कतारों को इन आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करते हुए ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से पार्टी के प्रचार–कार्य को भी पहलकदमी के साथ संचालित किया। 2009 में जब चिदम्बरम गिरोह वार्ता के नाम से, संघर्ष विराम के नाम से जनता को,

खासकर मध्यम वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका पर्दाफाश करने में कॉमरेड कोटेश्वर ने खासा योगदान दिया। कदम–कदम पर जनयुद्ध की अहमियत को ऊंचा उठाए रखते हुए क्रांतिकारी राजनीति को जनता में फैलाने के लिए असीम प्रयास किए। इस तरह करीब चार दशकों तक अनवरत जारी उनका क्रांतिकारी प्रस्थान 24 नवम्बर 2011 को अचानक समाप्त हुआ।

ykxk! tuokni lnk!!

इस बर्बर हत्या का सभी को खण्डन करना चाहिए। शासक वर्गों की साजिश यही है कि क्रांतिकारी नेतृत्व का सफाया कर देश की शोषित जनता को सही मार्गदर्शन और सर्वहारा नेतृत्व से वंचित किया जाए। साफ जाहिर है कि देश को मनमाने ढंग से लूटने–खसोटने में तथा यहां के जल–जंगल–जमीन को बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपकर अपने हिस्से की दलाली की मोटी रकम को स्विस बैंकों में छुपाने में इन महाचोरों और दलालों के लिए माओवादी आंदोलन ही सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए वे आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से पिछले दो सालों से चौतरफा व देशव्यापी बर्बर अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत हुई है यह निर्मम हत्या। आज तमाम देशभक्तिपूर्ण व स्वतंत्रताप्रेमी जनता का यह कर्तव्य बनता है कि क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी नेतृत्व की आंख की पुतली के समान रक्षा की जाए। इस तरह रक्षा करने का मतलब है देश और हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य को बचाना।

57 साल की उम्र में, कठोर गुरिल्ला जीवन में युवाओं से भी होड़ लगाते हुए, जहां भी रहें वहां के सभी कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह का संचार करने वाले कॉमरेड कोटेश्वर राव का जीवन खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। वे बिना किसी आराम के घण्टों तक अध्ययन और पार्टी के अन्य कामों में भाग लेते थे। लम्बी दूरियों की परवाह न करते हुए, कम सोते हुए, सादा–सीधा जीवन बिताते हुए, ज्यादा मेहनत करने वाले शख़्स थे वे। हर उम्र के लोगों से तथा विभिन्न किस्म की सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले कॉमरेडों से आसानी से घुलते–मिलते हुए सभी में क्रांतिकारी जोश भर देते थे। इस बात में जरा भी शक नहीं कि कॉमरेड कोटेश्वर की मौत से भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को गंभीर नुकसान हुआ है। लेकिन जनता महान है। इतिहास का निर्माता है। जनता और जन आंदोलनों ने ही कोटेश्वर राव जैसे

साहसिक व समर्पित क्रांतिकारियों को पैदा किया। उनके अधूरे उद्देश्यों की स्फूर्तिभावना से तथा जगित्याल से जंगलमहल के जंगलों तक फैलाई गई क्रांतिकारी सुगंध से सशस्त्र होकर मजदूर–किसान और क्रांतिकारी भारत के नए जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन को विजय–पथ पर अवश्य आगे बढ़ाएंगे। साम्राज्यवादियों, उनके गुर्गे भारत के सामंती व दलाल पूंजीपति वर्गों और सोनिया, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, ममता बनर्जी वगैरह उनके प्रतिनिधियों का नामोनिशान तक मिटा देंगे।

हमारी केन्द्रीय कमेटी समूचे देशवासियों से यह अपील करती है कि कॉमरेड कोटेश्वर राव की बर्बर हत्या के विरोध में 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक 'विरोध सप्ताह' तथा 4–5 दिसम्बर को 48 घण्टे का 'भारत बंद' सफल बनाया जाए। विरोध सप्ताह के दौरान इस हत्या का खण्डन करते हुए सभा, जुलूस, धरना, काली पट्टियां लगा लेना, चक्का जाम जैसे विभिन्न कार्यक्रम अपनाने का हम आग्रह करते हैं। 4 और 5 दिसम्बर को आयोजित 'भारत बंद' के दौरान रेल, सड़क यातायात, शिक्षा संस्थानों, व्यापार–कारोबार और सभी किस्म की औद्योगिक गतिविधियों को बंद रखा जाए। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को हम बंद से मुक्त रखेंगे।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

16-7-2012

सब्यसाची पण्डा द्वारा शासक वर्गों के सुर में सुर मिलाते हुए हमारी पार्टी के खिलाफ लगाए गए तमाम जहरीले, बेबुनियाद और झूठे आरोपों को भाकपा (माओवादी) सिरे से खारिज कर देती है!

और गद्दारी के लिए उसे पार्टी से बहिष्कार करती है!

हमारी ओड़िशा सांगठनिक कमेटी (एस.ओ.सी.) के सचिव सब्यसाची पण्डा ने हमारी पार्टी के महासचिव के नाम 16 पृष्ठों वाला पत्र लिखकर 14 मई 2012 को मीडिया में जारी कर दिया। इस पत्र में उसने शासक वर्गों के सुर में सुर मिलाकर भाकपा (माओवादी) और उसकी अगुवाई में जारी क्रांतिकारी आंदोलन पर जहर उगलते हुए कोरी कल्पनाओं से कई बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए। पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की बुरी नीयत से उसने इस पत्र को जारी कर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद तथा सर्वहारा की अगुवा पार्टी से खुद को अलग कर लिया। पार्टी छोड़ने और जनयुद्ध की लाइन व क्रांतिकारी व्यवहार को त्यागने की खुलेआम घोषणा कर उसने अपने नव संशोधनवादी चेहरे को उजागर किया। उसने अत्यंत निंदनीय, नीचतापूर्ण व षड़यंत्रकारी तरीकों से पार्टी, क्रांति, शोषित जनता, खासकर ओड़िशा की शोषित जनता की मुक्ति से जुड़े महान उद्देश्यों के साथ विश्वासघात कर खुद को गद्दार साबित किया।

सब्यसाची पण्डा ने पहले कुछ समय तक सीपीएम में और उसके बाद

सीपीआई (मा.ले.) (लिबरेशन) में काम किया था। बाद में क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित होकर उसने दक्षिणपंथी लिबरेशन पार्टी को छोड़कर 1998 में भाकपा (मा.ले.) (पार्टी यूनिटी) में प्रवेश किया। क्रांतिकारी पार्टियों की एकता से वह भाकपा (मा.ले.) (पीपुल्सवार) और उसके बाद भाकपा (माओवादी) में बना रहा। 2003–05 के बीच ए.ओ.बी. एस.जेड.सी. सदस्य के रूप में, 2005 से ओड़िशा राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य के रूप में और 2008 से उस कमेटी के सचिव के रूप में काम करता रहा। क्रांतिकारी पार्टी में 15 साल के लम्बे अंतराल तक काम करने के बावजूद खुद को एक असली सर्वहारा क्रांतिकारी के रूप में ढालने में वह विफल रहा। उसके क्रांति–विरोधी व अवसरवादी राजनीतिक विचारों, रुझानों और व्यवहार की साथियों, कैडरों और सी.सी. कामरेडों ने कई बार आलोचना की। पिछले दिसम्बर में जब राज्य स्तर का विशेष प्लीनम आयोजित किया गया था, उसमें उसके खिलाफ कई आलोचनाएं उठी थीं। लेकिन उसने उनमें से कुछ को रस्मी तौर पर स्वीकार कर बाकी को टालमटोल कर दिया। एक सच्चे सर्वहारा क्रांतिकारी के तौर पर अपनी गलतियों को ईमानदारी से चिन्हित कर सुधार लेने की बजाए वह एक कायर की तरह क्रांतिकारी आंदोलन से भाग गया।

उसके 16 पृष्ठों वाले पत्र में झूठ, विकृतियां और सच को तोड़ने–मरोड़ने वाले कुतर्क ही थे, जबकि रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस पत्र को उसने ओड़िशा में हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर कर, छिन्न–भिन्न कर, विनाश करने की ही नीयत से लिखा था। यह किसी से छिपी नहीं है कि महान क्रांतिकारी लक्ष्य को समर्पित, असीम कुरबानियों से नहीं डरने वाली, निस्वार्थ रूप से काम करने वाली, देश की मुक्ति के लिए कटिबद्ध और शोषित जनता के लिए आशा की किरण के रूप में हमारी पार्टी को प्राप्त प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर, शासक वर्गों की सेवा में संलग्न होकर अपनी स्वार्थ राजनीति को साधने की बुरी मंशा ही पण्डा के इस पत्र के पीछे निहित थी। इतिहास में ऐसा अक्सर देखा गया है कि शासक वर्ग पण्डा जैसे लोगों को इस भ्रम के साथ सामने लाते हैं कि इससे क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ जारी अपने दुष्प्रचार को वैधता मिल जाएगी। क्रांतिकारी आंदोलन

की शुरूआत से देखा जाए तो दुश्मन ने पण्डा जैसे अवसरवादियों को सामने रखकर इस तरह की कोरी कल्पनाओं के सहारे कामरेड्स चारु मजुमदार, कन्नाई चटर्जी आदि हमारे कई नेताओं पर, पार्टी पर तथा क्रांतिकारी आंदोलन पर कई बार हमले किए थे।

पण्डा द्वारा लगाए गए आरोपों की तह में जाने से पहले हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी समय–समय पर बैठकें, प्लीनम और अधिवेशन चलाती रहती है ताकि अपने कार्याचरण को सुधारा जा सके तथा उसे बेहतर बनाया जा सके। अपनी गलतियों को चिन्हित कर उन्हें आलोचना–आत्मालोचना, समीक्षा और विशेष भूल सुधार अभियानों के जरिए सुधार लेती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह सब जान–समझकर भी पण्डा अपने सोलह पन्नों वाले झूठे आरोपों के साथ सामने आया है तो उसके बुरे मंसूबों को साफ समझा जा सकता है। असल बात यह है कि चूंकि वह इस तरह की प्रक्रिया में भाग लेकर खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया।

हालांकि पण्डा के सड़ांध से भरे आरोपों की फेहरिश्त काफी लम्बी है, लेकिन उनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं –

1. माओवादियों के लिए विवेकहीन हिंसा और बेकसूर लोगों को मारना आम बात बन गया। वे अपने कैडरों को तथा भोलेभाले और बेकसूर पुलिस वालों को अंधाधुंध मार डालने के आदेश देते हैं। 2. पार्टी में तेलुगु और कोया कामरेडों का दबदबा कायम है। 3. माओवादी ही आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। उनसे खाना बनवाते हैं। सामान उठवाते हैं। कार्यकर्ताओं को त्यौहारों पर भी अपने परिवारों से मिलने नहीं देते हैं। माओवादी आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। 4. गणपति आतंक और भय पर आधारित तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं।

अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली जनता पर राजसत्ता अपने पास मौजूद तमाम हथियारों से दमनचक्र चलाती है। अगर यह लड़ाई जनता की मुक्ति के लक्ष्य से, यानी उत्पीड़ित जनता की राजसत्ता को कायम करने के लिए चलती हो

तो राजसत्ता उस पर तीखे दमन पर उतारू हो जाती है। उसके पुलिस, अर्द्धसैनिक व फौजी बल आगे रहकर हमला करते हैं, जबकि उसके तमाम दूसरे अंग इस हमले में सुनियोजित, तालमेल के साथ, बेहद क्रूरता व षड़यंत्रकारी तरीकों से भाग लेते हैं। इसलिए इस हिंसा का मुकाबला करने के लिए जनता को सशस्त्र संघर्ष जरूरी हो जाता है। मार्क्सवाद के बारे में एबीसीडी जानने वालों को भी क्रांतिकारी हिंसा से सम्बन्धित इस बुनियादी व प्राथमिक विषय के बारे में जरूर मालूम होगा। जब पण्डा ने दक्षिणपंथी अवसरवादी सीपीआइ (एम.एल.) लिबरेशन पार्टी को छोड़ क्रांतिकारी पार्टी की लाइन को कबूलकर पार्टी में शामिल हुआ था और एकता कांग्रेस की लाइन को मान लिया था, तब उसे इसके बारे में मालूम नहीं था ऐसा तो नहीं हो सकता। चूंकि पण्डा ने खुद को पार्टी से अलग करना चाहा, इसलिए वह अवसरवादी तरीके से जहर उगल रहा है कि माओवादियों की हिंसा विवेकहीन है और वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इन सबका विरोध करने का दिखावा करते हुए वह यह उम्मीद कर रहा है कि भारतीय राजसत्ता उसके प्रति रहमदिली दिखा दे। जनता को कई प्रकार की हिंसा का शिकार बनाते हुए, उनके जीवन के तमाम पहलुओं को ध्वस्त करते हुए, उनकी हत्याएं करते हुए, बर्बर राजकीय दमन चलाने वाले और उसमें हिस्सा लेने वाले सरकारी सशस्त्र बल व अधिकारी तथा लक्ष्मणानंद, जगबंधु जैसे वर्ग–दुश्मन पण्डा को अब अचानक निर्दोष नजर आ रहे हैं। शासक वर्गों के चरणों पर नतमस्तक होने के लिए वह झूठे इलजाम लगाने के मामले में शत्रु–दुष्प्रचार को भी पीछे छोड़ रहा है।

‘ओड़िशा में तेलुगु और कोया कामरेडों का दबदबा चल रहा है’ वाला आरोप लगाकर पण्डा ‘फूट डालो और राज करो’ की उसी घिसी–पिटी व ओछी चाल चल रहा है जोकि दरअसल ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और उनके नक्शेकदम पर चल रहे भारतीय शासक वर्गों की है। दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन के अनुसार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रणनीतिक दृष्टि से बिखरे हुए इलाकों से देशव्यापी स्तर में तथा छोटे इलाकों से व्यापक इलाकों में विस्तार करने के लिए और खुद को छोटी ताकत से एक बड़ी ताकत के रूप में विकसित करते हुए अंततः देशव्यापी पैमाने पर राजसत्ता हासिल करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण हो रहा है। इसके लिए पार्टी रणनीतिक दृष्टि

से अपनी ताकतों को शुरू से ही विभिन्न इलाकों में तैनात करके काम कर रही है। स्थानीय स्तर पर जनाधार को बढ़ाते हुए पार्टी व जनसेना को विकसित करते हुए इलाकेवार राजसत्ता की स्थापना कर रही है। इस लाइन पर चलते हुए रणनीतिक तौर पर शक्ति संतुलन में बदलाव लाकर अंततः शहरों को घेरकर देशव्यापी राजसत्ता पर कब्जा करनी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के हर सदस्य को देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने के लिए तैयार रहना होगा। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीयवादी होने के चलते कम्युनिस्टों को दुनिया के किसी भी देश में या क्षेत्र में जाकर वहां की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मुक्ति के लिए काम करने को तैयार रहना चाहिए। भारतीय क्रांति के इतिहास पर नजर डाली जाए तो हम यह समझ सकते हैं कि अपने इलाकों व राज्यों को छोड़कर दूसरे इलाकों व राज्यों में जाने वाले कामरेडों के कड़े प्रयासों के फलस्वरूप ही देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार हो पाया है। इन कामरेडों ने भाषाएं सीखीं। वहां की जनता की संस्कृति का सम्मान किया। उनके साथ एकताबद्ध हुए। नए इलाकों में निर्मित आंदोलनों को ऐसे कामरेडों के सामूहिक परिश्रम के नतीजे के रूप में देखा जा सकता है। पण्डा के संकीर्ण क्षेत्रीयवादी नजरिए के चलते दूसरे राज्यों से आए कामरेडों का ओड़िशा में आकर काम करना उसे कभी रास नहीं आया। ऐसे कामरेडों की निस्वार्थ भावना की प्रशंसा करने की बजाए उसने उनके और ओड़िया कामरेडों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए षड़यंत्रकारी तरीकों व गुटबाजी से ही लगातार काम किया। आंदोलन की जरूरत के अनुसार दूसरे राज्यों से ओड़िशा में काम करने के लिए आने वाले कामरेडों के मामले में उसने क्षेत्रीय अंधराष्ट्रवाद का प्रदर्शन करते हुए नौकरशाहीपूर्ण, गैर–जनवादी व संकीर्ण तरीके से काम किया। वास्तव में ओड़िया जनता और ओड़िया कामरेडों ने उनके लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए आंध्रप्रदेश, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ से आए हुए कामरेडों का खुशी से ही स्वागत किया। इस सच्चाई को स्वीकार किया। हम आशा करते हैं कि पण्डा के साथ कार्यरत चंद कामरेड्स जनयुद्ध की लाइन के बारे में दोबारा चिंतन–मनन कर उसके झूठों को समझ लेंगे और उसकी साजिशों को समझकर उसका

पर्दाफाश कर देंगे।

क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आदिवासियों की मुक्ति का लक्ष्य त्याग देने वाले पण्डा 'माओवादियों के हाथों आदिवासियों का शोषण' के बारे में शासक वर्गीय हत्यारों की ही तर्ज पर हमारी पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हुए मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है जोकि उसके छलकपट का साफ सबूत है। पार्टी में रहते समय शारीरक श्रम में कभी भाग न लेने वाले पण्डा की आंखों पर जब शासक वर्गीय चष्मे सज गए, आदिवासी कामरेडों का स्वैच्छिक रूप से, अत्युन्नत क्रांतिकारी चेतना के साथ क्रांति के लिए अपनी सारी शारीरक शक्ति को बाहर लाकर काम करना 'माओवादियों के हाथों शोषण' के रूप में दिखाई दे रहा है। आखिर माओवादी कौन हैं? और आदिवासी कौन हैं? क्या पार्टी में काम करने वाले आदिवासी माओवादी नहीं हैं? क्रांति को छोड़कर शासक वर्गों की वकालत करने पर उतारू ठेठ अवसरवादी पण्डा को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान रोजमर्रा के जीवन में जरूरी व्यक्तिगत श्रम और सामूहिक जीवन में सैन्य, तकनीकी, उत्पादन–विकास, जन कल्याण आदि क्षेत्रों में आवश्यक श्रम, जन आंदोलन में जनता का विभिन्न प्रकार का श्रम माओवादियों द्वारा आदिवासी जनता के शोषण के रूप में दिखाई देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वहारा पार्टी में हरेक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना–अपना काम कर लेते हैं। भार उठाते हैं। बीमार, शारीरक रूप से कमजोर और विशेष कामों में लगे साथियों की मदद दूसरे लोग करते हैं। दरअसल जनसेना प्रधान रूप से युद्ध का संचालन करते हुए अपने लिए जरूरी रसोई, भार उठाना आदि काम खुद ही कर लेती है। राष्ट्रीयता, लिंग, क्षेत्र आदि का फर्क किए बगैर हरेक को जनयुद्ध के अंतर्गत उपरोक्त काम करने ही होंगे। देश के विभिन्न गुरिल्ला जोनों में यही चलता आ रहा है। और चल रहा है। दरअसल हमारी पार्टी की संस्कृति जनवादी व समाजवादी संस्कृति है जिसमें स्त्री–पुरुषों के बीच, पढ़े–लिखे व अनपढ़ों के बीच तथा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी के प्रति आदिवासियों के आकर्षित होने का यह एक अहम कारण है। हमारी पार्टी इसी संस्कृति को बड़े पैमाने पर, लाखों लोगों के बीच ले जा रही है।

राजसत्ता यह आरोप बार–बार लगा रही है कि माओवादी अपनी पार्टी में शामिल महिलाओं/आदिवासी महिलाओं को अत्याचाार व यौन प्रताड़ना का शिकार बनाते हैं। गद्दार बन चुके पण्डा ने भी माओवादियों पर शासक वर्गों की तरह बेहद नीचतापूर्ण तरीके से हमला किया है तो इसमें अश्चर्य क्या है? अतीत में हमारी पार्टी ने हर बार जो जवाब दिया आज भी इस पर हमारा वही जवाब है। हालांकि इस आरोप का अत्युत्तम जवाब दे रही हैं वे सैकड़ों महिलाएं जो हमारी पार्टी में भर्ती हो रही हैं, वे हजारों–लाखों महिलाएं जो क्रांतिकारी महिला संगठनों में सदस्यता ले रही हैं, वे महिलाएं जो आंदोलन के इलाकों में मौजूद हैं और वे सैकड़ों महिला साथी जो नक्सलबाड़ी के दिनों से लेकर पिछले 45 सालों से शोषित जनता की मुक्ति के लिए अपने प्राणों को कुरबान कर चुकी हैं।

1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद, आंदोलन के अब तक के 90 से ज्यादा सालों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 25 बरसों में जनता, जन संस्कृति और जन जीवन के तमाम पहलुओं के साथ जितना ज्यादा एकताबद्ध हुई, उतना पहले कभी नहीं हुई थी। न सिर्फ एकताबद्ध हुई, बल्कि वह जन जीवन के राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलुओं में से तमाम प्रगतिशील अंशों को ऊंचा उठाकर, उन्हें अपने अंदर समाहित कर, उनका और ज्यादा क्रांतिकरण कर रही है। पण्डा के इस आरोप को कि त्यौहारों पर घर देखने को इच्छुक कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाता है, क्रांतिकारी जनता कतई विश्वास नहीं करेगी। जिन लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन के साथ ज्यादा परिचय नहीं है, ऐसे लोगों को उस पर घृणा की भावना पैदा करने की नीयत से ही वह इस प्रकार अवसरवादी तरीके से हमला कर रहा है।

यह आरोप कि गणपति आतंक और भय पर आधारित तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, इतना हास्यास्पद है कि दरअसल इसके लिए स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है। भाकपा (माओवादी) किसी बुर्जुआई पार्टी जैसी कतई नहीं है। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मौजूदा अर्द्ध सामंती व अर्द्ध औपनिवेशिक राजसत्ता को क्रांतिकारी हिंसा के जरिए ध्वस्त कर, नई जनवादी क्रांतिकारी सत्ता, यानी सर्वहारा की अगुवाई में मजदूर–किसान एकता की बुनियाद पर

आधारित चार वर्गों – मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्गों की जनवादी तानाशाही की स्थापना हमारा फौरी लक्ष्य है, जबकि बाद में समाजवाद और साम्यवाद लाना अंतिम लक्ष्य है। ऐसा भी नहीं है कि यह सब पण्डा को मालूम नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की आड़ में देश में मनमानी तरीके से तानाशाही चलाने वाली दलाल नौकरशाही बुर्जुआ व सामंती वर्गों की निरंकुश व्यवस्था से, जिसकी साम्राज्यवादियों से सांठगांठ है, समझौता करके उसमें अपनी जगह पक्की करने के इरादे से ही पण्डा कामरेड गणपति और हमारी पार्टी पर गलत आरोप लगा रहा है।

दरअसल पण्डा खुद ही ओड़िशा में अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। राज्य की विशेष प्लीनम में की गई समीक्षाओं और फैसलों को देखने के बाद उसने समझ लिया था कि पार्टी के कैडर उससे दबकर रहने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने उसके नौकरशाहाना व्यवहार और अन्य राज्यों के साथियों के प्रति गैर–जनवादी व संकीर्णतावादी रवैये की आलोचना की। यह पहचानते हुए कि नौकरशाहाना व्यवहार को जारी रखना संभव नहीं है, इस अवसरवादी ने पार्टी छोड़ने का फैसला लेकर तबसे अपनी पूर्व तैयारियों में तेजी लाई।

दरअसल, राज्य स्तरीय प्लीनम के आयोजन के बाद से उसने ओड़िशा राज्य प्रभारी सी.सी. कामरेड से संपर्क करना ही छोड़ दिया। तबसे, करीब छह महीनों तक वह अपने बयानों और साक्षात्कारों में लगातार पार्टी पर जहर उगलता रहा। इससे पार्टी में राजनीतिक व सांगठनिक समस्याएं उत्पन्न हुईं जिससे ओड़िशा के आंदोलन को तीव्र नुकसान पहुंचा। क्योंकि बहुत से मामलों में उसका रवैया विशेष प्लीनम के फैसलों, पार्टी लाइन और नीतियों के खिलाफ रहा। उसकी अगुवाई में जब इटली के सैलानियों को बंदी बनाया गया था, तब वह निहायत अवसरवादी तरीकों पर उतर आया। उसने समूचे ओड़िशा राज्य में एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा की। ओड़िशा और उसके सीमावर्ती इलाकों के उल्लेखनीय हिस्से में जब दो–दो सीमावर्ती कमेटियां काम कर रही हों, तब उसका इस तरह घोषणा करना अनुचित था। इस तरह बाकी दो कमेटियों को आदेश देने का उसे कोई अधिकार भी नहीं था। उसके द्वारा एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा के बाद जब एओबी के साथियों ने एक वि

ाायक को बंदी बनाया और एक एसआई को गोली मार दी, तब उसने न सिर्फ एओबी के साथियों की खुलेआम आलोचना की, बल्कि यह तक कह दिया कि उनके लिए मारना फैशन बन गया।

ओड़िशा एसओसी के दायरे में समूची पार्टी द्वारा की गई समीक्षाओं को ताक पर रखकर पण्डा ने यह घोषणा की कि लक्ष्मणानंद, जगबंधु जैसे वर्ग–दुश्मनों का सफाया गलत था। दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर उसने कामरेड निखिल के नाम से बयान जारी करते हुए अलग–अलग समुदायों व अलग–अलग राज्यों से आए हुए कामरेडों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिशें करते हुए एक जहरीली मुहिम शुरू कर दी। जब मीडिया में लगातार खबरें आने लगी थीं कि पण्डा पार्टी छोड़ने वाला है और एक नया ग्रुप बनाने वाला है, लगातार मीडिया के संपर्क में रहते हुए भी पण्डा की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आना महज इत्तेफाक नहीं था। साफ जाहिर है कि विशेष प्लीनम के बाद ही उसने पार्टी छोड़ने की योजना बनाकर खुलेआम अवसरवादी तरीकों और विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। अपने पतन की पराकाष्ठा के रूप में उसने आखिरकार पार्टी छोड़ दिया।

ओड़िशा आंदोलन के दौरान सामने आई राजनीतिक समस्याओं पर दक्षिणपंथी अवसरवादी रुख अपनाते रहे पण्डा का पतन आखिर में संशोधनवाद के स्तर पर हुआ जो दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन को ठुकरा देता है। उसके अंदर मौजूद संकीर्णतावादी, अतिजनवादी, अनुशासनहीन, गुटीय, गैर–सांगठनिक, पदलोलुपतावादी, नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागने आदि रुझानों ने ओड़िशा में पार्टी और आंदोलन को बेहद नुकसान पहुंचाया। वह हमेशा सुखी जीवन की तलाश में रहता था। उसके अंदर मेहनती स्वभाव का बिल्कुल अभाव था। संगठित होने के क्रम से गुजर रही ओड़िशा राज्य पार्टी को हुए गंभीर नुकसान की स्थिति और सी.सी. पर दुश्मन का हमला केन्द्रित होने से जो गंभीर नुकसान पहुंचा था उसका इस अवसरवादी ने फायदा उठाया ताकि राज्य में विघटनकारी गतिविधियां जारी रखी जा सकें। इन सबकी जड़ उसके अंदर गहराई से मौजूद व्यक्तिवाद में है जो व्यक्ति को केन्द्र में रखता है। इसके अलावा, क्रांतिकारी आंदोलन पर साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सम्पूर्ण सहयोग से भारत के शासक वर्गों द्वारा जारी प्रति–क्रांतिकारी युद्ध में 2009 के मध्य से आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से खासा बदलाव आ गया।

तबसे हमारे आंदोलन के खिलाफ जारी देशव्यापी व चौतरफा भारी सैनिक हमले की पृष्ठभूमि में ही पण्डा के पतन व विश्वासघात को देखना होगा। इस हमले में पार्टी को देश भर में तीखे नुकसान हुए हैं। हालांकि ओड़िशा में आंदोलन अभी भी कमजोर ही है, लेकिन वह भी इस हमले का बुरी तरह शिकार हो रहा है। खासकर 2010 के आखिर से उसे गंभीर नुकसान झेलने पड़े। यह हमला और भी तीखा होने वाला है। भारत जैसे पिछड़े देशों की प्राकृतिक सम्पदाओं और संसाधनों को लूटने के रास्ते में बाधा बनने वाले संगठनों और लोगों को कुचलने के पीछे अहम कारण बहुराष्ट्रीय व देश की दलाल कार्पोरेट कम्पनियों के हित ही है। विश्व अर्थव्यवस्था को घेरने वाला वित्तीय संकट और जितना तीखा होगा, क्रांतिकारी पार्टी, उसके नेतृत्व, आंदोलन व शोषित जनता पर वे अपना हमला उतना ही तेज करेंगे ताकि वे खुद को उससे उबार सके। इस पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी पार्टी के नेताओं के लिए आंदोलन को चलाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। पार्टी के सच्चे नेता देश और दुनिया में छाई हुई बेहतरीन क्रांतिकारी परिस्थिति का फायदा उठाकर जनता को राजनीतिक रूप से तैयार करते हुए, जनयुद्ध को विकसित करने व क्रांति के पक्ष में बदलने की ही कोशिश करेंगे। इसके लिए क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता, दृढ़ इरादे, साहस के साथ फैसले लेना, पार्टी, जनसेना व जनता को एक सूत्र में बांधकर चलाना, बलिदानी भावना आदि जरूरी होते हैं। क्रांति की जरूरतों और कार्यभारों के मुताबिक खुद को और पार्टी को ढालने के लिए फौलादी संकल्प जरूरी हो जाता है। ऐसे लक्षणों के अभाव में कोई भी नेता क्रांति का नेतृत्व करने में या तो विफल हो जाएगा या फिर अक्षम हो जाएगा। ऐसे लोगों में से कुछ जंगे मैदान को छोड़कर कायरों की तरह भाग खड़े हो जाएंगे या फिर दुश्मन की शरण में चले जाएंगे। इस सच्चाई को छुपाते हुए ऐसे अवसरवादी और क्रांति–द्रोही शासक वर्गों का बचाव करते हुए पार्टी और पार्टी–नेतृत्व पर अनाप–शनाप आरोप लगाते रहते हैं। अतीत में न सिर्फ हमारी पार्टी के इतिहास में, बल्कि विभिन्न देशों की क्रांतियों में भी ऐसे गद्दार रहे थे। ऐसे लोगों में पण्डा आखिरी व्यक्ति भी नहीं होगा।

उपरोक्त सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारी केन्द्रीय कमेटी ने पण्डा पर आए तमाम आरोपों को उसके सामने राजनीतिक रूप से पेश कर, उसे गलतियों से बाहर आने का मौका देते हुए, सुधारने की विशेष कोशिश शुरू

की। लेकिन राज्य की विशेष प्लीनम के बाद से उसने सम्बन्धित सी.सी. कामरेड से पूरी तरह सम्बन्ध तोड़ लिया और पार्टी, आंदोलन व नेतृत्व पर लगातार खुला हमला करता रहा। इन सबकी पराकाष्ठा के रूप में मीडिया को यह जहरीला पत्र जारी करके खुद को गद्दारों में शामिल कर लिया। इसलिए हमारी केन्द्रीय कमेटी सब्यसाची पण्डा को पार्टी से बहिष्कार करती है। और हम इसकी सूचना ओड़िशा में मौजूद हमारी पार्टी के तमाम साथियों, समूची क्रांतिकारी जनता और देश के तमाम क्रांतिकारी खेमे को देते हैं।

ओड़िशा के साथियों, जन संगठनों और क्रांतिकारी व जनवादी जनता से हम अपील करते हैं कि वे हमारी पार्टी, आंदोलन और नेतृत्व के प्रति पण्डा द्वारा अपनाए गए शत्रुतापूर्ण व अवसरवादी रुख तथा शासक वर्ग–अनुकूल व जनविरोधी रुख का खण्डन करें। उसे, उसकी सड़ी–गली नव संशोधनवादी राजनीति और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को ठुकरा दें। इतिहास ने कई बार साबित किया है कि जो खुद ही खुद को बेजोड़ क्रांतिकारी नायक के रूप में दिखाते हैं या फिर शासक वर्गों द्वारा इस तरह फोकस किए जाते हैं, ऐसे गद्दार आखिरकार इतिहास के कूड़ेदान में ही फेंक दिए जाएंगे जबकि सच्ची क्रांतिकारी पार्टी, उसके नेता और उसकी अगुवाई में क्रांतिकारी जनता अनुपम साहस के साथ, भारी तूफानों से होकर अंतिम जीत की ओर अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे। जनता ही इतिहास का निर्माता है, पण्डा जैसे नकली क्रांतिकारी नहीं। हमारी पार्टी को सम्पूर्ण विश्वास है कि ओड़िशा का सिक्का चलाते हुए शासक वर्गों की चरण–सेवा में जी–जान से जुट जाने वाले पण्डा जैसे गद्दारों को ओड़िशा की क्रांतिकारी जनता जरूर ठुकरा देगी तथा ओड़िशा के साथी व व्यापक उत्पीड़ित जनता भाकपा (माओवादी) की अगुवाई में क्रांति के पथ पर अग्रसर होंगे।

आनंद
पीबीएम, सीआरबी सचिव
केन्द्रीय कमेटी की ओर से
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
पूर्वी रीजनल ब्यूरो

2012

'दैनिक जागरण' पत्रिका की ओर से नक्सली संगठनों के पास रखे गये दस सवालों के बारे में भाकपा (माओवादी) का जवाब

प्रिय सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण,

आपने आपकी पत्रिका 'दैनिक जागरण' के जरिए 2012 के 1 मार्च से ''और कितना वक्त चाहिए झारखंड को?'' शीर्षक के तहत 'नक्सलवाद समाधान कब तक' इस विषय को लेकर पक्ष-विपक्ष के मतामतों का आह्वान कर एक खुली चर्चा तथा बहस की शुरूआत की है।

उक्त चर्चा का शुरूआती अंक में ही आपने 'कुछ सवाल नक्सली संगठनों के लिए' इस उप-शीर्षक के माध्यम से दस सवाल रखे हैं।

खुली बहस चलाने की आपकी यह पहल स्वागत योग्य है और इस पहल का हम आपनी पार्टी भाकपा (माओवादी) की ओर से स्वागत भी करते हैं।

हमें उम्मीद है कि उक्त सवालों का उत्तर सहित इस मुद्दा से जुड़ी हुई हमारी बातों को भी आप हूबहू छापेंगे।

अब आपका संवाद-पत्र द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर सिलसिलेवार ढंग से नीचे दिया जा रहा है। वे हैं :

सवाल एक: गांवों में नक्सली का राज होने के बावजूद विकास योजनाओं में इतनी गड़बड़ी सरकारी अधिकारी कैसे कर पाते हैं। नरेगा के तहत मजदूरों का हक मारा जाता है और मानव तस्कर गांव-गांव में सक्रिय हैं। ग्रामीण उत्पादन में बिचौलियों का बोलबाला है। ये विरोधाभासी स्थितियां कैसे संभव है?

उत्तर : हालांकि विकास योजनाओं में हो रही गड़बड़ी या घोटालाबाजी से

संबंधित इन सारे सवालों को नेता-मंत्री और सरकार के प्रशासनिक स्तर के अफसरों से पूछना चाहिए था और साथ-साथ तथाकथित आजादी के बाद पिछले 65 सालों के दौरान नेता-मंत्री व बड़े-बड़े अफसरों द्वारा हजारों-हजार करोड़ रूपए का घोटाला कैसे हुआ इसके बारे में भी पूछना चाहिए था, फिर भी चूंकि सवाल हमसे पूछा गया, इसलिए इसके जवाब में कुछ कहना लाजिमी है।

शायद हम सभी लोग प्रशासनिक स्तर के उपर से नीचे ब्लॉक स्तर तक कैसे सारे विकास योजनाएं बनती हैं इसके बारे में भलीभांति वाकिफ हैं। इन सारी योजनाओं के अंदर हर एक योजना के लिए निश्चित राशि का अनुमोदन भी होता है। अब योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को ठेका दे देने के साथ-साथ वहां से ही ऊपर से लेकर ब्लॉक स्तर के बीडीओ- सीओ तक किसको कितना प्रतिशत की राशि घूस के बतौर मिलेगी वह न केवल एक अवैध नियम के बतौर तय है बल्कि बैंक से उक्त अनुमोदित राशि निकलने के साथ-साथ उसका भाग-बंटवारा भी पूरा हो जाता है। विकास योजना के नाम पर अनुमोदित राशि का यह बंदर-बांट एक आम बात है। जहां तक झारखण्ड का सवाल है यहां नेता-मंत्री-एम.एल.ए.-अफसरों व ठेकेदारों द्वारा विकास योजना की राशि का बंदर-बांट सबसे ज्यादा है। दरअसल, विकास योजना की राशि का बंदर-बांट - यह एक सिस्टम बन गया है। यह सिस्टम मौजूदा व्यवस्था के अंदर ही निहित है। इसलिए गांवों में नक्सली राज रहे और न रहे नेता-मंत्री व सरकारी पदाधिकारी द्वारा विकास योजनाओं को लेकर जो गड़बडी चल रही है उसे हमेशा के लिए बंद करने हेतु मौजूदा व्यवस्था को बदलना अत्यावश्यक है। वही माओवादी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी गड़बड़ी को रोकने के लिए अथवा गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास योजना के अंतर्गत जो भी काम जारी है उसके लिए क्रान्तिकारी किसान कमिटी अथवा अन्य कुछ सांगठनिक ढांचा द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे- स्कीम क्या है और स्कीम के लिए अनुमोदित राशि कितनी है, मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है, इत्यादि सारी सूचनाओं को काम के जगह पर खुले रूप से बोर्डों पर टांगने का नियम को पालन करना प्रशासन के लिए बाध्यतामूलक करना। फिर भी इससे गड़बड़ी या घूसखोरी बंद नहीं हो सकती, और सरकारी अधिकारी तो ग्रामीण क्षेत्र

में आते ही नहीं कि उससे सवाल-जवाब किया जा सके। अभी तो छोटे-मोटे सरकारी अधिकारी भी विशाल पुलिस वाहिनी के बिना देहाती क्षेत्र की तरफ पैर ही नहीं बढ़ाते हैं। कभी काल मौका मिल जाता है तो गांवों की जनता अधिकारियों को घेरकर कुछ सवाल-जवाब करते हैं, कुछ कैफियत भी लेते हैं।

इसी तरह नरेगा के अंदर जारी व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाने से लेकर कुछ जन-कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। गांव की जनता की ओर से अथवा क्रान्तिकारी किसान कमिटी अथवा अन्य प्रकार के किसान संगठन की ओर से कुछ हदतक निगरानी भी रखी जा रही है। नरेगा के तहत मजदूरों का सही हक की प्राप्ति के लिए मजदूरों को संगठित कर जगह-जगह पर जुझारू आंदोलन भी किया जा रहा है।

जहां तक गांव-गांव में मानव तस्कर सक्रिय है कहकर आपने कहा है वह असल में दूर-दराज गांव-गांव में नहीं, कुछ रोड के बगल के बड़े गांवों में और गंज-कस्बा व शहरों में बैठकर अपना मानव तस्करी का नेटवर्क चलाते हैं। इसके लिए लोकल थानेदारों से लेकर बड़े पुलिस अफसरों के साथ घूस के बतौर महीनावार कितनी राशि देनी होगी वो निर्धारित है। ये मानव तस्कर लोग स्थानीय एम.एल.ए व दारोगा बाबू के साथ एकसाथ बैठकर चाय-नास्ता करते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं और सांठगांठ बनाए रखते हैं, इत्यादि, इत्यादि। जाहिर है कि इसके बिना पुलिस के नाक पर बैठकर मानव तस्करी जैसा घृणित काम किसी भी सूरत से नहीं चलाया जा सकता है। हमारी ओर से ऐसे घृणित कामों में लिप्त विचौलिये, ठेकेदार व उसके चमचा लोगों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी पहले से ही घोषित है और ऐसे गलत तत्वों को पकड़ कर विभिन्न किस्म की कार्रवाई भी की गई है और भविष्य में ऐसी कार्रवाई और कड़ाई से की जाएगी इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों को हमारे खिलाफ मुखबिरी करने के काम में भी पुलिस व खुफिया विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

अत: मानव तस्करी का गिरोह नेता-मंत्री और प्रशासन-पुलिस यानी राष्ट्रशक्ति के साथ सांठगांठ रखकर कैसे उसका चरम अपराधमूलक नेटवर्क चला रहा है- इसकी पीछे की सच्चाई वही है जो उपर में जिक्र किया गया।

फिर, ग्रामीण उत्पादन में बिचौलिया का बोलबला पर तो जहां–जहां हमारा आधार मजबूत है अथवा प्रभाव मौजूद है, वहां–वहां ग्रामीण उत्पादन पर बिचौलिया का बोलबाला अथवा रोब–दाब कुछ कम हुआ है। ग्रामीण बाजारों में भी बिचौलियों की बदमाशी कुछ कम हुई है। पर, गंज–कस्बों–शहरों में बिचौलियों का दबाव व मनमानी बहुत ज्यादा है। चूंकि बिचौलिया व्यवस्था देश की शोषणमूलक अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था से ओतप्रोत है, इसलिए मौजूदा अर्थव्यवस्था को बदल कर एक जन–मुखी अर्थव्यवस्था और उत्पादन व बंटन पर जनता का नियंत्रण स्थापित करने के दौरान ही बिचौलिया व्यवस्था का अंत किया जा सकता है। इसके अलावे, भाकपा (माओवादी) एक राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद और हमारा एक सुस्पष्ट पार्टी कार्यक्रम रहने के बावजूद हमें तमाम खुले राजनीतिक गतिविधियों से वंचित रखा गया है। जुलूस–सभा–जमायत आदि का भी आयोजन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी न्यूनतम जनवादी अधिकारों से हमें पूरी तरह वंचित रखा गया है। इसलिए, घूसखोरी के खिलाफ, नरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ और साथ–साथ मजदूरों की हक प्राप्ति के लिए तथा मानव तस्करी की समस्या और बिचौलिया की समस्या के खिलाफ बहुत–कुछ चाह कर भी हमारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगे रहने के कारण हमारे लिए कारगर ढंग से कुछ कर पाना नामुमकिन साबित हो रहा है।

यहां एक बात याद रखना है कि 'गांवों में नक्सली राज' (जो आपके पेपर में जिक्र है) स्थापित हो गया ऐसा कहना हम सही और उचित नहीं समझते हैं। हम कभी भी 'गांव में हमारा राज स्थापित है' अथवा 'मुक्त इलाका तैयार कर लिए हैं' ऐसा दावा पेश नहीं किए हैं अथवा घोषणा नहीं किए हैं। क्योंकि 'राज' स्थापित करने के साथ कई महत्वपूर्ण पहलुवें या शर्तें जुड़े हुए होते हैं। जब तक वे सब शर्तें पूरी नहीं होगी तब तक सही अर्थ में जनता का राज भी स्थापित नहीं हो पाएगा। हां, जहां पर जनता की जनसत्ता के निकाय के बतौर क्रान्तिकारी जन–कमिटी (आर.पी.सी) मौजूद है वहां वैसी एक भी जुल्म या शोषण नहीं है जैसे कि आपने पूछा। पर, आरपीसी के इलाके बहुत ही सीमित है और इस मजदूर–किसान राज को भ्रूण अवस्था में ही कुचल डालने के नापाक इरादे से शासक वर्ग द्वारा 'आपरेशन ग्रीन हंट' जैसे बर्बर सैनिक अभियान या अघोषित

युद्ध चलाया जा रहा है। बस्तर, सारंडा, लातेहार, भीमबांध, जिलगा पहाड़-इत्यादि क्षेत्रों में चलाया जा रहा सैनिक अभियान ही इसकी जीती-जागती मिसालें हैं। ऐसी स्थिति में आपने जिसको विरोधाभासी स्थितियां कही हैं, असल में उल्लिखित चर्चा के दौरान यह साफ है कि ये 'विरोधाभासी स्थिति' नहीं बल्कि वास्तविक सच्चाई है।

सवाल दो : सरकार का मतलब क्या सिर्फ पुलिस होती है। सरकारी नीतियों को बनाने और उसे लागू कराने में तो पूरा सरकारी और प्रशासनिक तबका लगा होता है। तो सिर्फ पुलिस ही लचर सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की दोषी कैसे हुई, जो हर बार उन्हें ही आसान निशाना बनाया जाता है।

उत्तर : शायद आप भाकपा (माओवादी) के पार्टी कार्यक्रम, किनको-किनको जनता के दुश्मन के बतौर चिन्हित किया गया और मौजूदा राजसत्ता का प्रधान अंग के रूप में पुलिस-मिलिट्री की भूमिका क्या है, वाकिफ नहीं है।

दरअसल, शोषण-शासन चलाने वाले वर्ग और उसके हित में विभिन्न सरकारी नीतियों को बनानेवाले नौकरशाह अफसर तंत्र - ये सारे लोग जो भी जन-विरोधी नीतियां बनाते हैं उसको जोर-जबरन जनता पर थोप दिया जाता है तथा जबरन लागू करने के लिए पुलिस-मिलिट्री को इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में, इतिहास गवाह है कि पुलिस-मिलिट्री के बल पर यानी और स्पष्ट कर कहा जाए तो बंदूक और केवल बंदूक के बल पर ही वे शोषक-शासक वर्ग उन तमाम जन-विरोधी नीतियों को लागू करते हैं। और जब सत्ता का दमन करने वाला अंग ही प्रधान अंग होता है और जब बंदूक हाथ में लेकर पुलिस जोर-जबरन उन नीतियों को लागू करने में उतर आती है तब जनता द्वारा प्रतिरोध का प्रथम व प्रधान टार्गेट वही बंदूक हाथ में लिए हुए पुलिस दल ही होता है। साफ है कि उस समय पुलिस की भूमिका शोषण-शासन चलाने वाले वर्ग की हित रक्षा करना ही एकमात्र काम बन जाता है। इसके लिए उक्त वर्ग के स्वार्थ में कितने ही मार-पीट, लूटपाट, गिरफ्तारी, इज्जत लूट, गोली मार कर हत्या, फसल बर्बादी -इत्यादि चरम अपराधमूलक कुकर्म क्यों न करना पड़े- पुलिस से वही काम करवाया जाता है और पुलिस तथा उसके अफसर खुद भी ऐसे

करते हैं। अब हम सभी को मालूम है कि आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा खातिर हथियार उठाने का अधिकार जनता का जन्मगत अधिकार है और साथ-साथ जनवादी अधिकार भी है। अतः बंदूक हाथ में लिये हुए दुश्मन से बचने हेतु जवाबी बंदूक पकड़ना किसी भी प्रगतिशील व जनवादी व्यक्ति के विचार से सही ही होगा।

आपका दैनिक जागरण में ही पिछले कुछ वर्षों तक झारखंड में माओवादी सहित कितने लोग फर्जी मुठभेड़ और विभिन्न गोली कांड में मारे गए हैं उसका ब्यौरा प्रकाशित हुआ है। इसके अलावे ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर जो बर्बर सैनिक अभियान चलाया जा रहा है उससे संबंधित कुछ रिपोर्ट भी आपने प्रकाशित किया है।

इसलिए 'लाचार पुलिस को ही आसान निशाना बनाया जा रहा है' ऐसी बात सत्य नहीं है। बल्कि सत्य तो यह है कि आज शोषक-शासक वर्ग उसकी पूरी दमनात्मक ताकतों के साथ शोषित-उत्पीड़ित वर्ग पर अत्याचार की बाढ़ बहा दिया है और शोषित-उत्पीड़ित वर्ग उसकी सीमित क्षमता के अनुसार उसका प्रतिरोध कर रहे हैं।

हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस गरीब घर से आए हुए हैं। वर्ग के रूप में वे हमारा दुश्मन भी नहीं हैं। पर, बंदूक हाथ में लिए हुए पुलिस जबतक शोषकों के पक्ष होकर गरीब जनता को निशाना बनाएगा तबतक गरीब जनता और उसकी सेना पीएलजीए भी आत्मरक्षार्थ जवाबी बंदूक सहित हर संभव उपाय का इस्तेमाल करेगी। अगर वे बंदूक का निशाना विपरीत दिशा में घुमा देते हैं तो जिस क्षण से वे ऐसा करेंगे उस क्षण से ही वे जनता का दोस्त बन जायेंगे और उसके खिलाफ जनता व पीएलजीए का जवाबी निशाना भी नहीं बनेंगे।

सवाल तीन : बीते चार दशकों में उनकी लड़ाई कहां तक पहुंची और उनकी क्या-क्या उपलब्धियां रही और इससे असमान सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर क्या और कितना सकारात्मक हस्तक्षेप करने में सफल हुए वे स्पष्ट करें।

उत्तर : भारतीय जनता के दुश्मन साम्राज्यवाद, सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों को उखाड़ फेंककर जनता की जनवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जो लड़ाई जारी है, उसे कुचलने हेतु क्रूर पुलिसिया अत्याचार सहित अन्य अनेकों प्रकार के रूकावटें पैदा करने के बावजूद आज भारत के बहुत-से प्रांतों में वह लड़ाई फैल गई-यह खुद सरकार की ही बात है। वास्तव में, माओवादी पार्टी के नेतृत्व में जनता की फौज यानी पीएलजीए और तमाम मित्र शक्तियों को लेकर एक संयुक्त मोर्चा यानी पार्टी, जनफौज व संयुक्त मोर्चा ये तीन जादूगरी हथियार भी आज कमोबेश मौजूद हैं। बीते चार दशकों से जारी क्रान्तिकारी संघर्ष के दौरान हासिल अनेकों उपलब्धियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक उपलब्धि यह है कि कुछ जगहों पर जनता की जनवादी व्यवस्था यानी जनसत्ता के भ्रूण रूप के बतौर एक सही चुनाव-प्रणाली के जरिए जनता के सही जन-प्रतिनिधि व जन-परिषद का चुनाव करने के दौरान क्रान्तिकारी जन-कमिटी (आर.पी.सी.) की स्थापना और उस कमिटी के माध्यम से जनता की इच्छा के अनुसार जनवादी राजनीति, अर्थनीति व संस्कृति की स्थापना करना तथा जनता की शासन-व्यवस्था लागू करना।

विगत चार दशकों से जारी लड़ाई के दौरान और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है विशाल संख्यक किसान-मजदूर-मेहनतकश जनता सहित उत्पीड़ित जनता व जाति की जनता के आत्मसम्मान व आत्ममर्यादा बोध के सवाल पर काफी जागरूकता लाना। इसके अलावे और एक उपलब्धि है क्रान्तिकारी किसान कमिटी के नेतृत्व में जमीन्दार-जोतदार के कब्जा से कई हजार एकड़ जमीन जप्त कर गरीब व भूमिहीनों के बीच बांट देना और खेती-बारी करवाना।

विदित है कि सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गुट के कथनानुसार आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा माओवादी ही है। इसके अलावे, पूरे भारत में माओवाद और माओवादी आंन्दोलन पर चर्चा व बहस आज एक आम बात बन गई है। इस आन्दोलन की लोकप्रियता को देखते हुए इसे रोकने के उद्देश्य से जबरदस्त सैनिक अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट व तथाकथित विकास के कार्यक्रम सहित बहुत सारी पॉलिसियों को तैयार किया गया है तथा किया जा रहा है। साफ

जाहिर है कि कारपोरेट घरानों के साथ किए गए बहुत-से एमओयू (करार) का क्रियान्वयन माओवादी आन्दोलन के फलस्वरूप ही आज बंद पड़ा हुआ है। हालांकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर माओवादी आन्दोलन का व्यापक प्रभाव पड़ रहा है तथा ढांचे में बदलाव लाने हेतु कुछ न कुछ सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। फिर भी व्यापक व बुनियादी बदलाव लाने का काम अभी बाकी ही है जो क्रान्तिकारी लड़ाई की अग्रगति के साथ-साथ क्रमबद्ध रूप से करना पड़ेगा।

सवाल चार : क्या नक्सल आन्दोलन का पर्याय बस पुलिस दल पर हमला, लेवी वसूलना, बंद का आह्वान कर आम जनजीवन को ठप करना, मुखबिरी के आरोप में ग्रामीणों की नृशंस हत्या, से है। किस तरह के संदर्भों और मामलों का आरोपी नक्सलवादियों का दुश्मन है साफ करें।

उत्तर : हमने पहले ही कहा कि आम जनता का सर्वांगीण विकास के लिए हमारी पार्टी का एक व्यवस्थित कार्यक्रम है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक -सांस्कृतिक व सामरिक सभी पहलू मौजूद हैं। साथ-ही जनता द्वारा सत्ता कब्जा करने के बाद उस जनवादी राज की विदेश नीति क्या होगी उसकी भी एक सुस्पष्ट रूपरेखा मौजूद है।

पर, चूंकि शोषक-शासक वर्ग उसकी पुलिस-मिलिट्री यानी बंदूक के बल पर जनता के इस क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने व कुचलने के लिए चौतरफा हमला चला रहे हैं और अपने देश की जनता के खिलाफ ही ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से एक अन्यायपूर्ण युद्ध चला रहे हैं तब उस युद्ध का न्यायपूर्ण युद्ध के जरिए मुकाबला करना हमारा एक प्रमुख काम बन जाता है। दुश्मन हमें वैसा प्रतिरोध युद्ध चलाने के लिए मजबूर किया है। ऐसा प्रतिरोध युद्ध चलाने हेतु हमें बहुत तरह की चीजों की आवश्यकता है। उसमें रूपया-पैसा की भी जरूरत है जो कि एक नियम के मातहत हम जुगाड़ करते हैं। लेवी वसूलना उसी नियम का एक अंश है। सरकार भी टैक्स लेती है। क्रान्तिकारी सरकार भी टैक्स या लेवी लेती है। इसमें कोई अन्याय बात नहीं है।

फिर, बंद के बारे में आपने जो सवाल उठाया, उसके बारे में हमारा कहना

है कि जनता के ज्वलंत मुद्दों से लेकर फर्जी मुठभेड़ के जरिए हत्या, बलात्कार, व्यापक पुलिसिया अत्याचार इत्यादि मुद्दों को लेकर हम कभी-कभी बंद बुलाते हैं। इस बंद से जन-जीवन पर क्या असर होता है इस पर हमलोगों ने समीक्षा भी की है। उसकी निचोड़ बात है:

*"**बन्द:** हाल के दिनों में केन्द्र व राज्य कमेटियों के साथ-साथ जनसंगठनों द्वारा भी कई बार बन्द का आह्वान किया जा रहा है। जनता, पार्टी, पीएलजीए व क्रान्तिकारी आन्दोलनों पर चलाये जा रहे सरकार के हमले को, उसके जनविरोधी नीतियों को तथा काले कानूनों का प्रतिरोध करने के लिए बन्द को एक संघर्ष के रूप के बतौर उपयोग करना ही चाहिए। लेकिन कुछ जगहों में बार-बार बन्द होने से जनता की आर्थिक जीवन और यातायात प्रभावित हो रही है। इससे कुछ जगहों में जनता से प्रतिवाद भी व्यक्त की जा रही है। इन मामलों को ध्यान में रखकर हमें बन्द का आह्वान देना चाहिए। केन्द्र व राज्य कमेटियां और जनसंगठन तालमेल के साथ बन्द का आह्वान करना चाहिए। हर दो बन्द के आह्वानों के बीच कम से कम दो महीनों का अन्तर रहना चाहिए। पार्टी के केन्द्र व राज्य कमेटियों की सदस्यों की गिरफ्तारियां और मुठभेड़ों के संदर्भ में अन्य राजनीतिक मामलों पर बंद का आह्वान करना पड़े तो यह नियम लागू नहीं होंगे।*

बन्द के दौरान बसों को जलाना, स्कूल व हॉस्टल को ध्वस्त करने आदि कार्रवाइयां को रोकना चाहिए। अस्पताल को बन्द से अलग रखना चाहिए। इससे जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दलाल पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्पत्ति पर, सरकार के यातायात, संचार व अन्य मुख्य व्यवस्थाओं के निशानों पर हमले करने चाहिए। शहीदों के स्मारक सप्ताह के अवसर पर हम बंद का आह्वान नहीं किये तो भी बन्द हो रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति के जरिए हमें इस बात को स्पष्ट करने चाहिए। हर प्रतिवाद दिवस के संदर्भ में हमें जनता के सामने ठोस कार्यक्रम रखना चाहिए। बन्द के संदर्भ में आम गाड़ियों को नहीं जलाना चाहिए। बसों पर फायरिंग नहीं करना चाहिए। बन्द के दौरान चलने वाले आम गाड़ियों को फायरिंग के जरिए नहीं, बल्कि अन्य पद्धतियों के जरिए रोकना चाहिए।"

जहां तक मुखबिरों का सफाया का सवाल है हम ग्रामीणों की नहीं, सही मुखबिरों को ही मारते हैं। क्योंकि विपरीत पक्ष उसकी कम तीव्रता वाला युद्ध (Low intensity conflict) पॉलिसी के अनुसार क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेता व कर्मियों को पकड़ने व फर्जी मुठभेड़ के जरिए हत्या करने की साजिश के तहत व्यापक मुखबिर नेटेवर्क तैयार किए हैं। भाकपा (माओवादी) के नेता व कार्यकर्ताओं को झूठी मुठभेड़ के जरिए नृशंस हत्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले (24 नवम्बर, 2011 को) पोलित ब्यूरो व सेन्ट्रल कमिटी के नेता का. कोटेश्वर राव को जिस नृशंसता से फर्जी मुठभेड़ में ठंढे दिमाग से हत्या की गई है, शायद वह किसी की जानकारी के बाहर नहीं है। भारत के पैमाने पर प्रगतिशील बुद्धिजीवी व मानवाधिकार कर्मी भी उक्त घृणित हत्या के खिलाफ जोरदार आवाज उठाए हैं और इसकी तीव्र निंदा भी किए हैं। फिर पिछले 2/3 वर्षों के दौरान विभिन्न नामों से जारी ऑपरेशन और खासकर ऑपरेशन मॉनसून, ऑपरेशन एनाकोंडा के तहत सारंडा इलाके में मुस्लिम, नेपाली, बोंगा, सुखराम, मंगल होनहगा व सोमा गुड़िया, जुड़िदा होनहगा, सहित कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ दिखा कर नृशंस रूप से हत्या की गई है। का. चमेली (का. कुंदन पाहन की पत्नी) को उसकी बच्ची के साथ बोकारो शहर से गिरफ्तार कर (असल में अपहरण कर) गायब कर देना (जिसका अता-पता आज तक नहीं मिला); वैसा ही जोनल कमिटी सदस्य का. वीरेन्द्र महतो (रांची-सोनाहातु के) और एक ग्रामीण डॉक्टर सुमन सिंह को दिन दस बजे गिरफ्तार कर गुप्त हत्या करते हुए लाश गायब कर देना; तमाड़ के एतवा मुण्डा और राजेश मुण्डा को, लातेहार जिला के बढ़निया गांव में 5 आदिवासियों को पकड़कर ठंडे दिमाग से मुठभेड़ के नाम पर हत्या, व नावरनागो के लूकस मिंज (मुक-बधिर) को फर्जी मुठभेड़ के जरिए हत्या, फिर 2010 में लातेहार के लादी ग्राम निवासी जसमिंता देवी व पलामू के छतरपुर थाना में राजेन्द्र यादव को पीट-पीट कर हत्या करना, इन सारी बातों के बारे में भी सभी को मालूम है। एक सर्वमान्य मानवाधिकार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10/11 वर्षों के समयकाल के अंदर झारखंड में, माओवादी होने का आरोप लगाकर, झारखण्ड पुलिस 550 आदमी को गोली मारकर हत्या की है।

अतः नक्सलवादी लोग केवल पुलिस को मारते हैं, लेवी वसूलते हैं, मुखबिरी के आरोप में ग्रामीणों को नृशंस रूप से हत्या करते हैं – ये बातें सत्य नहीं है। ये सब नक्सलवादियों के खिलाफ एक घृणित दुष्प्रचार है, दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा कम तीव्रता वाला युद्ध के तहत मनोवैज्ञानिक लड़ाई का हिस्सा है।

सवाल पांच : बीते चार दशकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के संबंध में वे अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें।

उत्तर : यह सवाल लगभग तीन नम्बर सवाल जैसा ही है जिसका जवाब उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते समय पहले ही दिया गया है। इसके अलावा चार दशकों की रिपोर्ट कार्ड भी बहुत बड़ी होगी। फिर भी संक्षेप में कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है, जो है:

1) हमारी एकता कांग्रेस – 9वीं कांग्रेस के बाद के पांच/छह सालों के हमारे व्यवहार में केन्द्रीय कार्यभार को लागू करने के लिए जारी कामकाज ही प्रधान पहलू रहा। इस दौरान दुश्मन ने क्रांतिकारी आंदोलन का जड़ से सफाया करने की मंशा से बर्बरतम व फासीवादी दमन आक्रमण चलाए जिसके अंतर्गत पिछले ढाई/तीन सालों से 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' जारी है। इन दमनात्मक अभियानों का मुकाबला करने हेतु हमने जनता की राजनीतिक गोलबंदी की तथा गुरिल्ला युद्ध को तेज करते हुए और दुश्मन की राजसत्ता को ध्वस्त करते हुए जनता की राजनीतिक हुकूमत को मजबूत बनाने की कोशिश की। देश के विभिन्न इलाकों में अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से संगठित हुई पीएलजीए ने पिछले तीन सालों में ऐतिहासिक मुकरम हमला समेत नयागढ़, सिल्दा, लखीसराय-कजरा, बलिमेला, कोंगेरा, लाहेरी, कलिमेला, मदनवेड़ा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली एम्बुश, धरधरिया एम्बुश (लोहरदगा), लातेहार गारू का सतनदिया एम्बुश, गढ़वा के सठलो एम्बुश, बालुमाथ के सुरंगी-टोंगरी एम्बुश, सारंडा-थोलकोबाद पुलिस पर रेड, जिलगा पहाड़ मुठभेड़, पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत बान्दु जवाबी कार्रवाई आदि कई भारी सैन्य कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया तथा ममाइल व सारंडा में दुश्मन के भारी हमलों को परास्त कर दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से जारी दुश्मन के सैन्य हमलों का माकूल जवाब देते

हुए उन्नत सैनिक अनुभव हासिल किया। गुरिल्ला युद्ध को केन्द्र स्थान पर रखते हुए पार्टी की समूची गतिविधियों को संचालित करने में हमने बेहतर अनुभव हासिल किया। इस दौरान गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध के रूप में तथा पीएलजीए को पीएलए में विकसित करने हेतु हम गुरिल्ला आधार-क्षेत्रों को अपेक्षाकृत और पहले के मुकाबले ज्यादा संगठित कर पाए।

2) हमारी पार्टी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लालगढ़ और नारायणपटना जन उभार भड़क उठे हैं। इन संघर्षों की विशिष्टता यह है कि इन्होंने जनता को बड़े पैमाने पर कार्यवाही में उतारा, संघर्ष व संगठन के नए स्वरूपों को सामने लाया तथा हमारे देश में सामंतवाद-विरोधी व साम्राज्यवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल बनाया। देश के कुछ और इलाकों में प्रधान रूप से जमीन के मुद्दे को केन्द्र बिंदु बनाकर खदानों, भारी परियोजनाओं और सेजों (एसइजेड) के विरोध में तथा जनता का बलपूर्वक विस्थापन का विरोध करते हुए जुझारू जन संघर्ष उभरे हैं। बहुराष्ट्रीय कारपोरेट कम्पनियों और बड़े दलाल पूंजीपतियों की लूट-खसोट की नीतियों तथा साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित भूमण्डलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ अनेक जगहों में जन संघर्ष उभरकर सामने आए। इन संघर्षों का हमारी पार्टी ने समर्थन किया और नेतृत्व भी किया। इसने हमारी पार्टी के अनुभवों को और भी समृद्ध किया। हमारे संघर्ष के इलाकों के विस्तार में, पार्टी के विस्तार में तथा पीएलजीए के अंदर नई शक्तियों की भर्ती में इन जन संघर्षों का खासा योगदान रहा।

3) दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड के कई हिस्सों, एओबी (नारायणपटना, मलकानगिरी व विशाखापटनम) और पश्चिम बंगाल (लालगढ़) आदि इलाकों में आकार ले रही वैकल्पिक जन राजसत्ता के संगठन आरपीसी (जनता सरकार) ने धीरे-धीरे मजबूत होते हुए पिछले तीन सालों में विस्तार किया। भारत की व्यापक जनता में नई आशाएं जगाते हुए देश के अंदर एक वैकल्पिक ताकत के रूप में वह अपनी पहचान बना रही है। आर.पी.सी. अपने स्तर पर रणनीतिक संयुक्त मोर्चा ही है जो आज देशव्यापी रणनीतिक संयुक्त मोर्चे के निर्माण की नींव रख रही है।

4) भारत के लुटेरे शासक वर्ग पिछले आठ सालों से हमारी पार्टी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एकमात्र व सबसे बड़ा खतरा घोषित करते आ रहे हैं। दुश्मन ने खासकर पिछले ढाई/तीन साल से 'आतंकवाद पर हमला' का नारा देकर फासीवादी ग्रीन हंट ऑपरेशन को जारी रखते हुए अपनी एलआईसी नीतियों के तहत मनोवैज्ञानिक (दुष्प्रचार) युद्ध को भी तेज किया। जनता के दिलोदिमाग को जीत लेने की योजना (WHAM - winning hearts and minds) के तहत दुश्मन ने करोड़ों रुपए खर्च कर एक व्यापक मुहिम शुरू कर रखी है। दरअसल यह एक सैद्धांतिक व राजनीतिक युद्ध है जिसका लक्ष्य जनता से हमें दूर करना है। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हमारी पार्टी ने मुकाबला किया और राजनीतिक प्रचार युद्ध चलाया। हमारी पार्टी के नेतृत्व में देश भर में बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील चिंतकों में स्पष्ट ध्रुवीकरण की प्रक्रिया जारी है। दुश्मन द्वारा लिए गए 'वार ऑन टेरर' (आतंकवाद पर हमला) को 'वार ऑन पीपुल' (जनता पर युद्ध) के रूप में साबित करते हुए वे देश-विदेश की जनता के सामने रखने में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। जहां एक तरफ पीएलजीए दुश्मन के सैनिक हमलों का पलटकर जवाब दे रही है, वहीं दूसरी ओर जनवादियों और बुद्धिजीवियों की सक्रिय व जन-पक्षधर भूमिका ने मनोवैज्ञानिक युद्ध का खण्डन करते हुए संयुक्त मोर्चा के क्षेत्र में पार्टी को एक नया अनुभव प्रदान किया।

5) लड़ाई के दौरान नेतृत्व के स्तर पर हुए नुकसानों के बावजूद भी देश के कुछ हिस्सों में हमारी पार्टी मजबूत हुई। पार्टी कमटियों में विकास व विस्तार हुआ। विभिन्न फौजी यूनिटों तथा जन संगठनों के अंदर भी पार्टी कामकाज में प्रगति हुई है। आंदोलन के पुराने कार्य-क्षेत्रों में जरूरी विस्तार के साथ पिछले पांच/छह सालों में कुछ प्रगति हासिल की गई। हालांकि नई रणनीतिक इलाकों में अपनाया गया विस्तार ही प्रधान पहलू है जिससे पार्टी को एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है।

देश भर में जनता की दैनंदिन व राजनीतिक समस्याओं पर आंदोलन तेज हो रहे हैं। चूंकि सरकार जनता को शोषण व उत्पीड़न का शिकार बना रही है और किसी भी समस्या का हल नहीं कर रही है, इसलिए जनता में तीखा विरोध

भड़क रहा है। जमीन, रोटी व मुक्ति के लिए तथा जल-जंगल-जमीन पर अधिकार को लेकर और विस्थापन, सेज, कई भारी बांध, अवैध उत्खनन आदि के खिलाफ जनता लड़ रही है। जनवादी अधिकारों के लिए तथा ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ कई तबके (विभिन्न सामाजिक जन समुदाय) लड़ रहे हैं। सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों के लिए, साम्राज्यवादियों की नव-उदार नीतियों के खिलाफ तथा पृथक राज्यों के निर्माण की मांगों पर कई किस्म के आंदोलन बड़े पैमाने पर उभरकर आ रहे हैं। इन आंदोलनों में विभिन्न किस्म की राजनीतिक (ज्यादातर जनवादी व प्रगतिशील) विचारधारा रखने वाले लोग समस्याओं के आधार पर हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। खासकर एमएल पार्टियों तथा वामपंथी पार्टियों की निचले स्तर के कैडर इन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी ले रहे हैं। कई उदार पूंजीवादी ताकतें (जैसे कि सर्वोदय के गांधीवादी, पुराने समाजवादी, चुनावों में भाग लेने वाली एमएल पार्टियां, एनजीओ आदि) भी, जो यह मानते हैं कि जन आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और बंदूक से जनता की मांगों को पूरा करना असंभव है, इन जुझारू आंदोलनों में भागीदारी ले रहे हैं।

हमारी पार्टी के नेतृत्व में उभर कर आए लालगढ़ जन विद्रोह ने देश की जनता को बेहद उत्साहित किया। नारायणपटना जन उभार, कलिंगनगर, सिंगूर, नंदिग्राम, सोंपेटा, नियामगिरी जैसे जुझारू जन आंदोलनों ने अपनी जायज समस्याओं को सामने रखते हुए केन्द्र व राज्य सरकारों का पर्दाफाश किया। देश में चल रहे इन तमाम जन संघर्षों ने साम्राज्यवादी, सामंती व दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्गों के खिलाफ संघर्ष में एक नई परम्परा पैदा किया। 2009 में फिर से तेज हुए पृथक तेलंगाना राज्य के आंदोलन से देश भर में छोटे राज्यों के गठन पर नई बहस छिड़ गई। जनता चाहे कोई भी संघर्ष शुरू करे, वह जुझारू रूप धारण कर रहा है। कुछ मौकों पर वह सशस्त्र स्वरूप ले रहा है। इन संघर्षों का प्रभाव विदेशों में भी मजदूर वर्ग और अन्य तबकों पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है। देश में शासक वर्गों द्वारा जारी फासीवादी ग्रीन हंट ऑपरेशन के खिलाफ फिलिपींस, तुर्की, ब्राजील, अमेरिका और लंदन के दूतावासों के सामने मजदूर वर्ग ने प्रदर्शन किए, सेमिनार आयोजित किए। देश भर में दिल्ली, पंजाब,

आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखण्ड, बिहार, बंगाल, ओड़िशा और मुम्बई में रैलियों, सभा-सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट का विरोध करते हुए 'फोरम एगेंस्ट वार ऑन पीपुल' नामक एक संगठन बनाकर बुद्धिजीवियों, जनवादियों, कवियों और कलाकारों ने व्यापक आंदोलन शुरू किया।

विभिन्न समस्याओं पर आंदोलन करते हुए तथा सरकारी दमनचक्र का खण्डन करते हुए आंदोलन करने वाले बुद्धिजीवियों और जनवादियों का गला घोंटने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने से लेकर आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई जा रही है। जन चिकित्सक और मानवाधिकार नेता डॉ. विनायक सेन को रायपुर जिला सत्र न्यायालय द्वारा दी गई उम्र कैद सभी जन संगठनों व सामाजिक कार्यकत्ताओं को सरकार द्वारा दी गई एक चेतावनी है। जन आंदोलनों पर तीव्र दमनचक्र चलाया जा रहा है। लाठीचार्ज और गोलीबारियों के अलावा अवैध गिरफ्तारियां कर जेलों में कैद किया जा रहा है। इन पांच-छह सालों में देश में उभरे इन जन आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। व्यापक जनता और उत्पीड़ित तबके हमारी पार्टी का नेतृत्व चाह रही है। देश भर में संशोधनवाद, आधुनिक संशोधनवाद और सुधारवाद दिन-ब-दिन नंगे हो रहे हैं। जनता और कार्यकर्ता अपनी पार्टियों और संगठनों को धता बताकर आंदोलन में अगुवा भूमिका निभा रहे हैं। रणनीतिक संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत हमारी पार्टी के नेतृत्व में प्रधान रूप से डीके (दक्षिणी छत्तीसगढ़), बीजे (बिहार-झारखण्ड-उः छत्तीसगढ़), एओबी (आंध्र-ओड़ीशा बोर्डर) और बंगाल के लालगढ़ (जंगल महल) इलाके में जनता की राजनीतिक सत्ता के संगठन खड़े हो रहे हैं। इन नई राजनीतिक संगठनों और उनके द्वारा जारी क्रांतिकारी सुधारों के प्रति देश की जनता में दिलचस्पी बढ़ रही है। डीके (दक्षिणी छत्तीसगढ़ में) डिवीजन स्तर पर विकसित हो चुकी इस राजनीतिक सत्ता का उच्च स्तर के कार्यभारों से संगठित होकर विस्तार हो रहा है। पार्टी और जनता के लिए ये अध्ययन के नए विषयों के रूप में सामने आए हैं।

दुश्मन हमारी पार्टी पर ऑपरेशन ग्रीन हंट अभियान चलाते हुए सीसी से लेकर निचले स्तर के नेतृत्व को गिरफ्तार कर जेलों में डाल रहा है और फर्जी मुठभेड़ों में हत्या कर रहा है। आंदोलन में अगुवा भूमिका निभाने वाले हजारों

लोगों पर फर्जी मामले दर्ज कर जेलों में डाल रहा है। ऐसे मौके पर जेलों में बंद कैदियों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई तथा फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ जारी संघर्षों का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई और उनके राजनीतिक अधिकारों पर आंदोलन चलाना चाहिए। खूब संक्षेप में यही हमारी उपलब्धियां भी हैं और हमारी कामकाज की रिपोर्ट भी है। इससे बीते चार दशकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के संबंध में कोई भी व्यक्ति एक अच्छी-खासी धारणाएं प्राप्त कर सकते हैं।

सवाल छः संगठन का विघटन और उससे उभरी विचारधाराओं की उपशाखाएं किन कारणों और वजहों से प्रभावित होकर टूटी। टूट का कारण सैद्धांतिक क्रियान्वयन था या फिर व्यक्तिवादी, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।

उत्तर : किसी भी मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी पार्टी में समाज में मौजूद विभिन्न वर्गों से आये हुए लोगों के विचारों की अभिव्यक्तियां होती रहती हैं। जब वर्ग संघर्ष तीखा व तीव्र होता है तो पार्टी के अंदर पेटी बुर्जुआ, गैर सर्वहारा और सर्वहारा विचारों के बीच के संघर्ष तीखे रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसी समय पार्टी के अंदर भी नेतृत्व के पद पर बैठे हुए कुछ लोग पार्टी की सही लाइन को त्याग कर संशोधनवादी लाइन या शांतिपूर्ण रास्ते से समाजवाद में जाने की लाइन ग्रहण कर पार्टी में टूटन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। जब पार्टी के अंदर दो लाइन का वितर्क चला कर अंत तक पार्टी कांग्रेस अथवा पार्टी प्लेनम के जरिए दो-लाइन का वितर्क का बहुमत द्वारा हल निकाला जाता है, उसे न मानने से ही पार्टी में टूट अनिवार्य हो जाता है। फिर, पार्टी के नेतृत्व पद पर बैठे हुए कुछ लोग व्यक्तिवादी व उच्चाकांक्षी होने पर पूरी पार्टी पर कब्जा जमाने हेतु पार्टी में तोड़फोड़ के काम सहित विभिन्न प्रकार के पार्टी विरोधी हथकंडे अपनाते हैं जिससे टूट अनिवार्य हो जाता है। असल, में मार्क्सवाद और संशोधनवाद के बीच साफ विभाजन हो जाना ही उक्त टू-लाइन वितर्क का मूल मकसद होता है। यही हर वस्तु अथवा विषय में दो विपरीत तत्व की एकता व विरोध की प्रक्रिया का हल करने का तरीका है। यह एक वैज्ञानिक नियम है। पार्टी के अंदर वितर्क न रहना और सही और गलत के बीच संघर्ष न रहना और उसे हल करने हेतु जनवादी केन्द्रीयता का नियम लागू नहीं रहना पार्टी का प्राण न रहने के बराबर

है। किसी भी सही मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मानने वाली पार्टी में व्यक्ति संगठन के अधीन, अल्पमत बहुमत के अधीन और पूरे संगठन केन्द्रीय कमिटी के अधीन होते हैं। कितना ही बड़ा व शीर्ष नेता हो कोई भी इस नियम से परे नहीं है। किसी भी सही कम्युनिस्ट पार्टी में एक व्यक्ति के मतामत अथवा एक व्यक्ति की बात पर ही सब कुछ तय होने की शैली अथवा पद्धति कतई ग्रहणयोग्य नहीं है।

यह बात सत्य है कि पुरानी सी.पी.आई. (एम.एल) और पुरानी एम. सी. सी. आई. में कई टूट हुई है। उक्त सभी टूट का बुनियादी कारण भी मार्क्सवाद बनाम संशोधनवाद ही था। इतिहास प्रमाण कर दिया कि संसदीय तथा संशोधनवादी लाइन व कार्यशैली अपनाने वाले सभी ग्रूप आज जनता से पूरी तरह अलग–थलग होकर शोषक–शासक वर्ग के हित में ही काम कर रहे हैं और विपरीत रूप में 2004 के 21 सितम्बर, सी. पी. आई. (एम. एल.) पी. डब्ल्यू. और एम. सी. सी. आई. दोनों मिलकर एक नई पार्टी भाकपा (माओवादी) का गठन किया है। वही पार्टी आज भारत में जारी क्रान्तिकारी संघर्ष का नेतृत्व दे रही है। आज झारखण्ड में टीपीसी, जेपीसी, एसपीएम, संघर्ष जन–मुक्ति, जेएलटी, पीएलएफआई, इत्यादि नाम से जो भी गुट काम कर रहे हैं, उसके साथ जन–मुक्ति या क्रान्ति का कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल, इन सभी गुटों के नेतालोग पुलिस व खुफिया विभाग के बड़े अफसरों के साथ गुप्त तरीके से सांठगांठ कर भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रान्तिकारी संघर्ष का काफी नुकसान करने हेतु खूनी संघर्ष में उतर चुके हैं। इसमें टीपीसी ही शासक वर्ग और पुलिस का सबसे विश्वस्त गुट है। इसलिए ये सभी गुट जिसके साथ (केवल लेवी के बतौर जोर–जबरन पैसा वसुलने के सिवाय) मालेमा, क्रान्ति इत्यादि से कोई संबंध नहीं है, उन सभी गुटों को भी एक सोची–समझी साजिश के तहत नक्सली अथवा माओवादी का लेबुल लगाकर प्रचार किया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है, आम जनता के बीच ऐसा एक भ्रम पैदा करना जिससे कौन सही जनक्रान्ति की रहनुमाई कर रहा है और कौन इसका विरोधी है, उसे पहचान न सके।

फिर, 2004 के 21 सितम्बर में एम. सी. सी. आई. और सी. पी. आई.

(एम. एल.) पी. डब्ल्यू के मिलन के जरिए एक नई व एकताबद्ध पार्टी सी. पी. आई. (माओवादी) का गठन हुआ। भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में सी. पी. आई. (माओवादी) का गठन एक ऐतिहासिक महत्व रखनेवाली घटना है। इसे कोई नहीं इनकार कर सकते हैं। पर, जब से इस नई व एकताबद्ध पार्टी का जन्म हुआ है और तेजी से भारत के कुछ प्रांतों में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तार हुआ है, तब से इसकी लोकप्रियता देख चिन्तित व आतंकग्रस्त शोषक-शासक वर्ग और प्रतिक्रियावादी भारत सरकार के प्रचार-यंत्र व तंत्र और मीडिया के कुछ लोग - 'पार्टी की एकता में दरारें', 'पार्टी के अंदर दो पुरानी पार्टियों का मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है', 'का. आजाद और का. कोटेश्वर राव को मार दिए जाने के बाद पूरी पार्टी में नेतृत्व का संकट हो गया', 'पार्टी में अनुशासन का भारी अभाव हो गया' इत्यादि, इत्यादि बातों को खूब उछाल रहे हैं। असल में, ये सब दुष्प्रचार हैं और सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम फासीस्ट गुट द्वारा हमारे खिलाफ चलाया जा रहा मनोवैज्ञानिक लड़ाई का ही सबूत है। वास्तव में नई पार्टी के गठन के बाद पिछले आठ सालों के दौरान पार्टी सैद्धांतिक-राजनीतिक रूप से और दृढ़ व और एकताबद्ध हुई है, क्रान्तिकारी आन्दोलन का संचालन के दौरान अनेक नए-नए अनुभव हासिल की है। भविज़्य में भी ऐसा ही होता रहेगा।

हालांकि यह बात सत्य है कि का. आजाद और का. कोटेश्वर की शहादत से हमारी पार्टी का भारी नुकसान हुआ है। पर, हमारे पार्टी के विभिन्न स्तरों की कमिटियों में बहुत-से वरिष्ठ व अनुभवी कामरेड मौजूद हैं। इसके अलावे नए नौजवान कामरेड लोग भी वर्ग-युद्ध के मैदान से उभर कर अगली पंक्ति में खड़ा होने के लिए सामने आ रहे हैं।

असल में, पार्टी के अंदर जबरदस्त मतभेद सामने आ गया-इस तरह की बात कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों के दिमाग की उपज है, जिसके साथ सच्चाई का कोई संबंध नहीं है। दरअसल मालेमा सिद्धांत के अनुसार पार्टी में भी दो विपरीत चीज की एकता का नियम लागू रहता है। पार्टी में सारे मतों को रखने का और एक मत द्वारा दूसरा मत का खण्डन करने का भी पूरा जनवादी अधिकार मौजूद रहता है। इसी को ही 'सौ फूल खिलने दो और एक मत को दूसरा मत के साथ

प्रतियोगिता करने दो' का सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रक्रिया से पार्टी का बहुमुखी विकास होता है तथा इस प्रक्रिया से पार्टी हर तरह से शक्तिशाली होती है।

विपरीत तौर पर अगर भारत में विभिन्न संसदीय पार्टियों के कामकाज के तरीके को देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी, सहित अधिकांश पार्टी में एक व्यक्ति की राय के अनुसार पार्टी का संचालन करने की पद्धति परिलक्षित होती है। असल में, जिस पार्टी के अंदर जनवाद नहीं है, वह पार्टी कभी भी देश की जनता को सही जनवादी अधिकार नहीं दे सकती है। भारत में जारी चुनाव व्यवस्था भी जनता का सही जनवादी अधिकार प्रयोग करने की अभिव्यक्ति नहीं है। कारण, यहां जनता अपनी पसंद के अनुसार न उम्मीदवार खड़ा कर सकती है और न ही चुन सकती है और न ही चुने गए प्रतिनिधि को ठीक से काम नहीं करने के कारण वापस बुला सकती है। यहां बहुत ज्यादा संख्या में करोड़पति व अरबपति लोग चुनाव में खड़े होते हैं और जीतने हेतु सभी प्रकार के अवैध हथकंडे अपनाने सहित विशाल काले धन व्यय करते हैं। भारत की मौजूदा व्यवस्था में आम मजदूर-किसान-मेहनतकश जनता और उत्पीड़ित जनता जिनका प्रतिशत कुल जनसंख्या के लगभग 90 भाग है, न कानून बना सकती है और न ही जनता की इच्छा के अनुसार राजनीति, अर्थनीति व संस्कृति का निर्माण कर सकती है। इसलिए भारत का 'वोटतंत्र' आम जनता के लिए 'धोखा तंत्र' के अलावा कुछ भी नहीं है।

सवाल सात : अब तक जितने भी आम नागरिक नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं, उनके नाम और उन पर नक्सली कार्रवाई क्यों हुई, इसका एक विस्तृत ब्योरा पेश किया जाना चाहिए ताकि अंधहिंसा की आमधारणा साफ हो सके। जनता तय करे कि ये कार्रवाइयां उचित थी या अनुचित।

उत्तर : पहले ही कहा जा चुका है कि सबसे घृणित व अत्याचारी वर्ग दुश्मन और उसके बहुत तरह की निजी सेनाओं के गिने-चुने सरगना, चिन्हित पुलिस मुखबिर इत्यादि पर ही कार्रवाई की जाती है। किसी भी आम नागरिक पर नहीं। 'इसलिए आम नागरिक नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं' यह बात सत्य नहीं है। हां, कभी-कभी कार्रवाई करते समय हमारी गलती के कारण कई लोग

मारे गए हैं। इसके लिए तुरंत प्रेस रिलीज जारी कर हम क्षमा याचना भी किए हैं और जहां-जहां संभव हुआ मुआवजा स्वरूप कुछ राशि भी दिए हैं। पार्टी स्तर पर भी गलती की समीक्षा करते हुए कुछ जरूरी निर्णय लिए गए तथा ऐसी गलती के लिए दोषी पार्टी सदस्य (चाहे किसी भी स्तर की पार्टी कमिटी के सदस्य क्यों न हो) पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई।

हमारी तरफ से जो कुछ भी कार्रवाईयां हुई हैं तथा हो रही हैं उसके बारे में खुले रूप से घोषणा करना हमारी पॉलिसी है। अतः किसी कार्रवाई की बात को छिपाना (चाहे गलत कार्रवाई की बात भी क्यों न हो) हमारा अपना बनाया हुआ नियम के विरूद्ध है, सब कुछ खुलकर जनता के सामने में रखने की हमारी परम्परा के विरूद्ध है।

जहां तक हिंसा अथवा अंधहिंसा की बात है, हम नहीं, मौजूदा राज्यमशीनरी या राष्ट्रशक्ति ही हिंसा अथवा अंधहिंसा की जड़ है। सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम फासीवादी गुट तथा शोषक-शासक वर्ग ही हिंसा के पैरोकार है। अंतिम विश्लेषण में राष्ट्रशक्ति या राजसत्ता बंदूक और केवल बंदूक पर आधारित होकर ही शोषक-शासक वर्ग का शोषणमूलक राज टिकाकर रखती है। शोषित-उत्पीड़ित जनता, मजदूर-किसान-मेहनतकश जनता और जन-मुक्ति छापामार सेना तथा भाकपा (माओवादी) उक्त हिंसा का, हमेशा के लिए बंद करने के मकसद से, प्रतिवाद-प्रतिरोध व सशस्त्र प्रतिरोध का रास्ता अपनाती है। जनता बढ़िया से समझ जाती है कि हिंसा करने वाले कौन हैं और हिंसा का प्रतिरोध करने वाला कौन हैं तथा किस पक्ष की कार्रवाई सही व उचित है और किसकी कार्रवाई गलत व अनुचित है।

सवाल आठ : संगठन के भीतर महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण जैसी खबरों का खंडन करें, क्योंकि माओत्सेतुड. ने ही कहा था कि अगर कोई कामरेड किसी महिला का दुष्कर्म करता है, तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए।

उत्तर : शायद इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है कि शासक वर्ग द्वारा सच्चे कम्युनिस्टों व जनता के सच्चे सेवकों के खिलाफ उसकी 'कम तीव्रता वाली युद्ध

पॉलिसी' के तहत मनोवैज्ञानिक लड़ाई के रूप में जितने किस्म के दुष्प्रचार चलाते हैं उसमें सबसे गंदा दुष्प्रचार है- संगठन अथवा पार्टी के भीतर महिलाओं के उपर यौन शोषण चलाने और खासकर नेतृत्व द्वारा महिला कामरेडों के उपर यौन शोषण चलाने संबंधी दुष्प्रचार। इस गंदे हथकंडे को सही दिखाने के लिए ये लोग यानी पुलिस व खुफिया विभाग के बड़े अफसर लोग गिरफ्तार किए गए महिला कामरेडों के उपर कपड़ा उतर देने से लेकर मारपीट व यौनांग पर बिजली का झटका लगाना अथवा यौनांग के अंदर पत्थर डालना, (जैसा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एक स्कूल शिक्षिका सोनी सोरी पर एस. पी. अंकित गर्ग द्वारा पूछताछ के समय इस तरह के घृणित व क्रूर यातनाएं दी गई है और बाद में कोलकाता के एक हॉसपिटल से गुप्तांग से उस पत्थर के टुकड़े को निकाला गया है।)' जांघ व शरीर पर हाथ रखकर पूछताछ चलाना इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्रूर यातनाएं देकर जबरदस्ती 'पुरूष कामरेड खासकर नेतृत्व द्वारा महिला कामरेडों पर यौन शोषण चलाया जाता है' ऐसी बात बुलवा लेने की हर संभव कोशिश करते हैं। क्रूर यातनाएं तबतक चलायी जाती है जबतक गिरफ्तार किए गये महिला कामरेडों के मुंह से जबर्दस्ती उपरोक्त बात नहीं कहलवा ली जाती। इसकी अनगिनत प्रमाणित मिसालें भी मौजूद हैं, जो आपकी पत्रिका में भी छपाई गई है। विपरीत रूप में भाकपा (माओवादी) पार्टी में आकर ही आम महिला कामरेड सबसे ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, समान मर्यादा व समान मान-सम्मान पाने के हकदार बनती हैं-शायद यह बात कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसके अलावा, महिलाओं के बारे में पार्टी कार्यक्रम में कहा गया है:

''वर्ग-विभाजित समाज के उद्भव के बाद से ही महिलाएँ विभिन्न किस्म की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भेदभाव व वंचना के शिकार हैं। ये घिनौनी परम्पराएँ, जैसे जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, देवदासी प्रथा आदि मुख्यत: आज भी जारी हैं। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। साम्राज्यवादी-सामन्ती शोषण-उत्पीड़न झेलने के अलावा वे परिवार, धर्म, जाति व्यवस्था, सम्पत्ति के सम्बन्धों और संस्कृति के क्षेत्र में पितृसत्तात्मक संस्थाओं के बने रहने के कारण पुरुष प्रधानता तथा उत्पीड़न के शिकार हैं। उन्हें कानूनी तौर पर सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद वस्तुत: व्यवहार में

उनके ये अधिकार फरेब साबित होते हैं। महिलाओं की भागीदारी उत्पादन के क्षेत्रों में बढ़ी तो है, पर उन्हें कम मजदूरी मिलती है तथा कार्य–स्थल पर तमाम तरह के उत्पीड़न के साथ–साथ लिंग–आधारित पेशेगत असमानताओं को भी झेलना पड़ता है। हाल के वर्षों में, खास कर साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और उपभोक्तावाद के चलते महिलाओं पर यौन–उत्पीड़न व अत्याचार बढ़े हैं। साथ ही पितृसत्तात्मक विचारधारा के प्रभाव में महिलाओं के खिलाफ जारी भेदभाव के फलस्वरूप महिला–पुरुष अनुपात चिंताजनक परिमाण में घटा है। साम्प्रदायिकता और कट्टरतावाद को, खासकर हिन्दू कट्टरतावाद को भड़काने की शासक वर्गों की कोशिशों ने महिलाओं की पीड़ा–व्यथा को और भी बढ़ा दिया है। अपने न्यायोचित अधिकारों के लिए उठ रही उनकी आवाजों को दबाने के लिए उनके खिलाफ बलात्कार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हथियार का इस्तेमाल राज्य भी विभिन्न संघर्षों में शामिल हो रही महिलाओं के ऊपर दमन के अत्यन्त नीचतापूर्ण तरीके के बतौर कर रहा है। राज्य और शासक वर्ग की विभिन्न पार्टियों द्वारा समर्थित सामन्ती शक्तियों की निजी सेनाएँ भी उत्पीड़न के अत्यन्त जघण्य तरीके के रूप में इस हथियार का इस्तेमाल कर रही हैं।''

''यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और पुरुष–प्रधानता तथा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा। यह राज्य महिलाओं को घरेलू कामकाज की बेड़ियों से मुक्त करायेगा और सामाजिक उत्पादन तथा अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह सार्वजनिक कपड़ा धुलाई स्थल, शिशु–गृहों और सार्वजनिक रसोईघरों को चलायेगा। यह सम्पत्ति पर महिलाओं के समान अधिकार की भी गारण्टी करेगा। महिलायें जिन असमानताओं का सामना करती हैं, उनको तेजी से खत्म करने के लिए यह विशेष नीतियों को बढ़ावा देगा और महिलाओं की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। यह राज्य वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं का पुनर्वास करेगा और उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करेगा।''

इससे महिला के प्रति पार्टी का दृष्टिकोण साफ झलकता है।

फिर, अगर पार्टी के अंदर पुरूष कामरेडों द्वारा महिला कामरेडों के साथ किसी प्रकार के अशोभन आचरण किया गया अथवा यौन शोषण किया गया तब तुरंत उक्त कामरेडों पर अपराध के अनुसार कड़ी से कड़ी अनुशानिक कार्रवाई की जाती है। पार्टी के अंदर ऐसे गलत काम करने वालों के लिए सजा पाना निश्चित है।

पर मौजूदा व्यवस्था में नेता-मंत्री-बड़ा प्रशासनिक व पुलिस अफसरों द्वारा महिलाओं पर बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध किए जाने के बावजूद भी कोई सजा नहीं मिलती है। न केवल उसकी कोई सजा होती है, बल्कि उसकी खुली छूट मिली हुई है। वे उसी पद पर रह जाते हैं, घमंड और शान से घुमते हैं। इसकी भी अनेकों मिसालें मौजूद हैं। झारखण्ड में कार्यरत कुछ राजनेता, कुछ पुलिस व प्रशासनिक अफसर, थाना दारोगा व सीआरपीएफ के कमांडेंट, सीआरपीएफ के सिपाही, जैप के, कोबरा-जगुआर-बीएसएफ के सिपाही इत्यादि बलात्कार की गम्भीर आरोप से आरोपित रहने के बावजूद अभी तक किसी को कुछ भी सजा नहीं मिली है। यह बात सौ प्रतिशत सही है-इसमें संदेह की कोई अवकाश नहीं है। मिशालस्वरूप झारखंड में कार्यरत पुलिस के बड़ा अफसर एडीजी पी.एस. नटराजन व डीआईजी परवेज हयात इत्यादि प्रमाणित बलात्कार के आरोपी होने के बावजूद आज तक उन लोगों की दृष्टांस्वरूप सजा नहीं हुई है। ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों द्वारा किये गए बलात्कार सहित विभिन्न दुष्कर्मों की सूची तो काफी बड़ी ही होगी जो यहां उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बात से सभी कोई वाकिफ हैं।

अंत में एक बात का जिक्र करना जरूरी है और वह यह है कि ''माओत्सेतुङ ने ही कहा था कि अगर कोई कामरेड किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है, तो इसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए (आपका प्रश्न से)'' -ऐसी बात हमलोग कभी सुने भी नहीं है अथवा उनके लेखों का अध्ययन से

भी नहीं मिला है। लगता है कि यह बात का. माओ के नहीं हैं। इसलिए दिवंगत नेता का. माओत्सेतुङ के नाम पर ऐसी बात बाजार में चालू कर देना कतई उचित नहीं है। भविष्य में ऐसा न करें तो ठीक रहेगा–यह हमारा अनुरोध है।

सवाल नौ : नक्सलवादी साफ करें कि उन्हें चीन से किसी तरह की मदद मिल रही या नहीं।

उत्तर : मौजूदा समय का चीन से किसी तरह की मदद लेने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि बहुत पहले ही यानी का. माओ की मृत्यु (9 सितम्बर,1976) के तुरंत बाद ही गद्दार तेंङ शिआयो पिङ के नेतृत्व में पार्टी में छिपे पूंजीवाद के राहगीर लोग पार्टी और सत्ता पर कब्जा कर लिए और चीन में बुनियादी तौर पर पूंजीवाद की पुर्नस्थापना की गई। अभी तो चीन उसी पूंजीवाद के रास्ते पर तेजी से और आगे बढ़ते ही जा रहा है। चीन के बारे में भाकपा (माओवादी) का यही स्टैंड या मूल्यांकन है। चीन के मौजूदा संशोधनवादी नेतृत्व भी भाकपा (माओवादी) का तथा भाकपा (माओवादी) की रहनुमाई में जारी क्रान्तिकारी संघर्ष का पूरा विरोध कर रहे हैं।

अत: पूंजीवादी चीन से किसी भी तरह की मदद लेने का मतलब ही है, हमारी पार्टी की बुनियादी पॉलिसी के खिलाफ खुद को खड़ा कर देना। 'चीन से भाकपा (माओवादी) मदद ले रही है' ऐसी बात अगर बाजार में चालू है तो हमारी पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से ही ऐसा गलत प्रचार किया जा रहा है। इसमें भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। हम क्रान्तिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं अपने बलबूत्ते पर आधारित होकर। इसलिए, मौजूदा चीन अगर समाजवादी चीन भी होता तो भी 'उससे मदद लेकर ही भारतीय क्रान्ति को आगे बढ़ाया जा सकेगा' ऐसी सोच को हम पूरे तौर पर खारिज करते हैं।

फिर, ''एक–ही मिथ्या को बार–बार कहकर उसे सच्च के रूप में मान लेने के लिए मजबूर करो'' फासिस्ट हिटलर मंत्रीमंडल के एक प्रमुख मंत्री गोवेबल्स

द्वारा निकाली गई उक्त घृणित नीति का भारत में हूबहू पालन करने वाला युद्धबाज चिदम्बरम भी 'भाकपा (माओवादी) पाकिस्तान के खुफिया विभाग आई.एस.आई से सांठगांठ कर हथियार सहित विभिन्न प्रकार की मदद ले रही है' ऐसा सौ प्रतिशत झूठा प्रचार कर रहा है। ये सब कुछ का एकमात्र उद्देश्य है– साम्राज्यवादी परोक्ष शासन व लूट का खात्मा कर आजाद भारत का निर्माण करने वाले सच्चे देशप्रेमिक (या देशभक्त) और साम्राज्यवाद, सामंतवाद व दलाल पूंजीपति द्वारा उत्पीड़ित जनता पर जारी क्रूर शोषण व जुल्म से मुक्ति की राह पर आगे बढ़ाकर ले जाने वाली पार्टी भाकपा (माओवादी) को बदनाम करना, उसकी क्रान्तिकारी छवि पर चोट पहुंचाना। जो अंततः नापाक इरादा के बतौर ही इतिहास में चिन्हित रहेगा। असल में सच्चाई यह है कि भारत के अनेकों राजनेता, मंत्री, मिलिट्री अफसर, खुफिया विभाग के कुछ लोग (जो डबल एजेंट का काम करते हैं), प्रशासनिक अफसर–पाकिस्तान के खुफिया विभाग आई.एस.आई. के साथ विशाल राशि पाने की लालच में सांठगांठ कर देश विरोधी कार्य में लिप्त हैं।

सवाल दस : लेवीवाद की आमधारणा को साफ करने के लिए अपने बजट और खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए।

उत्तर : भाकपा (माओवादी) के खिलाफ केन्द्र व राज्य सरकार की मिलीभगत से जितने किस्म के कुप्रचार या दुष्प्रचार चलाया जा रहा है उसमें और एक प्रमुख दुष्प्रचार है, "लेवी वसुलना, ऐस–मौज करना और लोगों को मारना केवल यही सब माओवादी पार्टी का काम है"। असल में, हमें 'लेवीवादी' के रूप में चित्रित करना कतई सही नहीं है। विरोधी पक्ष द्वारा चलाया जा रहा दुष्प्रचार से प्रभावित होकर ही आपकी पत्रिका की तरफ से भी वही सवाल रखा गया है– ऐसा प्रतीत होता है।

पर आपके द्वारा उठाया गया सवाल कि 'बजट और खर्च का ब्योरा

सार्वजनिक करना चाहिए' का स्पष्टीकरण देने की इच्छा हमारी सौ–प्रतिशत है। हमारे पूरे आय और व्यय के ब्यौरा हम खुले रूप से दे सकते हैं। क्योंकि कमिटी के स्तर पर आय–व्यय का ब्योरा तैयार है और राज्य कमिटी अथवा स्पेशल एरिया कमिटी के प्लेनम में (तीन वर्षों के अंतराल में अनुष्ठित होता है।) आय–व्यय के ब्यौरा पेश करना अनिवार्य है। फिर केन्द्रीय स्तर पर आयोजित कांग्रेस में पूरी पार्टी के आय–व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना भी बाध्यतामूलक है।

पर, अभी के समय में खूले रूप से इसका प्रकाशित करने से विरोधी पक्ष या प्रतिपक्ष हमारे बारे में ऐसा कुछ जान जा सकता है जिससे हमारा नुकसान करने की कोशिश हो सकती है। इसलिए आय–व्यय के ठोस ब्यौरा अभी के समय में पार्टी के बाहर खूले रूप से सार्वजनिक करने के मामले में हमारे लिए कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। अतः अभी आय–व्यय के ब्यौरा को सार्वजनिक न करने की पॉलिसी हमने ग्रहण की है।

पर, एक बात का जिक्र करना जरूरी है। वह यह है कि एक वर्ष के लिए भाकपा (माओवादी) की जितनी राशि की जरूरत है उसका एक/तिहाई हिस्सा भी हम जुटाने में अक्षम रह जाते हैं। माओवादी पार्टी सलाना एक–सौ / दो–सौ/ तीन–सौ करोड़ या अरबों रूपया कमाती है इस तरह का प्रचार के साथ सच्चाई का जरा–सा भी कोई तालूकात नहीं है।

पुनः 'भाकपा (माओवादी) अपनी आय के लिए विभिन्न गांवों में अफीम की खेती करवा रही है' ऐसा दुष्प्रचार भी लगातार चलाया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि शासन कार्य चलाने वाले कुछ ऊंचे ओहदे के लोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत साम्राज्यवादी खुफिया विभाग के कुछ लोग– इन दो प्रकार के लोग मिलकर साम्राज्यवाद खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा रची गई एक गहरी साजिश के तहत विभिन्न देशों में जारी साम्राज्यवाद –सामंतवाद विरोध ी संघर्ष को कुचलने के उद्देश्य से पूरे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने हेतु

यह अफीम की खेती करवाते हैं। यानी इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश व गिरोह मौजूद है जिनलोग अमेरिकी साम्राज्यवाद के खुफिया विभाग सी. आई. ए. द्वारा संचालित हो रहा है।

फिर, आय के स्रोत के लिए माओवादी किसानों को दबाव देकर अफीम की खेती करवाता है- यह सरासर झूठ है। स्पष्ट है कि अफीम व अफीम की खेती माओवादियों की नीति-विरूद्ध चीज है और नीति-विरूद्ध कोई चीज से माओवादी कभी समझौता नहीं करते हैं। जगजाहिर है कि आय के लिए हमारा तयशुदा अनेकों स्रोत मौजूद हैं, इसलिए आय के स्रोत के लिए अफीम की खेती करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अतः माओवादियों के खिलाफ यह भी एक घृणित आरोप है, एक सोची-समझी दुष्प्रचार है।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ
पूर्वी रीजनल ब्यूरो
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
पूर्वी रीजनल ब्यूरो

2012

शोषक-शासक वर्ग और विरोधी तत्वों द्वारा चलाये जा रहे कुछ दुष्प्रचारों के जवाब में

प्रिय सम्पादक महोदय,

'दैनिक जागरण' अखबार में 'और कितना वक्त चाहिए झारखण्ड को'- शीर्षक के तहत एक विषय के बतौर 'नक्सलवाद-समाधान कबतक' पर धारावाहिक रूप में पक्ष-विपक्ष की ओर से कुछ लेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अन्दर विपक्ष में लिखा हुआ एक लेख जो सीपीएम के झारखण्ड राज्य कमिटी के सचिव ज्ञान शंकर मजुमदार का लिखा हुआ है उसमें हमारे खिलाफ किये गये कुछ गलत आरोपों का खण्डन कर तथा मीडिया के जरिए बीच-बीच में उछाले गये कुछ दुष्प्रचारों का खण्डन कर हम भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमिटी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो की तरफ से यहां पर एक लेख प्रकाशित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस लेख को बिना किसी बदलाव के आप हूबहू छापेंगे।

पहला दुष्प्रचार : "भटक गये माओवादी', 'माओवादी अब अपनी विचारधारा से पूरी तरह भटक चुके हैं," "धीरे-धीरे आन्दोलन पर अंधहिंसा और लेवीवाद हावी हो गए" और "माओवादी केवल पुलिस को मारते हैं" इत्यादि-इत्यादि।।

जवाब : जिन सज्जन लोग ऐसा सोचते हैं अथवा सोच रहे हैं अथवा प्रचार करते फिर रहे हैं उनसे हमारा विनम्र प्रश्न है- क्या आप माओवादी विचारधारा के बारे में वाकिफ हैं और उसे मानते भी हैं? नहीं तो आप 'माओवादी अब अपनी विचारधारा ...भटक चुके हैं' ऐसा क्यों कह रहें हैं? यहां 'अब' की बात आप कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले हम अपनी विचारधारा से जरूर

नहीं भटके थे और उस वक्त हम सही थे। जिसको आप भी सही समझते हैं। नहीं तो आप 'अब .... विचारधारा से भटक गये' की बात क्यों कह रहे हैं? फिर जब आप 'अब' कहते हैं तो सवाल उठता है कि आपके विचार से कब से हमारी भटकने की प्रक्रिया शुरू हुई है?

हमारे लिए विचारधारा से भटकने का मतलब मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का बुनियादी सिद्धांत से भटक जाना, समाज को समाजवाद-साम्यवाद की ओर ले जाने का महान कर्तव्य से भटक जाना। हमारे विचार में दुनिया से पूंजीवादी-साम्राज्यवादी शोषण-जुल्म सहित भारत के आम जनता पर जारी साम्राज्यवादी-सामन्तवादी व दलाल नौकरशाह पूंजीवादी शोषण-जुल्म व अत्याचार तथा जातिगत शोषण-उत्पीड़न को जड़ से उखाड़ फेंक कर जनता की जनवादी व्यवस्था तथा समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण केवल सबसे उन्नत व वैज्ञानिक सिद्धांत मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद पर आधारित होकर ही हो सकता है। हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) उस सिद्धांत को ही, भारत की ठोस परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए तथा परिस्थिति की विशिष्टताओं के मद्देनजर उसे प्रयोग कर रही है। हमारा उद्भव अचानक आसमान से टपक कर नहीं हुआ है और न ही अंधहिंसा व लेवी उठाकर अवैध धन कमाने और मौज-मस्ती का जीवन व्यतीत करने के लिए हुआ है। हमारा उद्भव अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर घमसान लाइन वितर्क के दौरान पहले ही 1964 और बाद में 1967 में महान नक्सलबाड़ी विद्रोह के दौरान हुआ है। 1964 में अनुष्ठित अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं कांग्रेस के जरिए ही मार्क्सवाद बनाम संशोधनवाद- इस लाइन-वितर्क का एक सुस्पष्ट विभाजन का परिणाम निकला और 1967 में नक्सलबाड़ी विद्रोह के दौरान सी.पी.एम. के अन्दर रहे सच्चे क्रान्तिकारी लोग अलग हुए और 1969 में सीपीआई (एम.एल) और माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र बन उठे जो अनेकों विघ्न-बाधा अतिक्रम कर अंततः 2004 के 21 सितम्बर में आकर सही लाइन, नीति व व्यवस्थित पार्टी कार्यक्रम पर आधारित होकर एक ऐतिहासिक मिलन की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता की मुक्ति आन्दोलन की रहनुमाई के रूप में आज की नई व एकताबद्ध पार्टी

भाकपा (माओवादी) का उदय हुआ। हमारे विचार में सीपीआई व सीपीएम नेतृत्व घोर अवसरवादी है और उक्त दोनों पार्टी घोर संशोधनवादी पार्टी हैं और खासकर सीपीएम एक सामाजिक फासीवादी पार्टी है जो कि पश्चिम बंगाल में 30/35 साल तक राज चलाकर भाकपा (माओवादी) के कार्यकर्ता सहित अन्यान्य पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी व्यापक रूप से हत्या कर एक निरंकुश आतंक का राज स्थापित किया था।

सीपीएम और उसकी गुण्डावाहिनी हर्माद वाहिनी द्वारा पश्चिम बंगाल में चलाया गया अत्याचार की बात आज किसी से छीपी हुई नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल के बाहर झारखण्ड सहित भारत के अनेकों राज्यों में तो जनता के बीच कहने लायक इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। अगर सीपीएम मजदूर-किसान व उत्पीड़ित जनता के स्वार्थ में ही हर काम करती है तो झारखण्ड सहित अनेकों राज्यों में उसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? इस सवाल पर ही दूसरी किसी पार्टी पर कुछ टिप्पणी करने के पहले उस पार्टी के नेताओं को काफी मनन करना चाहिए। उनके कथनानुसार अगर भाकपा (माओवादी) केवल गुण्डा गिरि करती है, केवल लेवी वसूलती है तथा पैसा का लालच देकर युवक-युवतियों को लाती है और आपराधिक व अराजक काम करती है तो उन सज्जनों से एक सवाल करना शायद अनुचित नहीं होगा कि तब झारखण्ड सहित विभिन्न प्रांतों की जनता भाकपा (माओवादी) को खदेड़ क्यों नहीं दे रही है। उल्टे और कुछ नई जगहों में पार्टी कामकाज का विस्तार कैसे हो पा रहा है तथा 'ऑपरेशन ग्रीन हण्ट' का बर्बर सैनिक अभियान चलाये जाने के बावजूद जनता क्यों भाकपा (माओवादी) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ रही है, पार्टी को हर हालत में बचा रही है और शहादत देकर भी जल-जंगल-जमीन सहित तमाम आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई में कूद पड़ रही है? हमारे विचार से इस पर अनाप-शनाप टिप्पणी करने के पहले किसी के लिए भी गम्भीरतापूर्वक संबंधित सारे विषयों पर सोच लेना चाहिए।

अगर भाकपा (माओवादी) केवल आपराधिक कामकाज में ही लिप्त है तब शासक गुट और केन्द्र-राज्य सरकार, अन्य चिन्हित क्रीमीनल गुटों के

खिलाफ जो दिखावा कार्रवाई करती है, उससे सम्पूर्ण रूप से अलग एक क्रूर दमनात्मक सैनिक अभियान भाकपा (माओवादी) के खिलाफ क्यों चला रही है, क्यों हजारों करोड़ रुपए व्यय कर विशाल संख्या में नये किस्म के कमाण्डो फोर्स का गठन कर तथा अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर पूरे ग्रामीण क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दी है? माओवादी गतिविधियों के बारे में पता लगाने के लिए चालक रहित विमान का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? पहले की बात छोड़ दी जाय तो पिछले 2/3 सालों के दौरान ही क्यों भाकपा (माओवादी) के नेता व अनगिनत कार्यकर्ता तथा समर्थक जनता व आम जनता को गोली से भून दिया जा रहा है, फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या की जा रही है, गिरफ्तार कर गायब कर दिया जा रहा है, बेटा के बदले बाप अथवा भाई को अथवा पत्नी को गिरफ्तार किया जा रहा है तथा महिला आन्दोलन के नेता व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर थार्ड डिग्री टॉर्चर कर जेल के शिकंजे के पीछे झूठे मुकदमों में फंसा कर वर्षों तक डाल दिया जा रहा है? हमें उम्मीद है कि आप उपरोक्त सारे जवाबों के बारे में अपना विचार व्यक्त करेंगे।

फिर सवाल उठाया गया है कि माओवादी अंधहिंसा पर आधारित है। क्या यह आरोप सही है? अगर माओवादी हिंसा अथवा अंधहिंसा पर आधारित है तो मौजूदा राज्य-मशीनरी या शासन-तंत्र क्या अहिंसा पर आधारित है अथवा अहिंसा की पूजारी है? अगर शासन-तंत्र अहिंसा पर आधारित है तो पुलिस-मिलिटरी को भारी संख्या में वृद्धि करते हुए व अत्याधुनिक हथियारों से लैस करते हुए इतनी शक्तिशाली बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पूरी व्यवस्था को लगातार फासीवादीकरण व सैनिकीकरण क्यों किया जा रहा है? असल में जब से समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति व वर्गों का उदय हुआ तब से एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने के लिए ही राज्य-मशीनरी अथवा राष्ट्रयंत्र का उदय हुआ। कहना अधिक होगा कि हर वर्ग समाज में शोषक वर्ग शोषित वर्ग को दबाने हेतु राज्य-मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यह बात आज भी उतना ही सत्य है जितना कि अतीत में थी। इसलिए माओवादी हिंसा अथवा अंधहिंसा पर आधारित है- यह बात सत्य नहीं है। उल्टे इसकी विपरीत बात ही सत्य है। यानी शोषक-शासक वर्ग शोषित-शासित वर्ग को दबाकर रखने हेतु हिंसा अथवा अंधहिंसा पर आधारित

होकर ही राज्य–मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। एक बात में कहा जा सकता है कि बन्दूक केवल बन्दूक पर आधारित होकर ही शोषक–शासक वर्ग अपनी शोषण–शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है। मौजूदा समय में माओवादी नहीं, बल्कि सोनिया–मनमोहन–चिदम्बरम फासीवादी गुट के नेतृत्वाध ीन केन्द्र की यूपीए सरकार और झारखण्ड की शिबू–अर्जून–हेमन्त–सुदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारें ही हिंसा अथवा अंधहिंसा के पैरोकार हैं और हिंसा पर आधारित होकर ही शासन कार्य चला रही हैं।

तब सवाल उठता है कि माओवादी क्यों हथियार उठाये हुए हैं? वस्तुतः हिंसा तथा बन्दूक के अत्याचार को हमेशा के लिए खात्मा के उद्देश्य से माओवादी और माओवादी पार्टी और जनता जवाबी हथियार पकड़े हुए हैं और ऐसा हथियार पकड़ने के तरीके को हम सम्पूर्ण रूप से न्यायोचित समझते हैं और इसकी वकालती भी करते हैं। यानी हिंसा का प्रतिरोध हेतु जवाबी हिंसा, बन्दूक हाथ में लिये दुश्मन का प्रतिरोध बन्दूक हाथ में लेकर ही करना होगा– माओवादी इस सिद्धांत को मानकर इसका साकार रूप देने की कोशिश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ही जब 'घेरा डालो और विनाश करो' की मुहिम चलायी जा रही है तब उस मुहिम को पूरी तरह विफल करने के उद्देश्य से हम प्रतिरोध ी कार्रवाई करते हैं। इस कार्रवाई के दौरान कुछ पुलिस अवश्य ही मारे जाते हैं। अगर पुलिस बन्दूक तानकर जनता व जनफौज पर गोली चलाएगी तब क्या उसका सशस्त्र प्रतिरोध ना कर अहिंसा का मंत्र पाठ करना है? शोषक–शासक वर्ग के हितरक्षक पुलिस ही लड़ाकू जनता व छापामार सेना की हत्या करती है। पिछले इतिहास व अनुभव दिखाता है कि मुक्तिकामी जनता बे–वजह पुलिस को कभी नहीं मारती है। अतः 'माओवादी केवल पुलिस को मारते हैं'– यह आरोप एकदम ही यानी सौ प्रतिशत गलत व झूठा है। बल्कि भारत के नब्बे प्रतिशत जनता 'पुलिस हत्यारे है', 'पुलिस अत्याचारी है', 'जुल्मी है', 'बलात्कारी है', 'घूस खाने वाली है'– यही बोलती है। मौजूदा भारत में अमीरी–गरीबी के बीच की लड़ाई यानी वर्ग युद्ध के मैदान में शोषक–शासक वर्ग आक्रमणकारी है और जनता व माओवादी आत्मरक्षा की भूमिका निभा रही है। आत्मरक्षा खातिर हथियार पकड़ना जनता का जनवादी अधिकार है, जन्मगत अधिकार है। यहां

शासक वर्ग अन्याय युद्ध चला रहा है और आत्मरक्षा खातिर माओवादी पार्टी की रहनुमाई में जनता न्याय युद्ध चला रही है।

इसलिए "माओवादी भटक गये" से लेकर "माओवादी केवल पुलिस को मारते हैं" इत्यादि सारे प्रचार सोची-समझी पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा दुष्प्रचारों के अलावे और कुछ भी नहीं है।

दूसरा दुष्प्रचार : "माओवादी के पास विकल्प कह कर कुछ नहीं है"

जवाब : सवाल है कि अगर माओवादी के पास विकल्प व्यवस्था निर्माण करने का कोई कार्यक्रम नहीं है तो देश और ऐसाकि देश के बाहर भी भारत के माओवादी और माओवादी आन्दोलन पर इतनी चर्चाएं व पक्ष-विपक्ष में बहस क्यों चल रही है? अगर माओवादी और माओवादी आन्दोलन के पीछे अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व सामाजिक व्यवस्था, सामरिक नीति, विदेश नीति, जनता की इच्छानुसार जनता की सरकार गठन करने हेतु सबसे निचले स्तर गांव से लेकर देश के पैमाने पर एक सही चुनाव व्यवस्था की रूपरेखा, और साथ ही साथ कृषि, उद्योग, व्यापार-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, धर्मीय अल्पसंख्यकों के अधिकार, दलित उत्पीड़न व छूआछूत का खात्मा, बाल श्रम का खात्मा, बेरोजगारी समस्या का हल इत्यादि लेकर कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा तो माओवाद व माओवादी आन्दोलन पर इतनी चर्चाएं क्यों और माओवादी पार्टी मौजूदा राज्य-मशीनरी का प्रधान आक्रमण के निशाना बना हुआ है, क्यों? दरअसल, एक विकल्प व्यवस्था की स्थापना हेतु माओवादी पार्टी का एक जनमुखी, वैज्ञानिक व व्यवस्थित पार्टी कार्यक्रम मौजूद है- यह बात शोषक-शासक वर्ग और उसके चाटुकार लोगों को मालूम है। वे भलीभांति जानते हैं कि माओवादी पार्टी का कार्यक्रम लागू होने का मतलब ही है साम्राज्यवादी-सामंतवादी व दलाल नौकरशाह पूंजीवादी शोषण-शासन का खात्मा होना। वे जानते हैं कि ऐसा होने से उसका राज-पाट, ठाट-बाट, मौज-मस्ती का जीवन, सारे कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ही शोषक-शासक वर्ग और उसके दलाल राजनीतिक प्रतिनिधि सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम फासीवादी गुट आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक माओवादी है कहकर अनाप-शनाप

बक रहा है और उक्त फासीवादी गुट व विभिन्न राज्य सरकारों के संयुक्त आक्रमण का प्रधान निशाना माओवादी पार्टी व माओवादी आन्दोलन बना हुआ है।

सीपीएम की झारखण्ड राज्य कमिटी के राज्य सचिव ज्ञान शंकर मजुमदार तो भाकपा (माओवादी) को दहशत पैदा करने वाली, हिंसा बढ़ावा देने वाली, अपने ही लोगों की नृशंस हत्या करने वाली, केवल पैसा उगहने वाली, जन स्वार्थ के विरोध में काम करने वाली व जन आधारहीन एक पार्टी के रूप में दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है।

पर, सवाल उठता है कि 'अलग झारखण्ड' आन्दोलन और 'झारखण्डी जनता की अपनी भाषा व शिक्षा सहित अलग सांस्कृतिक पहचान को बचाये व बनाये रखने हेतु आन्दोलन' सहित 'शोषणमुक्त झारखण्ड' आन्दोलन की पूर्ण सफलता हेतु आत्मबलिदानी देकर संघर्ष की है तथा आज भी कर रही है कौन, भाकपा (माओवादी) अथवा 'अलग झारखण्ड' आन्दोलन का कट्टर विरोधी सीपीएम? झारखण्ड में आदिवासी व मूलवासी जनता सहित आम मजदूर-किसान व मेहनतकशों को अधिकार-बोध, आत्म-सम्मान बोध, आत्म मर्यादा-बोध, इज्जत-बोध व अस्मिता-बोध से लैस किया है कौन भाकपा (माओवादी) अथवा सीपीएम? झारखण्डी जनता की जल-जंगल-जमीन सहित आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों के लिए जारी संघर्षों के साथ ओत-प्रोत कौन है माओवादी पार्टी है या सीपीएम? झारखण्ड की खनिज सम्पदा सहित प्राकृतिक सम्पदा की लूट की खुली छूट के खिलाफ यानी कारपोरेट घरानों के साथ किये गये एमओयू के खिलाफ, एमओयू को जोर-जबरन साकार करने के खिलाफ जो लड़ाई या जन आन्दोलन जारी है, उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए माओवादी हैं या सीपीएम? सेज के खिलाफ जारी जन आन्दोलन में माओवादी पार्टी शामिल है या सीपीएम? विस्थापन विरोधी विशाल जन आन्दोलन में सक्रिय भूमिका पालन करने वाली माओवादी पार्टी है अथवा सीपीएम? मानव तस्करी खासकर लड़की तस्करी के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई करने के जन आन्दोलन के साथ जुड़ी हुई माओवादी पार्टी है या सीपीएम? दो जून रोटी की खातिर

झारखण्ड से विशाल संख्या में युवक-युवतियों के बाहर राज्यों में काम की तलाश में निकल जाने के लिये मजबूर करने (जिसे यहां 'पलायन' शब्द से परिभाषित किया जाता है) के खिलाफ जोरदार प्रतिवाद व प्रतिरोध की आवाज उठायी है कौन भाकपा (माओवादी) अथवा सीपीएम? छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट (CNTA) में फेर-बदल लाकर आदिवासी-मूलवासी का जमीन पर जो पक्का अधिकार हासिल है उससे उसे वंचित करने की साजिश के खिलाफ जोरदार प्रतिवाद की आवाज उठाने वाली माओवादी पार्टी है या सीपीएम? आम खट-कमाऊ जनता और ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी हासिल करने हेतु आन्दोलन का संचालन सीपीआई (माओवादी) करती है या सीपीएम? झारखण्ड में केन्दू पत्ता मजदूरों की मजदूरी वृद्धि (जो 10 साल पहले 20 रुपए था अभी लगभग सौ रुपए हुआ है) के लिए आन्दोलन का संचालन माओवादी पार्टी करती है या सीपीएम? पिछले दस वर्षों के दौरान झारखण्ड में बड़ा जमीन्दार-महाजन-सूदखोरों का क्रूर शोषण व जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए सामंती बोलबाला की नींव हिलाकर उनके कब्जे से हजारों एकड़ जमीन जप्त कर भूमिहीन व गरीबों के बीच बंटवारा की है माओवादी पार्टी अथवा सीपीएम? झारखण्ड के विशाल जंगल क्षेत्र से जनता पर जंगल विभाग के अफसर व जंगल सिपाही का क्रूर जुल्म-अत्याचार और मां-बहनों की इज्जत लूट व घूसखोरी इत्यादि कुकर्मों के खिलाफ जोरदार लड़ाई का संचालन भाकपा (माओवादी) की है अथवा सीपीएम? जंगल माफिया और जंगल विभाग के अफसरों के सांठ-गांठ से अवैध रूप से जंगल कटाई व जंगल उजाड़ने के खिलाफ लड़ाई लड़कर जंगल रक्षा कर रही है कौन, सीपीआई (माओवादी) अथवा सीपीएम? नेता-मंत्री-माफिया ठेकेदारों की मिलीभगत से विशाल परिमाण में जारी अवैध खनन-कार्यों को तुरन्त बन्द करने के लिये जोरदार आवाज उठाई है भाकपा (माओवादी) अथवा सीपीएम?

उपरोक्त तमाम तथ्य यही प्रमाण करता है कि झारखण्ड में एकमात्र भाकपा (माओवादी) पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखण्डी राष्ट्रीयता जनता की शोषण-मुक्ति सहित झारखण्डी जनता की अस्मिता तथा झारखण्डी सांस्कृतिक पहचान की समस्याओं को लेकर और साथ ही जनता की जीवन-जिन्दगी की

समस्याओं को लेकर, क्रूर पुलिसिया अत्याचार के बावजूद, जनता को संगठित करते हुए विभिन्न प्रकार के लड़ाइयों का संचालन किया और कुछ सफलता भी हासिल किया।

हालांकि उपरोक्त सारे कामों को करते समय हमसे यानी भाकपा (माओवादी) से कुछ भूल भी होती है। हम उसको मानते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की रचनात्मक आलोचना से हम सिखते हैं। हमारी भूल के प्रति हम सचेत व सजग हैं। भूल समझने के साथ-साथ हम बिना किसी हिचकिचाहट से सिर झुकाकर खुले रूप से जनता के सामने आत्मालोचना पेश करते हैं और सुधारों की कोशिश भी करते हैं। भविष्य में भी हम ऐसा करते रहेंगे। पर, हमारी भूल हमारा समग्र कामकाजों के गौण पहलू मात्र ही है। फिर भी भूल को भूल के रूप में मानते हुए ही हम उसे सुधारने हेतु लगातार प्रयास चलाते रहेंगे ताकि एक ही भूल की पुनरावृति न हों और अन्य प्रकार की भी भूल न हों।

संघर्षों का इतिहास बताता है कि झारखण्ड की धरती वीर सिद्धू-कान्हू, बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में साम्राज्यवाद-सामंतवाद विरोधी ऐतिहासिक लड़ाई की परम्परा से गौरवान्वित धरती है। उस गौरवशाली परम्परा से लैस झारखण्ड की जनता स्वाधीनता-कामी व मुक्तिकामी जनता हैं। आज की जल-जंगल-जमीन की लड़ाई, दरअसल अन्तर्वस्तु में, स्वाधीनता, मुक्ति, अस्मिता व आत्म मर्यादा-बोध सहित तमाम अधिकारों की प्राप्ति हेतु संचालित लड़ाई है। भाकपा (माओवादी) इन सारे पहलुओं के साथ ओतप्रोत है और रहेगी भी। चाहे ऑपरेशन ग्रीन हंट चले, गोली बरसे, खून की बाढ़ बहे अथवा अपने देश की जनता के खिलाफ युद्ध चले, अन्त तक प्रतिरोध युद्ध, न्यायपूर्ण युद्ध तथा जनयुद्ध की जीत होगी यानी जनता ही जीतेगी- यह विश्वजनीन सच्चाई है। इतिहास की इस गति को कोई नहीं रोक सकता। भारत में भी इस गति को कोई नहीं रोक सकता।

तीसरा दुष्प्रचार : "माओवादियों को मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए"

जवाब : "माओवादियों को मुख्यधारा में शमिल होना चाहिए"- तमाम संसदीय पार्टियां, मीडिया और करोड़पति-अरबपति-खरबपतियों के राजनीतिक

प्रतिनिधियों द्वारा रटा जा रहा यह एक अतिपरिचित वाक्य है। आवें इस पर हमारे विचार क्या है इस पर नजर डालें।

यह बात स्पष्ट है कि जिनलोग मुख्यधारा की बात कर रहे हैं, असल में उनलोग संसदीय क्रिया-क्लापों में यानी मौजूदा व्यवस्था की देखरेख में जो चुनाव का खेल (या तमाशा) जारी है उसमें भाग लेने की बात ही कर रहे हैं। सवाल है कि भारत में मुख्यधारा का मतलब 'चुनाव में हिस्सा लेना' ही है- ऐसी परिभाषा किसने तय की है? क्या भारत के मजदूर- किसान-मेहनतकश जनता, जिनलोग भारत की कुल लोक संख्या के नब्बे प्रतिशत होते हैं उनलोग मुख्यधारा की वैसी परिभाषा तय किये हैं? जाहिर है कि उनलोग मुख्यधारा की ऐसी परिभाषा तय नहीं किये हैं। तब कौन लोग तय किये हैं? स्पष्ट है कि भारत के दस प्रतिशत लोग जिसमें शोषक-शासक वर्ग और उसके चाटुकार लोग ही केवल अन्तर्भूक्त हैं, वे ही मुख्यधारा की ऐसी परिभाषा का बहुत प्रचार किये हैं तथा आज भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मीडिया भी वैसा प्रचार व्यापक रूप से कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि भारत के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नियंत्रण विशाल-विशाल धनी कारपोरेट घराने ही करते हैं। सरकारी प्रचार-यंत्र व प्रचार-तंत्र - इस पर भी मुट्ठीभर शोषक-शासकों का ही नियंत्रण है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत के नब्बे प्रतिशत मजदूर-किसान व मेहनतकश जनता की राय का कोई महत्व मौजूदा प्रचारयंत्र अथवा मीडिया नहीं देते हैं।

इसलिए मुख्यधारा का मतलब मौजूदा चुनाव व्यवस्था में हिस्सा लेना- हम ऐसा तर्क को सही नहीं समझते हैं। कारण है कि मौजूदा संविधान व कानून के तहत आयोजित चुनाव के जरिए भारत के नब्बे प्रतिशत जनता के वर्ग-हित का कोई प्रतिफलन नहीं होता है, न ऐसा होना संभव है। क्योंकि साम्राज्यवादी देशों के विशाल-विशाल पूंजीपति और भारत के टाटा-जिन्दल-मित्तल, अम्बानी, वेदान्ता, एस्सार इत्यादि दलाल नौकरशाह पूंजीपति - ये सारे लोग मिलकर राजनेता-मंत्री, प्रशासन, पुलिस व खुफिया विभाग के बड़े-बड़े अफसर, पार्लामेण्टरी संस्था, मीडिया, न्याय-व्यवस्था, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक अनुसंधान

(रिसर्च) केन्द्र इत्यादि सभी पर काफी नियंत्रण जमाए हुए बैठे हैं। इसलिए मौजूदा चुनाव व्यवस्था के जरिए मजदूर-किसान-मेहनतकशों के हित में अथवा उनकी भलाई के लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन है।

फिर, यह बात भी सभी को मालूम है कि यूरोप के देशों की तरह, भारत में किसी जनवादी क्रान्ति का काम सम्पन्न कर संसदीय व्यवस्था का आगमन नहीं हुआ है। यहां दूसरा विश्वयुद्ध के समय काल और उसके बाद देश-देश में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की जो लहर चल रही थी, उसी को देखते हुए प्रत्यक्ष शोषण-शासन के कायदा को बदल कर साम्राज्यवादी लोग परोक्ष शोषण-शासन का नव-उपनिवेशवादी तरीका अपना लिये और उसी समय साम्राज्यवादी साजिश के तहत चरम धोखाधड़ीपूर्ण मौजूदा संसदीय व्यवस्था को ही आज महिमामंडित करने खातिर हजारों कोशिश जारी हैं। इसलिए भारत की चुनाव व्यवस्था सौ प्रतिशत जन-विरोधी है। अतः इस चरम धोखाधड़ीपूर्ण चुनाव व्यवस्था के अन्दर अभी चुनाव में हिस्सा लेने की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना भी उचित नहीं है।

वस्तुतः पिछले 60/62 वर्षों के दौरान हुए तमाम चुनाव नतीजे का विश्लेषण किया जाएगा तो हम देख पाएंगे कि उन सभी चुनावों के दौरान मुश्किल से औसतन लगभग 50 प्रतिशत वोट ही पड़े हैं। मिसाल के लिए 15वीं लोकसभा के चुनाव में कुल पंजीकृत वोटरों में से मुश्किल से 50 प्रतिशत वोट ही डाले गये थे। फिर यह 50 प्रतिशत वोट का बंटवारा कांग्रेस, बीजेपी सहित विभिन्न वोट लड़वा पार्टियों के अन्दर ही हो जाता है। तब देखने को मिलता है कि प्रदत्त कुल वोट के अन्दर लगभग 29/30 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ वैसी पार्टी ही देश की सरकार बनाती है तथा उस पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री सहित विभिन्न मंत्री बनाते हैं। मिसालस्वरूप, 15वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस को सिर्फ कुल वोट का 29.67 प्रतिशत वोट ही मिला और बीजेपी को कुल वोट के 19.29 प्रतिशत वोट मिला। इस रूप से कांग्रेस कुल वोट के 15 प्रतिशत वोट हासिल कर साझा सरकार बनायी। इस कटु सच्चाई को ही बहुमत के शासन और जनादेश के बतौर व्यापक प्रचार किया जाता है। उपरोक्त

विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कभी भी विशाल बहु संख्यक लोगों के वोट के जरिए सरकार नहीं बनती है और न ही भविष्य में कभी बन सकेगी। अतः कहा जा सकता है कि भारत की मौजूदा चुनाव व्यवस्था के जरिए जनता के लिए सही जन प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो सकता है और ऐसा होना संभव भी नहीं है। असल में, भारत में मौजूदा चुनाव के जरिए ज्यादा से ज्यादा करोड़पति, अरबपति और कुछ अपराधी–माफिया–साम्प्रदायिक फासिस्ट लोग ही संसद व विधानसभा के सदस्य बनकर आते हैं। यह बात तो दिन के उजाला जैसे स्पष्ट है। वास्तविक तथ्य ही इस बात का अकाट्य प्रमाण है। मिसाल के लिए विगत 15वीं लोकसभा का चुनाव के दौरान 543 सांसदों में 315 सांसद करोड़पति हैं, उसमें से कुछ अरबपति भी हैं। फिर, जीत कर आए ऐसे 150 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें से 73 पर गम्भीर आरोप है जो पिछले सभी चुनावों के तथ्य को मात दिया है। हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय संस्था ग्लोबल इंटीग्रिटी द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनावी राजनीति में ध नबल को रोकने में भारत विफल साबित हुआ है। इसका ताजा उदाहरण झारखण्ड राज्यसभा चुनाव है। यहां चुनाव के दौरान रांची के ठीक बाहर में एक उद्योगपति की गाड़ी से जप्त 2.15 करोड़ के जरिए खुलेआम धनबल का इस्तेमाल देखा गया। इसके पहले भी लोकसभा में रुपए की गड्डियां लहराने जैसी घटना की बात भी देश–दुनिया के लोग अच्छी तरह से जानते हैं।

इसलिए मुख्यधारा का मतलब मौजूदा चुनाव व्यवस्था में हिस्सा लेना– यह तर्क कतई ग्रहण योग्य नहीं है। विपरीत तौर पर, मौजूदा चुनाव व्यवस्था का अन्त कर एक सही जनता की चुनाव व्यवस्था को सामने लाना बहुत जरूरी है। हमारे विचार से खूब संक्षेप में, एक सही चुनाव व्यवस्था के जरिए जन सरकार का चुनाव की रूप–रेखा निम्न प्रकार होगी : 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके समस्त व्यस्क चुनाव में हिस्सा लेंगे। चुने जाने के लिए 20 वर्ष आयु होना जरूरी है। पर, मौजूदा व्यवस्था को ज्यों के त्यों रखकर इसके अन्दर ही कभी चुनाव आयोग की भूमिका को बढ़ाकर तो कभी न्याय–व्यवस्था का हस्तक्षेप करवाकर ऐसी जनता की चुनाव व्यवस्था को सामने ला पाना कतई सम्भव नहीं। इसलिए एक सामाजिक क्रान्ति के दौरान मौजूदा व्यवस्था को सम्पूर्ण रूप से बदल कर

ही एक सही चुनाव व्यवस्था का तरीका सामने लाया जा सकता है। माओवादी वैसा ही एक जन-पक्षीय चुनाव व्यवस्था का पक्ष पोषण करते हैं। उस चुनाव व्यवस्था के जरिए गांव स्तर से लेकर क्रमशः ऊपर स्तर तक तथा राज्य व केन्द्रीय स्तर तक जनता के सही प्रतिनिधि चुन कर आ सकेंगे। और जनहित में सभी कुछ कर पाएंगे, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

अतः "माओवादियों ......मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए" भारत की ठोस स्थिति में पिछले चुनावों के अनुभवों से यह बात तर्कसंगत नहीं है तथा मौजूदा चुनाव व्यवस्था भी जनता के हित के लिए नहीं मुट्ठीभर शोषक-शासक वर्ग के हित में ही है। इस धोखाधड़ीपूर्ण चुनाव व्यवस्था को ही मुख्यधारा के रूप में प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि माओवादियों को उग्रवादी-अतिवादी के रूप में दिखाने का एक आधार मिल जा सके। इसलिए हम उक्त बातों को एक सोची-समझी दुष्प्रचार के रूप में ही देखते हैं व मानते हैं।

चौथा दुष्प्रचार : "नक्सलवादी-माओवादी उग्रवादी-अतिवादी है"

जवाब : आवें, वास्तविकता की कसौटी पर यह आरोप सही है अथवा गलत इस पर विचार किया जाए।

यह बात स्पष्ट है कि हमारी पार्टी यानी भाकपा (माओवादी) आज की दुनिया के सबसे उन्नत व वैज्ञानिक सिद्धांत मालेमा को ही अपने सारे कामकाजों का सैद्धांतिक आधार मानने वाली और जनवादी केन्द्रीयता की नीति लागू करने वाली एक पार्टी है जिसकी गांव स्तर से लेकर विभिन्न स्तरों की पार्टी कमिटी होते हुए सर्वोच्च स्तर केन्द्रीय कमिटी तक मजबूत सांगठनिक ढांचा मौजूद है। हमारी पार्टी जनता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने वाली एवं गलती होने पर तुरन्त आत्मालोचना पेश करने में अभ्यस्त पार्टी है। भाकपा (माओवादी) का एक व्यवस्थित व सुसम्बद्ध पार्टी कार्यक्रम है और एक साफ वीजन (vision) है। भारत जैसा विकासशील देश की कमजोर अर्थव्यवस्था का सार्विक विकास व उन्नति के लिए कृषि को आधार (base) व कृषि का सार्विक विकास हेतु उद्योग को प्रमुख उपादान (leading factor) और फिर उद्योग के अन्दर हल्का उद्योग को डायरेक्ट कृषि का विकास के लिए और हल्का उद्योग के लिए

जरूरत मशीनों का उत्पादन हेतु भारी उद्योग यानी कृषि, हल्का उद्योग व भारी उद्योग- तीनों के बीच एक सही तालमेल बैठाते हुए अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार पर खड़ा करने की एक स्पष्ट रूपरेखा मौजूद है। और खासकर झारखण्ड के बारे में कहने से तो लगभग 1400 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले इस राज्य के लिए उक्त तीनों पहलुओं के बीच सही तालमेल बैठाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के अलावा पशु पालन (गाय-भैंस, भेड़-बकरी, मुर्गी-बतख, सुअर आदि), मधुमक्खी पालन, रेशम-कीट पालन, बागवानी आदि उत्पादन व्यवस्था को तथा साथ ही कुटीर व लघु उद्योगों के जरिए उत्पादन व्यवस्था को भी जोड़कर अभी झारखण्ड अर्थव्यवस्था के आधार को एक मजबूत आधार पर स्थापित किया जा सकता है। तब तालमेलपूर्ण ढंग से अन्य उद्योगों का भी योजनाबद्ध तरीके से विकास करवाया जा सकता है। इसकी भी एक साफ रूपरेखा हमारे पास मौजूद है।

यह बात स्पष्ट है कि अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन से जुड़ी हुई हमारी पार्टी का लम्बा इतिहास है। हमारी पार्टी के एक सैद्धांतिक, राजनीतिक व सैनिक लाइन के साथ-साथ अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण, लिंग, राष्ट्रीयता, महिलाओं के अधिकार आदि पर सही और सुस्पष्ट नीतियां हैं। हमारा एक वैज्ञानिक-जनमुखी व उन्नत वस्तुवादी दर्शन है और एक सही विश्व-दृष्टिकोण भी है।

उल्लिखित बातों से यह स्पष्ट होता है कि माओवादी उग्रवादी अथवा अतिवादी नहीं है। बल्कि गांधीवाद अथवा अहिंसा की बात कहने वाली मौजूदा शासन व्यवस्था या राजसत्ता ही असल में हिंसा पर आधारित है। राज्य-मशीनरी के सभी अंग (यानी पुलिस-मिलिटरी, नौकरशाह, जेलखाना, न्याय व्यवस्था इत्यादि) वर्गीय दृष्टिकोण से अमीर वर्ग के हित में काम करते हैं, गरीब या शोषित-उत्पीड़ित वर्गों के हित में नहीं। पिछले 65 वर्षों के अनुभव भी हमें यही दिखाता है। भारत में गरीब-दलित- आदिवासी-राष्ट्रीयता की जनता-धर्मीय अल्पसंख्यक आज प्रतिवाद का न्यूनतम जनवादी अधिकारों से यानी रैली-जुलूस,

सभा व इच्छा के अनुसार संगठन बनाना इत्यादि से वंचित है। प्रतिवाद व प्रतिरोध की आवाज उठाने वाले अनगिनत लोग आज जेल हिरासत में बन्द पड़े हैं। इसके अलावे जेल हिरासत में मृत्यु (अथवा हत्या) की संख्या भी काफी ज्यादा है। गरीब–आदिवासी–दलित इनलोगों के लिए भारी खर्चीली न्याय–व्यवस्था में न्याय या इन्साफ मिलने की आशा करना और हवाई किले बनाना एक ही जैसी बात है।

असल में, राज्य मशीनरी या राजसत्ता का उदय एक वर्ग द्वारा दूसरा वर्ग को दबाने के लिए ही हुआ है और वर्ग समाज में शोषक–शासक वर्ग के हित में शोषित–शासित–उत्पीड़ित वर्ग को दबाने खातिर ही इस मशीनरी या सत्ता का इस्तेमाल होता है। यह एक विश्वजनीन सच्चाई है।

इसलिए बन्दूक हाथ में ली हुई सत्ता या राज्य–मशीनरी ही, सच्चे अर्थ में, उग्रवादी है, अतिवादी है। भारत में राज्य–आतंक ही शासन–व्यवस्था की जड़ है, प्रमुख पहलू है। जब जनता की एक भी जायज बात व मांग को नहीं मानी जाती है और उल्टे उन मांगों को बन्दूक के बल पर दबाया जाता है तब आत्मरक्षा खातिर हथियार पकड़ना अनिवार्य हो जाता है। अतः बन्दूक के बल पर शासन चलाना और उस बन्दूक से बचने हेतु जवाबी बन्दूक पकड़ना– दोनों एक बात नहीं है। बल्कि एक–दूसरे के विपरीत है। माओवादी आत्मरक्षा खातिर हथियार उठाने की बात को सौ प्रतिशत सही मानते हैं और ऐसा करने की वकालती भी करते हैं। इसलिए बन्दूक हाथ में लिए हुए शोषक–शासक वर्ग और उसकी राज्य–मशीनरी को जवाबी बन्दूक पकड़ कर व ध्वस्त कर ही एक नया समाज यानी जनता की जनवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। इस अर्थ में ही बन्दूक की नली से राजनीतिक सत्ता का जन्म के उसूल को हम माओवादी लोग सही मानते हैं। जवाबी बन्दूक पकड़ कर ही महान लेनिन–स्तालिन के नेतृत्व में 1917 साल की रूसी क्रान्ति सफल हुई और मजदूर राज बना और महान माओ के नेतृत्व में 1949 में चीनी क्रान्ति सफल हुई और जनता की जनवादी राज स्थापना हुई। वियतनाम, लाओस, कम्पुचिया की क्रान्ति भी उसी बात को साकार की है।

इसलिए, माओवादी को नहीं, बल्कि शोषक–शासक वर्ग को ही इस बात का प्रमाण करना चाहिए कि वे बन्दूक पर आधारित होकर नहीं, अहिंसा पर यानी बिना बन्दूक पकड़ कर शासन कार्य चला रहे हैं। अतः नक्सलवादी–माओवादी उग्रवादी–अतिवादी है– यह सरासर या बिल्कूल ही गलत प्रचार है और इसलिए यह शोषक–शासक वर्ग द्वारा चलाया जा रहा बहुत से दुष्प्रचारों में से एक प्रमुख दुष्प्रचार है।

पांचवां दुष्प्रचार : "माओवादी अपना आय के स्रोत के लिए अफीम की खेती करवा रहे हैं।"

जवाब : विरोधी लोग जब देखा कि दूसरे–दूसरे दुष्प्रचार से खास कोई फायदा नहीं हो रहा है तब 'माओवादी अफीम की खेती करवा रहे हैं' कहकर सबसे निकृष्ट किस्म के दुष्प्रचार का हथकण्डा अपनाना ही उचित समझे। सवाल है कि शासन कार्य में बैठे हुए ऊपर ओहदे के कुछ लोगों के साथ सांठ–गांठ किये बिना तथा लोकल थाना के साथ मिलीभगत के बिना इतने व्यापक इलाके में यानी कई प्रांतों में विस्तृत इलाके में कैसे अफीम की खेती हो पा रही है? इस सवाल का सही जवाब दिये बिना नक्सलवादी–माओवादी के मत्थे पर अफीम खेती का आरोप मढ़ देने से कोई भी अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि माओवादियों के लिए यह नीति का सवाल है। असल में दुनिया भर में जहां–जहां साम्राज्यवाद और खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी आम संघर्ष व क्रान्तिकारी संघर्ष काफी तीखा है वहां–वहां युवा पीढ़ियों को बर्बाद करने के उद्देश्य से एक अन्तरराष्ट्रीय साजिश के तहत अमेरिकन गुप्तचर विभाग सीआईए द्वारा कोकेन, चरस, हिरोइन, अफीम इत्यादि प्रतिबन्धित नशा का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और किया भी जा रहा है। उसी अन्तरराष्ट्रीय साजिश के तहत ही ऊपर ओहदे में बैठे हुए लोगों के एक अंश के जरिए अफीम के नशा में युवा पीढ़ी को आदत करवाने और अफीम की खेती करवाने का काम धड़ल्ले से करवाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन–पुलिस व खुफिया विभाग– इन तीनों की मिलीभगत ही प्रधान रूप से जिम्मेवार है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

फिर, मौजूदा केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों की मिलीभगत से दूर–दराज के गांव–गांव तक अंग्रेजी शराब और देशी शराब की दुकान खोलने के लिए ध ड़ल्ले से लाइसेंस दी जा रही है। इसका भी वही उद्देश्य है यानी आम गरीब मेहनतकश जनता और खासकर युवा पीढ़ी को नशाग्रस्त कर रखना ताकि वे नहीं सोच सके कि काफी मेहनत करने के बावजूद उसकी इतनी गरीबी हालत क्यों और कौन इसके लिए जिम्मेवार है? माओवादी इसका भी जबरदस्त विरोधी है और नशाखोरी के खिलाफ लगातार आन्दोलन भी चलाते जा रहे हैं। यह बात भी सभी लोग जानते हैं।

असल में सच्चाई तो यह है कि युवक–युवतियों को व्यापक पैमाने पर पीएलजीए (जन मुक्ति छापामार सेना) में भर्ती करवाने हेतु माओवादियों के लिए अफीम व अफीम खेती सहित तमाम किस्म के नशा के खिलाफ लगातार प्रचार चलाना एक अत्यावश्यक कर्तव्य है। साथ–साथ विभिन्न नशा के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिक्षा अभियान का संचालन करना भी एक जरूरी कर्तव्य होता है।

फिर, आय के स्रोत के लिए माओवादी किसानों को दबाव देकर अफीम की खेती करवाता है– यह भी सरासर झूठ है। पहले ही कहा जा चुका है कि अफीम व अफीम की खेती माओवादियों की नीति विरूद्ध चीज है और नीति विरूद्ध किसी चीज से माओवादी कभी समझौता नहीं करते हैं। जग जाहिर है कि आय के लिए हमारा तयशुदा अनेक स्रोत मौजूद है। इसलिए आय के स्रोत के लिए अफीम की खेती करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अतः माओवादियों के खिलाफ यह एक घृणित आरोप है, एक सोचा–समझा दुष्प्रचार है।

छठा दुष्प्रचार : "माओवादी पार्टी के नेता लोग लेवी के अकूत धन हासिल किये हैं और उस पैसे से विभिन्न शहरों में आलीशान भवन बनाये हैं तथा अपने लड़के–लड़कियों को विदेश भेजकर अध्ययन करवाते हैं, इत्यादि–इत्यादि।"

जवाब : माओवाद–विरोधी प्रतिक्रियावादी तत्वों द्वारा हमारे खिलाफ यह एक पुराने व अतिपरिचित दुष्प्रचार है जो बीच–बीच में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते रहता है। सभी को मालूम है कि भारत तथा दुनिया के सबसे

ज्यादा धनकुबेर लोग ही मीडिया के मालिक होते हैं। इसलिए मीडिया वैसे धनकुबेर (या विशाल-विशाल बड़ा पूंजीपति) लोगों के वर्ग हित में ही संचालित होता है तथा धनकुबेर लोगों के पास भारी मात्रा में वेतन व अन्य सुख-सुविधा पाने की लालच में कलम बेच दिये हैं ऐसे कतिपय तथाकथित नामी-गिरामी पत्रकार कहलाने वाला व टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला कतिपय नामी-गिरामी (ऐंकर-मैन, ऐंकर-वोमैन कहलाने वाला) व्यक्ति ही उल्टा-सीधा प्रचार कर आम जनता को गुमराह करते हैं, दिगभ्रमित करते हैं। इनलोगों के द्वारा प्रचारित बात ही ज्यादा मात्रा में मीडिया में हावी रहती है। मीडिया के साथ जुड़े हुए ज्यादा पत्रकार व टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले जिनलोग प्रगतिशील व जन-पक्षीय होते हैं उनलोगों के द्वारा प्रचारित, सही बातें सामने आ नहीं पाती हैं। अगर कभी काल कुछ सही बातें आती भी हैं तो उसकी उतनी तरजीह नहीं मिलती है।

हम चाहते हैं और जनता भी चाहती है कि माओवादियों के खिलाफ अथवा माओवादी नेताओं के खिलाफ कोई भी आरोप या बातें सबूत के साथ कहा जाए अथवा पेश किये जाएं। ऐसा न हो कि आरोप हवा में ही सैर करते रहे। चाहे आरोप शहरों में आलीशान बिल्डिंग बनाने का हो अथवा आरोप विदेश भेजकर बच्चों को पढ़ाने का हो अथवा दो-चार ट्रक, बस, बोलेरो का मालिक होने का हो, अथवा बहुत बड़ा बिजनेस (या कारोबार) का मालिक होने का हो इन सारे आरोपों को तथ्यों के साथ पेश किये जाएं।

हमारे विचार में भारत के पिछले दो सौ साल के इतिहास पर नजर दौड़ाने से साम्राज्यवाद व सामन्तवाद के खिलाफ हुए बहुत से विद्रोह जैसे- सन्यासी विद्रोह, चौवाड़ विद्रोह, महान सिद्धू-कान्हू हूल, महान बिरसा मुण्डा उलगुलान और फिर 1857 के महान सिपाही विद्रोह, शहीद-ए-आजम भगत सिंह विद्रोह, नेताजी का आजाद हिन्द फौज विद्रोह, वीर खुदीराम सहित ऐसे अनेकों महान देश भक्तों के आत्म बलिदान और 1946-48 का हैदराबाद निजामशाह के खिलाफ महान तेलंगना क्रान्तिकारी आन्दोलन- इन सभी आन्दोलनों से जुड़े हुए नेता, कर्मी व योद्धा यानी इन सारे सच्चे देश भक्तों के खिलाफ साम्राज्यवाद-सामन्तवाद व उनके चाटुकार व चमचे लोगों ने तत्कालीन समय में

भी डाकू, दस्यु, अवैध धन हासिल करने की दुष्ट इच्छा रखनेवाले लूटेरे, राज का कानून न मानने वाले दुष्ट व्यक्ति, नारी यातनाकारी इत्यादि विभिन्न दुष्प्रचारों के जरिए व्यापक जनमत को भ्रमित करने का नाकाम प्रयास किया है। इतिहास गवाह है कि धन-दौलत, नाम-यश के लिए नहीं, बल्कि, भूख-प्यास व चरम गरीबी हालत में रहकर केवल देश को लूटेरा शोषक-शासकों के कब्जे से मुक्त करने हेतु वे सबसे प्यारा व मूल्यवान प्राणों को भी न्यौछावर करने में जरा-सा भी नहीं हिचकिचाएं। देश प्रेम की इससे बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती है। आज हालत ऐसा है कि इतिहास में इनलोगों के असीम योगदान को केवल दिखावा रूप से दो/चार लाइन के अन्दर ही सीमित कर दिया गया है। जबकि कुछ वीरों के नामों को तो इतिहास के पन्ने में जगह तक नहीं मिली है। महान सिद्धू-कान्हू, बिरसा मुण्डा के बचे हुए परिवार के लोग तो आज भी काफी सम्मानहीन व गरीबी हालत में है और किसी प्रकार से दिन गुजर-बसर कर रहे हैं। शोषक-शासक वर्ग व उसके चमचे व चाटुकार लोगों द्वारा आज के सच्चे देश-प्रेमी, जनवादी, प्रगतिशील व समाज व्यवस्था का आमूल परिवर्तन चाहने वाले तत्वों को भी वही पुराने कायदे के दुष्प्रचारों के जरिए ही यानी लूटेरा, डाकू, धन कमाने में व बिल्डिंग बनाने में व्यस्त, बच्चों को विदेश में रखकर शिक्षित करने में व्यस्त इत्यादि आरोपों से आरोपित करने का नाकाम प्रयास चलाया जा रहा है।

जबकि सच्चाई इसकी विपरीत बात को ही प्रमाणित करती है। थोड़े ही दिन पहले प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार सोनिया गांधी अकूत धन के मालकिन है। नेहरू परिवार के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो फिर देखा जाएगा कि मोतीलाल नेहरू के बेटा जवाहरलाल इंगलैण्ड से बैरिस्टरी पास कर आए; जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी विदेश से पढ़कर आयी; फिर, इंदिरा जी के दो बेटे राजीव व संजय भी विदेश से कुछ न कुछ अध्ययन कर आए; और राजीव-सोनिया के बेटी व बेटा भी विदेश से अध्ययन पूरा कर ही आए हैं। फिर देश के पिता कहलाने वाले गांधी जी ने भी विदेश में ही बैरिस्टरी पास की है। प्रधानमंत्री मनमोहन और जंगबाज चिदम्बरम भी विदेश से ही अध्ययन पूराकर अब देश की जनता को अपने बच्चों को यहीं पढ़ाने के लिए उपदेश देते रहते हैं। अभी कांग्रेस-बीजेपी से लेकर बाकी किसी भी पार्टी के शायद ही

ऐसा कोई नेता है जिनके बेटा-बेटी विदेश से अध्ययन कर अपनी मातृभाषा भूलकर फुटानी करने वाली भाषा अंग्रेजी में बात न करता हो। मूलायम जी के बेटा हो अथवा लालू जी के अथवा आंचलिक पार्टी के नेता हो सभी कोई बेटा-बेटी को विदेश में रखकर ही पढ़ाना पसंद करते हैं। पर, सभी कोई देश की जनता को ज्ञानगर्भ भाषण देकर देश के अन्दर ही स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई करने को कहते हैं। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? इधर, ग्रामीण क्षेत्र में जहां 65/70 प्रतिशत जनता रहती है, वहां तो स्कूल ही नहीं है, अथवा टूटा हुआ स्कूल भवन है तो शिक्षक नहीं है और अभी तो पिछले 3/4 साल के दौरान भारत के पांच/छः प्रांतों में माओवाद विरोधी ऑपरेशन ग्रीन हंट अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्कूलों को पुलिस कैम्पों में तब्दील कर दिया गया है।

पुनः दूसरा एक पहलू पर कुछ सवाल उठाना यहां प्रासंगिक ही होगा, जैसे- नेता-मंत्री-एम.पी, एम.एल.ए. - इनलोग और इनलोगों के बच्चों का इलाज विदेश के अच्छा से अच्छा हॉस्पीटल में ही होता है, देश में क्यों नहीं? प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी तथा अन्यान्य मंत्री व नेता लोगों का इलाज अगर विदेश से ही करवाया जाएगा तो देश के लोगों को यहां ही उपदेश देने का उनलोगों का अधिकार क्यों रहेगा? क्या ये सब देश प्रेम के नमूने हैं? क्या ये सब देश की जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं है? जनता ही विचार करें।

अब और एक बिन्दू पर देखा जाए। क्या विभिन्न शहरों में आलीशान भवन माओवादी नेताओं के हैं अथवा भारत के केन्द्रीय व विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्री-एम.पी.-एम.एल.ए. सहित विभिन्न नेताओं के हैं? अभी तक विभिन्न दैनिक अखबारों में अवैध धन व आलीशान मकान व जमीन इत्यादि पर इतने तथ्य निकल गये हैं कि इस पर इस लेख में ज्यादा चर्चा करना बेकार साबित होगा। स्वीस बैंक में भी कितने लाख करोड़ कालेधन जमा है वह भी आज देश की जनता के सामने साफ है। अतः ज्यादा चर्चा की कोई जरूरत नहीं है।

अन्त में एक बात कहना जरूरी है और वह यह कि 1974 में जेपी आन्दोलन के समय भी जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि भारत में केन्द्र व राज्य की गद्दी पर आसीन किसी भी पार्टी के नेता हो और खासकर केन्द्र

में आसीन शासक पार्टी के नेता लोग इनमें कोई भी नि:स्वार्थ भावना रखने वाला तथा सच्चा देश प्रेम रखने वाले नहीं हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। पर, भारत में दो ही प्रकार के लोग हैं- जिनलोग अपनी धन कमाई अथवा नाम-यश, सुख्याति के लिए नहीं; देश के लिए, देश की जनता के लिए सोचते हैं और कुछ करते भी हैं। इनमें से एक हैं सर्वोदय पंथी जो नि:स्वार्थ देश सेवा करते हैं; दूसरा हैं नक्सलवादी लोग, जिनके मार्ग से वे (जयप्रकाश जी) सहमत नहीं थे, पर नक्सलवादी देश के लिए नि:स्वार्थ भावना से काम करते हैं, और जरूरत पड़ने पर प्राणों की आहुती देते हैं- ऐसा मानते थे।जेपी जी की ऐसी टिप्पणी के बारे में उल्टा-सीधा लिखने वाले व बोलने वालों को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

जयप्रकाश जी की टिप्पणी इसलिए यहां दिया गया कि अभी की युवा पीढ़ी इस बात की जानकारी रखें ताकि वे समझ जाएं कि भ्रष्टाचार के महासागर में डूबे हुए नेता-मंत्री लोग उनका प्रचारयंत्र व तंत्रों का इस्तेमाल कर जिन दोषों में वे खुद दोषी व अपराधी है, वे ही माओवादी के खिलाफ उक्त प्रकार के दुष्प्रचार चलाकर जनमत को गुमराह करने का नाकाम व पागलपन प्रयास चला रहे हैं। अत: नि:संदेह कहा जा सकता है कि उक्त बातें माओवादियों के खिलाफ चलाये जा रहे विभिन्न दुष्प्रचारों में से ही एक है।

हम मजदूर-किसान, मेहनतकश, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध नागरिकों के पास विनम्र अपील करते हैं कि माओवादियों को बदनाम करने हेतु उनके खिलाफ एक सोची-समझी पॉलिसी के तहत चलाये जा रहे तमाम दुष्प्रचारों का भण्डाफोड़ व खण्डन करें तथा ऐसे घृणित हथकण्डे की तीव्र निन्दा व कठोर भर्त्सना करें।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ

पूर्वी रीजनल ब्यूरो

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
सेंट्रल रीजनल ब्यूरो

19-7-2012

शोषित जनता के शुभचिंतक और अथक योद्धा
कामरेड बीएसए सत्यनारायण को लाल सलाम!

कामरेड बीएसए सत्यनारायण (72), जिन्होंने दशकों से शोषित जनता के पक्ष में रहकर संघर्ष किए और आंध्रप्रदेश के जन संघर्षों के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई थी, 22 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भाकपा (माओवादी) के एक सदस्य के रूप में इन्होंने क्रांतिकारी लाल परचम को हमेशा बुलंद रखा। कामरेड बीएसए को इस अवसर पर हमारी पार्टी, पीएलजीए और तमाम जन संगठन तहेदिल से लाल सलाम पेश करती है। हम उनके शोक संतप्त परिजनों और दोस्तों को अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और यह शपथ लेते हैं कि हम क्रांतिकारी आन्दोलन को आगे ले जाते हुए उनके सपनों को साकार करेंगे।

बोम्माकान्ति श्री अजंनेय सत्यनारायण जो बीएसए के नाम से लोकप्रिय हैं का जन्म 1940 में पश्चिम गोदावरी जिला के अत्तिली में एक कम्युनिस्ट परिवार में हुआ था। रेलवे डाक कर्मचारी के रूप में उन्होंने उस समय के डाक तार विभाग में कार्यरत हुए और 1950 के दशक के अंत में वह हैदराबाद आए। नक्सलबाड़ी आन्दोलन से प्रभावित होकर वह डाक तार कर्मचारी आन्दोलन के नेता के रूप में सामने आए। उनके साथी शहीद कामरेड यू श्रीनिवासलु और अभी जेल में कैद कामरेड एलएसएन मूर्ति के साथ मिलकर उन्होंने कर्मचारियों और मजदूरों के कई संघर्षों का नेतृत्व किया। हैदराबाद के सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और केन्द्र सरकार के दफ्तरों के अलावा कर्नुल और आदोनी जैसे शहरों के मजदूर वर्ग के बीच उन्होंने क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार किया। वक्ता की हैसियत से वह राज्य के हर कोने में मई दिवस के कार्यक्रमों में उत्साह के साथ हिस्सा लेते थे। 1974 के रेलवे हड़ताल और 1980 के दशक

के डाक तार हड़ताल, जो देश के सबसे बड़े हड़ताल के रूप में जाने जाते हैं, में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

मजदूर वर्ग के बीच काम करने के साथ–साथ कामरेड बीएसएन ने 1970–75 के दौरान हैदराबाद में छात्र, नौजवान और लेखकों के सभाओं को आयोजित करने में भी अपनी सक्रिय सहयोग दिया। नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम संघर्ष में आए गतिरोध के बाद क्रांतिकारी आन्दोलन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का भी वह महत्वपूर्ण हिस्सा बने।

अपातकाल के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और बेरहमी के साथ यातनाएं दी। दो महीने के कैद के बाद वह रिहा हुए। प्रबंधन जो संघर्षों में उनके भूमिका के वजह से बदला लेने के लिए पहले से ही तैयार थी, उनके गिरफ्तारी का बहाना बनाकर उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया। गिरफ्तारी, यातना और प्रबंधन द्वारा किए गए उत्पीड़िन के बावजूद उनके क्रांतिकारी उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मार्क्सवादी शिक्षक के रूप में वह पूरे राज्य में घुमकर राजनीतिक कक्षाओं के जरिए पार्टी और जन संगठन के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से लैस करने में अहम भूमिका निभाई। वह मार्क्सवादी दर्शन और मजदूर संघर्ष के इतिहास के बारे में पढ़ाते थे। 1984 में जिस घर में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक कक्षा का आयोजन किया गया था और जहां कामरेड बीएसए भी शिक्षक के रूप में मौजूद थे, पुलिस ने हमला किया और सभी गिरफ्तार कर लिया। षड़यंत्र का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक पूर्णकालीन मार्क्सवादी शिक्षक के तौर पर काम किया और कार्मिक पथम (मजदूरों की राह) जैसे क्रांतिकारी पत्रिकाओं के प्रकाशन में अपना योगदान दिया।

1990 में फिर से वह डाक विभाग में कार्यरत हुए। साथ ही उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी शुरू कर दी और जल्द ही वकील बन गए। एक वकील के रूप में उन्होंने राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। नागरिक अधिकार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। लगातार मेहनत किया और यहां तक कि गांवों में जाकर भी जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता दी। वह उन चंद वकीलों में से हैं जिन्होंने चन्द्रबाबु नायडु

और राजशेखर रेड्डी के शासन काल के दौरान किए गए भंयकर पुलिसिया दमन और हत्यारे गिरोहों और निजी सेनाओं के आतंक के बीच भी निर्भय होकर क्रांतिकारियों और जनता को कानूनी मदद की। एक अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में भेजने के बाद केवल वकील के मौजूदगी में ही पूछताछ करने का जो नियम है पुलिस इसका कभी पालन नहीं करता था। कुछ क्रांतिकारियों से पूछताछ के दौरान इस निमय का पालन करने के लिए उन्होंने पुलिस को मजबूर किया। जीवन के शेष तीन दिन वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ महिला साथी कामरेड सीताक्का और उनके साथ गिरफ्तार हुए अन्य कामरेडों के साथ थे जब उन्हें पुलिस पूछताछ के लिए ले गए। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि गिरफ्तार साथी पुलिसिया दमन और यातनाओं का शिकार न बनें। इसी तरह उन्होंने बहुत से क्रांतिकारियों को पुलिस के यातनाओं से बचाया। एक वकील के रूप वह जज और सरकारी वकील के सामने कड़वे सच्चाइयों को पेश करते थे और यहां तक कि अदालत के अवमानना से भी नहीं कतराते थे।

उन्होंने 'श्रमजीवी' नाम से एक मजदूर पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। मजदूर संघर्ष के नेता और वकील के रूप में उनके अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस पत्रिका को मजदूरों के सच्चे हमराही और पथ प्रदर्शक के रूप में विकसित किया। इस पत्रिका के लिए उन्होंने कई अहम लेख लिखे। पिछले कुछ समय से वह राजनीतिक बंदी रिहाई कमेटी (सीआरपीपी) के आन्ध्रप्रदेश विभाग के उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय थे। खराब स्वास्थ्य के बावजूद वह राजनीतिक बंदियों के रिहाई और उनके उत्साह बढ़ाने के लिए आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जेलों में उन्हें मिला करते थे। राजनीतिक बंदियों के मामलों की जल्द सुनवाई और फैसले के लिए वह हर संभव कोशिश करते थे।

अपने जीवन के लंबे समय तक जन संगठनों में काम करने वाले और जनता के बीच में रहकर दृढ़ता के साथ लड़ने वाले कामरेड बीएसए सत्यनारायण एक अध्ययनशील व्यक्ति और लेखक थे। नौकरी से निलंबन, अदालत के अवमानना के नाम पर उत्पीड़िन, आर्थिक समस्या, खराब स्वास्थ्य

– कुछ भी उनके राजनीतिक एकनिष्ठा को कम नहीं कर पाए। कई बेहतरीन प्रमूल्यों और आदर्शों को आत्मसात किए और अपने जीवन तथा व्यवहार में अपनाए। भूखे पेट रहने पर भी वह कभी अपने आदर्शों और क्रांतिकारी राजनीति के साथ समझौता नहीं किए। सम्पत्ति या सुविधाओं के लिए उन्होंने कभी परवाह नहीं किया और एक साधारण जीवनशैली अपनाए। उनका यह जीवनशैली जनता और पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए एक उदाहरण रहेगा। 1970 के दशक के क्रांतिकारी मजदूर संघर्ष के कुछ नेता और कामरेड बीएसए जैसे कुछ अंशकालीन पार्टी सदस्य हफ्ते में तीन दिन लगातार ओवर टाइम काम करने के बाद बाकी के तीन कार्य दिवसों में और छुट्टियों में पार्टी के लिए काम करते थे। इस तरह से जनता की सेवा में कड़ी मानसिक और शारीरिक मेहनत करके इन साथियों ने जिस कम्युनिस्ट आदर्श का मिसाल रखा यह हर पार्टी सदस्य अपनाने योग्य है।

आज की इस परिप्रेक्ष्य में, जब भारत सरकार जनता के उपर एक चौतरफा युद्ध चला रहा है इस आदर्श जन नेता जिन्होंने दृढ़ निष्ठा के साथ बिना समझौता किए हमेशा जनता के पक्ष में खड़े रहे, इनके व्यवहार से सीखना और उसे अपने व्यवहार में लागू करना जनता के लिए, जनसंगठनों के लिए तथा जनवादी संघर्षों के लिए और भी अधिक जरूरी बन जाता है। हमारी पार्टी यह दृढ़ विश्वास रखती है कि कामरेड बीएसए सत्यनारायण के दिखाए आदर्श और एक निष्ठता और जुझारू संघर्षशील हौसले को अपनाकर तमाम क्रांतिकारी जन संगठन जन संघर्षों में और भी सक्रिय भूमिका निभाकर उनके शहादत से हुए क्षति को पूरा करेंगे।

- dkejsM ch,l, vej jgsA
- 'kghnksa ds vjekuksa dks lkdkj djks!
- ekDlZokn&ysfuuokn&ekvksokn ftUnkckn!
- lozgkjk varjk"Vªh;rkokn ftUnkckn!

आनन्द

सचिव & सीआरबी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

20-9-2012

दुनिया के मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का निंदा करो!

हाल ही में अमेरिका की मुसलमान विरोधी और प्रतिक्रियावादी एक इसाई धार्मिक कट्टरपंथी गुट ने 'मुसलमानों की बेगुनाही' (Innocence of Muslims) नाम से वीडियो फिल्म तैयार किया। इसे इंटरनेट के विभिन्न वीडियो शेयरिंग वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया जिसमें पैगम्बर का अपमान कर पूरे दुनियाभर के मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया। इसके खिलाफ विश्व के अलग–अलग जगहों पर मुसलमानों ने लिबिया से लेकर टुनिशिया और वहां से थाइलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर भारत तक व्याप्त होकर खासकर उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया और अरब देशों में विशाल विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं पर अमेरिकी साम्रज्यवादियों के इस सांस्कृतिक हमले का घोर निंदा करती है और अमेरिकी सरकार तथा उस फिल्म के निर्माताओं से विश्व के मुसलमानों के सामने बिना शर्त माफी मांगने मांग करती है।

9/11 के समय से ही अमेरिकी साम्राज्यवाद दुनियाभर के मुसलमानों को तथाकथित 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के नाम पर तेजी से अपना निशाना बनाता आ रहा है। यह हमला सिर्फ राजनीति, सामरिक, अर्थनीतिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हो रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद और इसके मित्र शक्तियों की इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का स्वरूप ईसाई धार्मिक कट्टरवाद और अबुगरीब जैसे यातना गृह के खौफनाक मंजर से

लेकर अभिव्यक्ति के अधिकार के आड़ में फिल्मों और कार्टूनों के जरिए पैगम्बर, कुरान आदि मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों के ऊपर हमला और अपमान तक शामिल हैं। इस सांस्कृतिक हमले का मकसद है मुसलमानों को मानसिक रूप से आहत करना और उन्हें गैर बराबरी का अहसास दिलाना, ताकि वह साम्राज्यवादी आक्रमण और आतंक के खिलाफ युद्ध के तहत उन पर हो रहे ज्यादातियों का प्रतिरोध न कर सकें। लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवादियों का हिसाब पूरी तरह से गलत निकला। मुसलमानों के हौंसले को तोड़ने के लिए किया गया हर अपमान का जवाब विशाल विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आ रहा है। इसीलिए इस फिल्म में सांस्कृतिक मसले पर आज तक होने वाले विश्व के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। यह विरोध जुलूसों, प्रदर्शनों, अमेरिकी झण्डे का दहन और साम्राज्यवादी सम्पत्तियों का तोड़फोड़, अमेरिकी राजसत्ता के प्रतीकों तक हमले से लेकर अमेरिकी दुतावासों पर हमला तथा राजदूत तक हत्या व्यापक रूप से हुआ।

यह समझने की जरूरत है कि इस अभूतपूर्व जन सैलाब का उभार केवल पैगम्बर के अपमान का ही परिणाम नहीं है। अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा मुसलमान जनता पर – खासकर इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जनता पर – किए गए तमाम तरीके के जुल्मों सितम के खिलाफ नफरत का ही इजहार है। साथ ही अमेरिका से इज्राइल राज्य को फिलिस्तीनी जनता पर दमन के लिए मिल रहा खुला समर्थन और हर तरह के मदद भी इन विरोधों का एक अप्रत्यक्ष कारक है। इन विरोध प्रदर्शनों को एक विशेष धार्मिक समुदाय का मजहबी मसला के रूप में सीमित कर देखना गलत होगा। एक व्यापक प्ररिप्रेक्ष्य में हमें इस गोलबंदी को दुनिया के अवाम का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के एक मजबूत कड़ी के तौर पर समझना होगा जो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी लड़ा जा रहा है। प्राकृतिक संशाधनों से भरपूर अरब और उत्तरी अफ्रीका के देशों तथा तेल अर्थनीति से जुड़ा खाड़ी का इलाकों पर कब्जाकर नवउपनिवेशिक शोषण व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से अमेरिका और नाटो द्वारा छेड़ा गया साम्राज्यवादी युद्ध इन विरोधों का एक मुख्य कारण है।

मुसलमान बहुसंख्यक इन देशों की जनता के प्रतिरोध को विफल करने के लिए जानबूझकर किए गए सोची समझी इस्लाम विरोधी अमेरिकी दुष्प्रचार की वजह से ही इन प्रदर्शनों ने धार्मिक रूप अपनाया।

अपने साम्राज्यवाद परस्त चरित्र का परिचय देते हुए इन देशों के दलाल शासकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां, आंसू गैस, लाठी और गिरफ्तारी का कहर बरपाकर इन विरोधों का दमन करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। दशकों से इन शासक वर्गों ने साम्राज्यवाद के पालतू कुत्ते की भूमिका अदा किया है और दूसरी तरफ अपने ही देश की जनता पर निरंकुश तानाशाही का हुकूमत चलाया है। मसलन, एक ऐसे समय जब अमेरिकी ड्रोन अफगान गांवों को तबाह कर रहा है और हर रोज सैकड़ों बेकसूर लोगों का कत्लेआम कर रहा है, जब दुनिया के समूचे मुसलमान समुदाय इस फिल्म के रूप में हुए अमेरिकी सांस्कृतिक हमले का पुरजोर विरोध कर रहा है, ठीक उसी समय हामिद करजई यह ऐलान करता है कि 'आतंक के खिलाफ युद्ध' जरूर जारी रहना चाहिए और ओबामा से यह गुहार लगाता है कि इस जंग को बस अफगान गांवों में न लड़ा जाए। साम्राज्यवाद के द्वारा सारे दुनिया के मुसलमानों पर किए गए तमाम अत्याचार और उत्पीड़िन के लिए इस तरह के दलाल उतने ही जिम्मेदार हैं वह इस तरह के साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हमले के समय मुसलमान जनता के इज्जत और अस्मिता का कभी ख्याल नहीं करेंगे बल्कि इन्हें कुचलने की कोशिश करेंगे। शोषित जनता ही आखिरकार इन गद्दारों का पर्दाफाश करेगी।

विरोधों के तीव्रता और व्यापकता से हैरान अमेरिकी सरकार ने हाल ही में 70 हजार डालर खर्च कर विज्ञापन के जरिए ओबामा और हिलेरी क्लिटंन का यह संदेश प्रचार किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से ही सभी धर्मों का सम्मान करता आया है। यह रोष बढ़ते हुए बवंडर को रोकने का एक नकाम कोशिश ही था।

यह साफ है कि इस फिल्म का निर्माण कोई व्यक्ति ने अपने मनमर्जी के मुताबिक नहीं किया है। यह अमेरिकी सरकार और उसके मित्र शक्तियों द्वारा

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित, प्रायोजित और समर्थित इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार तंत्र का अभिन्न अंग है जिसे आतंक के खिलाफ युद्ध में उपयोग किया जा रहा है। मुसलमान जनता के धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर किया गया अपमान के सिलसिले में – जिनके तहत पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों ने कुरान का दहन किया – यह ताजा घटना है। इस प्ररिप्रेक्ष्य के बगैर न यह फिल्म तैयार किया जाता और न ही इसको असानी से व्यापक प्रचार हासिल होता।

अमेरिकी सरकार के विशाल खुफियातंत्र के रहते यह मान लेना कि वह इस फिल्म के निर्माण और प्रचार के बारे में अनजान था, या तो नादानियत हो सकता है या फिर धोखा। इतने व्यापक विरोध के बावजूद अमेरिकी सरकार ने फिल्म के निर्माताओं को गिरफ्तार करने, और इसके पश्चात प्रदर्शनों को रोकने या मुसलमान जनता से माफी मांगने जैसी कोई भी कदम नहीं उठाया है। जनता को धोखा देने तथा अपने लिए और अधिक समय हासिल करने के उद्देश्य से वह इस फिल्म के ढुलमुल और नाम मात्रा के लिए निंदा कर रहे हैं। साथ में सभी धर्मों को सम्मान करने का दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन इतिहास और कुछ ही कहती है जो इस दावे का संपूर्ण विपरीत है। इसके अलावा लिबिया जैसे देशों के नागरिकों को उस देश की ही सरकार और सेना से रक्षा करने के बहाने अमेरिका आज साम्राज्यवादी हमला तेज कर रहा है, अपनी सेना भेज रहा है।

मुसलमान जनता अमेरिकी साम्राज्यवाद के तरकीबों से इतनी अपरिचित नहीं है कि इन करतूतों को न पहचान पाए। यही कारण है कि अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्र देशों के विरूद्ध हर दिन विश्व के अलग–अलग कोने से शांतिपूर्ण तथा हथियारबंद संघर्ष पनप रहे हैं। पश्चिमी साम्राज्यवादियों का मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया – या फिर साम्राज्यवादी निरो जैसा व्यवहार – का झलक इससे मिलता है कि जब इस फिल्म की वजह से पूरा दुनिया दहक रहा था, तभी फ्रांस की एक पत्रिका ने पैगम्बर को अपमान करते हुए बीस कार्टून प्रकाशित किए। इसके

तुरंत बाद फ्रांस ने विरोध प्रदर्शनों का अंदेशा करते हुए बीस देशों में अपने दूतावास बंद कर दिए। लेबनान के हसन नसरूल्ला – जिनको अमेरिका समर्थित इज्राइली हमले का लेबनान के तरफ से सफल प्रतिरोध का नेतृत्व करने का श्रेय है और जो साम्राज्यवाद विरोधी के रूप में जाने जाते हैं – जैसे नेताओं के आह्वान पर दुनिया भर में पैगम्बर के अपमान के विरोध में नए प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ है।

हर जनवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना चाहिए और विशेषकर इस्लाम के अनुयायिओं को निशाना बनाकर किया जा रहा अमेरिकी और यूरोपीय साम्राज्यवादियों का सांस्कृतिक हमलों का निंदा करना चाहिए। धार्मिक भावनाओं को अघात करना इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का एक मुख्य पहलू है। अक्टोपस रूपी इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के पंजो को – जो एशिया, आफ्रिका और लातिन अमेरिका के देशों जन संस्कृति (भाषा, कला, खान–पान, रहन–सहन इत्यादि) का गला घोंटने का कोशिश कर रहा है – पर्दाफाश और प्रतिरोध भी इन प्रदर्शनों के जरिए करना होगा। अमेरिकी सरकार और फिल्म के निर्माताओं से बिना शर्त माफी की मांग करने के साथ–साथ इन प्रदर्शनों को व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों में तब्दील करना होगा, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो अपनी भौगोलिक राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने और उत्पीड़ित देशों के तेल और अन्य प्राकृतिक संपदाओं पर कब्जा जमाने के लिए इन देशों के मुसलमान जनता को निशाना बना रहा है। इसी तरह साम्राज्यवाद का व्यापक और सार्थक प्रतिरोध हो सकता है।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

21-9-2012

खुदरा व्यापार, असामरिक विमान परिवहन, विद्युत और दूरसंचार क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग करो!

भारत के दलाल शोषक वर्गों और संसद में बैठे साम्राज्यवाद के पालतू कुत्तों को हमारे देश की संप्रभुता को बड़े विदेशी निवेशकों के हाथों बेचने की प्रक्रिया का प्रतिरोध करो!

14 सितम्बर को केन्द्र सरकार की केबिनेट में लिए गए एक फैसले के मुताबिक मल्टीब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51%, सिंगल ब्राण्ड में 51% से ऊपर, असामरिक विमान परिवहन में 49%, विद्युत वितरण में 49% और डायरेक्ट टू होम डीटीएच सहित दूरसंचार क्षेत्र में 49–74% की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। साथ ही इस फैसले के खिलाफ हुए व्यापक विरोध को दरकिनार कर इसको तात्कालिक रूप से अमल में लाने के लिए 20 सितम्बर को एक अध्यादेश भी जारी किया। 10 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में अब विदेशी निवेशक अपना खुदरा दुकान खोल पाएंगे और बाकी प्रदेशों की सरकारें यह फैसला ले पाएंगे कि इसे लागू करना है या नहीं। सामान के पैकेट में लिखा 'राष्ट्र हित' में जारी मानो यह विधिवत चेतावनी है – प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सभी क्षेत्रों में आने वाला है, यह 'शुभारंभ' हमारे देश के अंत का शुरूआत है, प्रतिरोध करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही जले पर नमक छिड़कने की तरह डिजील का भाव 5 रूपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है।

जबकि सब्सीडि में दिए जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डर की संख्या प्रति परिवार वार्षिक 6 तक सीमित कर दी गई है।

विपक्षी दलों ने इस निर्णय के खिलाफ 20 सितम्बर को 'बंद' का आह्वान किया। लेकिन इनके इतिहास से पता चलता है कि जिन–जिन राज्यों में ये पार्टियां सत्ता में हैं या रहे हैं, सभी में इन्होंने साम्राज्यवाद परस्त नीतियों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं। इससे यह साफ पता लगता है कि नवम्बर 2011 की तरह इस बार भी इन संसदीय पार्टियों का विरोध मजह दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। यूपीए, एनडीए या विपक्ष के नाम से प्रचलित इन गुण्डा गिरोहों के बीच में कोई फर्क नहीं है। इस भद्दा संसदीय नाटक में ये दलाल अपने–अपने भूमिका अदा कर लेने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भव्य आगमन होगा। करोड़ों छोटे खुदरा व्यापारियों और किसानों को अपने पैरों तले रौंदते हुए भारत के दलाल शोषक वर्गों के बिछाए लाल कालीन पर से चलकर विदेशी खुदरा निवेशकों का देश के कोने–कोने में प्रवेश होगा। सम्प्रभुता का हनन तो बस एक छोटा सा मुल्य है। इसके वजह से खुदरा व्यापारियों और किसानों की आत्महत्या की दर में जो भारी इजाफा होने जा रहा है उस कोलेट्रल डैमेज को तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से होने वाले 'अर्थनीतिक विकास' के आगे कुरबान करना ही होगा।

एक नियम के अनुसार खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को राज्यों में लागू करना है कि नहीं यह राज्य सरकारों को तय करना है। इससे यह तय है कि कांग्रेस शासित राज्यों में तुरंत इसे लागू किया जाएगा। अकाली दल ने भी बेशर्मी के साथ इस निर्णय के पक्ष में होने का घोषणा किया है। बाकी पार्टियां भी धीरे–धीरे कांग्रेस की इस नीति के साथ पिछले दरवाजे से हाथ मिलाएगी, क्योकि इन दलाल पार्टियों ने अपने–अपने राज्यों में जहां भी सत्ता में हैं वहीं साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वार्थ को हर क्षेत्र में पूरा करने के लिए तत्पर हैं। त्रिणमूल कांग्रेस ने बहुत ही बेमन से यूपीए–2 सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन साथ ही यह भी इशारा कर रहा है कि इन फैसलों में केन्द्र सरकार की तरफ से कुछ छूट मिलने से –

जैसे डिजिल की दर में 2–3 रूपये की कमी, सब्सीडी प्राप्त गैस सिलेण्डरों की संख्या में बढ़ोत्तरी या मल्टीब्राण्ड रिटेल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कुछ प्रतिशत की कमी – से वह फिर से सरकार को समर्थन देगी। खास इसी मामले पर बातचीत के लिए हिलेरी क्लिंटन ममता बनर्जी से मिली और हैरानी नहीं होगी वह भी अपने राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कालीन बिछा दे। सवाल सिर्फ इस बात का है कि यह निर्णय वह किस समय लेंगे – चुनाव, सत्ता जैसे 'जरूरी' पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मुलायमसिंह का बयान जिसमें बोला गया है कि साम्प्रदायिक ताकतों को मौका नहीं देने के लिए ही उनकी पार्टी यूपीए–2 से समर्थन वापस नहीं लेंगी, सरासर झूठ है। दिल्ली हूकमत के इन सरगनाओं को न ही 4–5 करोड़ छोटे खुदरा व्यापारियों (और उन पर निर्भर 15–20 करोड़ जनता) का फिक्र है जो अपनी रोजी–रोटी खोने जा रहे हैं और न ही उनके पास हैं प्रतिरोध के लिए जरूरी रीड की हड्डी। यह बात गौर करने की है कि संशोधनवादी सीपीआई और सीपीआईएम समेत कोई भी पार्टी न खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को लागू करने के निर्णय को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं और न ही इसे सम्पूर्ण रूप से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनकी मिलिभगत की यही सबसे बड़ी सबूत है। इन पार्टियों के तथाकथित विरोध और बंद का आह्वान और धरना–प्रदर्शनों का मकसद है अपने–अपने शासनाधिन राज्यों के लिए केन्द्र से और मोटी रकम हासिल करना जिसे वह निगल सकें या केन्द्र सरकार के नियंत्रण में रहने वाले करोड़ों रूपये के रिश्वतखोरी और भष्ट्राचार के अनगिनत मामलों को ठण्डा करवा सकें।

वर्ल्ड आफ वर्क 2011 का रिपोर्ट आने वाले समय के लिए रोजगार के क्षेत्र में प्रतिकूल माहौल का भविष्यवाणी कर रहा है। 150 देशों में किए गए एक समीक्षा का निर्ष्कष है कि दुनियाभर में अर्थ सामाजिक असुरक्षा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दावा खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष निवेश से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, छलावा के सिवाए और कुछ नहीं है। वालमार्ट और टैस्को जैसे बड़े खुदरा कम्पनियों ने अमेरिका तथा दुनियाभर के जिस भी देश में कदम रखा वहीं भारी मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न किए। वालमार्ट का सिर्फ

एक दुकान 13 हजार छोटे खुदरा दुकानों और 4 हजार नौकरियों को बर्बाद कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हरेक नियुक्ती के पीछे कम से कम 20 नौकरियों की नुकसान होगी। भारत जैसे एक पिछड़े देश में एक व्यक्ति के आमदनी पर उनके परिवार के कितने लोग निर्भर रहते हैं इसका हिसाब आप खुद लगाइए और इससे जो तस्वीर उभरेगी वह प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं वह ऐसे सुन्दर होने के बजाए बहुत ही भयानक होगी। बहुत ही मामूली संख्या में जो भी इस क्षेत्र में निकलेगी वह भी सामयिक, कम मजदूरी के, कमरतोड़ मेहनत वाला तथा अरसुक्षित होगा और यह लंबे संघर्षो के बाद हासिल किया गया श्रम कानूनों और अधिकारों का उल्लंघन करेगा। अमेरिका तथा यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के मुखिया आज तेजी से बढ़ती बेरोजगारी की समस्या और इससे जुड़ी उनके जनविरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ चल रहे विरोध को कैसे निपटा जाए इसको लेकर परेशान हैं। भारत में आज मंडरा रहे सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जन्म और पालन–पोषण इन्हीं 'विकसित' देशों में हुआ था। यह हमारे देश में रोजगार के अवसर कैस उत्पन्न करेंगे जब वह अपने ही देश में इस क्षेत्र में बुरी तरह से नकाम हो रहे हैं? 'आर्ट आफ लाइंग' के गुरू हमारे प्रधानमंत्री यह सोचते हैं कि हम भूल गए कैसे ओबामा अपने जत्थे के साथ व्यापार करारनामों पर हस्ताक्षर कराने भारत आए और उन्होंने कैसे अमेरिकी नागरिकों के लिए ज्यादा नौकरियों का भारत में इंतजाम कर लिया है इस बात की गुणगान करते हुए अपने देश लौट गए। अमेरिकी राष्ट्रपति आखिर क्यों नौकरियों की तलाश में दुनियाभर का दौरा कर रहे हैं अगर उनके ही देश के वालमार्ट, टेस्को, केरीफोर और मेट्रो जैसे खुदरा व्यापार की कम्पनियां नौकरियों का बौछार कर सकते हैं? इन जैसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों हमारे देश बुलाकर 'हमें हमारे मुश्किलों से छुटकारा दिलाने' से पहले क्यों न प्रधानमंत्री उनके अमेरिकी आकाओं से पहले इन विराटकाय मोनोपोली कम्पनियों के दिवालीया को रोकने का आग्रह करते, इसके बावजूद कि इन कम्पनियों को अनगिनत बेल ऑउट पैकेज उपलब्ध कराये जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री का यह कहना खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के प्रवेश से कृषि में मध्य भोगियों का भूमिका खत्म हो जाएगा और किसानों के मुनाफे में

बढ़ोत्तरी होगी, एक भद्‌दा मजाक है। इन बड़े खुदरा कम्पनियां ही किसान क्या उत्पादन करना है, क्या बीज रोपना है, क्या रासायनिक खाद और कीटनाशक इस्तेमाल करना है, यानी उत्पादन के हर पहलुओं को ही नहीं तय करेगी, बल्कि बाजार में अपना वर्चस्व कायम कर लेने के बाद किसानों के मुनाफे में भी भारी कटौती करेंगी। वह किसानों को एक ही किस्म के फसल उगाने के लिए मजबूर करेंगे। इसके वजह से रोजमर्रा के जिन्दगी के लिए जरूरी सारे सामान ज्यादा भाव पर खरीदने के लिए किसान बाजार पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा। पर्यावरण की विस्तृत क्षति करने के अलावा यह उपजाउ जमीन को भी बंजर बना देगा। इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम यही होगा कि छोटे और मध्यम किसान इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे और कृषि इनके लिए एक घाटे का सौदा बन जाएगा। वह अपने जमीन को कार्पोरेट कृषि उद्योगों के हाथों बेचकर खुद भिखारी बनने पर मजबूर हो जाएंगे। यह प्रक्रिया पहले से ही देश में मंडरा रहे कृषि संकट को और भी गहरा बना देगा तथा किसानों के आत्महत्या और असंतोष, दोनों में तेजी लाएगा। इन बड़े कम्पनियों द्वारा बेचे जाने वाले सामानों को 30 प्रतिशत स्थानीय रूप से आपूर्ति करने का प्रावधान भी एक बड़ा धोखा है। क्योंकि इन दुकानों के खरीद बिक्री की देखरेख करने के लिए देश में कोई भी व्यवस्था लागू नहीं है। भविष्य में इस तरह के कोई व्यवस्था बनने का प्रक्रिया भी रिश्वतखोरी से खत्म कर दी जाएगी या डब्ल्यूटीओ इस प्रावधान के उल्लंघन का कोई न कोई जरिया निकाल ही लेगा।

लेकिन हां एक पहलु पर प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही है उत्पादक और उपभोगता की बीच की बड़ी लंबी और जटिल कड़ी का हिस्सा बनकर जो लाखों–करोड़ों मध्यभोगी अपना रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मुनाफा भी कमा रहे हैं उनको खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश खतरे में डाल देगा। हम उन्हें मध्यभोगी कहें या कुछ और, सामानों को उपभोगता तक पहुंचाने के लिए जरूरी इस जटिल प्रक्रिया में अनगिनत लोंगो की योगदान रहती है। सवाल है उनके जगह अब कौन लेंगे और कौन उनके गंवाए हुए 'मुनाफे' को हस्तगत करेंग? किसान तो कतई नहीं उपभोगक्ताओं को भी

इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि देश का खुदरा बाजार एक बार इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े पूंजीपतियों के हाथ चले जाने के बाद उत्पादों के कीमत आसमान छूने लगेंगे। उसके बाद से तो इन कम्पनियां ही यह तय करेंगी कि उपभोक्ताओं को क्या खाना, पीना, पहनना, देखना और सुनना चाहिए। (यह भी एक तथ्य है कि दुनिया में कहीं भी इन दुकानों में उपलब्ध सामान का कीमत कभी कम नहीं हुए हैं।) ये तो संसद और प्रदेशों के विधानसभाओं में बैठे 'बड़े मध्यभोगी' हैं जो हमारे देश को पानी के भाव बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेचकर अपना तिजोरी भरने के उतावले व्यापारियों के जैसे पेश आ रहे हैं। इससे होने वाले मुनाफे के सबसे बड़ा हिस्सा देश के अंदर जाएगा दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों को जो अपने पूंजी को खुदरा व्यापार में लगाए गए विदेशी विनियोग तथा इस तरह के अन्य नीजि कारोबारों के साथ मिलकर नियोजित करेगा। जब पूरी दुनिया में ही मोनोपोली का बोलबाला है तो क्यों न मध्यभोगी के व्यापार में भी छोट–मोटे चोर उछक्कों और पाकेटमारों को भगाकर इन बड़े बहुराष्ट्रीय सेठों द्वारा एकाधिकार कामय किया जाए? अमेरिका के बदौलत भारत आखिर सुपर पावर जो बनने जा रहा है!

वित्तमंत्री चिदम्बरम ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि वह विनियोजन के जरिए 30 हजार करोड़ रूपये इकठ्ठा करेंगे और वित्तीय घाटा नामक उस राक्षस को जिससे निपटने के बहाने प्रधानमंत्री विदेशी पूंजी निवेश को न्यौता दे रहे हैं, को नियंत्रित करेंगे। जाहिर है चिदम्बरम को उनके अमेरिकी मालिकों ने कुर्सी पर इसीलिए बिठाया है ताकि वह 'कुशलता' के साथ इस तरह के 'आर्थिक सुधारों' को अंजाम दे सके। लेकिन 30 हजार रूपये ही क्यों? क्यों न कुछ बड़ा सोचा जाए? कैसा होगा अगर पूरे भ्रष्टाचार उद्योग का ही विनियोजन कर दिया जाए जो आज सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला सरकारी इकाई बन गया है और हमारे सम्माननीय मंत्रियों के सकुशल हाथों में अरबों रूपये का खजाना पहुंचा रहा है? या फिर आईपीएल के ही एक सीजन को क्यों न रद्द कर दिया जाए? और नहीं तो कम से कम 2जी घोटाला (एक करोड़ 75 हजार करोड़ रूपये) या उससे थोड़ा ही बड़ा कोयला ब्लॉक आबंटन घोटाला (2 लाख करोड़ रूपये) को ही विनियोजित किया जाए?

विदेशी बैंको में जमा किए गए 80 लाख करोड़ रूपये (एक हिसाब के मुताबिक) पूरा के पूरा नहीं तो एक चौंथाई को भी वापस लाने के बारे में चिदम्बरम का क्या ख्याल है? गाली बंधुओं या जगन मोहनरेड्डी जैसे खदान माफिया के मुनाफे को स्थाई रूप से नहीं तो बस एक साल के लिए जब्त कर हमारे देश के 'महानुभवी प्रधानमंत्री' स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान और रोजगार – जिसके नाम से वह हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जहर पिलाना चाहते हैं – इन सबके लिए जरूरी रकम को मुहैया करा सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री जिन्दल, मित्तल जैसे दलाल पूंजीपतियों के परिवारों के उपयोग में एक सिलेण्डर के बाजए केवल दो वर्षों के लिए महीने में एक सिलेण्डर सीमित करने के लिए कह पाएंगे ताकि अभी के 'सिलेण्डर संकट' से उभर सकें? क्या इनके एंटिला जैसे आलिशान मकानों पर किए गए करोड़ों रूपए के फिजुलखर्ची पर प्रतिबंध लगाकर इन पैसों को माल गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिससे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जादुई छड़ी से ही तैयार कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री का यह भी मानना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को न्यौता देना आज हमारी अर्थनीति जिस मुश्किल हलात से गुजर रहें हैं उससे निकलने के लिए जरूरी और भारत को विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बनाकर 'राष्ट्रीय हित' की रक्षा की जा सकती है। लेकिन हमारे प्यारे देश भारत में ही जब विश्व के सबसे कीमती प्राकृतिक सम्पदाओं में से अनेकों उपलब्ध हैं तथा इनके मानव संशाधन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े संख्या में ही नहीं बल्कि अपार सृजनशीलता से भी भरपूर है? अगर इन सम्पदाओं को बड़े जमींदार, दलाल नौकरशाह पूंजीपति और उनके साम्राज्यवादी मालिकों के शोषण के चंगुल से मुक्त कर देश की जनता को देश की विकास के लिए इस्तेमाल करने दिया जाए तो हम न तो वित्तीय घाटा और न ही आर्थिक संकट के समस्याओं से ग्रसित होगें।

आज समय की मांग विनियोजन नहीं मांग है संसद में बैठे गुण्डे गिरोहों से उस क्षमता को छीन लेना (जो असल में 'गैर कानूनी' रूप से सत्ता पर

कब्जा किए हुए हैं क्योंकि उनको जनता के एक चौथाई भाग का भी समर्थन हासिल नहीं है और उनको हमारे देश के करोड़ों लोगों का भाग्य निर्णय करने का कोई अधिकार या योग्यता नहीं है) जिसके बलबूते पर भारत के शोषक वर्ग देश के एक सौ दस करोड़ जनता जिनमें बहुसंख्या मजदूर, गरीब किसान, शहरी मेहनतकश और मध्य वर्ग से हैं, का जीवन और आजीविका को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं। हमें मुश्किल दौर से उभरने के लिए विदेशी निवेश की जरूरत नहीं बल्कि साम्राज्यवादियों को अपने आर्थिक संकट से, जिसके गिरफ्त में वह 2008 से ही घिरा हुआ है, हमारे देश के व्यापक और कीमती संशाधनों की जरूरत है।

हमारे मुश्किल दौर का कारण देश एक आकर्षक विदेशी निवेश का गंतव्य स्थान नहीं बन पाना बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है बड़े जमींदारों और दलाल बड़े पूंजीपतियों का शोषण तथा इनके द्वारा हमारे देश की सम्प्रभुता को साम्राज्यवादियों के हाथों गिरवी रखना जिसके वजह से साम्राज्यवाद हमें हर तरीके से लूट खशोट रहा है।

देश के प्यारे जनता, जनवाद पंसद नागरिकों और देश प्रेमियों!

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने के लिए सोनिया– मनमोहन –प्रणब –चिदम्बरम –आहलुवालिया–रंगराजन गिरोह द्वारा दिए जा रहे उलटफेर दलीलों को पर्दाफाश करों और सिरे से खारिज करो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खुदरा व्यापार और अन्य क्षेत्रों में अनुमति देने के निर्णय को वापस लेने की मांग करो। विपक्षी दलों का, जिनमें से ज्यादातर बहुत दिनों से इस निर्णय को अपने दल द्वारा शासित राज्यों में लागू करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे हैं, विरोध नाम पर किए जा रहे ढोंग का पर्दाफाश करो। खुदरा व्यापार क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उन्मुक्त करने की निर्णय कोई आम निणर्य नहीं है। यह सरकार की आज तक के सबसे बड़े नए उदारीकरण की आर्थिक निर्णय साबित हो सकती है जो देश के बहुसंख्यक जनता के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। हमारा देश, जो पहले से ही नई उपनिवेशिक शोषण, लूट और नियंत्रण का शिकार है, इस निर्णय के बाद जल्द ही एक

गुलाम देश में तब्दील हो जाने का रास्ता खुल जाएगा। हमारे जीवन के कोई भी पहलु या क्षेत्र इस निर्णय से अनछुए नहीं रहेंगे। क्योंकि जीवन के हर पहलु बाजार से तेजी से जुड़ रहा है। आइए, इस निर्णय से हमारे देश की जनता पर मंडरा रहे खतरे को समझें और इसका पुरजोर प्रतिरोध करें। सच्चे देशप्रेमियों को हम आगे आकर देश के सम्प्रभुता को लालची साम्राज्यवादी लुटेरों के पंजों से मुक्त करने के अपील करते हैं।

अभय

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

30-9-2012

सत्यमूर्ति का कैसे मुल्यांकन करना चाहिए?

कम्भम ज्ञाना सत्यमुर्ति, जिन्होंने भारत के नवजनवादी क्रांतिकारी संघर्ष के इतिहास में पहले एक प्रगतिशील भूमिका अदा किया, बाद में एक क्रांतिकारी भूमिका तथा शेष चरण में एक विघटनकारी का भूमिका निभाया – का 17 अप्रैल 2012 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके मौत पर अलग–अलग लोगों ने अपने–अपने वर्गीय दृष्टिकोण और वर्ग स्वार्थ के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त किया। किसी–किसी ने शिवसागर के नाम से उनके क्रांतिकारी रोमांटिक साहित्य और दलित साहित्य के लिए उनके योगदान को सराहा, तो किसी ने एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उनके तारीफों के पुल बांध दिए। किसी और ने उन्हें जातिय–वर्गीय क्रांतिकारी नेता मानकर प्रशंसा किया, तो कोई और उन्हें शोषित, दलित जनता के मुक्ति दाता तथा बहुजनों के मसीहा के रूप में पेश किया। उनमें से कई प्रशंसकों ने – जिन्होंने सत्यमूर्ति के दलित आन्दोलन और साहित्य के क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों का गुणगान किया – हमारे क्रांतिकारी आन्दोलन पर झूठों और विकृत 'तथ्यों' के आधार पर मनगढ़ंत आरोप लगाए और अपवाद फैलाया। इन लोगों ने या तो जानबूझकर सत्यमूर्ति के असली चरित्र और विघटनकारी के रूप में उनके अंतिम चरण (क्रांतिकारी चरण के बाद) की जीवन में भूमिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया या फिर उसे छुपाये रखा। कुछ लोगों ने उनको एक क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी कवि या दलित आन्दोलन के नेता–कवि के रूप में अभिवादन किया। लेकिन उनके जीवन के शेष 25 सालों के अवसरवादी विघटनकारी कार्यकलाप तथा क्रांतिकारी संघर्ष के प्रति इस दौरान उनके रवैये के बारे में चुप्पी साध ली। इसी प्रक्षापट में हमें देर से ही सही इस विज्ञप्ती को जारी करना पड़ रहा है।

सत्यमूर्ति ने उनके लंबे जीवन के दौरान एक दशक तक छात्र, नौजवान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पहले एक कम्युनिस्ट राजनीति के समर्थक के रूप में प्रगतिशील भूमिका अदा किया। नक्सलबाड़ी के बाद वह क्रांतिकारी आन्दोलन के एक कार्यकर्ता के भूमिका में विकसित हुए और करीबन दो दशकों तक मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी के नेता के रूप में क्रांति में योगदान किया। उसके बाद के ढाई दशक वह एक विघटनकारी कार्यकर्ता बनकर क्रांति के खिलाफ काम किया। इस प्ररिप्रेक्ष्य में हम सत्यमूर्ति का मूल्यांकन कैसे करें?

igyk i;k; % केजी सत्यमूर्ति का जन्म आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिला के एक मध्य वर्गीय दलित परिवार में 1931 को हुआ। अपने छात्र जीवन में वह कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए और छात्र संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान किया। पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने छात्र, नौजवान और साहित्य के क्षेत्र में काम किया और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। उन्होंने दैनिक 'विशाल आंध्र' और युवा पत्रिका 'युवजन' में भी कार्यरत रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वह हिस्सेदारी करते थे और इसके लिए गाने भी लिखते थे। इस पूरे समय के दौरान वह एक कवि और लेखक के रूप में कारगर रहे। एक बुद्धिजीवी के भूमिका में उन्होंने अलग–अलग कार्य क्षेत्रों में प्रभावशाली काम किए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के 1964 में विभाजन के बाद वह भाकपा (मार्क्सवादी) के साथ जुड़े रहे, लेकिन इसमें उनका कोई भरोसा नहीं था।

nljk ;k Økfrdkjh i;k; % सत्यमूर्ति के जीवन का यह पर्याय नक्सलबाड़ी के क्रांतिकारी किसान संघर्ष से शुरू होकर 1980 के दशक के मध्य तक चला। 1960 के दशक के दौरान काजीपेट के सेन्ट गेब्रियलस् हाई स्कूल के शिक्षक के रूप में काम करते हुए उन्होंने छात्र, युवा, शिक्षक, मजदूर आन्दोलनों में कोण्डापल्ली सीतारामय्या के साथ मिलकर निभाया हुआ भूमिका बहुत ही सराहनीय है। नक्सलबाड़ी राजनीति से प्रभावित होकर दोनों ने रीजनल इंजिनियरिंग कालेज से लेकर विभिन्न छात्र संगठनों में क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को विकसित किए और वरंगल जिला के किसानों से भी

कार्यकर्ताओं को तैयार किए। कुछ ही समय के अन्दर ही उनका कामरेड चारू मजुमदार सहित बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ। सत्यमूर्ति ने कोण्डापल्ली के साथ मिलकर तेलंगाना के वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम आदि जिलों में भी नक्सलबाड़ी सशस्त्र विद्रोह के तुरंत बाद शुरू हुए श्रीकाकुलम क्रांतिकारी सशस्त्र किसान संघर्ष जैसे आन्दोलन खड़ा करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाए। इसी सिलसिले में कामरेड चारू मजुमदार के नेतृत्व में आन्ध्रप्रदेश राज्य के नेतृत्वकारी कामरेडों के साथ गुत्थीकोण्डा बिलम में 1969 को हुए बैठक में उन्हें राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य के रूप में चुन लिया गया। 1970 के शुरूआत में हुए 11वीं राज्य पार्टी सम्मेलन में वह राज्य कमेटी के सदस्य चुने गए। तेलंगाना रीजनल कमेटी के सदस्य के तौर पर उन्होंने कुछ दिनों तक खम्मम में गुरिल्ला दस्तों को नेतृत्व किया। आंध्रप्रदेश में शुरू किए गए साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रांतिकारी जन संगठनों के गठन में भी उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1972 को कामरेड चारू मजुमदार से मिलने गए आंध्रप्रदेश की पार्टी प्रतिनिधि मंडल के वह भी एक सदस्य थे। उस समय जब पार्टी एक बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रही थी, तभी नवम्बर 1972 में खम्मम से वह गिरफ्तार हुए और 5 साल से अधिक समय जेल में बिताए। नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम आन्दोलनों के दौरान पार्टी द्वारा अपनाए वाम अति क्रांतिकारी रणनीतियों की वजह से आए गतिरोध से उभरने के लिए कोण्डापल्ली सीतारामय्या द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों का भी उन्होंने जेल से ही समर्थन किया। साथ, इन आन्दोलनों पर हो रहे फासीवादी दमन और पार्टी नेतृत्व के एक हिस्से में उभरे दक्षिणपंथी अवसरवादियों द्वारा किए जा रहे विघटनकारी कार्यों – जिनकी मात्र खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था – के खिलाफ संघर्ष में भी उन्होंने साथ दिया। जनदिशा के आधार पर पार्टी और आन्दोलन के पुनर्निर्माण के लिए उस समय कोण्डापल्ली ने जो प्रयास किए उसे भी सत्यमूर्ति ने समर्थन किया।

1978 में जेल से रिहा होने के बाद एक राज्य कमेटी सदस्य के रूप में उन्होंने फिर से क्रांतिकारी आन्दोलन को नेतृत्व करना शुरू किया। जनदिशा को अपनाने के बाद पार्टी के नेतृत्व में उभरे जगित्याल–सिरसिला,

करीमनगर–आदिलाबाद क्रांतिकारी किसान आन्दोलनों को विकसित करने में भी सत्यमूर्ति एक अहम भूमिका निभाई। इन किसान आन्दोलनों का धीरे–धीरे राज्यव्यापी आन्दोलनों के रूप में हुए विकास और कुछ जगहों पर फिर से शुरू हुए छात्र, युवा, साहित्य–आलोचना तथा मजदूर आन्दोलनों का जल्द ही राज्य स्तर के आन्दोलन में तब्दील होने में सत्यमूर्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी के प्रतिनिधी मंडल के सदस्य के बतौर वह भाईचारा क्रांतिकारी संगठनों के साथ एकता वार्ताओं में भी शामिल हुए। भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) के गठन में और बाद में इसके एक नेता के रूप में उनका योगदान रहा। 2 जनवरी 1982 को भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के सचिव कोण्डापल्ली सीतारामय्या के गिरफ्तारी के बाद सत्यमूर्ति ने पार्टी के सचिव का पद संभाला। इस तरह, एक उत्पीड़ित सामाजिक प्रेक्षापट से आने वाले सत्यमूर्ति ने भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी जिम्मेदारी को हाथ में लिया। इससे पार्टी के सदस्यों, क्रांतिकारी जनता और क्रांतिकारी शिविर उत्साह और प्रेरणा से भर गए।

सत्यमूर्ति ने अपने छात्र जीवन से ही साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। नक्सलबाड़ी राजनीति अपनाने के बाद उनके क्रांतिकारी व्यवहार और इससे जुड़ा उनके साहित्य कर्म ने उन्हें एक महान कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। शिवसागर के नाम से लिखे गए कविताओं से उस समय के आंध्रप्रदेश की युवा पीढ़ी बेहद प्रभावित थे। अपने लेखन से तेलुगु साहित्य के क्षेत्र को एक जबर्दस्त झटका देने वाले और इसमें एक नई धारा का जन्म देने वाले सत्यमूर्ति एक महान कवि थे। उस समय के महान क्रांतिकारी कवियों में सबसे प्रमुख कवि के रूप में वह प्रसिद्ध हुए।

लेकिन पार्टी सचिव की जिम्मेदारी लेने के बाद पार्टी और क्रांतिकारी आन्दोलन का कुशल नेतृत्व करने में वह दयनीय रूप से नकाम रहे। 1982 और 1985 के बीच में वह जब पार्टी के सचिव के रूप में कार्यरत थे, उस समय वह पार्टी कार्यकर्ताओं के विश्वास जीतने में असफल रहे। अपने जीवन के अधिकतर समय उन्होंने प्रचार क्षेत्र में बिताए। प्रत्यक्ष रूप से पार्टी कमेटियों को

नेतृत्व करने का अनुभव उन्हें नहीं था, विशेषकर उच्च स्तर के कमेटियों को। वैचारिक सिद्धांत को वह रचनात्मक तरीके से व्यवहार में लाने में विफल रहे। इस वजह से वह उस समय पार्टी के केन्द्रीय कमेटी या राज्य कमेटी और क्रांतिकारी आन्दोलन को उचित रूप से नेतृत्व नहीं कर पाए। अपने कमियों को विनम्रता से स्वीकार करने, व्यवहार से सीखने और आन्दोलन को सामूहिक नेतृत्व करने में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। छह बुराइयों (गैर सर्वहारा रूझान) जो उस समय के आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी में पनपी, उनमें भी पाया गया। 1984 में कोण्डापल्ली के रिहाई के बाद उनके द्वारा इन गलत रुझानों को सही करने के प्रयासों को सत्यमूर्ति ने तहेदिल से समर्थन नहीं किया बल्कि झूठे प्रतिष्ठा और केरियरज्म से प्रेरित होकर साजिशों और चतुराई के माध्यम से केन्द्रीय कमेटी और पार्टी के अंदर अपना गुट बनाकर पार्टी में फूट डालने की कोशिश की। इस खतरे को भांपकर केन्द्रीय और राज्य कमेटियों के साथियों ने तथा पार्टी अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें और उनके गुट में शामिल तीन केन्द्रीय कमेटी सदस्य जो पार्टी मंचों पर एक गुट की तरह काम करते थे (पार्टी के राज्य कमेटी बैठक और राज्य प्लीनम में) का तीखा आलोचना किया। लेकिन अपनी गलतियों को समझकर उन्होंने आत्मालोचना करने से इंकार किया। इसके अलावा, 'दो लाइन संघर्ष' नाम पर और पार्टी को दक्षिणपंथी अवसरवाद के खतरे से बचाने के बहाने उन्होंने अपने विघटनकारी गतिविधियों और षड़यत्रों में तेजी लाई। उस समय हमारी पार्टी ने क्रांतिकारी संघर्ष को आंध्रप्रदेश के चारों कोनों तक तेजी फैला दिया था और इसे एक मजबूत आन्दोलन के रूप में विकसित कर लिया था। मुक्तांचल स्थापित करने के उद्देश्य से आन्दोलन दण्डकारण्य तक विस्तृत हो गया। एक ऐसे समय में जब क्रांतिकारी आन्दोलन वहां के आदिवासियों को एकजुट कर आगे बढ़ रहा था, सत्यमूर्ति गुट द्वारा पार्टी के अंदर लाए गए वैचारिक, राजनीतिक और सांगठनिक संकट ने पार्टी को गंभीर लेकिन सामयिक रूप से क्षति किया। पूरी पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद केन्द्रीय कमेटी की गतिविधियां सम्पूर्ण रूप से रूक गई और अंत में इसे भंग किया गया। एक क्रांतिकारी केन्द्र के दिशानिर्देश के बगैर ही राज्य कमेटी अलग से काम करता रहा। फलस्वरूप,

सितम्बर 1987 में हुए आंध्रप्रदेश राज्य पार्टी के 13वीं सम्मेलन ने सत्यमूर्ति को पार्टी से बहिष्कार किया। इस तरह से पार्टी के आम कार्यकर्ताओं और राजनीतिक रूप से सचेत संघर्षशील लोगों ने सत्यमूर्ति गुट के विघटनकारी और विघ्नकारी प्रयासों तथा इनके गलत वैचारिक और राजनीतिक मत, गलत सांगठनिक कार्यशैली जिसे वाम लफ्फाजी के आड़ में स्वार्थपूर्ण अभिप्राय से पेश किया गया था उसे ध्वस्त किया। सत्यमूर्ति ने इस प्रकार अपनी क्रांतिकारी भूमिका को खुद–ब–खुद खत्म किया और पार्टी को विघ्नीत करने के भूमिका में सामने आए। इतिहास के कूड़ेदान में इस तरह सत्यमूर्ति का पतन हुआ।

rhljk i;kl; ;k Økfr fojk/kh i;kl; % यह प्रयास शुरू होता है उस समय से जब सत्यमूर्ति ने केन्द्रीय कमेटी के अंदर अपना गुट तैयार कर पार्टी में अंदरूनी संकट पैदा किया और यह उनके पार्टी से बहिष्कार किए जाने के बाद से ठोस रूप से पार्टी विरोधी पर्याय में तब्दील हो गया। इस पूरे दौर में उनका मुख्य लक्ष्य था पार्टी के नेतृत्व में चल रहा क्रांतिकारी संघर्ष के खिलाफ और हमारे नेतृत्वकारी साथियों पर गलत आरोप लगाना, झूठे आलोचना करना और निराधार दावों को प्रचार करना, पार्टी विरोधी मुहिम चलाना। ऐसी कोई आलोचना, आरोप, झूठे इल्जाम या मनगंढ़त गलती नहीं है जिसे उन्होंने हमारी पार्टी के नेतृत्व पर और क्रांतिकारी आन्दोलन पर नहीं थोपा हो। ऐसी कोई झूठ और ऐसी कोई अभियोग नहीं जिसे उन्होंने हमारे खिलाफ नहीं जाहिर किया हो। एक शब्द में कहें तो उन्होंने दुश्मन के स्वर से स्वर मिलाकर पार्टी नेतृत्व पर जहर बरपाया और कीचड़ उछाले। अंत तक वह यही करते रहे, हालांकि अलग–अलग समय में अलग–अलग मुखौटा पहनकर।

सत्यमूर्ति के मृत्यु के प्ररिप्रेक्ष्य में कुछ दलित और अन्य लेखकों ने मन में जो भी आया लिखकर उनका गुणगान किया और साथ–साथ हमारे पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। सच्चाई तो यह है कि सत्यमूर्ति और अन्य अवसरवादियों ने दलित बहुजनों के मुक्ति के नाम पर अवैज्ञानिक सिद्धांतों वर्गविहीन राजनीति का वकालत किया जो हर दिन जघन्य ब्राह्मणवादी पादानुक्रमिक

जाति व्यवस्था के शिकार हैं और जिन्हें इस समाज में पीढ़ियों से चरम शोषण और दमन सहन करना पड़ रहा है। जाति जो भारतीय समाज का एक विशिष्टता है इसे उन्होंने वर्ग के विपरीत खड़ा किया और वर्ग संघर्ष के राजनीति को दरकिनार किया। इस तरह वर्ग संघर्ष को और उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों को उन्होंने व्यापक क्षति पहुंचाया। पिछले साढ़े तीन दशकों से तीखी वर्ग संघर्ष में हिस्सा लेकर और अनेकों कुर्बानियां देकर हमारी पार्टी आंध्रप्रदेश में जाति उन्मूलन के लिए साहस के साथ लड़ रही है। पार्टी के नेतृत्व में ही विकसित हुए क्रांतिकारी संघर्ष की वजह से सिर्फ आंध्रप्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में दलित, महिला, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक सहित सभी उत्पीड़ित जनता आत्म सम्मान के साथ सर उठाकर अपनी जिन्दगी जी रहे हैं। कारमचेडु, चुन्डूरू जैसे गांवों में अमानवीय हिंसा और जनसंहार को अंजाम देने वाले ऊंचे जाति के खूंखार जमींदारों को कोई सत्यमूर्ति या कोई नकली नेता जो आज उनके प्रशंसा में व्यस्त है, ने नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने उचित सजा दिया। हमारी पार्टी ही दलित जनता के एक मजबूत सहारे के रूप में खड़ा रहा और उन्हें संघर्ष के राह पर गोलबंद किया, जाति उन्मूलन तथा मुक्ति के लिए उनके संघर्षों का नेतृत्व किया और उन्हें इस संघर्ष का हिस्सेदार बनया।

तेलुगु जनता और क्रांतिकारी राजनीति के जानकार कोई भी व्यक्ति को मालूम है कि सत्यमूर्ति को पार्टी से बहिष्कार करने के बाद उन्होंने कितने ही घिनौने वैचारिक और राजनीतिक हथकंडे अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनाए। वह कितने ही पार्टियों में शामिल हुए और छोड़े या बहिष्कृत हुए और कितनी बार अपने परचम का रंग बदले। इससे भी हम लोग भलीभांति परिचित हैं। कोण्डापल्ली के नेतृत्व में पीपुल्सवार पार्टी के रणनीतिक लाइन को दक्षिणपंथी घोषित कर आलोचना करने और अपने लाइन को असली ठहराने के दो वर्ष के अंदर ही क्यों वह तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अपने साथियों को मुंह दिखाने की भी काबिल नहीं रहे? सत्यमूर्ति और मार्क्सवादी–लेनिनवादी सेन्टर (एमएलसी) अन्य नेताओं द्वारा जिस लाइन को भारतीय क्रांति के संघर्ष के लिए सही घोषित किया गया था, क्यों वह लाइन प्रारंभ में ही मौत का

शिकार बन गई, अगर वह गलत, आधारहीन और विघटनकारी न होती तो? क्रांतिकारी आदर्श और राजनीति को परित्याग करने के बाद बहुजनों के मुक्ति के नाम पर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर उन्होंने कितने बहुजनों को मुक्ति दिलाई? आंध्रप्रदेश में क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो यह नहीं जानता हो कि सत्यमूर्ति ने दलित, बहुजन की मुक्ति के लिए आखिर क्या सक्रिय व्यवहार और ठोस सांगठनिक प्रयास अपनाये? मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद को परित्याग कर भाकपा (मा–ले) पीपुल्सवार को छोड़ने और एक धुर्त अवसरवादी और स्वार्थी इंसान में तब्दील होने के बाद उन्होंने अपने जीवन के लंबे 25 सालों में कितने जुझारू आन्दोलन तैयार किए, जिस दलित–बहुजन आन्दोलन को संगठित करने का दावा वह करते हैं उसी को बुर्जुआ संसदीय राजनीति दलदल में पतित करने के बाद क्या वह बुर्जुआ दलित आन्दोलन से अलग रह सकता है? उनके द्वारा अलग–अलग समय पर लिए गए अंतरविरोधी और अवसरवादी वैचारिक – राजनीतिक स्थितियों तथा अलग–अलग समय पर उनके द्वारा बनाए गए या शामिल हुए अवसरवादी पार्टियों के बीच का अंतरसबंध को हमारी पार्टी ने तथ्य के आधार पर जिस तरह सिद्ध किया है क्या इसे कोई नकार सकता है? सत्यमूर्ति द्वारा विभिन्न समय पर लिया गया विभिन्न वैचारिक–राजनीतिक स्थिति और विभिन्न संगठनों में उनका जुड़ाव को उनके लिखे गए कविताओं और उनके गाए गए गानों से अलग कर देखना या तो नदानी होगी या फिर चतुराई।

एक तरफ दलित–बहुजन के मुक्ति के नाम पर और दूसरी तरफ क्रांतिकारी आन्दोलन के खिलाफ जो उन्होंने साहित्य रचे और क्रांतिकारी संघर्ष को त्यागने के बाद दोहरी जुबान से जो कविताएं पढ़े, क्या वह शोषित वर्गों और शोषित जातियों के मुक्ति संघर्षों में मददगार थे, या फिर वह इन संघर्षों को विघ्नीत करने या उनको क्षति पहुंचाने में सहायक हुए? आंध्रप्रदेश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह नहीं जानता कि सत्यमूर्ति द्वारा अलग–अलग मुखौटों में क्रांतिकारी पार्टी और आन्दोलन के खिलाफ केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ सुर से सुर मिलाकर – एक ऐसे समय जब ये सरकारें आंध्रा में क्रांतिकारियों का झूठे मुठभेड़ों में खून बहा रहे थे – दिए गए बयानों

और विज्ञप्तियों को हमारी पार्टी ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और उनके राजनीतिक कोवर्ट की भूमिका को जनता के सामने उजागर किया।

सत्यमूर्ति के पिछले 25 साल के व्यवहार ने यह फिर से साबित किया कि हर आन्दोलन में अवसरवादियों, विघटनकारियों और स्वार्थी व्यक्तियों भाषण देने में सबसे आगे रहते हैं पर व्यवहार में वह अंतिम पंक्ति में भी नजर नहीं आते। कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में जातिगत, लैंगिक तथा अन्य सामाजिक असमानताओं के उन्मूलन के उद्‌देश्य से तैयार किए गए कार्यक्रमों, आन्दोलनों को अपने आप में स्वयं सम्पूर्ण मानते हैं और इसे वर्गीय मुक्ति की संघर्ष से अलग–थलग कर देखते हैं तथा इसे व्यवधान रखते हैं। यह लोग कभी भी उत्पीड़ित जनता और उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को मुक्ति का पथ नहीं दिखा पाएंगे। जनवादी क्रांति के अभिन्न अंग के रूप में व्यापक उत्पीड़ित समुदायों के आन्दोलनों की जरूरत कितना भी क्यों न हो अगर इनके नेतृत्व मौजूद अवसरवादी तत्वों की वजह से इन्हें सामाजिक क्रांति के विपक्ष में खड़ा कर दिया जाता है या वह अपने आपको इस क्रांति से अलग कर लेता है, तो वह इस बेहद जघन्य, निर्मम और असमान वर्गीय समाज, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के जड़ों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वह अपने संघर्षों और समझौतों से वर्तमान समाज को कोई भी नुकसान न करते हुए कुछ आंशिक सुधार ही हासिल कर पाएंगे। सिर्फ मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद ही सभी सामाजिक बुराइयों और समस्याओं के समाधान के लिए वैचारिक रोशनी दिखा सकती है। एक सही राजनीतिक लाइन से ही इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। वर्ग संघर्ष के सर्वोच्च स्तर यानी सशस्त्र संघर्ष ही इसकी धुरी होगी। इसी से शोषित वर्गों और उत्पीड़ित जनता के बीच एकता स्थापित हो सकती है, उत्पीड़न और शोषण के विरूद्ध जुझारू आन्दोलन संगठित किया जा सकता है और सामाजिक मुक्ति हासिल की जा सकती है। केवल इस तरह ही वर्ग विभाजित इस समाज से उत्पन्न सभी बुराइयों – जैसे शोषण, दमन और उत्पीड़न – से मानव समाज के सम्पूर्ण मुक्ति का पथ प्रशस्त हो सकता है।

उत्पीड़ित जनता के हित में काम करते हुए सत्यमूर्ति ने अपने राजनीतिक जीवन के जितने समय गुजारे उससे कई अधिक समय उनके आशा, आकांक्षाओं को गलत मोड़ देने, उन्हें निरस्त करने और क्षति पहुंचाने में बिताए। अपने राजनीति जीवन के अंतिम चरण में अलग–अलग नकाब पहनकर सत्यमूर्ति ने जो प्रतिक्रांतिकारी भूमिका अदा किया, उसे नजरअंदाज कर उनका मूल्यांकन करना लगत होगा। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले चरण के प्रगतिशील भूमिका को और दूसरे चरण के सामाजिक क्रांतिकारी भूमिका को अंत तक बरकारार रखा, एक ऐसे वीर पुरूष जिन्होंने शोषित जनता को निस्वार्थ रूप से सेवा किया, एक सच्चे जन कवि जिन्होंने अपने सृजन को तहेदिल से जनता के हित में समर्पित किया या एक ईमानदार राजनीतिक नेता जिनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है के रूप में आकलन करना भी सरासर गलत होगा। एक क्रांतिकारी या प्रगतिशील कार्यकर्ता का मुल्यांकन करते समय उनके राजनीति जीवन कैसे शुरू हुई और किस तरह यह कुछ या काफी समय तक जारी रहा बस इसको ही ध्यान में रखने के बजाय हमें जरूर उनके राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण तक और इसके अंत होने के तरीके की भी जांच–पड़ताल करनी चाहिए। सत्यमूर्ति जैसे एक व्यक्ति का मुल्यांकन करते समय महान मार्क्सवादी शिक्षक माओ के सिखाए मापदण्ड ही क्रांतिकारियों के लिए दिगदर्शक है। ''एक नौजवान क्रांतिकारी है या नहीं इसका निर्णय कैसे करें? हम कैसे बता सकते हैं? इसका एक ही मापदण्ड हो सकता है, और वह है, क्या वह व्यापक मजदूर और किसान जनता के साथ अपने आपको एकाकार करने के लिए और इसे व्यवहार में अमल में लाने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वह ऐसा करने के लिए तैयार है और वास्तव में करता है, तो वह एक क्रांतिकारी है; नहीं तो वह एक गैर क्रांतिकारी या प्रतिक्रांतिकारी है। अगर वह आज अपने आपको मजदूर और किसान जनता के साथ एकत्रित करता है, तो वह आज क्रांतिकारी है; अगर कल वह इससे परहेज करता है या पलटकर आम जनता का दमन करता है तो वह एक गैर क्रांतिकारी या प्रतिक्रांतिकारी बन जाता है'' – माओ ['युवा आन्दोलन की दिशा'',(4 मई 1939), संकलित रचनाएं, भाग–2, पेज 246] केवल सत्यमूर्ति ही

क्यों, कोई भी कार्यकर्ता के बारे में हम सही निष्कर्ष पर सिर्फ इसी तरीके से ही पहुंच पाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर एक वर्गीय समाज में जिसमें अलग–अलग वर्गीय दृष्टिकोण और वर्ग स्वार्थ मौजूद है, विभिन्न व्यक्ति और संगठन सत्यमूर्ति के मुल्यांकन में भिन्न–भिन्न या एक दूसरे के विरोधात्मक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उनके पहले चरण में सत्यमूर्ति एक प्रगतिशील व्यक्ति थे; और दूसरे चरण में एक क्रांतिकारी थे। अंतिम चरण में उन्होंने पहले दो चरण के दौरान अलग–अलग क्षेत्र में उनके निभाए भूमिका को अपने ही हाथों से नष्ट किया। उनके महान क्रांतिकारी भूमिका को उन्होंने खुद मिट्टी में मिलाया। एक क्रांतिकारी परिर्वतित हुए एक भगोड़े में। उनके जीवन के क्रांतिकारी समय का सत्यमूर्ति हमारे लिए एक आदर्श है। उनके जीवन के प्रतिक्रांतिकारी चरण के सत्यमूर्ति हमारे लिए एक वियोगात्मक शिक्षक है। यही है क्रांतिकारी द्वंदवाद।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

13-2-2013

अफजल गुरू की फांसी की निंदा करो!

भारतीय राजसत्ता खुद ही सबसे बड़ा आतंकवादी है, जन आंदोलन कार्यकर्ता, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनकारी और क्रांतिकारी नहीं!

खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने वाली भारतीय राजसत्ता ने 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरू को बेहद गोपनीय तरीके से फांसी दी। 13 दिसम्बर 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार अफजल को खुद को बेकसूर साबित करने का मौका न देते हुए, यहां तक कि उन्हें अपनी इच्छा से वकील नियुक्त करने का मौका भी न देकर भारत की सर्वोच्च अदालत ने 'समाज के सामूहिक विवेक को संतुष्ट करने' के लिए 2005 में फांसी की सजा मुकर्रर की थी। संसद पर हुए हमले के सूत्रधार कौन थे, इसके पीछे साजिश क्या थी, इस पर निष्पक्ष जांच किए बिना ही इस मामले में कश्मीरी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को साजिशाना ढंग से फंसाया गया था।

9/11 हमलों के बाद अमेरिका द्वारा छेड़े गए 'आतंकवाद पर भूमण्डलीय जंग' के तहत भारतीय राजसत्ता ने राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों तथा क्रांतिकारी संगठनों को आतंकवादी बताते हुए कार्पोरेट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार शुरू कर रखा है। देश की जनता का ध्यान उसकी फौरी और बुनियादी समस्याओं से हटाकर इस भावना को कि 'आतंकवाद' ही सबसे बड़ा खतरा है, हर तरफ फैलाया जा रहा है। कश्मीर और देश के सभी राज्यों में कांग्रेस व भाजपा की सरकारों तथा संघ गिरोह से जुड़ी विभिन्न हिंदू धर्मोन्मादी ताकतों द्वारा इस्लामिक आतंकवादियों के बहाने मुसलमानों पर सालों से जारी फासीवादी हत्याकाण्डों, अत्याचारों, यातनाओं, जेल की सजाओं और अमानवीय

भेदभाव के चलते मुस्लिम जनता बेहद गुस्से में है। कुछ मुसलमान इसका अपने ढंग से प्रतिरोध कर रहे हैं। इसके एक रूप के बतौर कुछ अवांछित विध्वंसकारी हमले भी हो रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासक वर्गों और हिंदू धर्मोन्मादी ताकतों की ही है। उसी समय, भारत सरकार की खुफिया संस्थाएं, अमेरिकी खुफिया संगठन और हिंदू धार्मिक कट्टरपंथी संघ गिरोह से जुड़े संगठन देश के कई हिस्सों में षड़यंत्रपूर्ण ढंग से बम हमलों और विध्वंसकारी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। सरकार और उसके सुर में सुर मिलाने वाली मीडिया द्वारा इन सभी मामलों में बेकसूर मुसलमानों और राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों को दोषी बताया जा रहा है। उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। भारतीय राजसत्ता का मकसद यह है कि इस बहाने जनता के सभी जायज आंदोलनों को कुचल दिया जाए। इसी साजिश का हिस्सा है संसद पर नाटकीय ढंग से हुआ हमला।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने, जो अफजल गुरू की फांसी को टालते आ रही थी, अगले साल आने वाले चुनावों को नजर में रखकर ही इस तरह अचानक उसे फांसी पर चढ़ा दिया ताकि भाजपा को मात देकर खुद को 'आतंकवाद' पर चैम्पियन साबित किया जा सके। इस क्रम में उसने अपनी ही न्यायप्रणाली के कई नियमों का खुला उल्लंघन किया। माफी की अपील को राष्ट्रपति द्वारा नकार दिए जाने के बारे में उसके परिवार को न बताकर, उसे आखिरी बार अपने परिवारजनों से मिलने का मौका तक न देकर, कश्मीर की समूची वादी में पहले से कर्फ्यू लगाकर इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहां तक कि अफजल का शव भी उनके परिवार को न सौम्पकर – ठीक उसी तरह जिस तरह विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की लाश को समुद्र में गिरा दिया था – जेल के ही अंदर दफनाकर बेहद अमानवीयता बरती।

अफजल गुरू को फांसी देकर भारत सरकार ने कश्मीरियों समेत भारत के तमाम जनवादपंसद अवाम की मनोभावनाओं को बुरी तरह आहत कर दिया। हकीकत यह है कि अब तक 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करने और 7 लाख सशस्त्र बलों के साथ समूची वादी को सैन्य छावनी में तब्दील करने के बावजूद कश्मीरी कौम के अंदर आजादी की तमन्ना

खत्म नहीं हुई है। भारत सरकार दिवास्वप्न देख रही है कि अफजल गुरू को फांसी देकर वह कश्मीरी जनता के लड़ाकू जज़्बे पर पानी फेर सकेगी। अपनी रष्ट्रीयता की मुक्ति के लिए, आजादी के लिए कश्मीरी अवाम दशकों से जो संघर्ष कर रहा है वह पूरी तरह जायज है। कई उतार–चढ़ावों के बावजूद यह संघर्ष अलग–अलग रूपों में आज भी जारी है जो कई मौकों पर विस्फोटक रूप भी धारण कर रहा है। भारत के फासीवादी शासकों की इस तरह की अमानवीय करतूतों से कश्मीरियों के दिलों में नफरत ही बढ़ेगी। उन्हें हमेशा के लिए दबाकर रखना नामुमकिन है।

इस फासीवादी कार्रवाई की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कड़ी निंदा करती है। और यह चेतावनी देती है कि इस तरह की करतूतों के जरिए शोषित जनता और राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों का दमन कर पाने का जो सपना शासक वर्ग पाले हुए हैं वह नाकाम होकर ही रहेगा। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। उस पर न तो भारत को अधिकार है, न ही पाकिस्तान को। कश्मीरी जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का हमारी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है। देश को राष्ट्रीयताओं के कैदखाने में तब्दील किए हुए बड़े दलाल नौकरशाह पूंजीपति व सामंती शासक वर्गों और उनका नेतृत्व करने वाले साम्राज्यवादियों के खिलाफ देश के मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, व्यापारियों.... समूची शोषित जनता और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए। भारत की नई जनवादी राजसत्ता, जो मजदूरों, किसानों, निम्न और राष्ट्रीय पूंजीपतियों के संयुक्त मोर्चे के रूप में होगी, के गठन के लिए जारी संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से ही राष्ट्रीयताएं अलग होने का अधिकार समेत आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल कर सकेंगी। समूची उत्पीड़ित जनता हर किस्म के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति पा सकेगी।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

22-3-2013

तात्कालिक रूप से रणनीतिक गतिरोध का कार्यभार लेकर जीत की तरफ आगे बढ़ रहे फीलीपीन्स क्रांति को लाल सलाम!
फिलीप्पीन की क्रांति और फिलीप्पीन की संघर्षरत जनता का दृढ़ता से समर्थन करो!
ओप्लान बयनिहान का निंदा करों और इसका विरोध करो!
22 से 28 अप्रैल तक फिलीप्पीन्स क्रांति के समर्थन में भाईचारा सप्ताह मनाओ!

दुनिया के तथा भारत के जनता के सामने अब यह साफ हो चुका है कि यह अमेरिका की कठपुतली फिलीप्पीन्स के बेनिग्नो अक्विनो सरकार ओप्लान बयनिहान के नाम से एक अमानवीय सैन्य अभियान चला रहा है जिसका मकसद है फिलीप्पीन्स के कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चल रहे क्रांतिकारी आन्दोलन का सफाया करना। यह आन्दोलन अब रणनीतिक आत्मरक्षा से रणनीतिक गतिरोध के पड़ाव तक सक्रमण को मुख्य और तात्कालिक नारा और कार्यभार के रूप में लेकर आगे बढ़ रहा है।

तीन लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला फिलीप्पीन्स एक दक्षिण–पूर्व एशियाई देश है जिसकी जनसंख्या है साढ़े नौ करोड़। शांतिप्रिय फिलीप्पीनी जनता का उपनिवेशी शासन, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद, के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष और वीरोचित शहादत का एक गौरवशाली इतिहास और लंबी परम्परा है। उम्दा सांस्कृतिक धरोहर के वारिश फिलीप्पन्स एक अर्द्ध उपनिवेशिक

अर्द्ध सामंती देश है। आत्मनिर्भरता के लिए इस देश में पर्याप्त रूप से विभिन्न संपदाएं मौजूद हैं। इस देश को सर्वभौमिक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में परिवर्तित करने के लिए इसके करोड़ों मेहनतकश जनता सबसे मजबूत आधार है। साम्राज्यवादियों और उनके दलाल शासक वर्गों के शोषण और दमन का खात्मा कर इस समाज में असली लोकतंत्र और प्रगति हासिल करने के लिए देश के मजदूर और किसान वर्ग प्रमुख स्रोत हैं।

फिलीप्पीन्स के राष्ट्रीय जनवादी क्रांति की शुरूआत की गई थी 1896 में। देश में चले सामंतवाद–विरोधी संघर्षों के क्रम में 1930 के दशक के प्रारंभ में फिलीप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। एक टेढ़ा–मेढ़ा रास्ता तय करते हुए और पार्टी में उभरे संशोधनवादियों को परास्त करने के बाद 1960 के दशक के दूसरे भाग में ही पार्टी एक सही क्रांतिकारी दिशा अपना पाई। यह अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ माओ – चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और असली क्रांतिकारी और जनवादी शक्तियों के नेतृत्व में हो रहे उस व्यापक उथल–पुथल के अन्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ। उस समय से फिलीप्पीन्स की नई जनवादी क्रांति नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगा। नई जनसेना (एनपीए) और राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा (एनडीएफ) की मदद से और जनता की विशाल गोलबंदी के जरिए नई जनवादी क्रांति नए सफलताओं के साथ आगे बढ़ती गई। अभी के समय में फिलीप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी देश की जनता की सबसे चहेती और विश्वसनीय पार्टी है जो इस समाज के शोषित तबकों और समुदायों को अमेरिकी साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में एकत्रित कर रही है और इस संघर्ष का नेतृत्व कर रही है ताकि राष्ट्रीय जनवादी क्रांति को उसके मुकाम तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सके। फिलीप्पीन्स के अर्द्धउपनिवेशिक–अर्द्धसामंती व्यवस्था में बढ़ते जा रहे संकट के साथ–साथ हर शोषित वर्ग की जनता कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झण्डे तले एकजुट होने लगे हैं।

इस नई जनवादी क्रांति के बढ़ते लोकप्रियता तथा इसके वजह से फिलीप्पीन्स के वर्तमान शोषणपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ बढ़ रहे खतरे से परेशान बेनिग्नो इक्विनो सरकार ने पिछले दशकों में एक के बाद एक फासीवादी

प्रतिक्रांतिकारी सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी साम्राज्यवाद के दलाल बेनिग्नो सरकार द्वारा इस कड़ी में फिलहाल चलाया जा रहा चौतरफा दमन अभियान का ही नाम है ओप्लान बयनिहान। अमेरिका की कठपुतली प्रतिक्रियावादी फिलीप्पीन सरकार द्वारा फासीवादी तरीके से चलाया गया यह अब तक का सबसे कू.र अमनावीय और व्यापक चौतरफा दमन अभियान है।

लेकिन फिलीप्पीन्स कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में और नई जनसेना तथा राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा की मदद से इस देश की जनता फासीवादी दमन ओप्लान बयनिहान के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश के हर कोने में जुझारू प्रतिरोध कर रही है। इस तरह से फिलीप्पीन्स की जनता आज पूरे दुनिया मेहनतकश वर्गों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और शोषित जनता के सामने प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बन गए हैं।

फिलीप्पीन्स की क्रांतिकारी जनयुद्ध आज रणनीतिक आत्मरक्षा के पड़ाव से रणनीतिक गतिरोध तरफ बढ़ रही है। आज .... गुरिल्ला मोर्चा गठन हो चुका है। 2015 तक इसे .... तक बढ़ाने की लक्ष्य से क्रांतिकारी पार्टी कार्यरत है। 2011 में सम्पन्न हुए नई जनसेना के 42वीं वर्षगांठ में फैसला लिया गया कि आने वाले पांच साल में 25 ....हथियार दुश्मन से जब्त किया जाएगा और उसे .... तैयार होने वाले नए कम्पनियों के हाथों सौंपा जाएगा। कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों के जरिए एनपीए दुश्मन को भारी चोट पहुंचा रहा है और इस तरह दुनिया के शोषित जनता, खासकर जनसेनाओं को, प्रेरित और उत्साहित कर रही है। राज्य द्वारा किया जा रहा अपहरण, उत्पीड़न, गांव दहन, लूट और क्रांतिकारी संगठनों पर लगया गया प्रतिबंध आदि के बावजूद जनता उनके सहयोगी नई जनसेना तथा राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा फिलीप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में संघर्षरत है। आइए, उनको समर्थन का हाथ बढ़ाएं। आइए, उन्हें कहें वह अकेले नहीं हैं। आइए, उन्हें हमारी भाईचारा संदेश भेजें।

अक्विनो सरकार द्वारा चलाया जा रहा 'जनता के खिलाफ युद्ध' को तुरंत रोकने की मांग करो! फिलीप्पीन्स में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य छावनियों को बंद करने की मांग करो! फिलीप्पीन्स की जेलों में कैद सभी राजनीतिक बंदियों

की रिहाई की मांग करो! साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद तथा सामंती वर्गों के सेवक बेनिग्नो अक्विनो की फासीवादी शासन के खिलाफ संघर्षरत साहसिक फिलीप्पीन्स क्रांति का समर्थन करो!

भारत के तमाम क्रांतिकारी जनता की तरफ से भाकपा (माओवादी) आपको मजबूत समर्थन और भाईचारा पेश करती है। अपनी तात्कालिक और अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से भारत और फिलीप्पीन की दोनों पार्टियां असीम त्याग और शहादत के साथ क्रांतिकारी युद्ध लड़ रही है। हम वादा करते हैं कि किसी भी तरह के बलिदान से न कतराते हुए दृढ़ संकल्प के साथ हम अपनी क्रांतिकारी युद्ध को जारी रखेंगे ताकि हम नई जनवादी क्रांति को सफल कर सकें। हम यह भी शपथ लेते हैं कि विश्व सर्वहारा क्रांति के एक अभिन्न अंग होने के नाते हम फिलीप्पीन्स क्रांतिकारी युद्ध के एक भरोसेमंद सहयोद्धा होगें। सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयतावाद से प्रेरित होकर हम फिलीप्पीन्स की नई जनवादी क्रांति के समर्थन में दृढ़ता से खड़े रहेंगे तथा विश्व सर्वहारा क्रांति में अपना योगदान देंगे। फिलीप्पीन्स की महान जनता, फिलीप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी और नई जनसेना अपराजय है। विश्व के मजदूर वर्ग, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं और शोषित जनता तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, आखिर जीत तुम्हारी ही होगी। अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके फिलीप्पीनी दलालों की हार होगी।

- ओप्लान बयनिहान का विरोध करो!
- फिलीप्पीन की नई जनवादी क्रांति का समर्थन करो और उसका साथ दो!
- फिलीप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद!
- मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद जिन्दाबाद!
- सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयतावाद जिन्दाबाद!
- साम्राज्यवाद और उसके दलाल मुर्दाबाद!

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

31-3-2013

झारखण्ड के चतरा जिला अन्तर्गत लकड़बंधा गांव के हत्याकाण्ड की भर्त्सना करें!

16 अप्रैल, 2013 को भाकपा (माओवादी) द्वारा 24 घंटे भारत बन्द को सफल करे!

विदित हो कि दिनांक 27 मार्च, 2013 को झारखण्ड के चतरा जिला अन्तर्गत कुन्दा थाना के लकड़बंधा गांव में चतरा के एस.पी. अनुप बिरथरे के नेतृत्व में भारी संख्या में झारखण्ड सशस्त्र पुलिस और सीआरपीएफ, कोबरा आदि के बलों ने एक साजिश के तहत टीपीसी (जो 'नक्सलवादी'-'माओवादी' होने का मुखौटा पहनकर दरअसल, पुलिस और खुफिया विभाग के बड़े अफसरों की प्रत्यक्ष देखरेख में संचालित हो रहा है और पुलिस के नेटवर्क से जुड़कर एसपीओ के रूप में काम कर रहा है) को सामने रखकर जन समस्याओं को लेकर गाांव में मीटिंग करने गये भाकपा (माओवादी) के कार्यकर्ता और पीएलजीए के एक दस्ता को चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। इस लड़ाई के दौरान कुछ लोग शहीद हुए और कुछ लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और उन पर बहुत ही बर्बर तरीके से यातनाएं देकर-किसी की अंगुली काट ली गयी, किसी को पत्थर से कूच-कूच कर मारा गया, किसी को सीना में गोली मारा गया, किसी को सिर पर और किसी के मुंह में बैरल घुसाकर गोली मार कर हत्या कर दी गयी। इसके पश्चात पुलिस अपनी बर्बरता को छुपाने के लिए मीडिया द्वारा यह झूठा प्रचार करवायी कि टीपीसी के साथ मुठभेड़ में दस माओवादी मारे गये। पुलिस उनकी लाश और उनके हथियार को जप्त कर ली है।

दोस्तो, चतरा एसपी के नेतृत्व में झारखण्ड पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा के बलों ने एक साजिश के तहत दस माओवादी क्रान्तिकारियों की हत्या करने की यह घटना कोई नई नहीं है, बल्कि अमरीकी साम्राज्यवाद के दिशा-निर्देशन में उसके विश्वस्त दलाल सोनिया-मनमोहन-सुशील कुमार सिंदे-पी.

चिदम्बरम और जयराम रमेश के नेतृत्व में माओवादी क्रान्तिकारी संघर्ष को कुचलने के बूरे मनसूबे से चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन हंट नामक बर्बर पुलिसिया दमन अभियान के तहत की जानेवाली बर्बर पुलिसी कार्रवाई का ही एक हिस्सा है। आज इस तरह का बर्बरतापूर्ण पुलिसिया दमन अभियान साम्राज्यवादियों खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद की LIC Policy (कम तीव्रतावाला युद्ध नीति) के तहत चलाया जानेवाला छल-बल-कौशलपूर्ण युद्ध अभियान ही है, जिसके तहत पुलिस के द्वारा एसपीओ बनाकर, विभिन्न गुण्डा गिरोह का गठन कर उसकी प्रत्यक्ष देखरेख में संचालन किया जा रहा है तथा उन्हें AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार मुहैया करके माओवादी क्रान्तिकारियों और क्रान्तिकारी आन्दोलन-समर्थक जनता के ऊपर हमले करवाये जा रहे हैं। ये हमले कहीं टीपीसी, जेपीसी, जेएलटी, पीएलएफआई जैसे गुण्डा गिरोह के द्वारा पुलिस की प्रत्यक्ष देखरेख व मदद पर, कहीं सलवा जुड्म के नाम पर, कहीं सेंद्रा के नाम पर, नागरिक सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा दल, शांति सेना, महात्मा गांधी तंटा मुक्ति संगठन, भैरव वाहिनी, हरमद वाहिनी आदि के नाम पर करवाये जा रहे हैं। विदित हो कि टीपीसी, जेपीसी, जेएलटी, पीएलएफआई आदि हत्यारे गिरोह और नागरिक सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा दल (ये सरकार द्वारा पोषित हैं) झारखण्ड में सक्रिय हैं, जो पुलिस की प्रत्यक्ष देखरेख व मदद से माओवादियों के खिलाफ संचालन किया जा रहा है। 27 मार्च, 2013 को चतरा में घटित घटना भी जो पुलिस द्वारा माओवादी और टीपीसी के बीच मुठभेड़ की घटना के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल पुलिस द्वारा सुनियोजित योजना के तहत साजिशपूर्ण ढंग से किया गया हत्या काण्ड ही यह है।

इस तरह आज अमरीकी साम्राज्यवाद का विश्वस्त दलाल सोनिया-मनमोहन-पी. चिदम्बरम-सुशील कुमार सिंदे-जयराम रमेश माओवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के बुरे इरादे से ऑपरेशन ग्रीन हंट नामक अघोषित युद्ध माओवादी क्रान्तिकारियों सहित शोषित-उत्पीड़ित मेहनतकश जनता के ऊपर थोप दिया है। इस प्रतिक्रान्तिकारी युद्ध अभियान के तहत साजिशपूर्ण ढंग से माओवादी क्रान्तिकारी नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थक जनता ऐसाकि आम मेहनतकश जनता की बर्बर हत्या व नरसंहार जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। चतरा की उपरोक्त हत्या काण्ड व नरसंहार की घटना

उसकी ही धारावाहिकता में की गयी साजिशपूर्ण बर्बर पुलिसी कार्रवाई की पुनरावृति है। इसके अलावे कुछ ही दिन पूर्व महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला अहेरी तहसील के अन्तर्गत गोबिन्द गांव में 19 जनवरी को वहां के एसपी सुवेज हक की साजिश के तहत 6 क्रान्तिकारियों की हत्या की गयी। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला के पामेड़ थानान्तर्गत कंचाल गांव के आम आदिवासी किसान महिला और पुरूष को 8 मार्च को झूठी मुठभेड़ में कत्ल कर माओवादी का नाम दिया। वहीं पर नारायणपुर जिलान्तर्गत मंदोड़ा गांव में एक युवक को दिन दहाड़े मार्च दो तारीख को कत्ल कर मुठभेड़ का नाम दिया है। इसके पूर्व का. आजाद, का. कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी की हत्या, पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबंधा के साजिशपूर्ण नरसंहार, छत्तीसगढ़ के सरकेगुड़ा का नरसंहार जैसी अनेकों घटनाएं घट चुकी हैं जो उसकी जीती-जागती मिसालें व सबूत हैं।

पुलिसवाले आम जनता को ही नहीं, बल्कि मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। ओड़िशा में मानवाधिकार कार्यकर्ता दण्डपाणि महंती को 2013 फरवरी में झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार कर UAPA के तहत जेल में ठूंस दिये हैं। आज देश के कई जगहों में खासकर माओवादी संघर्षशील इलाकों में जनता पर भयानक फासीवादी दमन चल रहा है। हमारी पार्टी तमाम जनता छात्र, बुद्धिजीवी, जनवाद प्रेमियों से यह अपील कर रही है कि जहां के वहां जन आन्दोलन निर्माण कर अपना विरोध जताएं।

अमरीकी साम्राज्यवाद तथा उसके विश्वस्त दलाल केन्द्र और राज्य सरकारें इस तरह क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थक जनता की बर्बर हत्या व नरसंहार कर क्रान्तिकारी आन्दोलन को ध्वस्त करने का कितना ही असफल प्रयास क्यों न करे, कभी भी उनका बुरा मनसूबा सफल नहीं होगा। आखिरकार क्रान्तिकारी जनता उनके बुरे मनसूबों को ध्वस्त करके रहेगी। क्रान्तिकारी जनता चतरा जैसे हत्याकाण्ड को अंजाम देनेवाले हत्यारों व गुनाहगारों को एक दिन अवश्य जन अदालत के कठघरे में खड़ाकर उसे सजा देगी और अपने जनप्रिय नेता का. प्रशांत सहित अपना दस वीर जनयोद्धा का राजनीतिक बदला लेकर रहेगी।

वर्तमान में दुश्मन द्वारा चलाये जा रहे चौतरफा हमले को आज के

साम्राज्यवाद, सामंतवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गों के आर्थिक संकट से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। 2008 से जारी साम्राज्यवादी वित्तीय संकट खत्म होने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, बल्कि और दीर्घकालीन रूप लेते जा रहा है। यहां के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को लूट कर अपने संकट के दलदल से निकलने की कोशिशों के तहत ही आज के चौतरफा हमले को वे तेज करते जा रहे हैं। इसके अन्तर्सम्बन्ध को समझ कर यहां पर चल रहे व्यापक जन संघर्ष एवं जनयुद्ध के साथ दृढ़ता से खड़ा होने के लिए हमारी पार्टी तमाम जनता और जनवादियों से अपील कर रही है।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमिटी शोषक-शासक वर्ग के भाड़े के टट्टू पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया चतरा-लकड़बंधा नरसंहार की तीव्र निन्दा व कठोर भर्त्सना करते हुए इसके खिलाफ में 16 अप्रैल, 2013 को 24 घंटे भारत बन्द की घोषणा करती है। केन्द्रीय कमिटी किसान-मजदूर, छात्र-नौजवान, मेहनतकश महिलाएं, प्रगतिशील बुद्धिजीवी, कलाकार, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे दुकानदार, न्यायपसंद प्रबुद्ध नागरिकों सहित तमाम मेहनतकश जनता से भाकपा (माओवादी) द्वारा आहूत एक दिवसीय भारत बन्द को सफल करने का आह्वान करती है। साथ ही साथ यह आह्वान करती है कि आवें, शोषक-शासक वर्ग द्वारा जनता पर थोपा गया 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' नामक अघोषित युद्ध के खिलाफ तथा उसके तहत चलाये जा रहे देश व्यापी बर्बर पुलिसिया जुल्म व दमन-अत्याचार के खिलाफ और चतरा-लकड़बंधा जैसे बर्बरतापूर्ण हत्या-काण्ड के खिलाफ एकजुट होकर जनप्रतिवाद व जनप्रतिरोध आन्दोलन को तेज करें; आवें, वर्तमान इस शोषणमूलक व हत्यारी राजसत्ता को उखाड़ फेंककर नवजनवदी भारत का निर्माण हेतु भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन व जनयुद्ध में शरीक हो जाएं।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
सेंट्रल रीजनल ब्यूरो

19-4-2013

पुव्वार फासीवादी हत्याकाण्ड का खण्डन करो!

आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व ओड़िशा के पुलिस, विशेष कमाण्डो/ग्रेहाउण्ड्स व केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा सेंट्रल रीजियन में चलाए जा रहे हत्याकाण्डों और विध्वंस के खिलाफ...

27 अप्रैल को सेंट्रल रीजियन बंद सफल बनाओ!

16 अप्रैल 2013 को आंध्रप्रदेश की सीमा पर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला, कोंटा ब्लॉक के पुव्वार गांव में एपी ग्रेहाउण्ड्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपी–कोबरा बलों द्वारा खम्मम एसपी रंगनाथ और कोत्तागूडेम ओएसडी के नेतृत्व में, मुखबिरों से मिली पक्की सूचना के साथ हमला कर उत्तर तेलंगाना के पांच महिला कामरेडों समेत नौ कामरेडों की हत्या कर दी। इस हमले में कामरेड्स मर्री रवि उर्फ सुधाकर (उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य), गुगलोत लक्ष्मी उर्फ पुष्पा (केकेडब्ल्यू डीवीसीएम), वेट्टि नरसक्का उर्फ सबिता (एटूरनागारम एसी सचिव), दुर्गम राजू (एसीएम), रीना (एसीएम), वेट्टि रामक्का उर्फ ऊर्मिला (एसीएम), मद्दि सीता उर्फ नवता (डीवीसीएम की गार्ड), मड़काम भीमा उर्फ अजय (डीवीसीएम का गार्ड) और अरलि वेंकटि उर्फ गौतम (एसजेडसीएम का गार्ड) शहीद हो गए। सेंट्रल रीजनल ब्यूरो इन तमाम शहीदों को लाल–लाल जोहार पेश करते हुए उनके सपनों को साकार करने की शपथ लेता है। एपी ग्रेहाउण्ड्स पिछले कुछ सालों से दण्डकारण्य में घुसकर इस तरह के हत्याकाण्डों और तबाही को अंजाम देते आ रहे हैं। 2008 में हुए कंचाल हत्याकाण्ड के बाद यह और एक भारी

हत्याकाण्ड है। हमारी पार्टी इस हत्याकाण्ड की कड़ी निंदा व खण्डन करते हुए जनता और पीएलजीए का आह्वान करती है कि पुलिस, ग्रेहाउण्ड्स और अर्द्धसैनिक बलों के हमलों का प्रतिरोध किया जाए।

पिछले चार महीनों से दण्डकारण्य, आंध्र–ओड़िशा सीमांत जोन, उत्तर तेलंगाना व गोंदिया (महाराष्ट्र) के इलाके पुलिस, ग्रेहाउण्ड्स और अर्द्धसैनिक बलों के लौह पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। हर दिन, हर कोने से सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाए जा रहे हत्याकाण्डों, फर्जी मुठभेड़ों, विध्वंस और आतंक से जुड़ी खबरें आ रही हैं। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने वाले भारत के शोषक शासक वर्ग सदियों से अत्यंत क्रूरतापूर्ण शोषण, उत्पीड़न, दमन, अन्याय, भेदभाव और उपेक्षा की शिकार जनता पर, खासकर आदिवासियों पर अभूतपूर्व पाशविकता बरत रहे हैं। दण्डकारण्य में पिछले दस दिनों के दरमियान कम से कम 20 क्रांतिकारियों और आम जनता को फर्जी मुठभेड़ों में कत्ल कर दिया गया। खासकर आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में विभिन्न राज्यों के पुलिस व कमाण्डो बल और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल संयुक्त आपरेशन चलाकर मनमानी मुठभेड़ों, हत्याकाण्डों और विध्वंसकाण्ड को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में और आंध्रप्रदेश के करीमनगर जिले के काटारम में चार राज्यों के पुलिस के आला अधिकारियों ने विशेष बैठकें कर इन ताजा हमलों की साजिश रची। वायु सेना के हेलिकाप्टरों और मानवरहित विमानों के प्रयोग को बढ़ाने के अलावा वायुसेना के जरिए हवाई हमले करने की योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सेना के प्रशिक्षण के बहाने माड़ क्षेत्र पर कब्जा कर क्रमगत रूप से जनता के खिलाफ जारी युद्ध में सेना की तैनाती करने की योजना भी उनके एजेंडे में है। इन हमलों के जरिए जनता द्वारा निर्मित हो रही नई राजसत्ता को, उसकी गुरिल्ला सेना को और उसकी पार्टी को जड़ से खत्म करने पर जोर लगा रहे हैं। हाल में हुई कुछ अन्य घटनाएं इस बात का सबूत हैं।

- 12 अप्रैल को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला, धनोरा तहसील के सिंदेसूर गांव में जनता जब गुरिल्ला सैनिकों को भोजन की व्यवस्था कर रही थी तब पुलिस ने अचानक हमला किया जिसमें कामरेड

कैलास उर्फ पंकज (एसीएम) और कामरेड चम्पा नुरोटी (कम्पनी–4 की सदस्या) के अलावा गांव की दो निहत्थी महिलाएं वसंती कोवासी और संगीता आत्रम को गोली मार दी गई।

- 4 अप्रैल को इसी जिले के भामरागढ़ तहसील, भटपार गांव में जनता के साथ बैठक करने वाले गुरिल्ला दस्ते पर सी–60 कमाण्डों ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें कामरेड लक्ष्मण (एसीएम), मिलिशिया सदस्य कामरेड्स प्रकाश और सुधाकर के अलावा गांव की अम्मी और सुनिता नामक दो किशोरियों की हत्या की गई।
- 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला, माड़ क्षेत्र के ग्राम कोंगे में हमला कर जंगल में शिकार पर गए छह भोलेभाले आदिवासियों को पकड़कर ले जाया गया और उन्हें 'इनामी नक्सली' के रूप में पेश किया गया। इसके पहले गांव के अंदर घुसकर डकैतों की तरह लूटपाट और तबाही मचाई।
- 14 मार्च को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला, खोब्रामेण्डा गांव के जंगलों में पार्टी नेतृत्व का सफाया करने के लक्ष्य से भारी हमला किया गया।
- 9 मार्च को बीजापुर जिला, कंचाल गांव के पास एपी ग्रेहाउण्ड्स द्वारा की गई गोलीबारी में कुंजाम देवे नामक ग्रामीण महिला की मौत हुई और एक अन्य महिला घायल हुई। देवे की लाश और घायल महिला को हेलिकाप्टर में ले जाकर वर्दी पहनाकर उन्हें नक्सलवादी घोषित किया गया।
- 1 मार्च को नारायणपुर जिले के मांदोड़ा गांव में मिलिशिया सदस्यों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर कामरेड गुधराम नेंडी की हत्या की।
- 24 फरवरी को बीजापुर जिला, कोरसेली गांव में अर्द्धसैनिक बलों, छत्तीसगढ़ पुलिस व एसटीएफ ने हमला कर गांव में साधारण जीवन बिताने वाले कामरेड सलीम (सम्मिरेड्डी) को पकड़कर अगले दिन आवुनार गांव के पास ले जाकर गोली मार दी।
- 5–8 फरवरी के मध्य माड़ डिवीजन (नारायणपुर जिला) के गट्टाकल

गांव पर छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के पुलिस बलों और सीआरपीएफ ने सैकड़ों की संख्या में हमला कर तबाही और लूटपाट मचाई। गांव में क्रांतिकारी जनताना सरकार द्वारा संचालित आश्रम पाठशाला को जला डाला।

- 4 फरवरी को सिंगम और रेंगम गांवों पर हमले कर गांव की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया।
- 12–13 जनवरी को बीजापुर जिले के गंगलूर के निकट पिड़िया गांव पर पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने भारी विध्वंसकाण्ड मचाया। घरों में घुसकर मनमानी लूटपाट की और उसके बाद 20 घरों में आग लगा दी। डोडी तुमनार में जनता द्वारा क्रांतिकारी जनताना सरकार के नेतृत्व में संचालित आश्रम पाठशाला को जलाकर राख कर दिया।
- 19 जनवरी को गढ़चिरोली जिला, अहेरी तहसील के गोविंदगांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर जा रहे गुरिल्लों पर पहले से मिली खबर के आधार पर पुलिस ने घात लगाकर हमला किया जिसमें कामरेड्स शंकर लकड़ा (डीवीसीएम), विनोद कोड़ोपी (अहेरी दल कमाण्डर), गीता कुमोटी (प्लाटून–14 की उप कमाण्डर), मोहन कोवासी (डिप्यूटी कमाण्डर) के अलावा सदस्य कामरेड्स लेब्बे गावड़े और जूरू मट्टामी शहीद हो गए।
- 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला, भुरभुसी गांव में स्नान करते समय गुरिल्लों पर बीएसएफ ने गोलीबारी की जिसमें दो महिलाएं कामरेड्स सनोति और सुमित्रा शहीद हो गईं।
- जनवरी के दूसरे सप्ताह में एपी–छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ग्राम निम्मलागूड़ेम में हमला कर दो ग्रामीण महिलाओं को ले जाकर वर्दी पहनाकर मार डालने की कोशिश की। बाद में अदालत में पेश किया।
- चरला व दुम्मुगूडेम के इलाकों में तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांवों में एपी पुलिस ने गांवों पर लगातार हमले कर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आंध्रप्रदेश–छत्तीसगढ़ की सीमा पर

हाट बाजारों को बंद किया जा रहा है।

उपरोक्त घटनाएं चंद उदाहरण भर हैं। और भी असंख्य घटनाएं आए दिन घट रही हैं। आदिवासी किसानों को गिरफ्तार कर उन्हें इनामी नक्सली घोषित कर फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। झूठी गवाही से कठिन कारावास की सजाएं दी जा रही हैं।

शोषक शासक वर्ग अपने दमनात्मक हमलों के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध को भी संचालित कर रहे हैं। मीडिया के जरिए यह प्रचारित करवा रहे हैं कि माओवादी नेता बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। यह झूठा प्रचार करवा रहे हैं कि माओवादी नेता पैसा लेकर भाग रहे हैं। समर्पण कर चुके लोगों के जरिए यह दुष्प्रचार करवा रहे हैं कि पार्टी में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और जबरन नसबंदी करवाई जा रही है। दूसरी ओर सरंडर पालिसी का बार–बार प्रचार करते हुए सिर पर कीमत लगा रहे हैं। हथियार लेकर भागकर आने वालों को लाखों रुपए का इनाम देने की घोषणाओं के साथ बड़े पैमाने पर पोस्टर लगवा रहे हैं। इधर पुलिस व अर्द्धसैनिक बल सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम से गांवों में लोगों को तरह–तरह का सामान बांट रहे हैं। लुटेरी सरकारें अपने एलआईसी हमले के तहत सैनिक दमन के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध और ढोंगी सुधार कार्यक्रमों को तेज कर रही हैं।

देश भर में क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करना, देश के विभिन्न क्रांतिकारी संघर्ष के इलाकों में विकसित हो रही जन राजसत्ता को खत्म करना, इसके द्वारा देश की अनमोल प्राकृतिक संपदाओं को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की कार्पोरेट कम्पनियों के द्वारा लुटवाने की राह में आ रही बाधाओं को दूर कर लेना ही इस हमले का मकसद है। इस हमले की अगुवाई सोनिया–मनमोहन–चिदम्बरम–शिंदे–जयराम रमेश शासक गिरोह कर रहा है, जबकि विभिन्न राज्य सरकारें इसमें तालमेल के साथ भाग ले रही हैं। टाटा, मित्तल, जिंदल, एस्सार, अल खैमा, नेको जयस्वाल्स आदि दलाल व विदेशी कार्पोरेट कम्पनियों के साथ किए गए

लाखों रुपए के एमओयू को इसलिए कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि देश भर में जनता प्रतिरोध कर रही है और कई इलाकों में इस प्रतिरोध का नेतृत्व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कर रही है। इसीलिए आज माओवादी आंदोलन देश के लुटेरे शासक वर्गों की नजर में 'बहुत बड़ा खतरा' बन गया। इसीलिए साम्राज्यवादी, दलाल नौकरशाह पूंजीपति और सामंती वर्ग इसका अंत करने पर आमदा हैं।

जनता से हमारा आह्वान है कि वह अपनी रक्षा के लिए, अपने एकजुट प्रयासों के बल पर अपना भविष्य खुद ही तय करने के लिए और अपनी जनवादी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साम्राज्यवादियों और उनके पालतू कुत्ते भारत के शोषक शासक वर्गों की तमाम आर्थिक, राजनीतिक व दमनात्मक नीतियों का मजबूती से विरोध करें तथा उनके भाड़े के पुलिस, अर्द्धसैनिक व सैन्य बलों का दृढ़तापूर्वक सामना करें। हम देश के मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, जनवादियों और तमाम देशभक्तों से अपील करते हैं कि वे इस हमले का खण्डन करें और इसे रोकने की मांग करें। क्रांतिकारी संघर्ष के क्षेत्रों में डेरा जमाए हुए तमाम अर्द्धसैनिक बलों को वापस लेने तथा सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करने की मांग करें। हमारा सेंट्रल रीजनल ब्यूरो समूची जनता का यह आह्वान करता है कि इस हमले के खिलाफ आगामी 27 अप्रैल को सेंट्रल रीजियन के क्षेत्र में (उत्तर तेलंगाना, आंध्र–ओड़िशा सीमांत क्षेत्र, दण्डकारण्य, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली व गोंदिया जिलों तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में) बंद रखा जाए। शिक्षण संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, रेल व परिवहन आदि सभी गतिविधियों को बंद रखकर लुटेरी सरकारों को यह बताया जाए कि हम इस हमले का खण्डन करते हैं। (हालांकि छात्रों की परीक्षाओं और चिकित्सा आदि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा जाएगा।)

प्रताप

प्रवक्ता

सेंट्रल रीजनल ब्यूरो

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

20-4-2013

भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करो – जल–जंगल–जमीन के लिए संघर्ष तेज करो! हमारे जमीन को हड़पने की साम्राज्यवादी, दलाल पूंजीपतियों और बड़े जमींदार के साजिश को ध्वस्त करो! भूमि अधिग्रहण नहीं, असली भूमि सुधार ही समय की मांग है!

जमीन हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए उत्पादन का प्रमुख जरिया है। इसे अपनी माता के सामान मानते हैं क्योंकि जमीन के उपज के सहारे ही किसान पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपना जीवनयापन और पालन पोषण करते हैं। इसी जमीन को चालू संसद सत्र में हमसे छीन लेने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 – एक उपनिवेशिक कानून जिसके 'कानूनी' आड़ में ब्रिटिश राज के दौरान इतिहास के सबसे अमानवीय और क्रूर भूमि अधिग्रहणों में से एक को अंजाम दिया गया। आज इसका सतही परिवर्तन कर एक नया नकाब पहनाया जा रहा है। सतही परिवर्तन इस लिहाज से कि इसका मकसद पहले जैसा ही है – हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का खुला लूट – उस समय उपनिवेशिक शासकों के स्वार्थ के लिए और अब साम्राज्यवादियों के लिए। और यह 'बदलाव' पहनके आएगा 'सही मुआवजा', 'पारदर्शिता', 'पुनर्वास और पुनर्स्थापन' का नया मुखौटा और भूमि अधिग्रहण के पत्थरिला जमीन पर औपनिवेशिक समय में बाकी रह गया जो भी रूकावट हो उसे भी नेस्तनाबूद कर देना। अर्थनीति से जुड़ा देश के सभी कानून जो उपनिवेशिक काल से ही जैसे की तैसे बरकरार रखा गया या 1947 के सत्ता हस्तांरण के बाद कुछ फेरबदल के साथ लागू किया गया वह साम्राज्यवादी ताकतों व भारत

के बड़े नौकरशाह पूंजीपतियों के उस दौर के अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलु जरूरतों के मुताबिक था। अभी पेश किए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम इससे अलग नहीं है। यूपीए–2 की सरकार द्वारा 'विपक्षी पार्टियों' के परोक्ष सहयोग से और कार्पोरेट मीडिया के व्यापक प्रचार के साथ लाया जा रहा बड़े 'सुधार' कार्यक्रमों का ही हिस्सा है, *भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन और उचित मुआवाजे का अधिकार विधेयक 2012*, जो पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की जगह लेने जा रहा है।

साम्राज्यवाद आज गहरी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बढ़ते हुए इस संकट से उभरने के लिए बैचेन वह भारत में उनके सबसे विश्वसनीय दलाल – प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री – के पीट पर उतावले होकर चाबुक चला रहे हैं और साथ में चिल्ला रहे हैं ''तेजी से'', ''और तेजी से''। हांफते हुए तीनों हमें ''आश्वासन दे रहे हैं कि सितम्बर 2012 में घोषित बड़े सुधारों के बाद अब और भी सुधारों को जल्दी ही लागू किया जाएगा। इसी वादे के तहत अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम को संसद नामके ढकोसले के जरिए जनता पर थोपा जा रहा है। जहां एक तरफ यह जमीन हड़पने का सबसे बढ़िया तरीका खोज निकालने के लिए शोषकों के बीच आम सहमति बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे बरसों के कोशिशों का नतीजा है, दूसरी तरफ इसपर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुहर लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश है।

जैसा कि इसका नाम ही सूचित करता है, यह विधेयक लोगों के जमीन को 'विकास' के नाम पर अधिग्रहण करने के लिए काम में लाया जाएगा। वह विकास जो भारत के शोषक वर्गों की भाषा में खदान, बड़े बांध, विशेष आर्थिक जोन, राजमार्ग, हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेल पथ, सैनिक शिविर आदि के समार्थक है। दरअसल 1947 के औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के समय से ही चल रही है (याद कीजिए नेहरू के 'आधुनिक मंदिर' यानी बड़े बांधों के द्वारा लाखों लोगों को विस्थापित किया गया था। जिन्हें आज तक कोई मुआवाजा नहीं मिला।) हालांकि 1991 के बाद पहली पीढ़ी के नई उदारवादी नीतियों को भारत में लागू करने के बाद इसके गति में और तेजी आ गई है। 1947 के बाद

का इतिहास दर्शता है कि लगभग बिना मुआवाजा – उपयुक्त मुआवाजा तो दूर की बात – बिना पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता के बिना ही भारत में सरकारी और निजी पूंजी (साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के) द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण विनाश की एक लंबी श्रृखंला है। (दस करोड़ विस्थापित, जिसमें से एक आकलन के मुताबिक केवल 17 से 20 प्रतिशत को ही किसी भी तरह का पुनर्स्थापन या मुआवाजा मिला।) इस विनाश का हिस्सा है भूमि अधिग्रहण की वजह से बड़े संख्या में लोगों की मौत, विस्थापन के खिलाफ और हमारे देश के बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं (जल–जंगल–जमीन, खनिज संपदा आदि) को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करने के विरोध में हुए जन संघर्षों का दमन आदि।

देश की जनता का 'विकास' से मोहभंग हो चुका था। भारत के मानचित्र में लाल निशानों की संख्या – जो भूख हड़ताल से लेकर सशस्त्र संघर्ष तक विभिन्न रूप में तथाकथित विकास की वजह से हुए विस्थापन के खिलाफ जनता के संघर्षों को दर्शता है – देशभर में तेजी से बढ़ने और फैलने लगा। इसकी वजह से विकास के इस विध्वंसी रथ थम गया। यही परिप्रेक्ष्य है 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवाजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक 2012' का, जो अब संसद में पारित होने के लिए तैयार है।

'जन प्रयोजन' (Public purpose) शब्द के दायरा को और व्यापक करते हुए यह विधेयक कृषि, कृषि उत्पाद के प्रोसेसिंग, कूल स्टोरेज, औद्योगिक कारिडोर, खदान, राष्ट्रीय उत्पादन नीति के द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पूंजी निवेश और उत्पादन क्षेत्र तथा कोई भी बुनियादी ढांचागत प्रकल्प जिसे सरकार संसद में पेश करने के बाद अधिसूचित करता है, इन सबके लिए इस विधेयक के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इस तरह यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए बेरोकटोक भूमि अधिग्रहण का राह प्रसस्त कर जो भी नाम मात्र का सम्प्रभुता और आत्मनिर्भरता रह गया था वह भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जमीन पर निर्भर किसानों के अलावा भी हमारे देश में करोड़ों ऐसे भूमिहीन लोग हैं जो अपने रोजी–रोटी के लिए जमीन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भरशील हैं। ऊपजाऊ जमीन के अधिग्रहण के बाद कृषि आधारित उद्योग भी

प्रभावित होंगे। यह साफ है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक केवल किसान परिवारों को ही नहीं बल्कि इन उद्योगों पर निर्भर मजदूर परिवारों को भी विघटित करेगा।

निजी कम्पनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले जमीन के 80 प्रतिशत मालिकों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी वाले कम्पनियों के लिए 70 प्रतिशत मालिकों की सहमति लिए जाने का प्रावधान यह भूमि अधिग्रहण विधेयक करता है। लेकिन यह सहमति प्रावधान केवल जमीन के मालिकों तक ही सीमित है, इसमें अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले सभी परिवारों का सहमति लेने का कोई व्यवस्था नहीं है। भूमि अधिग्रहण के इतिहास का निराशाजनक और अन्यायपूर्ण रिकार्ड को देखकर यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस 'सहमति' का क्या हश्र होगा। 80–70 प्रतिशत सहमति क्यों जब यह पूरे 100 प्रतिशत होनी चाहिए? भूमि अधिग्रहणों के परिणामों के बारे में लोग कितना जानकार होंगे? लोगों को गुमराह करने या अंधेरे में रखने के लिए कितने ही दुष्प्रचार किया जाएगा? इस प्रक्रिया में बल प्रयोग का कितना हिस्सा रहेगा और कितना रहेगा मध्यभोगियों का रिश्वत का हिस्सा? जमीन के लूट प्रतिरोध कर रहे जनता को दमन करने के लिए पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और विशेष बलों के हिंसा का व्यापकता कितना होगा? हर प्रदेश के लोग इन सवालों पर गौर किए हैं और इसके सच्चाई को उजागर किए हैं।

यह विधेयक सरकार को इस तरह के निरंकुश क्षमता देता है कि वह मनमाने ढंग से नहर और जल सिंचन सुविधायुक्त बहु फसलीय कृषि क्षेत्र को भी उस राज्य के विशेषताओं को ध्यान में रखने बहाने अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर सकता है। इसका व्यवहारिक मतलब यही होता है कि सरकार साम्राज्यवादियों – दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों को अपने इच्छा अनुसार ऊपजाऊ बहु फसलीय जमीन हड़पने के लिए सहयोग करेगा। पेसा कानून और वन अधिकार कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए इस विधेयक में उन्हीं ग्रामसभाओं और नगरपालिकाओं में पुनर्संस्थापन के रूपरेखा पर जन सुनवाई करने की प्रावधान है जहां से 25 प्रतिशत से ज्यादा जमीन अधिग्रहण

किया जाना है, न कि हरेक प्रभावित ग्रामसभा से। यह विधेयक सरकार को पुनर्संस्थापन और पुनर्वास योजना के घोषणापत्र जारी करने में टालमटोल करने की भी क्षमता देती है।

किसानों को मिलने वाला मुआवाजा (लाखों में) और उनके जमीन को फिर से बेचकर मिलने वाला रकम (करोड़ों में) के बीच का फर्क को देखकर भी अपनी जमीन मुनाफाखोर कम्पनियों को बेचने के लिए मजबूर किसानों की दुर्दशा का अनुमान असानी से लगाया जा सकता है। करोड़पति अरबपति में बदल जाते हैं और एक समय स्वतंत्र किसान बन जाते हैं कंगाल। इस विधेयक बेहद खतरनाक प्रावधान यह है कि अधिग्रहण किया हुआ जमीन अगर पांच साल तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया तो वह जमीन के मालिक के पास वापस न जाकर प्रदेश के भूमि बैंक में जमा होगा। इस प्रावधान की वजह से भारी मात्रा में जमीन अधिग्रहण होगा जिसको बाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हस्तांतरण करने के लिए सरकार के पास पूरा मौका रहेगा।

शहरी इलाकों में गरीबों के साथ–साथ मध्य वर्ग का भी व्यापक स्तर पर विस्थापन एक नियम जैसा बन गया है। शहरी (Land ceiling) कानूनों को दरकिनार कर दिया गया। यह विधेयक लागू हो जाने से व्यापक पैमाने पर गांवों से शहर की तरफ लोगों का पलायन होगा और इसके वजह से पहले से ही विकट शहरी बेरोजगारी की समस्या और भी भयंकर रूप लेगी। यह स्थिति साम्राज्यवादी – दलाल नौकरशाह पूंजीपति गठजोड़ के लिए अनुकूल है क्योंकि वह 2007 के अंत से गहरी आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं जिससे निकलने के लिए उन्हें बेरोजगारों की एक बड़ी फौज की जरूरत है जो मजदूरी के दर को कम से कम स्तर पर कायम रखेगा। फलस्वरूप, यह विधेयक भारत के संविधान में उल्लेखित कई मौलिक अधिकारों का, जैसे रोजगार, जीवन, खाद्य, शिक्षा का अधिकार और यहां तक कि मतदान का अधिकार – जिन अधि ाकारों के दम भरते संसद में बैठे लुटेरे कभी नहीं थकते – उल्लंघन होने जा रहा है। जमीन पर निर्भर तमाम लोगों के खाद्य और आजिविका के सुरक्षा पर और भी यह विधेयक एक बड़ा हमला है। यह क्षेत्रीय विषमताओं को अमीर और गरीब के बीच व्यवधान को तथा शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच अंतरविरोध

ा को तेज करेगा। यह विधेयक यहां तक कि औपचारिक संसदीय राजनीतिक ढांचा को भी नुकसान पहुंचाएगा और साथ–साथ प्रदेशों के क्षमता को सीमित कर फासीवादी केन्द्रीय सत्ता को मजबूत करेगा।

कांग्रेस पार्टी या इसके नेतृत्व में बहु दलीय गठबंधन 1947 के बाद ज्यादातर समय देश के केंद्र और राज्यों में सत्ता पर रहें हैं। जमीन की लूट का रथ का संचालन कर यही लाखों मजदूरों, किसानों और अन्य शोषित वर्गों तथा शोषित समुदाय जैसे दलित, आदिवासी, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक और पिछड़े क्षेत्रों की जनता को विस्थापित किया है। बाकी संसदीय पार्टियां भी इससे पीछे नहीं हैं। इन सभी पार्टियों को विस्थापित जनता अभियुक्त समझते हैं। साम्राज्यवादी मालिकों की सेवा में एकत्रित संसद की सभी पार्टियां इस विधेयक को पारित करने के लिए जल्द ही आम सहमति में आ गए।

विपक्षी दलों के 'आपत्तियों' का दायरा बहु फसली कृषि जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाने (समाजवादी पार्टी) से लेकर राज्य का भूमि अधिग्रहण में किसी भी तरीके के भूमिका का विरोध (त्रिणमूल कांग्रेस) शामिल है। एनजीओ आपत्ति और सुझाव आजिविका केंद्रित पुनरसंस्थापन और पुनर्वास योजना, भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभाओं की सहमति, प्रकल्प प्रभावित या विस्थापित लोगों के सौ प्रतिशत की सहमति, शहरी विस्थापितों के लिए उपयुक्त पुनर्संस्थापन की व्यवस्था आदि से संबधित है। इन विरोधों से प्रस्तावित विधेयक कुछ बुनियादी खामियां तथा इसके सीमिताएं तो रेखांकित होती है, लेकिन जब पूरी विधेयक ही जन विरोधी हो तो तब उसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करने का मतलब है उसे परोक्ष रूप से मंजूरी देना। सभी सत्ताधारी संसदीय दल जो केन्द्र या राज्य में शासन कर रहे हैं या पहले सत्ता में थे, बड़े पैमाने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन हड़पने के लिए बदनाम हैं। यह पार्टियां भू माफिया का रखरखाव और उनके द्वारा किसानों को, खासकर आदिवासियों और शहरी गरीबों को, बेदखल करने तथा राज्य के दमन तंत्र का इस्तेमाल कर विस्थापन के खिलाफ जनता के प्रतिरोध को रोकने के लिए भी जाने जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि इन पार्टियों में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने जमीन कब्जाकर अपना तिजोरी न भरा हो। और सभी

एनजीओ का भूमिका ठीक उसी तरह है जिसके लिए उनको प्रयोग में लाया गया था – यानी समाज में एक सुरक्षा दीवार (Safety valve) का भूमिका जो जनता के समस्याओं के समाधान के नाम पर यह निश्चित करने की कोशिश करते हैं कि देश के किसानों का सबसे बुनियादी मांग – जमीन जोतने वालों का हक – यानी असली भूमि सुधार के मांग पर समाज में सम्पूर्ण चुप्पी कायम रखना।

भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय कमेटी देश की जनता से अपील करती है कि वह इस प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने पर एकत्रित होकर संघर्ष करें। साथ ही, गरीब किसान, मध्यम व धनिक किसानों से लेकर शहरी गरीब तथा मध्य वर्ग तक उन सभी तबके जो इस विधेयक से प्रभावित होंगे, जनता के इस व्यापक हिस्से को भी हम एकताबद्ध होकर जल–जंगल–जमीन पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार के लिए और भूमि अधिग्रहण तथा विस्थापन के खिलाफ संघर्ष तेज करने की गुजारिश करते हैं। हमारी पार्टी फिर से दोहराती है कि असली भूमि सुधार के बगैर 'विकास' का कोई मायने नहीं। भारत एक अर्द्धसामंती–अर्द्धउपनिवेशिक देश है जिसके 70 प्रतिशत जनसंख्या अपने परवरिश के लिए अब भी जमीन पर निर्भर है। लेकिन सही भूमि सुधार लागू करने के बजाए देश लुटेरे शासक वर्ग किसानों के जमीन को विकास के बहाने कौड़ियों के भाव हड़पकर बेशुमार मुनाफा लूट रहे हैं। लाखों के तताद में गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर दिन–ब–दिन कंगाल होते जा रहे हैं। और उनके आत्महत्या की बढ़ती संख्या इस सामग्रिक त्रास्दी का ही एक प्रमुख संकेत है।

साम्राज्यवाद, मुख्यत अमेरिकी साम्राज्यवाद को हमारे देश के सभी क्षेत्रों पर, खासकर अर्थनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र पर बढ़ रहे हस्तक्षेप के साथ–साथ विदेशी सेना का देश में प्रत्यक्ष अवतरण के बिना ही नई उपनिवेशिक शोषण की प्रक्रिया तेज हो रही है। विशेष आर्थिक जोन को देश के कानून व्यवस्था के बाहर रखने का मतलब नाम मात्र सम्प्रभुता का भी मजाक बनने का ही सूचक है। अलग–अलग रूप में बढ़ती हुई नई उपनिवेशिक हस्तक्षेप की परिप्रेक्ष्य में नई जनवादी क्रांति के तहत एक असली राष्ट्रीय क्रांति की अभी सख्त जरूरत है। बड़े जमींदारों के स्वार्थ भी साम्राज्यवादियों और दलाल बड़े

पूंजीपतियों से अलग नहीं है। इसलिए हमारी केन्द्रीय कमेटी यह स्पष्ट ऐलान करना चाहती है कि नई जनवादी क्रांति के धुरी के रूप में सशस्त्र कृषि क्रांति ही जनता के इन तीनों दुश्मनों को उखाड़ फेंक कर देश में असली भूमि सुध ाार, असली लोकतंत्र, आत्मनिर्भरशीलता तथा सम्प्रभुता कायम कर इस विनाशकारी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगायेगी। हम देश की जनता से गोलबंद होकर गद्दारों और साम्राज्यवाद के पालतू कुत्तों – जो संसदीय लोकतंत्र के आड़ में सत्ता में काबिज होकर देश को नीलाम कर रहे हैं – के खिलाफ चल रहे दीर्घकालीन जनयुद्ध को व्यापक और विस्तारित करने की आह्वान करती है ताकि भारत की नई जनवादी क्रांति को अपने मुकाम तक पहुंचाया जा सके।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

11-6-2013

25 मई की हमला को एक बहाना बनाकर भारत के शासक वर्ग जनता पर और बड़ा आक्रामक युद्ध छेड़ने की षड्यंत्र का पर्दाफाश करो !

संगठित हो, प्रतिरोध करो और 'जनता पर युद्ध' को परास्त करो !

जिस गुण्डा गिरोह ने भारत के संसद को अपना अड्डा बना लिया है वह आज विचलित है। वह हैरान है, आतंकित है, गुस्से में है, युद्धोन्माद है, खून के प्यासे हैं, कत्ले-आम पे आमादा है। क्यों न हो ? आखिर 25 मई के दरभा घाटी हमले ने उनके सबसे काबिल सिपाह-सालारों में से एक को जो मार गिराया! उसके बोखलाहट को हम भली भांती समझ सकते हैं।

सच्चाई यह है कि घोटालेबाज गुण्डा गिरोह को महेंद्र कर्मा के मौत का कोई परवाह नहीं। जब वह सलवा जुडूम का कहर ढा रहे थे और कत्ले-आम को अंजाम दे रहे थे तब से ही वह कर्मा के इस अंत से अच्छी तरह वाकिफ थे। सलवा जुडूम के कर्ता-धर्ता यही लोग थे जो इसका दूर से निगरानी कर रहे थे जब की महेन्द्र कर्मा इस मुहिम का परिचित चेहरा था और केन्द्र और राज्य के फासीवादी सुरक्षा बलों का जिसे पूरा समर्थन हासिल था। वह इसलिए भी ज्यादा घबराये हुए है क्योंकि भारत जैसे एक देश में जहां हर किस्म के शोषण, दमन, भ्रष्टाचार और धांधली को लगभग बेलगाम और बेरोक-टोक दिन दहाड़े बेशर्मी के साथ अंजाम दिया जाता है, यह बात हजम करना आसान नहीं के 'कोई' इस फासीवादी, घोटालेबाज और भ्रष्ट गुण्डा गिरोह को न्याय के कठघरे में खड़ा करे और उन्हें सजा दिला सके। यह ऐसी ही परिस्थिति है जब जेड प्लस सुरक्षा का पर्दा गिर पड़ता है, पूरा पुलिसिया

बन्दोबस्त नाकाम हो जाता है और वह अपने आपको शोषित जनता के क्रोध के सामने बेनकाब और लाचार पाता है। क्या नाराज होने का यह जायज और पर्याप्त कारण नहीं !!

कौन जाने अगला नम्बर किसका आयेगा ? और भी खतरनाक, क्या होगा अगर देश के अवाम इन दलाल राजनेताओं के बेहद असहनीय, जनविरोधी, चतुर करतुतों का खात्मा करने के लिए दरभा घाटी के मोडल को एक औजार के रूप में अपना लेता है? इससे भी खतरनाक होगा वह मंजर अगर जनता इस संसदीय व्यवस्था के साथ साथ राजनेताओं के इस पूरे गिरोह को ही उखाड़ फेंकने का ठान ले, जैसे के माओवादी एलान करते हैं और जनता को इसके लिए आह्वान करते हैं ? सचमुच गहरे परेशानी की बात है!

और उन्हें कम से कम एक बार परेशान होना ही बेहतर है। यह उनको समझ लेना जरूरी है की हर राजनीतिक नेता जो देश के गरीब जनता पर नई-फासीवादी अत्याचार की होड़ लगा देता है - चाहे वह सलवा जुडूम के नाम से हो या सेन्द्रा, शान्ति सेना, शान्ति यात्रा, हर्मद वाहिनी, भैरव वाहिनी, टीपीसी, आपरेशन ग्रीन हंट के रूप में - हमेशा बचके नहीं जा सकते। उनको यह जान लेना चाहिए कि देश की जनता के संपदाओं को एक के बाद एक दिन-ब-दिन नीलाम करके और उस से साम्राज्यवादी ताकतों का तिजौरी भरके वह अपने आपको बचा नहीं पायेंगे। वह बच नहीं पायेंगे बेमतलब करके हर वो शब्द - आजादी, सार्वभौमत्व, स्वावलंबन, जनवाद - जो हमारे जिन्दगी को सार्थक बनाते हैं। उनको और एक बार (स्पार्टकस से ले कर आज तक अनगिनत बार) यह सबक लेनी चाहिए कि जनता का वह तबका जिसको इतनी बेरहमी से कुचला जा रहा है वह हमेशा चुप नहीं बैठेगा। वह एक बार बोखला जाये तो ही अच्छा है।

महेन्द्र कर्मा, जो एक मध्यकालीन जमींदार, सलवा जुडूम का जनक, लुटेरा, बलत्कारी और अपने ही आदिवासी भाई-बहनों के दुश्मन था, और उसके सुरक्षा कर्मी जो जनसंहारों और जनता के दमन मे उसका हथियार था, कुछ सलवा जुडूम के सरदार और आला कांग्रेसी नेताओं का 25 मई के हमले में सफाया हो गया। घटनाक्रम में कुछ अन्य लोग भी मारे गये जो शुरुवाती गोलीबारी के लपेट में आ

गए। हमले के प्रमुख निशाना हाथ में आने के बाद की गई हमारे अथक प्रयासों के बावजूद जिनकी जाने गई उनके मृत्यु के लिए हमारे दण्डकारण्य पार्टी प्रवक्ता कामरेड गुड्सा उसेन्डी ने पहले ही खेद व्यक्त किया है। कर्मा और उस जैसे दरिन्दों के करतूतो के दस्तावेजों से कई किताबें भरी जा सकती है। उनमें से कई वारदातों का भाकपा (माओवादी), क्रांतिकारी और जनवादी जनसंगठनों, मानवाधिकार संगठनों, जनवादी बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और न्यायपसंद नागरिकों ने खुलासा किया है। लेकिन इसके बावजूद इस हमले के पीछे कारणों को उजागर करने के नाम पर जो सारे बेबुनियाद साजिशों के बारे में संवाद माध्यमों में चर्चा हो रहे हैं उसका एक ही मकसद है जनता को सच्चाई से भटकाना। यह कार्पोरेट मीडिया का सच को छुपाने का और सलवा जुडूम, भारतीय सेना, बड़े पूंजीपतियों, केन्द्र और राज्य सरकारों, कांग्रेस और भाजपा की इसमें मिलीभगत, कर्मा का एक खुंखार आदमखोर के रूप में जन्म और विकास - इन सब पहलुओं पर पर्दा डालने की एक साजिश है। माओवादी आंदोलन को कुचलने के लिए वह इतना बेताब है कि इस सच्चाई का भी कोई जिक्र नहीं किया जाता कि उनके ही संस्थान सर्वोच्छ न्यायालय ने ही सलवा जुडूम को गैर कानूनी घोषित किया है। और जयराम रमेश समेत यह सभी लोग फिर से वहीं घिसापिटा और निरर्थक 'सेन्डविच थियोरी' का तर्क दोहरा रहे हैं जिस में कहा जाता है कि आदिवासी एक तरफ सरकारी सशस्त्र बलों और दुसरे तरफ माओवादियों के बीच पिस रहे हैं। अगर इस तर्क में वह सही में विश्वास रखते हैं तो फिर क्यों न वह पहले केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लाखों के तादाद में बहाल की गई सशस्त्र बलों को फौरी तौर पर वापस बुलाने की मांग करते हैं, जब वह मान ही रहे हैं कि सरकारी बल आदिवासियों का दमन करते हैं ? उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए यह तथ्य काफी है कि माओवादी आन्दोलन के मजबूत इलाकों में ज्यादातर माओवादी आदिवासी हैं। हम फिर से दोहराते हैं कि हम कभी जनता के हित के खिलाफ काम नहीं करते हैं। सिर्फ शासक वर्गों और उनके सेना है जो जनता पर दमन करते हैं और हमारी पार्टी इस दमन का प्रतिरोध करती है।

जनता के दुश्मनों को सच का सामना करना ही होगा - इस नंगे और सादे सच का। हमारे पार्टी और जन मुक्ति गुरिल्ला सेना दमन और शोषण के खिलाफ

प्रतिरोध के अधिकार के लिए संघर्षरत है। 25 मई को हमारे जांबाज गुरिल्ला सैनिकों ने जनता के प्रतिरोध का अगुवाई करके भारत के मुख्यतः दण्डकारण्य और खासकर बस्तर के क्रांतिकारी जनता के एक प्रमुख दुश्मन का खात्मा किया। यह हमला जनता के बड़े जमीन्दार और बड़े पूंजीपतियों के लूट-खसोट के खिलाफ व्यापक संघर्ष का हिस्सा है। और हम इस मौके पर फिर से यह ऐलान करना चाहते हैं कि जनमुक्ति गुरिल्ला सेना जनता और उनके प्रतिरोध के अधिकार को हमेशा रक्षा करती रहेगी। वह जनता के पहली कतार में शामिल होकर उनकी तब तक अगुवाई करेगी जब तक सरकारी सेना, सलवा जुडूम जैसे गुन्डा गिरोह और वर्ग दुश्मन 'जनता पर युद्ध' को जारी रखता है।

यह तो रही 25 मई के हमले की बात। लेकिन हम जिस बात के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते है वह ये है कि जब भी इस तरह का हमला होता है उसी मौके पर जनवाद और गणतंत्र का प्रश्न को सामने लाया जाता है, उसे बहस का मुद्दा बनाया जाता है। क्या यह अजब स्थिति नहीं है कि गणतंत्र संसद के चौराहे पर बिकनेवाला एक ऐसा माल बन गया है जिसको तभी बेचने के लिए बाहर लाया जाता है जब शोषित जनता देश के किसी कोने में बहरों को सुनाने के लिए भगत सिंह के तरीके अपनाते हैं ? सच में हम भी इस बात से चिंतित है कि माओवाद चर्चा में तभी आता है जब इस तरह की वारदातें होती हैं। व्यतिक्रम के रूप में क्यों न हम अपने चारों ओर नजर दौड़ायें और गौर करें उन बातों पर जो जनवाद और माओवाद को आज एक चर्चा का जरूरी विषय बना सकता है ?

अपने सामाजिक फासीवादी चरित्र को बखूबी उजागर करते हुए माकपा के पोलितब्यूरो ने "माओवादी उपद्रव" को रोकने के लिए "कड़ी कार्रवाई" की मांग की है और "सारे जनवादी शक्तिओं को माओवादियों के हिंसा की राजनीति के खिलाफ खड़े होने की" गुजारिश की है। कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और जद (यू) से लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस हमले को निंदा करने की होड़ लगा दी है। लेकिन इनमें से कोई भी दरभा घाटी हमले के सही कारणों का चर्चा नहीं करना चाहता है। बड़े पूंजिपतियों के दलाल और चाटुकार कार्पोरेट मीडिया ने तो तथाकथित गणतांत्रिक संस्थानों से भी आगे बढ़कर माओवादियों की खून की मांग की है।

25 मई के हमले के संदर्भ में बुलाए गये मुख्यमंत्रियों के बैठक और सर्वदलीय बैठक ने इस घटना को देश के "गणतंत्र और स्वतंत्रता" के ऊपर एक सीधा हमला ठहराया है। मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में घोषणा किया, "हम माओवादियों के आदर्श का घोर विरोध करते हैं। वह हिंसा द्वारा भारत के संसदीय गणतंत्र और संविधान को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसको हर हालत में पूरे ताकत के साथ रोकना होगा।" उन्होंने भाकपा (माओवादी) के कार्यकलापों को रोकने के लिए "सभी वैध उपायों का उपयोग करने" का प्रस्ताव पारित किया। उसी आवाज में उन्होंने माओवाद को सहन नहीं करने की और इसके साथ किसी भी प्रकार के समझौते नहीं करने की भी ऐलान किया। साथ में कहा है, "हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं से अपील करते हैं कि वह हिंसा का रास्ता छोड़ कर अपने लक्ष्य को वैध और जनवादी तरीके से हासिल करे। हम उनको यह आश्वासन देते हैं कि हम उनके आकांक्षाओं से हमदर्दी रखते हैं और उनको समाज और राजनीति के मुख्यधारा में लाने की हर संभव कोशिश करेंगे"। इसी समझ को सर्वदलीय बैठक ने भी दोहराया।

गणतंत्र ? जनवाद ? स्वतंत्रता ? किसका और कहां ? इन अर्थहीन शब्दों के मायने पूछो उन महिलाओं से जिन्हें बलात्कार/सामूहिक बलात्कार और/ अथवा हत्या किया गया, या फिर पूछो उन बच्चों से जो सलवा जुडूम जैसे हत्यारे गिरोह के द्वारा उनके परिजनों और गांववालों पर किये गये उत्पीडन तथा जन संहारों का या तो गवाह है या फिर इसका शिकार बने। हमे तो वही 'गणतंत्र' दिखाई पड़ता है जिसमें लुटेरों को हमारे देश के बहुमूल्य संपदाओं को कौड़ीयों के दाम में साम्राज्यवादियों के हाथों सौंपने की और अपना हिस्सा हथियाने की खुली छूट मिली हुई है। हमे तो 'स्वतंत्रता' का वही स्वरूप दिखता है जिसमें सुरक्षा बलों को लूटने की, जलाने की, बर्बाद करने की, बलात्कार करने की, जनसंहार करने की और शोषित जनता को बड़े जमींदार और बड़े पूंजीपतियों के खातिर विस्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत का संसद विश्व के उन सड़े-गले संस्थानों में से एक है जो इन सभी करतूतों को "गणतंत्र और स्वतंत्रता" के नाम पर प्रोत्साहित करता है। तो फिर इस संसद को, जिसने भारत के जनता को पिछले साठ साल से घोर अन्धेरे में रखा है, इस संसद को जड़ से उखाड़ फेंकने के अलावा जनता के पास और विकल्प ही क्या है ? क्या तुमने ही स्कूलों में नहीं सिखाया कि जनता से, जनता के लिए और

जनता द्वारा ही गणतंत्र है ? तो जब यह संसद जनता के स्वार्थ के विरुद्ध काम करने के लिए ही उपयोग होता है तब क्या जनता का यह हक नहीं बनता की वह इसे खारिज कर दे और उखाड़ फेंके ? ताडिमेटला या दरभा घाटी जैसे हमले जनता के प्रतिरोध का अभिन्न अंग है और रणनीति का हिस्सा है जो लाखों के तादात में उतारे गये अत्याधुनिक हथियारों से लैस सरकारी बलों के दमन का जवाबी कार्रवाई है। हमारे राजनीतिक सिद्धांत और कार्यपद्धति को इस तरह के हमले तक सीमित करके देखना सही नहीं है। भाकपा (माओवादी) एक राजनीतिक दल है जिसके पास मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का एक ठोस वैज्ञानिक विचार है, एक राजनीतिक दिशा और राजनीतिक कार्यक्रम है जो देश के जनता को असली जनवाद की स्थापना के तरफ ले जायेगा। माओवाद के बारे में कुछ बोलने या लिखने और माओवादियों के ऊपर 'आतंकी', 'वाम उग्रवादी' का ठप्पा लगाने से पहले हमारे यह दस्तावेज जरूर पढ़ लेना चाहिए।

संक्षिप्त में, माओवादी पार्टी का कार्यक्रम कहता है की भारत एक अर्द्ध-सामन्ती और अर्द्ध-औपनिवेशिक देश है; हमारे क्रांति के निशाने पर है साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और सामंतवाद, जो हमारे देश के जनता का शोषण और दमन कर रही है। जिसको नई जनवादी क्रांति के जरिये उखाड़ने के बाद एक लोकजनवादी राष्ट्र को यानी नवजनवादी राष्ट्र की स्थापना की जायेगी। सामंतवाद और व्यापक जनता के बीच का अंतरविरोध मौजूदा समय का प्रधान अंतरविरोध है। सशस्त्र कृषि क्रान्ति, जो नवजनवादी क्रांति की धुरी है, के जरिये यानी लोकयुद्ध के जरिए इस अंतरविरोध को हल करने के प्रक्रिया के दौरान ही बाकी अंतरविरोधों को हल करने का रास्ता आसान होगा। भारतीय समाज का अर्द्ध-औपनिवेशिक, अर्द्ध-सामन्ती चरित्र यह निर्धारित करता है कि भारतीय क्रान्ति को अवश्य ही दो मंजिलों से गुजरना होगा। पहली मंजिल का कार्यभार है - वर्तमान भारतीय समाज के दो मौलिक अन्तरविरोधों, अर्थात् साम्राज्यवाद के साथ भारतीय जनता के अन्तरविरोध और सामन्तवाद के साथ व्यापक जनता के अन्तरविरोध को हल करने के दरम्यान अर्द्ध-औपनिवेशिक, अर्द्ध-सामन्ती समाज को एक स्वतन्त्र नई जनवादी समाज में बदल डालना। फिर इसी धारावाहिकता में दूसरी मंजिल का कार्यभार है - समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना और क्रान्ति को निरन्तर जारी रखते हुए

विश्व के पैमाने पर साम्यवाद की ओर आगे बढ़ते जाना।

मजदूर, किसान और शहरी गरीब जनता जो देश के जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है आज भूखमरी, गरीबी, बिमारी, अमानवीय सामंती-साम्राज्यवादी शोषण और उत्पीड़न का शिकार है। उनको नई जनवादी क्रांति के जरिये मुक्ति मिलेगी। नव जनवादी क्रांति ब्राह्मणवादी सामंती जातिवाद के सीढ़ीनुमा सामाजिक उच्च श्रेणीक्रम (hierarchy) को उखाड़ फेंकता है जो सहयोग से दलितों और अन्य उत्पीड़ित जातियों के दमन का कारण है। यह महिलाओं को - जो समाज की आधी आबादी है - सामंती और साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीड़न से आजादी दिलाती है। धार्मिक अल्पसंख्यक - खासकर मुसलमान और ईसाई समुदायों को - हिंदु सांप्रदायिकता से मुक्त करेगा। और राज्य की वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की ग्यारंटी करेगा। आदिवासियों के भारी बहुसंख्या को बिना कोई विकल्प उपलब्ध कराये लम्बे दिनों से भूमि और जीविका के दूसरे परंपरागत साधनों से वंचित कर दिया गया है। वह तथाकथित "विकास" और उससे उत्पन्न विस्थापन का सबसे ज्यादा शिकार है। नव जनवादी समाज में वह इज्जत, स्वतंत्रता और स्वावलंबन की जिंदगी जी सकेंगे। आज का भारत राष्ट्रीयताओं का कारागार है। नव जनवादी राज्य राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार का और वर्तमान केन्द्रीकृत राष्ट्रतंत्र को पूरी तरह चकनाचूर करके स्थापना की जानी वाली लोक जनवादी गणराज्य के महासंघ से अलग होने का अधिकार को दृढ़ता से समर्थन करेगा। यह क्षरणशील, सामंती, औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी संस्कृति, जो हमारे जीवन की हर क्षेत्रों पर हावी है, और जिसका प्रतिफलन श्रम के प्रति नफरत, पितृसत्ता, अंधविश्वास व कुसंस्कार, निरंकुशता, साम्राज्यवादी गुलामी, अंधराष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, अंधलुलुपता, आत्म केन्द्रीकता, उपभोक्तवाद, विकृत योनलिप्सामूलक विचारधारा आदि में दिखाई देता है, इसके स्थान पर क्रांतिकारी नवजनवादी संस्कृति को स्थापित करेगा। यह सामंती संस्कृति, जो मुख्यतः अहंकारयुक्त जाति आधारित संस्कृति है, को खत्म करेगा। यह नव जनवादी राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा, पानी और दूसरे विवादों को शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीकों से सुलझाने का भरपूर प्रयास करेगा और उनके साथ मैत्रिपूर्ण संबंध विकसित करेगा। यह राज्य पड़ोसी देशों के साथ कभी भी विस्तारवादी व्यवहार नहीं करेगा।

भाकपा (माओवादी) ने इन बिंदुओं पर आधारित लोकजनवादी गणराज्य के महासंघ यानी नव जनवादी राज्य के भावी स्वरूप को अपने पार्टी कार्यक्रम के पच्चीस सूत्रीय कार्यभार के रूप में जनता के सामने रखा है। माओवाद पर होनेवाली कोई भी अर्थपूर्ण चर्चा या संवाद इस कार्यक्रम को केन्द्र में रख कर करें।

भारत के शासक वर्ग ने युवाओं को हिंसा का पक्ष छोड़कर 'वैध और जनवादी' तरीके से अपने आकांक्षाओं को पूरा करने की अपील की है। क्या यह ठीक बात है ? लेकिन 'वैध और जनवादी' तरीकों को अपनाने के लिए पहले जनवाद का होना लाजमी है। मजदूरों और किसानों के संगठन, खेत मजदूरों के संगठन, महिलाओं के संगठन, सांस्कृतिक संगठन, युवा और छात्र संगठन, और यहां तक की बच्चों के संगठन को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। लेखक, सांस्कृतिक कर्मी, जनवादी नागरिक, बुद्धिजीवी और उनके संगठनों के आवाज को दबाया जा रहा है। बुनियादी अधिकारों का रोज हनन हो रहा है। बढ़ते राजकीय दमन के साथ साथ औपनिवेशिक-कालीन जनविरोधी कानूनों का फिर से ईजाद किया जा रहा है या इनमें अकसर तबदीलिया लाया जा रहा है। अदालत बड़े घोटालेबाजों, भ्रष्ट राजनेताओं, तस्करों और बड़े पूंजीपतियों के तरफदारी करता है जबकि राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता और निर्दोष जनता को जेल में ढकेल दिया जाता है, यातनायें दिया जाता है और मौत के घाट उतारा जाता है। यही आज हमारे प्यारे देश के युवा - जो भारत को एक सही मायने में आजाद, सार्वभौम, जनवादी और खुशहाल देश के रूप में विकास करने की क्षमता रखते हैं - भुगत रहे हैं। आज के युवा जिनको लाखों के तादात में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल सोची समझी तरीके से हत्या कर रही है, चाहे वह कश्मीर में हो या उत्तर पूर्व में, या फिर आंध्रप्रदेश, दण्डकारण्य, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, मध्यप्रदेश और अन्य क्रांतिकारी इलाकों में, वह हमारे समाज के सबसे मेहनती और सृजनशील युवाओं में से है, जिन्होंने देश के भविष्य को एक बेहतर रूप देने के लिए जनवादी, क्रांतिकारी, शोषित राष्ट्रीयता के संगठनों और पार्टियों में हिस्सेदारी की है या उसको संगठित किया है। यह एक जमीनी सच्चाई है की युवाओं ने दशकों से अपनी मांगो और हकों के लिए 'वैध और जनवादी' तरीकों से लड़ने और उसको भारत राष्ट्र द्वारा बेरहमी से कुचले जाने

के बाद ही हाथ में हथियार उठाने का और सिर्फ जनता के ताकत पर निर्भर होकर एक नई समाज और एक नया भविष्य तैयार करने का ऐतिहासिक कार्यभार अपने कंधों पर लिया है। उनको हथियार त्यागने का आह्वान करना और 'वैध और जनवादी' तरीके इस्तेमाल करने का सलाह देना सच्चाई को अनदेखा करना ही नहीं एक भद्दा मजाक भी है। युवाओं ने बंदूक इसलिए नहीं उठाये हैं कि उनको हिंसा से लगाव है या वह जनवाद से परहेज करते हैं या फिर उनको एक ऐसा माहौल उपलब्ध है जिसमें 'वैध और जनवादी' तरकिबों की सुनवाई हैं। स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। इन्होंने बंदूक इसलिए उठाये हैं क्योंकि वह असली जनवाद के पक्षधर हैं। हमारी नई जनवादी क्रांति इसी की हिमायत करती है, आज के तथाकथित 'जनवाद' और 'गणतंत्र' के बदले।

यह सरकार जिसने जनता के बुनियादी समस्याएं जैसे जमीन, शिक्षा, स्वास्थ आदि का मुख्यमंत्रियों के बैठक या सर्वदलीय बैठक में जिक्र तक नहीं किया, अब युवाओं को - मुख्यतः आदिवासी युवाओं और महिलाओं को - हजारों संख्या में रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की और उनमें से आधे को सुरक्षा बलों में भर्ती करने की घोषणा की है। यह विकास के 'पेकेज' के अंतर्गत है (दूसरा है दमन का 'पेकेज' जो हत्या और दहशत का पेकेज है और जिससे अपनी युवा ज्यादा परिचित है।) उन नौजवानों के पैरों से पहले तो जमीन खींच लिया जाता है, उनको अपने पुरखों के घरों से बेघर कर दिया जाता है, उनको रोजगार के पारंपरिक साधनों से महरूम किया जाता है और बदले में कुछ हजारों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने का वादा किया जाता है जो उनको अपने पैरों पर खड़े होने में कोई मदद नहीं करता। विकास का यह क्या नयाब नमूना है ! इस तरह के नौकरी अगर एक छोटे तबके को दिया भी जाता है तब भी यह एक परिवार के जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। जंगल के पारंपरिक साधनों से कट जाने और रुपये के मूल्य में आयी भारी गिरावट के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो गयी है।

जिस दम्भ के साथ शासक वर्ग नौजवानों के हिमायती होने का दावा पेश कर रहे हैं वह देखने लायक है। यह सब उनके झूठे वादे हैं और धोकेबाजी हैं। युवाओं के सामने आज की सच्चाई तो आसमान छूती बेरोजगारी है। अगर वह सही में नौजवानों के लिए चिंतित है तो PESA, पांचवी और छठवी अनुसूची, वन

अधिकार (FRA) जैसे कानून - जो उनके ही संसद में पारित किया गया है और जिनके लिए नौजवान चिंतित हैं - को क्यों लागू नहीं करते ? यह हमें समझना चाहिए कि यह सब माओवादी पार्टी के खिलाफ चलाये जा रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है जो नौजवानों को संघर्ष के राह से भटकाना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री जिस समय मुख्यमंत्रियों के बैठक में यह कहते हैं कि सरकार सभी 'उग्रवादी संगठनों' से वार्ता करने को तैयार है, ठीक उसी समय गृह सचिव आर के सिंह कहते हैं कि 25 मई घटना के बाद माओवादियों से बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं है। जाहिर है कौन इस तरह के पालसी निर्धारित करते हैं। हमारे पार्टी ने पहले ही कई बार सरकार के साथ वार्ता को लेकर हमारे रुख को स्पष्ट किया है। हम उन सारे लोगों और जनवादी नागरिकों - जो सराकर के साथ वार्ता का हिमायत कर रहे हैं, और सरकार के तरफ से वार्ता के लिए किये गये आह्वान का फाइदा उठाने के सलाह दे रहे हैं - हम उन सभी का ध्यान सिर्फ इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इस तरह के सरकारी आह्वान के पीछे कितना गंभीरता है इसका अंदाजा वह खुद लगायें। क्योंकि वर्तमान एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सरकारी बल माओवादी संघर्ष के इलाकों में हत्या, विध्वंस, यातना और बलात्कार के उद्देश्य से कोई अभियान नहीं चला रहे हो। और हमारे कई वरिष्ट नेता सालों से अमानवीय परिस्थिति में कैद हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाओं तथा जमानत से भी सालों साल वंचित किया जा रहा है।

अभी के संदर्भ में नजर आता है कि भारत के शासक वर्ग माओवादियों को खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान के तैयारी में है और 25 मई के हमले को वह महज एक बहाने के तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हम सभी से आह्वान करते हैं कि वह इस सरकारी साजिश को समझे और यह न सोचे कि 25 मई जैसी घटनाएं राज्य दमन को बढ़ावा या न्यौता देते हैं। सच्चाई तो यह है कि एड्समेट्टा जैसे जनसंहार जिसमें तीन बच्चे समेत 8 आदिवासी ग्रामीणों को राजकीय सेना ने हफ्ते भर पहले 17 मई को हत्या किया, 'जनता के ऊपर युद्ध' का ही हिस्सा है। जनसंहारों के साथ साथ इस नये अभियान का हिस्सा होंगे हवाई हमले - भारतीय वायुसेना के कई यूनिट, चालक विहीन विमान और ड्रोन। रक्षामंत्री ने घोषणा किया है कि भारतीय सेना को नक्सल विरोधी अभियान में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

पर 25 मई के बाद और उससे पहले भी सेना इस मुहिम में कोवर्ट रूप से शामिल है। एक विदेशी राष्ट्र पर हमला करने की तैयारी की तरह ही जनता के खिलाफ युद्ध के लिए पुरजोर तैयारी चलायी जा रही है। 17 मई के जनसंहार के बाद एड्समेट्टा के जनता ने दर्दनाक तरीके से यह सही कहा है कि "वह आदिवासियों को खत्म करना और जड़ से मिटाना चाहते हैं"।

इस अवसर पर हम फिर से उन लोगों से अपील करना चाहते हैं जो सारकिनगुडा, एड्समेट्टा आदि आदिवासी जनसंहारों के बाद पूर्णरूप से विलुप्त होने के डर से अपने अपने गांवों से पलायन कर रहे हैं, पलायन के बजाय वह क्रांतिकारी जनतना सरकार के नेतृत्व में एकत्रित होकर राज्य के हमले का प्रतिरोध करें। पार्टी और पीएलजीए आपके जान और अधिकारों के सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए वचनबद्ध है।

हम देश के व्यापक जनता - मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, महिला, दलित, आदिवासी, प्रगतिशील नागरिक, उत्पीड़ित राष्ट्रीयता, धार्मिक अल्पसंख्यक और इन वर्ग, तबको और जन समूहों के संगठनों से अपील करते हैं की वह शासक वर्ग - जो साम्राज्यवाद, मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवाद के दलाल है - जनता के ऊपर ठोपने के लिए कर रहे दमनकारी हमले की तैयारी को समझे। व्यापक रूप से संगठित होकर और प्रतिरोध में एकत्रित शक्ति बनकर इस फासीवादी मुहिम को ध्वस्थ करें। इस तरह ही हम राज्य के आतंक से मुक्त होकर असली जनवाद और असली आजादी के तरफ कदम बढ़ा सकते हैं; अपने युवाओं को - जो हमारे देश के भविश्य का सबसे मूल्यवान धरोहर हैं - बचा सकते हैं।

अभय
प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

26-6-2013

उत्तराखण्ड में आई आपदा भारत के दलाल शासक वर्गों के साम्राज्यवादपरस्त – जनविरोधी अर्थ नीतियों व पर्यावरण नीतियों का परिणाम है!

बादल फटने और मुसलाधार वर्षा के कारण 16 जून 2013 से आई प्रलयकारी बाढ़ ने उत्तराखण्ड राज्य में भारी तबाही मचाई। हजारों की संख्या में लोग और अनगिनत तादाद में मवेशी मारे जाने की आशंका है। एक लाख से ज्यादा लोगों को बचाए जाने के बाद भी हजारों अन्य की पहाड़ो में फंसे होने या लापता होने की अंदेशा अभी भी है। त्रासदी को हुए दस दिन गुजरने के बाद अब यह भी खबर है कि बहुत से लोग भुखमरी से मर सकते हैं। साथ ही, इस तरह के भयानक तबाही के बाद जिसमें बड़ी संख्या में लोग और पशुओं की मौत हुई है, महामारी फैलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बाढ़ से हजारों करोड़ों की संपत्ति भी बर्बाद हो गई है। गांव के गांव, घर और मकान, गाड़ियां, सड़क, पुल, दूरसंचार और हर तरह के बुनियादी ढांचा, यानि हर एक ऐसी संरचना जो इस सैलाब के सामने आया वह बर्बाद हो गया या बह गया। यह तबाही सर्वव्यापी था और इसका पैमाना बेहिसाब। रोजगार की क्षति इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि स्थानीय जनता के लिए इसका दीर्घकालीन परिणाम बहुत ही दुखद होंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि जनता को इस आपदा से उबरने और अपनी आम जिन्दगी में लौटने के लिए बरसों लग सकते हैं।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी उत्तराखण्ड के जनता की इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। और उन तमाम लोगों के प्रति जिन्होंने अपने परिजनों व अपनों को खो दिया है, तहेदिल से अपनी संवेदना प्रकट करती है। हम उन सभी के दुख के सहभागी हैं जो गंभीर शोक और त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। हम अपने पार्टी के सभी सदस्यों, पीएलजीए,

क्रांतिकारी जन कमेटियों, क्रांतिकारी जन संगठनों और जनताना सरकारों से अपील करते हैं कि वह उत्तराखण्ड की जनता का साथ दें तथा उनके राहत और पूनरवास के काम में सहयोग करें और उनको हर तरह से मदद पंहुचाने का यथासंभव कोशिश करें। हम आज गंभीर और आक्रामक राज्य हिंसा से घिरे रहने के बावजूद हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उत्तराखण्ड की जनता का साथ दें। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी सभी से आग्रह करती है कि वह पीड़ित लोंगों की मदद के लिए आगे आएं और उनके पूनर्वास में सहयोग करें।

राहत और बचाव का काम फौरी तौर पर पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि हम आज के संदर्भ में कुछ अहम सवालों पर गौर करें। क्या इस भयानक आपदा को टाला जा सकता था? क्या इस खौफनाक त्रासदी से बचा नहीं जा सकता था? या कम से कम इससे हुइ तबाही को कम किया नहीं जा सकता था, जबकि जलवायु, भू–तत्व और जलविज्ञान आदि क्षेत्रों में भारी प्रगति हुइ है? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह आपदा मानव–निर्मित था? इन सभी सवालों का दुःखद लेकिन सही जवाब है – हां।

प्राकृतिक आपदा अतित में भी हुए हैं और जाहिर है भविष्य में भी होंगें। लेकिन यह 21वीं सदी है और विज्ञान में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। इन ''प्राकृतिक आपदाओं'' के पीछे का असली त्रासदी यही है कि विज्ञान को जनता के सर्वात्मक विकास के लिए उपयोग में लाने के बजाए उसे आज मुनाफाखोर साम्राज्यवादियों और भारत के दलाल बड़े पूजीपतियों की सेवा में लगाए गए हैं। इसका ही परिणाम है ''विकास'' का यह एकतरफा मॉडल जिसका एकमात्र मकसद है लालची बड़े कंपनियों के लिए मुनाफा बटोरना, न कि जनता का कल्याण, जैसे कि दावा किया जाता है। उत्तराखण्ड में आई आपदा इसी जनविरोधी अर्थनीति और पर्यावरण नीति का तथा विकास के मॉडल का नतीजा है।

प्रकृति के गोद में प्राचीन जंगलों और प्रदूषणरहित नदियों से भरे उत्तराखण्ड पूरे विश्व के सुन्दर जगहों में से एक समझा जाता है। लेकिन दलाल शासक वर्गों द्वारा उस राज्य के जल, जंगल, जमीन का अव्यवस्थित दोहन के बाद यह स्थिति जल्द ही बदल गई। राज्य का एक पर्यटन स्थल के रूप में ''विकास'' और धर्मस्थलों (लगभग सारे हिन्दू) के द्वारा आसपास के नदियों

का बेरोकटोक प्रदूषण ने स्थिति को और ज्यादा बदतर बना दिया। इस छोटे से राज्य में 70 से भी ज्यादा जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित किए गए हैं या निर्माणरत हैं। अनगिनत होटल, मोटल, गेस्ट हाउस आदि, तीर्थयात्रियों के लिए आश्रम और धर्मशालाओं को नदियों के तट तथा सड़कों के किनारे डाइनामॉइट से पहाड़ों को तोड़कर अस्थिर जमीन पर बनाया गया। इन इमारतों और सड़कों के निर्माण के लिए हजारों टन डाइनामॉइट और लाखों डेटोनेटरों का इस्तेमाल करके पहाड़ों को तोड़कर उन्हें खोखला किया गया। जनता के पारम्परिक ज्ञान को दरकिनार कर नदी–नालों पर और उनके पुराने धारों के पथ पर व्यापक निर्माण कार्य किए गए।

यह सारे ''विकास'' के परियोजनाओं ने एक प्राकृतिक आपदा से होने वाले तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। यह प्रलय कभी भी होने के कगार पर था। लेकिन इस कहानी का यहीं अंत नहीं होता। उत्तराखण्ड के आपदा को पूरे विश्वभर में साम्राज्यवादी ताकतों की वजह से हो रहे पर्यावरण की बर्बादी का एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रदूषण और पर्यावरण का नुकसान पूंजीवादी विकास का पहचान है। पूरे विश्व की जनता साम्राज्यवादियों द्वारा, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा, लागू किए गए पर्यावरण नीतियों की विध्वंसकारी परिणामों का शिकार है। अमेरिकी साम्राज्यवाद इस लिहाज से भी विश्व की जनता का एक नम्बर दुश्मन है। प्रकृति के हर तत्व जो हमारे धरती को रहने लायक बनाती है – अंतरिक्ष, सागर, जंगल, नदियों, पहाड़, आकाश, मिट्‌टी, हवा, पशु–पक्षी आदि – को साम्राज्यवादियों की लालच और आक्रमण ने प्रदूषित, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त या विलुप्त कर दिया है। तथाकथित विकासशील देशों के दलाल शासक वर्गों ने भी उनके साम्रज्यवादी आकाओं से हाथ मिलाकर अपने स्वार्थ के लिए धरती और ब्रम्हाण्ड का दोहन कर रहे हैं। वह सब इस अपराध में साथ के अपराधी हैं। ब्राजिल के अमाजान जंगलों को लूला सरकार और उनके बाद आने वाले सरकारों के साथ मिलकर साम्राज्यवादियों द्वारा किया गया निरंतर विध्वंस हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। मिसाल है। ग्लोबल वार्मिगं, कार्बन उत्सर्जन (मउपेपवद) के स्तर में बढ़ोत्तरी, सागर के प्रवाहों में आई तब्दीली विश्वव्यापी इस तरह के पर्यावरण संबंधित बदलाव सभी देशों के पर्यावरण पर बुरा असर डाल रहा है, और इससे उत्तराखण्ड का आपदा भी कोई व्यतिक्रम नहीं है।

हर बार की तरह इस बार हुए आपदा में भी आम जनता ही शिकार हुई

है, और हर बार की तरह दलाल पूंजिपति ही पुनर्निर्माण के नाम पर राहत कोष के राशि को लूटेगें। भुज के भूकम्प और सुनामी – जनता पर कहर ढाने वाले बीते समय के दो बड़े ''प्राकृतिक आपदाओं'' की तरह ही भ्रष्टाचार चरम पर होंगी। जोरशोर से प्रचारित सरकारी राहत और बचाव कार्य, जो केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर चला रहे हैं, वह बिल्कुल अपर्याप्त है। भारतीय सेना और वायुसेना के व्यापक संसाधनों को ''जनता पर युद्ध'' के लिए तैनात करने के बजाय क्या यह सही कदम नहीं होगा कि उन्हें इस तरह के आपदाओं के बाद कम से कम समय पर पीड़ित लोगों के जान बचाने के लिए उपयोग किया जाए? भारत सरकार की सभी अत्याधुनिक सामरिक सामग्री जनता के खून पसीने से ही इकट्ठा किया गया है। इस तरह इन सामग्रियों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए होगें, न कि उनके दमन के लिए।

उत्तराखण्ड की जनता का केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा थोपी गई जनविरोधी और साम्राज्यवादपरस्त पर्यावरण नीतियों के खिलाफ संघर्ष का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ संघर्ष और जंगलों के कटाई के खिलाफ चिपको आन्दोलन से सभी वाकिफ हैं। सुधारवादी नेतृत्व की वजह से इन संघर्षों में पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद जनता मुनाफाखोर बड़े पूंजिपतियों – जो पर्यावरण और प्रकृति के विनाश के लिए कार्यरत हैं – के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। उत्तराखण्ड के लोग अपने पारम्परिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी सदियों से निर्माण, उत्पादन और आध्यात्मिक कार्य करते आए थे। जंगल इस तरह से संरक्षित और पुनर्जीवित होते थे। नदियां प्रदूषणमुक्त होती थी, लोग अपने आपको प्रकृति के संतान मानते थे। मानव और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध होते थे।

उत्तराखण्ड में आए आपदा ने कई सारे जरूरी सवाल खड़े किए हैं जिनमें से कुछ का जिक्र हमने ऊपर किये हैं। हमें इन मुद्दों पर गंभीर रूप से विचार करते हुए इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कोशिश करने का यही सही अवसर है। शोषक वर्गों के जनविरोधी नीतियों और विकास के मॉडल की वजह से होने वाले प्राकृतिक आपदाओं के बाद ''आपदा प्रबंधन'' के बदले हमें प्रकृति के नियमों के बारे में ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए इन आपदाओं के रोकथाम के लिए या फिर उनमें होने वाली तबाही और नुकसान – खासकर जान की नुकसान को – सीमित या कम करने की कोशिश करनी

चाहिए। इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि इस तरह की आपदा संपूर्ण रूप से ''प्राकृतिक'' नहीं होते बल्कि ज्यादातर मानवनिर्मित होते हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि यह ''विकास'' मॉडल केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि इसके दीर्घकालीन परिणाम भी विनाशकारी होंगे। इन जनविरोधी अर्थनीति और पर्यावरण नीतियों के वजह से आने वाली पीढ़ियां भी जोखिम में हैं।

हमारे देश के अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था न केवल उत्पादन शक्तियों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेहनतकश जनता – को ध्वस्त कर रहे हैं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण को भी तबाह कर रहे हैं। जब तक देश के दलाल शासक वर्ग साम्रज्यवादियों की सेवा में इस तरह के विनाशकारी अर्थनीति और पर्यावरण नीतियों का सिर्फ और सिर्फ मुनाफा लूटने के अभिप्राय से लागू करते रहेगें, तब तक इस तरह के आपदा होते रहेगें। भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी जनता से इस ''विकास मॉडल'' को, जो हमारे व पर्यावरण और हमारे बच्चों के भविष्य को तबाह कर रहे हैं, को खारिज करने की अपील करती है, और इसके खिलाफ जनसंघर्ष तेज करने की आह्वान करती है। इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करते हुए भी उत्तराखण्ड की जनता ने जिस साहस और संवेदना के साथ आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता की उसे हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी सलाम करती है। अलग–अलग राज्यों और विदेशों से उत्तराखण्ड में कार्यरत लोग जो तमाम मुश्किलों और खतरों के बावजूद राहत और बचाव कार्य में शामिल हैं, उन्हें भी हम सलाम करते हैं। राहत के लिए आबंटित रकम का उपयोग जनता की जवाबदेही के साथ और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। इसलिए हम उत्तराखण्ड की जनता से अपील करते हैं कि वह राहत कोष को भ्रष्ट सरकार और एनजीओ के हवाले करने के बजाए अपने हाथों में सौंपने की मांग करे। साथ ही, उत्तराखण्ड की जनता से हम यह भी अपील करते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पिछले दशकों में किए गए गौरवशाली जनसंघर्षों को पुनर्जीवित और तेज करें। हमारी पार्टी आपके दुःख और संघर्ष दोनों में शामिल है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारी केन्द्रीय कमेटी फिर से दोहराती है कि सिर्फ एक नई जनवादी समाज में ही पारम्परिक ज्ञान के प्रगतिशील पहलूओं को आधुनिक विज्ञान के

साथ जोड़कर एक लोककेन्द्रिक और पर्यावरण के अनुकूल नीति लागू करने की रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इस तरह विज्ञान को लालची साम्राज्यवादियों और दलाल शोषक वर्गों के शिकंजे से मुक्त करते हुए जनता की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हम जनता से इस बात पर भी गौर करने की आग्रह करते है कि जब तक साम्रज्यवाद का दुनिया से पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक हम अपनी सुन्दर धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित नहीं रख पायेंगे। आइए, इन साम्राज्यवादी ताकतों और हमारे देश के दलाल शोषकों से लड़ने के लिए एकताबद्ध हों ताकि हम मानव–निर्मित आपदाओं का रोकथाम कर सकें जो इस सड़ी गली व्यवस्था का ''प्राकृतिक'' हिस्सा है। आइए, जनता और पर्यावरण के इस निरंकुश शोषण से मुक्त एक नई दुनिया का निर्माण करें जहां प्राकृतिक आपदा तो जरूर होंगे, पर ऐसी मानव–निर्मित त्रासदियां नहीं। कारण स्पष्ट है – राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होती है, दोहनकारी साम्राज्यवादी, दलाल बड़े पूंजीपति और सामंतों के हाथ नहीं।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

17-9-2013

ओड़िशा की नव फासीवादी नवीन पटनायक सरकार द्वारा मलकानगिरी में किये गए 14 माओवादियों के बर्बर नरसंहार के खिलाफ 5 अक्तुबर को भारत बंद सफल करो!

ओड़िशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) व जिला वालियंटरी बल व पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर मलकानगिरी जिला के पोदिया ब्लॉक के सिलाकोटा जंगल में 14 माओवादियों को बर्बरता पूर्ण नरसंहार में कत्ल कर दिया, जिसमें एक महिला कामरेड भी शामिल है। पुलिस ने उनके हथियार भी जब्त कर लिये। ओड़िशा की नव फासीवादी नवीन पटनायक सरकार व केंद्र सरकार ने मिलकर साम्राज्यवाद और खासतौर से अमेरीकी साम्राज्यवाद के मार्गदर्शन में इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी देश की जनता का आव्हान करती है कि 5 अक्तुबर 2013 को इसके खिलाफ भारत बंद को सफल बनाइये।

नवीन पटनायक जब से सत्ता में आया है तब से बेशर्मी के साथ एक दलाल की भूमिका निभा रहा है। ओड़िशा के अकूत प्राकृतिक भंडारों, संसाधनों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों सौंपने के लिए अनगिनित एमओयू ओं पर हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर कर रहा है। कार्पोरेट घराने, राज्य व केंद्र सरकार एमओयूओं को लागू करते हुए जनता को विस्थापित कर रहे हैं। ओड़िशा की जनता खासतौर पर आदिवासी व दलित किसान केंद्र–राज्य सरकार व इसके माइनिंग माफियाओं खिलाफ जीवन–मरण का संघर्ष छेड़े हुए हैं। दूसरी और जोंक की तरह खून चूसने वाले जमींदारों, सूदखारों और शराब माफियओं के खिलाफ भी जुझारू संघर्ष कर रहे हैं। ओड़िशा की बहादुर जनता द्वारा लंबे

समय से चलाये जा रहे लड़ाकू व समझौताविहीन संघर्ष – काशिपुर, नियमगिरी, नारायणपटना व पोस्को के खिलाफ – न केवल देश की जनता बल्कि नव उदारीकरण की बीमारू नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे विश्व के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं।

नवीन पटनायक सरकार जन्मजात बहरी है, अपने दलाल चरित्र के चलते इसने हमेशा ही जनता की मांगो को अनसुना किया है और उलटा उसने जनता के सभी जन आंदोलनों का दमन किया है। उसने इसके लिए कोबरा बलों साहित 27 बटालियनों को लगा रखा है। माओवादियों सहित आम जनता व कार्यकर्ताओं को नरसंहारों में कत्ल करना आम बात होती जा रही है। गिरफ्तारियां, झूठे केस, यातनाएं, अमनवीय तरीके से पिटाई, बलात्कार, अत्याचार, जनता की संपत्ति व घरों को जलाना आदि क्या–क्या नहीं यहां हो रहा है? जनता की जायज आकंक्षाओं को दमन करने के लिए नव फासीवादी सरकार ने क्या–क्या क्रूर कर्तूतें नहीं की।

शासक वर्गों के हाथों शोषण व उत्पीड़िन झेलती आ रही ओड़िशा की जनता व खासकर आदिवासी जनता को हमारी पार्टी दशकों से संगठित करने के कार्य में लगी हुई है। न केवल ओड़िशा बल्कि तमाम राज्यों में जहां उदारीकरण, भूमंडलीकरण व निजीकरण के खिलाफ जन संघर्ष चल रहे हैं का हमारी पार्टी नेतृत्वकर रही है या पूर्ण समर्थन कर रही है। इसलिए भारतीय शासक वर्गों ने साम्राज्यवाद के निर्देशों व उसके वृदहस्त से देशव्यापी बहुमुखी हमला ऑपरेशन ग्रीनहंट. जो जनता पर नाजायज युद्ध 2009 के मध्य से चलाया जा रहा है। इसका मकसद है हमारे और शोषित उत्पीड़ित जनता के जायज संघर्षों को दबाना। उत्पीड़ित जनता का दमन करना ही हर राज्य का प्रमाणिक चिन्ह होता है, और आपरेशन ग्रीनहंट की बर्बरता व व्यपकता ने इसको और ज्यादा प्रमाणित किया है। इसने पूर्व के तमाम दमन अभियानों को पछाड़ दिया है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ऑपरेशन ग्रीनहंट केवल माओवादियों के खत्मे के लिए चलाया जा रहा जा रहा है बल्कि यह तमाम उत्पीड़ित–शोषित जनता की जनवादी मांगों को विशेषतौर पर

जल–जंगल–जमीन की मांग को दबाने के लिए चलाया जा रहा है। इसलिए आज तमाम जनवादी संगठन, व्यक्ति और जनता इसके हमलों को झेल रही है।

नाजी हिटलर, फासीवादी मुसलोनी और उनकी वर्तमान औलाद बुश, ओबामा, हलांदे, कैमरून साहित इसके देशी अवतार सोनिया, मनमोहन, राहुल गांधी, चिदंबरम, जयराम रमेश, प्रणब मुखर्जी व राज्यों में इनके दूत रमन सिंह, नवीन पटनायक, किरणकुमार रेड्डी, ममता बैनर्जी, पृथ्वीराज चव्हान आदि सब एक ही थाली के चटे–बटे हैं। वो हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि जनता के जीवन से किस प्रकार खिलवाड़ किया जाये। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे कि जनता का संचित आक्रोश उनकी धुर्ताओं को एक दिन दफन कर देगा। काशिपुर, नियमगिरी, नारायणपटना व अब 14 सिंतबर को मलकानगिरी में पुलिस फायरिंग व झूठी मुठभेड़ो में हत्याएं कभी भी ओड़िशा की जनता के संघर्षों को दबाने में सफल नहीं होंगी। इनसे सरकार के खिलाफ जनता की नफरत और बढ़ेगी व जनता इस सरकार को उखड़ फैंकने के लिए व्यापक रूप से संगठित होगी।

ओड़िशा के मूर्ख डीजीपी ने शासक वर्गों के पालतू कुत्ते होने का परिचय देते हुए चेतावनी दी कि ओड़िशा में प्रवेश करने वाले हर माओवादी का इन 14 माओवादियों की तरह मौत के घाट उतार दिया जायेगा। ये शासक क्यों नहीं कभी इतिहास से सीखते कि कभी न कभी उनपर कयामत टूटने वाली है! साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद व सामंतवाद परस्त जनविरोधी नव उदारवादी नीतियां पूरे भारतवर्ष व सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में माओवाद के उदय होने का मार्ग परस्त कर रही हैं। उनको 'आउटसाइड' राज्यों से किसी राज्य में प्रवेश करने या आसमान से टपकने की जरूरत नहीं है। जो दलाल शासक वर्ग उदारीकरण, नीजिकरण व भूमंडलीकरण की नीतियों को लागू कर रहे हैं उन सभी को जनता के जुझारू संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। और ये संघर्ष एक कदम आगे बढ़ते हुए माओवाद की दिशा में मुड़ रहे हैं। गोबेल्स की औलाद सभी फासीवादी इस तथ्य को नजरंदाज कर रहे हैं और मलकानगिरी में ओड़िशा की जनता के प्यारे सपूतों को 'बहारी' बता रहे हैं। ओड़िशा की जनता सिलाकोटा जंगलों में कुर्बान हुए अपने प्यारे

बेटे–बेटियों की शहादतों का बदला अवश्य लेगी और बड़ी संख्या में माओवाद से लैस होकर नवीन पटनायक गिरोह को मुंहतोड़ सबक सीखाएगी।

Hkkjr dh l;kjh turk

मलकानगिरी में मारे गए हमारे कामरेड ज्यादातर आदिवासी कामरेड थे। उन्होंने नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने का बिड़ा उठाया हुआ था। यह न केवल आदिवासी जनता के लिए बल्कि देश की तमाम शोषित–उत्पीड़ित जनता के लिए बड़ा नुकसान है। इसलिए न केवल बर्बर दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ बल्कि शासक वर्गों की साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के खिलाफ भी तमाम साधनों के जरीये अपने प्रतिरोधी आवाज को उठाइये।

इस साल कई जगहों पर साधारण जनता व माओवादियों के नरसंहार रचे गए हैं – झारखंड में लकड़बंघा, महाराष्ट्र के गडचिरोली में गोविंदगांव, भटपार, सिंदेसुर, मेडरी व भगवानपुर, छत्तीसगढ़ में एड़समेट्टा व पूवर्ति इनमें से कुछ हैं। इन तमाम जनसंहारों में महिला व बच्चों, माओवादी महिलाओं की बर्बरतापूर्वक हत्या की गयी है। ये सभी कामरेड देश के शोषित–पीड़ित तबकों से आये थे और देश की तमाम उत्पीड़ित–शोषित जनता की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। हम तमाम नागरिकों से अपील करते हैं कि हर कहीं इन जन संहारों का विरोध करें। शासकवर्गों के विकृत विकास के मॉडल का प्रतिरोध करें। हम उन तमाम नागरिकों से अपील करते है जो देश में जनवाद चाहते हैं कि इस प्रतिरोध में शामिल हों।

हम देश के तमाम सच्चे जनवादी संगठनों, पार्टियों व व्यक्तियों से अपील करते हैं कि 14 सितंबर के नरसंहार की एकजुटता के साथ निंदा करें और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हों। हम देश की तमाम जनता से अपील करते हैं कि 5 अक्तुबर को भारत बंद का पालन करे और भारी संख्या में विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

2-12-2013

विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करनेवाली आम जनता को क्रांतिकारी जय जयकार!!

नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ विधारसभा के चुनाव दो चरणों में संपन्न हुये। चुनाव आयोग के निर्णय अनुसार उन इलाकों में जहॉं क्रांतिकारी आंदोलन जारी है, पहले चरण में ही यानी 11 नवंबर को चुनावी प्रहसन पूरा कर लिया है। पहले चरण के विधानसभा चुनावों के दौरान थल मार्ग से पुलिस, अर्ध सैनिक बल, वाहनों व सुरंगरोधक वाहनों के अलावा गगनतल पर हेलिकॉप्टरों व ड्रोन विमानों का इतना भारी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया कि पहले कभी नहीं हुआ। मई 25 को जीरमघाटि के पास हमारे पीएलजीए बलों द्वारा किया गया वीरतापूर्ण हमले में जुडूम के खूंखार नेता, जन दुश्मन, कांग्रेस नेता महेन्द्रकर्मा की मौत के परिप्रेक्ष्य में भारी पैमाने पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को एक बहाना मिल गया। सच्चाई देखा जाय तो पिछले तीन दशकों में इस इलाके में चलने वाले संसदीय चुनावों के हर मौके पर अधिक संख्या में बलों की तैनाती के बारे में दुनिया जानती है! फर्जी संसदीय चुनावों का लोकशाही प्रहसन बंदूकों के साये में पूरा करना सभी देख रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल जनता एक ओर अपनी वैकल्पिक राज्य सत्ता की इकाइयों (जनताना सरकारों) को चुनकर उन्हें मजबूत कर रही है तो दूसरी ओर सक्रिय रूप से फर्जी चुनावों का बहिष्कार कर रही है। उस समरशील जनता को हमारी केन्द्र कमेटि की तरफ से क्रांतिकारी जय जयकार!!

चुनाव आयोग ने भारी पैमाने पर पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के अलावा अपना दुष्प्रचार को भी उतना ही व्यापक पैमाने पर चलाया। बृहत बस्तर के सात जिलों के कलेक्टरों ने भी एक कदम आगे बढ़कर क्रांतिकारी आंदोलन पर विष उगलते हुए दुष्प्रचार में उतर पड़े हैं। चुनाव बहिष्कार के इतने सालों के इतिहास में कहीं भी न किसी मतदाता को धौंस देने या दंडित

करने का एक भी घटना घटित नहीं हुई, ऐसी परिस्थितियों में 7 जिलों के कलेक्टरों ने एक नया शस्त्र का प्रयोग किया। वोट डालने से माओवादी उंगलियॉं काटने की अपनी झूठी प्रचार को वैधता प्रदान करने के लिए इस बार मतदाताओं की उंगलियों पर चुनावी चिन्ह नहीं लगाने का प्रस्ताव सामने ला रहे हैं। इसके साथ साथ 'नोटा' (नन ऑफ द अबौ) 'ऊपर उल्लेखित किसी को नहीं' का महत्व को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि जनवादी तरीके से क्रांतिकारी सरकारों के प्रतिनिधियों को चुनने वाली जनता नोटा से बढ़कर रीकाल करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी है। चुनाव आयोग और पुलिस द्वारा अफवाहें व डर फैलाने के बावजूद लोगों ने अपने चुनाव बहिष्कार की परंपरा को पहले से ज्यादा क्रियाशील तरीके से जारी रखा। साप्ताहिक बाजार बंद करने, सड़कों की नाकेबंदी, रॉशन कार्ड बंद करने की धमकियों के अलावा बहुत ही घटिया किस्म का प्रचार को जोरों से चलाने व गॉवों व जंगलों में खाकियों के संगीनों के निशाने कदम कदम पर साधे रहने के बावजूद जनता के राजनीतिक दृढ़ संकल्प को हिला नहीं सके। उल्टा फर्जी संसदीय चृनावों के असली चेहरे को सामने लाया।

फर्जी चुनावों का बहिष्कार करने वाली क्रांतिकारी जनता को सुरक्षा प्रदान करने में अत्यंत जिम्मेदाराना भूमिका निभानेवाली पीएलजीए को हमारी केन्द्र कमेटि बधाई दे रही है। जनता की सुरक्षा के दौरान कई जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ टकराव भी हुआ है। इन प्रतिरोध कार्यवाहियों में कम से कम दो दर्जन संख्या में खाकी बलों को या तो धूल चटाया गया या जख्मी किया गया है। खाकी बलों की आतंकी कार्यवाहियॉं पुराना बस्तर तक ही सीमित नहीं हुईं। सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली व गोंदिया जिलों में सी–60 कमाण्डो बलों ने हमलों के द्वारा दहशत फैला दिया।

चुनावों के दौरान शोषक शासकों के सुरक्षा बलों द्वारा फैलाई दहशत से क्रांतिकारी जनता को सुरक्षा मुहैया कराते हुए गड़चिरोली में कॉ. सरिता व कॉ. रीता ने अपनी जानें कुरबान की। उसी प्रकार चुनाव बहिष्कार में शामिल जनता की सुरक्षा में लगी जन मिलिशिया कार्यकर्ताओं में कॉ. मंगलू दुर्घटनावश बंदूक फायर होने से शहीद हुए। हमारी केन्द्र कमेटि उनकी बलिदान को विनम्र श्रध्दांजलि पेश कर रही है।

अभूतपूर्व तरीके से पुलिस बलों की तैनाती के बावजूद कई जगहों पर एक भी वोट नहीं डाला गया। चुनाव आयोग ने 35 चुनाव केन्द्रों से खाली मशीन वापस आने की घोषणा की है। संघर्ष वाले इलाकों की जमीनी हकीकत को देखा जाय तो सैकड़ों केन्द्रों में नाम मात्र मतदान हुआ। अंदरूनी इलाकों के 170 मतदान केन्द्रों को पुलिस की देखरेख में रवाना करना पड़ा है वहॉ की स्थिति का आसानी से जायजा ले सकते है। इतना ही नहीं क्रांतिकारी आंदोलन जारी इलाकों में ड्यूटि पर तैनात अर्ध्द सैनिक बलों के दो जवानों की हार्ट एटैक से मृत्यु हुई तो दूसरी घटना में एक कांस्टेबल ने अपने प्लाटून कमाण्डर को ही गोली मार दिया। इस पर परदा डालते हुए छत्तीसगढ के डीएसपी द्वारा चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा बलों की सराहनीय भूमिका की बधाई देना हास्यास्पद ही होगा।

जनताना सरकारों की चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए बुर्जुआ विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करने वाली जनता को हमारी केन्द्र कमेटि एक बार फिर क्रांतिकारी बधाई पेश करती है। अपनी जनवादी अधिकारों को हासिल करने के लिए लगभग सात साल तक कानूनी संघर्ष चलाकर 'नोटा' को हासिल करने वाली तथा फर्जी चुनावों का बहिष्कार करने के साथ साथ रीकाल अधिकार के साथ अपनी सरकारों को चुननेवाली क्रांतिकारी जनता के पक्ष में खड़े होकर उनके अधिकारों का समर्थन के लिए आगे आने का निवेदन तमाम जनवादी प्रेमियों, बुध्दिजीवियों व नागरिक अधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं से करती है।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

14-3-2014

दण्डकारण्य के जनता पर टूट पड़ रही केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा बलों का विरोध करो ! संसदीय जनवाद मात्र एक ढकोसलापण है!

प्यारी जनता एवं जनवादी प्रक्रियों,

2013 नवंबर में 5 राज्यों के पिधान सभा चुनाव हुआ था। उस समय सभुतपूर्व तरिके से संपूर्ण दण्डकारण्य में पोलिस एवं अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। हर 30 लोगों के पीछे 1 पोलिस का होना; यह लोकतंत्र है या पोलिसतंत्र ? इस बारे में हम सबको सोचना की जरूरत है। उस समय जनता में एक दहशत का माहौल निर्माण हुआ था। चुनाव के समय सुरक्षा बलों द्वारा 3 ग्रामिणों की हत्या कर झूठी मुठ़भेड की मनगडंद कहानी बतायी गयी।

चुनाव के समय जनता अपनी रोजमरा की जरूरतों के लिए हाट (बाजार) भी नहीं जा पा रही थी। उस समय पार्टी द्वारा घोषित 'चुनाव बहिष्कार' में सक्रिय भाग ले रह जनता के सुरक्षा में लगे हुए हमारे PLGA कॉमरेड पोलिस एवं सुरक्षा बलों का मुकाबला करते हुए 4 जन शहीद हुए है। चुनाव के तुरंत बाद 2013 दिसंबर में दिनेश त्रिवेदी के मार्गदर्शन मे 40,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल ३ दिन देशव्यापी अभियान चलाया गया है। उस समय माड़ के कुतुल के साप्ताहिक बाजार में ग्रामिण महिला को पकड़कर उपस्थित जनता के सामने उसपर फायरींग की गयी और बाद में पोलिस के फायरिंग में महिला नक्सलवादी घायल हुई है, ऐसा झुठा प्रचार किया गया। उनके बलिदान को खुन अभी सुखा ही नहीं था कि महाराष्ट्र पोलिस द्वारा गडचिरोली के बेतकाटी गांव में हमारे 7 कॉमरेडों ही हत्या की गयी जिनमें कॉ. श्यामको और कॉ. पुन्नी यह दो महिलाए शामिल है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगड में फरवरी इस एक माह अंदर ही 10 लोगों की

हत्या की गयी, जिनमें 7 तो ग्रामिण जनता ही है। लोकसभा चुनाव के घोषणा के चुद दिन पहले ही सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामिणों को पकड़ना, उन्हें प्रताडित करना, जेल भेजना और झूठी मुठभेडों के द्वारा हत्या करना जैसे आम बात हो गयी। इनमें स्त्री या पुरूष अथवा वयोवृद्ध उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसी सिलसिले को लोकसभा चुनाव के साथ-साथ पोलिसी कारवाईयों में भी इजाफा हुआ हो। हमारे पाटी द्वारा घाषित 'चुनाव बहिष्कार'को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा जनता में दहशत का वातावरण निर्माण करने के लिए जंगलों में छानबीन चालु कर दी गयी है। ऐसी ही परिस्थिति मे हमारे PLGA कॉमरेडों द्वारा पोलिस और अर्धसुरक्षा बलों को मुकाबला करते हुए 15 सुरक्षा बलों को मार गिराया है।

जनता पर चलाए जा रहे पोलिसी घोर हमलों पर, देश की कोई भी संसदीय पार्टी आजतक ना जनता के पक्ष में खडी रही है, नाही प्रत्यक्ष संघर्ष मे भाग लिया है। लेकिन आज मतदाताओं को लुभाने के लिए पोलिस कर्मीयों की मौत पर शोक जाताते हुए काँग्रेस पार्टी ने राज्य में बंद का आवाहन किया है।

हम जनता एवं जनवादी प्रेमियों से यह अपील करते है कि, काँग्रेस समेत सभी संसदीय पार्टीयों के जनविरोधी कारवाईयों क निंदा किजीए।

तोंगपाल की घटना पर केन्द्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जांघ पिटते हुए बेशर्मी के साथ बयानबाजी कर रहे है। पोलिसों की मौत पर बदला लेने की घाषणा कर रहे है। लेकिन असली बात यह है कि देश की जिम्मेदारी निभा रह महोदय गृहमंत्री जी किनपर अपना बदला लेंगे ?

क्या उनका देश के कानुन और न्याय-व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है ? शिंदे बदला लेने के इस बयान का यही मतलब निकलता है कि जनता पर जारी युद्ध को ओर तेज करना है।

फिलहाल, यहाँ की स्थिति समुचा दण्डकारण्य पोलिस एवं अर्धसैनिक बलों के छावनी में तब्दील हो चुका है। ऐसे परिथतियों में जनता का जीवन और बद-से-बदतर होते जा रहा है। खासकर चुनावों के पहले शिंदे द्वारा दिया गया यह बयाना सही तें यह संकेत

दे रहा है कि , संसदीय जनवाद एक ढ़कोसलेपण के सिवाय और कुछ नहीं है। इस प्रकार के जनवाद में कोई क्यों और कैसे भाग लेगा ?

अपने ही मातृभूमि मे जनता को दुश्मन के तर्ज पर देखते हुए जनता पर युद्ध का ऐलान करने से जनता कब तक मौन धारण बनाए रखेंगी। जनता क्यों नहीं विकल्प चुनेंगी। इस परिस्थिति मे हो रहे झूठे चुनावों का बहिष्कार करते हुए ऐ वैकल्पित व्यवस्था का चुनाव करना अनिवार्य बन गया है।

हमारी पार्टी तमाम जनवादी प्रेमियों, देशभक्तों, कवियों, लेखकों, कलाकारों, पत्रकार-मीडिस कर्मियों, आदिवासीयों के हितचिंतकों, राजनीतिक पार्टीयों एवं तमाम जनता से यह अपील कर रही है कि संघर्षरत जनता के पक्ष में खड़ें होकर शिंदे को माफी माँगने की माँग करना है। तब चुनाव बहिष्कार करते हुए संघर्ष की राह पर ड़टें रहना है।

हमारी पोलिस कर्मीयों से यह विनंती है कि, शिंदे की इस बयानबाजी का शिकार मत बनिये। हमारा जनयुद्ध आपसे नहीं, इस लूटेरी व्यवस्था के खिलाफ है। आप अपने बंदुकों का इस्तेमाल जनता के खिलाफ मत करो। संसदीय ढ़कोसलपण से आप अच्छे से वाकीफ है। ड्यटी के समय आप कितने मानसिक तनाव में रहते है इस बारें में आपको सोचना है। २०१२-१३ इस एक साल में दो दर्जन से भी ज्यादा पोलिस कर्मीयों द्वारा की गयी खुदकुशीओं से यही जाहीर होता है। साथ आप यह भी जानते होंगे कि, छत्तीसगड विध ाानसभा चुनाव के समय भैरमगड के आपके प्लाटून कमाण्डर द्वारा अपने ही पोलिस कॉनस्टेबल पर गोलि चलाई गयी थी।

हमारी पार्टी आपसे भी यह अनुरोध करती है कि, ढ़ेर सारे तनावों के बिच रहत हुए और जनता के दुश्मन मत बनो।

अभय

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

1-5-2014

भा.क.पा. (माओवादी) और भा.क.पा (मा–ले) नक्सलबाड़ी का विलय जिंदाबाद!
भारतवर्ष में एक ही पार्टी के रूप में दो माओवादी पार्टियों के विलय को ऊंचा उठायेंगे।

दुनिया के सर्वहारा वर्ग के महान गौरवशाली अन्तर्राष्ट्रीय दिवस–मई दिवस के मौके पर हम भारत के माओवादी एक महान उत्तरदायित्व की चेतना के साथ भाकपा (माओवादी) और भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी के एक ही पार्टी भाकपा माओवादी के रूप में विलय की घोषणा करते हैं। इससे भारत के सर्वहारा वर्ग का हिरावल दस्ता जो कि विश्व सर्वहारा वर्ग की एक टुकड़ी है, मजबूत हुई है। भारत की क्रांति और विश्व सर्वहारा क्रांति के लक्ष्य को सफल बनाने के प्रति हम स्वयं को दृढ़तापूर्वक समर्पित करते हैं। 1967 के महान नक्सलबाड़ी के किसान सशस्त्र संघर्ष के उभार के साथ भारत में माओवादी आन्दोलन का उदय हुआ। हमारी पार्टी के संस्थापक नेता कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी से प्रेरणा लेकर और उनके नेतृत्व में क्रांतिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए तथा एक मजबूत पार्टी के निर्माण के लिए हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा जनता ने अपने अनमोल प्राणों को न्योछावर कर दिया।

1970 के दशक के धक्के और कामरेड चारू मजुमदार की शहादत के बाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शक्तियां अनेक गुटो में विभाजित हुई थी। असली क्रांतिकारियों ने अलग–अलग इलाकों में आन्दोलन के निर्माण के लिए प्रयास करते हुए सभी क्रांतिकारियों को एक पार्टी में एकताबद्ध करने की गंभीर कोशिशें की थी। पिछले 4 दशकों की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अलग–अलग रह रही दो प्रधान धाराएं जो पूर्ववर्ती भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) और

एमसीसीआई का प्रतिनिधित्व करती थी, 21 सितंम्बर 2004 को एक ही पार्टी भाकपा (माओवादी) के रूप में विलय हो गई थी। यह विलय भारतवर्ष के मजदूर, किसान और अन्य पीड़ित जनता की बहुप्रतीक्षित अकांक्षाओं को कायान्वित करने के एक गुणात्मक छलांग को चिन्हित करता है और देश में नवजनवादी क्रांतिकारी युद्ध की जीत के लिए और समाजवाद, बाद में साम्यवाद की स्थापना की ओर आगे बढ़ने के लिए एक ही मार्ग निर्देशक केंद्र बनाना चाहता था। उसी तरह भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी ने भी विघटनकारी के. वेनू के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सीआरसी, भाकपा (मा–ले) और अवसरवादी के.एन. रामचंद्रन के नेतृत्व वाली रेड् फ्लैग के संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनमें मौजूद सभी असली माओवादी शक्तियों को एकताबद्ध करने के गंभीर प्रयास किये थे। दोनों पार्टियों की इन प्रक्रियाओं के अंतिम नतीजे के रूप में भाकपा (माओवादी) और भाकपा (मा–ले) नक्सलबाडी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) मजबूत हुई है। निःसंदेह इस एकीकरण ने साबित किया है कि एक तरफ शासक वर्गो और साम्राज्यवाद के खिलाफ दीर्घकालीन लोकयुद्ध में पीड़ित जनता को एकजुट करते हुए, दूसरी तरफ मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के सिद्धान्त तथा पार्टी की क्रांतिकारी लाइन पर अटल रहते हुए, संशोधनवादियों तथा विघटनकारियों के खिलाफ दृढ़तापूर्वक संघर्ष करते हुए सभी असली माओवादी शक्तियों को एक ही पार्टी में एकताबद्ध कर सकते हैं, चाहे यह प्रक्रिया जितनी भी लंबी क्यों न हो। हमारी पार्टी विभिन्न मार्क्सवादी–लेनिनवादी गुटों में काम करने वाली सभी असली क्रांतिकारी शक्तियों को एकताबद्ध करने के कार्यभार को जारी रखती है।

एकीकृत पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद को अपने मार्ग निर्देशक सिद्धांत के रूप में अपनाती है। उसे ऊंचा उठाने, उसकी रक्षा करने तथा सृजनात्मक ढंग से कार्यन्वित करने के द्वारा उस पर अपनी समझदारी को गहराती है। हमारे क्रांतिकारी व्यवहार की हमेशा समीक्षा करते हुए तथा दुनिया भर के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी दस्तों के और संघर्षरत जनता के अनुभवों से सीख लेते हुए अपनी लाइन व व्यवहार को विकसित करती है। यह पार्टी सामंतवाद विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी नवजनवादी क्रांति के कार्यभारों को अपने कंधों पर लेती है। यह क्रांति, सांस्कृतिक क्रांतियों के जरिए क्रांति को जारी रखने के द्वारा समाजवाद, बाद में साम्यवाद की तरफ अग्रसर होती

है। नव जनवादी क्रांति के लक्ष्य हैं– सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद जिसका मुख्य सारांश है, सशस्त्र कृषि क्रांति। दीर्घकालीन लोकयुद्ध ही क्रांति का रास्ता है। सामंतवाद तथा व्यापक पीड़ित जनता के बीच का अन्तरविरोध प्रधान अन्तरविरोध है। पार्टी का मानना है कि साम्राज्यवाद तथा उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं एवं जनता के बीच जो अन्तरविरोध है वह दुनिया के स्तर पर प्रधान अन्तरविरोध है।यह दुनिया के अन्य मौलिक अन्तरविरोधों के साथ–साथ तीखा होता जा रहा है।

अभी हासिल हुई एकता भाकपा (माओवादी) की क्षमता को बढ़ावा देती है। इससे भारत की क्रांति के हिरावल दस्ते के रूप में अपनी भूमिका को वह बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकती है। कई दशकों के कठिन संघर्ष, हजारों महान कम्युनिस्ट नेताओं, लाल योद्धाओं तथा पीड़ित जनता के बलिदानों के द्वारा ही भाकपा (माओवादी) ने भारत देश में जनयुद्ध को इस स्तर तक विकसित किया कि मध्य और पूर्व भारत में गुरिल्ला आधार क्षेत्र और क्रांतिकारी जन कमेटियों के रूप में लाल राजनीतिक सत्ता स्थापित किया गया है। इसकी सुरक्षा जन मुक्ति छापामार सेना तथा जन मिलिशिया कर रही है। अत्यंत अमानवीय दमन अभियानों, जो अभी जनता पर युद्ध, ऑपरेशन ग्रीनहंट के रूप में केंद्रीकृत हुई है, के खिलाफ संघर्ष करने के द्वारा ही यह हासिल हुआ है। ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत दसियों हजार जनता पर क्रूरतापूर्वक हमले किये जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार, घरों को जलाना तथा फसलों को बर्बाद करना, जबरन विस्थापित करना और कई अन्य आमनवीय हथकंडे साधारण हो गई हैं। अभी भारतीय राज्य अपनी थल सेना और वायुसेना के साथ सक्रिय रूप से वैमानिक और जमीनी हमले करने का पूर्वाभ्यास कर रही है। इस तरह के कत्लेआम के बावजूद दीर्घकालीन लोकयुद्ध का लहरों की तरह आगे बढ़ना जारी है। हाल ही में भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट से लगी पश्चिमी घाटी के दक्षिणी भाग में विस्तार इसका एक सबूत है। दक्षिण एशिया में साम्राज्यवाद का स्तम्भ– भारतीय राज्यसत्ता के ध्वस्त होते तक क्रांति की लपटें विस्तार होती जायेंगी।

चूंकि साम्राज्यवादी और उनके दलाल शासक दुनिया भर में बेरोकटोक संकट फंसे हुए हैं। इससे दुनिया भर में अनुकूल क्रांतिकारी परिस्थिति बन रही है। यह दुनिया भर में वर्ग संघर्षो को तेज करेगी, माओवादियों के नेतृत्व में जनयुद्धों की तरफ, पीड़ित देशों में अन्य शक्तियों के नेतृत्व में साम्राज्यवादी

विरोधी संघर्षो की तरफ ले जायेगी। देश के मध्य और पूर्वी भाग में शासक वर्गों ने अपने चार लाख भाड़े के बलों को तैनात किया है जहां वर्ग संघर्ष तीव्र क्रांतिकारी अन्तर युद्ध के चरण में पहुंच गया है। यह एक क्रांतिकारी विकल्प के रूप में उभर रहा है और व्यापक पीड़ित जनता को क्रांति की तरफ प्रेरित कर रहा है। इतना ही नहीं जनमुक्ति छापामार सेना मजबूती से संगठित हो रही है और नवजनवादी राजसत्ता अपने भ्रूण रूप में उभर रहा है। पश्चिम घाटी में अंकुरित होने वाले क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष को कुचलने के लिए भारतीय राज्य के द्वारा वहां सैनिकीकरण तेज हो रहा है। दूसरी तरफ वह मजदूरों, किसानों आदिवासी दलितों महिलाओं तथा अन्य पीड़ित जनता पर जनविरोधी वैश्वीकरण नीतियों को जबर्दस्ती थोप रहा है। इस वजह से समरशील आन्दोलनों में तेजी आ रही है। इस अनुकूल परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए पार्टी क्रांतिकारी आन्दोलन को एक उच्चस्तर तक आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास करेगी और अपने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यभारों को बेहतर तरीके से पूरा करेगी। वह लाखों की संख्या में जनता को एकजूट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। गुरिल्ला युद्ध को तेज व विस्तृत करेगी। क्रांतिकारी आन्दोलन के सामने जो कठिन चुनौतियां मौजूद हैं उनका समाधान करेगी और अवरुद्धों को पार करेगी।

हम इस बात से चिंतित हैं कि भारत और दुनिया भर में अमानवीय विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था की वजाह से व्यापक जनता दूभर तथा अभाव की स्थिति में जीने को विवश है। हम वाकिफ हैं कि इस व्यवस्था की वाजह से विश्व पर्यावरण पर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है उससे धरती पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है।

साम्यवाद के लक्ष्य के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले हजारों शहीदों की यादों को समेटकर उनके खून से सने सुर्ख लाल झण्डे के तले एकजुट होकर शपथ लेते हैं कि जो एकता हमने हासिल की है उसे क्रांति के एक शक्तिशाली हथियार बनायेंगे।

गणपति ,	**अजित ,**
महासचिव ,	**सचिव ,**
भाकपा (माओवादी)	**भाकपा (मा–ले)नक्सलबाड़ी**

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

20-5-2014

नक्सलबाड़ी के वरिष्ठ नेता और क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी कामरेड सुनीति कुमार घोष को विनम्र श्रद्धांजलि

भाकपा (मा-ले) के वरिष्ठ नेता और क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी कामरेड सुनीति कुमार घोष का 11 मई 2014 को पश्चिम बंगाल के असनसोल में 96 वर्ष के उम्र में मृत्यु हो गयी। बढ़ते उम्र के चलते कुछ समय से वह बीमार थे। भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी, पार्टी के सभी कतारों, पीएलजीए, क्रान्तिकारी जनसंगठनों तथा जन सत्ता के अंगों की तरफ से अपनी क्रान्तिकारी श्रद्धांजलि तथा उनके परिजनों और साथियों को संवेदना पेश करती है।

कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके लम्बे जुड़ाव के दौरान कामरेड घोष ने भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1940 के दशक से ही वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहे जब देश प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शोषण के दौर से गुजर रहा था। औपनिवेशिक शोषण-दमन के माहौल में पले-बड़े कामरेड घोष ने अपनी छोटे उम्र से ही उपनिवेश-विरोधी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। साथ ही, ग्रामीण बंगाल में बड़े जमीनदारों के सामंती शोषण से पस्त गरीब किसानों की हालत के बारे में भी वह वाकिफ थे। इसलिए जब 1946 में तेभागा आन्दोलन उमड़ उठा, वह भी इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कूद पड़े। इस तरह उनका क्रान्तिकारी जीवन शुरू हुआ। उन्होंने भारत की मेहनतकश जनता की पीठ पर सवार तीन पहाड़- जमीनदार, दलाल नौकरशाह पूंजीपति और साम्राज्यवाद - को उखाड़ फेंकने की लड़ाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

अगले कुछ सालों में भाकपा की संशोधनवादी राजनीतिक लाइन (दिशा) और भी स्पष्टता से उजागर होने लगी, विशेषकर जब पार्टी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी संघर्ष के साथ 1951 में पार्टी ने विश्वासघात किया। भाकपा ने 1956 में फिर से अपनी वैचारिक पतन को दर्शायी जब पार्टी ने कामरेड स्तालिन तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर गद्दार क्रुश्चेव द्वारा किये गये शातिराना हमलों को स्वीकार किया। कामरेड घोष ने विरोध में पार्टी से इस्तीफा दिया। महान बहस के तहत सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की संशोधनवादी रणनीति का पर्दाफाश करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा छेड़ा गया संघर्ष को उन्होंने उत्साह के साथ समर्थन किया। भाकपा के अन्दर चले अन्दरूनी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जब पार्टी में विघटन हुआ और भाकपा (मार्क्सवादी) का गठन हुआ, संशोधनवाद के साथ एक स्पष्ट विच्छेद की अपेक्षा से अन्य क्रान्तिकारियों के साथ कामरेड घोष ने भी 1964 में नई पार्टी में शामिल हुए।

लेकिन बुनियादी सामाजिक बदलाव की तरफ कोई भी कदम का विरोध कर भाकपा(मा) का नेतृत्व ने जल्द ही अपना संशोधनवादी चरित्र उजागर किया। पार्टी के अन्दर पैठ जमाये संशोधनवाद ने कामरेड चारु मजुमदार, कामरेड कन्हाई चटर्जी आदि सच्चे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में दो लाइनों के बीच एक नये संघर्ष की पृष्टभूमि तैयार किया। 1965 में कामरेड घोष ने भाकपा(मा) से इस्तीफा दिया और कामरेड चारु मजुमदार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा उत्तरी बंगाल में सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी संघर्ष निर्माण करने के लिए किये जा रहे कोशिशों का भरपूर समर्थन किया। भारत की कम्युनिस्ट आन्दोलन में चले इस तीखी वैचारिक-राजनीतिक संघर्ष का ही परिणाम था 1967 की महान नक्सलबाड़ी आन्दोलन। संशोधनवाद को नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाये जा रहे महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के परिप्रेक्ष्य में नक्सलबाड़ी का उदय

हुआ। नक्सलबाड़ी ने भाकपा और माकपा के संशोधनवाद को धूल चटाई। भारत के इतिहास में एक नई सुबह की शरुआत करने वाली ऐतिहासिक मोड़ के रूप में कामरेड घोष ने इसका स्वागत किया।

बसंत बज्रनाद के साथ-ही शुरू हुआ महान क्रान्तिकारी उभार में जल्द ही कामरेड सुनीति कुमार घोष ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। बंगाल में सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी आन्दोलन की नेतृत्व करनेवाली पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की समन्वय कमेटी (WBCCCR) की वह 1967 में सदस्य बन गये। 1967 नवंबर में शुरु की गई कमेटी का अंग्रेजी मुखपत्र 'लिबरेशन' की सम्पादना की जिम्मेदारी उन्हें दी गयी। 'लिबरेशन' और 'देशब्रती' में 'सौम्य' नाम से उन्होंने कई वैचारिक और विश्लेषनात्मक लेख प्रकाशित किये। 1968 में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की अखिल भारत समन्वय कमेटी (AICCCR) का गठन होने पर वह इसका एक नेतृत्वकारी सदस्य बन गये और उन्होंने इस कमेटी का मुखपत्र 'लिबरेशन' की सम्पादना जारी रखे। क्रान्तिकारी उभार के साथ संघर्ष आगे बढ़ने के क्रम में AICCCR के ज्यादातर घटकों ने मिलकर 1969 में भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की स्थापना किया। इसके कुछ महीनों के बाद कामरेड कन्हाई चटर्जी के नेतृत्व में 'दक्षिण देश' गुट ने भी 'माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (MCC)' गठित कर क्रान्तिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाया।

एक केन्द्रीय कमेटी सदस्य और 'लिबरेशन' के सम्पादक के रूप में कामरेड घोष ने नवगठित पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कामरेड चारु मजुमदार के दिशानिर्देश और कामरेड घोष के दक्ष सम्पादना में लिबरेशन ने पार्टी कतारों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सैद्धांतिक-वैचारिक लेख, संशोधनवाद व दक्षिणपंथी अवसरवाद के खिलाफ आलोचनात्मक लेख, घरेलु और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर समीक्षा, संघर्ष रपट आदि नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। केन्द्रीय कमेटी और विभिन्न पार्टी कमेटियों के बीच इस पत्रिका ने सेतु का काम

किया। 1970 अप्रैल में पुलिस ने पत्रिका के कार्यालय में छापा मारकर उसे बन्द कर दिया, लेकिन इस तरह के बढ़ते फासीवादी राज्य दमन का सामना करते हुए भी कामरेड घोष ने पत्रिका की नियमित प्रकाशन को बरकरार रखने के लिए भरसक प्रयास किये। 1972 की शुरुआत तक यह पत्रिका समय-समय पर प्रकाशित होता रहा, लेकिन उस समय आन्दोलन में आये गतिरोध की वजह से इसका प्रकाशन बंद हो गया।

पार्टी को मिटाने की उद्देश्य से किये जा रहे दुश्मन के बढ़ते दमन और आन्दोलन के गद्दारों के आक्रमणों के बीच कामरेड घोष और उनके साथियों ने नक्सलबाड़ी की क्रान्तिकारी लाइन का बचाव किया और उसे बरकरार रखा। सत्यनारायण सिंह, शिवकुमार मिश्र आदि अवसरवादियों ने दीर्घकालीन जनयुद्ध की कार्यनीतिक लाइन को ही नकारा और कामरेड चारु मजुमदार की नेतृत्व का विरोध किया। उस समय कामरेड चारु मजुमदार के दिखाये राजनीतिक दिशा और 1970 की पार्टी कांग्रेस की कार्यक्रम के साथ दृढ़ता से खड़े रहकर कामरेड घोष ने दक्षिणपंथी अवसरवादी हमलों से पार्टी का बचाव किया।

इस तरह, 1972 तक क्रान्तिकारी आन्दोलन को वैचारिक और राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने में कामरेड घोष ने सकारात्मक सहयोग दिया। कामरेड चारु मजुमदार के साथ कई नेतृत्वकारी कामरेडों की शहादत और गिरफ्तारी के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन उस समय गतिरोध का सामना करते हुए कठिन दौर से गुजर रहा था। पार्टी में विघटन और बिखराव हो रहा था। जनता के सहयोग से कामरेड घोष दुश्मन के शिकंजों से बचने में सफल रहे। लेकिन चारु मजुमदार और अन्य नेतृत्वकारी साथियों के नुकसान के बाद उत्पन्न कठिन परिस्थिति में कामरेड घोष अपनी नेतृत्वकारी भूमिका नहीं निभा पाये। क्रान्तिकारी खेमे के उम्मीदों के बावजूद वह देशभर के बिखरे हुए क्रान्तिकारी शक्तियों को एकत्रित कर गतिरोध का सामना कर रही आन्दोलन को पुनर्गठित नहीं कर पाये।

1973 में कामरेड्स शर्मा, सुनीति कुमार घोष, के.एस. और रामनाथ जैसे नेतृत्वकारी साथियों द्वारा एक सांगठनिक केन्द्रीय कमेटी (COC) बनाकर पार्टी को एकत्रित करने की कोशिश मतभेदों की वजह से असफल रही। अतीत के आंकलन और भविष्य में अपनाये जाने वाले रणनीति के बारे में कोई आम सहमति नहीं बन सकी। कामरेड घोष ने आन्दोलन का मूल्यांकन कर उनकी आलोचना सामने रखे, जो इस कमेटी के अन्य सदस्यों को मंजूर नहीं था और उन सभी का इस विषय पर अलग अलग आंकलन था। इसके बाद क्रान्तिकारी धाराओं ने अलग अलग रह कर काम किये। कामरेड घोष ने पार्टी और सांगठनिक कामों से अपने आपको दूर कर लिया और भारत के इतिहास और समाज के बारे में मा-ले-मा की नजरिये से अध्ययन तथा व्याख्या करने में अपना ध्यान केन्द्रित किया। 1970 के दशक के अंत से लेकर अब तक प्रकाशित कई पुस्तकों और लेखों के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जीवन के अन्तिम वर्षों में कामरेड घोष ने नक्सलबाड़ी आन्दोलन के बारे में अपनी स्मृतियाँ और आंकलन प्रकाशित किए और आन्दोलन के बुनियादी लाइन को ऊंचा उठाते हुए उन्होंने पार्टी द्वारा अपनाये गये कुछ रणनीतियों व कार्यशैलियों तथा पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता कामरेड चारु मजुमदार के नेतृत्व के कुछ पहलुओं पर अपनी आलोचना और मतभेद व्यक्त किये। 2009 में प्रकाशित इन आलोचनाओं की निरंतरता कामरेड घोष द्वारा 1973 में पेश किये गये सिंहावलोकन से है। उनके सभी निष्कर्षों व आलोचनाओं को हमारी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि कामरेड घोष के कुछ आंकलनों और आलोचनाओं पर हमारी मतभेद हैं।

इसके बावजूद, कामरेड सुनीति कुमार घोष जीवनभर एक क्रांतिकारी रहे और वह मुख्य रूप से नक्सलबाड़ी के सैद्धांतिक-राजनीतिक दिशा के एक सच्चे अनुयायी थे। नक्सलबाड़ी के झंडा को ऊंचा उठाये रखनेवाले क्रांतिकारी धाराओं के वह एक अच्छे मित्र और शुभचिंतक थे। आन्दोलन

के एक वरिष्ठ साथी के रूप में वह क्रान्तिकारियों को अपना बहुमूल्य सलाह व सुझाव समय समय पर देते थे। भूतपूर्व भाकपा (मा-ले)(पीपुल्सवार), एमसीसीआई, भाकपा (मा-ले) पार्टी यूनिटी तथा वर्तमान में भाकपा(माओवादी) ने विभिन्न तरीकों से उनके साथ मित्रतापूर्ण संपर्क बरकरार रखे थे। यह कामरेड घोष की महान आदर्शों की ही पहचान है कि एक ऐसे समय जब देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट आन्दोलन को गतिरोधों का सामना करना पड़ रहा था और जब पूंजीवादी व्यवस्था की स्थायित्व का दावा करने वाले प्रतिक्रियावादी शक्तियों के पिट्ठुओं ने समाजवाद और साम्यवाद की अन्त का घोषणा कर दिया था, तब भी उन्होंने मा-ले-मा और सामाजिक क्रांति के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं होने दिया। गहरी और व्यापक अध्ययन के प्रति उनका लगाव, फौलादी दृढ़संकल्प, कठोर श्रम और साधारण जीवन शैली - उनके इन सभी आदर्शों को हमें अपनाने की जरूरत है। उनकी मौत से हमारी पार्टी और देश की मेहनतकश जनता ने एक महान मित्र और हमराही खो दिया। सर्वहारा विचार, सर्वहारा क्रान्ति का महान लक्ष्य और शोषित जनता के हितों के प्रति उनका समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। शहीद कामरेडों से विरासत में मिली क्रांतिकारी लाल परचम को हर हाल में ऊंचा उठाये रखने की शपथ लेकर ही हम अपने प्यारे कामरेड सुनीति कुमार घोष को सच्ची श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

19-6-2014

भारतीय क्रान्ति के महान नेता कामरेड सुशील राय हमेशा एक लाल सूरज की तरह हमारे राह को रोशन करते रहेंगे ! आइए, उनके महान कम्युनिस्ट गुणों और आदर्शों को आत्मसात करें, अमल करें और व्यापक प्रचार करें !

हमारे वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य और भारतीय क्रान्ति के गरिमाशाली नेता कामरेड सुशील राय (अशोक, शोम, बरुणदा) का 18 जून 2014 को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में लम्बी बीमारी के बाद मृत्यु हो गयी। इसके साथ ही हमारे देश की सर्वहारा और मेहनतकश जनता ने अपने महानतम बेटों में से एक को खो दिया जिसने सिर्फ जनता और क्रान्ति के हितों को दिलों-जहन में रखकर अपनी आखरी सांस तक पांच दशकों से भी ज्यादा समय

उनकी सेवा की। कामरेड सुशील राय अमर है !

केन्द्रीय कमेटी, भाकपा (माओवादी) हमारे प्यारे साथी कामरेड सुशील राय को पार्टी के सभी कतारों, पीएलजीए, क्रान्तिकारी जन संगठनों, क्रान्तिकारी जनसत्ता के अंगों और क्रान्तिकारी जनता की तरफ से विनम्र लाल श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इस अवसर पर बन्द मुट्ठी और उठे हाथों के साथ हम शपथ लेते हैं कि उनसे और हमारे महान शहीदों से सीखते हुए शरीर में आखरी बून्द खून रहने तक हम दुगुने दृढ़निश्चय और एकनिष्टता से उनके लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कामरेड सुशील राय के शोक-सन्तप्त परिजनों, मित्रों और भारतीय क्रान्ति के शुभचिंतकों को हम अपनी गहरी संवेदना पेश करते हैं।

76 साल पहले कामरेड सुशील राय का जन्म आज के बंगलादेश में हुआ। वह महान क्रान्तिकारी शहीद दिनेश गुप्ता के भतीजे थे, जिनका देश और देशवासियों के लिए प्रेम, कुरबानी और प्रेरणा उन्होंने अंत तक अपने दिल में रखा। 1960 के दशक की शुरुआत में वह कम्युनिस्ट आन्दोलन में सक्रिय हो गये। उन्होंने मजदूर आन्दोलन में काम किया और 1963 में भाकपा में शामिल हुए। वियतनाम के खिलाफ छेड़े गये अन्यायपूर्ण युद्ध के विरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवाद-विरोधी प्रदर्शनों और 1966 की दक्षिण कोलकता की खाद्य आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। भाकपा में मौजूद संशोधनवादियों के खिलाफ अन्दरूनी संघर्ष में वह शामिल थे। उनके कई समकालीन क्रान्तिकारियों की तरह उनकी भी अपेक्षा थी कि संशोधनवादी भाकपा से अलग होकर गठित माकपा एक क्रान्तिकारी पार्टी में तब्दील होगी और इसी आशा के साथ वह 1964 में इस नई पार्टी में शामिल हुए।

उनका सम्पर्क कामरेड्स कन्हाई चटर्जी और अमुल्य सेन से हुआ जो चीनी क्रान्ति की तर्ज पर एक क्रान्तिकारी पार्टी की निर्माण के लिए और एक नई जनवादी क्रान्ति की अग्रगति के लिए अथक वैचारिक, राजनीतिक और सांगठनिक तैयारियों में जुटे हुए थे। संशोधनवाद के खिलाफ बसंत बज्रनाद बनकर कहर ढानेवाली नक्सलबाड़ी की ललकार को उन्होंने 'नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता' के नारे के साथ समर्थन और अभिवादन किया। 'चिंता' तथा 'दक्षिण देश' गुटों के वह शुरुआत से ही हिस्सा थे और माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एमसीसी) के एक संस्थापक सदस्य थे। पेशेवर क्रान्तिकारी के रूप में एक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए वह पश्चिम बंगाल के अन्दरूनी गांवों में चले गये।

दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन को सृजनात्मक तरीके से व्यवहार में अमल करने

के क्रम में पश्चिम बंगाल के सोनारपुर और कांक्सा इलाकों में एमसीसी को आन्दोलन निर्माण का पहला अनुभव हासिल हुआ। पार्टी ने इन संघर्षो में आई सामयिक गतिरोध का कारण बने कमियों के बारे में गहराई से समीक्षा किया। सच्ची कम्युनिस्ट उत्साह के साथ गया-हजारीबाग (उस समय यह एरिया बिहार के अन्तर्गत था) में आन्दोलन को आगे बढ़ाने की गम्भीर कोशिश की गई, जहां कामरेड केसी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में पिछले गलतियों से सीखकर एक रणनीतिक योजना के साथ जनसेना और आधार इलाका निर्माण करने के लिए काम शुरु किया गया। जल्द ही सशस्त्र कृषि क्रान्ति की आग चारों ओर फैल गयी और इसके साथ राज्य दमन भी गम्भीर रूप से बढ़ गयी। कुछ अहम नुकसानों के बावजूद आन्दोलन ने कामरेड सुशील राय सहित पार्टी के नेतृत्वकारी साथियों के सकुशल दिशानिर्देश की वजह से दुश्मन के हमलों का सफल मुकाबला किया। उन्होंने एक मजबूत सर्वहारा पार्टी, एक जनसेना और एक क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा की नींव रखी और सशस्त्र कृषि क्रान्ति की राह पर महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल किये।

18 जुलाई 1982 को गम्भीर बीमारी की वजह से कामरेड केसी की अकाल मृत्यु के बाद उसी साल कामरेड सुशील राय ने एमसीसी की सचिव की जिम्मेदारी ली। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर दृढ़ता से पार्टी लाइन को थामते हुए उन्होंने पार्टी को एकताबद्ध तरीके से गोलबन्द व विकसित करने तथा आन्दोलन की निर्माण के लिए प्रयास किये। 1989 में आयोजित पार्टी की पहली केन्द्रीय अधिवेशन में उन्हें सचिव चुन लिया गया। पार्टी, सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी युद्ध और जनाधार की निर्माण में, खासकर बिहार-झारखण्ड और बंगाल में, वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक, सैनिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में कामरेड सुशील राय का योगदान अनमोल साबित हुआ। उन्होंने अपनी निष्ठा, सर्वहारा रणनीतिक नेतृत्व की कुशलता, मार्गदर्शन, कर्मठता और निस्वार्थ सेवा से अपनी कमेटी, निचले स्तर की कमेटियों, तथा पूरे पार्टी कतारों का विश्वास जीत लिया। गम्भीर दृष्टिहीनता और बीमारी की वजह से उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी सचिव की पदभार से मुक्त होने का प्रस्ताव पार्टी के सामने रखा। 1996 में हुई पार्टी की दूसरी केन्द्रीय अधिवेशन में पार्टी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उस समय से वह एक केन्द्रीय कमेटी सदस्य के हैसियत से अपनी भूमिका निभाते रहे। केन्द्रीय कमेटी और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका - खासकर वैचारिक और राजनीतिक क्षेत्र में, पार्टी के अन्दर सफलतापूर्वक दो-लाइन संघर्ष चलाने में, आन्दोलन का मूल्यांकन करने में, अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित करने और सच्चे माओवादी संगठनों के साथ,

खासकर भाकपा (मा-ले)[पीपुल्सवार] के साथ, एकता हासिल करने में जारी रहा।

पार्टी के कई अन्दरूनी संघर्षों का सफलतापूर्वक संचालन करने में और पार्टी की सही लाइन की रक्षा करने में एक नेतृत्वकारी सदस्य तथा बाद में पार्टी के सचिव व वरिष्ठ केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में कामरेड सुशील राय की विशिष्ट भूमिका थी। इन अन्दरूनी संघर्षो में 1999 और 2001 के बीच केन्द्रीय कमेटी के अत्यन्त अवसरवादी विघटनकारी भरत-बादल गुट के खिलाफ चलाया गया दो लाइन संघर्ष सबसे तीखी थी। अवसरवादियों के विघटनकारी गतिविधियों की वजह से आन्दोलन ने कुछ सामयिक नुकसान उठाने के बावजूद उन्होंने और अन्य नेतृत्वकारी साथियों ने इन अन्दरूनी संघर्षों में पार्टी के अन्दर 'वाम' और दक्षिणपंथी अवसरवादी रुझानों का सफल मुकाबला किया और फिर से पार्टी को सही पथ पर संचालित किया।

देश के सच्चे क्रान्तिकारियों के साथ एकता स्थापित करने में कामरेड सुशील राय की भूमिका भारत की कम्युनिस्ट आन्दोलन की इतिहास में विशेष रूप से दर्ज रहेगी। कामरेड केसी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में 1981 में ही पी.डब्ल्यु. के साथ एकता का प्रयास शुरु हुआ था जिसने एकता की एक मजबूत आधारशिला रखी। अन्य कारणों के अलावा, एमसीसी की पहलकदमी से सन 2000 में ऐलान किये गये एक तरफा युद्ध विराम - जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था - के बाद एमसीसी और पीडब्ल्यु के बीच एकता के प्रयासों ने अंततः रंग लाना शुरु किया। इस निर्णय में और इस महान एकता को वास्तविक रूप देने की पूरी प्रक्रिया में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे विलय प्रक्रिया में उन्होंने एमसीसी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल के एक नेतृत्वकारी सदस्य के हैसियत से हिस्सा लिया। इस विलय के कुछ ही समय पहले आरसीसीआई, आरसीसीआई(एम) और सेकंड सीसी के साथ एकता में भी उन्होंने इसी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एमसीसीआई ने भाकपा(मा-ले) नक्सलबाड़ी के साथ एकता वार्ता की और एकता स्थापित करने की क्रम में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचे। दोनों पार्टियों के बीच करीबी सम्बन्ध थे। इन वार्ताओं में भी कामरेड सुशील राय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाकपा(माओवादी) और भाकपा(मा-ले) नक्सलबाड़ी के बीच हाल ही में 2014 में हुए विलय का भी इसने नींव रखी।

विलय के बाद, पार्टी के एक वरिष्ठ कामरेड और पोलित ब्यूरो सदस्य होने के नाते वह पार्टी के निचले स्तरों में विलय प्रक्रिया को संपूर्ण करने और एक एकत्रित

पार्टी के रूप में काम करने की नई परिस्थिति में पूरे पार्टी को ढालने की प्रयासों में व्यस्त थे। एकता कांग्रेस की तैयारियों में वह शामिल थे और जनयुद्ध को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए किये गये केन्द्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो की सभी निर्णयों का वह हिस्सा थे तथा कुछ अंतरराष्ट्रीय काम भी देख रहे थे।

विलय के बाद भारतीय क्रान्ति के एकमात्र मार्गदर्शक केन्द्र के तहत पार्टी, पीएलजीए और जनाधार में गुणात्मक बदलाव आया और जनयुद्ध आगे बढ़ा। इसलिए, भारत की प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों ने उनके साम्राज्यवादी आकाओं के दिशानिर्देशन पर नवगठित भाकपा (माओवादी) की नेतृत्व को गिरफ्तार या हत्या करने की सुनियोजित योजनाएं बनाई। इसी क्रम में कामरेड सुशील राय को 21 मई 2005 को गिरफ्तार किया गया। कई फर्जी मामलें थोपने के बाद उन्हें पूछताछ किया गया, मानसिक रूप से यातनायें दिया गया और जेल में डाला गया। पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के जेलों में उन्हें अमानवीय और निर्मम बरताव से गुजरना पड़ा। दरअसल उनके कारावास के पूरे अवधि में उन्हें दो-तीन बार जमानत दिया गया था। लेकिन झूठे अभियोगों के आधार पर उन्हें जेल के गेट से ही उठाकर फिर से जेल में ठूस दिया जाता था। नेतृत्वकारी साथियों को, खास कर केन्द्रीय कमेटी सदस्यों को, क्रान्ति की नेतृत्व और सेवा करने से रोकने के लिए राज्य इस साजिश पर अमल कर रहा है। उनके बढ़ते उम्र और गम्भीर बीमार हालत की पूरी तरह उपेक्षा कर उन्हें बिना किसी सहायता के (अपने दिनचर्या के कामों के लिए भी जिसका उन्हें बहुत जरूरत था) बन्द कोठरी में अलग रखा गया । इससे उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया। जेल में ही उनको कुल्हे की हड्डी टूटकर गम्भीर छोट भी आयी। कई साल इस हालत में जेल में गुजारने के बाद सितम्बर 2012 में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया और वह भी कई जनवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शनों और प्रयासों के बाद।

कामरेड सुशील राय मूत्राशय की केन्सर से पीड़ित थे। डाक्टरों ने पहले उनके मूत्राशय से एक ट्यूमर आपरेशन के जरिए निकाल लिया था और केन्सर के लिए एक अन्य आपरेशन भी किया गया। वह हृदयरोग की मरीज थे। उनका एक किडनी (गुर्दा) पूरी तरह खराब हो गया था जबकि दूसरा संक्रमित था। फिर भी एक योद्धा के तरह अंतिम सांस तक उन्होंने इन बीमारियों से संघर्ष किया। इसी क्रान्तिकारी उमंग की वजह से ही वह अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य का सामना कर कुछ समय के लिए मृत्यु को टाल सके। इस तरह की अत्यंत दुखदायी शारीरिक पीड़ा और

विकलांगता सहन करते हुए उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी हिम्मत और दृढ़ता नहीं खोयी।

कामरेड सुशील राय की दुखद मृत्यु बेशक एक भारी क्षति है और हमारी पार्टी व आन्दोलन के लिए एक बहुत ही दुखदायी घटना है। लेकिन हमारी पूरी पार्टी तथा क्रान्तिकारी जनता इस महान शहीद से सीखेंगे और क्रान्ति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुगुने दृढ़संकल्प के साथ काम करेंगे। हमारे चहेते नेता और वरिष्ठ साथी कामरेड सुशील राय एक प्रशंसनीय नेता और आदर्श कम्युनिस्ट थे। वह हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे और प्रेरणा का स्त्रोत होंगे। हमारे महान शहीदों के अरमानों को पूरा करने के लिए आगे आनेवाले कम्युनिस्टों के पीढ़ियों के लिए उन्होंने कई उच्च आदर्श प्रतिस्ठित किये। कामरेड सुशील राय की पूरी जिन्दगी भारत की कम्युनिस्ट आन्दोलन के उतार-चढ़ावों, ज्वार-भाटों, सफलताओं और गरिमाओं के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा रहा है। उन्होंने समूह में अपने आपको इतने गुमनाम रखकर और सच्चे कम्युनिस्ट भावना से समाहित किया की उनके जीवन और काम हमारे देश की क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की इतिहास को ही बयान करेगी।

हर एक कम्युनिस्ट को हमारे महान नेता कामरेड सुशील राय से इन विषयों को सीखना चाहिए - मा-ले-मा का दृढ़ अनुसरण और उसका सृजनात्मक प्रयोग; एक तरफ अवसरवाद व विघटनवाद का विरोध और दूसरी तरफ एकता की प्रयास तथा उस एकता को बरकरार रखने की कोशिश; गलतियों को स्वीकार करने और दूसरों के गलतियों को सुधारने में इमानदारी; तीन जादुई हथियारों का निर्माण कर आन्दोलन को सफलतापूर्वक आगे ले जाने में हरसंभव प्रयास करना, और व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों के मातहत रखना।

कामरेड सुशील राय सरलता के प्रतीक थे और एक बहुत ही मितव्ययी जीवन जीते थे। जीवनभर वह अविवाहित रहे। नक्सलबाड़ी, सोनारपुर और कांक्सा आंदोलनों पर क्रूर राज्य दमन के समय और उसके बाद आन्दोलन के उतार-चढ़ावों के दौरान वह दृढ़ता से खड़े रहे। वह कभी भी नहीं डगमगाये और हमेशा पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी या कार्यभार दी उसे पूरा करने में एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। अन्य पार्टियों व आन्दोलनों के प्रति वह हमेशा सकारात्मक रवैया रखते थे और उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सीखने और अध्ययन करने की कोशिश करते थे। उनका अध्ययन गहरा था। वह बहुत ही धैर्य के साथ कामरेडों से सम्बन्ध रखते थे। एक क्रान्तिकारी जीवन में आनेवाले हर तरह की मुश्किलों का उन्होंने

सामना किया और इन सभी का एक सच्चे क्रान्तिकारी के गरिमा के साथ मुकाबला किया।

यह एक कम्युनिस्ट की कृतसंकल्प ही है जिस की वजह से वह मानव की पीड़ा की खात्मे के लिए कोई भी पीड़ा सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उनके संपर्क में आये, कभी भी उनके हंसमुख मिज़ाज को नहीं भूल सकते जो कठिनतम परिस्थितियों को भी क्रान्तिकारी जोश से भर देते थे। यह उनके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक पहलू ही नहीं, बल्कि एक महान लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट वचनबद्धता ने ही उसे मुमकिन बनाया, और वह महान लक्ष्य था - सभी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से दुनिया के जनता का मुक्ति।

हमारे देश के प्यारे लोगों और भारतीय क्रान्ति के शुभचिंतकों !

इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कामरेड सुशील राय को इतनी पीड़ा भुगतना नहीं पड़ता और उनकी इतनी जल्द मौत नहीं होती अगर भारतीय राज्य का उनके तरफ इतना लापरवाह बरताव नहीं होता। हम शासक वर्गों की, उनकी राज्य यंत्र की और साम्राज्यवादियों की इस बर्बर अमानवीय कोवर्ट हत्या की तीव्र निंदा करते हैं और सभी जनवादियों से इस क्रूरता का पर्दाफाश करने की अपील करते हैं। हमें इस तथ्य को जनता के बीच व्यापकता से प्रचार करना चाहिए ताकि जेलों में बन्द नेतृत्वकारी साथियों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर उन्हें सचेत कर सकें और उनके व अन्य बन्दियों पर ढाये जा रहे अनगिनत अन्यायों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्हें जागृत कर सकें। कामरेड सुशील राय, जिन्होंने इतने भयंकर परिस्थितियों में भी राज्य के खिलाफ अपनी अथक संघर्ष से एक मिसाल कायम किया, जनता को इस लड़ाई में भी प्रेरित करते रहेंगे।

कामरेड सुशील राय की एम्स में दाखिला के और आपरेशन के बाद वह चल-फिरने में भी समर्थ नहीं थे और उन्हें हर समय सहायता की जरूरत थी। क्रान्तिकारी और जनवादी जनसंगठनों तथा व्यक्तियों व लोगों ने इस जरूरत को पूरा किया। भाकपा(माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी तथा समस्त क्रान्तिकारी शिविर तहे-दिल से अपनी क्रान्तिकारी कृतज्ञता और लाल सलाम उन सभी को पेश करते है जिन्होंने उनकी रिहाई और उपयुक्त इलाज के लिए जी-जान से कोशिश की और अन्तिम समय तक उनको बेहद जरूरी व्यक्तिगत सहायता उपलब्द करायी। कामरेड सुशील राय की सेवा में उन्होंने जो सच्चे मानवीय मूल्यों का परिचय दिया उसे हमारी पार्टी और क्रान्तिकारी जनता हमेशा याद रखेंगे। हमारे अनमोल नेता के प्रति भारतीय

राज्य का अमानवीय व्यवहार की तुलना में यह और भी उज्वलता से झलकता है। हमारी पार्टी का मानना है कि उनके जेसे ज्येष्ठ और सच्चे जननेताओं का सेवा करना पूरे विश्व में सच्चे मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थित करने की हमारी व्यापक संघर्ष का एक अभिन्न हिस्सा है।

एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब हमारे कई वरिष्ठ कामरेड बिना जमानत, उपयुक्त इलाज, साफ सफाई और सहुलियत के पांच से दस साल तक जेलों में कैद हैं और गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इस तरह के और भी कार्यभार आनेवाले दिनों में सामने आना तय है। कामरेड सुशील राय की उचित इलाज के लिए किया गया लड़ाई सभी राजनीतिक बन्दियों की बिनाशर्त रिहाई और बन्दियों के अधिकारों की संघर्ष का एक हिस्सा है। सच्चे जननेताओं की रिहाई और उनका समुचित इलाज करवाना जनता का अधिकार और जिम्मेदारी है।

केन्द्रीय कमेटी, भाकपा(माओवादी) अपने सभी कार्यकर्ताओं और देश के पूरे क्रान्तिकारी शिविर को हमारे सभी संघर्ष इलाकों तथा अन्य जगहों पर स्मरण सभाओं का आयोजन कर इस महान कम्युनिस्ट को श्रद्धांजलि पेश करने और उनके आदर्शों का हरसंभव प्रचार करने की आह्वान करती है। हम सभी स्तर के साथियों को, तथा भारतीय क्रान्ति के हमदर्दों और शुभचिंतकों को उनके आदर्शों को विभिन्न रूपों में (लेख, फिल्म, डाक्युमेन्टरी आदि) प्रचारित करने को आगे आने के लिये आह्वान करती है। हमारे प्यारे कामरेड सुशील राय और अन्य शहीदों के क्रान्तिकारी गुणों और आदर्शों को अपनाकर और अमल में लाकर ही हम अपनी नई जनवादी क्रान्ति को निश्चित विजय की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं और समाजवाद तथा साम्यवाद हासिल करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

21-6-2014

रेल किराया में वृद्धि की 'कड़वी घूंट' का विरोध करें जो मोदी हमारे गले में ठूॅसना चाहता है!
आसमान छूती महंगाई के खिलाफ एकताबद्ध संघर्ष तैयार करें!

सत्तासीन होने के कुछ ही दिनों के बाद मोदी ने गोवा में घोषणा किया कि अर्थनीति को पटरी पर लाने के लिये हमें कुछ 'कड़वी घूंट' पीनी ही पड़ेगी। सच्चाई तो यह है कि भाजपा नेतृत्वाधीन राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की एक महीना पूरा होने से पहले ही ऐसी कड़वी घूंटों की संख्या गिनती से बाहर हो रही हैं।

मूल्यवृद्धि पर रोक लगाना और मुद्रास्फीति का नियन्त्रण भाजपा की एक प्रमुख चुनावी वादा था। लेकिन एक महीने के अन्दर ही अभूतपूर्व ढंग से रेल किराया में वृद्धि (14.2 प्रतिशत यात्री किराये में व 6.5 प्रतिशत मालभाड़े में) किया गया। इससे सभी उपभोक्ता सामग्रियों के और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोत्तरी होगी। प्यॉज, सबजियां और फलों के दाम आसमान छू रहे है और मुद्रास्फीति भी बड़ रही है। डीजल का दाम हर महीने बढ़ाने की युपीए सरकार की नीति को तो भाजपा सरकार ने (विश्व बाजार की कीमतों के साथ समन्वय करने के बहाने) वैसे भी जारी रखा है। प्राकृतिक गैस उत्पादन के सिलसिले में रिलायन्स कम्पनी को दी जा रही सब्सीडी (सरकारी अनुदान) और इसकी वजह से हो रही गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बारे में अलग अलग तबकों के लोग गम्भीर सवाल उठा रहे हैं। घरेलू गैस का भाव तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

युपीए सरकार ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी का कारण वैश्विक आर्थिक संकट और तेल की कीमतों में अस्थिरता बताया था। विपक्ष में रहते समय भाजपा ने कांग्रेस की नेतृत्ववाली युपीए सरकार को इसके लिये तीखी आलोचना की थी और इसे अपना एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। लेकिन अब वह हाल ही के मूल्यवृद्धि को जायज ठहराने के लिये उसी

तरह की तर्क देकर कह रहे है कि इसका कारण है इराक की उत्तरी भाग में नूरी अल मलिकी सरकार के खिलाफ आइएसआइएस विद्रोहियों की तेजी से आगे बढ़ने की वजह से विश्व बाजार में हो रही तेल कीमतों में उतार–चड़ाव, इत्यादि। 'रेलवे की आधुनिकीकरण' और युपीए सरकार की दस साल की शासन के दौरान देश की अर्थनीति में जमा हुए 'कीचड़ को साफ करने' की जरूरत को भी मूल्यवृद्धि का एक अन्य कारण के रूप में हमारे सामने पेश करने की कोशिश हो रही है।

रेल किराया और मालभाड़े में की गई इस जनविरोधी वृद्धि की जिम्मेदारी रेल मंत्री ने बेशर्म तरीके से युपीए सरकार पर यह कह कर थोपने की कोशिश की कि वह तो केवल पूर्व सरकार की निर्णय को लागू कर रहे है जिसे चुनावों को देखते हुए रोक दिया गया था। साम्राज्यवादियों व उनके भारतीय दलालों के और ज्यादा हित साधने के लिये मोदी सरकार रोजाना युपीए सरकार की कई निर्णयों व प्रशासनिक ढांचों को रद्द कर रहे है। लेकिन वह चाहते है कि जनता विश्वास करें कि रेल किराया वृद्धि की निर्णय को रोकने में वह 'असमर्थ' है! पोलवरम बांध से तेलंगाना राज्य के खम्मम जिला में डूबनेवाली सात मंडलों को आन्ध्र प्रदेश को सौंपने के लिये लाये गये अघ्यादेश के बारे में भी वही बहाना बनाया गया। इन दो मुद्दों में दिये गये कुतर्को ने इस सच्चाई को पूरी तरह उजागर किया कि प्रतिक्रियावादी जनविरोधी निर्णय लेने में यह 'नई' सरकार 'पूरानी' सरकार से किसी भी मायने में अलग नहीं है।

अगर हम याद करें कि मोदी केबिनट की पहली घोषणाओं में शामिल थी रेलवे सहित कई क्षेत्रों में सौ प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) लाने के लिये जमी़न तैयार करना, तो 'रेल आधुनिकीकरण' व 'पूरानी सरकार की फैलायी कीचड़ की सफाई करना' आदि बहानों का भंडाफोड़ होता हैं। इस विशाल सरकारी क्षेत्र की इकाई का आधुनिकीकरण इसका निजीकरण और कौड़ियों के भाव में साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाही पूँजीवादियों को बेचने का ही दूसरा नाम है।

16 मई की चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए मोदी ने कहा था, 'अच्छे दिन आनेवाले हैं'। यकीनन, अच्छे दिन आनेवाले है, मगर सिर्फ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, उनके तलवे चॉटनेवाले दलालों, राजनेताओं व सभी बड़े नौकरशाहों के। क्योंकि एक ऐसे 'सशक्त प्रधानमंत्री' के होने से ही उनको ज्यादा कमाई और मुनाफा हो सकता है जो हमारे गले में एक के बाद एक 'कड़वी घूंट' ठूॅसने

में जरा सी भी पीड़ा अनुभव न करता हो जब तक दम घुटकर हमारी मौत न हो जायें। आम जनता के लिये आनेवाले दिन तीखी मूल्यवृद्धि, इसके परिणामस्वरूप उनके जीवनस्तर में भारी गिरावट, अमीर और गरीब के आमदनी के बीच अभूतपूर्व गति से बढ़ती खाई, आदि से भरे होंगे।

हमारे देश के प्यारे लोगों,

आनेवाले खराब दिनों के ये महज कुछ नमूने है। शपथ ग्रहण के बाद ही मोदी ने घोषणा किया कि पूर्व सरकार की सभी निर्णयों को वह खारिज नहीं करेंगे और जो नीतियां 'उपयोगी' होंगे उन्हें जारी रखेंगे। इसके प्रारम्भिक संकेत इतने साफ है कि उन्हें कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। दरअसल, सभी लोग इससे प्रभावित होंगे। प्रधान मंत्री की पदभार सम्भालने के बाद ही मोदी ने उसकी सरकार की तीन प्राथमिकताएं घोषणा की जिसकी अलग से व्याख्या की जरूरत नहीं – निवेश को आकर्षित करना, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को पूरा करना/तैयार करना और प्राकृतिक संसाधनों का बेरोकतोक दोहन करना – जो अन्तरराष्ट्रीय व घरेलू कार्पोरेटों का सुनियोजित एजेन्डा है। इस एजेन्डे के लागू होने से आनेवाले दिनों में सत्ता में काबिज होनेवाले अब तक के सबसे क्रूर सरकार की शासन का हमारा देश गवाह होगा। इसका अगर हम एकत्रित होकर प्रतिरोध न करे तो हमारे देश की जनता का जीवन असहनीय हो जाना तय है, जिसका परिणाम होगा असीमित गरीबी, मौत और विनाश।

केन्द्रीय कमेटी, भाकपा (माओवादी) हमारे देश के सभी लोगों से आह्वान करती है कि साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हित में मोदी सरकार द्वारा हम पर थोपे जा रहे रेल और माल भाड़े मे भारी बढ़ोत्तरी, खाद्य सामग्रियों की मुल्यवृद्धि, डीजल व गैस की कीमतों में वृद्धि, आदि का पूरजोर विरोध करें। हम अपनी पार्टी के सभी कतारों और पीएलजीए को आह्वान करते हैं कि व मूल्यवृद्धि और महंगाई के खिलाफ व्यापक स्तर पर जनता को एकजूट कर विस्तारित आन्दोलन तैयार करें। सभी क्रान्तिकारी व जनवादी सगंठनों और व्यक्तियों से हम अपील करते है कि रेल किराये और अन्य मुल्यवृद्धियों के विरोध में एक मजबूत और एकताबद्ध संघर्ष के लिये सभी उत्पीड़ित वर्गों तथा तबकों को व्यापक रूप से गोलबन्द करें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

29-6-2014

आदिवासियों के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध और मानवीय त्रासदी व पर्यावरण की विनाश का दूसरा नाम – पोलवरम परियोजना का विरोध करें! इस परियोजना के खिलाफ एक व्यापक जन आन्दोलन खड़ा करें!

मोदी केबिनट की पहली बैठक ने ही एक अध्यादेश पारित कर तेलंगाना के खम्मम जिले के पोलवरम परियोजना के वजह से डूबनेवाले सात मन्डलों के सभी गांवों (लगभग 400 गांव) को आन्ध्र प्रदेश हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया। आदिवासी गावों का हस्तान्तरन और एक आदिवासी इलाके का विभाजन न केवल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों तथा जन आन्दोलनों की वजह से सरकारों द्वारा पिछले समय में लाये गये कई कानूनों का उल्लंघन है बल्कि यह निर्णय आदिवासियों के कल्यान, उनके आकांक्षाओं व अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय लेने का अधिकार के भी बिल्कुल खिलाफ हैं। मोदी सरकार ने, जो 'पारदर्शिता' के बारे में बोलते नहीं थकती, इस अध्यादेश को इतनी चोरी-छिपे पारित किया कि पत्रकारों को केबिनट की निर्णय के बारे में अवगत करते समय केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैशर्मी से घोषणा किया कि इस मुद्दे पर अभी भी बातचीत जारी है। जब सच्चाई सामने आयी, तेलंगाना की जनता, खासकर आदिवासी जनता, आक्रोश से इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। तेलंगाना में प्रतिरोध की आग भड़क उठी और अध्यादेश को तुरन्त वापस लेने की मांग पर राज्यव्यापी बन्द, विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रेलियां आदि आयोजित किये गये।

मोदी सरकार ने अपने निर्णय का यह कहकर बैशर्मी से बचाव किया कि इस अध्यादेश को लाने का निर्णय युपीए-2 का था और वह सिर्फ इसको लागू कर रहे है। दरअसल, साम्राज्यवादियों और घरेलू दलालों के हित में जनविरोध

ी व प्रतिक्रियावादी निर्णय लेने के मामले में युपीए और एनडीए सरकारों के बीच कभी भी कोई फर्क नहीं रहा है। इसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में है। इस अध्यादेश को पारित करने में देशी और विदेशी कार्पोरेट लुटेरों के विश्वस्त दलाल नायुडू जोड़ी (आन्ध्र प्रदेश के मूख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायुडू और केन्द्रीय शहरी विकाश व संसदीय परिक्रमा मंत्री वेंकया नायुडू) की प्रमुख भुमिका रही हैं। जनता, विशेषकर आदिवासी जनता, अच्छी तरह समझती है कि मोदी, जिसने युपीए-1 और 2 के कई निर्णय रद्द किये है, किस के हित में यह अध्यादेश ला रहा है। सच तो यह है कि शासक वर्ग के पार्टियों के इन दोनों गठबन्धनों ने मिलकर पिछले समय में पोलवरम की साजिश रची थी और अभी भी उसे जारी रखा है। उन दोनों में केवल एक ही फर्क है, वह है उनकी बैठने की जगह - शासक की कुर्सी पर या विपक्ष के कतार में। जनता ने, खासकर आदिवासी जनता ने, उनके साजिश को समझ लिया है। इसीलिये वे पूर्व के युपीए और वर्तमान के एनडीए सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध कर रहे है।

नवगठित आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान सभा ने उसकी पहली ही सभा में मांग की कि केन्द्र सरकार इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान्यता दें और इसकी निर्माण में तेजी लाये। इस प्रतिक्रियावादी अध्यादेश को लाने में नायुडू-जोड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका के लिये उनको विधान सभा ने सराहना कर सातवें आसमान पर चढ़ा लिया। इस अध्यादेश के पक्ष में इस जोड़ी या उनके दलाल माफिया गिरोहों ने जो कुतर्क दिये, उनमें से एक यह है कि परियोजना से डूबनेवाले सभी गॉव उसी राज्य से होनी चाहिये। अन्तरराज्यीय परियोजनाओं को लागू करते समय भारत के किसी भी जगह न इस तरह की कोई बेतुकी तर्क पेश किया गया है और न ही इस तरह की अजीब प्रस्ताव को कहीं भी लागू किया गया है। इसके पीछे असली कारण है - सभी डूबनेवाले गावों को आन्ध प्रदेश के हवाले करने से आदिवासियों के पुनर्वास जैसे मुद्दों को बहुत ही मनमाने ढंग से निपटारा करने तथा अनियमितताओं व धाँधलियों को बेरोकटोक चलाने में उनको सहूलियत होगी।

पोलवरम परियोजना से तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के 400, उड़िशा के 50 और छत्तीसगढ़ के 50 गांव जलमग्न होंगे। इस अध्यादेश के मुताबिक कुकुनूर, वेलेरीपाडू, बूरगूमपहाड़, चिन्तूर, कूनावरम और वररामचन्द्रपुरम मंडल के सभी गांव व भद्राचलम राजस्व गांव, जंहा एक राम मन्दिर है, को छोड़कर भद्राचलम मंडल के सभी अन्य गांवों को आन्ध्र प्रदेश हस्तान्तरित किये जायेंगे। जब भूतपूर्व

यूपीए सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में यह संसोधन करने का प्रस्ताव रखा, तब भी तेलंगाना के आदिवासियों, जनता के अलग-अलग तबकों और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया। अध्यादेश को वापस लेने की मांग पर उनका विरोध जारी हैं। दोनों मौकों पर हमारी केन्द्रीय कमेटी और सम्बन्धित राज्य कमेटियों तथा क्रान्तिकारी और जनवादी संगठनों ने इस निर्णय का तीव्र निन्दा किया। इस निर्णय के विरोध में वे एक जनान्दोलन खड़ा कर रहे हैं।

आदिवासी जनता, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश की क्रान्तिकारी व जनवादी ताकतें, पर्यावरणविद, नृतत्वविद (anthropologists), इंजिनीयर, विशेषज्ञ आदि के प्रगतिशील हिस्सें पोलवरम परियोजना के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। विशाखापट्टनम-नेल्लूर औद्योगिक करिडोर के निर्माण से होनेवाले मुनाफा लूटनेवाले, इस करिडोर में गृह निर्माण व्यवसाय से लाभ उठानेवाले और इसमें बड़े पैमाने पर होनेवाले भ्रष्टाचार से जेब गरम करनेवाले घरेलू और विदेशी कार्पोरेटों, सीमान्ध्र के बड़े जमीन्दारों, बड़े माफिया, राजनेताओं और बड़े ठेकेदारों के अलावा कोई भी इस बहुआयामी परियोजना का समर्थन नहीं कर रहा है। वे यह दलील दे रहे हैं कि कृष्णा और गुन्टूर जिलों के किसानों को इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा मिलेगी। लेकिन यह एक फर्जी दलील है। यहां 'किसान' का मतलब है मुख्य रूप से जमीन्दार और धनी किसान। यह केवल उनको ही प्रमुख तौर पर फायदा पहुँचायेगा। इस परियोजना से होनेवाले नुकसान इसके लाभों से कई गुणा ज्यादा है। इसलिये पोलवरम से कुछ लाख एकड़ जमीन की होनेवाली सिंचाई की सुविधा के आधार पर परियोजना की निर्माण को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आन्ध्र प्रदेश के सिंचाई से वंचित किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिये और भी कई तरीके अपनाये जा सकते है। दरअसल, यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश के किसानों के लिये भी हानिकारक है और कई विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि बाढ़ की पानी के तेज बहाव की वजह से बांध टूट जायेगा और इसका परिणाम होगा पूर्वी घाटी में अकल्पनीय मानवीय त्रासदी। इस दैत्य के निर्माण के खतरों के बारे में उन्होंने कई वैज्ञानिक सबूत और तथ्य पेश किये हैं। इसलिये, आन्ध्र प्रदेश की जनता को इन तथ्यों को समझकर पोलवरम परियोजना के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करना चाहिए और इसमे शामिल होना चाहिए।

इस 'आधुनिक विनाशकारी मंदिर' का प्रमुख शिकार होंगे तेलंगाना की जनता, खासकर वे लाखों आदिवासी जो इससे विस्थापित होनेवाले हैं। सांस्कृतिक

जनसंहार के अलावा यह और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसके वजह से तीन लाख कोया, कोन्डारेड्डी (अनुसूचित जनजाति), अनुसूचित जाति और समुदाय के लोगों को अपने पुरखों की मूल निवास, जमीन और जंगलों से बेरहमी के साथ उखाड़ दिया जायेगा। सभ्य समाज की भाषा मे – उन्हें विस्थापित किया जायेगा।

यह परियोजना सिर्फ भारत तथा संयुक्त राष्ट्र की संविधानों में उल्लेखित और जनसंघर्षों से हासिल किये गये मानव अधिकारों का ही हनन नहीं करता बल्कि आदिवासियों के मानव व सांस्कृतिक अधिकारों को भी नेस्तनाबूद करता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इस इलाके के आदिवासियों ने अपनी अस्तित्व को कायम रखा हैं, इसमें अड़चन पहुँचानेवाले केन्द्र व राज्य सरकारों की नीतियों का खिलाफत किया है – और इस पूरे समय में अपने आपको तेलंगाना के ही नागरिक माना है। वे इस हस्तान्तरन के सख्त खिलाफ है। अगर ये गांव आन्ध्र प्रदेश को हस्तान्तरित किया जायेगा तो उनके अस्मिता, अर्थनीति, भाषा और संस्कृति – सभी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके अलावा, सलवा जूडूम और ग्रीन हण्ट अभियान के दौरान ढाये गये विनाश व उत्पीड़न–अत्याचार की वजह से हजारों आदिवासी बस्तर से खम्मम के जंगलों में पलायन के लिये मजबूर किये गये थे। इस परियोजना के गिरफ्त में आने से उनकी क्या दशा होगी यह कल्पना करना भी कठिन हैं। उपयुक्त पुनर्वास का दलील भी महज एक खोखला वादा बनकर रह जायेगा क्योंकि उन्हें इस इलाके के निवासी के तौर पर सरकारी स्वीकृति भी आज तक नहीं दी गयी है।

आदिवासियों से कोई बातचीत किये बिना या उनके सहमति लिये बिना पोलवरम परियोजना निर्माण करने और इस भयानक अध्यादेश को जारी करने के लिये मनमानी ढंग से आगे बढ़कर केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनुसूचित इलाकों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) 1996 के धाराओं के तहत अनिवार्य ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व अनुमति लेने की नियम को दरकिनार किया है। संविधान के कई अन्य धाराओं व अनुच्छेदों का भी खुला और लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। उदाहरण के लिये, यह कदम अनुच्छेद 244 का उल्लंघन है, जो अनुसूचित इलाकों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के मामलों में पाँचवी अनुसूची के तहत राज्य के आदिवासी सलाहकार परिषद से परामर्श व अनुमोदन लेने की अनिवार्य प्रक्रिया का जिक्र करता है। यह भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्संस्थापन का अधिकार कानून 2013 के भी खिलाफ है, क्योंकि यह कानुन प्रभावित लोगों को कमांड इलाके में सिंचाई

सुविधायूक्त और सुरक्षित 'जमीन के बदले जमीन' देने का वादा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'अनुसूचित जनजातियों व जातियों को प्रभावित इलाके में मिलनेवाली आरक्षण सहित सभी सुविधाएं पुनर्वास इलाके में भी जारी रहेगी'। यह परियोजना राष्ट्रीय आदिवासी नीति का भी उल्लंघन है जो कहता है कि 50,000 से ज्यादा आदिवासियों को विस्थापित करनेवाली कोई भी परियोजना हाथ में लेनी ही नहीं चाहिए।

इस परियोजना को ओड़िशा और छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति, ग्राम सभाओं की अनुमति, वन अधिकार कानून के तहत जरूरी अनुमोदन तथा कई पर्यावरण सम्बन्धित अनुमोदन मिलना अभी तक बाकी है। और यह सूची बहुत लम्बी है। कुछ समय पहले जब आन्ध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी सरकार सत्तासीन थी, उसने निविदा आह्वान कर बड़े निर्माण कम्पनियों को परियोजना पर काम शुरू करने के लिये ठेका आवंटित किया था। मोदी सरकार, जो शोषक वर्गो के हितों की रक्षा करता है, इतने तेजी से अनगिनत प्रतिक्रियावादी निर्णय ले रही है कि सम्भव है वह ये सभी अनुमति और अनुमोदन हासिल कर लेंगे या इसका निर्माण तेज करने के लिये कुछ धूर्त हथकंडे अपनायेंगे।

इस परियोजना के विरोध में छत्तीसगढ़ और ओड़िशा सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में डाले गये कई याचिकाएं लम्बित है। पर्यावरण के लिये लड़ रहे आदिवासी और तेलंगाना संगठनों द्वारा इस विवादास्पद परियोजना के निर्माण को चुनौती देते हुए दर्ज किये गये कई अन्य याचिकाएं भी वहा लम्बित है। फिर भी, आदिवासियों को पैरों तले रौंदकर आन्ध्र प्रदेश सरकार भाजपा नेतृत्वाधीन राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन की समर्थन से इस परियोजना को लागू करना चाहता है।

केन्द्र और आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा, तेलगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस इस परियोजना के लिये राष्ट्रीय मान्यता और इसकी अविलम्ब निर्माण की मांग कर रहें हैं। उनके 'बेचैनी' का एकमात्र कारण है – आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम–काकीनाड़ा करिडसेर में स्थित बहुराष्ट्रीय कार्पोरेटों के अनगिनत विशेष आर्थिक क्षेत्रों, औद्योगिक करिडोर, पर्यटन 'उद्योग' तथा इस तरह के अन्य 'विकास' परियोजनाओं को जल्द पानी पॅहुचाना और इससे मिलनेवाले रिश्वत से अपनी जेब गरम करना। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण व्यय में वह लगातार भारी बढ़ोत्तरी कर रहे है और इसके अनुपात में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं भी बढ़ रही है। इसमें आनवाले दिनों में और भी बढ़ोत्तरी होगी। कोई अचरज

नहीं कि टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस बेहद कुख्यात और भ्रष्ट नेता ठेकेदार के रूप में और बड़े ठेकेदार नेता के रूप में पोलवरम परियोजना की पैरवी करने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। इस परियोजना के निर्माण में लगनेवाले आम जनता की अरबों रूपयों को हड़पने के लिये यह होड़ लगाया जा रहा है।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने कभी भी पोलवरम के निर्माण को रोकने के लिये जरूरी विरोध दर्ज नहीं किया। दो-में-एक फर्मुला के अन्तर्गत एक तरफ तटीय आन्ध्र और रायलसीमा को दस साल के लिये संयुक्त राजधानी और पोलवरम परियोजना का वरदान दिया गया तो दूसरी तरफ शर्तो के साथ तेलंगाना राज्य दिया गया। आदिवासिओं के खिलाफ रचे गये इस साजिश का टीआरएस अगर हिस्सा नहीं था तो इस फर्मुला को उसने स्वीकार क्यों किया? पोलवरम परियोजना के निर्माण के लिये ऊचें स्तर पर रचे गये इस साजिश का उसने समय रहते पर्दाफाश क्यों नहीं किया? इस परियोजना का और हैदराबाद को दस साल के लिये आम राजधानी बनाने की निर्णय का विरोध नहीं कर्ना जनता को गुमराह करने की कोशिश के अलावा और क्या है? टीआरएस ने तीन लाख स्थानीय आदिवासी और गैर-आदिवासियों की जीवन दाव पर लगा दिया और तेलंगाना राज्य के बदले जितना भी मिले उतने से जनता को सन्तुष्ट रहने को कहा। उसने जनता को 'विजय उत्सव' मनाने के लिये आह्वान किया। उस अवसर पर भी उसने कोई विरोध क्यों नहीं दर्ज किया? इस अध्यादेश के खिलाफ अब टीआरएस बंद का आह्वान कर रहा है लेकिन सच तो यह है कि इसका जब विरोध करना चाहिये था तब उसने कोइ विरोध नहीं किया। टीआरएस की मगरमछवाली नकली आँसू क्या सीमान्ध्र, घरेलू और विदेशी कार्पोरेट उपनिवेशवादियों से आदिवासियों को बचा सकता है? और भी महत्वपूर्ण बात, उसने कभी पोलवरम का निर्माण का विरोध नहीं किया। आज भी उसकी मांग सिर्फ परियोजना की खाका और ऊँचाइ को बदलने तक ही सीमित है। टीआरएस अपने कार्पोरेट आकाओं को यह आश्वासन देने में पूरी तरह व्यस्त है कि वह किसी भी तरह इसके निर्माण के खिलाफ नहीं है।

स्थानीय लोगों ने सात मंडलों के गावों को हाथ की सफाई से आधी-रात को आन्ध्र प्रदेश के हवाले करने की मोदी सरकार की शातिराना निर्णय को खारिज किया और वे अपने आपको तेलंगाना का हिस्सा होने की घोषणा करते हुए परियोजना का निर्माण रोकने की मांग कर रहे हैं। इसलिये केन्द्र सरकार के

निर्णय के खिलाफ होने का दावा करनेवाली केसीआर सरकार से हमारी पार्टी मांग करती है कि इस इलाके को तेलंगाना का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकृति दें, यहा के लोगों को तेलंगाना की नागरिक घोषणा करें और उन्हें नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, परिवहन आदि के अधिकार व सुविधा मुहैया करें तथा उन्हें भी तेलंगाना के अन्य नागरिकों की तरह ही व्यवहार करें। हम इस इलाके की जनता के साथ साथ आन्दोलन का समर्थन कर रहे सभी संगठनों, व्यक्तियों व लोगों को भी यही मांग करने की अपील करते है। केवल तभी यह साफ होगा कि केसीआर और उनकी सरकार किसके पक्ष में खड़े है। तेलंगाना के दूसरे राजनीतिक पार्टियों के प्रति हमारी पार्टी का रूख भी यही है।

एक व्यापक संयुक्त मोर्चा खड़ा कर आदिवासी संगठनें पहले से ही पोलवरम के खिलाफ संघर्ष कर रही है। क्योंकि वे इसके खिलाफ तीखी लड़ाई लड़ रहे हैं, खम्मम के बुर्जोआ और संसोधनवादी पार्टियां भी उनके संघर्ष का समर्थन कर रहे है, हालांकि ये केवल नाममात्र व दिखावे के लिये ही है। लेकिन वे प्रमुख रूप से केवल तेलंगाना के सात मंडलों को आन्ध्र प्रदेश हस्तान्तरित करने के खिलाफ बात करते हुए आन्दोलन में शामिल हो रहे हैं।

सिर्फ यह महत्वपूर्ण नहीं कि डूबनेवाले गांव किस राज्य के अन्तर्गत होंगे, बल्कि यह कि उन्हें जलमग्न किया ही क्यों जा रहा है। तानाशाही मोदी या चन्द्रबाबु की सरकारें हो या फिर दुनिया की कोई अन्य शक्ति, किसी को भी स्थानीय मूलनिवासियों तथा जनता की इच्छा, आशा-आकांक्षा, मत और हित के खिलाफ यह परियोजना निर्माण करने या इस इलाके को आन्ध्र प्रदेश को सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। बेशक, जीत जनता की ही होगी बशर्ते वे यह संघर्ष अपनी ताकत पर निर्भर होकर लड़ें। आदिवासी, क्रान्तिकारी, जनवादी, देशभक्त, पर्यावरण-सम्बन्धित और नृतत्व-सम्बन्धित सभी वर्ग और ताकतें तथा इस परियोजना का विरोध करनेवाले आदिवासियों के हमर्दद - सभी जनता के दोस्त हैं। जो इस विनाशकारी परियोजना का समर्थन कर इस परियोजना से प्रभावित होनेवाले तीन लाख आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम करता है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो इस बांध का समर्थक है - वे केवल जनता के दुश्मन ही हो सकते हैं। जान बूझकर या अनजाने में इस परियोजना का समर्थन करनेवाले सभी शक्तियों को यह समझना चाहिये

कि वे जनता के खिलाफ खड़े हैं।

प्यारे लोगों,

हमारे देश में पिछले परियोजनाओं से विस्थापित होनेवाले लोगों को अभी तक कोई उपयुक्त पुनर्वास मुहैया नहीं किया गया है। उनकी मुसीबतें अनेक और अन्तहीन हैं (जिसमें उनकी मौत भी शामिल है)। हम जानते हैं कैसे नल्लमला, मन्यम और सारन्डा पर भीषण राज्य दमन और क्रूर हथियारबन्द आक्रमणों के द्वारा इन इलाकों को बहुराष्ट्रीय व बड़े घरेलू कम्पनियों को खनन और अन्य परियोजनाओं के लिये सौंपा गया है, जनविरोधी निर्णयों को कैसे दमन के जरिए लागू किया गया है, कैसे नर्मदा बचाव, जैतापूर व कूडनकुलम परमाणु संयन्त्र–विरोधी आन्दोलनों के सन्दर्भ में उभरे जनमत को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है और कैसे कलिंगनगर तथा पोस्को–विरोधी जुझारू जनान्दोलनों को कुचलकर कार्पोरेट एजेन्डे को लागू किया जा रहा है। इससे यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि साम्राज्यवादियों और उनके दलालों के हित साधने के लिये जनता को खुन की दरिया में डुबोने से भी शासक वर्ग नहीं हिचकिचायेंगे। इसलिये और भी जरूरी हो जाता है कि हम महसूस करें कि यह सिर्फ पोलवरम परियोजना की निर्माण का ही मुद्दा नहीं बल्कि हमारे देश की भविश्य से ही सम्बन्धित मुद्दा है। अगर हम इस बार पोलवरम के खिलाफ एकजुट होने और संघर्ष करने में असफल रहें तो शासक वर्ग हमारे प्यारे देश का और हमारे लोगों का पूरी तरह विनाश करेंगे। यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा किये गये जनसंहार की तरह ही वर्तमान हमारे देश में एक जनसंहार चलाया जा रहा है। फर्क केवल यह है कि शासक अब हमारे देश के ही हैं। यह अन्दरूनी औपनिवेशवाद की तरह ही है।

अध्यादेश का विरोध करने के साथ साथ हमें इस परियोजना को, जो मानव और प्रकृति के भयंकर विनाश का दूसरा नाम है, रद्द करने की मांग पर चल रहे आन्दोलन को तेज, विस्तारित व मजबूत करने के लिये जनता को गोलबंद करना होगा। सभी परियोजना–विरोधी लोगों को एकजुट कर एक विस्तारित, एकताबद्ध व जुझारू आन्दोलन खड़ा कर हमें एक तीखी संघर्ष लड़नी होगी। इस परियोजना के निर्माण के संर्दभ में मोदी और चन्द्रबाबू सरकारों द्वारा लिये गये सभी प्रतिक्रियावादी निर्णयों के खिलाफ होनेवाले संघर्ष इस आन्दोलन का हिस्सा होना चाहिये।

हमें इस आन्दोलन को इन ठोस मांगों के आधार पर लड़ना चाहिए और

आन्दोलन के क्रम में आये बदलावों के मुताबिक आनेवाले दिनों में नयी मांगे भी रखनी चाहिये:

1. बहुआयामी पोलवरम परियोजना का निर्माण तुरंत बन्द होना चाहिये।
2. इस तरह का एकतरफा और मनमानी निर्णय लेने की अधिकार पर रोक लगाने के लिये कानून में जरूरी बदलाव लाना चाहिये।
3. हमें स्थानीय आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के लिये लड़ना चाहिये।
4. पाँचवी अनुसूची, पेसा, 1/70, वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण कानुन आदि में उल्लेखित आदिवासियों के अनुकूल अनुच्छेदों को लागू करने के लिये संघर्ष करना चाहिये, जो अब तक सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गयी है और जिसे सरकार ने कभी भी अमलीजामा पहनाने की कोशिश नहीं की है।
5. इस इलाके में बहुसंख्या में मौजूद आदिवासियों की स्वायत्तता की अधि कार के लिये चल रहे संघर्षों से पोलवरम परियोजना-विरोधी आन्दोलन को जोड़ना चाहिये।
6. यह इलाका तेलंगाना में ही रहना चाहिये और उसे आन्ध्र प्रदेश को हस्तान्तरन नहीं किया जाना चाहिये।

तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ - इन चारों राज्यों के लोगों का यह आम मुद्दा है। इसलिये यह चारों राज्यों के लोगों का एक एकताबद्ध संघर्ष होना चाहिए। क्योंकि भले ही तेलंगाना इस परियोजना का केन्द्रबिन्दु हो, लेकिन इसका सिर्फ दोनों राज्यों के तेलुगु लोगों के लिये ही नहीं बल्कि ओड़िशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के लोगों के लिये भी विनाशकारी परिणाम होंगे। इस परियोजना से प्रभावित होनेवाले चारों राज्यों के सभी आदिवासी व गैर-आदिवासी ताकतों और संगठनों को एकजुट होकर इस आन्दोलन को एक विशाल जनसघंर्ष में तब्दील करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला और ओड़िसा के मलकानगिरि जिला में पहले से ही शुरू किये गये विरोध को और भी तेज करना चाहिए। परियोजना के खिलाफ लड़ रहे सभी संगठनों का एक व्यापक संयुक्त मोर्चा तैयार करना चाहिए। सात मंडलों के गावों के हस्तान्तरन के विरोघ में सीमित एजेन्डे के साथ चल रहे आन्दोलन को परियोजना-विरोधी व्यापक आन्दोलन का

हिस्सा बनाना चाहिए।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी चारों राज्यों की जनता से अपील करती है कि इस मानव-निर्मित आपदा का तथा समाज के हाशिये पर रहनेवाले आदिवासियों के ऊपर ढाये जा रहे अन्याय का तथा उनके अधिकार, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और इज्जत की हनन का तीव्र निन्दा करने के लिये आगे आयें। हमारे देश में चल रहे इस तरह के अन्य आन्दोलनों के साथ इस आन्दोलन को जोड़ने और इसे एक व्यापक देशव्यापी आन्दोलन में तब्दील करने की हम अपील करते हैं।

मजदूर, किसान, आदिवासी, छात्र, नौजवान, कवि, कलाकार, बूद्धिजीवी, पत्रकार, टीवी-सिनेमा कलाकार, सरकारी व निजी कर्मचारी, व्यापारी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं को इस आन्दोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में गोलबन्द होने के लिये हम अपील करते हैं। खासकर कश्मीर और पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय मुक्तिसंघर्ष के योद्धाओं को भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी अपील करती है कि वे मूलनिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिये आगे आयें तथा पोलवरम-विरोधी आन्दोलन का समर्थन करें।

हम तेलंगाना सरकार के साथ ओड़िशा और छत्तीसगढ़ सरकारों, जो इस परियोजना के खिलाफ होने का दावा कर रहे हैं, से मांग करते हैं कि वे केन्द्र सरकार की इस फासीवादी निर्णय का विरोध कर रही जनता के साथ खड़े हो क्योंकि यह परियोजना इन राज्यों के लोगों की हितों को रौंद रहे है और ये संघीय ढांचा की अवधारणा के भी खिलाफ है। हमारी पार्टी उन्हें चेतावनी देती है कि मोदी और चन्द्रबाबू सरकारों के साथ कोई धूर्ततापूर्ण समझौता करने पर उनको जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

बड़े बांध तथा अन्य जनविरोधी व पर्यावरण-विध्वंसी परियोजनाओं का विरोध करनेवाले और मूलनिवासियों के हक-अधिकारों के लिये लड़नेवाले सभी अन्तरराष्ट्रीय ताकतों को पोलवरम से प्रभावित होनेवाले लोगों की आन्दोलन के समर्थन में खड़ा होने और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर यथासम्भव दबाव डालने की हमारी पार्टी अपील करती है।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी पार्टी के सभी कतारों और पीएलजीए को तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन के इलाकों के क्रान्तिकारी और जनवादी संगठनों व लोगों को इस आन्दोलन का समर्थन करने, इसमें एक सक्रिय

भुमिका निभाने और इसकी पहली कतार में खड़े होकर लड़ने की आह्वान करती है। हमारी पार्टी उनसे आह्वान करती है कि वे आन्दोलन के पक्ष में सभी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी को, जो जनता के हितों को प्राथमिकता देती है, इस आन्दोलन को एक व्यापक, जुझारू और एकताबद्ध जनान्दोलन में विकसित करने, इसके लिये विभिन्न देशव्यापी आन्दोलनों का समर्थन हासिल करने तथा हमारे देश की हितों को नुकसान पहुँचानेवाले शासक वर्गों की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ चल रही जनवादी आन्दोलन के एक अभिन्न अंग के तौर पर व्यापक जनता को गोलबन्द करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस आन्दोलन को विश्वव्यापी साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का एक अटूट हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

30-7-2014

गाजा में इजराइली हमला और फिलिस्तीनी जनता का कत्ले-आम का निंदा करें!
आजाद फिलिस्तीन के लिए चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का समर्थन करें!!

इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रामक हमला कर ज्यादातर बच्चों और महिलाओं सहित अब तक 1200 से भी अधिक जनता का कत्ल किया है। इजराइल की इस बर्बरतापूर्ण हमला को भाकपा(माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी निंदा करती है। गाजा पर अमानवीय आर्थिक नाकेबंदी और इजराइल की सैनिक हमलों को तुरंत बंद करने की हम मांग करते हैं। अनगिनत कुर्बानियों से आगे बढ़ रहे फिलिस्तीनी प्रतिरोध को हम अभिनन्दन करते हैं।

सभी फिलिस्तीनी भू-भागों को जोड़कर एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए हमास और अल-फतह संस्थाओं के बीच हुए समझौते को नाकाम करने के लिए इजराइल ने यह हमला किया है। साथ ही, अरब देशों के बीच में पनप रहे दरारों का इजराइल फायदा उठाना चाहता है, जो खासकर सीरिया और इराक में शीया-सुन्नी के बीच संघर्ष के बाद बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुख्य एजेंट होने के नाते इजराइल को अमेरिकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों का समर्थन मिल रहा हैं।

संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बेशर्मी से घोषणा किया कि फिलिस्तीन की संघर्ष को समर्थन देते हुए भारत सरकार इजराइल से भी अपने रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। इस बयान का मतलब है इजराइली हमले का खुला समर्थन और फिलिस्तीनी जनता की लड़ाई से गद्दारी। भारत के शासक वर्ग और खासकर इसके ब्राह्मणवादी हिन्दू-फासीवादी गुट जिसका भाजपा प्रतिनिधित्व करती है, इजराइल की विस्तारवादी, अंधराष्ट्रवादी और मुसलमानविरोधी नीति से अपने आपको काफी करीब महसूस करती है। इजराइल के साथ भारत

ने करीबी रिश्ता कायम किया है और उससे सबसे ज्यादा मिलिटरी उपकरण आयात करनेवाली देश बन गयी है। 'इस्लामिक आतंकवाद' और माओवादी आन्दोलन को कुचलने के लिए भारत और इजराइल संयुक्त मिलिटरी अभ्यास कर रहे हैं, इजराइल भारत की फौज और पुलिस को प्रशिक्षित कर रही है और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में नियमित मदत दे रही है। इजराइल की हमलों को निंदा करने में भाजपा सरकार की असहमति को के बारे में कांग्रेस पार्टी अब जोरशोर से विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस शासन के समय ही भारत ने इजराइल के साथ आर्थिक और कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये थे।

सभी क्रान्तिकारी और जनवादी संगठनों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के अमन चाहने वाले जनता को फिलिस्तीनी आन्दोलन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और इजराइल के प्रति भारत सरकार की सकारात्मक रवैया का घोर विरोध करना चाहिए। हमारी पार्टी सभी देशों के माओवादी ताकतों, साम्राज्यवाद-विरोधी संगठनों, राष्ट्रीय मुक्ति संगठनो तथा दुनिया के अमन और आजादीपसंद जनता को आह्वान करती है कि वे एकजुट होकर इजराइल की आक्रामक युद्ध का विरोध करें और फिलिस्तीन की संघर्षरत जनता का साथ दें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

28-8-2014

वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड कोबाड गांधी को हैरान-परेशान करना तुरंत बंद करो!
वरिष्ठ नागरिक माओवादी राजनीतिक बंदियों को बेशर्त रिहा करो!

17 सितम्बर 2009 को आंध्र प्रदेश और दिल्ली पुलिस व खुफिया विभाग ने मिलकर वरिष्ठ कॉमरेड कोबाड गांधी को दिल्ली के एक सार्वजनिक स्थान से अपहरण कर गैरकानूनी हिरासत में पूछताछ के नाम पर तीन दिन तक तीव्र मानसिक और शारीरिक यातनाएं दिये। मनावाधिकार और जनवादी संगठनों के कड़े विरोध के बाद उन्हें 21 सितम्बर को कोर्ट में पेश किया गया। उस समय के गृहमंत्री चिदम्बरम ने बेशर्मी से झूठा घोषणा किया कि उन्हें 20 सितम्बर के रात को गिरफ्तार कर '24 घंटे के अंदर' 21 तारीख को ही कोर्ट में पेश किया गया था। जिंदगी खतरे में डालनेवाली बीमारियों से ग्रसित कामरेड कोबाड गांधी के गिरफ्तारी के बाद अनेक दिनों तक अमानवीय ढंग से इलाज और दवाईयों से वंचित रखा गया।

इस तरह से उनकी गैरकानूनी गिरफ्तारी और जेल में रखने के पांच साल गुजरने के बाद भी उनको राज्य जमानत नहीं दे रही है और झूठे मुकदमें लगाकर ज्यादा समय जेल में रख रही है। कॉमरेड कोबाड गांधी का उम्र 69 साल है। वे गंभीर हृद्‌य रोग, आंत की बीमारी, रीढ़ की हड्‌डी की दर्द, बी. पी. और प्रोस्टेट के मरीज हैं। उनके उम्र और गंभीर बीमारियों की हालत और बारम्बार अनुरोध को दरकिनार करते हुए केन्द्र व राज्य के खुफिया विभाग, पुलिस व जेल अधिकारी और न्यायालय उनकी तकलीफों की अनदेखी कर रहे है और कानून के मुताबिक मिलनेवाले सुविधाओं के लिए किए गये उनके मांगों को भी ठुकरा रहे हैं। यह उनके तबियत को बिगाड़ने की षड्‌यंत्र के

तहत किया जा रहा है। उनके बहन द्वारा दिये गये स्वास्थ्य उपकरणों, लिखने–पढ़ने के लिए कुर्सी–टेबुल, पेड जेसे लेखन सामग्री, बिस्तर और किताबों के लिए भी उन्हें काफी लड़ाई करना पड़ा, और इसे भी जेल अधिकारियों ने बहुत ज्यादा छानबीन के बाद ही उपलब्ध करवाया।

फरवरी 2013 को तिहार जेल में अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बाद, जो भारत की न्यायव्यवस्था पर ही एक दाग है, बंदियों के कड़े विरोध के बावजूद सभी बंदियों को हाई–रिस्क वार्ड नम्बर 3 (तिहाड़ जेल, दिल्ली) से बदली किया गया। कॉमरेड कोबाड के तीव्र विरोध के बावजूद उन्हें बलपूर्वक ढंग से जेल नम्बर 1 में बदली किया गया। इसके अतिरिक्त, एक इतने उम्रदराज और बीमार व्यक्ति को जेल अधिकारियों ने क्रूरता से अपना सामान खुद ढोने के लिए मजबूर किया और उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाया। इस कारण से उन्हें कई हफ्तों तक बिस्तर में ही रहना पड़ा। रोजमर्रा की जरूरी कामों, जैसे बकेट में पानी लाना, बैठकर कपड़ा धोना आदि काम करने में बेहद मुश्किलों का सामना करने के बावजूद कॉमरेड कोबाड को जेल अधिकारियों के तरफ से कोई सहायता नहीं दी गयी।

उन्हें एक जेल से दूसरे जेल में बदली करने के बाद हर बार उन्हें मामूली सुविधाओं और सहुलियतों के लिए भी अर्जी की प्रक्रिया फिर से शुरू करना पड़ता है, जिससे पहले से मिल रही कुछ सुविधाएं फिर से दी जाती हैं तो कुछ अन्य रोक दिये जाते हैं। तिहार जेल के वरिष्ठ नागरिक वार्ड में रखे जाने की उनकी मांग को पूरा करने के बजाए उन्हें जुलाई 2014 में जेल नम्बर 2 में फिर बदली किया गया। उन्होने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बदलियों से उनकी तबियत और भी बिगड़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बदली की गयी। उनके पास आमरण अनशन के अलावा विरोध का और कोई चारा नहीं था। इसी बीच 16 जुलाई को उन्हें बलपूर्वक स्ट्रेचर मे डालकर जेल नम्बर 2 में बदली किया गया।

जिस तरह भाकपा(माओवादी) के पोलितब्यूरो सदस्य कॉमरेड सुशील राय को 2005 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस और जेल अधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत सही ढंग से इलाज नहीं करवाकर 18 जून 2014 को मौत के मुह

में ढकेल दिया था, इस आलोक में कॉमरेड कोबाड गांधी की हालत पर चिंतित होना स्वाभाविक है। सरकार 50-60-70 साल उम्र के माओवादी नेताओं के साथ क्रूर व अमानवीय व्यवहार कर रही है और उन्हें काल-कोठरी में ही अन्तिम सांस लेने के लिए मजबूर करने की साजिश रच रही है। उन्हें जमानत नहीं दिया जा रहा है, अगर जमानत मिले तो नये मुकादमें लगाये जा रहे है, रिहा होने पर जेल की गेट से ही फिर से गिरफ्तार कर जेल में ठूँस रहे हैं। कॉमरेड्स नारायण सन्याल, भूपेशदा, परेशदा, साहेबदा, चिंतनदा, शीला दीदी, अमित बाग्ची, प्रमोद मिश्र, बच्चा प्रसाद सिंह, चन्द्र शेखर रेड्डी, एल.एस.एन. मुर्ति, पतितपावन हलदार, वाराणसी सुब्रहमण्यम और कई अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं को उनके बढ़ते उम्र या गम्भीर बिमारियों की परवाह किये बिना और उनसे कोई सहानूभुति न रखते हुए लगातार हैरान-परेशान किया जा रहा हैं। सभी कानुनों को पेड़ो के निचे कुचलते हुए जीएन साईबाबा जेसे 90 प्रतिशत विकलांग बुद्धिजीवी को भी कोई सुविधा उपलब्ध न करवाकर जेल में परेशान किया जा रहा है। इस तरह की परिस्थिति में देशभर की जेलों में केद आम आदिवासी, दलित और महिला बंदियों के साथ क्या व्यवहार हो रहे होंगे उसका हम अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। बिना कोई सुविधा और सहुलियत के, पुलिस-जेल अधिकारियों के उत्पीड़न का सामना करते हुए तथा अन्यायपूर्ण न्यायव्यवस्था का शिकार होते हुए ये बंदी सालों-साल जेल के शलाखों के पीछे बीता रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकने के कारण कुछ बंदियों की जेल में ही मौत हो रही हैं।

अमित शाह जेसे हत्यारों को बेकसूर घोषित करने के लिए मोदी सरकार न्यायव्यवस्था को आदेश दे रही है और उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इस ढंग से उनके हत्याओं और करतूतों को मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर राजनीतिक बंदियों और आम बंदियों के मामूली मुकदमों को भी पुलिस एसकोर्ट की अभाव आदि बेतूकी बहानों से असीमित समय तक लम्बित किया जा रहा है। बंदियों को कानून के मुताबिक मिलनेवाली सुविधाएं मुहैया नहीं किया जा रहा है और राज्य उनके खिलाफ बदले की भावना से बरताव कर रही है।

भाकपा(माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी सभी क्रान्तिकारी, जनवादी व नागरिक अधिकार संगठनों और ताकतों तथा अधिवक्ताओं से अपील करती है कि कॉमरेड कोबाड गांधी को खासकर निशाना बनाकर जेल अधिकारियों के द्वारा उनपर ढाये जा रहे सभी तरह के जुल्मों को बंद करने के लिए एक दृढ़तापूर्ण व एकताबद्ध संघर्ष खड़ा करें और उनकी तत्काल बेशर्त रिहाई की मांग करें। हम तमाम जनता से अपील करते हैं कि सालों-साल जेलों में बंद उपरोक्त वरिष्ठ नागरिक राजनीतिक बंदियों की रिहाई और उनकी राजनीतिक बंदी की मान्यता के अधिकार के लिए बड़े पैमाने पर आन्दोलन तैयार कर सरकार व न्यायव्यवस्था के ऊपर जोरदार दबाव बनायें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

29-8-2014

वरिष्ठ कम्युनिस्ट और जननेता
कामरेड एम.टी. खान को श्रद्धांजलि!

आन्ध्रप्रदेश (आज का तेलंगाना सहित) में क्रान्तिकारी लेखक और मानवाधिकार संगठनों के संस्थापकों में से एक कामरेड एम.टी. खान का 2014 अगस्ट 20 तारीख को निधन हो गया। उनके मृत्यु से भारत की माओवादी आन्दोलन ने एक गहरे दोस्त को खो दिया। भाकपा(माओवादी), की केन्द्रीय कमेटी सिर झुकाकर उनको लाल श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनके परिजनों और मित्रों को गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है। उनके मृत्यु से जनवादी और क्रान्तिकारी संगठनों के दुख में हमारी पार्टी शरीक हो रही है।

खान साहेब के नाम से परिचित मुहम्मद ताजुद्दीन का हैदराबाद के पुराना पूल दरवाजा के पास 1935 में जन्म हुआ था। सिटी कॉलेज में हाई स्कूल की शिक्षा पूरा कर विवेकवर्धिनी कॉलेज में पी.यू.सी कोर्स में प्रवेश हुए। उसमानीया विश्वविद्यालय में बी.ए में प्रवेश होने के बावजूद आर्थिक कारणों से बी.ए पूरा नहीं कर पाये। तेलंगाना में उन दिनों में हुए कम्युनिस्ट, किसान और छात्र आन्दोलनों से प्रभावित होकर कम्युनिज्म की ओर आकर्षित हुए और भाकपा पार्टी में शामिल हो गये। खान साहेब ने तेलंगाना सशस्त्र आन्दोलन के समय एक प्रमुख कम्युनिस्ट नेता और कवि हैदराबाद निवासी कामरेड मकदुम महयुद्दीन के कुरियर का काम भी किया। महयुद्दीन का प्रभाव खान साहेब पर रहा। खान साहेब ने प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और संस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया।

सन् 1964 में जब भाकपा दो पार्टियों में विभाजित हो गया। संशोधनवाद से सम्पूर्ण रूप से नाता तोड़कर माकपा भारत की क्रान्ति का नेतृत्व करने की आशा से खान साहेब माकपा में शामिल हुए। लेकिन वह माकपा से भी निराश हो गये क्योंकि माकपा संशोधनवादी मार्ग पर ही चल रही थी। सन् 1967 में उभरे

नक्सलबाड़ी आन्दोलन और सन् 1968 के श्रीकाकुलम आन्दोलनों से प्रेरणा लेकर उन्होंने नक्सलबाड़ी मार्ग पर चलने का फैसला लिया। उस मार्ग पर चलने का निर्णय लेने के बाद वे कभी भी नहीं डगमगाये और दृढ़संकल्प के साथ आगे बढ़े।

सन् 1972 में कामरेड चारू मजुमदार शहीद होने के बाद आन्दोलन को गतिरोध का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में पार्टी ने आन्दोलन को फिर से रास्ते पर लाने के लिए कोशिश किया। उस समय में पार्टी लाईन के पक्ष में खड़ा होने वालों में खान साहेब भी एक थे। सन् 1972 में आन्ध्र राज्य कमेटी ने 'पिलूपू' (आह्वान) पत्रिका को प्रकाशित करना शुरू किया। बहुत कठिन परिस्थिति में भी खान साहेब ने उस निर्णय को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। पत्रिका के माध्यम से दीर्घकालीन लोकयुद्ध के पक्ष में कार्यकर्ताओं को जुटाने का काम शुरू किया। दक्षिणपंथी अवसरवादी लोग चारू मजुमदार को निन्दा करते हुए प्रचार कर रहे थे। कुछ विघाटनकारी शक्तियां पूरे आन्दोलन का खात्मा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इन परिस्थितियों में 'पिलूपू' पत्रिका द्वारा राजनीतिक और सैद्धांतिक बहस चलाके उन सभी शक्तियों को मुहतोड़ जवाब दिया था। सही कार्यकर्ताओं को जुटाया भी था। सरकारी दमन के चलते कुछ लोग आन्दोलन छोड़ गये थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी खान साहेब ने बहुत अच्छा काम किया।

सन् 1973 में 'मीसा' के नाम पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1974 में एक षड्यंत्र केस लगाया गया। आपातकालीन समय में उन्हें सरकार ने जेल में रखा था। राजनीतिक और सैद्धान्तिक बहस के लिए उन दिनों में जेल एक केन्द्र बन गया था। ऐसे राजनीतिक उलझन के परिस्थितियों में सही मार्ग पकड़ना आसान नहीं है। ऐसे राजनीतिक बहसों के जरिए खान साहेब सही मार्ग पर खड़े हुए थे और वह इस अनुभव से और भी ज्यादा फौलादी बनकर निकले।

सन् 1970 में क्रान्तिकारी लेखक संघ की स्थापना में खान साहेब भी शामिल थे। 1971 में इस संगठन का पहला सम्मेलन इनकी अगुवाई में हुआ। इस संगठन ने नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम आन्दोलनों के पक्ष में प्रचार किया और मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की सिद्धान्त को भी जबर्दस्त रूप में प्रचार किया। 1974 में ए.पी.सी.एल.सी को गठन करने में और उसको विस्तार करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाया। खान साहेब 1992 से 1998 तक उस संगठन के अध्यक्ष के रूप में रहे। उन दिनों वेंगलराव सरकार ने जनता के ऊपर क्रूर

दमन चलाया और फर्जी मुठभेड़ों में बहुत कार्यकर्ताओं को मार दिया था। इसके खिलाफ खान साहेब ने अपनी आवाज उठायी।

भाकपा और माकपा की नेतृत्व वाली जनसंगठन सुधारवादी दलदल में फंस गये थे। इस कारण नक्सलबाड़ी समय में जनसंगठनों का निर्माण नहीं किया गया था। ये सभी परिस्थितियों को समीक्षा करके आन्ध्रप्रदेश में जनसंगठनों का निर्माण शुरू किया गया था। इस सिलसिला में नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम आन्दोलनों को समर्थन देने वाले लेखकों और जनवादियों को लेकर क्रान्तिकारी लेखक संघ और ए.पी.सी.एल.सी को निर्माण किया गया था। राजनीतिक बहस और लड़ाई में शामिल होते हुए इन संगठनों को उन्होंने सुधारवादी दलदल में पड़ने नहीं दिया। आन्ध्रप्रदेश की जनता का क्रान्तिकारी और जनवादी चेतना बढ़ाने में इन संगठनों का योगदान अहम है। इसमें खान साहेब की भूमिका अविस्मरणीय है।

भारत–चीन मित्र मंडली में खान साहेब चीन समाजवादी देश रहने तक सदस्य के रूप में थे। चीन संशोधनवादी बनने के बाद वे मित्र मंडली से हट गये। हैदराबाद में साम्प्रदायिक दंगों के खिलाफ बनी कई संगठनों में उन्होंने भाग लिया। फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ आन्दोलन में, राजनीतिक बंदियों की रिहाई आन्दोलन में, अलग तेलंगाना राज्य आन्दोलन में और कई जनवादी आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया था।

मानवाधिकार, कला, साहित्य और नाट्क आदि क्षेत्रों में उनकी रूचि थी। इन क्षेत्रों में उन्होंने विशेष काम किया। वह एक कवि भी थे और उन्होंने कई कविताएं लिखे। उन्होंने कई रचनाओं को उर्दू में अनुवाद किया। हैदराबाद में मुसलमान जनता के बीच उर्दू में क्रान्तिकारी राजनीतिक परचा लिखकर प्रचार किये। 'सियासत' जैसे उर्दू पत्रिकाओं और 'न्यूज़ टाईम' जैसे अंग्रेजी पत्रिकाओं को ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण किये गये लेख भेजते थे।

खान साहेब ने छः दशक से जनता के बीच रह कर अनेक जिम्मेदारियां निभाये। आन्दोलन के मुख्य मोड़ों पर अहम भूमिका निभाये। साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए बहुत कठिन कामों को भी उन्होंने पूरा किया। क्रान्तिकारी लेखक संघ, ए.पी.सी.एल.सी के मुख्य स्तंभ के रूप में रहते हुए, आन्ध्रा और तेलंगाना में अनेक आन्दोलनों में शामिल होते हुए नौजवानों को प्रेरित किया। उनके कुछ समकालीन लोग मार्क्सवादी सिद्धांत पर विश्वास खोकर और पारिवारिक दबाव में फंसकर आन्दोलन से अलग हो गये और स्वार्थी बन गये। पिछले दशक में आन्ध्रप्रदेश में क्रान्तिकारी आन्दोलन की नेतृत्व की लगातार

नुकसान के परिस्थितियों में जनसंगठनों के नेतृत्व को लचीलापन और दृढ़ता के साथ काम करने की आवश्यकता थी। खान साहेब जैसे साथियों ने ये काम अच्छी तरह निभाये थे। ये तरीका आनेवाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। सैद्धान्तिक रूप से इसकी जरूरत को साफ तौर पर जाहिर करने के बावजूद क्रान्तिकारी आन्दोलन ने मुसलमान जनता के बीच में उतना पकड़ नहीं बना सकी है। इस परिस्थिति में खान साहेब जैसे लोगों की जरूरत ज्यादा हैं। खान साहेब के अधूरे सपनों को पूरा करना उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी। उनके जीवन के बारे में मुसलमान जनता के बीच प्रचार कर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। राज्य व्यवस्था हिन्दू फासीवादी रूप लेते हुए मुसलमानों को लक्ष्य बना कर खतरे में डालने की आज की परिस्थिति में खान साहेब की जीवनी को उन लोगों के बीच प्रचार कर उनको आन्दोलन की ओर आकर्षित करना होगा। साम्राज्यवाद की उपभोक्तावादी संस्कृति आज जब चरम पर है, ऐसी परिस्थिति में जनता से प्यार करना और एक सरल जीवन बिताना तथा अपनी जड़ों को न भूलना एक महान आदर्श है। जिंदगीभर आर्थिक समस्याओं से जूझने के बावजूद खान साहेब ने अपने आप को क्रान्तिकारी उद्देश्यों से अलग होने और कभी भी क्रान्तिकारी उत्साह को कम होने नहीं दिया।

इस देश में आजादी के लिए, जनवाद के लिए और लूट-खसोट की व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हजारों शहीदों के साथ-साथ खान साहेब के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए भाकपा(माओवादी) की केन्दीय कमेटी फिर एक बार शपथ लेती है। नवजनवादी समाज की स्थापना ही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी। हमारा अनुरोध है कि हर एक क्रान्तिकारी कार्यकर्ता खान साहेब की जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके दिखाये मूल्यों व सरल रहन-सहन को आत्मसात कर उनके राह पर आगे बढ़ें। हम सभी से अपील करते हैं कि हमारे प्यारे खान साहेब के स्मृतियों और उनके आदर्शों को जिंदा रखे और उन्हें प्रचारित करें।

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)